



आर्थिक समीक्षा 2019-20

खण्ड 1

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
आर्थिक प्रभाग
नॉर्थ ब्लॉक
नई दिल्ली-110001

ई-मेल: cordecndn-dea@nic.in
जनवरी, 2020

विषय सूची

अध्याय सं.	पृष्ठ सं.	अध्याय का नाम
1		अर्थ संपदा सृजन: विश्वास भरे अदृश्य हाथों की भूमिका
	2	अर्थ सृजन का महत्व
	6	खुली अर्थव्यवस्था के माध्यम से अर्थ सृजन
	9	संपत्ति सृजन के लिए उपकरण
	14	इस शताब्दी के पहले के वर्षों में विश्वास का टूटना
2		जमीनी स्तर पर उद्यमिता एवं धन सृजन
	28	उद्यमिता एवं जीडीपी
	35	उद्यमी गतिविधि के निर्धारक तत्व
	38	तेज रफ्तार उद्यमिता एवं धन सृजन हेतु नीति निर्धारण
3		व्यापार समर्थक बनाम पक्षवाद
	43	बाजार समर्थक, रचनात्मक विनाश एवं संपत्ति सृजन
	52	पक्षपातवाद और वैभव विनाश
	55	नीलामियों के माध्यम से आबंटन की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना आबंटन
	60	जोखिम रहित प्रतिफल - जानबूझ कर चूक का मामला
	63	नीतिगत सुझाव
4		बाजार की अनदेखी: जब अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से लाभ की बजाय नुकसान होता है।
	72	आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई सी ए), 1955
	78	ईसीए के अंतर्गत औषधि मूल्य नियंत्रण
	82	खाद्यान्न बाजारों (मंडियों) में सरकारी हस्तक्षेप
	88	ऋण माफियां
	93	सरकारी हस्तक्षेप को कम करने के लिए अपेक्षित विधायी बदलाव
5		नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात-विशेषज्ञता द्वारा रोजगार-सृजन और विकास
	102	चीन की तुलना में भारत का निर्यात में निम्न-निष्पादन
	109	ग्लोबल वेल्यू चेन में भागीदारी से लाभप्राप्त करना।
	110	रोजगार के सृजन हेतु कौन से उद्योगों में भारत को विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए?
	116	प्रवेश का पैटर्न
	119	रोजगार एवं जीडीपी का संभावित लाभ
	121	क्या व्यापार समझौता लाभकारी है?
	124	भावी परिदृश्य
6		भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने का लक्ष्य
	128	परिचय
	130	वैश्विक तुलना
	132	विनिर्माण में विधिक जटिलता एवं सांविधिक अनुपालन की आवश्यकता
	134	व्यवसाय शुरू करना: रेस्टोरेट चलाने में नियामक बाधाएं
	136	निर्माण अनुज्ञा

137	व्यापार के बड़े पैमाने को प्राप्त करना
137	सीमापार व्यापार
139	विशिष्ट खंडों में संभारतंत्र में भारत के निष्पादन का केस अध्ययन
147	निष्कर्ष
7	बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती: एक समीक्षा
156	बैंकिंग संरचना: राष्ट्रीयकरण से अब तक
157	राष्ट्रीयकरण के लाभ
163	पीएसबी की दक्षता बढ़ाना: भावी परिदृश्य
176	निष्कर्ष
8	एनबीएफसी सेक्टर में वित्तीय भंगुरता
183	आवर्ती जोखिम (रोल ओवर रिस्क) का संकल्पनात्मक ढांचा
186	एचएफसी तथा खुदरा-एनबीएफसी के बीच अंतर
193	परिसंपत्ति वित्तीय भंगुरता आकलन हेतु निदान
199	नीतिगत विवक्षाएं
9	निजीकरण और धन सृजन
206	निजीकरण का प्रभाव: फर्म स्तर का विश्लेषण
224	भावी परिदृश्य
10	क्या भारत की जीडीपी वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जाता है? नहीं।
231	परिचय
233	क्या जीडीपी का गलत आकलन किया गया है?
251	एक निदानकारी विश्लेषण
257	निष्कर्ष
11	थालीनॉमिक्स: भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र
260	प्रस्तावना
263	थाली की कीमतें
267	थाली की वहनीयता
272	थाली के घटकों के मूल्यों का रूझान
274	थाली स्फीति
276	थाली की कीमतों में परिवर्तनशीलता
285	निष्कर्ष

आभारोक्ति

आर्थिक समीक्षा 2019-20 मिलजुल कर किए गए कार्य एवं परस्पर सहयोग का परिणाम है। यह आर्थिक समीक्षा माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन तथा माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर की मूल्यवान टिप्पणियों तथा उनकी अंतर्दृष्टि से अत्यंत लाभान्वित हुई है। यह समीक्षा जिन अधिकारियों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके द्वारा दी गई जानकारी से भी लाभान्वित हुई है उनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-श्री राजीव कुमार, अतनु चक्रवर्ती, अजय भूषण पांडे, डॉ० टी.वी. सोमनाथन, तुहिन पांडे, अरविंद श्रीवास्तव एवं विशाल शर्मा शामिल हैं।

इस समीक्षा को तैयार करने में आर्थिक प्रभाग के जिन कार्मिकों का योगदान उल्लेखनीय है उनमें: संजीव सान्याल, सुष्मिता दासगुप्ता, अरुण कुमार, राजीव मिश्रा, राजश्री रे, ए. सृजा, सुरभि जैन, अश्विनी लाल, अथिरा एस बाबू, अभिषेक आचार्य, जितेन्द्र सिंह, रजनी रंजन, अविनाश दाश, सिंधुमन्निक्ल थंकप्पन, प्रेरणा जोशी, धर्मेन्द्र कुमार, आकांक्षा अरोड़ा, दिव्या शर्मा, एम. राहुल, रवि रंजन, तुलसीप्रिया राजकुमारी, शमीम आरा, गुरविंदर कौर, जे.डी. वैशंपायन, आर्या बालन कुमारी, संजना कादयान, अमित श्योरन, श्रेया बजाज, मनोज कुमार मिश्रा, सुभाष चंद, रियाज अहमद खान, मो. आफताब आलम, प्रद्युत कुमार पाईन, नरेंद्र जेना, श्रीवत्स कुमार परिदा, मृत्युंजय कुमार, राजेश शर्मा, अमित कुमार केसरवानी, अर्पिता वायकरे, महिमा, अंकुर गुप्ता, अर्जुन वर्मा, लविशा अरोड़ा, सोनाली चौधरी, कविशा गुप्ता, तीर्थकर मंडल, हर्ष मीनावत, रघुवीर राघव, एस. रामकृष्णन और सत्येंद्र किशोर शामिल हैं।

यह समीक्षा जिन अधिकारियों की मूल्यवान टिप्पणियों एवं उनके द्वारा प्रदान की गई जानकारी से लाभान्वित हुई है उनमें विशेषकर श्री आदिल जैनुलभाई, अध्यक्ष, भारतीय गुणवत्ता परिषद्, श्री चेतक सीतापति, परियोजना प्रबन्धक, रूद्रनील चट्टोपाध्याय, परियोजना प्रबन्धक, हेल्वी मारवीय, प्रशिक्षु, (क्यूसीआई), श्री एच नागराज, वेलंकनी इलेक्ट्रानिक्स गरीमा धीर तथा श्री अरुण कुमार झा, महानिदेशक, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् शामिल हैं।

महत्वपूर्ण जानकारियों एवं आर्थिक समीक्षा के विभिन्न आयामों पर चर्चा हेतु आर्थिक समीक्षा दल प्रोफेसर के० वैद्यनाथन का आभार व्यक्त करता है। साथ ही यह दल अजित पाई, अमियतोष पूर्णानंदम, आनंद नंदकुमार, अन्नपूर्ण सिंह, सी वीरामणि, दीप मुखर्जी, दीपा मणि, एजाज गनी, गौतम छाओछरिया, हर्षिणी शंकर, जेफरसन अब्रहम, महेश नंदुरकर, एन प्रभाला, नीलकंठ मिश्रा, नितिन भसीन, पीयूष चौरसिया, प्रांजल शर्मा, प्रसन्ना तंत्री, राजदीप शर्मा, रम्या कृष्णा, रवि अंशुमान, समीर सिंह जैनी, शास्वत आलोक, शिव दीक्षित, सुनील शंघाई तथा यक्षुप चोपड़ा सदृश विद्वानों द्वारा प्रदान की गई महत्वपूर्ण जानकारियों एवं टिप्पणियों के लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता है।

उपरोक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विभागों एवं संगठनों ने अपने संबंधित क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कई मंत्रालयों ने मुझसे सीधा संपर्क कर मेरे समक्ष प्रस्तुति के माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई। आर्थिक समीक्षा उनके मूल्यवान समय, कार्य और योगदान के लिए कृतज्ञ है। आर्थिक कार्य विभाग के मीरा स्वरूप, के. राजारमन, राजकुमार तिवारी, रविन्दर कुमार, जसबीर सिंह, अमित कुमार, सुनील दत्त, रोहित, संजय कुमार पंडिता, साधना शर्मा, अरुण गुलाटी, सुशील शर्मा, मनीष पंवार, मुन्ना शाह, सुरेश कुमार, जोध सिंह तथा मुख्य आर्थिक सलाहकार कार्यालय के अन्य कर्मचारियों एवं सदस्यों द्वारा कुशल प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया गया। समीक्षा के हिन्दी भाषान्तरण में सहयोग के लिए अनुराधा मित्रा, सचिव, राजभाषा विभाग व मंजुला सक्सेना, उप सचिव, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। समीक्षा का हिन्दी अनुवाद अत्यंत कम समय में निहारिका सिंह, सन्तोष मिश्रा, ओमप्रकाश त्रिपाठी, अर्चना सिंह, अनिता कुमारी, बबीता, लिजी थॉमस, झोन्टू मंडल, शौफाली, पवित्र जायसवाल, अंकुर भटनागर, हितेश कुमार गुप्ता, वीना, सुखदेव तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के ओमप्रकाश सिंह, मुरारी लाल गुप्ता, जगत सिंह रोहिल्ला, जनवारियुस तिकी, जय वीर, डॉ. गौतम शर्मा, मनीष भटनागर, अजय कुमार चौधरी, अनुप शॉ, विजय कुमार, रामाश्रय, डॉ. सुरेश कुमार यादव, ध्रुव नारायण आजाद, डॉ. आनंद प्रकाश यादव, सचिन कुमार गुप्ता, रंजीत कुमार साव, राघवेन्द्र पाण्डेय और जी.के. डावर द्वारा किया गया। इस समीक्षा खंड का हिन्दी संपादन प्रोफेसर बी.एस. बागला, डॉ. अब्दुल रहीम अंसारी और डॉ. लोकेंद्र कुमावत द्वारा किया गया। हिंदी टंकण कार्य कमलेश तक्खी, कुसुम लता, कल्याणी बासुमतारी, विजय कुमार कोष्टा, सुरेश चंद, धर्मवीर, संजय प्रसाद द्वारा किया गया। समीक्षा के आवरण पृष्ठ का डिजाइन इंडिया ब्रैंड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा किया गया। इस समीक्षा के हिंदी व अंग्रेजी संस्करण का मुद्रण कार्य चंद्र प्रभु ऑफसेट प्रिंटिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड द्वारा किया गया।

अंत में, आर्थिक समीक्षा कार्य से जुड़े सभी व्यक्तियों के परिवार जनों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने इस कार्य के दौरान असीम धैर्य और उदारता का परिचय तो दिया ही, साथ ही इस समीक्षा को तैयार करने में अपना निरंतर भावनात्मक सहयोग एवं प्रोत्साहन भी प्रदान किया। आर्थिक समीक्षा में समर्पित सहयोगियों के लिए निस्संदेह उनके परिवार शक्ति के मूक स्तंभ रहे हैं।

कृष्णमूर्ति वी सुब्रमणियन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

प्राक्कथन

सन 1976 में एडम स्मिथ द्वारा रचित आधुनिक अर्थशास्त्र का महाप्रबंध ग्रंथ का बड़ा रोचक नाम रखा गया—“ऐन इनक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन”। वर्ष 2019 में जब भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी और वर्ष 2055 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, स्मिथ द्वारा उठाए गए आधारभूत प्रश्नों में से इस प्रश्न की ओर वापस जाना उपयुक्त प्रतीत होता है कि “किसी राष्ट्र की संपदा और समृद्धि के मूल कारण क्या हैं? इस आर्थिक समीक्षा 2019-20 में ऐसी नीतियों का फ्रेमवर्क तैयार करने का विनम्र प्रयास किया गया है जो भारत में संपदा की वृद्धि का कारण बन सकें। इस स्तर पर यह समीक्षा विशेषरूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत वर्ष 2025 तक + 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है—एक महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण जो—जैसा कि स्मिथ ने उल्लेख किया था “सार्वभौम समृद्धि जिसका विस्तार समाज के सबसे निचले तबके तक है”, का सृजन करे।

माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त, 2019 के अपने 73वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस बात पर जोर दिया कि समृद्धि का वितरण तभी हो सकता है जब समृद्धि का सृजन किया जाए। अतः भारत के सम्पन्नता सृजकों के प्रति संदेह और असम्मान की भावना अविवेकी है। समाजवाद के साथ भारत का “वास्ता” को देखते हुए संपदा सृजन के लाभों के बारे में संशय कोई इत्फाक नहीं है। इस संदर्भ में team@ecosurvey2019-20 ने आर्थिक विचारण और आर्थिक नीति निर्माण दोनों ही स्तरों पर बाजार अर्थव्यवस्था से होने वाले लाभों के संबंध में किसी भी संदेह को दूर करने का प्रयास किया है।

इस समीक्षा में उल्लेख है कि सम्पदा सृजन के विचार का मूल कॉटिल्य के अर्थशास्त्र से लेकर थिरूवल्लुवर के “थिरूकुरल” की प्राचीन और समृद्ध भारतीय परंपरा में निहित है, जिसमें नैतिक रूप में सम्पदा सृजन के कार्य को आदर्श मानवीय व्यवसाय मानने पर बल दिया गया है। इस समीक्षा में प्राचीन साहित्य और समकालीन साक्ष्य का उपयोग यह दर्शाने के लिए दिया गया है कि समाजवाद के साथ भारत का जुड़ाव-सहस्रवर्षीय इतिहास में कुछ दशकों के क्षणिक अवधि का है जो मानक के रूप में बाजार के अदृश्य हाथ पर विश्वास एक अपवाद है। मेंडीसन (2007) ने ऐतिहासिक साक्ष्य रूप में उल्लेख किया है कि भारत अर्थव्यवस्था के ज्ञात इतिहास के तीन चौथाई से अधिक समय तक प्रभावी वैश्विक आर्थिक ताकत रहा है। यह प्रभुत्व भारत की सुगठित अर्थव्यवस्था का परिणाम है न कि कोई संयोग है। यह समीक्षा प्राचीन व्यवस्था को व्यस्त करने वाले साहित्य के आधार पर यह दर्शाने के लिए तैयार की गयी है कि बाजार के अप्रत्याशित उतार चढ़ाव को जब विश्वास द्वारा समर्थन मिलता है तो इस प्रकार आर्थिक सुदृढ़ता प्राप्त की जा सकती है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के पश्चात भारत को अपनी जड़ों की ओर लौटने के परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में हुई वृद्धि समकालीन साक्ष्यों को प्रस्तुत करती है। वैश्विक वित्तीय संकट की घटनाएं और भारतीय वित्तीय क्षेत्र की चुनौतियां अप्रत्याशित आर्थिक समस्याओं के सहारे के लिए विश्वास के सहारे की आवश्यकता के साक्ष्य प्रस्तुत करती है। विश्वास को जन मानस के हित में प्रयोग किए जाने से इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इस समीक्षा में लोगों के हितों में वृद्धि के लिए भी कुछ सुझाव हैं। इस प्रकार सम्पन्नता सृजन के लिए इस समीक्षा की अवधारणा प्राचीन और नवीन संश्लेषण प्रस्तुत करती है जोकि प्राचीन भारतीय परम्परा और समकालीन साक्ष्य का संयोजित रूप है अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे बैंकों के संबंध में फिन टेक का सुझाव प्रस्तुत करते हैं। इस समीक्षा में संश्लेषण के साथ ही साथ नए 100 रुपए के नोट और पुराने 100 रु. के नोट दोनों की महक समाहित है।

इस समीक्षा में संपदा सृजन के क्रम को आगे बढ़ाने हेतु बहुत से लीवर दिए गए हैं: भारत के विभिन्न जिलों में नई फर्म चालू करने में यथा प्रदर्शित जमीनी स्तर पर उद्यमिता, व्यापार अनुकूल नीतियों को प्रोत्साहित करना जो प्रो-क्रोनी की वृत्तिभोगी निजी हितों की पक्षधर नीतियों के विरुद्ध सम्पन्नता लाने के लिए प्रतियोगी बाजार की शक्तियों को उजागर करती है। समीक्षा में यह विषय आया है कि स्वस्थ बाजारवाद पद्धति द्वारा तैयार किए गए आंदोलन ने स्थैतिक सहयोगवाद पद्धति की बजाए अधिक धनार्जन किया है।

यह उल्लेख किया जाए कि समीक्षा दोनों पद्धतियों के विपरीत है; दलील व्यक्ति या प्रतिष्ठान केंद्रित नहीं है। इसकी बजाए, इसमें उन नीतियों को समाप्त करने की दलील दी गई है जो सरकारी हस्तक्षेप जहां पर यह आवश्यक नहीं है, के माध्यम से बाजारों का कमतर मूल्यांकन करती है; श्रम-गहन उद्योग निर्यात पर बल देने के लिए “एसेंबल इन इंडिया” को “मेक इन इंडिया” में समाकलित करती है तथा बड़े पैमाने पर जॉब सृजित करती है; भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र में प्रभावी ढंग से वृद्धि करती हैं तथा आभासी बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य की देखरेख करती हैं; दक्षता को बढ़ाने के लिए निजीकरण का प्रयोग करती हैं। अदृश्य हाथ के सहयोग से विश्वास की उम्मीद के साथ समीक्षा में सतर्क साक्ष्य दिया गया है कि जीडीपी वृद्धि के प्राक्कलन पर विश्वास किया जा सकता है।

आर्थिक नीति की लिखतों के रूप में व्यावहारिक अर्थशास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करने के लिए आर्थिक समीक्षा 2018-19 के सामान्य उद्देश्य को जारी रखने हुए तथा मानव व्यवहार के बारे में अवलोकन करने के आसान आंकड़ों के रूप में आर्थिक समीक्षा 2019-20 में वस्तु, जिसका सामना पुरुष या महिला प्रतिदिन करती है—खाने की प्लेट अर्थात् थाली, का प्रयोग करके सामान्य व्यक्ति को अर्थशास्त्र से जोड़ने का प्रयास है।

हमने समीक्षा को दो खण्डों में प्रस्तुत करने की लोकप्रिय परंपरा को जारी रखा है। खण्ड 1, इसमें उन विचारों को प्रस्तुत किया है जो “आर्थिक आजादी एवं धन सृजन” को संपुटित करते हैं, इसमें विश्वसनीय नीति निर्माण के लिए हाल ही के आर्थिक विकास कार्यों के आर्थिक विश्लेषण पर आधारित साक्ष्य दिए गए हैं। खण्ड II में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में हुए हाल ही के विकास कार्यों की समीक्षा की गई है तथा यह संगत सांख्यिकीय तालिकाओं एवं डाटा से समर्थित है। क्षेत्र की मौजूदा स्थिति एवं नीतियों के लिए रैडी रेकनर का कार्य करेगा।

इस आर्थिक समीक्षा के अस्तित्व और लोकप्रियता का श्रेय, भारत सरकार के सभी कार्यालयों, विभागों, आर्थिक सेवा के अधिकारियों के विलक्षण संसाधन आधार, शोधकर्ताओं, सलाहकारों, सरकारी और बाह्य दोनों क्षेत्रों के प्रबुद्ध मंडल/विशेषज्ञ दल के बहुमूल्य परामर्श तथा आर्थिक प्रभाग, आर्थिक कार्य विभाग के सभी अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों को जाता है। इस समीक्षा में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुसरण करने, इसे समझने और इसके बारे में चिंतन करने की दिशा में अपरिहार्य मार्गदर्शक बनने की अभिलाषा पर खरा उतरने का निश्चल प्रयास किया गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बेहतरी के लिए गहनता से विचार-विमर्श करने में team@ecosurvey2019-20 का वैयक्तिक परितोषण हमारे अनंतिम पंचाट को प्रस्तुत करता है। हमे पूरी आशा है कि सुधी पाठकगण भी उसी आशावाद का अनुभव करेंगे जिसके प्रयोजनार्थ हमने इस समीक्षा को प्रस्तुत किया है।

कृष्णमूर्ति वी सुब्रमणियन
मुख्य आर्थिक सलाहकार
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

संकेताक्षर

3 एस.एल.एस.	3 स्तरीय न्यूनतम वर्ग	सी.आई.बी.आई.एल.	ऋण आसूचना ब्यूरो लिमिटेड
ए.ए.आई.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	(सिबिल)	
ए.सी.एन.ए.एस.	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी सलाहकार समिति	सी.आई.पी.	केन्द्रीय निर्गम मूल्य
ए.डी.	मृत्यु उपरांत	सी.के.डी.	पूर्णतः घटी कीमतें
ए.ई.ओ.	प्राधिकृत आर्थिक संचालक	सी.एम.सी.एल.	कम्प्यूटर प्रबंध निगम लिमिटेड
ए.ई.पी.	समवेत अंतिम उत्पाद	सी.पी.आई.आई.डब्ल्यू.	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक - औद्योगिक श्रमिक
ए.ई.आर.ए.	विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण	सी.पी.	वाणिज्यिक पत्र
ए.एल.एम	आस्ति-देयता प्रबंधन समस्याएं	सी.पी.एस.ई.	केन्द्रीय लोक सेवा उपक्रम
ए.एस.ई.ए.एन.	दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ	सी.आर.आई.एल.सी.	बड़े कोर्पोरेट्स पर सूचनाओं का केन्द्रीय भण्डार
(आसियान)			
ए.यू.एम.	प्रबंधाधीन परिसंपत्तियां	सी.एस.ओ.	केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन
बी.ए.सी.एल.	भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड	सी.वी.सी.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
बी.ई.सी.	व्यापक आर्थिक श्रेणियां	डी.बी.टी.	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण
बी.एल.ई.एल.(भेल)	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	डी.सी.ए.	उपभोक्ता मामले विभाग
बी.आई.एफ.आर.	औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड	डी.जी.सी.आई. एण्ड एस.	वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय
बी.आई.एम.एस.टी.ई.सी.	बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की (बिम्सटेक) खाड़ी पहल	डी.एच.एफ.एल.	दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
बी.पी.सी.एल.	भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	डी.आई.सी.जी.सी.	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
बी.एस.ई	मुंबई शेयर बाजार (बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज)	डी.आई.डी.	अंतरों-में-अंतर
बी.एस.ई.एस.	मुंबई उपनगरीय विद्युत आपूर्ति	डी.आई.आई.	घरेलू संस्थागत निवेशक
बी.टी.	ब्रिटिश टेलीकॉम	डी.आई.पी.ए.एम.(दीपम)	निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग
सी.ए.जी.	नियंत्रक और महालेखा परीक्षक	डी.पी.सी.ओ.	औषधि कीमतें नियंत्रण आदेश
सी.ए.जी.आर.	घातांकी वार्षिक वृद्धि दर	डी.आर.टी.	ऋण वसूली न्यायाधिकरण
सी.ए.आर.	पूँजी पर्याप्तता अनुपात	डी.वी.ए.	घरेलू मूल्यवर्धन
सी.बी.आई.	केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो	ई.सी.ए.	अनिवार्य वस्तु अधिनियम
सी.बी.आई.सी	केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड	ई.आई.एल.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
सी.बी.यू.	पूर्णतः निर्मित इकाई	ई-एन.ए.एम.	इलैक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार
सी.सी.ई.ए.	आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति	ई.ओ.डी.बी.	कारोबारी सुगमता
सी.सी.आई.एल.	भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड	ई.एस.ओ.पी.	कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना
सी.सी.टी.	सशर्त नकद अंतरण	ई.टी.एफ.	विनिमय व्यापारित निधि
सी.डी.	परितर्कनीय डिबेंचर	ई.यू.	यूरोपीय संघ
सी.जी.डी.	विनिवेश का कोर समूह	एफ.सी.आई.	भारतीय खाद्य निगम

एफ.डी.आई.	प्रत्यक्ष विदेशी निवेश	आई.पी.ओ.	प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव
एफ. ई.	स्थाई प्रभाव	आई.आर.डी.ए.आई.	भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण
एफ.ई.एम.ए. (फेमा)	विदेशी विनियम प्रबंधन अधिनियम	आई.एस.आई.	भारतीय सांख्यिकी संस्थान
एफ.आई.आई.	विदेशी संस्थागत निवेशक	आई.एस.डब्ल्यू.जी.एन.ए.	राष्ट्रीय लेखाओं पर अंतर-सचिवालयीय कार्यदल
एफ.टी.ए.	मुक्त व्यापार करार	आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
एफ.टी.सी.	संघीय व्यापार आयोग	आई.टी.सी.	अंतरराष्ट्रीय व्यापार केन्द्र
एफ.वाई.	वित्त वर्ष	आई.टी.डी.सी.	भारतीय पर्यटन विकास निगम
जी.डी.डी.पी.	सकल घरेलू जिला उत्पाद	जे.ए.एम.	जन धन-आधार मोबाइल
जी.डी.पी.	सकल घरेलू उत्पाद	जे.एन.पी.टी.	जवाहरलाल नेहरू पार्ट ट्रस्ट
जी.सैक	सरकारी प्रतिभूतियां	एल.डी.एम.एफ.एस.	नकदी ऋण म्यूचुअल फण्ड
जी.एस.एफ.सी.	गुजरात राज्य उर्वरक और रसायन	एम.ए.पी.ई.	अधिकतम अनुमत्य पश्च-विनिर्माण व्यय
जी.एस.टी.	वस्तु एवं सेवा कर	एम.बी.ए.	व्यवसाय प्रशासन निष्णात
जी.वी.सी.	वैश्विक मूल्य श्रंखलाएं	एम.सी.ए.	कार्पोरेट कार्य मंत्रालय
एच.सी.आई.	भारतीय होटल निगम	एम.एफ.आई.	लघु वित्त संस्थान
एच.ई.एल.पी. (हैल्प)	हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति	एम.एफ.आई.एल.	मॉडर्न फुड इंडस्ट्रिज लिमिटेड
एच.एफ.सी.	आवास वित्त कंपनी	एम.जी.एन.आर.ई.जी.ए.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
एच.एल.ए.जी.	उच्च स्तरीय सलाहकारी समूह	एम.एम.टी.सी.एल.	खनिज और धातु व्यापार निगम लिमिटेड
एच.पी.सी.एल.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	एम.एन.ई.	बहु-राष्ट्रीय उद्यम
एच.टी.	हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स	एम.पी.सी.	सीमांत उपभोग प्रवृत्ति
आई.बी.बी.आई.	भारतीय दिवालियापन एवं शोधन अक्षमता बोर्ड	एम.पी.सी.ई.	मासिक प्रति व्यक्ति व्यय
आई.बी.सी.	दिवालियापन एवं शोधन अक्षयता संहिता	एम.आर.टी.पी.	एकाधिकार और अवरोधक व्यापारिक व्यवहार
आई.बी.पी.	इंडो ब्राइट पेट्रोलियम	एम.एस.एम.ई.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
आई.सी.डी.	अंतरदेशीय कंटेनर डिपो	एम.एस.पी.	न्यूनतम समर्थन मूल्य
आई.सी.आई.सी.आई.	भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम	एम.टी.एन.एल.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
आई.डी.बी.आई.	भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	एम.यू.एल.	मारुति उद्योग लिमिटेड
आई.ई.एफ.	आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक	एन.बी.एफ.सी.	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
आई.आई.पी	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	एन.सी.डी.	अपरिवर्तनीय डिबेंचर
आई.एल.एफ.एस.	अवसंरचना लीजिंग और वित्तीय सेवाएं	एन.ई.एल.पी.	नवीन अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति
आई.एम.एफ.	अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष	एन.एफ.एस.ए.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
आई.-ओ.	आगम-निर्गम	एन.आई.टी.आई. (नीति)	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान
आई.ओ.सी.	भारतीय तेल निगम	एन.एल.ई.एम.	अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची
आई.पी.सी.एल.	भारतीय पेट्रोरसायन निगम लिमिटेड	एन.एम.डी.सी.	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

एन.एम.एस.ए.	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	आर.ई.सी.	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
एन.पी.	नेटवर्क उत्पाद	आर.ओ.ए.	आस्तियों पर परिलाभ
एन.पी.ए.	अनर्जक परिसंपत्ति	आर.ओ.ई.	इक्विटी पर परिलाभ
एन.पी.बी.	नए निजी बैंक	आर.पी.टी.	संबंधित पक्ष के लेन-देन
एन.पी.पी.ए.	राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्रधिकरण	एस.ए.एफ.टी.ए.(साफ्टा)	दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र
एन.आर.ए.आई.	भारतीय राष्ट्रीय रेस्त्रां संघ	एस.ए.आई.एल.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड
एन.एस.ओ.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय	एस.बी.आई.	भारतीय स्टेट बैंक
एन.टी.सी.	राष्ट्रीय वस्त्र निगम	एस.सी.आई.	भारतीय नौवहन निगम
ओ.ई.सी.डी.	आर्थिक सहयोग और विकास संगठन	एस.डी.जी.	संधारणीय विकास लक्ष्य
ओ.एन.जी.सी.	तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	एस.ई.बी.आई.	भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड
ओ.पी.बी.	पुराने निजी बैंक	एस.ई.सी.	प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग
ओपेक्स अनुपात	प्रचालन व्यय अनुपात	एस.एच.आर.यू.जी.	भारत के सामाजिक-आर्थिक उच्च-विभेदन ग्रामीण-शहरी भौगोलिक डाटासेट
पी. एंड सी.	भाग एवं घटक	एस.आई.सी.ए.	रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम
पी.ए.टी.	कर पश्चात लाभ	एस.आई.डी.बी.आई.	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
पी.डी.पी.एस.	भावांतर भुगतान योजना	एस.आई.टी.सी.	मानक अंतरराष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण
पी.डी.एस.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	एस.के.डी.	आधी कीमतें
पी.के.वी.वाई.	परंपरागत कृषि विकास योजना	एस.एम.ई.एस.	लघु और मध्यम आकारीय उद्यम
पी.एल.एफ.एस.	आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण	एस.एन.ए.	राष्ट्रीय लेखा प्रणाली
पी.एम.-आशा	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान	टी.-बिल	खजाना बिल
पी.एम.एफ.बी.वाई.	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना	टी.एफ.पी.	कुल घटक उत्पादकता
पी.एम.जी.एस.वाई.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	टी.पी.डी.एस.	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
पी.एम.जे.डी.वाई.	प्रधानमंत्री जन धन योजना	यू.एन.	संयुक्त राष्ट्र
पी.एम.के.एस.वाई.	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	यू.एन.आई.डी.ओ. (यूनिडो)	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन
पी.पी.एस.एस.	निजी प्रापण और स्टॉकिस्ट स्कीम	यू.एन.एस.सी.	संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग
पी.एस.बी.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	यू.एस.ए.	संयुक्त राज्य अमेरिका
पी.एस.एफ.	मूल्य स्थिरीकरण कोष	यू.एस.डी.	संयुक्त राज्य डॉलर
पी.एस.एस्फ.	मूल्य समर्थन स्कीम	डब्ल्यू.सी.ओ.	विश्व सीमा शुल्क संगठन
पी.एस.यू.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	डब्ल्यू.डी.आई.	विश्व विकास संकेतक
आर.बी.आई.	भारतीय रिजर्व बैंक	डब्ल्यू.आई.पी.ओ.	विश्व बौद्धिक संपदा संगठन
आर.सी.ई.पी.	क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी	वाई.ओ.वाई.	वर्ष-दर-वर्ष

अर्थ संपदा सृजन: विश्वास भरे अदृश्य हाथों की भूमिका

01

अध्याय

பொருளென்னும் பொய்யா விளக்கம் இருளறுக்கும்
எண்ணிய தேயத்துச் சென்று

“धन एक अमेध दीपक है जो प्रत्येक
भूमि को गति प्रदान करता है।”

-थिरुकुरल, अध्याय 76, दोहा 753

செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும்
எ.கதிற் கூரிய தில்

“धनार्जन करे - अपने दुश्मनों के गर्व को
तोड़ने के लिए कोई हथियार इससे ज्यादा कारगर नहीं है।”

-थिरुकुरल, अध्याय 76, दोहा 759

विदित आर्थिक इतिहास की तीन-चौथाई से अधिक अवधि तक भारत ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक संप्रभुता कायम रखी है। संप्रभुता अपनी दक्षता को सुस्पष्ट करती है। भारत की अधिकांश आर्थिक संप्रभुता अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था ने अर्थ सृजन के लिए विश्वास के साथ बाजार के अदृश्य हाथों (कारोबारियों) पर भरोसा जताया है। विशेषरूप से, बाजार के अदृश्य हाथ (इनविजिबल हैंड), जिसे आर्थिक लेन-देन के खुलेपन में प्रदर्शित किया जाता है, को विश्वास के साथ जोड़ा गया है जिससे नैतिक एवं दार्शनिक आयामों की मांग करके अंतर्निहित प्रेरणा को प्रोत्साहित किया जाता है।

समीक्षा में यह दर्शाया गया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद परंपरागत साक्ष्य हमारी परंपरागत विचारधारा में समर्थित आर्थिक मॉडल का समर्थन करता है। उदारीकरण के बाद भारत की जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति जी डी पी में हुई प्रचण्ड वृद्धि स्टॉक मार्केट में अर्जित होने वाले धन के अनुरूपी है। इसी प्रकार अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों के साक्ष्यों में उन असंख्य लाभों की सौदाहरण व्याख्या की गई है जो बाजार के अदृश्य हाथों को सक्षम बनाकर प्रोद्भूत किए गए हैं। निसंदेह, समीक्षा में यह स्पष्ट है कि बंद क्षेत्रों की बनिस्पत उदारीकृत क्षेत्रों में अधिक तेजी से प्रगति हुई है। वर्ष 2011-13 के दौरान हुई वित्तीय क्षेत्र की घटनाओं एवं परिणामों, जिन्होंने उनका अनुसरण किया है, में द्वितीय स्तंभ-अदृश्य हाथ के समर्थन में विश्वास की आवश्यकता, के बारे में व्याख्या की गई है।

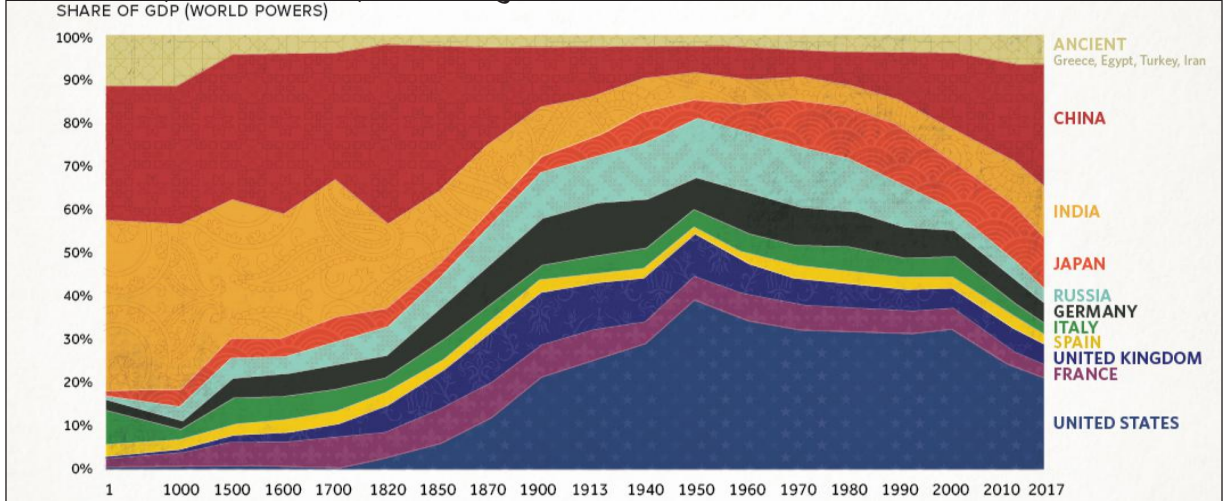
सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की भारत की महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण से बाजार के अदृश्य हाथ एवं विश्वास, जो बाजार का समर्थन करता है, दोनों को सुदृढ़ करने पर निर्भर है। बाजार के अदृश्य हाथ को (प) नए व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करके, निष्पक्ष प्रतियोगिता करके एवं व्यवसाय को सुगम करके (पप) उन नीतियों को अनावश्यक होने पर समाप्त करना जो सरकारी हस्तक्षेपों के माध्यम से बाजारों की शक्तियों को कम आंकती हैं, (पपप) रोजगार सृजन के व्यापार को सक्षम बनाकर (पअ) भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार के अनुरूप बैंकिंग क्षेत्र में प्रभावी ढंग से वृद्धि करके, बाजार अनुकूल नीतियों का प्रचार करके सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। विश्वास को सक्षम बनाने के लिए उन नीतियों, जो अंतर्निहित प्रेरणा को प्रोत्साहित करती है, को डाटा, पारदर्शिता एवं प्रभावी प्रवर्तन से अधिकृत करना।

अर्थ सृजन का महत्व

1.1 विदित आर्थिक इतिहास की तीन-चौथाई से अधिक अवधि तक भारत वैश्विक स्तर पर प्रमुख आर्थिक

शक्ति रहा है। यह देश ऐतिहासिक रूप से प्रमुख अर्थ-सृजक रहा है तथा विश्व(मैडिसन, 2007)की जीडीपी का महत्वपूर्ण अंशदाता है जैसा कि चित्र 1 दर्शाया गया है।

चित्र 1: 1एडी से 2003 एडी तक प्रमुख अर्थव्यवसाओं द्वारा विश्व की जी डी पी में योगदान



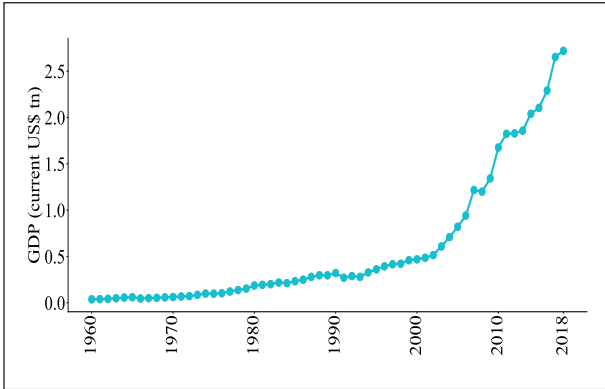
स्रोत 1: मैडीसन ए (2007) टिप्पणी: आरेख के अक्ष पर अरेखीय पैमाना है, विशेषकर 1-500 एडी के लिए, जिसमें भारत की संप्रभुता को कम आंका गया है।

1.2 इतनी लंबी अवधियों तक का आर्थिक नियंत्रण केवल अक्समात न होकर दक्षता को स्पष्ट करता है। इस संदर्भ में, समीक्षा में यह उल्लेख है कि हमारे पुरानी परंपराओं ने सदैव अर्थ-संपदा सृजन की सराहना की है। जबकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक नियमबद्ध उदाहरण है, अर्थ-संपदा सृजन एक विश्वसनीय मानव व्यवसाय है जिसको अन्य परंपरागत साहित्य के समान मान्यता दी गई है। थिरूक्कुरल, तमिल संत एवं दार्शनिक द्वारा, थिरूवल्लुर द्वारा मानवीय जीवन को समृद्ध बनाने के लिए दोहों के रूप में लिखी गई पुस्तक है, इसके अध्याय 76 के 753वें पद्य में स्वीकार किया गया है: “धन एक अमोघ दीपक है जो प्रत्येक भूमि को गति प्रदान करता है; अपने मालिक के आदेश पर अंधकार को दूर करता है।” इसी अध्ययन के दोहा 759, जो थोरुक्कुरल के दूसरा भाग है, जिसे पोरुल पाल या भौतिक संपदा का सार कहा जाता है; थिरूवल्लुर, घोषणा करते हैं: “धन अर्जित करें - अपने दुश्मनों के गर्व को तोड़ने के लिए कोई हथियार इससे ज्यादा कारगर नहीं है।” यह कहने की आवश्यकता नहीं है, थिरूक्कुरल नैतिक साधनों से धन अर्जित करने का समर्थन करता है - इस

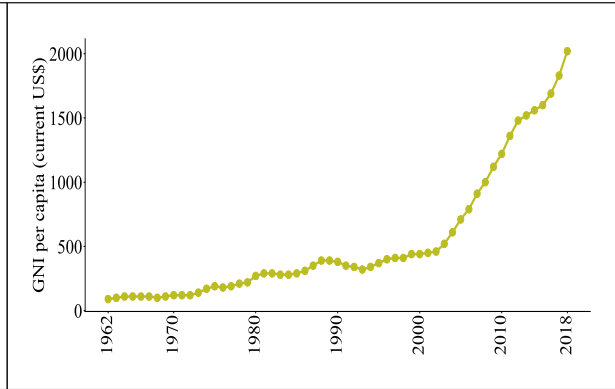
पहलू पर हमने इस अध्याय में बाद में चर्चा की गई है। इस अध्याय का दोहा 754 स्वीकार करता है: “(धन) से शुचिता एवं आनंद मिलता है, कोई क्षति पहुंचाए बिना अर्जित धन।”

1.3 अर्थ सृजन पर बल देने वाली “समृद्ध” परंपरा होने के बावजूद भारत स्वतंत्रता के बाद के अनेक दशकों तक इस मॉडल से विचलित रहा, हालांकि भारत 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद अपनी मूल अर्थचिन्तन पर लौट आया है। उदारीकरण के बाद भारत की जीडीपी (चित्र 2क) एवं प्रति व्यक्ति (चित्र 2ख) जी डी पी में हुई प्रचण्ड वृद्धि स्टॉक बाजार के धनार्जन के अनुरूप है (चित्र 3)। 1991 के बाद संसेक्स में न केवल वृद्धि हुई है, बल्कि इसमें त्वरित गति से वृद्धि हुई है। जबकि 1986 में इसकी शुरुआत से 13 वर्षों में पहले अतिरिक्त 5000 बिंदु को पार किया या है; आगे के वर्षों में प्रत्येक अतिरिक्त लक्ष्य को प्राप्त करने में लगने वाले समय में काफी कमी आई है। यह उल्लेख किया जाता है कि संसेक्स में वृद्धि आधार प्रभाव के कारण नहीं थी। वास्तव में, उच्च वृद्धि उच्च संचयी वार्षिक वृद्धि दर से प्रतिपादित होती है। (सीजीएआर)

चित्र 2क: भारत की जीडीपी (वर्तमान ट्रिलियन अमेरिका डॉलर) (1960-2018)

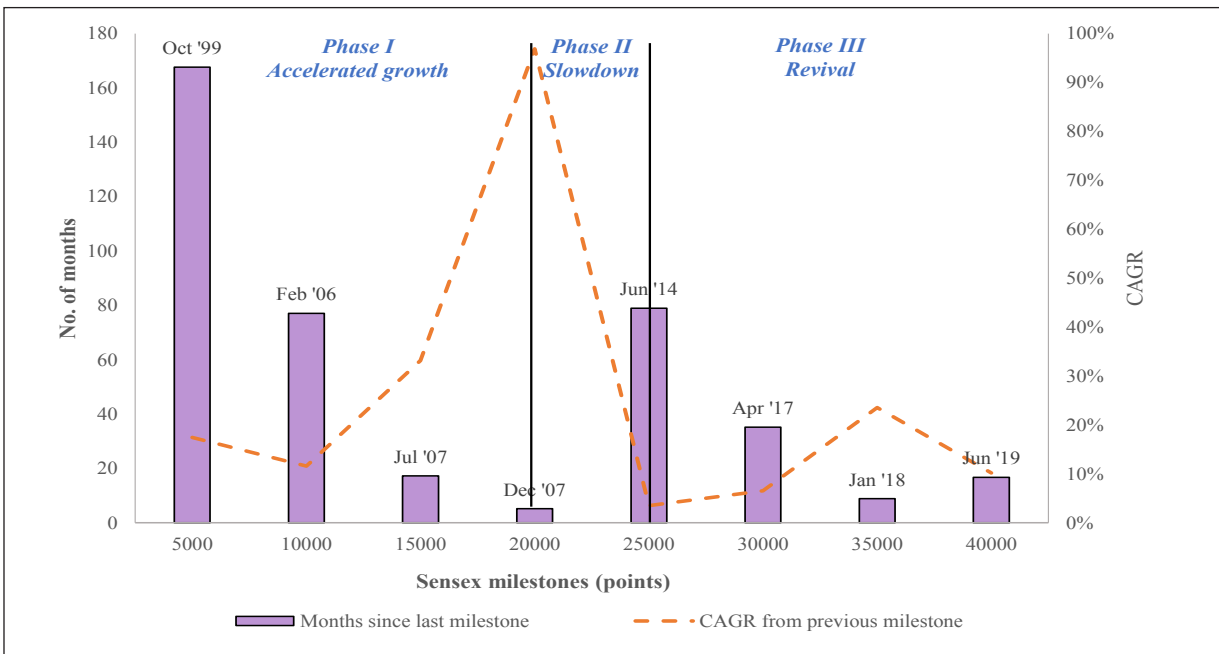


चित्र 2ख: भारत की जीडीपी एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी (1960-2018)



स्रोत: विश्व बैंक

चित्र 3: 5000 बिंदु लक्ष्य को पार करने में सेसेक्स द्वारा लिए गए अतिरिक्त महीने



स्रोत: बी एस ई

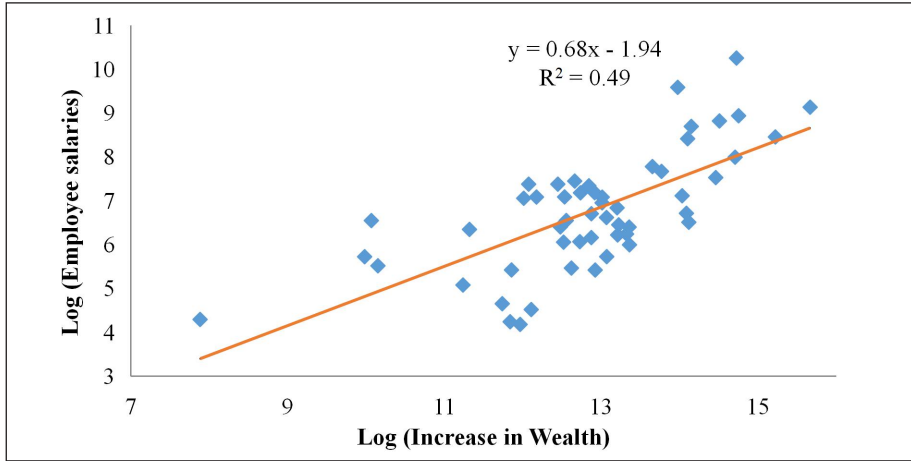
टिप्पणी: प्रत्येक लक्ष्य को पार करने में लगने वाले समय को उस बीते हुए समय से परिभाषित किया जाता है पिछले लक्ष्य पर पहली बार सेसेक्स बंद होने तथा वर्तमान लक्ष्य पर पहली बार बंद होने के बीच बीत गया। यह उल्लेख करें कि सेसेक्स बंद होने वाले मूल्यों पर आधारित होते हैं। बीते हुए समय को कैलेण्डर दिनों की संख्या के रूप में रिकार्ड किया जाता है तथा महीने में 30 दिन मानकर महीनों में बदला जाता है।

1.4 फिर भी, समाजवाद के साथ भारत के “सम्मिलन” को देखते हुए आज के परिवेश में लाभों पर बल देने के लिए यह अनिवार्य है। धन सृजन के लाभों को समझने के लिए, मार्च 2019 में फार्ब्स द्वारा देश के अनुमानित 100 धनी उद्यमियों द्वारा निर्मित कंपनियों को शामिल किया जाता है। अनेक फिल्टरों का प्रयोग करके दूषित धन वाले लोगों को अलग करने के बाद, हम एक दशक (31 मार्च 2009 से 31 मार्च 2019) में उद्यमी

के धन में हुई वृद्धि को उन लाभों से समन्वित करते हैं जो कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, सरकार आदि समेत अनेक अन्य पणधारियों द्वारा प्रोद्भूत हुए हैं। चित्र 4 में यह दर्शाया गया है कि उद्यमी द्वारा सृजित धन का उन लाभों से सुदृढ़ रूप में सहसंबंध होता है जो उद्यमी की फर्मों में कार्य करने वाले कर्मचारियों से प्रोद्भूत होते हैं।

1.5 चित्र 5 में यह दर्शाया गया है कि उद्यमी द्वारा

चित्र 4: धन अर्जन एवं कर्मचारियों को अदा किया गया वेतन



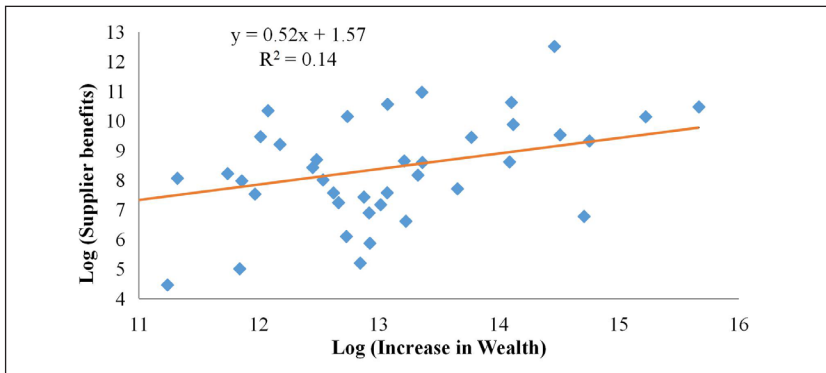
स्रोत: फोर्ब्स, सीएमआई कैपिटालाइन ब्लूमबर्ग तथा समीक्षा गणनाएँ

सृजित धन सुदृढ़ रूप से उद्यमी की फर्मों द्वारा प्रोद्भूत कच्चे माल की लागतों से सहसंबंधित होता है, जो आपूर्तिकर्ता उद्यमी की फर्मों को कच्चे माल की आपूर्ति करके कमाते हैं। चित्र 6 में यह दर्शाया गया है कि उद्यमी द्वारा सृजित धन सुदृढ़ रूप से उद्यमी की फर्मों द्व

ारा किए गए पूंजीगत व्ययों से सहसंबंधित होता है, जो उन लाभों का स्थान लेता है जो पूंजीगत उपस्कर के विनिर्माता उद्यमी की फर्मों को इन उपस्करों की आपूर्ति करने से कमाते हैं।

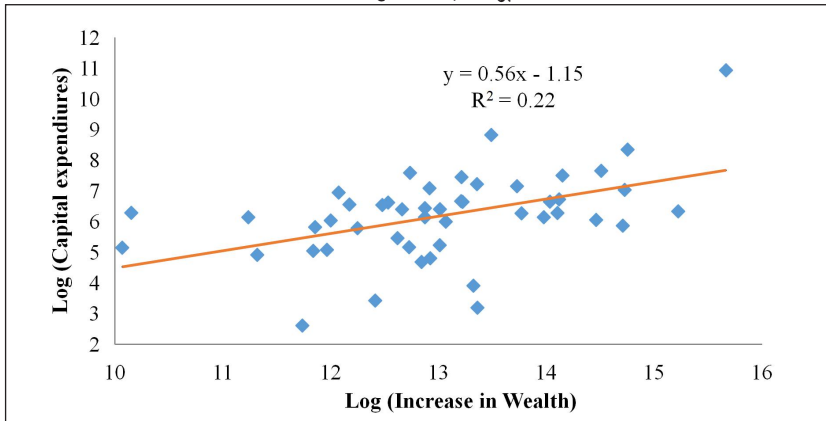
1.6 विदेशी मुद्रा में अर्जित राजस्व से समष्टि आर्थिक

चित्र 5: धन सृजन एवं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कमाए गए लाभ



स्रोत- फोर्ब्स, सीएमआई कैपिटालाइन ब्लूमबर्ग तथा समीक्षा गणनाएँ

चित्र 6: धन सृजन एवं पूंजीगत व्यय

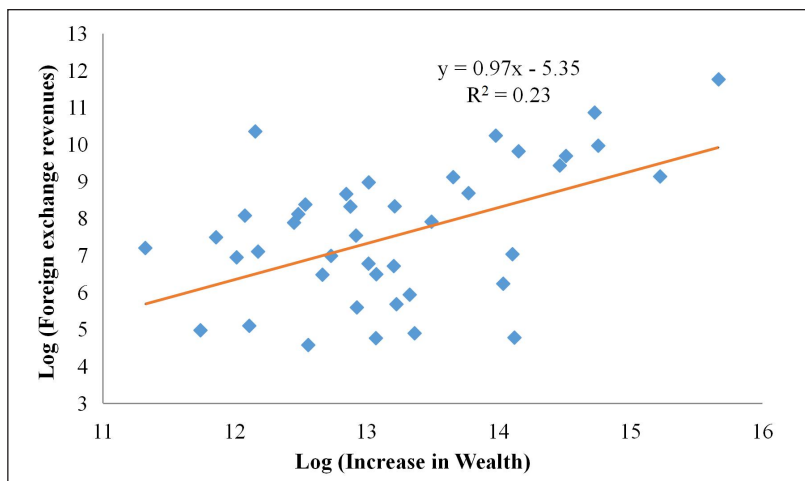


स्रोत-फोर्ब्स, सीएमआई कैपिटालाइन ब्लूमबर्ग तथा समीक्षा गणनाएँ

स्थिरता आती है जिससे देश अपने आयात का भुगतान करने में सक्षम होता है तथा चालू खाते को प्रबंधन योग्य स्तरों पर रख पाता है।

चित्र 7 में यह दर्शाया गया है कि उद्यमियों द्वारा अर्जित धन सुदृढ़ रूप से उद्यमी की फर्मों द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा राजस्व से सहसंबंध स्थापित करता है।

चित्र 7: धन सृजन एवं विदेशी मुद्रा राजस्व

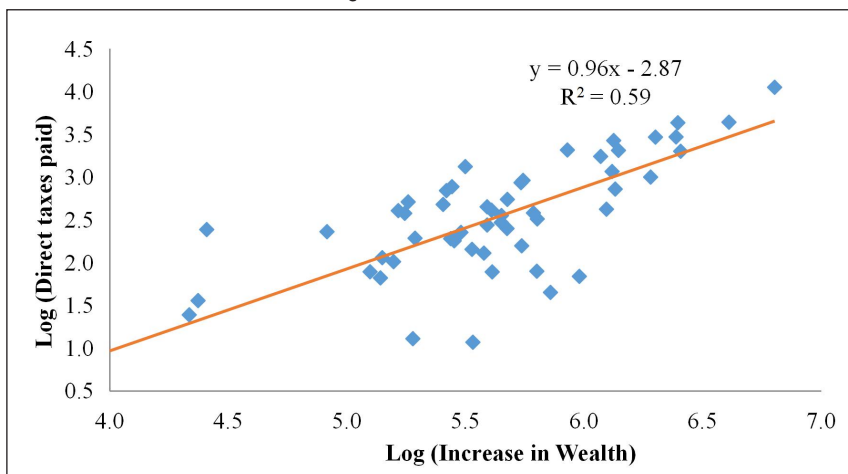


स्रोत: फोर्ब्स, सीएमआई कैपिटालाइन ब्लूमबर्ग तथा समीक्षा गणनाएँ

1.7 अंत में, चित्र 8 यह दर्शाता है कि उद्यमियों द्वारा अर्जित धन आम नागरिकों की सहायता करता है। कर राजस्व के फलस्वरूप सरकार सार्वजनिक वस्तुएं निर्मित करने एवं नागरिकों को बेहतर सेवाओं पर खर्च करती है। हम उद्यमी द्वारा निर्मित धन का प्रदत्त प्रत्यक्ष करों से समन्वय स्थापित करते हैं स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि प्रत्यक्ष कर सरकार को प्रोदभूत लाभों को कमतर आंकते हैं, चूंकि इसमें उद्यमी की फर्मों द्वारा

प्रदत्त अप्रत्यक्ष कर कर्मचारियों या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा प्रदत्त प्रत्यक्ष शामिल नहीं होते; फिर भी सरकार द्वारा कर राजस्व के खर्च के माध्यम से नागरिकों को प्रोदभूत होने वाले लाभों की अनुमान के रूप में, इस चित्र में देश के सामान्य नागरिकों को प्रोदभूत होने वाले लाभों को दर्शाया गया है। अतः प्रदत्त करों का उद्यमियों द्वारा सृजित धन के प्रबल सहसंबंध धन सृजन से समाज को होने वाले अन्य महत्वपूर्ण लाभ को प्रदर्शित करता है।

चित्र 8: अर्थ सृजन और प्रत्यक्ष कर अन्तर्वाह



स्रोत: फोर्ब्स, सीएमआई कैपिटालाइन ब्लूमबर्ग तथा समीक्षा गणनाएँ

खुली अर्थव्यवस्था के माध्यम से अर्थ सृजन

1.8 किसी भी अर्थव्यवस्था में अर्थ सृजन तब होता है जब सही नीति के विकल्प का अनुसरण किया जाता है। उदाहरण के लिए, कई उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में अर्थ-सम्पदा सृजन और आर्थिक विकास का मार्गदर्शन एडम स्मिथ के 'अदृश्य हाथ' दर्शन के अनुसार किया जाता है जिसमें स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाले कारोबारियों की भूमिका होती है। समाजवाद के प्रति झुकाव के बावजूद सहस्राब्दी के इतिहास में चार दशक की अल्पकालिक अवधि में भारत ने बाजार आदर्श को अपनाया है जो हमारी परम्परागत विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, बाजार अर्थव्यवस्था से मिलने वाले लाभों पर संदेह अभी भी बना हुआ है। यह एक घटना नहीं है क्योंकि कई दशकों से समाजवाद के प्रति हमारा 'संयोजन' ने, इस संबंध में अधिकांश भारतीयों को विश्वास दिला दिया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक ऐसे आर्थिक मॉडल पर भरोसा कर रही है जो बाजार अर्थव्यवस्था के उन अदृश्य हाथों पर विश्वास करती है जिनका देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है। किंतु यह विश्वास सच्चाई से बहुत दूर है।

1.9 वास्तव में, हमारे पारंपरिक आर्थिक दृष्टिकोण ने हमेशा बाजार को सक्षम बनाने और आर्थिक गतिविधियों में बाधाओं को दूर करने पर जोर दिया है। जहां तक आधी सदी पूर्व की बात है, स्पेंगलर (1971) ने लिखा है कि कौटिल्य ने अर्थव्यवस्था में कीमतों की भूमिका को स्वीकार किया है। कौटिल्य (पृष्ठ 149) ने प्रमाणित किया है कि "सम्पदा के मूल आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं और इनके अभाव के चलते भौतिक संकट आता है। फलदायी आर्थिक क्रियाकलाप की अनुपस्थिति में, वर्तमान की समृद्धि और भविष्य में होने वाली वृद्धि दोनों के ही विनिष्ट होने का खतरा होता है। एक राजा वांछित लक्ष्यों को हासिल कर सकता है और उत्पादक आर्थिक क्रियाकलापों द्वारा प्रचुर समृद्धि हासिल कर सकता है। (1-9)" कौटिल्य "आर्थिक क्रियाकलापों के सभी अवरोधों के निराकरण" की मांग करते हुए आर्थिक आजादी का समर्थन करता है (सिहाग, 2016)।

1.10 भारत की प्राचीन समृद्धि में अन्तरिक और भारी व्यापार एक मुख्य सहभागी थे दो मुख्य हईवे उत्तरपथा (उत्तरी सड़क) और दक्षिणपथा (दक्षिणी सड़क) और

इसकी सहभागी सड़कें जो उपमहाद्वीप का जोड़ती हैं हालांकि, भारत के लंबे कोसिल लाइन द्वीपो ने इजिप्ट, रोम, ग्रीस, ईरान और पश्चिम अरब, और चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया से पूर्वी तक (सान्यल 2016) के साथ व्यापार किया। इस व्यापार में अधिकतर बड़े कोरपेरेट मंडली जोकि आजकी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और जिनको मंदिर बैंको से निधि बद्ध किया गया था। इसलिए व्यवसाय और समृद्धि का अनुसरण भारत की सभ्यता का एक अन्तर भाग है।

1.11 कुछ समय पूर्व मैडिसन (2007) विश्लेषण करता है, कि भारत में एक "पणधारी-मॉडल अस्तित्व में है जिसकी "अर्थशास्त्र" में पुष्टि की गई है जिसमें, उद्यमियों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं की समृद्धि में भागीदारी होती है (देवधर, 2018)। अर्थशास्त्र आर्थिक नीति पर एक ग्रंथ के तौर पर, 12वीं शताब्दी तक अर्थव्यवस्था के कामकाज पर गहरा प्रभाव डालता रहा है (ओलिवेल, 2013)। जिसके परिणामस्वरूप, भारत की अधिकांश आर्थिक प्रभुत्व अवधि के दौरान में राज्य के दृश्य हाथों की अपेक्षा बाजार अदृश्य हाथों पर विश्वास जताया गया है।

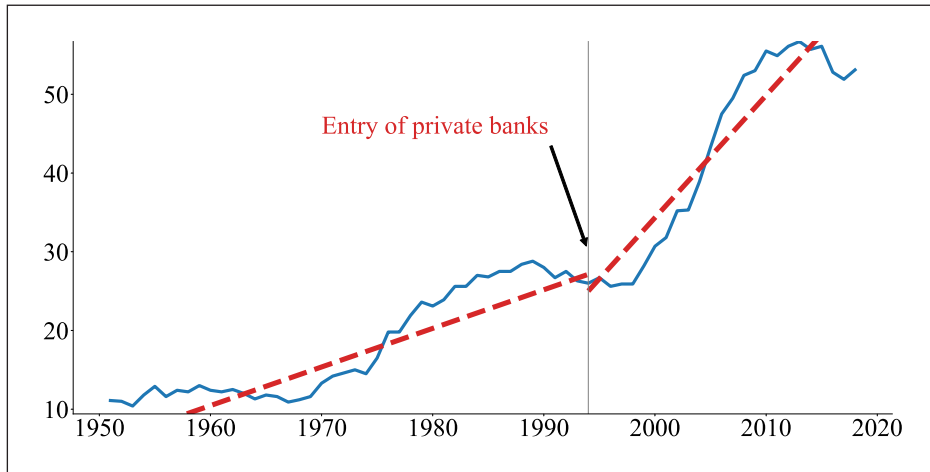
1.12 चूंकि धनार्जन विशेष प्रयास द्वारा ही किया जाता है, आर्थिक समीक्षा 2019-20 की व्यापक विषय-वस्तु धनार्जन और नीतिगत विकल्प हैं जो इसे सक्षम बनाते हैं। इस समीक्षा के भूल में, नीतियां संसाधन व अवरोधों के समूह के अंतर्गत अधिकतम सामाजिक कल्याण की अपेक्षा करती हैं। संसाधन अवरोध नीति निर्माताओं को दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विवश करते हैं, जो दिए गए संसाधनों यथा भूमि मानव संसाधनों और पूंजी, या कम संसाधन उपयोग द्वारा वैसी ही निर्गत (आउटपुट) का उत्पादन करने पर बल देते हैं।

1.13 1991 के बाद के साक्ष्यों से इस तथ्य का पता चलता है कि आर्थिक उदारीकरण का समग्रतौर पर और सेक्टरों के अंदर संपदा संवर्धन पर व्यापक प्रभाव रहा था। वास्तव में, नीचे प्रस्तुत किए गए साक्ष्य इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि जिन सेक्टरों को उदारीकृत किया गया था, उनका विकास उदारीकरण से वंचित रहे सेक्टरों की अपेक्षा काफी तेजी से हुआ। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बाजार अर्थव्यवस्था इस सिद्धांत पर आधारित होती है कि

संसाधनों का इष्टतम आबंटन तब होता है जब नागरिक उन उत्पादों या सेवाओं का स्वतंत्र रूप से चयन करने में सक्षम होते हैं जो वे चाहते हैं। इस तथ्य को दर्शाता है कि निजी क्षेत्र के बैंकों को दिए गए लाइसेंस के माध्यम से इस क्षेत्र को प्रतिस्पर्धा के लिए खोलने के बाद बैंकिंग क्षेत्र में ऋण का उच्च दर पर विस्तार हुआ है। जैसे कि प्रतिस्पर्धा ने नागरिकों के लिए उपलब्ध बैंकिंग विकल्पों का विस्तार किया है, इस क्षेत्र ने सुदृढ़ संवृद्धि का अनुभव किया है। चित्र 10 वर्ष 2003 में प्रतिस्पर्धा के द्वार खोलने के बाद म्यूचुअल निधि सेक्टर में ऐसे ही प्रभावों को दर्शाता है। चित्र 11-14 में, हम खुले क्षेत्र में वृद्धि की समीक्षा करेंगे, जिसमें इसे

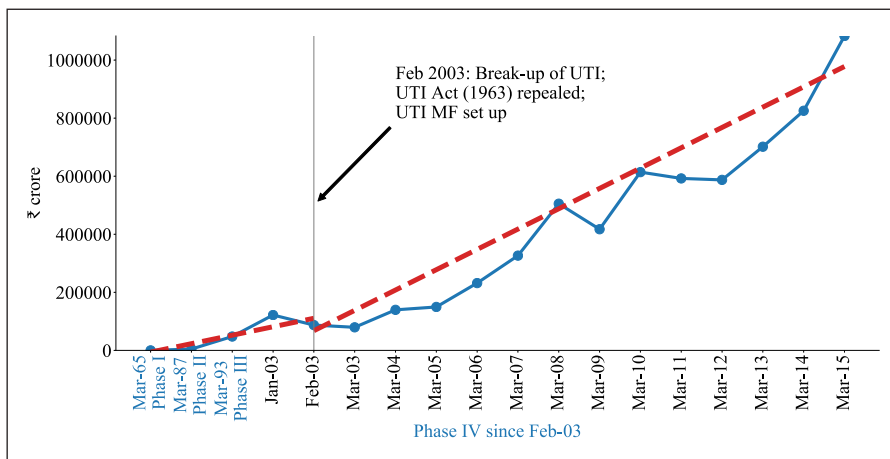
उस क्षेत्र के तौर पर निरूपित किया गया है, जहां पर नागरिक विभिन्न उत्पादकर्ताओं के मध्य किसी का चयन कर सकते हैं, जबकि संवृत सेक्टर के मामले में नागरिक किसी ऐसे विकल्प का चयन नहीं कर सकते। चित्र 11 खुले सेक्टरों (लघु पत्तन) बनाम प्रतिस्पर्धा से वंचित सेक्टर (बड़े पत्तन) में कार्गो प्रमात्रा में संवृद्धि को दर्शाता है। चित्र 12 सीमेंट और इस्पात जैसे खुले सेक्टरों बनाम प्रतिस्पर्धा से वंचित बंद सेक्टर, यथा, कोयले की संवृद्धि को दर्शाता है। चित्र 13 और 14 प्रतिस्पर्धी सेक्टर (सड़क) की प्रतिस्पर्धा से वंचित सेक्टर (रेलवे) के साथ तुलना किये जाने पर संवृद्धि को दर्शाते हैं। चित्र 11-14 तक का अवलोकन करने पर, हमें देखने

चित्र 9: निजी क्षेत्र के बैंकों के आगमन के बाद जी डी पी में घरेलू क्रेडिट में संवृद्धि



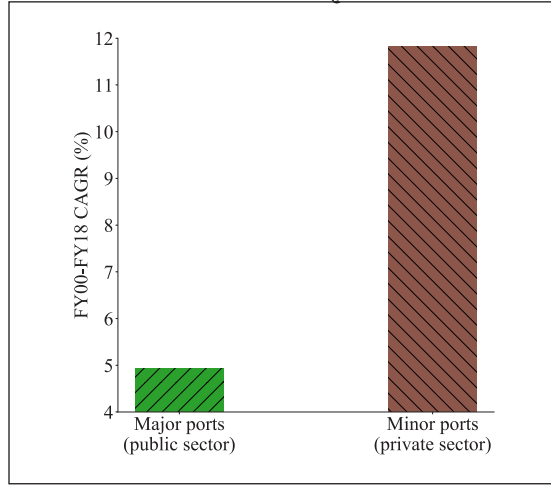
स्रोत:- विश्व बैंक डब्ल्यू डी आई तथा समीक्षा गणना

चित्र 10: 2003 में 'ओपनिंग-अप' के बाद म्यूचुअल फंड सेक्टर में वृद्धि

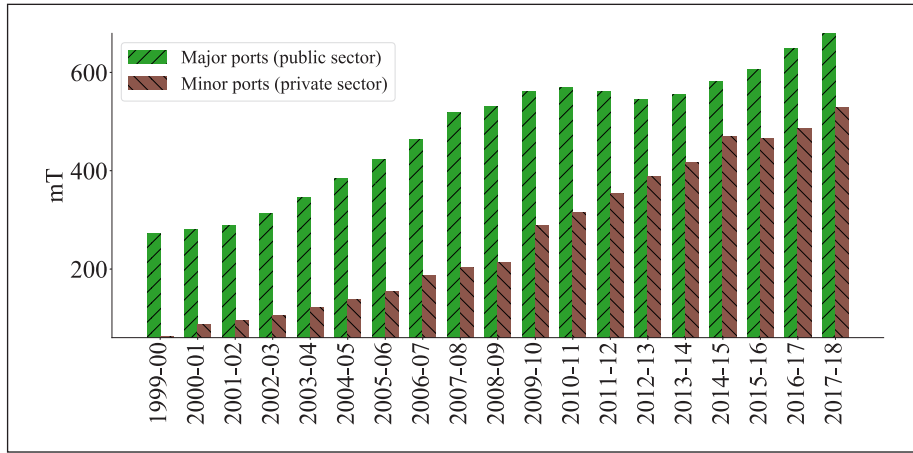


स्रोत:- एमएफआई आकड़े तथा समीक्षा गणना

चित्र 11: पत्तन सेक्टर में वृद्धि: अनावृत (लघु पत्तन) बनाम संवृत (मुख्य पत्तन)
संचयी वार्षिक वृद्धि दर

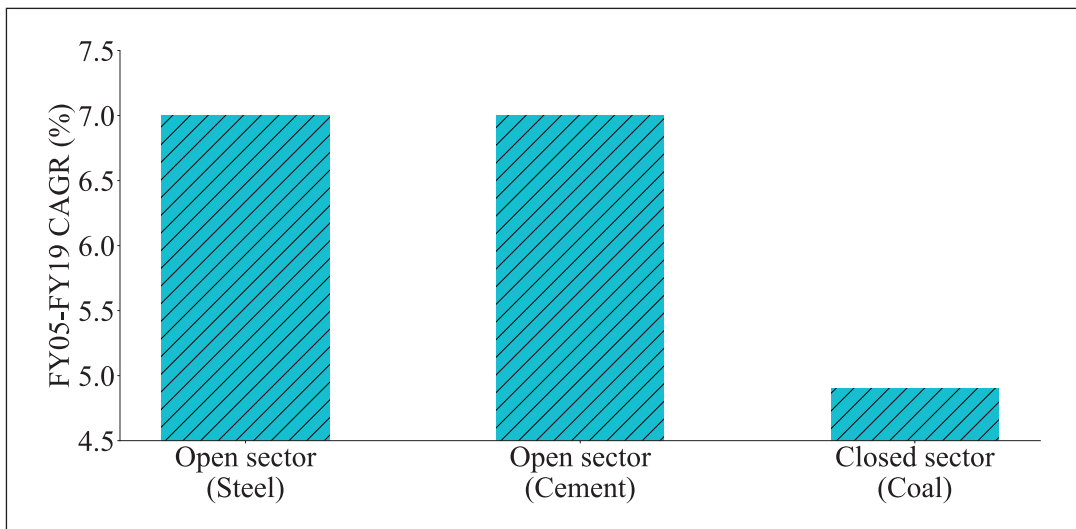


पत्तनों में कार्गो की प्रमात्रा



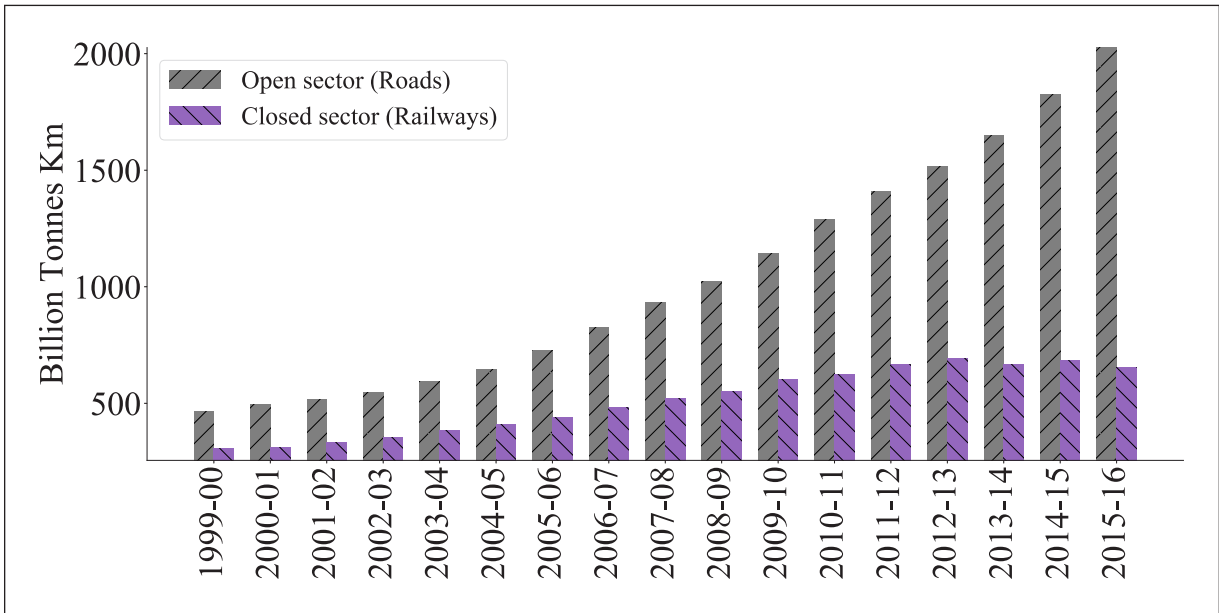
स्रोत:- सीएमआई कम्पनी वार्षिक रिपोर्टे तथा समीक्षा गणनाए

चित्र 12: खुले सेक्टर (इस्पात और सीमेंट) बनाम बंद सेक्टर में वार्षिक वृद्धि दर कोयला



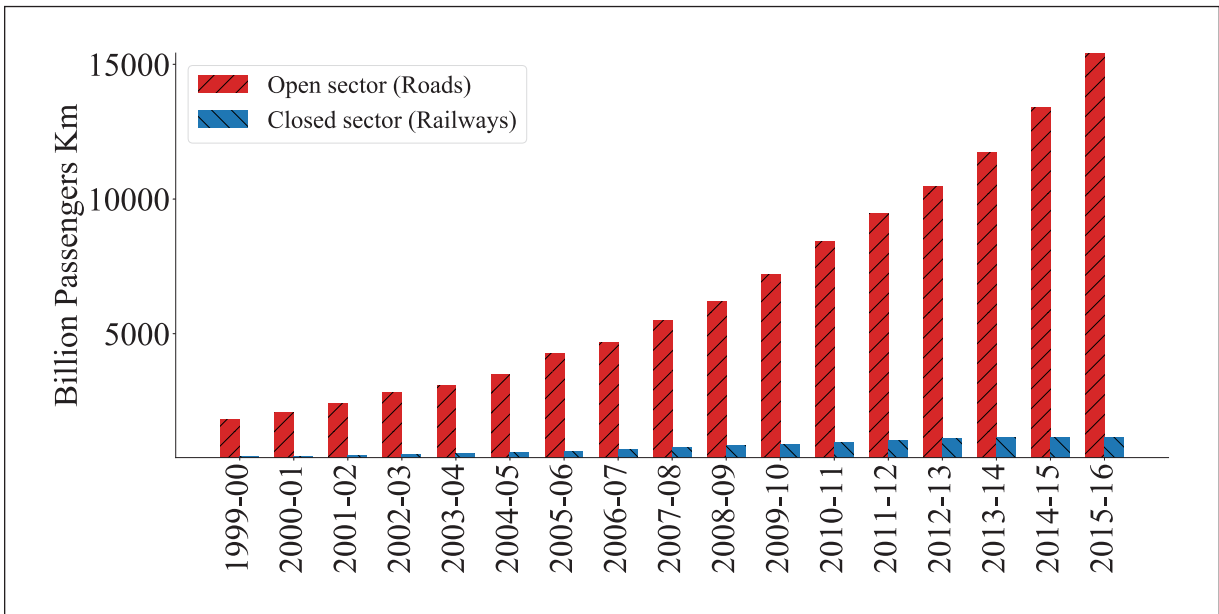
स्रोत:- सीएमआई कम्पनी वार्षिक रिपोर्टे तथा समीक्षा गणनाए

चित्र 13: खुले क्षेत्रों में मालदुलाई यातायात में वृद्धि (सड़के) और बन्द क्षेत्र (रेलवे)



स्रोत:- सीएमआईई कम्पनी वार्षिक रिपोर्टे तथा समीक्षा गणनाए

चित्र 14: खुले क्षेत्रों में यात्री यातायात में वृद्धि (सड़के) और बन्द क्षेत्र (रेलवे)



स्रोत:- सीएमआईई कम्पनी वार्षिक रिपोर्टे तथा समीक्षा गणनाए

को मिलता है कि प्रतिस्पर्धा से वंचित क्षेत्र की अपेक्षा प्रतिस्पर्धा वाले क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण संवृद्धि दर्ज की गई है। 9-14 तक के चित्र इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में नागरिकों को आर्थिक विकल्प के चयन में सक्षम बनाने के सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डालता है।

संपत्ति सृजन के लिए उपकरण

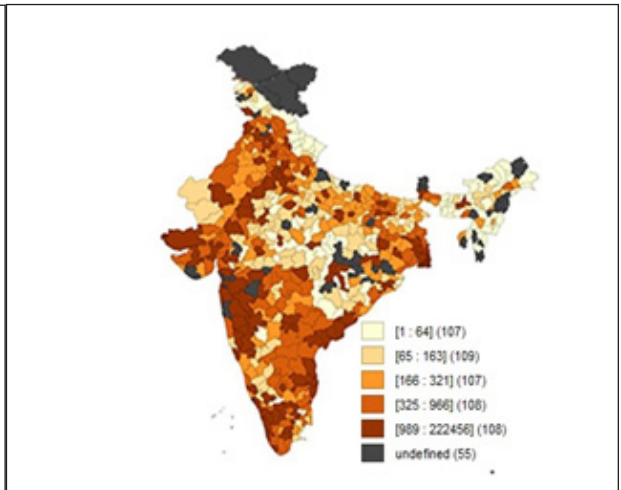
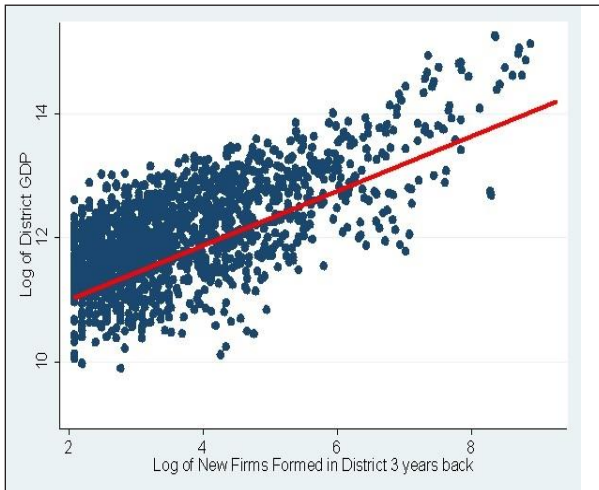
1.14 जैसाकि उपर्युक्त तर्क दिया गया है संपत्ति सृजन के लिए दक्षता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। दक्षता का प्रमुख आयाम अवसरों से संबंधित है। नये प्रवेशकों के लिए समान अवसर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि

समीक्षा के अध्याय दो में (उद्यमिता एवं निचले स्तर पर संपत्ति सृजन), जिले में नई कंपनियों में 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी सकल घरेलू जिला उत्पाद (जीडीडीपी) में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि करती है। यह प्रभाव चित्र 15 में दिखाए गए जिलों तथा चित्र 16 में दिखाए गए प्रदेशों दोनों में सतत रूप से फलीभूत होता है। यह प्रभाव जिला स्तरीय जीडीपी पर नई कंपनियों के सृजन को प्रदर्शित करता है जिससे कि निचले स्तर की उद्यमिता न केवल आवश्यकता द्वारा प्रेरित होती है। चित्र 15ख

वास्तव में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है कि यद्यपि प्रायदीपिय राज्य नई कंपनियों के प्रवेश में प्रभुत्व रखता है, उद्यमिता पूरे भारत वर्ष में बिखरी हुई है तथा यह न केवल कुछ महानगरों तक सीमित है। यह अध्याय विश्व बैंक के उद्यमिता आंकड़ों से आंकड़ों का उपयोग करते हुए दर्शाता है कि नई कंपनियों का सृजन 2014 से नाटकीय रूप से बढ़ा है। हालांकि नई कंपनियों की संख्या 2006-2014 से 3.8 प्रतिशत की संकलित वार्षिक वृद्धि दर पर बढ़ी थी, 2014-2018 तक वृद्धि दर

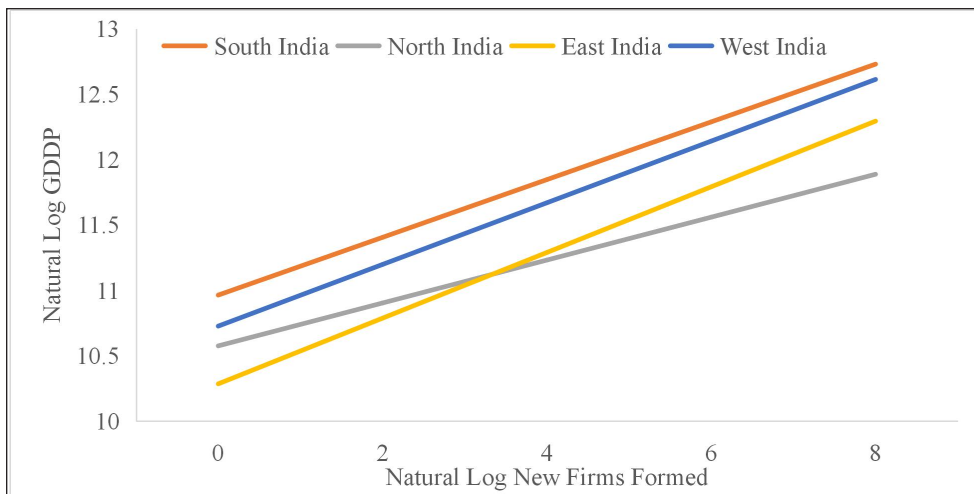
चित्र 15क उद्यमी क्रियाकलनों का जीडीडीपी पर प्रभाव का आकलन।

चित्र 15ख नये जिलों के अन्तर्गत नई फर्मों का वितरण



स्रोत: कोपिरेट मामला मंत्रालय (एमसीए) 21 डाटा बेस, सीईआईसी इन्डिया प्रमियम

चित्र 16 तीन वर्षों के पश्चात जिला स्तर पर जीडीपी का नए फर्मों के संरचना का प्रभाव



स्रोत: कोपिरेट मामला मंत्रालय (एमसीए) 21 डाटा बेस, सीईआईसी इन्डिया प्रमियम

12.2 प्रतिशत रही है। परिणामस्वरूप 2014 में लगभग 70,000 हजार नई कंपनियों सृजित हुई है, 2018 में लगभग 1,24,000 नई कंपनियों की लगभग 80 प्रतिशत संख्या में बढ़ी है। उद्यमिता में नये प्रवेशकों के लिए समान अवसर दक्ष संसाधन आवंटन एवं उपयोगीकरण, रोजगार वृद्धि को सुकर बनाने, अधिक उत्पाद विविधता के जरिए व्यापार वृद्धि एवं उपभोक्ता अधिशेष प्रोत्साहित करने में समर्थित करता है तथा आर्थिक गतिविधियों की संपूर्ण सीमा को बढ़ाता है।

1.15 अवसरों का प्रमुख आयाम नये प्रवेश को एवं पदस्थ के बीच अवसरों से संबंधित है। जबकि पदस्थ का शक्तिशाली, प्रभावशील तथा ऐसी आवाज होना जिसे शक्ति के गलियारे में सुना जाता है का होना संभावित है, नये प्रवेशक के लिए इन लाभों को पाने की संभावना नहीं है। तब भी नये प्रवेशक नये विचार तथा नवोन्मेष लाते हैं जो कि न केवल अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष रूप से मदद करते हैं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से पदस्थ को उनके नीचे रखने के द्वारा अर्थव्यवस्था को मदद करते हैं। अतः आर्थिक अवसरों को अर्थव्यवस्था किस हद तक उचित प्रतियोगिता को समर्थ बनाती है के रूप में परिभाषित किया जाता है जो कि “कारोबारानुकूल” अर्थव्यवस्था को संबोधित करती है। यह शक्ति के गलियारे में के निकट तथा उनके पदस्थ से रेन्ट लेने वाले में पदस्थ के प्रभाव की तुलना में जो कि “प्रोक्रोनी” अर्थव्यवस्था का परिचायक है। प्रत्येक आर्थिक भागीदार के लिए उचित प्रतियोगिता बनाये ऐसी अर्थव्यवस्था को कारोबारानुकूल शब्द के रूप में जोड़ने के लिए इस टेक्सोनॉमी में महत्वपूर्ण है। पृष्ठभूमि को देखते हुए क्या नये प्रवेशकों को पदस्थों जैसी धन सृजन की समान अवसर है? अध्याय तीन (प्रोबिजिनिस विरुद्ध प्रोक्रोनी) साक्ष्य प्रस्तुत करता है। कि भारतीय अर्थव्यवस्था संपत्ति सृजन के लिए स्थापित निवेशकों की तुलना में नये प्रवेशकों के लिए अवसरों के संबंध में कैसे दक्ष रही है। 1991 से आर्थिक घटनाएं मजबूत साक्ष्य प्रदान करती हैं जोकि संपत्ति सृजन करने के लिए प्रतियोगितात्मक बाजार की शक्तियों को खोलने के लिए नये प्रवेशको हेतु सामान अवसर प्रदान करके सहायता करती है। भारत की पांच ट्रिलियन बनने की अभिलाषा प्रो-बिजनेस नीतियों को प्रोत्साहित करने पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करती है। समीक्षा यह अध्ययन करती है

कि स्थायी प्रोक्रोनीतंत्र की अपेक्षा स्वस्थ प्रोबिजनेसतंत्र अधिक धन सृजित करने के द्वारा मंथन बनाता है। ध्यान दें कि समीक्षा दो प्राणालियों की तुलना करती है तर्क किसी व्यक्ति अथवा निकाय को निर्देशित नहीं किया गया है।

1.16 बाजार अर्थ व्यवस्था में बढ़ना हुआ अर्थ संपदा सभी नागरिकों के लिए कल्याणकारी है। समीक्षा क 1 अध्याय उदारीकरण के पश्चात अर्थव्यवस्था में अर्थसंपदा का प्रमाण प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए सेन्सेक्स 1978 की 100 बेस पाइन्ड्स से 1999 में पहली बार 5,000 मार्क पहुँचा। 1991 में जब भारत एक शसित अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थ व्यवस्था में बदली तो यह 1000 प्वाइंस से कम था। तब से जैसे रेखाचित्र में दर्शाया गया है, बाजार रेखाचित्र में दर्शाया गया है, बाजार पूंजीकरण आधारित सूचकांक में अभूतपूर्व विकास देखा गया है। 1999 के बाद के इस अप्रत्याशित विकास 3 चरणों में बांटा गया है। 1999 से 2007 तक के चरण I सेन्सेक्स वृद्धि में गति दिखाई दी, जिसमें हर अगले 5000 पाइंट को हासिल करने में पहले से कम से कम समय लगा। 2007 से 2014 तक के चरण II में सूचकांक वृद्धि में मंदी देखी गई। चरण III की शुरुआत 2014 हुई, जिसमें संरचनात्मक सुधारों की दिशा में पुर्नउद्धार देखा गया। खस तौर से, इस चरण में सेन्सेक्स दो साल में 30,000 मार्क से 40,000 मार्क तक की छलॉक लगाई। जैसे कि रेखाचित्र 3 में सीएजीआर स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं, यह फुर्ती बेस इफेक्ट के कारण नहीं हुआ है। असल में उच्चतम सीएजीआर के कारण ही उच्चतम वृद्धि उत्पन्न हुई है। इस तरह से 1991 से अर्थव्यवस्थाओं में अप्रत्याशित धन सृजन हो गया है।

1.17 चयन करने की आजादी मार्केट के जरिए अर्थव्यवस्था में उत्तम अभिव्यक्ति है जहां खरीददार एवं विक्रेता दोनों साथ आते हैं तथा वे कीमततंत्र के जरिए मोलभाव करते हैं। जहां कमी होती है तथा न्यून संसाधन तथा अन्य के उपयोग के बीच चयन किया जाना चाहिए, बाजार प्रतियोगी अवसरों के बीच चयन का समाधान करने के लिए उत्तमतंत्र प्रदान करती है। यह सिद्धांत बाजार अर्थव्यवस्था का आधार है। यह आदेश एवं नियंत्रण उपागम दावा करता है कि वस्तुओं की कीमत विनियमित की जानी चाहिए। हमारी अर्थव्यवस्था में अब तक उदारीकरण पूर्व युग के कुछ अवशेष हैं। समीक्षा

अध्याय चार (उपेक्षित बाजार जब सरकार का हस्तक्षेप उसकी मदद करने से ज्यादा आघात पहुंचाता है) में साक्ष्य प्रदान करता है कि सरकार के हस्तक्षेप बाजार में दक्ष प्रचालन में मदद करने की अपेक्षा इसे आघात पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग में सरकार ने अविनियमित फार्मूलेशन की अपेक्षा विनियमित फार्मूलेशन की कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा अविनियमित फार्मूलेशन की आपूर्ति विनियमित फार्मूलेशन की अपेक्षा अधिक है। सरकारी हस्तक्षेप अधिकतर गैर-इरादतन परिणाम जैसे कि कीमत बढ़ोत्तरी करता है जब इसे अविनियमित फार्मूलेशन की अपेक्षा बाजार में तुलना की जाती है। नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न जहां कीमतें सरकार द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था में निर्धारित की जाती हैं, वस्तुओं की कीमतें आपूर्ति एवं मांग बलों की परस्पर क्रिया द्वारा निर्धारित होता है। समीक्षा बाजार विस्तार संपत्ति सृजन के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का स्थिर होना पाती है।

1.18 उनके ईष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए संसाधन के आवंटन से संबंधित दक्षता के अन्य आयाम भी हैं। चूंकि संसाधन सीमित है राष्ट्र को चयन करना होता है। उदाहरणार्थ जनसांख्यिकीय लाभ को देखते हुए, क्या भारत को श्रम गहन उद्योगों अथवा पूंजी गहन उद्योगों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए? अध्याय पांच (नौकरियों का सृजन एवं नेटवर्क उत्पाद में निर्यातकों को विशेषता देने के द्वारा विकास) इस प्रश्न का जबाब देता है कि हमारी निर्यात नीतियों के जरिए करोड़ों नौकरियां सृजित करने के लिए एक स्पष्ट नीति निर्धारित करने की जरूरत है। समीक्षा “मेक इन इंडिया में विश्व के लिए असेंमलिंग इंडिया के एकीकरण द्वारा भारत 2025 तक अच्छी तरह से भुगतान वाली 4 करोड़ नौकरियों तथा 2030 तक 8 करोड़ नौकरियों को सृजित कर सकता है, यह पाता है। हमारी व्यापार नीति समर्थकारी होनी चाहिए क्योंकि निर्यात में वृद्धि भारत में नौकरियों के सृजन के लिए एक आवश्यक रास्ता प्रदान करती है।

1.19 जैसेकि अध्याय-6 (भारत में कारोबार करने की सुगमता को सुधारना) में चर्चा की गई है, कारोबार करने की सुगमता सुधारों से विगत पांच वर्षों में निरंतर बढ़ गई है जिसने अधिक आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान की है। भारत ने 2014 में 142 से 2019 में 63 तक विश्व बैंक

की कारोबार करने की रैंकिंग में लम्बी छलांग लगाई है। द डुइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट ने भारत को दस अर्थव्यवस्थाओं में से एक रूप में पहचाना है जिसने की सबसे ज्यादा सुधार किया है।

1.20 अब भी, कारोबार करने को सुगम बनाने में सुधारों की गति को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है ताकि भारत मैट्रिक पर शीर्ष 50 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो सके। भारत निरंतर कुछ मानदण्डों, जैसाकि कारोबार शुरू करने की आसानी, संपत्तियों का पंजीकरण, करने, कर अदा करने; तथा संविदाओं को लागू करने में पीछे रहता है। अध्याय 6 विश्व बैंक के सर्वेक्षण द्वारा लिए गए उपागम के बाहर भारत के कार्यनिष्पादन को अवरूद्ध करने वाले महत्वपूर्ण मामलों को चिन्हित करता है। यह निर्यात एवं आयात आपूर्ति में विशिष्ट बिन्दुओं को भी प्रदर्शित करता है जो कि असाधारण देरी एवं व्यवधानों को महसूस करता है। यद्यपि, प्राथमिक आर्थिक प्रचालक योजना ने पंजीकृत इलेक्ट्रॉनिकस निर्यातों/आयातों के लिए प्रक्रिया को आसान किया है। यहा और अधिक काम किया जाना है। कारोबार विनियमों को आसान बनाने के लिए समग्र मूल्यांकन एवं सतत प्रयास कारोबार को पनपने के लिए परिवेश बनाना का प्रमुख संरचनात्मक सुधार होगा जोकि भारत को 8-10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की सतत दर से बढ़ने में समर्थ बनाएगा। इसमें प्रतिक्रिया चक्र, निगरानी एवं निरंतर समायोजन के उपागम की आवश्यकता है।

1.21 अर्थव्यवस्था में दक्षता बढ़ाने के लिए एक दक्ष वित्तीय क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक रूप से, विगत 50 वर्षों में, शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं को उनके बैंकों द्वारा हमेशा सामर्थ्यपूर्ण सहायता मिलती रही है। यू.एस को सुपरपावर अर्थव्यवस्था बनाने में यू.एस बैंकिंग तंत्र की सहायता अच्छी तरह से जानी जाती है। इसी तरह अस्सी के दशक में जापानी अर्थव्यवस्था के अच्छे दिनों के दौरान जापान के पास तब के शीर्ष 25 बड़े बैंकों में से 15 बैंक थे। हालही के समय में, जैसे चीन अर्थव्यवस्था सुपरपावर के रूप में उभरा है, यह इसके बैंकों द्वारा निपुणतापूर्वक समर्थित रहा है विश्व के चार सबसे बड़े बैंक चीन के बैंक हैं। विश्व का सबसे बड़ा बैंक चीन औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बैंक लगभग 5वे अथवा 6वे स्थान के बड़े बैंकों से दो गुणा बड़ा है जो कि क्रमशः जापानी एवं अमरीकी बैंक हैं।

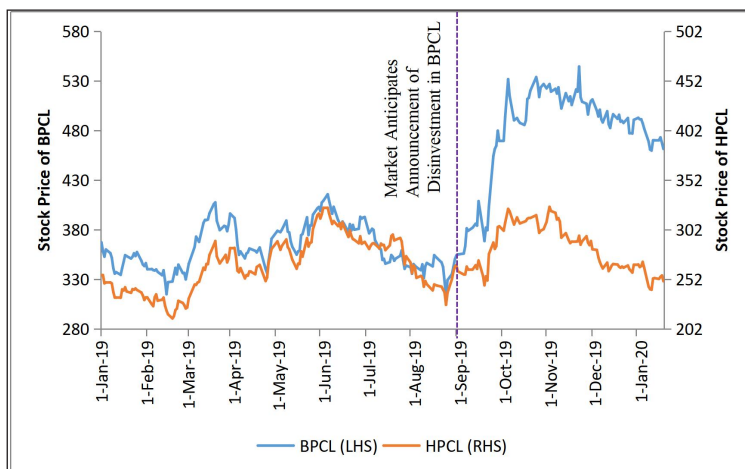
1.22 अध्याय 7 (बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्णजयंती: टेंकिंग स्टॉक) दिखाता है कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र इसकी अर्थव्यवस्था के आकार को देखते हुए बेहद गैर तौर पर अवकिसित है। उदाहरणार्थ; भारत के पास सिर्फ एक ही बैंक है जो कि वैश्विक शीर्ष 100 में है उन देशों के समान ही जो कि अपने आकार का भिन्न है: फिनलैंड (लगभग 1/11वाँ), डेनमार्क (लगभग 1/8वाँ) नार्वे (1/7वाँ) आस्ट्रिया (लगभग 1/7वाँ) एवं बेल्जियम (लगभग 1/6वाँ)। स्वीडन (1/6वाँ) तथा सिंगापुर (1/8वाँ) जैसे देशों से भारत का आकार वैश्विक बैंको की संख्या जैसाकि, भारत के पास क्षमता है, से तीन गुना है। बड़ी अर्थव्यवस्था को इसके विकास करने में सहायता करने के लिए दक्ष बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता है। चूकि भारतीय बैंकिंग प्रणाली में पीएसबी का बाजार हिस्सा 70 प्रतिशत है, भारतीय अर्थव्यवस्था को सहायता करने की जिम्मेदारी तथा इसके आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना भी इन पर निर्भर करता है। अब भी, प्रत्येक कार्यनिष्पादन पर पीएसबी अपने सहकर्मी समूह की तुलना में अप्रभावी है। अध्याय कुछ हल सुझाता है जो कि पीएसबी को अधिक दक्ष बना सकते हैं ताकि ये 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए संपत्ति सृजन में राष्ट्र को सही रूप से सहायता करने में सक्षम बन सकें।

1.23 छाया बैंकिंग क्षेत्र जो कि उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है, वित्तीय अर्न्तमध्यस्थता के महत्वपूर्ण अनुपात हेतु उत्तरदायी है विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां परंपरागत बैंकिंग क्षेत्र घुसने में सक्षम नहीं है। अध्याय 8 (एनबीएफसी

क्षेत्र में वित्तीय कमजोरी) छाया बैंकिंग क्षेत्र के स्वास्थ्य जिसके द्वारा वित्तीय क्षेत्र में निगरानी तंत्र जोखिम का पता लगाने के लिए उपचार का निर्माण करता है।

1.24 अध्याय 9 (निजीकरण एवं संपत्ति सृजन) उल्लेखनीय दक्षता लाभों जिनकी प्राप्ति सरकार की बजाए निजी क्षेत्र द्वारा कारोबार से होती है, को दिखाने के लिए निजीकरण के पश्चात् केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के प्रदर्शन में बदलाव का उपयोग करता है। चित्र 17 भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के निजीकरण की घोषणा का उपयोग करते हुए इसके सहकर्मी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की तुलना को सम्मोहक चित्रण प्रदान करता है। हम सितंबर 2019 के बाद से जब से बीपीसीएल के निजीकरण का समाचार आया था तब से बीपीसीएल एवं एचपीसीएल के शेयरों की कीमतों में अंतर पर ध्यान केन्द्रित करते हैं। बीपीसीएल एवं एचपीसीएलकी तुलना यह सुनिश्चित करती है कि स्टॉक मार्केट में अथवा तेल उद्योगों में किन्हीं वृहत गतिविधियों का प्रभाव 'नेट आऊट' हो जाता है। हम चित्र 17 में देखते हैं कि एचपीसीएल एवं बीपीसीएल की स्टॉक कीमत सितंबर तक समसामयिक रूप से आगे बढ़ी थी। तथापि, इनके स्टॉक की कीमतों में विचलन बीपीसीएल के विनिवेश की घोषणा के पश्चात् शुरू हुआ। बीपीसीएल की स्टॉक कीमतों में बढ़ोत्तरी जब हम समान अवधि में एचपीसीएल की कीमतों में तुलना करते हैं तब लगभग 33000 करोड़

Figure 17: Comparison of Stock Prices of BPCL and HPCL



Source: BSE, Survey Calculations

¹ <https://www.livemint.com/market/mark-to-market/why-privatization-of-bpcl-will-be-a-good-thing-for-all-stakeholders-1568309050726.html>

की बीपीसीएल की शेयर धारिता ईक्विटी के मूल्य में बढ़ोत्तरी में परिणत होता है

चूँकि इस अवधि के दौरान कर्मचारियों एवं उधारदाताओं सहित अन्य स्टॉकधारकों के मूल्य में कोई दर्ज बदलाव न था, यह 33000 करोड़ की बढ़ोतरी बीपीसीएल के संपूर्ण कंपनी मूल्य में स्पष्ट बढ़ोतरी में परिणत होती है तथा इसके द्वारा इस राशि के द्वारा राष्ट्र की संपत्ति में बढ़ोत्तरी होती है।

1.25 इस अध्याय में विश्लेषण यह दर्शाता है कि प्रमुख वित्तीय संकेतक जैसे कि औसतन निवल मूल्य, निजीकृत सीपीएसई की संपत्तियों पर निवल लाभ एवं प्रतिलाभ सहयोगी कंपनियों की तुलना में निजीकरण अवधि पश्चात में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। यह सुधरा हुआ प्रदर्शन अलग अलग रूप से ली गई प्रत्येक सीपीएसई के लिए भी सत्य है।

1.26 देश में संपत्ति का अंतिम माप देश की जीडीपी है। निवेशक अर्थव्यवस्था में निवेश करने का तय करते हुए देश के जीडीपी विकास को ध्यान रखता है, इसके परिमाण के बारे में अनिश्चितता निवेश को प्रभावित कर सकती है। इसलिए, 2011 में भारत की जीडीपी अनुमान प्राविधिकी में बदलाव के पश्चात भारत की जीडीपी वृद्धि दर के बारे में हाल ही के विवाद ने महत्ता हासिल की। सांख्यिकी एवं अर्थमितिपरक विश्लेषण का ध्यानपूर्वक उपयोग करते हुए जो कि इस मामले की महत्ता से न्याय करता है, अध्याय 10 (क्या भारत की जीडीपी बढ़ा चढ़ा कर बता दी गई है? नहीं।) भारत की जीडी पी वृद्धि के गलत अनुमान का कोई साक्ष्य नहीं पाता है।

1.27 अर्थव्यवस्था में संपत्ति सृजन माल एवं सेवाओं को खरीदने के लिए उसी अधिक क्रय शक्ति के माध्यम से आम आदमी की जीविका अंततः बढ़ानी चाहिए। आम आदमी के लिए पोषक खाद्य की एक प्लेट-एक थाली-एक मूल मद है जिसका प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति सामना करता है। अतः इसे सूचित करने के लिए बेहतर रास्ता नहीं हो सकता है कि अथवा आर्थिक नीतियां आम आदमी को प्रतिदिन थाली के लिए जो अदा करता है को बढ़ानी हैं। अध्याय 11 (थाली नामिक्स: भारत में खाने की प्लेट का अर्थशास्त्र) अप्रैल

2006 से मार्च 2019 तक भारत में 25 राज्यों/संघ शसित प्रदेशों में लगभग 80 केन्द्रों में थाली की सूची का निर्माण करता है। समीक्षा थाली की कीमत स्थिरता के मूल संकेतकों का उपयोग करते हुए यह साक्ष्य को प्रस्तुत करती है कि खाने की एक पोषक प्लेट अब आम आदमी के लिए अधिक सस्ती हो गई है।

1.28 यह अध्याय अर्थशास्त्र को आम आदमी से जोड़ता है। यह अध्याय के माध्यम से आर्थिक समीक्षा 2018-19 ने “नज का व्यवहारात्मक अर्थशास्त्र” पर मानव को मानव समझने के लिए विनम्र प्रयास किया था; नकि स्वहित प्रेरित आटामैटोन्स के लिए, ताकि आम आदमी अपनी स्वभावगत प्रतिक्रियाएं कर सके तथा इसे उपयोग करने के लिए जोकि अर्थव्यवस्था नीति के उपकरण के रूप में व्यवहारात्मक बदलाव को समझने के लिए आसान प्रिन्स के रूप में प्रयोग कर सके। आर्थिक समीक्षा 2019-20 ऐसा कुछ उपयोग करते हुए ‘प्रत्येक दिन की खाने की थाली’ से आम आदमी की अर्थव्यवस्था को संबंधित करने का यह सहस्र प्रयास जारी रखती है।

इस शताब्दी के पहले के वर्षों में विश्वास का टूटना

1.29 बाजार अर्थव्यवस्था में भी राज्य को अदृश्य हाथ की सहायता करने के नैतिक हाथ सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। जैसा कि सैंडल (2012) तर्क देते हैं। बाजार सभी की मत पर लाभों के अनुसरण में नैतिकता से विचलित हो सकते हैं। विश्वास औपचारिक एवं अनौपचारिक वित्तपोषण, दोनों में सकारात्मक रूप से योगदान देता है (ग्यूसो, और अन्य, 2004) विश्वास को दक्ष परिणाम प्राप्त करने के लिए बैंकिंग प्रणाली हेतु महत्वपूर्ण स्नेहक के रूप में समझा जाता है।

1.30 प्राचीन दार्शनिक विश्वास को समाज का एक महत्वपूर्ण अवयव मानते हैं तथा यह संपुटित करते हैं कि नैतिक एवं दार्शनिक आयामों का अनुरोध करके विश्वास को और बढ़ाया जा सकता है। इन लाइनों के साथ समीक्षा में “विश्वास” एक सार्वजनिक वस्तु है (जिसमें व्यापक प्रयोग से वृद्धि होती है) की शुरुआत की है। (बॉक्स 1 देखें) बॉक्स 1 अरस्तु जैसे दार्शनिकों की

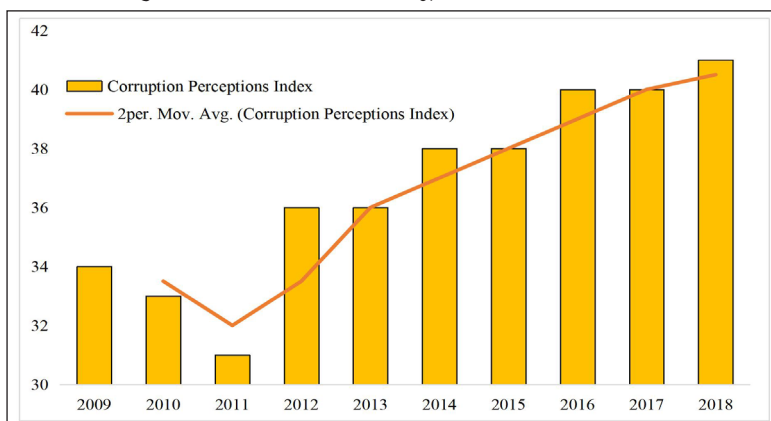
² See Gneezy Rustichini (2000a, 2000b), Gneezy, Meier, and Rey-Biel (2011), Meier (2000a, 2000b) for economic research on intrinsic motivation.

व्याख्या करता है तथा कम्प्यूशियक विश्वास को “अच्छे कानून अच्छे नागरिक बनाते हैं” की व्याख्या करते हुए सार्वजनिक वस्तु के तौर पर देखता है। जिंगल्स (2011) तथा से पियन्जा एवं जिंगल्स (2012) रेखांकित करते हैं कि वैश्विक वित्तीय संकट बाजार अर्थव्यवस्था में विश्वास में विफलता का स्पष्ट उदाहरण है। हमारे आसपास भी 2011 की घटनाओं ने इसी प्रकार की छवि प्रस्तुत की।

1.31 भ्रष्टाचार धारणा सूची, जिसको ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पूरे देशों में पता लगाती है, यह दर्शाती है कि भारत में हाल के वर्षों में 2011 में निम्नतम बिन्दु पर था। 2013 से, भारत ने इसी सूची पर उल्लेखनीय सुधार किया है (चित्र 18) विश्वास घाटे की घटना जोकि इस अवधि के दौरान भारत में घटी बहुत से अन्य मापको में भी

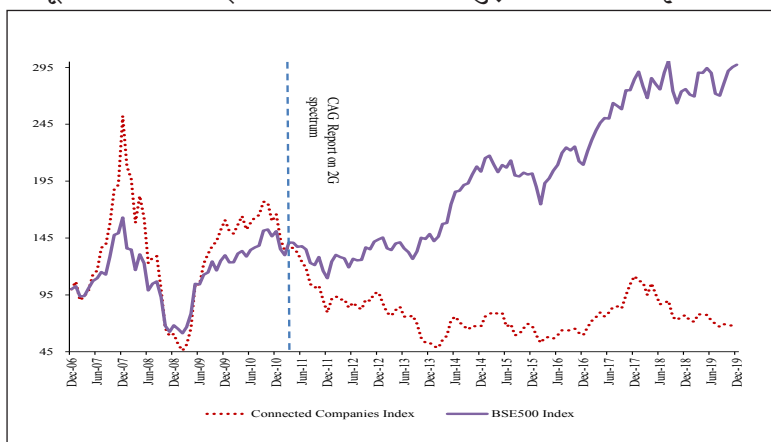
प्रदर्शित होती है। जैसा समीक्षा अध्याय 3 दर्शाता है, 2011 से पहले, इसने कंपनियों तथा इसकी शेयरधरिकों को कंपनियों के संस्थापक का राजनैतिक संबंध से लाभ होता था। राजनैतिक संबद्धित कम्पनियों की सूची ने बीएसई 500 सूची में निरंतर बेहतर प्रदर्शन किया था (चित्र -19)। राजनैतिक संबद्धित कम्पनियों व्यवस्थित रूप से नैतिक समर्थन वाली कंपनियों से अधिक कमाया था। अध्याय 3 यह भी प्रदर्शित करता है कैसे 2014 से पहले प्राकृतिक संसाधनों के मनमाने आवंटन ने लाभार्थियों द्वारा भाड़ाखोरी को बढ़ावा दिया था। जाने की तुलनात्मक रूप से 2014 के पश्चात प्राकृतिक संसाधनों की प्रतियोगात्मक नीलामी ने ऐसी भाड़ाखोरी के मौकों को हटा दिया है।

चित्र 18: भारत हेतु भ्रष्टाचार अनभिज्ञता सूचकांक भ्रष्टाचार अनभिज्ञता सूचकांक



स्रोत: ट्रांसपेरेंसी अंतर्राष्ट्रीय

चित्र 19: 2011 से पूर्व और पश्चात् राजनीतिक रूप से जुड़ी फर्मों द्वारा सृजित निवेशक संपत्ति सृजन



स्रोत: एंबिट प्राइवेट लिमिटेड नोट जनवरी, 2007 में दोनों संख्या को 100 तक क्रमबद्ध किया गया

Note: 1) The connected companies index is an aggregate market cap index which has been rebased and is adjusted for demergers, 2) 70 companies with political dependence and connectivity as on Dec'06 as per Ambit analysts.

बॉक्स 1: विश्वास एक सार्वजनिक वस्तु के रूप में: आरिस्टोल और कौटिल्या विरूद्ध मैकियावली

जन कल्याण के रूप में भरोसा जिसके प्रयोग में इजाजा होने से वृद्धि होती है” के विचार को प्रतिपादित किया है। लोक कल्याण के भरोसे को समर्थन के अभिलक्षणों के साथ अवधारणा के रूप में लिया जा सकता है। अर्थात् नागरिक बिना किसी प्रत्यक्ष वित्तीय लागत पर इसका लाभ उठा सकते हैं। विश्वास में प्रतिद्वंद्विता नहीं होती अर्थात् किसी अन्य नागरिक को इस जनहित को देने की सीमांत लागत शून्य होती है। यह स्वीकार्य भी होता है अर्थात् सभी नागरिकों के लिए सामूहिक आपूर्ति का अर्थ यह है कि इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अन्य सार्वजनिक वस्तुओं की तरह विश्वास भी बार-बार प्रयोग करने से बढ़ता है तथा इसीलिए इसे बनने में समय लगता है। (गमबेरा, 1998) विश्वास की कमी बाह्यता को दर्शाता है जहां निर्णय करने वाले अपने कार्यों के कुछेक परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं होते।

अर्थव्यवस्था में विश्वास के महत्व को देखते हुए कोई भी व्यक्ति इससे निपटने वाले आर्थिक सिद्धांत, विशेषकर लेन-देन लागत अर्थशास्त्र या अपूर्ण संविदाओं के साहित्य की प्रत्याशा कर सकता है। हालांकि यह विषय नहीं है। नाबल पुरस्कार विजेता ओलिवर विलियमसन, जिसने लेन-देन लागत अर्थशास्त्र में विशेषज्ञता हासिल की है, का स्पष्टकथन है कि आर्थिक कार्यकलाप में विश्वास नाम की कोई चीज नहीं है यह बेहद अनावश्यक है और उस वाणिज्यिक लेनदेन की व्याख्या करने में “विश्वास” शब्द का प्रयोग भ्रामक हो सकता है जिसमें अधिक प्रभावी लेन-देन के समर्थन में लागत-प्रभावी उपाय तैयार किए गए हैं। (विलियमसन, 1993 पृ. 463) विलियमसन का मानना है कि प्रोत्साहन एवं अधिशासन संरचनाओं पर आधारित गणनात्मक सहयोग की भूमिका होती है: यदि आर्थिक एजेंटों को आर्थिक संबंधों, जिनके वे घटक हैं, की अधिक दूरगामी समझ है तो उन पर उनके लिए उल्लेखित पक्षपाती में कियावली सिद्धांत की बजाए मैकियावली सिद्धांत हथियाना लागू नहीं होता। उनका तर्क है कि गणनात्मक प्रचालन की अधिका संभावना उस समझ होती है जब एजेंटों के पास लंबी अवधि हो, जो विश्वास के सच होती है।

समान रूप से, कोई भी व्यक्ति यह अपेक्षा करेगा कि विश्वास को अपूर्ण संविदा साहित्य में व्यक्त किया जाना चाहिए, अपूर्ण संविदा माडल का आविष्कार नोबल पुरस्कार विजेता ओलिवर हर्ट ने अपने सहयोगी लेखकों सेनफोर्ड ग्रासमैन, और जॉन मूर के साथ किया है। वे यह दलील देते हैं कि प्रत्येक संभावित आपात स्थिति में क्या किया जाना होता है इस बात को संविदा में विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए यह अपेक्षा कना उचित है कि विश्वास को आदर्श के रूप अभिव्यक्त किया जाए, चूंकि आर्थिक एजेंट केवल उन्हीं अपूर्ण संविदाओं में भाग लेने को जोखिम उठाएंगे, यदि ऐसे मैनेर में अप्रत्याशित परिणाम को स्वीकार करने के लिए उनके सहयोगी उन कर विश्वास करें कि उस संविदा से बेहतर आर्थिक आय मिलेगी।

हालांकि, जब अपूर्ण संविदाकारी साहित्य स्वतः, प्रवर्तनकारी प्रत्यक्ष संविदाओं का विश्लेषण करता है जहां पक्षपाती व्यवहार अर्थात् अवसरवाद, किसी भी पक्ष के हित में लंबी अवधि के अभिकलन के लिए उद्यम द्वारा प्रतिबंधित किया जाता है। (बेकर एट एल 1998)

लेन-देन लागत या अपूर्ण संविदाकारी पैटर्न की तुलना में व्यक्तियों की न केवल भौतिक आवश्यकताएं होती हैं। मानवीय दृष्टि प्रत्यक्ष रूप में बेनाबाऊ एवं रिशोल (2006) के स्केमा से संबंधित है जहां व्यक्ति स्वयं को संकेत देने के लिए कार्रवाई करते हैं कि वे कौन हैं। लोगों के आत्म-सम्मान की आवश्यकता को “विश्वसनीय” बनाने के लिए उनकी अंतर्निहित प्रेरणा से जोड़ा जाता है।

“आधुनिक आर्थिक सिद्धांत को मानने वालों के बीच “गाठ” रूपी विरोधाभास मनुष्यों के दृष्टिकोण को लेकर पैदा होता है जिसकी प्रस्तुती मैकियावेली और हूम ने की है। उदाहरण के लिए”, प्रत्येक व्यक्ति को अपने सभी कार्यों में गुलाम होना चाहिए तथा दूसरी कोई बात नहीं होनी चाहिए, इसके बाद अपने निजी हित को देखना चाहिए। हमें इस सहित से नियंत्रित

होना चाहिए, तथा इसके द्वारा वह अपनी अतृप्त धन-लोलुपता एवं अभिलाषा के बावजूद जनता की भलाई में सहयोग करें।” आज मौटे तौर पर आर्थिक नीति हूम के अधिकतम के अनुसार आगे बढ़ती है।

फिर भी, अरस्तु का दृष्टिकोण हूम या मैकियावेली के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। अरस्तु का मानना है कि आदतों एवं सामाजिक गुण विकसित करके अच्छे कानून अच्छे नागरिक बनते हैं” कन्फ्यूशियस सरकार को परामर्श देते हैं कि उनका सरकारी आदेशों से मार्गदर्शन करें, उन्हें शक्तियों से विनियमित करें तथा इससे लोग कानून से बचने एवं बेशर्मा होकर रहने का प्रयास करेंगे। उनका “गुणों” से मार्गदर्शन करें तथा “रीति-रिवाजों” से उन्हें विनियमित करें तथा इससे उनमें शर्मशार होने की भावना पैदा होगी ता “जिम्मेदार” बनेंगे। लोग आदेशों एवं शास्तियों की बजाए “गुण” से निर्देशित एवं “रीति-रिवाजों” से विनियमित होकर “जिम्मेदार” बनते हैं।

कौटिल्य को भारत के मैकियावेली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी उत्पत्ति प्रजातियों और आंतरिक/बाहरी सुरक्षा के संबंध में खंडों के विशेष उद्धरणों पर आधारित अर्थशास्त्र के आंशिक अध्ययन से हुई है। अर्थशास्त्र का वास्तविक अर्थ “अर्थ प्रबंधन” है और यह गहनरूप में शहरी शासन से कर संचालन और वाणिज्य के विविधा स्वरूपों पर विमर्श किया गया है। यह पुस्तक स्पष्टरूप से इसकी शुरुआत में यह अभिकथन करते हुए कि सुशासन ज्ञान की विविधा शाखाओं पर आधारित होता है, बौद्धिक रूपरेखा का निरूपित करता है: वार्ता (आर्थिक नीति), दंडनीति (कानून और इसे लागू करना), अणविकाशिकी (दार्शनिक और नैतिक रूपरेखा) और त्रावी (सांस्कृतिक संदर्भ)। कौटिल्य के लेखों में प्रायः अणविकाशिकी के महत्व की अनदेखी की जाती है। लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण में इसे समझना महत्वपूर्ण है। रोचकरूप में यह एडम स्थि को विवित करता है जो “अदृश्य हाथ” का न केवल समर्थन करता है बल्कि “पारस्परिक सद्भावना” के महत्व का भी समर्थन करता है (अर्थात् विश्वास)।

ऐसा ही विचार ‘फ्रैडरिक हाइक’ के लेखन में भी परिलक्षित होता है जो न केवल आर्थिक आजादी का समर्थन करता है बल्कि सामान्य नियमों और सामाजिक मानदंड जो प्रत्येक नागरिक पर लागू होते हैं, का भी समर्थन करता है।

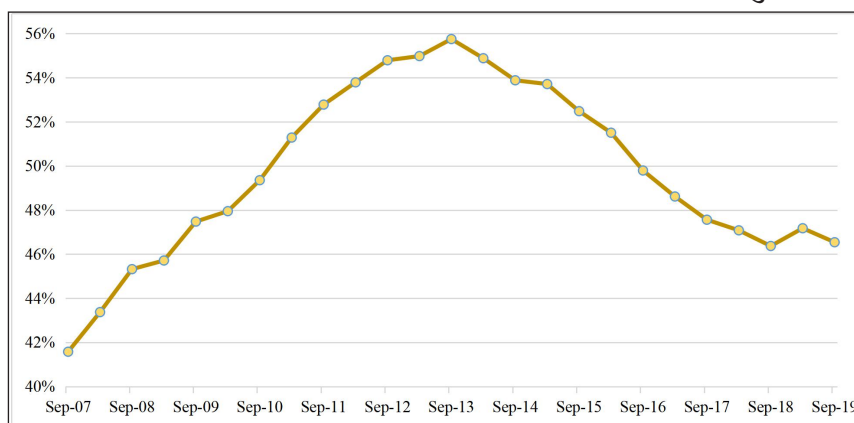
‘अरस्तु’, ‘कन्फ्यूशियस’ और ‘कौटिल्य’, के विचार 21वीं सदी, जिसमें आत्मक केंद्रित लोलुपता को महत्व दिया जाता है में अजीब लग सकते हैं। फिर भी, वैश्विक वित्तीय संकट को बढ़ाने वाले घटक औरसंकट के बाद के घटक स्पष्टरूप से दर्शाते हैं कि “विश्वसनीय” होने

की आंतरिक प्रेरणा जन कल्याण के रूप में विश्वास पैदा कर सकती है जबकि नितांत लालच की आंतरिक प्रेरणा विश्वास के जनकल्याण को पंगु बना सकती है। उदाहरण के लिए, इस दृष्टिकोण के लिए जिंगल्स (2011) और सैपिंजा और जिंगल्स (2012) का अवलोकन करें कि वैश्विक वित्तीय संकट ने बाजार की अर्थव्यवस्था में विश्वास की विफलता की एक शानदार मिसाल का प्रतिनिधित्व किया है।

एक अर्थव्यवस्था में विश्वास की महत्ता को देखते हुए विशेषतः लेन देन लागत अर्थशास्त्र अथवा अपूर्ति निविदाओं पर साहित्य के आर्थिक सिद्धांतों पर ध्यान दिलाने की यथोचित अपेक्षा की जाती है। नोबेल पुरस्कार विजेता ओलिवर विनियमसन जिन्होंने लेन देन लागत अर्थशास्त्र में अध्ययन किया है, स्पष्ट रूप से बताया है कि आर्थिक गतिविधि में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं है; यह उत्तम पर निरर्थक है और वाणिज्यिक विनियम का वर्णन करने के लिए “विश्वास” शब्द का प्रयोग करना भ्रामक हो सकता है जिसके लिए अधिक कुशल विनियम के समर्थन में लागत-प्रभावी संरक्षण पर विचार किया गया है। गणनात्मक विश्वास समय सीमा में अंतर्विरोध है (विलियमसन, 1993 पृष्ठ 463)। विलियमसन ने प्रोत्साहन और शासन संरचना पर आधारित गणनात्मक सहयोग की भूमिका को स्वीकार किया: कूटनीति पूर्वक झपटना अंतर्निहित नहीं है यदि आर्थिक एजेंटों के पास आर्थिक संबंधों की दूरदर्शी समझ है जिसमें वे अदूरदर्शी कूटनीति का कारण बनने की अपेक्षा उसका हिस्सा बनते हैं। (विलियमसन, 1993, पृष्ठ 474)।

उन्होंने तर्क दिया कि गणनात्मक सहयोग की अधिक संभावना तक है जब एजेंटों के पास अधिक समय सीमा है। जो विश्वास के लिए सही है। विश्वास पर अपूर्ण अनुबंध रचना के समान ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। अपूर्ण संविदात्मक नमूनों का सैनफोर्ड ग्रासमैन, ओलिवर हार्ट, और जॉन मूरे द्वारा संचालन किया गया। वे तर्क देते हैं कि अनुबंध, की जाने वाली हर संभव संभावना को निर्दिष्ट नहीं करते। अतः विश्वास को ऐसे उदाहरण के रूप में लेना तर्क संगत होगा क्योंकि आर्थिक एजेंट केवल अपूर्ण अनुबंधों में जोखिम प्रवेश कर रहे होंगे यदि वे अप्रत्याशित परिणामों, जो आर्थिक प्रतिफल के समुचित वितरण से संबंधित हों, को अनुकूल बनाने हेतु अपने प्रतिस्थनी पर विश्वास करते हैं। तथापि सैद्धांतिक अर्थशास्त्र में, अपूर्ण अनुबंध का केवल निम्नलिखित तीन प्रकार से विश्लेषण किया गया है: संपत्ति अधिकार के रूप में, लेनदेन लागत के रूप में, स्व-चालित अंतर्निहित अनुबंधों के रूप में। विश्वास की धारणा का सही तर्क संगतता के अनुमान के कारण अपूर्ण अनुबंधों अथवा उपर्युक्त तीन प्रकार में से किसी एक का आर्थिक सिद्धांत में कोई स्थान नहीं है। पूरे तौर पर तर्कसंगत आर्थिक एजेंटों के पास पूर्ण दूरदर्शिता है और इसी लिए गणना योग्य जोखिम अनिश्चितता की समस्या को कम किया जाए तथा चूंकि विलियमसन चह तर्क देते हैं कि गणनात्मक विश्वास समय सीमा में अंतर्विरोध है। साइमन (1982) यह तर्क देते हैं कि तर्क संगतता सीमित है क्योंकि हमारे सोचने की क्षमता, उपलब्ध सूचना, और समय की सीमाएं हैं।

चित्र 20: भारतीय गैर-खाद्य ऋण में कारपोरेट ऋण का अनुपात



स्रोत- आर बी आई

ऋण दोष

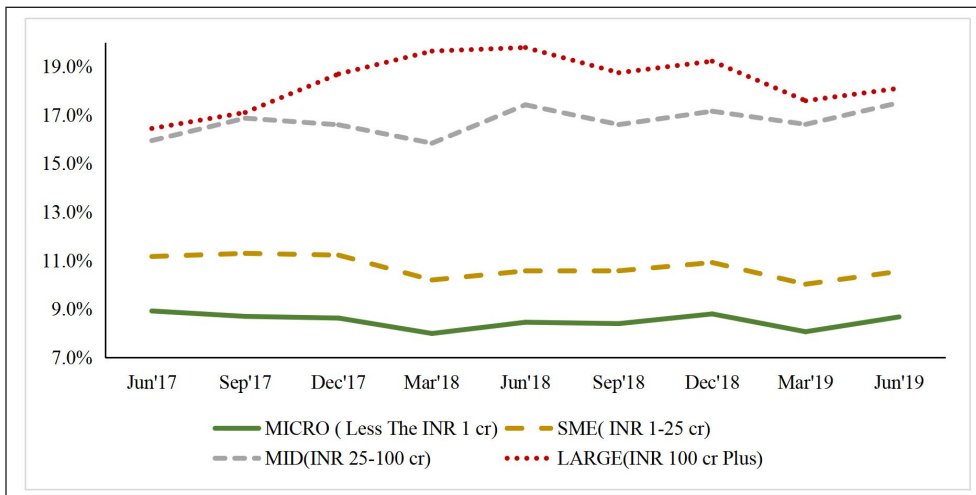
1.32 समीक्षा के अध्याय 3 में बड़े कारपोरेशन द्वारा अपने ऋणों में जान बूझ कर दोषी बनने के सक्ष्य मिलते हैं; इसके अतिरिक्त जान बूझ कर की गई ऐसी चूक जो संबंधित पार्टी के लेन देन के प्रयोग से और उसके प्रकटीकरण की कमी से यह संबंधित हो। सितम्बर 2007 और सितम्बर 2013 के दौरान कारपोरेट क्रेडिट में अभूतपूर्व और विषम वृद्धि के दौरान जमा में तेजी और मंदी की यह घटना प्रकट होती है और 2013 के पश्चात् कमी जैसा कि चित्र 20 में दिखाया गया है। चित्र 21

यह दर्शाता है कि बड़े ऋणों (100 करोड़ भारतीय रु. से अधिक) पर चूक की दरें अधिकांशतम थीं।

लेखा परीक्षा असफलताएं

1.33 जिस प्रकार से किसानों द्वारा फसल जलाने के कारण दूषित वायु के माध्यम से सभी नागरिकों हेतु नकारात्मक माहौल बनाता है उसी प्रकार जब एक कारपोरेट जानबूझकर गलत वित्तीय सूचना देता है तो वे अर्थव्यवस्था में फर्मों के वित्तीयनों में सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों हेतु निम्न विश्वास का नाकारात्मक

चित्र 21: ऋण के आकार द्वारा अनर्जक आस्थियां (एनपीए)



स्रोत: ट्रांसयूनियन सिबिल-सिडबी

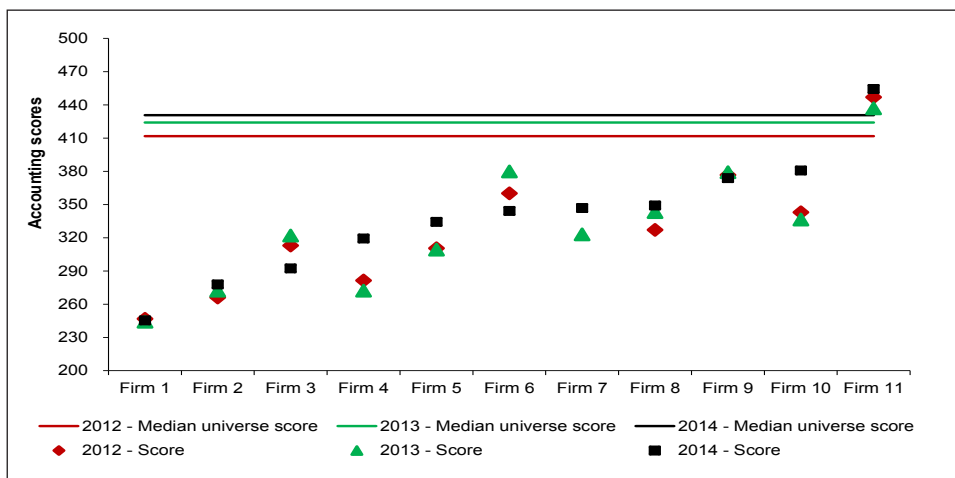
माहौल बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचता है। उधार देने वाले जिनसे अन्य वित्तीय प्रणाली मध्यस्थ और बड़े रूप में अर्थव्यवस्था शामिल हैं, वे कुछ की कारस्तानियों से आई नकारात्मक बाह्य प्रभाव से पीड़ित होते हैं।

1.34 इसी प्रकार से जब एक कॉर्पोरेट अपने ऋणों पर जानबूझकर गड़बड़ी करता है वे के अपने बैंक को नुकसान पहुंचाता है और सभी अन्य कॉर्पोरेटों तक नकारात्मक प्रभाव डालता है क्योंकि वे विश्वास की कमी के कारण साख की कम आपूर्ति पाते हैं। जैसा कि चित्र 20 से देखा जा सकता है, गैर-खाद्य क्रेडिट में कॉर्पोरेट लानों का अनुपात सितम्बर 2007 से हैं वर्षों

तक एक न्यूनाधिक बढ़त दर्शाने के बाद सितम्बर 2013 से घटता रहा है। जैसा कि समीक्षा के अध्याय 3 में जानबूझकर गलतियां करने वालों पर चर्चा की गई थी कुछ विवेकहीन प्रतिपालकों के अवसरपरस्त व्यवहार के कारण अन्य सभी फर्मों अधिक जोखिम से उपजे उच्चतर क्रेडिट प्रसार के माध्यम से इसका खामियाजा भुगतते हैं। मुफ्तखोरी की समस्या के परिणामस्वरूप उच्चतर क्रेडिट प्रवाह और अधिक कॉर्पोरेटों को अपने स्वयं के लोन बाध्यकाओं पर जानबूझकर गड़बड़ी उस को उकसाता हैं।

1.35 कुछ विवेकहीन प्रवर्तकों के अवसरवादी व्यवहार

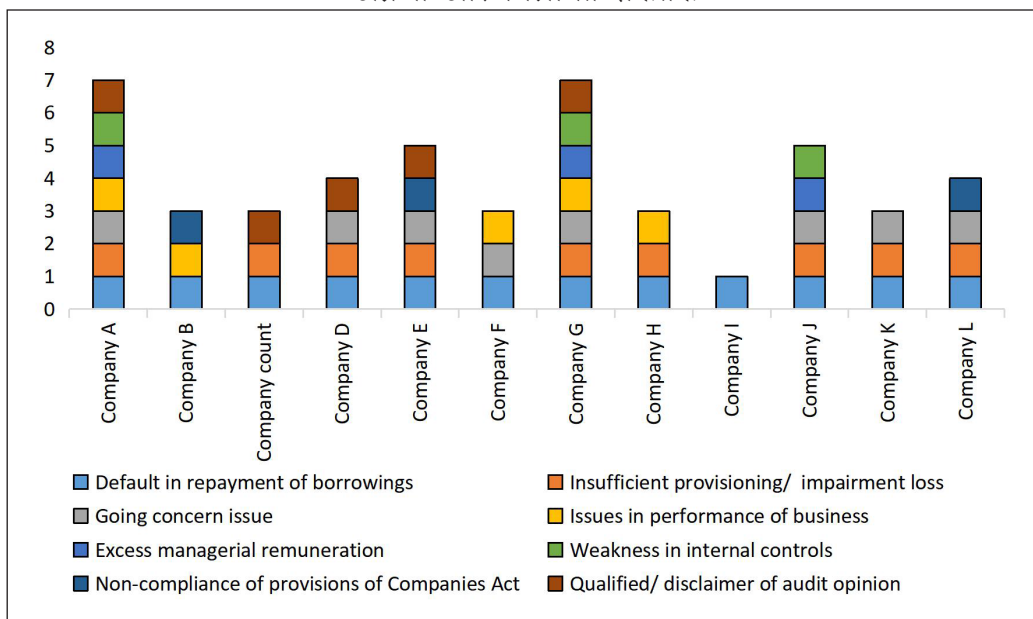
चित्र 22: बड़े दोषियों के एकाउंटिंग क्वालिटी स्कोर



स्रोत: भारतीय ऋण शोधन तथा दिवालियापन बोर्ड (आर बीआई)

चित्र 23: बड़े दोषियों द्वारा वित्तीय विवरणों में खुलासे:

अग्रणी और विलंबित संकेतक



स्रोत: कंपनी वित्तीय विवरण और समीक्षा आंकलन

की आम श्रंखला वित्तीय रूप से गलत रिपोर्टिंग और जानबूझकर गड़बड़ियों दोनों में दिखाई देती है। जून 2017 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसी बारह कंपनियों की पहचान की है। जिसमें भारत के कुल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का 25 प्रतिशत शामिल होता है। जैसा कि चित्र-22 में दर्शाया गया है बड़ी सूचिबद्ध एनपीए और कुछ जानबूझकर गलती करने वाली की लेखा योग्यता वर्ष 2012, 2013 और 2014 में अन्य समान रूप से सूचिबद्ध कॉरपोरेटों की लेखा योग्यता से काफी कम है। अध्याय 06 इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नए निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में एनपीए का कई अधिक अनुपात है। परिणामतः जानबूझकर गड़बड़ी करने वाले ने कर दाताओं के रुपए को धोखे से ले लिया।

1.36 इसी प्रकार, इस विश्वास के पटल पर भी बाजार विफल हुआ है कि आडिटर अपने ग्राहकों खातों की भरोसेमंद जांच करते हैं। समीक्षा ने बड़े अनुसूचित एनपीए और जानबूझकर दोषियों का विश्लेषण किया गया है ताकि यह जांच की जा सके कि क्या ऑडिटर ने जानबूझकर सामग्री का अस्पष्ट खुलासा किया है। यह संकेतक ऑडिटर्स द्वारा आदर्श रूप से चिन्हित

किए जाने चाहिए। अग्रणी संकेतकों को तालिका (1) में दिखाया गया है। और पीछे रहने वाले संकेतकों को तालिका 2 में

1.37 चित्र 23, बारह बड़े दोषियों में से केवल एक ने एक संकेतक का खुलासा किया है जबकि अधिकतरों ने आठ अग्रणी और विलंबित संकेतकों में से तीन और चार संकेतकों का खुलासा किया है। अतः 2011-13 के लगभग कुछेक बड़े संदेहात्मक प्रोत्सहिकों के कारण विश्वास की बाजार विफलत हुई। इसके परिणामस्वरूप बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ी गैर-निष्पादन परिसंपत्ति (एमपी) एकत्र हुई, विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों (पीएसबी) में यह विश्वास की विफलता कुछेक मुख्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एमबीएफसीएस) तक भी निरंतर फैलती गई। जब लिक्विड डेब्ट मैनुअल फंड के निवेशक अपने निवेश को नकद पाने के लिए सामूहिक रूप से चल पड़े तो इससे समूहों एनबीएफसी वित्त क्षेत्र में एक डर पैदा हो गया जिसके कारण एमबीएफसी क्षेत्र में संकट छा गया। यह अध्याय 7 में समझाया गया है।

विश्वास संपोषण ऐसी नीतियों को दूर रखना जिससे

तालिका 1: दबाव के मुख्य संकेतक अथवा संबंधित दोष

अग्रणी संकेतक	व्याख्या
व्यापार के निष्पादन में मुद्दे	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी के ऑपरेशनल नकद प्रवाह पर गहन दबाव • टर्नओवर और प्रचालन मार्जिन में गिरावट • अनुबंध बाध्यता की गैर-अनुपालनता • बैंक एकाउंटों में गैर मिलान/गड़बड़ी • आंतरिक कंट्रोल में कमजोरी
आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी	<ul style="list-style-type: none"> • कोई आंतरिक ऑडिट विभाग नहीं • प्रचालन में हस्तक्षेप
कंपनी एक्ट के प्रावधानों का गैर-अनुपालन	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी एक्ट (2013), नियम, विनियम और मार्गदर्शन के प्रावधानों के गैर-अनुपालन से संबंधित सचिवालय ऑडिट के अंतर्गत उठाए गए मुद्दों
ऑडिट ओपीनियन का क्वालिफाईड डिस्क्लेमर	<ul style="list-style-type: none"> • ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफाईड ओपीनियन। • ऑडिट ओपीनियन के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए एक पर्याप्त समुचित ऑडिट ओपीनियन की अक्षमता के कारण ओपीनियन का डिस्क्लेमर
अत्यधिक प्रबंधकीय पारिश्रमिक	<ul style="list-style-type: none"> • बैंकों, वित्तीय संस्थानों और डिबेन्चर होल्डरों को ऋणों के पुर्नभुगतान (मूलधन और ब्याज) में दोष। • ऋणदाताओं द्वारा एनपीए के रूप में ऋण वर्गीकरण

तालिका 2: दबाव अथवा आसन्न दोष के विलंबित संकेतक

बैंकिंग संकेतक	व्याख्या
लिए गए धन के पुर्नभुगतान में दोष	<ul style="list-style-type: none"> • बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और डिबेन्चर होल्डरों को ऋणों के पुर्नभुगतान में दोष • ऋण देने वाले द्वारा एनपीए के रूप में ऋण वर्गीकरण
अपर्याप्त प्रावधान/हानि	<p>नहीं/अपर्याप्त प्रावधान निम्नलिखित:</p> <ul style="list-style-type: none"> • संबंधित पार्टियों के ऋणों/कॉरपोरेट गॉरंटी की वसूलियता • संबंधित पाटियों में किए गए निवेश की वसूलियता • उधारकर्ताओं से शेष बकाया के पुष्टिकरण में त्रुटि • दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम
चल रहे संबंधित मुद्दे	<p>संग्रहित हानियों के परिणाम से कुल कारोबार में कमी आई।</p> <ul style="list-style-type: none"> • मौजूदा परिसम्पत्तियों से अत्यधिक चालू दायित्व • आवर्ती घाटे/कैश घाटे • नकारात्मक कुल कारोबार • प्राथमिक व्यापार गतिविधियों का निलंबन होना

अंतर्गत प्रेरणा दुष्प्रभावित होती है।

विश्वसनीयता बढ़ाना: अर्न्तभूत प्रोत्साहन को खत्म करने वाली नीतियों को हटाना।

1.38 वैश्विक वित्तीय संकट की ही भांति 2011-13 की के दौरान और इसके परिणामों को अपनाने से अर्थव्यवस्था में विश्वास की कमी हुई। इसे ठीक करने की जरूरत है, इस बात को समझते हुए कि विश्वास का पुनः निर्माण करने में समय लगेगा। हमारी परंपरा अर्थव्यवस्था संपत्ति सृजकों को घटकों के रूप में पूजती है। लेकिन थिरूवालायूवर में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यह केवल तभी होता है जब संपत्ति

செப்பம் உடையவன் ஆக்கக் குளிதவின்றி
எச்சத்திற் கேடமாப்பு உடைத்து.

“The just man's wealth unwasting
shall endure,

And to his race a lasting joy ensure.”

– *Thirukural, Chapter 12, verse 112.*

1.39 विश्वास वह गोंद है कि जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को पारंपरिक रूप से बांधता है तथा हमारी अर्थव्यवस्था की भलाई में एक आवश्यक घटक है। विश्वास बैंकिंग तथा वित्तीय बाजार की कार्यप्रणाली में भी एक प्रमुख घटक है। यदि विश्वास ज्यादा हो तो अवसरवाद की बढ़ी हुई संभावना के बावजूद आर्थिक गतिविधियाँ फलफूल सकती हैं। फिर भी, विश्वास कि कार्यात्मक रूप से उपयोगी है’ इसका अर्थ यह नहीं होता कि यह आवश्यक रूप से बढ़ेगी। हमें उन घटकों को पहचानने की आवश्यकता है कि जो कि मौकापरस्ती व्यवहारों में अंतर्निहित है तथा उस प्रक्रिया पर विचार करना चाहिए जिससे लगभग 2011-13 बाजार में विफलता हुई थी से और उसके परिणाम समाज को सहने पड़े थे।

1.40 जैसाकि सेडल (2012) ने मान लिया है, अच्छा व्यवहार तो आंतरिक प्रेरणा से ही उपजता है। और यह बाजार अर्थव्यवस्था के प्रभावी रूप से कार्यकरने का महत्वपूर्ण संपूरक है। दूसरे शब्दों में, बाजार के अदृश्य समर्थन में एक सहायतार्थ नैतिक समर्थन

की आवश्यकता होती है जो कि अर्थव्यवस्था में विश्वास को प्रोत्साहित करता है। इस संदर्भ में, नीति निर्माताओं को यह पहचानने की आवश्यकता है कि सार्वजनिक वस्तुओं, जैसे कि विश्वास, के अपर्याप्त प्रावधानों अधिकतर आंतरिक प्रेरणा से उपजे पुरस्कार तथा अच्छे व्यवहार की कमी होते के कारण हैं। जब बैंक कारपोरेट को पहचानते हैं जो अपने ब्याज एवं मूलधन गैर मौद्रिक तरीकों में समय में अदा करते हैं यह आंतरिक प्रेरणा को मजबूत बनने के लिए सहायता करता है। ऐसे संकेतों को अधिक प्रोत्साहनों, जैसे बढ़ी हुई साख सीमा अथवा पुरस्कार विजेताओं के लिए ब्याजदर में कटौती के साथ नहीं जोड़ना चाहिए अन्यथा लघु अवधि में पुरस्कार विजेता व्यवहार में भविष्य बेहतर क्रेडिट उपलब्धता या आर्थिक प्राप्तियों के लिए कथित रूप से चाटुकारिता हो जाएगी।

Reducing Information Asymmetry

1.41 किसी आर्थिक विनिमय में ऐसा महत्वपूर्ण घटक जो अवसरवादी सामर्थ्य को बढ़ाता है वह सूचना असममिति है। ऐसे अवसरवाद की वृद्धि को प्रवर्तन प्रणाली के मानकीकरण के माध्यम से और जन डाटाबेस के माध्यम से उपचारित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, 2014 पूर्व स्वेच्छाचारी चूक के मामलों में संबंधित लेनदार की वित्तीय सूचना तक की नापहुंची को सूचना असममिति का चालक कहा जा सकता था। पिछले पांच वर्षों में कारपोरेट लेनदानों के लिए ऋण की सूचना तक की पहुंच में अच्छी वृद्धि हुई है। अब इस बात पर बहस की जा सकती है कि यदि भारतीय अर्थव्यवस्था के पास आंकड़ों की अवसंरचना, जैसे सीआरआईएलसी (सेन्ट्रल रिपोजीटरी ऑफ इनफोरमेशन आन लार्ज कारपोरेट) 2014 पूर्व के दौरान ऋण उछाल, सूचीबद्ध एनपीए के विस्तार को बहुत कम कर सकती थी। इस सूचना ने उधरदाताओं को अन्य बैंकों या एनबीएफसी के द्वारा चिन्हित एनपीए कोरपोरेट्स की सीमा को निर्धारित करने की चेतावनी दी है। इस सूचना की उपलब्धता ने पुरी बैंकिंग प्रणाली में एनपीए को कम किया है क्योंकि जब कोई लेनदार किसी एक देनदार के साथ चूक करता है तो अन्य देनदार अपने ऋण को चूक

चिन्हित कर सकते हैं और इसलिए को ला सकते हैं। यह संभव है क्योंकि सभी कारपोरेट ऋण कागजात में अनुप्रस्थ चूक के प्रावधान होते हैं? यह अन्य बैंकों द्वारा उन व्यापारियों को ऋण सीमित कर सकता था अन्यथा। इस बात से परिचित नहीं होते कि अन्य वित्तीय संस्थाओं ने उसे एनपीए घोषित कर दिया है। ऐसे सार्वजनिक डाटाबेस सूचना असमिति को घटाते हैं।

1.42 चित्र 24 दर्शाता है कि 2014 में एनपीए पर दी हुई सूचना को देनदारों के बीच सांझा करना अतिन्यून था है। इस सूचना को सांझा करना एनपीबी की तुलना में पीएसबी के बीच सांझा करना बेहतर था है, लगभग एक चौथाई खातों को अन्य बैंकों के द्वारा एनपीए घोषित करने पर अन्य बैंकों ने भी वाद की संभावना एनपीए खातों में वर्गीकृत कर दिया था। कुछ ही वर्षों में यह हिस्सा बढ़कर 95 प्रतिशत हो गया। इसमें अवसर वा की संभावना को कम कर दिया है और वित्तीय संस्थाओं के ऋणों के क्रियाकलापों में अधिक विश्वास को प्रेरित किया है।

1.43 एक संबंधित मुद्दा यह है कि चूक को स्वेच्छाचारी या अनचाही कहा गया है। बैंकिंग क्षेत्र में सांझा डाटाबेस और आरोपण समस्या के बीच तनावग्रस्त चूकों और स्वेच्छाचारी चूकों को स्वेच्छाचारी सार्वजनिक चूको की सूची बना कर सुलझा दिया गया है। इस प्रकार की नामोल्लेखन ओर शर्मनाक स्वेच्छाचारी चूको ने ऐसे अपराधियों को बैंकिंग क्षेत्र से ऋण की गैर-उपलब्धता को स्वीकृति दे दी है।

पर्यवेक्षण की गुणवत्ता को बढ़ावा

1.44 अर्थव्यवस्था का एक अच्छा निर्णायक बनते हुए सरकार को नैतिकता के भाव से सहयोग देना होगा। निर्णायक का कार्य केवल तथ्यों से अवगत करना नहीं होता बल्कि यदि लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो अवसरवादी व्यवहार्य की पहचान करना भी होगा। जैसे स्वेच्छाचारी चूको, गलत वित्तीय सूचना जैसे भ्रष्टाचार और बाजारी चालबाजी को जल्दी ही पकड़ना होगा क्योंकि यह वह दीमक होता है वित्तीय बाजारों में निवेशकों के विश्वास को खत्म कर देता है, विनिवेश को समाप्त कर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विनिवेश

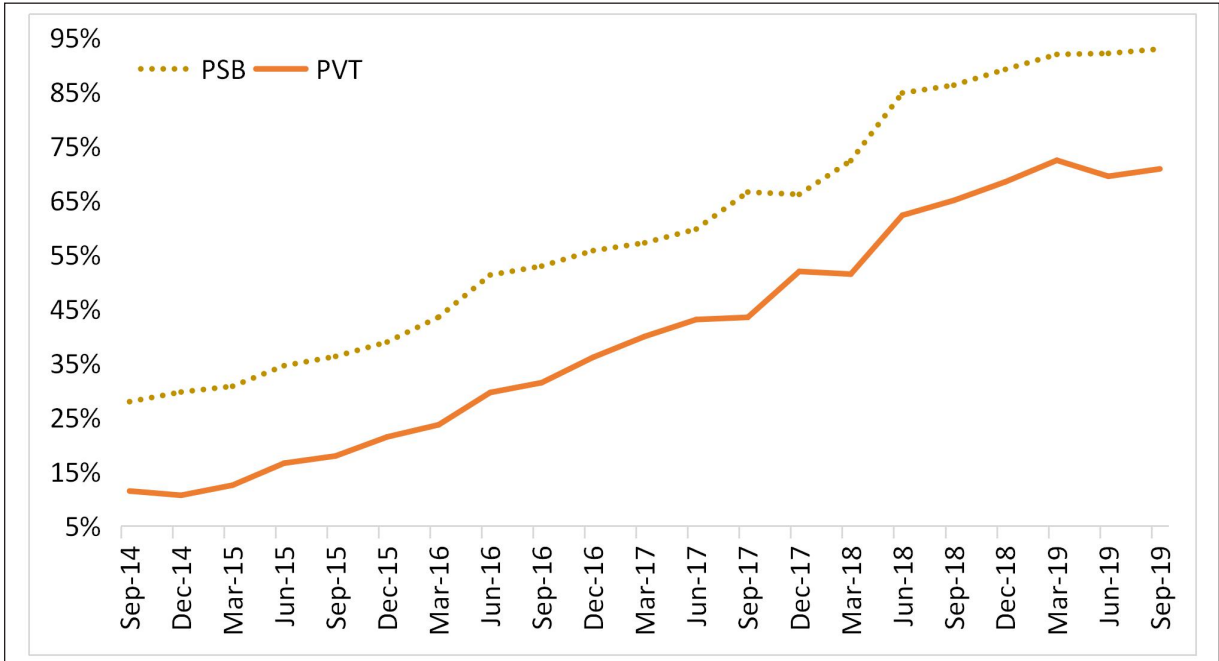
को निकाल देता है। यह न्यायसंगत और कानून का पालन करने वाली बाजार सहभागिता को हटा देता है। यह एक अभिशाप है जो विनिवेश को हटा देता है और तत्पश्चात अर्थव्यवस्था से नौकरियों को। वह जो लोग धन का अर्जन नैतिकता से करते हैं, उनके लिए तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि हमारा वित्तीय बाजार अच्छा और पारदर्शी हो। इस परिस्थिति में राज्य की सक्षम निर्णायक की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता।

1.45 अमेरिकी फेडरल आयोग के पास प्रत्येक दो फर्म के लिए एक कर्मचारी है, जबकि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पास प्रत्येक 38 सूचीबद्ध फर्मों के लिए एक कर्मचारी है। प्रतिभूतियां और विनिमय आयोग के पास प्रत्येक सूचीबद्ध कम्पनी के लिए एक कर्मचारी है। इसके विपरीत, सेबी के पास छः सूचीबद्ध कम्पनियों के लिए एक कर्मचारी है। वास्तव में, कारपोरेट वित्त के विभागों में एसईसी के पास सेबी की तुलना में 15 गुना अधिक कर्मचारी है। इस संसाधनों की कमी को घटा कर सरकार की निर्णायक की भूमिका को सबल करना सभी धन अर्जकों के लिए समतापूर्ण व्यवहार संभव बना देगा।

1.46 एस ई सी और एफटीसी व्यापक रूप से आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स और मशीन लर्निंग को पकड़ने और बाजारी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए प्रयोग कर रहे हैं ताकि हमारा कोई भी विनियामक गलत न कर सके। सीमित संसाधनों के विनियामक के परिणामस्वरूप बाजार अर्थव्यवस्था का पर्यवेक्ष बुरी तरह से प्रभावित होता है जिससे बाजारी दुष्प्रवहार बढ़ता है। अर्थव्यवस्था तब तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकती जब तक बाजारी भ्रष्टाचार को हटाना एवं यथेष्ट पर्यवेक्षण नहीं होता।

इसलिए, हमारे विनियमको की गुणवत्ता और संख्या में महत्वपूर्ण बदलाव (सीसीआई, आरबीआई, सेबी, आईबीबीआई) तकनीकी और विश्लेषण में महत्वपूर्ण विनिवेश एक साथ लाने की आवश्यकता है। यह नैतिकता भाव के प्रभाव को बढ़ाते हुए अधिक धन अर्जन के लिए मदद करेगा।

चित्र 24: एनपीए के लेखाओं के अनुसार एनपीए में पहले से ही टैग हुए देनदारों का अनुपात (अन्य बैंक के द्वारा)



Source: TransUnion CIBIL.

अध्याय एक नजर में

- विदित आर्थिक इतिहास के तीन चौथाई से ज्यादा हिस्से पर भारत का वैश्विक आर्थिक शक्ति पर प्रभुत्व रहा है। ऐसे प्रभुत्व की व्यक्ति डिजाइन से होती ना कि अनिश्चितता से। भारत की आर्थिक प्रभुत्वा को दौरान अर्थ सृजन के लिए अर्थव्यवस्था बाजार के अदृश्य हाथो पर विश्वसनीय हाथो पर विश्वास करती है। विशिष्ट रूप से, बाजारो के अदृश्य हाथ, जैसा कि आर्थिक लेनेदेन की खुलेपन में दर्शाया गया है, उसको विश्वसनीय हाथों के साथ जोड़ा गया जो कि नैतिक और दार्शनिक आयामों में पोषित अंतर्भाग प्रेरणा में पहुंचाती है लगभग आधी शताब्दी पहले, स्पेन्गलर (1971) ने यह तथ्य कौटिल्या के अर्थशास्त्र जो कि अर्थ व्यवस्था में कीमों की भूमिका को दर्शाता है।
- यह समीक्षा वर्तमान प्रमाणों के लिए हमारी परंपरावादी सोच में बताए गए आर्थिक मॉडल के दोनों स्तंभों को भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारता को सहायता देते है। भारत की जीडीपी और उदारीकरण से पूर्व प्रति व्यक्ति जीडीपी में घांताकी वृद्धि स्टोक बाजार में अर्थ सृजन के साथ होता है। इसी प्रकार से, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के प्रचुर लाभों को जो बाजार के अदृश्च हाथों को योग्य बनाने को दर्शाता है। वास्तव में, समीक्षा यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि वो क्षेत्र जो स्वतन्त्र है वह बन्द हुए क्षेत्र की तुलना में तेजी से महत्वपूर्ण ढक से बढ़े है। 2011-13 के दौरान वित्तीय क्षेत्र में की घटनाएं और उदाहरण के दुसरे स्तंभ का अनुसरण करते हुए - विश्वास के हाथों को अदृश्य हाथों की सहायता की आवश्यकता है। वास्तव में, वैश्विक आर्थिक मंदी को देखते हुए, अर्थव्यवस्था साहित्य की उभरती हुई शाखा को अदृश्य हाथो का मजबुत बनाने के विश्वसनीय हाथ की आवश्यकता को पहचाना है।
- यह समीक्षा बताती है भारत की 5 ट्रिलियन अमेरिकी डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की अभिलाषा बाजार के अदृश्य हाथो को मजबुत बनाने और इसको विश्वसनीयत हाथों की सहायता पर निर्भर करती है। व्यापार अनुकूल नीतियों को प्रेरणा देने के लिए अदृश्य हाथो को मजबुत होना पड़ेगा। (1) नये प्रवेशक के लिए समान अवसर प्रदान कराना निष्पक्ष प्रतिस्पर्ध और कारीबारी सुगतमा को बढ़ाना प् ऐसे नीतियों को हटाना जो बाजार को अनावश्यक रूप से सरकारी हस्तक्षेप के द्वा रा कमजोर कर देती है। प् नौकरी सृजन के लिए व्यापार बढ़ाना और प् भारतीय अर्थव्यवस्था के आकर के अनुपात में बैंकिंग क्षेत्र को दर्शातापूर्ण बढ़ाना। सार्वजनिक वस्तु के विश्वास के रूप में जो कि अधिक प्रयोग से और बढ़े के सिद्धांत से परिचय करना, समीक्षा नीतियों में पारदर्शिता लाने और आकड़ों और तकनीकी के दक्ष प्रयोग से सार्वजनिक वस्तु को बढ़ाने का सुझाव देता है।

संदर्भ

Aristotle. 1962. *Nicomachean Ethics*. Translated by Martin Ostwald. Indianapolis: Bobbs-Merrill.

Baker, George, Robert Gibbons, and Kevin J. Murphy. "Relational Contracts and the Theory of the Firm." *The Quarterly Journal of Economics* 117.1 (2002): 39-84.

Bénabou, Roland, and Jean Tirole. "Incentives and prosocial behavior." *American Economic Review* 96.5 (2006): 1652-1678.

Coase, Ronald (1960), "The Problem of Social Cost", *Journal of Law and Economics*, The University of Chicago Press, Vol. 3 (Oct., 1960): 1-44.

Confucius. 2007. *The Analects of Confucius*. Translated by Burton Watson. New York: Columbia University Press.

Deodhar, Satish (2018), "Indian Antecedents to Modern Economic Thought", Working Paper, Indian Institute of Management Ahmedabad, No WP 2018-01-02.

Gambetta, D. (1988). "Can we trust trust?". In Gambetta, D. (Ed.), *Trust*. Oxford: Blackwell, 213-38.

Gneezy, Uri and Aldo Rustichini. (2000a). "Pay Enough or Don't Pay At All." *Quarterly Journal of Economics*, 115(3): 791-810.

Gneezy, Uri and Aldo Rustichini. (2000b). "A Fine Is a Price." *Journal of Legal Studies*, 29(1): 1-18.

Gneezy, Uri, Stephan Meier, and Pedro Rey-Biel (2011). "When and Why Incentives (Don't) Work to Modify Behavior." *Journal of Economic Perspectives*, Vol. 25, No. 4, 191-210.

Guiso, L., P. Sapienza, L. Zingales (2004), "The role of social capital in financial development", *American Economic Review*, 94, pp. 526-556.

Hume, David. 1964. "David Hume: The Philosophical Works. Edited by Thomas Hill Green and Thomas Hodge Grose. 4 vols. Darmstadt: Scientia Verlag Aalen. Reprint of the 1882 London ed.

Maddison A (2007), *Contours of the World Economy I-2030AD*, Oxford University Press, ISBN 978-0199227204.

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. *Psychological Review*, 50(4), 370-96.

Meier, Stephan (2007a), "Do Subsidies Increase Charitable Giving in the Long Run? Matching Donations in a Field Experiment." *Journal of the European Economic Association*, 5(6): 1203-22.

Meier, Stephan (2007b), "A Survey of Economic Theories and Field Evidence on Pro-Social Behavior." In *Economics and Psychology: A Promising New Cross-Disciplinary Field*, ed. Bruno S. Frey and Alois Stutzer, 51-88. Cambridge: MIT Press.

Olivelle, Patrick (2013), *King, Governance, and Law in Ancient India: Kauṭilya's Arthaśāstra*, Oxford UK: Oxford University Press, ISBN 978-0199891825.

Sandel, Michael J. (2012). *What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets*. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Sanyal, S. (2016). *The Ocean of Churn*. Penguin.

Sapienza, Paola, and Luigi Zingales. "A trust crisis." *International Review of Finance* 12.2 (2012): 123-131. Shamasastri, R. "Kautilya's Arthashastra (translated in English)." Sri Raghuvir Printing Press, Mysore (1956).

Shamasastri, R. "Kautilya's Arthashastra (translated in English)." Sri Raghuvir Printing Press, Mysore (1956).

Sihag, Balbir S. "Kautilya's Arthashastra: A Recognizable Source of the Wealth of Nations." *Theoretical Economics Letters* 6.1 (2016): 59-67.

Spengler, J.J. 1971. "Indian Economic Thought," Duke University Press. Durham.

The Road to Serfdom, Friedrich Hayek, University of Chicago 1944

Williamson, Oliver E. "Calculativeness, trust, and economic organization." *The Journal of Law and Economics* 36.1, Part 2 (1993): 453-486.

Zingales, Luigi. "The role of trust in the 2008 financial crisis." *The Review of Austrian Economics* 24.3 (2011): 235-249.

जमीनी स्तर पर उद्यमिता एवं धन सृजन

அருவினை யென்ப உளவோ கருவியான்
காலம் அறிந்து செயின்.

– *Thirukural, Chapter 76, verse 753.*

प्रासंगिक अनुवाद: वह जो सभी संसाधनों एवं अवसरों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करता है वह सक्षम है (उद्यमी) और उसके लिए कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है।

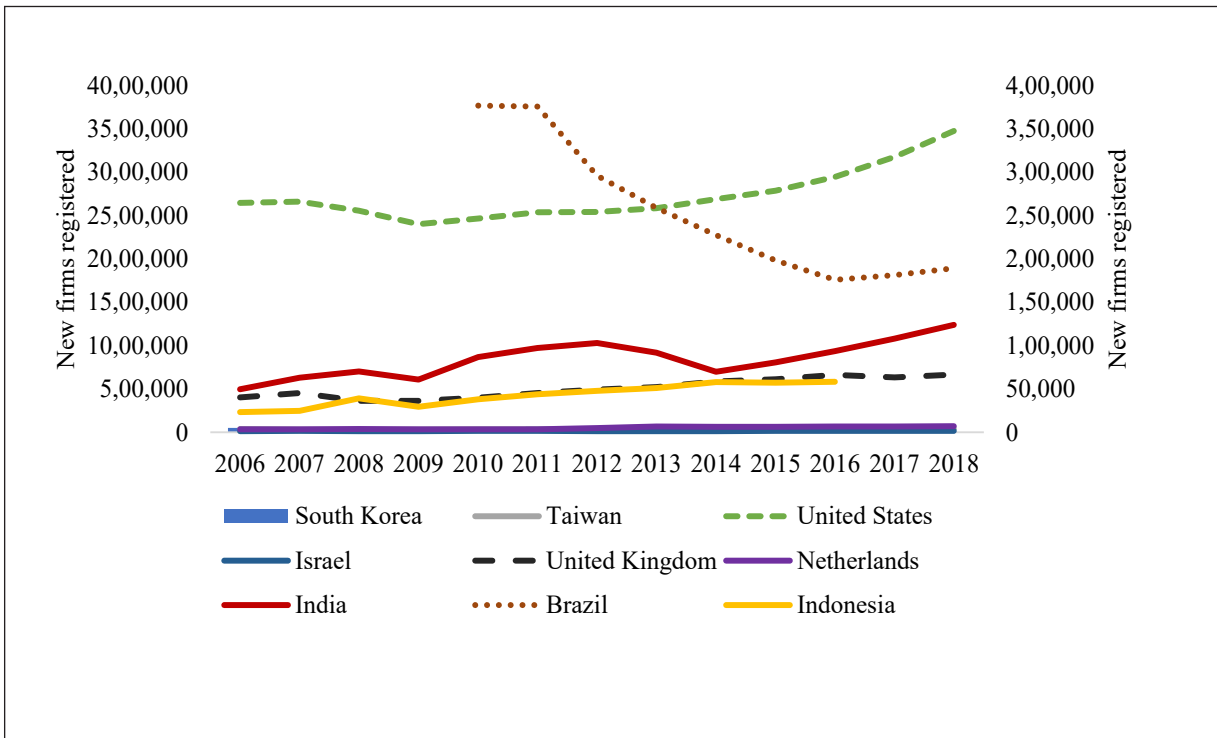
भारत सरकार के “स्टार्ट अप इंडिया” अभियान में भारत में उत्पादकता वृद्धि एवं धन सृजन के संवर्धन के लिए उद्यमिता की उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में पहचान की गई है। इस पहल को देखते हुए इस अध्याय में भारत के 500 जिलों की उद्यमिता संबंधी कार्यकलाप के विषय एवं संचालकों का परीक्षण किया गया है। जो प्रशासनिक सूची स्तंभ में सबसे नीचे हैं। एमसीए-21 डेटाबेस से व्यापक आंकड़ों का प्रयोग करते हुए सभी जिलों में औपचारिक क्षेत्र में प्रारंभ की गई नई फर्मों का विश्लेषण किया गया है। सर्वप्रथम, उद्यमिता पर विश्व बैंक के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, यह अध्याय इस बात की पुष्टि करता है कि भारत नई फर्मों के निर्माण के मामलों में तीसरे स्थान पर है। इसी आंकड़े से पता चलता है कि 2014 से भारत में नई फर्म का निर्माण प्रभावशाली रूप से बढ़ा है। 2006-2014 के दौरान औपचारिक क्षेत्र में नई फर्मों की संख्या 3.8 प्रतिशत के संचयी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी जबकि 2014 से 2018 तक विकास दर 12.2 फीसदी रही। नतीजनत, 2014 में बनाई गई लगभग 70,000 नई फर्मों से, 2018 में नई फर्मों की संख्या लगभग 80 प्रतिशत बढ़कर 1,24,000 हो गई है। दूसरा, सेवा क्षेत्र में भारत की नई आर्थिक संरचना, यानी तुलनात्मक लाभ को दर्शाते हुए, सेवाओं में नई फर्म का निर्माण विनिर्माण, बुनियादी ढांचे या कृषि की तुलना में काफी अधिक है। तीसरा, जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता केवल आवश्यकता से प्रेरित नहीं है क्योंकि जिले में नई फार्मों के पंजीकरण में 10 प्रतिशत की वृद्धि के कारण जीडीडीपी में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, प्रशासनिक पिरामिड के निचले स्तर में उद्यमशीलता का एक जिले का जमीनी स्तर पर संपत्ति सृजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जीडीडीपी पर उद्यमशीलता की गतिविधि का यह प्रभाव विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अधिकतम स्तर पर है। चौथा, नई कंपनियों का निर्माण भारतीय जिलों और क्षेत्रों में बहुत विषम है। इसके अतिरिक्त, यह स्थिति पूरे भारत में फैली हुई है, केवल कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं है। पांच, एक जिले में शिक्षा स्थानीय उद्यमिता को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत के पूर्वी भाग की साक्षरता दर न्यूनतम, 59.6 प्रतिशत है। यह वह क्षेत्र है जिसमें नई फर्मों का निर्माण न्यूनतम है। वस्तुतः उद्यमिता पर साक्षरता का प्रभाव उस समय अत्यधिक उल्लेखनीय होता है जब यह 70 प्रतिशत से ऊपर हो। छठा, एक जिले में स्थानीय शिक्षा स्तर और भौतिक अवसंरचना की गुणवत्ता नये फर्मों के सृजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं। अंत में, वह नीतियां जो व्यापार करने में सुगमता प्रदान करती हैं और श्रम अधिनियम

जो नये फर्म सृजन में सक्षम हो, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में। अतः विनिर्माण क्षेत्र में हमारे युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं और व्यापार सुगमता के बढ़ाने से तथा लचीली श्रम नीति अपनाने से जिलों में और पूरे देश में अधिकतम रोजगार सृजित होंगे। शिक्षा, साक्षरता और भौतिक अवसंरचना अन्य नीतियां हैं जिसे जिला और राज्य प्रशासन को उद्यम विकास के लिए अपनानी चाहिए जिससे रोजगार और धन सृजन हो सके।

2.1 आर्थिक विकास एवं उत्तरवर्ती रोजगार वृद्धि के संदर्भ में उद्यमिता अनेक नीति निर्माताओं के महत्वपूर्ण आकर्षण केंद्रों का प्रस्तुत करती है। उद्यमी उस परिवर्तन के एजेंट के रूप में देखे जा सकते हैं जो अर्थव्यवस्था में नवाचार को गति प्रदान करते हैं। चित्र 1क, विश्व बैंक के ईओडीबी उद्यम आंकड़ों और यूएस सेंसेस ब्यूरो के आंकड़ों को एक साथ प्रयोग करके भारत की नई फर्मों की कुल संख्या की एशिया, यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका के देशों के से की गई तुलना यह स्थापित करती है कि भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी उद्यमिता पारिस्थितकीय प्रणाली है।

सिर्फ यही नहीं बल्कि औपचारिक क्षेत्र में नई फर्मों की औसत संचयी वृद्धि दर जो 2006-2016 के बीच 3.8 प्रतिशत थी, यह वृद्धिदर 2014-2018 में बढ़कर 12.2 प्रतिशत हो गई। इसके कारण जहां 2014 में 70000 नई फर्में सृजित हुईं, उनकी संख्या 80 प्रतिशत की वृद्धि से 2018 में 1,24,000 हो गयी। चित्र 1ख उद्यमिता गहनता के तुल्यता की प्रस्तुती करती है। जिसे प्रति 1000 कामगार नई पंजीकृत निजी स्थापनाओं की संख्या द्वारा परिभाषित किया जाता है। (15-64 वर्ष की आयु वाली जनसंख्या में)

चित्र 1क: विभिन्न देशों की उद्यम संबंधी गतिविधि (नई फर्म) की तुलना



स्रोत: एमसीए-21, विश्व बैंक का ईओडीबी उद्यमिता डाटा यूएस जनसंख्या ब्यूरो एवं समीक्षा परिकल्पनों की निर्माण सांख्यिकी टिप्पणी: भारत, ब्राजील एवं इण्डोनेशिया के लिए द्वितीयक अक्ष।

बॉक्स 1: डाटा और कार्यविधि

तीन डाटा स्रोतों के प्रतिच्छन्न द्वारा प्रतिदर्श की रचना की जाती है। प्रथम, सीईआईसी इंडिया प्रीमियम डाटाबेस से प्रचलित कीमतों पर जिला स्तरीय जीडीपी पर डाटा हासिल किए गये हैं। डाटा संकलन की अवधि वर्ष 2000 की समाप्ति से लेकर 2018 की दर्ज की गई है। इसलिए, भारत के 22 राज्यों में से 504 जिलों की जिला स्तरीय जीडीपी को समाहित करते हुए 5,591 जिला-स्तरीय पर्यवेक्षण किए गए।

उद्यमिता का मापन कारपोरेट मामले (एमसीए) मंत्रालय-21 डाटा में शामिल नई फर्मों के तौर पर किया जाता है, ये डाटा सैट 1990 और 2018 के बीच कारपोरेट मामलों (एमसीए) के मंत्रालय में पंजीकृत सभी सक्रिय फर्मों की एक साथ सूचना उपलब्ध कराता है। उसके बाद एमसीए-21 में फर्मों के पंजीकृत कार्यालयों के पते का उपयोग करते हुए जिले की प्रत्येक फर्म का मिलान किया जाता है। इन डाटा के उपयोग के द्विगुणित निहितार्थ होते हैं। पहले, उद्यमिता का हमारा मापन, सामान्य अर्थव्यवस्था में प्राइवेट कारपोरेट सैक्टर तक सीमित है और इसमें उन स्थापनाओं को शामिल नहीं किया जाता जो मौजूदा कंपनियों का प्रसार हो। दूसरे, चूंकि ये डाटा एमसीए के साथ पंजीकृत सक्रिय फर्मों की एक साथ समग्र सूचना होती है, कम से कम एक परिसीमा जो अधिरोपित की जाती है वह यह है कि 2018 तक जो फर्म सक्रिय नहीं थी उस का पता नहीं लगाया जा सकता। हमारे डाटा में यह सर्वेक्षक रूझान यह भी सूचित करता है कि उद्यमिता के बारे में प्राक्कलन उर्ध्वगामी पक्षीय हो सकता है।

तृतीय, किसी भी जिले की भौतिक और सामाजिक अवसंरचना से संबंधित डाटा, भारत के सामाजिक-आर्थिक उच्च दृष्टित ग्रामीण शहरी भौगोलिक डाटासैट से संचित किए जाते हैं। और इनमें (एसएचआरयूजी, http://www.devdata.org/shrug_download पर उपलब्ध) चारों का एक सेट शामिल है जिसमें भारत की सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर का उल्लेख किया गया है। अन्य बातों में, एसएचआरयूजी में वे चर शामिल हैं जो वर्ष 1990 से 2018 के बीच प्रत्येक जिले के जनसांख्यिकीय, सामाजिक आर्थिक, फर्म एवं राजनैतिक आधारित संरचना की व्याख्या करते हैं। इन्हें विभिन्न डाटा स्रोतों से एकत्रित किया गया है। इन स्रोतों के वर्ष 1991, 2001, 2011 सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना, 2012, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, (पीएमजीएसवाई) सार्वजनिक डाटा शामिल किए गए हैं ताकि उन संकेतकों की रचना की जा सके जो भारत के प्रत्येक जिले के सामाजिक एवं भौतिक आधारित संरचना की व्याख्या करते हैं।

अन्य देशों से तुलना के लिए हम उद्यमिता विश्व बैंक के ईओडीवी उद्यमिता आंकड़ों का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र को छोड़कर सभी देशों के लिए करते हैं। संयुक्त राष्ट्र (यूएस) हेतु यूएस संसेक्स ब्यूरो के व्यापार स्थापना सूचकांक (बीएफएस) का प्रयोग करते हैं।

2.2 प्रति व्यक्ति के आधार पर भारत की औपचारिक अर्थव्यवस्था में उद्यमिता दरें निम्न हैं। वर्ष 2006 से 2016 के बीच प्रति 1000 कामगार प्रति वर्ष पंजीकृत नई फर्मों की औसत माध्यिका संख्या 0.10 (0.11) थी। इसके विपरीत इंग्लैंड एवं अमेरिका की औसत माध्यिका उद्यम तीव्रता क्रमशः 12.22 (11.84) एवं 12.12 (11.81) थी। सामान्य रूप में, विकसित अर्थव्यवस्थाओं की उद्यम तीव्रता सार्थक दृष्टि से ऊंची हैं। ब्राजील, जिसमें वर्ष 2010 से 2018 के बीच महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है, को छोड़कर यह सभी देशों में वृद्धि की ओर अग्रसर है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अन्य देशों की तुलना में, भारत के काफी अधिक उद्यम अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में प्रचलित होते हैं, जिनका आंकड़ा इनमें शामिल नहीं किया गया है। उद्यम तीव्रता को सापेक्ष निम्न दरें होते हुए भी चित्र 2क में समय के साथ-साथ नई फर्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण वृद्धि दर

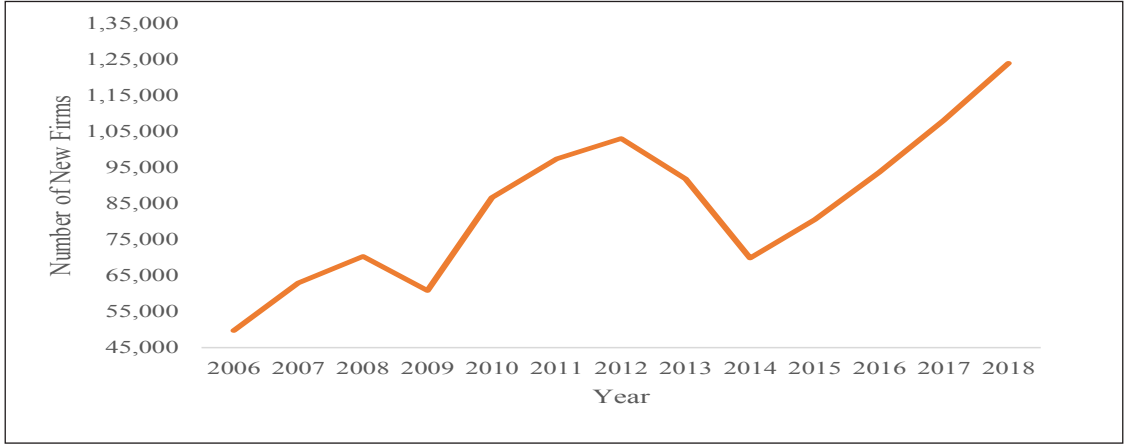
पायी गई है। चित्र 2ख यह दर्शाता है कि सेवा क्षेत्र में यह वृद्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह दर्शाता है कि भारत की नई आर्थिक संरचनाओं में सेवा क्षेत्र को तुलनात्मक लाभ प्राप्त है।

उद्यमिता एवं जीडीपी

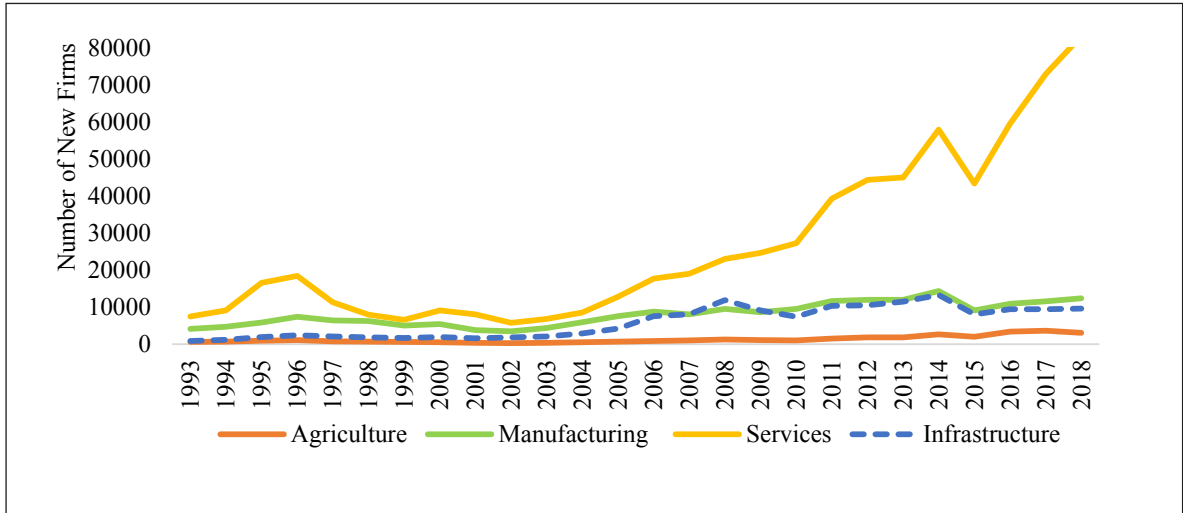
2.3 उद्यम क्रियाकलाप आर्थिक संवृद्धि से संबंधित है। इस संबंध के प्राक्कलन के विवरण बॉक्स 2 में देखें।

2.4 चित्र: 3क तीन वर्ष पूर्व के केंद्रित जिले में स्थापित नई फर्मों के प्राकृतिक लॉग पर सकल घरेलू जिला उत्पाद (जीडीपी) के प्राकृतिक लॉग की प्रतीपगमन के लिए प्रवृत्ति रेखा एवं प्रकीर्ण चित्रांकन को प्रस्तुत करता है। विशेष रूप में प्रति जिले में नई फर्मों के पंजीकरण में 10 प्रतिशत की वृद्धि से जीडीपी में 1.8 प्रतिशत वृद्धि होती है यह परिणाम इस बात पर बल देते

चित्र 2क: समय के साथ-साथ नई फर्मों में वृद्धि



चित्र 2ख: समय के साथ नई फर्मों की क्षेत्र-वार वृद्धि



स्रोत: एमसीए-21 और समीक्षा गणनाएं

बॉक्स 2: उद्यमिता एवं जीडीपी के बीच संबंध का आकलन

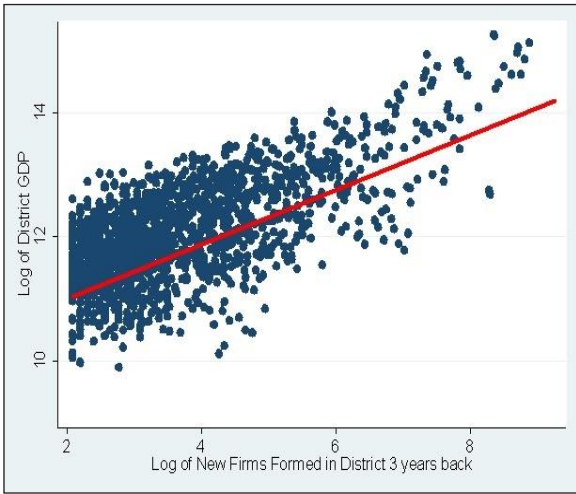
जिले में नई फर्मों की संख्या के अनुसार जिले की जीडीपी किस प्रकार परिवर्तित होती है, इसका पता लगाने के लिए हमने ओएलएस विनिर्देशन का क्रियान्वयन किया जो स्वतंत्र रूप में नई फर्मों की संख्या (प्राकृतिक लॉग में वर्तमान कीमतों पर) को जिले की जीडीपी (प्राकृतिक लॉग में चालू कीमतों पर) का प्रतीपगमन आकलन किया है। हमारे आमुख में कहा गया है कि आधारीक संरचना एवं पर्यावरण संबंधी अंतर मुख्यतः राज्य-वार परिवर्तित होते हैं, 17 समय आभासीचरों के साथ 21 राज्यों के निश्चित प्रभावों का प्रयोग किया गया है। इस संभाव्यता को न्यूनतम करने के लिए कि नई फर्मों की संख्या जिला स्तरीय जीडीपी की अंतर्जात है, जिले की नई फर्मों की पूर्व की संख्या तीन वर्ष का प्रयोग किया गया है। सारांश अनुमानित संबंध समीकरण इस प्रकार है:

$$\ln(District\ GDP_{it}) = \alpha + \beta(new\ firms_{i,t-3}) + X_i + \tau_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

उपर्युक्त 1 में i एवं t ज क्रमशः जिले एवं वर्ष का संकेत देती है, गप राज्य निर्धारित प्रभावों को तथा Tt वर्षानुगत स्थिर प्रभावों को निरूपित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि मानक त्रुटियां अधिवर्धित नहीं हो जाए, हमने जिला स्तर पर त्रुटियों को संगुच्छन कर लिया है।

हैं कि उद्यमिता का महत्व भारत की आर्थिक वृद्धि एवं परिवर्तन के इंजिन के रूप में है। चित्र 3ख: नये फर्मों की स्थापना में स्थानिक विसर्जन को दर्शाता है। हम यह पाते हैं कि प्रायद्वीप राज्यों का नये फर्मों के प्रवेश में प्रभुत्व है और उद्यमशीलता केवल कुछ महानगरों की ही सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे भारत में विखरा हुआ है।

चित्र 3क: जीडीपीपी पर उद्यम सम्बन्धी कार्यकलाप के प्रभाव का अनुमान



स्रोत: एमसीए-21 और समीक्षा गणनाएं

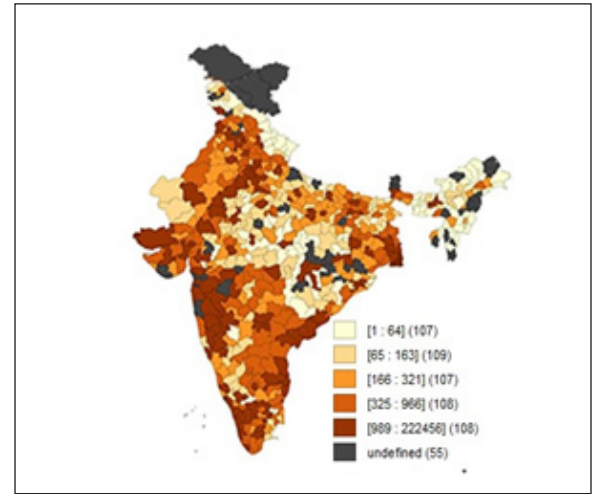
प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। यह उस दृष्टिकोण को खारिज करता है कि भारत में उद्यम क्रियाकलाप सिर्फ प्रेरक और रोजगार चुनावों की कमी के कारण नहीं है। बल्कि परिणाम यह दर्शाते हैं कि आगामी दशक में औपचारिक क्षेत्र में उत्पादकता और संवृद्धि निर्देशित उद्यम क्रियाकलाप महत्वपूर्ण होंगे। अन्य अनुत्पादक क्षेत्रों एवं निर्वाह उद्यमिता क्षेत्र से व्यवस्थित विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में श्रम के संचलन से भारत के उत्पादकता अंतरालों को समाप्त करने में मदद मिल सकती है। जब तक समान आकार की अर्थव्यवस्थाओं के सापेक्ष विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र अविकसित रहेंगे, तब तक व्यापक उद्यम क्रियाकलाप इन अंतरालों को समाप्त करने में मददगार साबित होंगे।

2.6 नीचे दिया गया चित्र 4ख भारत में चार क्षेत्रों के लिए उद्यम संबंधी कार्यकलापों में समय के अनुसार

उद्यम क्रियाकलाप में स्थानिक - विविधता

2.5 चित्र 4क जो सेक्टर द्वारा उद्यम क्रियाकलाप के प्रभुत्व के प्राक्कलन के लिए गुणांक प्लॉट को दर्शाता है, दर्शाता है कि नई फर्म प्रवेश का प्रभाव विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में सबसे अधिक है। निष्कर्ष इस बात पर बल देते हैं कि उद्यमिता आगामी दशकों में भारत की आर्थिक

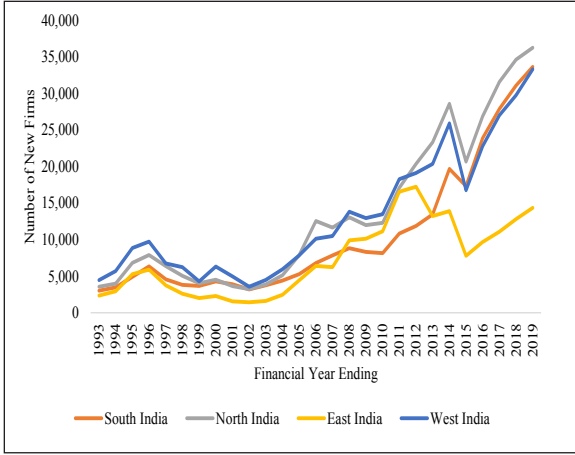
चित्र 3ख: क्षेत्र द्वारा उद्यम सम्बन्धी कार्यकलाप के प्रभाव में भिन्नताएं।



वृद्धि दर्शाता है पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी क्षेत्र समयोपरान्त उद्यम क्रियाकलापों में मजबूत वृद्धि दर्शाते हैं उद्यम-संबन्धी कार्यकलाप के स्तर की परवाह किए बिना सभी क्षेत्र उद्यम तथा उद्यम के व्यापक लाभ से परिचय कराने वाले जीडीपी के मध्य मजबूत सम्बन्ध को दर्शाते हैं।

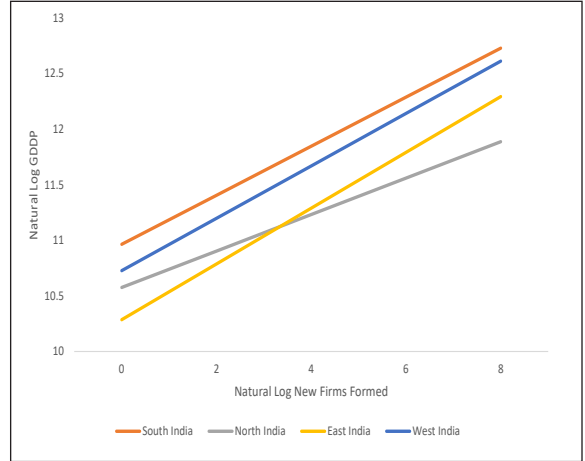
2.7 फिर प्रत्येक जिला क्षेत्र के लिए एक सूचक का आंकलन किया जाता है जो यह दर्शाता है कि उस क्षेत्र की उद्यमिता क्षमताएं विभिन्न जिलों में किस प्रकार विभाजित है। किसी भी क्षेत्र के लिए यह सूचक उस क्षेत्र में स्थापित नई फर्मों में संबद्ध जिले का अंश और जिले में स्थापित सभी नई फर्मों का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए यदि एक जिले में कृषि क्षेत्र की 20 प्रतिशत नई फर्म स्थापित करने की जिम्मेदारी थी, किन्तु सभी स्थापित नई फर्मों में से केवल 10 प्रतिशत

चित्र 4क: समय के साथ क्षेत्रों में नई फर्मों में वृद्धि

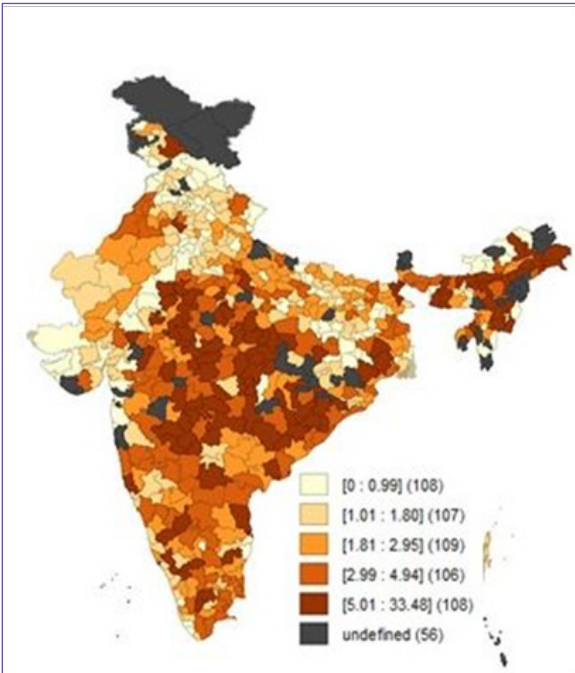


स्रोत: एमसीए-21 और समीक्षा गणनाएं

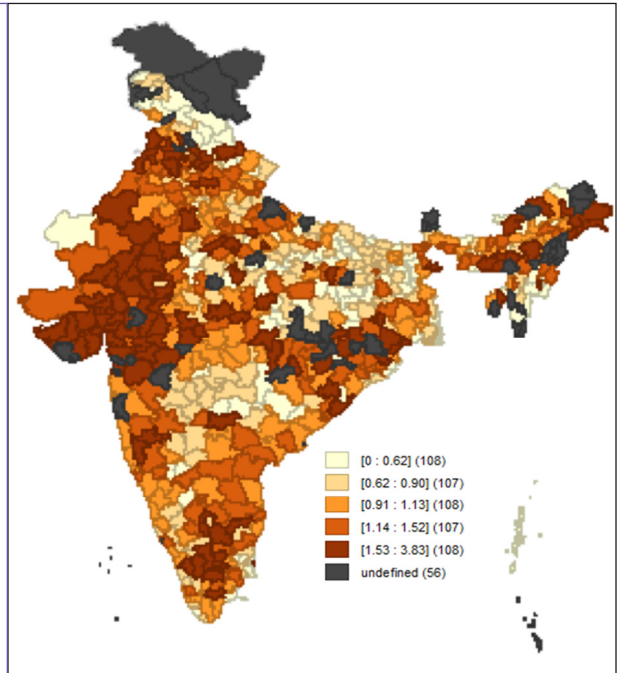
चित्र 4(ख) क्षेत्रों वार उद्यमिता गतिविधियों के प्रभाव में अंतर



चित्र 5(क) कृषि क्षेत्र में विभिन्न जिलों की सापेक्ष उद्यमिता क्षमता



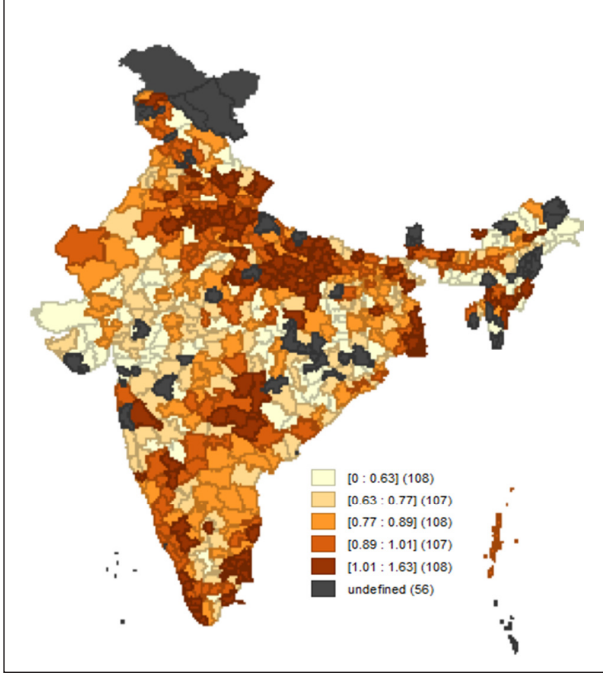
चित्र 5(ख) विनिर्माण क्षेत्र में विभिन्न जिलों की सापेक्ष उद्यमिता क्षमता



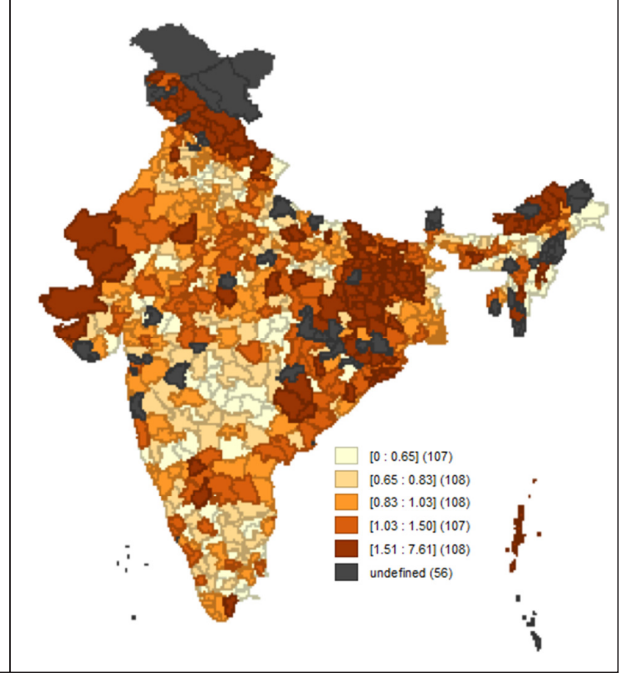
को यह मान 2 कृषि क्षेत्र में सापेक्ष उद्यम क्रियाकलाप का एक सूचक तो यह उस क्षेत्र की सापेक्ष शक्ति को दर्शाता है। चित्र 5क से 5घ क्रमशः कृषि, विनिर्माण, सेवा और अवसंरचना के सूचकों के जिलेवार सापेक्ष वितरण दिखा रहे हैं।

2.8 चित्र 5 क बताता है कि विनिर्माण, सेवाओं तथा अवसंरचना, की उद्यमी क्षमताओं की भांति कृषि उद्यमी क्षमताओं में भौगोलिक रूप में स्थानीय नहीं है और यह देश भर में समान रूप से वितरित है। कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित उद्यमी कार्यकलाप के उच्चतम क्विन्टाइल राज्य मणिपुर, मेघालय, मध्य प्रदेश, असम, त्रिपुरा तथा

चित्र 5(ग) सेवा क्षेत्र में विभिन्न जिलों की सापेक्ष उद्यमिता क्षमता



चित्र 5(घ) बुनियादी ढांचों में विभिन्न जिलों की सापेक्ष उद्यमिता क्षमता



स्रोत: एमसीए-21 और समीक्षा गणनाएं

उड़ीसा हैं। उत्तर-पूर्व में स्थापनाएं खाद्य व्यापार में सम्भवतः निजी उद्यमों के हाथ में होंगी जैसे कि जैविक उत्पाद तथा चाय के बागान। यद्यपि मध्य प्रदेश तथा उड़ीसा में स्थापनाओं की बहुलता किसान उत्पादक कम्पनियां हैं, जो सहकारी समितियों तथा निजी लिमिटेड कम्पनियों के मिश्रित स्वरूप की अभिकल्पना करती हैं और बाजार में किसानों में सौदेबाजी की ताकत में सामूहिक रूप से सुधार करती हैं।

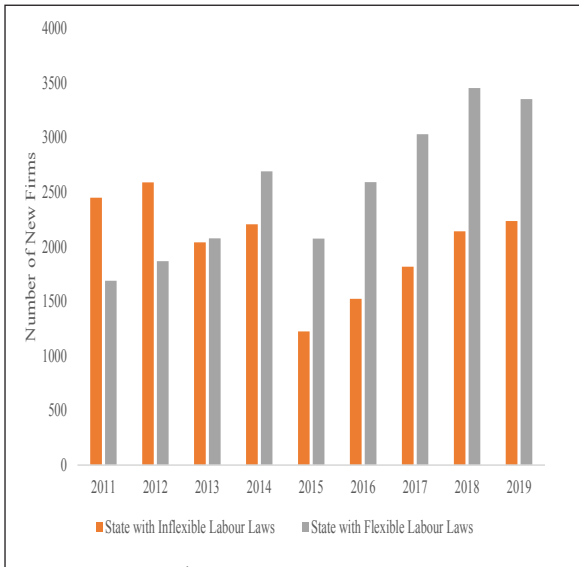
2.9 आंकड़ा 5ख सुझाता है कि गुजरात, मेघालय, पुदुचेरी, पंजाब तथा राजस्थान में विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमी कार्यकलाप उच्चतम हैं। गुजरात राज्य में विनिर्माण क्षेत्र में सर्वाधिक उद्यमी कार्यकलाप वाले जिले सुरेन्द्रनगर, राजकोट, भावनगर तथा सूरत हैं। इन क्षेत्रों में स्थापनाएं टैक्सटाइल, रसायन, धातु, प्लास्टिक तथा दवा निर्माण पर केन्द्रित हैं। प्रत्येक क्षेत्र में इन स्थापनाओं द्वारा (गनी और अन्य 2011) के शोध में प्रमाणित भारतीय विनिर्माण क्षेत्र के संदर्भ में समूहन की अर्थव्यवस्थाओं की पुष्टि होती है। यह आगत तथा उत्पाद के लिए परस्पर निर्भर औद्योगिक संरचनाएं हैं तथा किसी क्षेत्र

में विशिष्ट श्रमिक उस उद्योग-क्षेत्र में उच्चतम उद्यम कार्यकलाप से मजबूती से जुड़े हुए हैं।

2.10 विनिर्माण क्षेत्र में स्थान विषयक विविधता नीति की आवश्यकता पर जोर डालती है जो व्यापार करने की सुगमता में सुधार करती है। यह उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र में उद्यमी कार्यकलाप के उच्चतम क्विन्टाइल में तीन क्षेत्र गुजरात, पंजाब तथा राजस्थान पूर्व आर्थिक समीक्षा में लचीले श्रम कानूनों वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत थे। इसके अतिरिक्त, वे जहां श्रम कानून लचीले नहीं हैं, ऐसे राज्य जैसे पश्चिम बंगाल, असम, झारखण्ड, केरल तथा बिहार उद्यमी कार्यकलाप के न्यूनतम क्विन्टाइल में वर्गीकृत थे। वैसे गुजरात के श्रम सुधार को कामगार हितैषी के रूप में देखा जाता है। राज्य ने अन्य विनियमों को भी पारित कर दिया है जो अनुवृत्ति भार में कटौती, अनुमोदन की पारदर्शी तथा समयबद्ध प्रक्रिया तथा नवीकरण आवेदनों के साथ-साथ व्यापार करने की सुगमता तथा अन्य के बीच विनिर्माण लाइसेंस को स्वीकार करने तथा नवीकरण के लिए निर्धारित समय सीमा के में कटौती को सुदृढ़ करता है।

राजस्थान ने भी बहुत से सुधार किए हैं जो कि नियोजकता हितैषी के रूप में देखे जाते हैं। उदाहरणार्थ, व्यापार संघ के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य ने संघ बनाने के लिए पूर्व में 15% से बढ़कर स्थापना में कुल श्रमशक्ति के 30% के रूप में न्यूनतम सदस्यता आवश्यकता बढ़ा कर संघ निर्माण की लागत को बढ़ाया है। इसी तरह, राज्य ने कहा है कि 100 कामगारों की पूर्व सीमा से बढ़कर 300 लोगों तक रोजगार देने वाली कंपनियों में संघों की छंटनी अथवा बंद करने के लिए पूर्व संघों से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। कामगार केवल तीन वर्ष की अवधि के भीतर भी गलत तरीके से सेवा समाप्ति पर आपत्ति उठा सकता है प्रति वर्ष नई कंपनियों की माध्य संख्या में अंतर तथा प्रति वर्ष नई विनिर्माण कंपनियों की माध्य संख्या में लचीले श्रम कानूनों वाले राज्यों तथा कठोर श्रम कानूनों वाले राज्यों के बीच अंतर क्रमशः चित्र 6क एवं 6ख में प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 6(क): गैर शिथिलनीय और शिथिलनीय राज्यों के बीच नई स्थापित फर्मों की तुलना

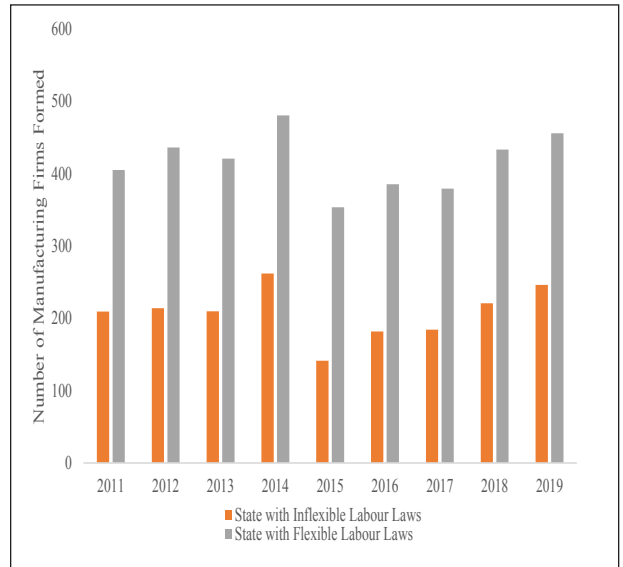


स्रोत: एमसीए-21 और समीक्षा गणनाएं

2.11 विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमी गतिविधियों के उच्चतर आर्थिक योगदान को देखते हुए यह उन नीतिगत उत्तोलकों पर विचार करने के लिए राज्यों हेतु महत्वपूर्ण है जोकि इन अपेक्षाकृत अधिक उत्पादक स्थापनाओं को कम उत्पादक क्षेत्र तथा अनौपचारिक क्षेत्र में निर्वाह गतिविधियों से श्रम का गमन सुकर बनाते हैं।

2.12 चित्र 5ग सुझाता है कि सेवा क्षेत्र में उद्यमी गतिविधि दिल्ली, मिजोरम, उत्तर प्रदेश, केरल, अंडमान निकोबार तथा हरियाणा के क्षेत्रों में सबसे अधिक है। पूर्व अनुसंधान (घानी एवं अन्य) के अवलोकन से संगत, इन क्षेत्रों में स्थापनाओं का स्वरूप संकुलन की मितव्ययता नहीं दिखा रहा है तथा यह विविध उद्योगों में जैसे कि व्यापार, वित्तीय सेवाएं, पर्यटन, एवं मेजबानी सेवाएं, खुदरा बिक्री, तथा धार्मिक संघटन एवं मिशनों में फैला है।

चित्र 6(ख): शिथिलनीय और गैर-शिथिलनीय राज्यों के बीच नई स्थापित विनिर्माण फर्मों की तुलना



2.13 चित्र 5घ सुझाता है कि अवसंरचना क्षेत्र में उद्यमी गतिविधि झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, जम्मू एवं कश्मीर तथा बिहार के राज्यों में

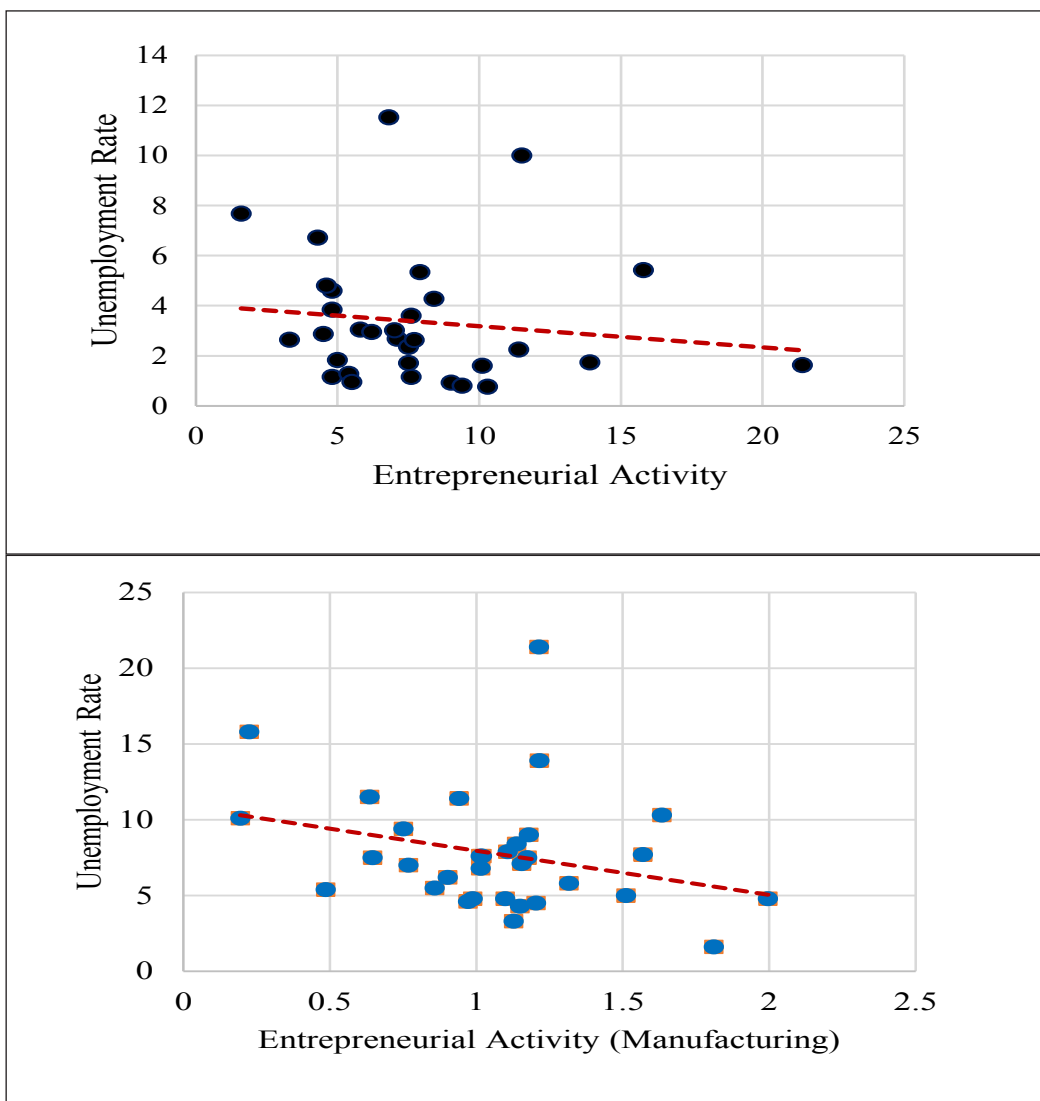
सबसे अधिक है जिनमें से कुछ विद्यमान अवसंरचना के खराब स्तर के लिए जाने जाते हैं। निस्संदेह, इन राज्यों में अधिकतर नई कंपनियां निर्माण, संधारिकी एवं

परिवहन, सुविधा सृजन, पारोषण एवं वितरण, वैकल्पिक ऊर्जा वितरण, एवं इंफ्रास्ट्रक्चर में लगी हुई है।

2.14 जिलों में उद्यमी गतिविधि का स्वरूप महत्वपूर्ण रूप से जिले में बेरोजगारी से सहसंबंधित है। आवधिक श्रम सर्वेक्षण (पीएलएफएस) आंकड़ों द्वारा यथा, मापी गई, कृषि एवं विनिर्माण क्षेत्र उद्यमी गतिविधि राज्यों में बेरोजगारी की दर के साथ क्रमशः -0.26 तथा -0.29 के सह संबंध हैं। इसके विपरीत, सेवाएं एवं अवसंरचना क्षेत्र में उद्यमी गतिविधि राज्यों में बेरोजगारी से क्रमशः 0.36 एवं 0.09 के सकारात्मक स्थानिक सहसंबंध पाए

गए हैं। ये अनुमान विशेषकर प्रमुख है क्योंकि सेवा क्षेत्र (14.475) में एकल व्यक्ति नई कंपनियों की गतिविधि की संख्या अन्य सभी तीनों क्षेत्रों में संयुक्त (2785) से पांच गुणा अधिक है। जीडीपी में उद्यमी गतिविधि की इस श्रेणी का योगदान भी महत्वहीन है। अतः कंपनियों के इस वर्ग के निष्पादन एवं उत्पादकता सुधारने के नीतियां सुझाने वाला शोध कार्य बहुत महत्वपूर्ण होगा। बेरोजगारी दर के साथ विनिर्माण में उद्यमी गतिविधि तथा संपूर्ण उद्यमिता के बीच सहसंबंध नीचे चित्र 7 में प्रस्तुत किया गया है।

चित्र 7: संपूर्ण उद्यमी गतिविधि और विनिर्माण उद्यमी गतिविधि के बेरोजगारी से सहसंबंध



स्रोत: एमसीए-21, पीएलएफएस और समीक्षा गणनाएं

उद्यमी गतिविधि के निर्धारक तत्व

2.15 स्वाभाविक प्रश्न जो कि प्रमुख स्थानिक विविधता के प्रलेखीकरण का अनुपालन करता है कि कौन से घटक हैं जो ऐसी विविधता को बढ़ाते हैं। इस तरह, इस संदर्भ में (बाक्स 3 देखें) अनुसंधनों के निष्कर्ष को सारांशित किया गया है तथा तदुपरांत भारत में नई कंपनियों के प्रवेश के चालक की जांच की गई है। बहरहाल पूर्व अनुसंधान नई कंपनियों के जन्म में स्थानीय जनसंख्या विशेषताओं, जिला स्तरीय परिस्थितियों तथा सामूहिक अर्थव्यवस्था को समाहित करते हैं, यह विश्लेषण जिला स्तरीय परिस्थितियों तक सीमित है जो कि सरकार हेतु महत्वपूर्ण नीतिगत उत्तोलक का प्रतिनिधित्व करता है।

2.16 जिला स्तरीय विशेषताओं के दो प्रमुख समुच्चय पर ध्यान केन्द्रित करना है जोकि जिला सामाजिक एवं वास्तविक अवसंरचना में उद्यमी गतिविधि के स्तर को आगे बढ़ाते हैं। हालांकि ये पूरी सूची का निर्माण नहीं करती है। ये भारत में उद्यमिता एवं आर्थिक विकास पर पूर्व अनुसंधान में वृहत्त रूप से प्रमुख रूप से प्रस्तुत की गयी है। जिले में सामाजिक अवसंरचना के ये उपाय जिले में सामान्य शिक्षा स्तर से अधिक संबंध रखते हैं। जिले में उच्चतर शिक्षा स्तर बेहतर मानव पूंजी के विकास को समर्थ बनाते हैं जो कि विचार एवं उद्यमी की बढ़ी आपूर्ति से संबंध रखता है। अतः यह अनुमानित है कि बेहतर शिक्षा वाले जिलों में उच्चतर उद्यमी गतिविधि होगी। जिले में महाविद्यालयों की संख्या तथा साक्षर जनसंख्या का अनुपात जिले में शिक्षा अवसंरचना मापने के लिए उपयोग किया जाता है।

2.17 भौतिक आधारिक संरचना के उपायों में भौतिक संयोजकता के साथ-साथ जिले में मूलभूत भौतिक आधारित संरचना तक पहुंच शामिल है जो ज्यादातर मामलों में जिले की आधारिक संरचना को साथ लेकर चलती है। एक जिले में भौतिक आधारित संरचना की पहुंच को जिले में पक्की सड़कों के अनुपात द्वारा मापा जाता है। यह उपाय बिजली, पानी/स्वच्छता सुविधाओं, और दूरसंचार सेवाओं जैसे अन्य सार्वजनिक वस्तुओं तक पहुंच के साथ सहसंबंधित है, जो सभी व्यवसायों के लिए मौलिक है। भौतिक संयोजकता को ऐसे जनसंख्या केंद्र से औसत दूरी के रूप में मापा जाता है जिसमें कम से कम 500,000 लोग होते हैं। बड़े जनसंख्या केंद्रों के निकटता से स्टार्टअप को बाजार तथा मापक संचालक में विस्तार करने की अनुमति मिलती है। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि ये दोनों उपाय उद्यमशीलता की गतिविधि के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करेगी। बाक्स 4 उस जिले में उद्यमशीलता की गतिविधि पर उस जिले की भौतिक और सामाजिक आधारिक संरचना के प्रभाव के आकलन के लिए कार्यप्रणाली का सार प्रस्तुत करता है।

2.18 जैसा कि उम्मीद की गई थी जिला में साक्षर जनसंख्या में वृद्धि में होने से उद्यमशीलता क्रियाकलापों में वृद्धि होती है जो नई फर्मों की संख्या द्वारा मापी जाती है। चित्र 8क दर्शाता है कि नई फर्मों की स्थापना में जो वृद्धि का नतीजा है। सर्वाधिक वृद्धि तब देखी गई जब साक्षरता दर 72 प्रतिशत तक बढ़ी। यह दर्शाता है कि साक्षरता दर की वृद्धि में कमी कोई मायने नहीं रखती। बावजूद इसके, साक्षरता में सबसे अधिक वृद्धि

बाक्स 3: उद्यमी गतिविधि के प्रचालकों विषयक अनुसंधान का सार

यह अध्ययन जिला स्तरीय स्थिति पर ध्यान केन्द्रित करता है विशेष रूप से सामाजिक तथा भौतिक आधारित संरचना पर, जो विशेष रूप से उद्यमी गतिविधि को बढ़ावा देते हैं। तथापि पूर्व शोध कार्य के समृद्ध संकलन उद्यमी गतिविधि में विषमता के अन्य स्थानिक और औद्योगिक चालक कारकों की भूमिका पर जोर देता है। इनमें जनसंख्या की विशेषताएं, अन्य जिला स्तरीय परिस्थितियां, विनियामक ढांचे तथा संकुलन की मितव्ययताएं शामिल हैं। ये कारक अवसर, कौशल तथा उद्यम में उपलब्ध संसाधनों, फर्म सृजन तथा संवृद्धि (मिटेवस्टेड तथा केरी 2008) को प्रभावित करते हैं।

जनसंख्या का आकार और घनत्व जैसी स्थानीय जनसंख्या विशेषताओं की भूमिका विशेष रूप से नई फर्मों के लिए मुख्य है, जहां स्थानीय बाजारों को फर्म के प्राथमिक उत्पाद बाजार माना जाता है और जहां अधिकांश उद्यमी अपने निवास के क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। (डाहल और सोरेंसन 2007)। ऐसे मामले में, क्षेत्र का आकार स्थानीय बाजार के आकार और कुछ हद तक, उद्यमियों और प्रबंधकों की संभावित आपूर्ति को दर्शाता है। जनसंख्या घनत्व स्थानीय संसाधनों और उच्च संसाधन लागत

(उदाहरणतः मजदूरी और भूमि किराया) (गनी एट अल. 2011) के लिए प्रतिस्पर्धा जैसे अन्य संचालित मापदंडों को भी प्रभावित करता है। कुछ अध्ययन (कार्लिनो एट अल. 2007); अर्जनी और हेंडरसन 2008) सशक्त ज्ञान प्रवाह के घनत्व को भी महत्वपूर्ण बताते हैं, जो उद्यमशीलता की गतिविधि पर एक आनुभाषिक सवाल को प्रभावित करते हैं। शोधकर्ताओं (इवांस और लियटन 1989; बोनेट एट अल. 2009; ग्लेशियर और कर 2009) ने क्षेत्रीय आयु संरचना और उद्यमशीलता दर के बीच एक विलोम-यू-संबंध का प्रदर्शन किया है जो भारत के “जनसांख्यिकीय लाभांश” को दर्शाता है, जो इसे उद्यमिता के एक महत्वपूर्ण चालक के रूप में स्थापित करता है।

जब भौतिक आधारित संरचना और शिक्षा में जिला-स्तर के निवेश पर विचार किया जाता है, डिजिटल साक्षरता और प्रौद्योगिकी और वित्त तक उद्यमियों की सुलभ पहुंच जैसी अन्य विशेषताएं उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और नए उपक्रमों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए भी महत्वपूर्ण है। (इस साहित्य और केस अध्ययन की समीक्षा के लिए मित्तल और सेरी 2008 और गनी एट अल. 2011 देखें) वित्त में बाधाएं, विशेष रूप से जोखिम पूंजी (बनाम विकास पूंजी) तक पहुंचने में कठिनाई, अक्सर छोटे और सूक्ष्म फर्मों (मेकी 2019) पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

इस क्षेत्र में विनियामक ढांचे द्वारा भी उद्यमशीलता की गतिविधि बाधित हो सकती है जो प्रवेश और निकास सीमित प्रतिस्पर्धा और अनुपालन और प्रशासन की लागत में वृद्धि (समीक्षा के लिए ओईसीडी (1998) द्वारा उद्यमिता को बढ़ावा देना से संबंधित अध्ययन को देखें) द्वारा इसे बाधित कर सकता है। इस संदर्भ में पूर्व अनुसंधान द्वारा जिन प्रमुख मापदंडों को निहित किया गया है उनमें प्रवेश, प्रतिस्पर्धा नीति, दिवालियापन कानून, कर बोझ, प्रशासनिक और अनुपालन लागत और बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण के लिए विनियामक बाधाएं शामिल हैं।

जिला-स्तर की परिस्थितियों के अलावा, जो सभी उद्योगों को समान रूप से प्रभावित करती हैं, इन परिस्थितियों और विशिष्ट उद्योगों के बीच पारस्परिक क्रियाएं सिद्धांतों संकुलन (मार्शल 1920; ग्लेशियर और कर 2009) के रूप में मौजूद हैं। भारत के संदर्भ में गनी एट अल. (2011) विनिर्माण में संकुलन की मितव्ययताओं के काफी सबूत पाए जाते हैं जो फर्मों के बीच आदान-उत्पादन संबंधों पर जोर देते हैं।

ये सभी कारक प्रमुख तरीकों को दर्शाते हैं जिनमें नीति निर्माता उद्यमशीलता गतिविधि के स्थानिक वितरण को प्रभावित करते हैं।

बॉक्स 4: उद्यमशीलता के प्रचालकों का अनुमान

जिला में और एक बार ओएलएस प्रतिमान का उपयोग करते हुए उद्यमशीलता के प्रचालकों का पता लगाने के लिए जिले में पक्की सड़कों द्वारा जुड़े हुए गांवों का अनुपात साक्षर नेपेरियन, निकटतम जनसंख्या केन्द्र से जिले की दूरी, जिसकी जनसंख्या कम से कम 5,00,000 हो (नेपेरियन लॉग में दूरी) और जिले में महाविद्यालयों की कुल संख्या (नेपेरियन लॉग में महाविद्यालयों की संख्या) वर्ष ज में जिला प में नई फर्मों पर प्रतीपगमन है।

हमारे सभी आकलित किया गया है के कारक हालिया जनगणना पर आधारित है और जिले में जनसंख्या के घनत्व के (नेपेरियन लॉग में जनसंख्या का घनत्व)। नीचे समीकरण (2) में निरूपण नई फर्मों की संख्या संबंधी सामाजिक एवं भौतिक अवसंरचना के भिन्न पहलुओं के प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है:

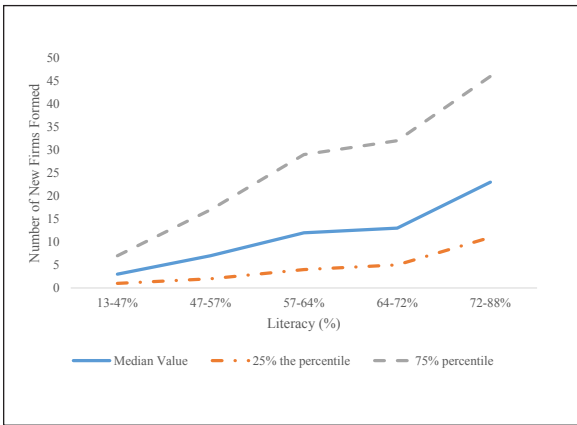
$$\begin{aligned} \ln(\text{newfirms}_{it}) = & \alpha + \beta_1 \ln(\text{roads}_{it}) \\ & + \beta_2 \ln(\text{colleges}_{it}) + \beta_3 \text{proportion literate}_{it} \\ & + \beta_4 \text{proportion connected}_{it} + X_i + \epsilon_{it} \\ & + \lambda_i + \epsilon_{it} \end{aligned} \quad (2)$$

समीकरण (2) अधोलेख प जिला का द्योतक है और ज जनगणना वर्ष का द्योतक है।-----जनगणना वर्ष प्रतिचर का द्योतक है और मानक त्रुटियों को जिला स्तर पर संगुच्छित किया जाता है।

तो उस समय होती है जब साक्षरता का स्तर पहले से ही उच्च हो, विशेष रूप से 72 वें शतमक से अधिक।

2.19 महाविद्यालयों की संख्या के साथ भी यही दृश्य दिखाई देते हैं यद्यपि विभिन्नताओं के साथ चित्र 8 ख उन दर्शाता है कि जो जिले जिनका महाविद्यालयों की संख्या के पृथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचमक में है, उनके पंचमक माध्य मूल्य वार्षिक रूप से 2,4,5,11 और 24 नए फर्मों से संबंधित है। तथापि, साक्षर जनसंख्या के अनुपात के विपरीत सबसे अधिक वृद्धि

चित्र 8 क: शिक्षा और उद्यमिता

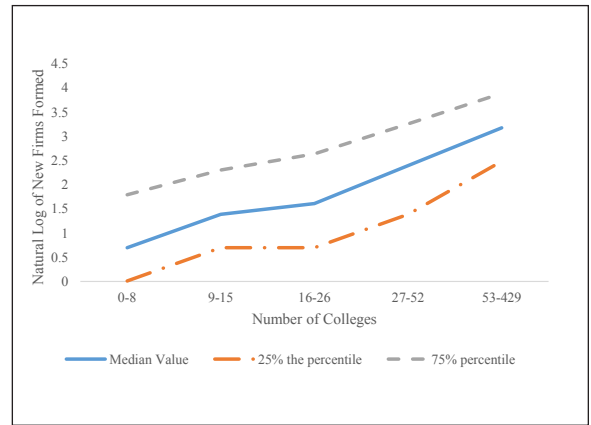


स्रोत: एम सी ए-21 एसएचआरयूजी और समीक्षा गणनाएं

40वें-60वें और 60वें-60वें शतमक के बीच प्रतीत होती है जो यह दर्शाता है कि उद्यमशीलता में सबसे अधिक वृद्धि तब होती है जब में जिले में महाविद्यालयों की संख्या मध्यवर्ती है। कुल मिलाकर चित्र 8क और 8ख के परिणाम दर्शाते हैं कि बेहतर उद्यमशीलता के साथ साक्षरता के उच्च स्तरों और बेहतर शिक्षा संरचना का संबंध है।

2.20 चित्र 9 क और 9ख में बाक्स चित्रण यह सुझाव देता है कि बाजारों में प्रवर पहुंच भी उच्चतर उद्यमिता

चित्र 8ख: महाविद्यालयों की संख्या और उद्यमिता



बॉक्स 4: बाक्स--विषय-वस्तु

बाक्स की विषय-वस्तु रुचि स्वतंत्र चरों को कैसे वितरित किया गया है को उनके वर्गों पर आधारित पांच भागों में बाटती है--सबसे निम्नतम पंचमक, 20वीं-40वीं शतमक, 40वीं-60वीं शतमक, 60वीं-80वीं शतमक और अधिकतम शतमक। हर वर्ग के अन्तर्गत यह आश्रित चर की कीमत को ढूंढता है, ऐसी स्थिति में, नई फर्मों की संख्या निम्नलिखित मानों तक पहुंच जाती है।

(क) क्षैतिज रेखा द्वारा न्यूनतम को दर्शाया गया है (ख) चतुर्भुज की नीचे की रेखा को पहला पंचमक दर्शाता है (ग) एक वर्ग के चतुर्भुज के अन्दर की नीली रेखा माध्यमिका को दर्शाता है (घ) एक वर्ग के चतुर्भुज की ऊपरि रेखा को तीसरा चतुर्थक है दर्शाता और (ङ) ऊपरि मुख्य क्षैतिज रेखा अधिकतम को दर्शाता है। बाक्स विषय वस्तु यह दिखाता है कि कैसे एक वर्ग से अन्य में जाने से दिए हुए वर्ग के अन्तर्गत स्वतंत्र चर के अलग मानों के लिए नई फर्मों की संख्या में परिवर्तन हो जाता है।

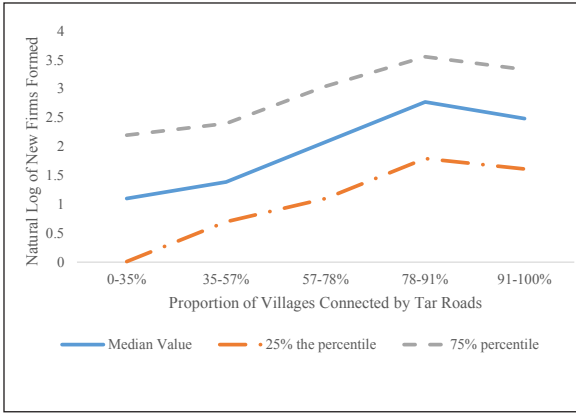
क्रियाकलाप से संबंधित है। चित्र 9क गावों की संख्या जो एक जिले में पक्की सड़क से जुड़ी हुई है उसके प्रभाव को दिखा रहा है, जिसे “कनेक्टिविटी” नाम दिया गया। चित्र दिखाता है कि जब तक संपर्क 9 प्रतिशत

तक बढ़ता है, इसका अर्थ है कि जिले के 91 प्रतिशत गाँव टार रोड़ से जुड़े हुए हैं। फर्म की संख्या एक समान बढ़ती है। भौतिक कनेक्टिविटी से इन परिणामों में से घटने की प्रक्रियाखजब स्थानीय बाजार में पहुंच एक

सीमा से अधिक हो जाए, तब प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ सकता है और यह संभवतः उद्यमिता क्रियाकलापों को हतोत्साहित कर सकता है। इसी प्रकार से, एक सीमा से परे अवसंरचना विकास का बढ़ा हुआ स्तर क्षमतावान

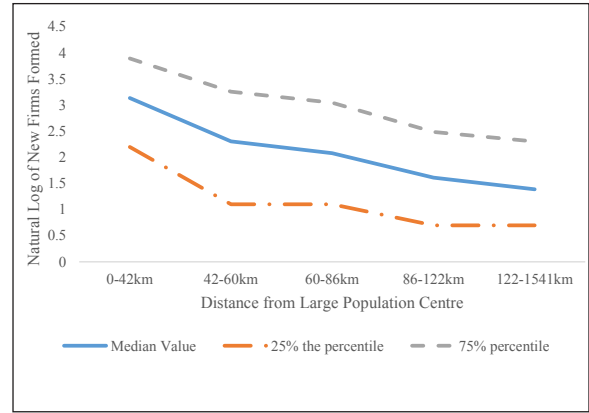
उद्यमियों के लिए अन्य अवसर खोल सकती है और जिसके फलस्वरूप उसके उद्यमी बनने की प्रेरणाएं कम हो जाती हैं।

चित्र 9क बाजार तक पहुंच और उद्यमिता



स्रोत: एमसीए-21, एसएचआरयूजी और समीक्षा गणनाएं

चित्र 9ख बड़े जनसंख्या केन्द्रों से दूरी और उद्यमिता



2.21 इसी प्रकार के स्वरूप चित्र 9ख में भी देख जा सकते हैं। चित्र 9ख जिलों की बाजार से निकटता के प्रभाव को दिखाता है जो कम से कम 500000 की जनसंख्या के केंद्र के निकटतम हो। वह जिले जो बाजार की निकटता के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवे पंचमक में हो उन्हें यह चित्र दर्शाता है, इस पंचमक के अन्तर्गत आए माध्यमिका है। मूल्य फर्म से संबंधित है। हम चित्र 9ख में यह भी नोट करते हैं कि जैसे हम पंचमक के चारों घूमते हैं वैसे ही कमी की दर में भी गिरावट आने लगती है। उदाहरण के लिए, नई फर्मों की संख्या का अन्तर साठवे-अस्सीवे शतमक की माध्यिका मूल्य से संबंधित है। इसी प्रकार से, नई फर्मों की संख्या में अन्तर साठवी-अस्सीवी परसेन्टाइल की माध्यिका मूल्य संबंधित है और उच्चतम पंचमक भी बहुत छोटा है। कुल मिलाकर, चित्र 9क और 9ख यह सुझाव देते हैं कि प्रवर भौतिक अवसंरचना उद्यमिता क्रियाकलाप को बढ़ाने में सहयोग देगी। यद्यपि, इससे भी यह सुझाव मिलता है कि अधिक सुधार से उद्यमिता में शिथलन भी आ सकता है। एक सीमा के पश्चात, स्थानीय बाजार में बढ़ती पहुंच अत्यधिक प्रतिस्पर्धा ला सकती है और उद्यमिता को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा,

साक्षरता में वृद्धि या शिक्षा अवसंरचना में सुधार के साथ ऐसा कोई द्वासमान प्रतिफल प्रतीत नहीं होता है। नए विश्वविद्यालयों की स्थापना एवं साक्षरता दर का बढ़ना फर्म की संख्याओं में एकसमान बढ़ोतरी को दर्शाता है।

तेज रफ्तार उद्यमिता एवं धन सृजन हेतु नीति निर्धारण

2.22 विश्लेषण से नया एक चित्रण उभर कर आता है। विश्व में उद्यमिता के लिहाज से तीसरा सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होने के बावजूद, अन्य देशों से तुलना की जाए तो लगता है कि भारत में प्रति व्यक्ति आधार पर औपचारिक उद्यमिता की दर अपेक्षाकृत कम है। प्रचलित ज्ञान के अनुसार, पाया गया कि जिले में खुलने वाली नई कंपनियों की संख्या और उस जिले की जीडीडीपी के बीच महत्वपूर्ण संबंध है। नई कंपनियों के पंजीकरण में 10 प्रतिशत वृद्धि का संबंध जीडीडीपी में 1.8 प्रतिशत वृद्धि से है। जीडीडीपी में उद्यमिता कार्यकलाप का यह योगदान विनिर्माण और सेवा सेक्टरों के लिए सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त, जिलों के बीच उद्यमिता कार्यकलाप में महत्वपूर्ण विविधता दर्शाती है कि ऐसी विविधता ज्ञात करने में सामाजिक और भौतिक

अवसंरचना द्वारा अहम भूमिका निभाई गई है। उदाहरण के लिए 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत के पूर्वी भाग में साक्षरता दर सबसे कम लगभग 59.6% है। इसी क्षेत्र में औपचारिक उद्यमिता कार्यकलाप भी सबसे कम हैं। अतः अध्याय में विश्लेषण निम्नलिखित निहितार्थों को परिलक्षित करता है।

2.23 सर्वप्रथम, अधिक विद्यालयों तथा महाविद्यालयों की संस्थापना के जरिए साक्षरता के स्तर में वृद्धि करने संबंधी उपायों से लोग उद्यमिता के लिए प्रेरित होंगे और फलस्वरूप स्थानीय संपदा में वृद्धि होगी। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यातों [अरोड़ा एवं बैज, 2011] में इंजीनियरी कॉलेजों के निजीकरण के सफल योगदान के पश्चात्, सरकारें शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण क्षमता की वृद्धि करने के लिए शिक्षा के निजीकरण के विकल्प पर भी विचार कर सकती है।

2.24 दूसरे तारकोल की सड़कों के माध्यम से गांवों तक बेहतर सड़क संपर्क से संभावना है कि स्थानीय बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी तथा उद्यमिता कार्यकलापों में सुधार

आएगा। तथापि, प्राथमिकता के लिहाज से यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि शिक्षा में निवेश। इसके अतिरिक्त, यह भी हो सकता है कि स्थानीय बाजारों तक पहुंच बढ़ाने से अन्य प्रकार के अवसर सृजित हो जाएं जिनसे उद्यमिता निरूत्साहित हो जाए। इसलिए अवसंरचना में निवेश, विशेषकर जो उद्यमिता संबंधी कार्यकलापों में वृद्धि हेतु किया गया है, का मूल्यांकन इस बात को समक्ष रखकर किया जाना चाहिए कि कैसे बेहतर अवसंरचना से अन्य तरह के अवसरों का सृजन होता है जो संभवतः जिले की जीडीडीपी के लिए अहम हों।

2.25 तीसरे, जो नीतियां कारोबारी सुगमता तथा लचीले श्रम विनियमों को प्रोत्साहन देती हैं, उद्यमिता कार्यकलापों, विशेषकर विनिर्माणकारी सेक्टर के कार्यकलापों को प्रोत्साहन प्रदान करेंगी। चूंकि विनिर्माण सेक्टर में अधिकतम रोजगार सृजन करने की क्षमता है, इसलिए रोजगार सृजन प्रोत्साहन हेतु राज्यों को कारोबारी सुगमता और लचीले श्रम विनियमों को सामर्थ्यशील बनाने पर ध्यान केन्द्रित करना होगा।

अध्याय एक नजर में

- यह अध्याय भारत में 500 से अधिक जिलों में प्रशासनिक परिमामिड के धरातल पर सामग्री और उद्यमशीलता गतिविधि के संचालकों की समीक्षा करता है। विश्लेषण कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय (एमसीए)-21 के आंकड़ों के अनुसार इन सभी जिलों में औपचारिक क्षेत्र में नई फर्म के निर्माण हेतु व्यापक आंकड़े प्रदान करता है।
- सर्वप्रथम, उद्यमिता पर विश्व बैंक के आंकड़ों का उपयोग करते हुए, यह अध्याय इस बात की पुष्टि करता है कि भारत नई फर्मों के निर्माण के मामलों में तीसरे स्थान पर है। इसी आंकड़े से पता चलता है कि 2014 से भारत में नई फर्म का निर्माण प्रभावशाली रूप से बढ़ा है। 2006-2014 के दौरान औपचारिक क्षेत्र में नई फर्मों की संख्या 3.8 प्रतिशत के संचयी वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ी जबकि 2014 से 2018 तक विकास दर 12.2 फीसदी रही। नतीजतन, 2014 में बनाई गई लगभग 70,000 नई फर्मों से, 2018 में नई फर्मों की संख्या लगभग 80 प्रतिशत बढ़कर 1,24,000 हो गई है।
- दूसरा, सेवा क्षेत्र में भारत की नई आर्थिक संरचना, यानी तुलनात्मक लाभ को दर्शाते हुए, सेवाओं में नई फर्म का निर्माण विनिर्माण, बुनियादी ढांचे या कृषि की तुलना में काफी अधिक है।
- तीसरा, जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता केवल आवश्यकता से प्रेरित नहीं है क्योंकि जिले में नई फार्मों के पंजीकरण में 10 प्रतिशत की वृद्धि के कारण जीडीडीपी में 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार, प्रशासनिक पिरामिड के निचले स्तर में उद्यमशीलता का एक जिले का जमीनी स्तर पर संपत्ति सृजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जीडीडीपी पर उद्यमशीलता की गतिविधि का यह प्रभाव विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों के लिए अधिकतम स्तर पर है।
- चौथा, नई कंपनियों का निर्माण भारतीय जिलों और क्षेत्रों में बहुत विषम है। इसके अतिरिक्त, यह स्थिति पूरे भारत में फैली हुई है, केवल कुछ शहरों तक ही सीमित नहीं है।
- पांच, एक जिले में शिक्षा स्थानीय उद्यमिता को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत के पूर्वी भाग की साक्षरता दर न्यूनतम, 59.6 प्रतिशत है। यह वह क्षेत्र है जिसमें नई फर्मों का निर्माण न्यूनतम है। वस्तुतः उद्यमिता पर साक्षरता का प्रभाव उस समय अत्यधिक उल्लेखनीय होता है जब यह 70 प्रतिशत से ऊपर हो।

- छठा, एक जिले में स्थानीय शिक्षा स्तर और भौतिक अवसंरचना की गुणवत्ता नये फर्मों के सृजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखते हैं।
- अंत में, वह नीतियां जो व्यापार करने में सुगमता प्रदान करती हैं और श्रम अधिनियम जो नये फर्म सृजन में सक्षम हो, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र में। अतः विनिर्माण क्षेत्र में हमारे युवाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं और व्यापार सुगमता के बढ़ाने से तथा लचीली श्रम नीति अपनाने से जिलों में और पूरे देश में अधिकतम रोजगार सृजित होंगे।
- शिक्षा, साक्षरता और भौतिक अवसंरचना अन्य नीतियां हैं जिसे जिला और राज्य प्रशासन को उद्यम विकास के लिए अपनानी चाहिए जिससे रोजगार और धन सृजन हो सके।

संदर्भ

- Arzaghi, M. and Henderson, J.V., 2008. Networking off madison avenue. *The Review of Economic Studies*, 75(4), pp.1011-1038.
- Bönte, W., Falck, O. and Heblich, S., 2009. The impact of regional age structure on entrepreneurship. *Economic Geography*, 85(3), pp.269-287.
- Carlino, G.A., Chatterjee, S. and Hunt, R.M., 2007. Urban density and the rate of invention. *Journal of Urban Economics*, 61(3), pp.389-419.
- Dahl, M. and Sorenson, O., 2007. Home sweet home: Social capital and location choice. *Social Science*, pp.1-22.
- Evans, D.S. and Leighton, L.S., 1989. The determinants of changes in US self-employment, 1968–1987. *Small Business Economics*, 1(2), pp.111-119.
- Ghani, E., Kerr, W. and O’Connell, S., 2011. Promoting entrepreneurship, growth, and job creation. *Reshaping Tomorrow*, pp.168-201.
- Glaeser, E.L. and Kerr, W.R., 2009. Local industrial conditions and entrepreneurship: how much of the spatial distribution can we explain?. *Journal of Economics & Management Strategy*, 18(3), pp.623-663.
- Meki, M., 2019, September. Microequity For Microenterprises: Evidence From An Artefactual Field Experiment And Survey. In *Economic Research Forum Working Papers* (No. 1348).
- Mittelstädt, A. and Cerri, F., 2008. Fostering entrepreneurship for innovation.
- OECD, 1998. Fostering entrepreneurship. *Industries Services and Trade*, 16(1), p.277.

परिशिष्ट

तालिका ए-1 नई फर्मों के नेपेरियन लॉग पर जीडीडीपी के नेपेरियन लॉग का ओएलएस प्रतीपगमन।

चर	(1) जीडीडीपी का लॉग	(2) जीडीडीपी का लॉग	(4) जीडीडीपी का लॉग
03 वर्ष पहले स्थापित नई फर्मों का लॉग	0.18*** (0.01)		
03 वर्ष पहले स्थापित नई कृषि का लॉग		0.03*** (0.00)	
03 वर्ष पहले स्थापित निर्माण फर्म का लॉग		0.07*** (0.00)	
03 वर्ष पहले सेवा क्षेत्र में स्थापित नई फर्मों का लॉग		0.07*** (0.00)	
03 वर्ष पहले बुनियादी क्षेत्रों में स्थापित नई फर्मों का लॉग		0.05*** (0.00)	
03 वर्ष पहले अन्य क्षेत्रों में स्थापित नई फर्मों का लॉग		0.04*** (0.01)	
दक्षिण भारत			10.96*** (0.05)
उत्तर भारत			-0.39*** (0.06)
पूर्व भारत			-0.68*** (0.07)
पश्चिम भारत			-0.24*** (0.06)
03 वर्ष पहले स्थापित दक्षिण भारत X नई फर्मों का लॉग			0.22*** (0.02)
03 वर्ष पहले स्थापित उत्तर भारत X नई फर्मों का लॉग			-0.06*** (0.02)
03 वर्ष पहले स्थापित पूर्व भारत X नई फर्मों का लॉग			0.03 (0.02)
03 वर्ष पहले स्थापित पश्चिम भारत X नई फर्मों का लॉग			0.02 (0.03)
स्थिरांक	10.66*** (0.02)	11.21*** (0.04)	
टिप्पणियां	5,591	5,591	5,591
आर-वर्ग	0.85	0.87	0.77
स्टेट स्थिर प्रभाव	Yes	Yes	No
वर्ष स्थिर प्रभाव	Yes	Yes	Yes
जिले स्तर पर संगुच्छित त्रुटियां	Yes	Yes	Yes

*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01

तालिका 1 2: वास्तविक और सामाजिक क्षेत्रों के उपायों पर नई फर्मों के प्राकृतिक लॉग का ओएलएस प्रतीपगमन

चर	(1) गठित की गई नई फर्मों का प्राकृतिक लॉग	(2) गठित की गई नई फर्मों का प्राकृतिक लॉग-कृषि	(3) गठित की गई नई फर्मों का प्राकृतिक लॉग-विनिर्माण	(4) गठित की गई नई फर्मों का प्राकृतिक लॉग-सेवा
पिछली जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व का प्राकृतिक लॉग	0.18*** (0.04)	0.09** (0.03)	0.16*** (0.04)	0.24*** (0.04)
पिछली जनगणना के अनुसार कॉलेजों का प्राकृतिक लॉग	0.74*** (0.09)	0.45*** (0.08)	0.69*** (0.10)	0.72*** (0.09)
पिछली जनगणना के अनुसार साक्षर जनसंख्या साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत	0.07*** (0.01)	0.03*** (0.01)	0.06*** (0.01)	0.08*** (0.01)
पिछली जनगणना के अनुसार तार की सड़कों के माध्यम से जुड़े गांव का प्रतिशत	0.02*** (0.00)	0.01*** (0.00)	0.02*** (0.01)	0.02*** (0.00)
पिछली जनगणना के अनुसार बिजली की पहुंच वाले गांव का प्रतिशत	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.01 (0.00)	0.00 (0.00)
जनसंख्या केंद्र से 500 के की औसत दूरी का प्राकृतिक लॉग	-0.15*** (0.05)	-0.16*** (0.03)	-0.18*** (0.05)	-0.16*** (0.05)
निरंतर	-6.11*** (0.67)	-5.96*** (0.51)	-7.47*** (0.72)	-7.92*** (0.67)
टिप्पणियां	5,337	5,337	5,337	5,337
आर-चुकता	0.53	0.44	0.43	0.56
राज्य निवल प्रभाव	मौजूद है	मौजूद है	मौजूद है	मौजूद है
जनसंख्या निवल प्रभाव	मौजूद है	मौजूद है	मौजूद है	मौजूद है
जिला स्तर पर हुई त्रुटियां	मौजूद है	मौजूद है	मौजूद है	मौजूद है

*p<0.10, **p<0.05, ***p<0.01

व्यापार समर्थक बनाम पक्षवाद

भारत की 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की आकांक्षा बाजार समर्थक नीतियों को गंभीरता से बढ़ावा देने पर निर्भर करती है जो एक और धन सृजन के लिए प्रतिस्पर्धी बाजारों की शक्ति को छूट देना चाहती है और दूसरी ओर उन 'व्यापार समर्थक' नीतियों से दूर रहती है जिससे निजी हितों, विशेषकर शक्तिशाली घरानों को बढ़ावा मिल सकता है। वर्ष 1991 के बाद की आर्थिक घटनाएं इस महत्वपूर्ण अंतर की मजबूत साक्षी हैं। शेयर बाजार, जो किसी भी अर्थव्यवस्था की नब्ज होता है, के दृष्टिकोण से देखने पर यह पता चलता है कि सुधार के पश्चात रचनात्मक विनाश में अत्यधिक वृद्धि हो गई है। उदारीकरण से पूर्व, एक संसेक्स फर्म, जिसके इस व्यवसाय में 60 वर्ष तक बने रहने की संभावना थी, वह उदारीकरण के पश्चात घटकर केवल 12 वर्ष तक रह गई। प्रत्येक पांच वर्षों में, एक तिहाई संसेक्स फर्मों में बदल जाती है। यह अर्थव्यवस्था में नई फर्मों, उत्पादों एवं प्रौद्योगिकियों के सतत अंतर्वाह को परिलक्षित करता है। प्रतिस्पर्धी बाजारों को सक्षम बनाने में प्रभावशाली प्रगति के बावजूद, व्यापार समर्थक नीतियों ने अर्थव्यवस्था में मूल्य का विनाश भी किया है। उदाहरण के लिए, राजनीति से संबद्ध फर्मों के इक्विटी सूचकांक ने एक आम नागरिक की कीमत पर असामान्य लाभ उत्सर्जित करते हुए वर्ष 2007-2010 के दौरान प्रतिवर्ष में बाजार से 7 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन किया। इसके विपरीत, राजनीतिक सांठ-गांठ के एक महत्वपूर्ण पर्दाफाश के कारण वर्ष 2010 के पश्चात् सूचकांक ने बाजार से 7.5 प्रतिशत कमजोर प्रदर्शन किया जो इन फर्मों की अक्षमता और इनमें अंतर्निहित मूल्य विनाश को दर्शाता है। वर्ष 2011 तक प्राकृतिक संसाधनों के विवेकाधीन आबंटन में परिलक्षित व्यापार समर्थक नीतियों के कारण लाभार्थियों द्वारा भाड़े की मांग की गई जबकि वर्ष 2014 के बाद उन्हीं संसाधनों के प्रतिस्पर्धी आबंटन से इस प्रकार की रेंट-सीकिंग व लॉबी प्रचार समाप्त हो गया। इसी प्रकार से, अंतरंग मित्रों को ऋण प्रदान करने के कारण स्वेच्छाकारी रूप से ऋण से ऋण का बकाया भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण प्रवर्तकों ने सामूहिक रूप से बैंकों से बेइमानी से पैसा निकाल लिया जिससे बैंकों को जो हानि हुई उसके समक्ष ग्रामीण विकास के लिए दिए जाने वाले अनुदान बहुत कम रह जाते हैं।

बाजार समर्थक, रचनात्मक विनाश एवं संपत्ति सृजन

3.1 वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से प्रतिस्पर्धी बाजारों को खुली छूट मिल गई। इससे रचनात्मक विनाश करने की शक्तियां सक्रिय हो गईं इनसे प्राप्त लाभों को हम आज भी देख रहे हैं। एस एवं पी बीएसई संसेक्स में अभिग्रहीत भारतीय इक्विटी बाजारों की दृष्टि से देखते हुए हम उदारीकरण के बाद

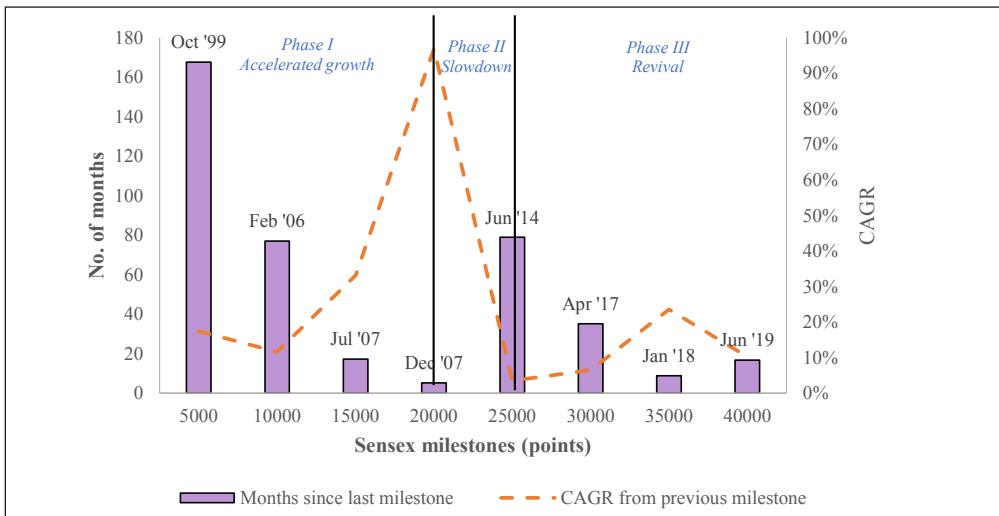
की अवधि में बाजार समर्थक भारत में बाजार की गत्यात्मकता में स्पष्ट वृद्धि देख सकते हैं। चित्र 1 से यह पता चलता है कि वर्ष 1991 के बाजार सुधारों के बाद संसेक्स में न केवल बढ़ोतरी हुई, अपितु, इसमें बती हुई गति से वृद्धि हुई। जहां एक ओर पहले 5000 अंकों की बढ़त के लिए 13 वर्ष लगे जो वर्ष 1999 में हासिल किया गया था, वहीं दूसरी ओर इतनी प्रत्येक बढ़त हासिल करने के लिए लगने वाले से समय में काफी कमी आ गई है।

3.2 व्यापक रूप से, चित्र 1 में दर्शाई गई संसेक्स की बढ़ोतरी को वर्ष 1999 के बाद तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। वर्ष 1999 से वर्ष 2007 तक के पहले चरण में संसेक्स में त्वरित बढ़ोतरी देखी गई जिसमें प्रत्येक उत्तरवर्ती 5000 अंकों का चिह्न हासिल करने में पहले से कम समय लगा। वर्ष 2007 से वर्ष 2014 के दूसरे चरण में सूचकांक की बढ़ोतरी में धीमी रफ्तार दिखी। यह चरण अन्य प्रतिकूल घटनाओं के साथ वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी का भी समय था। चरण

3 वर्ष 2014 में प्रारंभ हुआ था और इसमें संरचनात्मक सुधारों एवं वैश्विक तरलता में सुधार के प्रत्युत्तर में पुनः प्रवर्तन दिखाई दिया। इस चरण में, संसेक्स आचर्यजनक ढंग से मात्र दो वर्षों में 30,000 अंकों से 40,000 अंकों तक पहुंच गया। जैसा कि चित्र में दिखाई गई असामान्य वृद्धि दरें (सीएजीआर)।

स्पष्टतः दर्शाती हैं, संसेक्स में त्वरण आधार प्रभाव के कारण नहीं था। दरअसल, उच्चतर त्वरण, उच्चतर सीएजीआर के कारण था।

चित्र 1: संसेक्स-प्रत्येक 5000 अंकों के चरण को पार करने के लिए लगे वाले माह



स्रोत: बीएसई

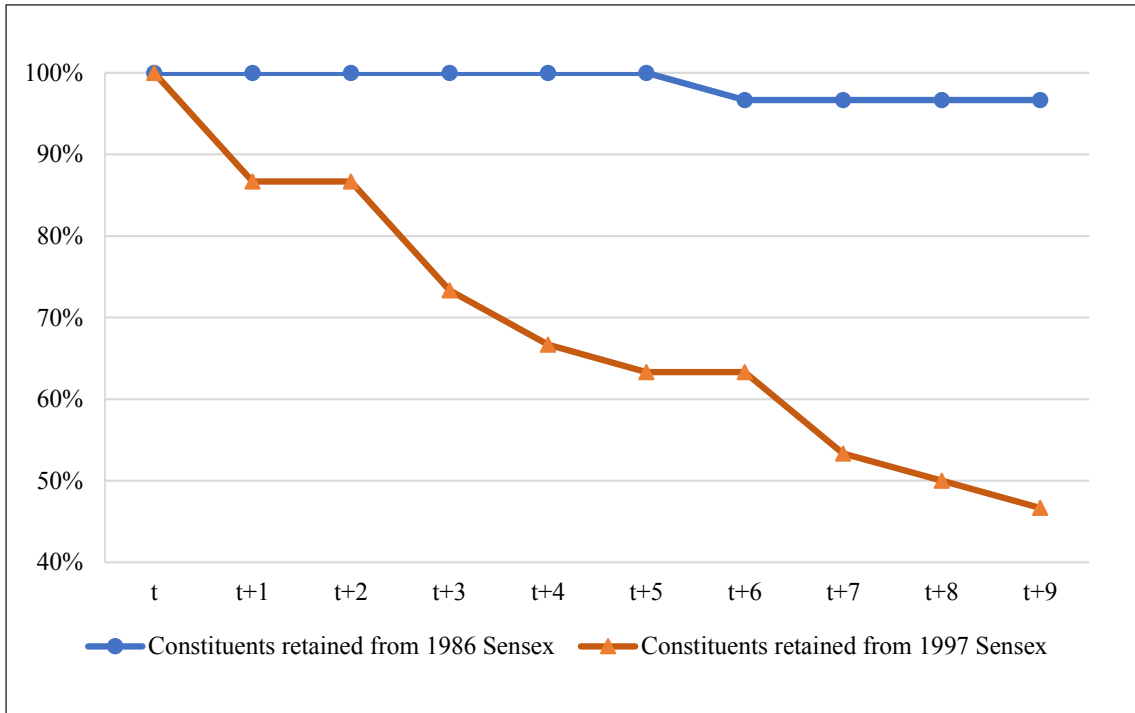
टिप्पणी: प्रत्येक चरण को पार करने के समय को पिछले चरण के बंद होने पर संसेक्स के पहली बार बंद होने और वर्तमान चरण पर इसके पहली बार बंद होने के बीच के समय के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह ध्यान दें कि यह चरण बंद कीमतों पर आधारित होता है। व्यतीत समय को कैलेंडर दिनों की संख्या के रूप में दर्ज किया जाता है और उसको 30 दिनों का माह मानकर माह में परिवर्तित किया जाता है।

3.3 बाजार समर्थक नीति एवं रचनात्मक विनाश के बीच संबंध को पिछले कुछ वर्षों के दौरान संसेक्स के संरचना से दर्शाया जाता है। वर्ष 1986 में संसेक्स की स्थापना के बाद से पहले दस वर्षों के लिए सूचकांक गठित करने वाली फर्मों में मुश्किल से कोई बदलाव आया था। जैसाकि चित्र 2 में दर्शाया गया है कि वर्ष 1986

में सूचकांक का गठन करने वाली फर्मों में से लगभग सभी फर्मों को अगले दशक में अधिकांश समय के लिए बनाए रखा गया था। जबकि दूसरी ओर, वर्ष 1997 के संसेक्स के घटकों में अगले दशक के दौरान बहुत दबाव आया जिससे कि वर्ष 2006 के संसेक्स में वर्ष 1997 के संसेक्स में रही मात्र आधी फर्म ही रह गई थी।

1. आंकड़ों को बीएसई एवं ब्लूमबर्ग से एकत्र किया गया है। समय के दौरान तुलनात्मकता के लिए मुक्त प्रवाह पूंजीकरण की अपेक्षा पूर्ण बाजार पूंजीकरण का प्रयोग किया गया है क्योंकि मुक्त प्रवाह कार्य-पद्धति का प्रारंभ केवल वर्ष 2003 में ही हुआ था। संसेक्स घटकों एवं बाजार पूंजीकरण आंकड़ों को वर्ष 1985-2000 के लिए बीएसई से एकत्र किया गया है। बीएसई के आंकड़े अवलोकन के लिए निम्नलिखित तारीखों पर उपलब्ध हैं: दिसंबर, 1991, जून 1992, जून 1993, नवंबर 1994 मार्च 1995, मार्च 1996, मार्च 1997, जून 1998, मार्च 1999, मार्च 2000। बाद के वर्षों के लिए आंकड़ों को ब्लूमबर्ग से एकत्र किया गया है जिसमें प्रत्येक अनुरूपी वर्ष के सितंबर माह को अवलोकन माह माना गया है। इसको लिखने के समय तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों पर आधारित। (वर्ष 2019 के आंकड़े 3 सितंबर 2019 तक के हैं)।

चित्र 2: अगल दशक के दौरान धारित संसेक्स घटकों की प्रतिशतता



स्रोत: ब्लूमबर्ग, बीएसई

टिप्पणी: 2001 से पूर्व व पश्चात् प्रेक्षण के माह में विसंगति (आंकड़ों के भिन्न स्रोत के कारण) के कारण 2000-02 हेतु व्यक्तिगत परिवर्तित दरों को सम्मिलित मानिए, हालांकि इन वर्षों में कल परिवर्तन दर सही है।

3.4 प्रारंभिक वर्षों में सूचकांक के गठन में गतिशीलता का अभाव सामान्यतः भारतीय अर्थव्यवस्था में गतिशीलता की कमी की अभिव्यक्ति थी। तथापि, वर्ष 1991 के उदारीकरण के बाद के वर्षों में नई फर्मों, नए विचारों, नई प्रौद्योगिकियों और नई प्रचालन प्रक्रियाओं का तीव्र गति से उदगम हुआ जिसके कारण वर्ष 1996 में संसेक्स में बड़ी तेजी से संशोधन हुआ। वर्ष 1996 में, सूचकांक के आधे घटकों को प्रतिस्थापित कर दिया गया था। वर्ष 1996 के पश्चात् संसेक्स में भारतीय बाजार की अधिक गतिशील प्रकृति, जोकि अब अधिक प्रतिस्पर्धी हो गई थी, के कारण बार-बार संशोधन हुए।

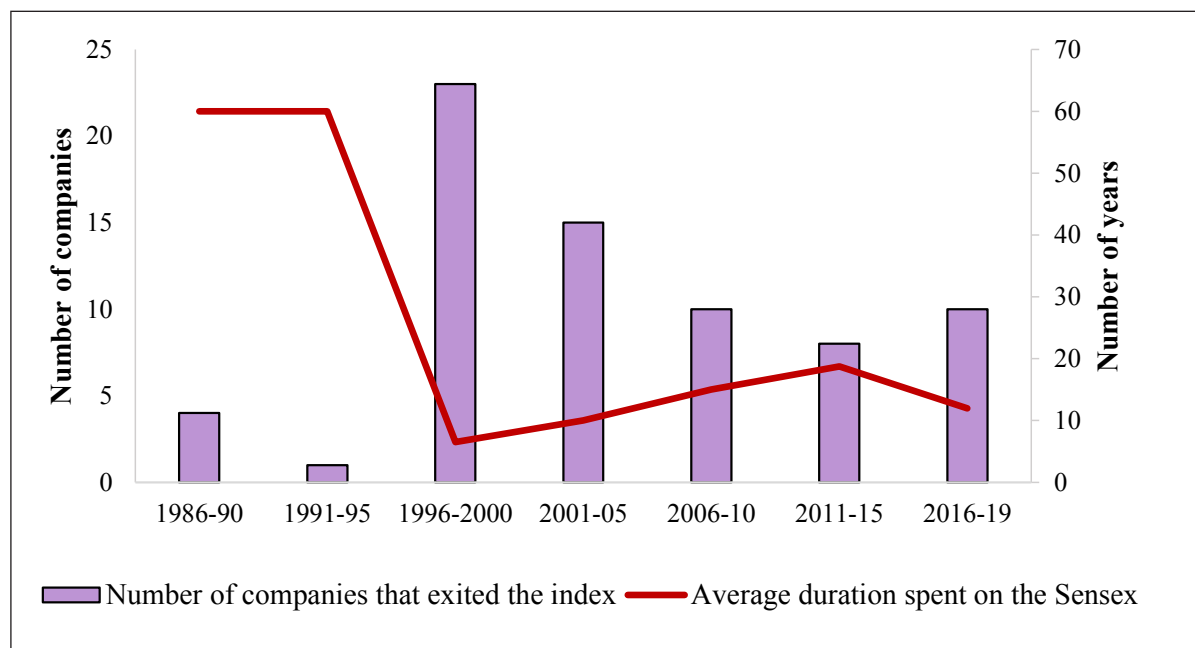
3.5 चित्र 3 उन फर्मों की संख्या दर्शाता है जिनको वर्ष 1986 के बाद प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि में संसेक्स से बाहर कर दिया गया था। उदारीकरण के तत्काल बाद के वर्षों में प्रतिस्थापित की गई फर्मों की संख्या में बड़ी तेजी से वृद्धि हुई प्रन्तु यह बाद के वर्षों को बढ़ने की दर बाद के वर्ष उदारीकरण से पूर्व के स्तर तक कम नहीं हुई। वर्ष 2006-2010 की समयावधि में पांच वर्षों में दस फर्मों का प्रतिस्थापन

किया एवं 2011-15 में आठ फर्मों का और 2016-19 में दस फर्मों का प्रतिस्थापन हुआ हुई। दूसरे शब्दों में प्रत्येक पांच वर्षों में सूचकांक में लगभग एक-तिहाई फर्म प्रतिस्थापित हो गई।

3.6 यह आंकड़े यह भी इंगित करते हैं कि सूचकांक में घटक के बने रहने की औसत अवधि क्या है। यह देखते हुए कि वर्ष 1986-95 के दौरान 10 वर्ष की अवधि में केवल 5 फर्मों को बाहर किया गया था तब उस समय तक उदारीकरण नहीं हुआ होता तो और जब एक फर्म वर्ष 1986 में सूचकांक में प्रविष्ट हुई उसकी सूचकांक में अगले साठ वर्ष तक बने रहने की संभावना व्यक्त होती। वर्ष 1991 के सुधार के पश्चात् सूचकांक में बनी रहने वाली फर्म की अवधि बड़ी तेजी से कम हो गई थी। मौजूदा समय में, एक फर्म के केवल 12 वर्षों तक सूचकांक में बने रहने की संभावना है - जोकि सुधार से पूर्व की संभावित अवधि का पांचवा भाग है।

3.7 इस स्थिति में एक प्रासंगिक प्रश्न यह उठता है कि क्या उपर्युक्त वर्णित प्रतिस्थापन भारतीय अर्थव्यवस्था

चित्र 3: संसेक्स में बढ़ती हुई वृद्धि



स्रोत: ब्लूमबर्ग, बीएसई

टिप्पणी: संसेक्स में बने रहने के औसत समय का आकलन उस अवधि में बढ़ती हुई दर के व्युत्क्रम के रूप में किया जाता है। प्रथम दो अवधियों में अत्यंत निम्न वृद्धि दर के कारण, वर्ष 1986-95 के दौरान कुल वृद्धि दर का प्रयोग इन दोनों अवधियों के लिए संसेक्स में बने रहने का अनुमान लगाने के लिए किया गया है।

के लिए लाभदायक है। किसी एकाधिकारी के स्थान पर कोई अन्य वैसे ही किसी एकाधिकारी का आना शायद ही लाभदायक हो। तथापि, भारतीय मामले में, संसेक्स कृत्रिम गत्यात्मकता हो नहीं बल्कि रचनात्मक विनाश

की प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है। जो फर्म संसेक्स के घटकों को प्रतिस्थापित करती है, वे अपने साथ नए विचारों प्रौद्योगिकियों एवं प्रक्रियाओं का लाती हैं। उदाहरण के लिए तालिका 1 में बाजार सुधारों के बाद

तालिका 1: (वर्ष 1996 में संसेक्स सूचकांक के घटकों का संशोधन)

बाहर		प्रतिस्थापन	
फर्म	उद्योग	फर्म	उद्योग (नए रूप से चिह्नांकित)
बल्लारपुर इंडस्ट्रीज	सामग्री	अरविंद मिल्स	उपभोक्ता डयूरेबल्स एवं वस्त्र
भारत फोर्ज	सामग्री	बजाज आटो	आटोमोबाइल्स एवं संघटक
जीएसएफसी	सामग्री	अंबुजा सीमेंट	सामग्री
इंडियन आर्गैनिक	सामग्री	आईसीआईसीआई	विविध वित्त
मुकुंद आयरन	सामग्री	एमटीएनएल	दूरसंचार सेवाएं
बाम्बे डाइंग	उपभोक्ता डयूरेबल्स एवं वस्त्र	बीएचईएल	पूंजीगत वस्तुएं
संचुरी टैक्सटाइल्स	उपभोक्ता डयूरेबल्स एवं वस्त्र	कॉलगेट	घरेलू एवं निजी उत्पाद
इंडियन रेयॉन	उपभोक्ता डयूरेबल्स एवं वस्त्र	आईडीबीआई	विविध वित्त

फिलिप्स	उपभोक्ता वस्तुएं और वस्त्र	रैनबैक्सी लैब्स	फार्मा, बायोटेक और लाइफ साइंस
वोल्टास	उपभोक्ता वस्तुएं और वस्त्र	टाटा केमिकल्स	सामग्री
सिएट	ऑटोमोबाइल्स और संघटक	बीएसईएस	उपयोगी वस्तुएं
हिन्दुस्तान मोटर्स	ऑटोमोबाइल्स और संघटक	एचपीसीएल	उर्जा
प्रिमिअर आटो	ऑटोमोबाइल्स और संघटक	एसबीआई	बैंक
किलॉस्कर कुमिन्स	पूंजीगत वस्तुएं	आईपीसीएल	सामग्री
सीमेंस	फार्मा, बायोटेक और लाइफ साइंस	सेल	सामग्री

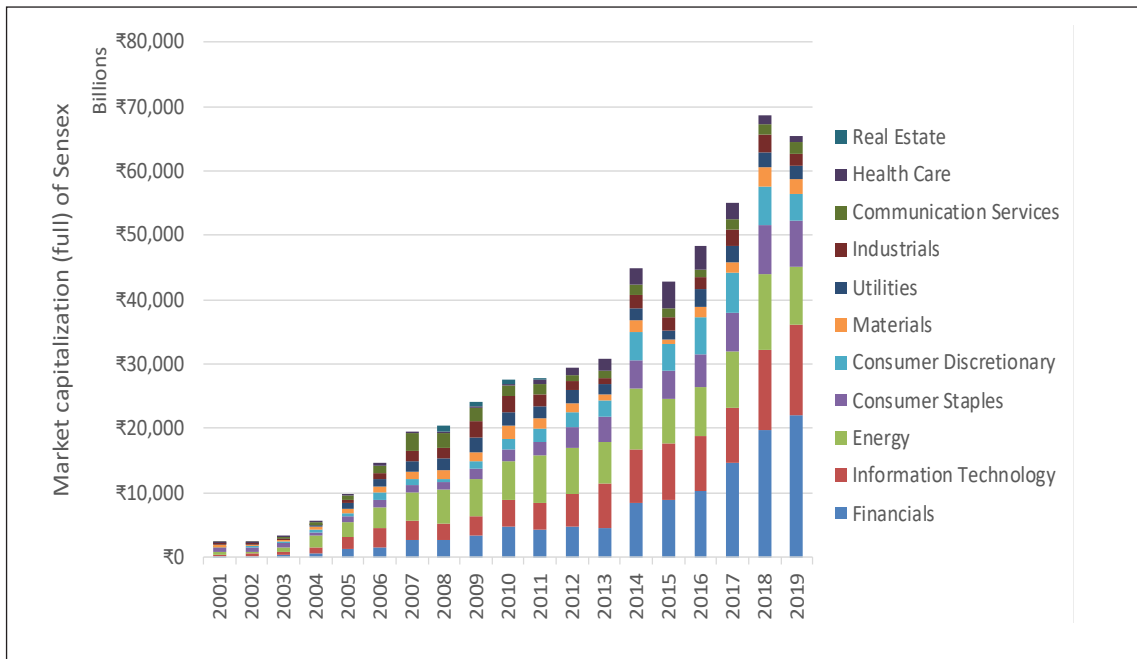
स्रोत: बीएसई, ब्लूमबर्ग

टिप्पणी: रेखांकित कोष्ठिकाएं उन नए क्षेत्रों को निरूपित करती हैं जिन्होंने प्रथम बार सेंसेक्स में प्रवेश किया है

वर्ष 1996 के सेंसेक्स संशोधन को दर्शाया गया है। बैंक एवं वित्त जैसे नए क्षेत्र पहली बार सूचकांक में प्रविष्ट हुए जिन्होंने सूचकांक पर विनिर्माण क्षेत्र के पूर्व प्रभुत्व को समाप्त किया और पहली बार सेवा क्षेत्र को मानचित्र पर रखा एवं उन दूरगामी परिवर्तनों को परिलक्षित किया जिनको भारतीय अर्थव्यवस्था उदारीकरण के परिप्रेक्ष्य में देख रहा था।

3.8 चित्र-4 में समय के साथ-साथ बाजार पूंजीकरण के अनुसार सेंसेक्स में विभिन्न क्षेत्रों के आकार को चित्रित किया गया है। वित्तीय एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जो कि 1990 के दशक के प्रारंभ तक सेंसेक्स में लगभग नहीं के बारबर विद्यमान होते थे अब वे सेंसेक्स के 50% से अधिक बाजार हिस्सेदारी का रखते करते हैं। इसलिए यह निर्विवाद है कि सेंसेक्स की रचना में परितर्वन उस

चित्र 4: उदारीकरण के बाद नवीन क्षेत्रों के उभरने से सेंसेक्स में क्षेत्रक आधारित सघनता में गिरावट



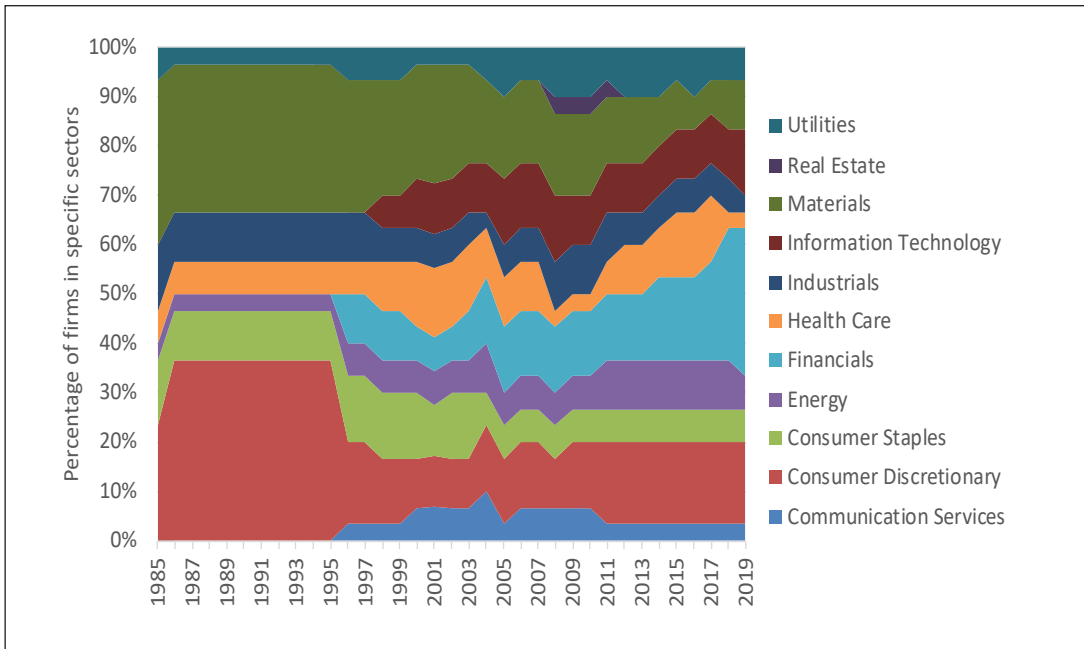
स्रोत: ब्लूमबर्ग, बीएसई

रचनात्मक विनाश की ही वास्तविक प्रक्रिया को दिखाते हैं जिसकी वजह से नई प्रौद्योगिकी, उत्पाद और सेवाएं संयुक्त स्तर में उपभोक्ताओं को प्राप्त हुईं।

3.9 बाजार संबंधी सुधारों के फलस्वरूप समय के साथ संसेक्स में क्षेत्रीय विविधता में निरंतर वृद्धि होती गई जैसा कि चित्र 5 में दर्शाया गया है। वर्ष 1986 के प्रारंभ संसेक्स में सामग्री एवं उपभोक्ता विवकाधीन क्षेत्रों की प्रमुखता थी जो संसेक्स पर उपलब्ध फर्मों

के दो-तिहाई भाग तक विस्तृत थी। उस समय वित्त, दूरसंचार, और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र इंडेक्स में न के बराबर अस्तित्व रखते थे। इन नए क्षेत्रों के प्रवेश के साथ आज का संसेक्स में 1980 और 1990 के दशकों के संसेक्स की तुलना में बहुत कम संकेंद्रण है और समग्र रूप में यह भारतीय अर्थव्यवस्था में एक अत्यन्त निम्नतर स्तर की क्षेत्रीय सघनता की तस्वीर को प्रतिबिंबित करता है।

चित्र 5: उदारीकरण के पश्चात नए क्षेत्रों के उभरने के कारण संसेक्स को क्षेत्रीय केंद्रीकरण का हास।



स्रोत: ब्लूमबर्ग, बीएसई

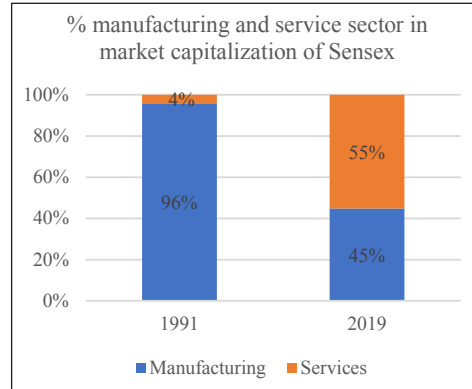
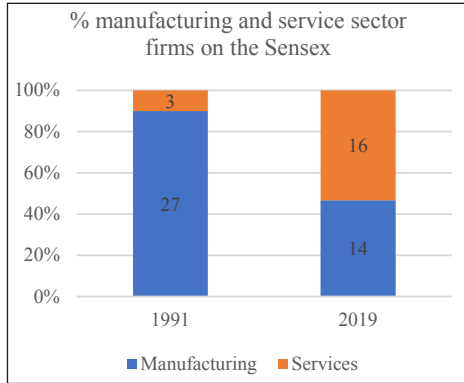
3.10 भारत ने एक विचित्र संवृद्धि पथ को अपनाया है जहां अर्थव्यवस्था का मुख्य प्रचालक कृषि के स्थान पर सेवा क्षेत्र बन गया है। अब लगभग 60 प्रतिशत जीडीपी सेवा क्षेत्र में उत्पन्न हो रही हैं। जैसा कि चित्र 6 दर्शा रहा है कि संसेक्स में 1988 से 2019 की अवधि में विनिर्माण फर्मों की संख्या में कभी आई है जबकि सेवा क्षेत्र की फर्मों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है। इस प्रकार इन वर्षों में संसेक्स में सेवा क्षेत्रीय फर्मों की संख्या का अंश अस्सी के दशक के शून्य प्रायः से बढ़कर अब प्रबल हो गया है।

3.11 वर्तमान में संसेक्स में न केवल बड़ी संख्या में क्षेत्र शामिल हैं, बल्कि कंपनियों के आकार के संबंध में अब यह काफी अधिक लोकतांत्रिक भी हुआ है। वर्ष 1991 में, बाजार पूंजीकरण के संबंध में इंडेक्स में इस शामिल सबसे बड़ी फर्म सबसे छोटी फर्म की अपेक्षा लगभग 100 गुना बड़ी थी। दस वर्ष बाद यह अनुपात लगभग 75 रह गया। वर्ष 2018 में तो यह मात्र 12 रह गया। बाजार उदारीकरण का लाभ-इस अनुपात में एक बार कमी तक सीमित नहीं रहा है-यह आज भी अनुभव हो रहा है और यही बात चित्र-7 में इस अनुपात की हासमान प्रवृत्ति से स्पष्ट हो रही है। इसी प्रकार जहां 1991 में विशालतम फर्म संसेक्स के

सकल बाजार पूंजीकरण के 20 प्रतिशत के बराबर थी वहां 2019 में इस का मान 13 प्रतिशत ही रह गया था।

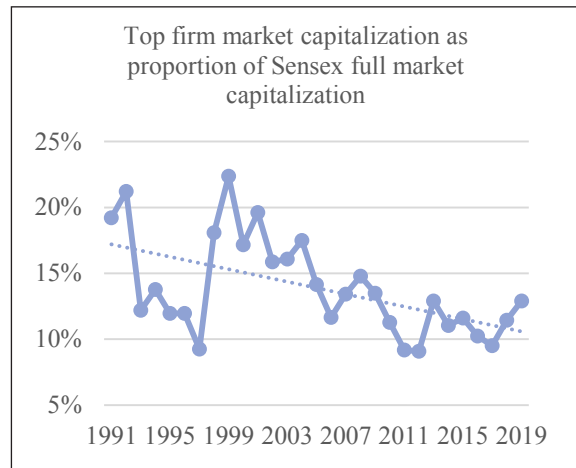
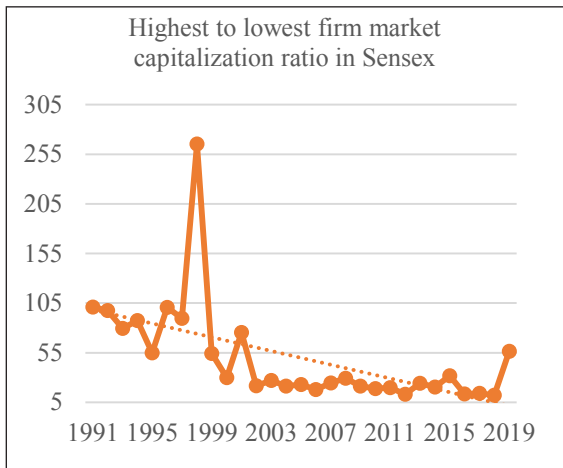
3.12 भारतीय अर्थ-व्यवस्था में उदारीकरण से उदित हुए सक्रिय विध्वंसक बलों के कारण वित्तीय एवं सूचना

चित्र 6: सेंसेक्स में सेवा क्षेत्र का विकास



स्रोत: ब्लूमबर्ग, बीएसई

चित्र 7: सेंसेक्स में फर्मों की सघनता का घटता आकार



स्रोत: ब्लूमबर्ग, बीएसई

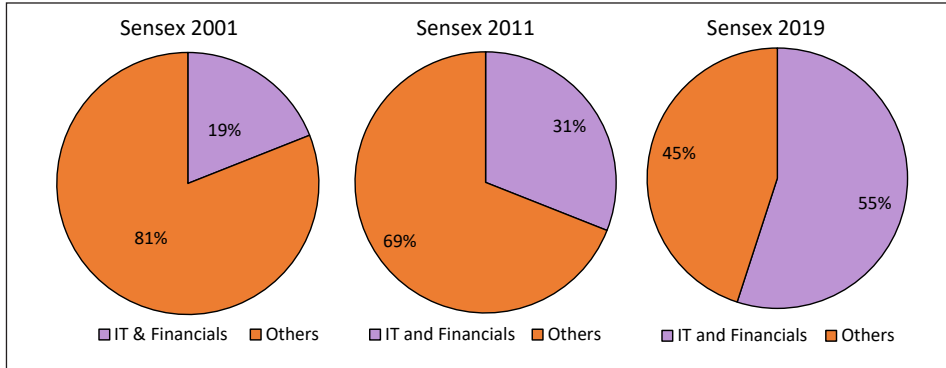
टिप्पणी: उन तारीखों के लिए पूर्ववर्ती पाद टिप्पणी देखें जिनमें प्रत्येक सांगत वर्ष के लिए बाजार पूंजीकरण का प्रेक्षण किया गया है। वर्ष 2019 के लिए डाटा 3 सितम्बर 2019 को यथास्थिति है।

प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों का उदय हुआ है। 1990 के दशक के प्रारंभ के सेंसेक्स में इसके लगभग अनुपस्थित होने वाले इन क्षेत्रों की कुल बाजार पूंजीकरण में इन क्षेत्रों की हिस्सेदारी में पिछले कई वर्षों में इतनी वृद्धि हुई है कि आज इन क्षेत्रों का दबदबा पूरे सेंसेक्स पर दिखाई देता है (चित्र 8 देखें)। पहली नजर में यह प्रवृत्ति चिन्ताजनक लगती है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में अधिक संकेन्द्रण होने या रचनात्मक विध्वंस की

प्रक्रिया के पलट जाने की संभावना लगती है। परन्तु इसकी गहन जांच करने से कुछ और ही प्रकट होता है।

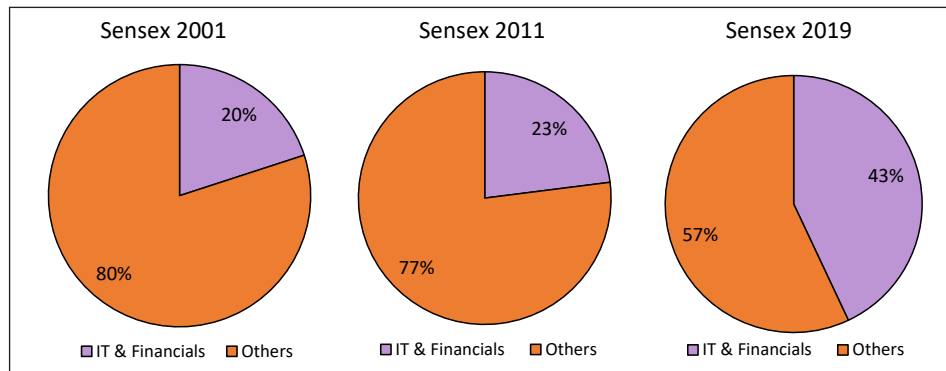
3.13 सबसे पहला बाजार पूंजीकरण में वृद्धि कंपनियों की संख्या में वृद्धि के कारण हुई है, पहले से मौजूद कम्पनियों के आकार में वृद्धि के कारण नहीं। इससे यह संकेत मिलता है कि इन क्षेत्रों के अन्दर प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई है। (चित्र 9)।

चित्र 8: सेंसेक्स के कुल बाजार पूंजीकरण में आईटी और वित्तीय क्षेत्र में बढ़ती हिस्सेदारी



स्रोत: ब्लूमबर्ग, बीएसई

चित्र 9: सेंसेक्स में आई टी एवं वित्तीय क्षेत्र की बढ़ती हिस्सेदारी (गणना द्वारा)



स्रोत: ब्लूमबर्ग, बीएसई

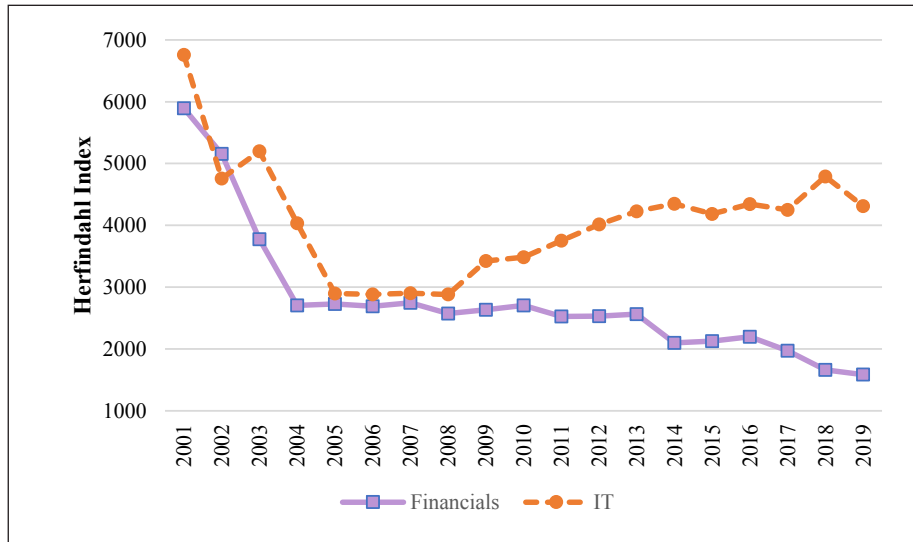
3.14 दूसरा इन दो क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा की डिग्री का विश्लेषण करने के लिए हरफिन्डल इंडेक्स का उपयोग करने से दोनों क्षेत्रों में संकेंद्रण में समग्र कमी का पता चलता है। परन्तु आई टी के क्षेत्र में हाल में हरफिन्डल इंडेक्स में थोड़ी बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखने लगी है जिससे यह संकेत मिलता है कि इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को और बढ़ाने की गुंजाइश है। (चित्र 10 देखें)

3.15 उपर्युक्त विश्लेषण से तीन मुख्य अंतर्दृष्टियाँ मिलती हैं। प्रथम आज की प्रबल फर्मों से केवल उस समय के पांचवे हिस्से तक प्रबल रहने की अपेक्षा कर सकते हैं जो उदारीकरण से पहले की फर्मों से की जाती थी। द्वितीय, जिन क्षेत्रों को कमी भारतीय अर्थव्यवस्था आधारस्तंभ जाता था, उनका स्थान अपने साथ नई प्रौद्योगिकी एवं उत्पाद लाने वाले नए क्षेत्र ले रहे हैं; जमी हुई फर्मों के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को तेजी से अपेक्षाकृत नई छोटी व चुस्त फर्मों से चुनौती मिल

रही है; प्रत्येक पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था में तीन फर्मों में से लगभग एक फर्म को सक्रिय विध्वंस बलों के द्वारा प्रभावशाली तरीके से चुनौती देने की अपेक्षा की जा सकती है। अंतिम में बड़ी एवं लघु फर्मों के आकारों के बीच का अंतर शीघ्रता से कम हो रहा है जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में एकाधिकारी शक्ति कम हो रही है अतः अधिक से अधिक प्रतिस्पर्धी बाजारों का रास्ता खुल रहा है। माल एवं सेवाओं की विविधता बढ़ने, मूल्य कम होने और मौजूदा उत्पादों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार होने से उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं।

3.16 यह एक सामान्य धारणा है कि मुक्त बाजार के पक्ष में रहने वाले लोग सेसी किसी चीज के भी चीज के इस के पक्ष में होने हैं जो बड़े व्यवसाय करते हैं। मिल्टन फ्रीडमैन (फ्रीडमैन 1999) ने लिखा है। यह बात सच्चाई से कोसों दूर है। प्रतिस्पर्धी बाजारों

चित्र 10: वित्तीय एवं आई टी क्षेत्रों का हरफिन्डल इंडेक्स



स्रोत: ब्लूमबर्ग, बीएसई

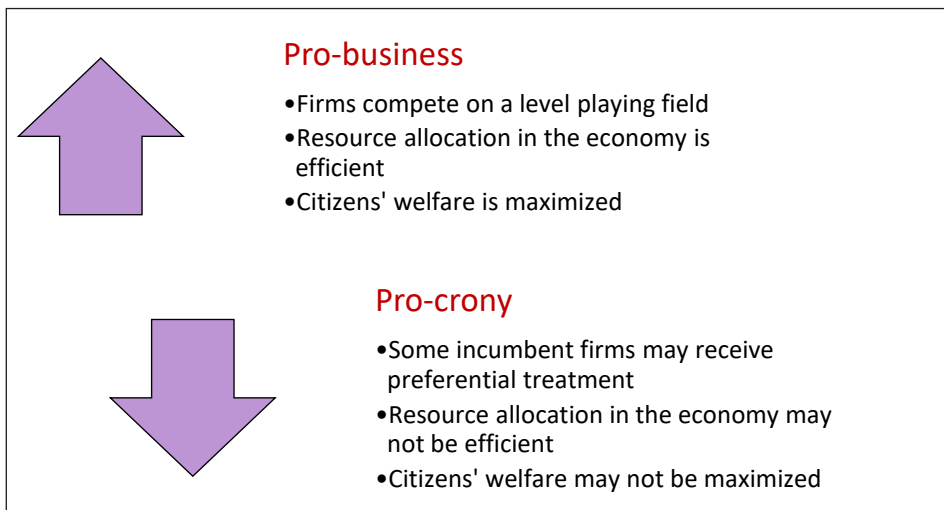
अथवा बाजारवादी के पक्ष में नीति अवस्थिति से प्रायः व्यवसायवादी अवस्थिति के भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। व्यवसायवादी नीति पदधारी फर्मों का समर्थन करती है परन्तु यह जरूरी नहीं है कि वह प्रतिस्पर्धी बाजारों को भी प्रोत्साहित करे (चित्र 11 देखें)

वहीं दूसरी ओर, प्रतियोगी बाजार व्यवस्था का पोषण करने वाली नीति (इसके बाद बाजारवादी नीति के रूप में उक्त) व्यवसायों के मध्य प्रतिस्पर्धा हेतु प्रतियोगिता स्थल निर्मित करती है। यह रचनात्मक विध्वंस के सशक्त बलों को उन्मुक्त करती है ताकि धन-संपदा का सृजन हो। आस्ट्रिया के अर्थशास्त्री और इस पद के सृजक, जोसेफ शंपीटर ने रचनात्मक विध्वंस का वर्णन

इस प्रकार से किया है, “यह औद्योगिक उत्परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो आर्थिक संरचना में निरंतर अंदर से ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने को प्रवृत्त हो कि पुराना निरंतर उच्छेदित (नष्ट) होता जाए और नया निरंतर सृजित होता जाए”।

3.17 रचनात्मक विध्वंस बाजार में ऐसे नव-परिवर्तन लाता है जो मौजूदा पुरानी प्रौद्योगिकियों के स्थान पर लोगों को अपेक्षाकृत बेहतर सेवाएं प्रदान करें। यह बाजार में ऐसी नई फर्मों को प्रविष्ट कराता है जो मौजूदा उपभोक्ताओं के लिए निम्नतर कीमतों के साथ, मौजूदा फर्मों से प्रतियोगिता करती हैं। यह बाजार-स्थल पर ऐसी गत्यात्मकता लाता है कि फर्मों निरंतर सतर्क रहते हुए,

चित्र 11: बाजारवादी और व्यवसायवादी अर्थ-शास्त्र के बीच अंतर



उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं देने के क्रम में बाजार पर दूर-दूर तक नजर रखती हैं। इसकी केवल एकमात्र पूर्वशर्त है-प्रतियोगी, निरबंध बाजार।

3.18 जब रचनात्मक विध्वंस को प्रोत्साहन दिया जात है तो संबंधित क्षेत्र समग्र रूप में धन-संपदा के सृजन और अधिकतम कल्याण हेतु उस क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तिगत कंपनियों की अपेक्षा सदैव ही बेहतर निष्पादन करते हैं। इस में भारत के लिए वह प्रेरणा निहित है कि व्यवसायवाद की बजाय बाजारवादी विकास की संकल्पना का अनुसरण किया जाए।

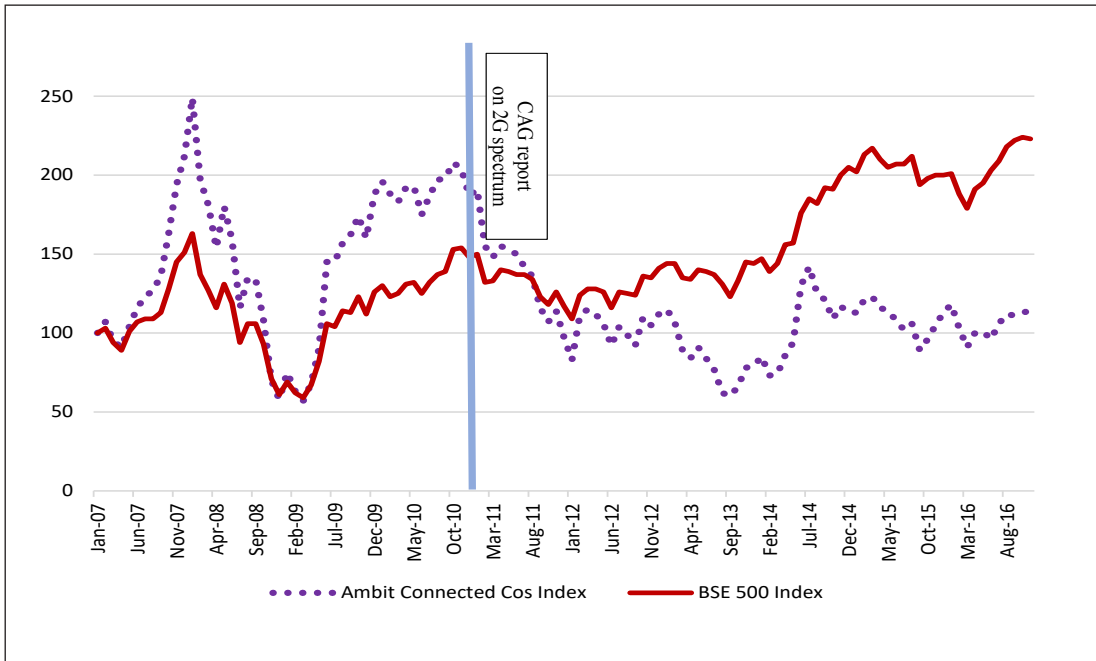
पक्षपातवाद और वैभव विनाश

3.19 बाजारवादी नीतियों के विपरीत व्यवसायवादी नीतियों से अर्थव्यवस्था में धन का क्षरण होता है, क्योंकि पक्षपातवाद से रचनात्मक विध्वंस (क्रियेटिव डिस्ट्रक्शन) की प्रक्रिया रूक जाती है, जिससे अक्षमता में वृद्धि होती है। रघुराम राजन और लुइगी जिंगेल्स ने अपनी पुस्तक में निजी हितों द्वारा विनियामक कब्जे के खतरों का जिक्र करते हुए “पूंजीवादियों से पूंजीवाद को बचाने” की आवश्यकता पर जोर दिया है, (राजन और जिंगेल्स 2003)।

3.20 एंबिट प्राइवेट लिमिटेड, एक ब्रोकरेज फर्म, उन 75 भारतीय फर्मों, जो राजनीतिक रूप से संबंधित हैं, के शेयर बाजार के सूचकांक को प्रकाशित करता है। चित्र-12 में समय के साथ इस सूचकांक के प्रदर्शन की तुलना बीएसई 500 सूचकांक से की गई है।

3.21 2010 से पहले, यदि फर्म के प्रवर्तकों के राजनीतिक संपर्क होते थे तो उस फर्म और उसके शेयरधारकों को स्पष्ट लाभ प्राप्त होता था। बीएसई 500 सूचकांक में राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों के सूचकांक ने लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है, क्योंकि किसी अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में जितना लाभ कमाना संभव हो सकता था, इन फर्मों ने व्यवस्थित रूप से उससे अधिक लाभ कमाया। बाजार में इन फर्मों के वर्तमान और भविष्य के असामान्य मुनाफे का मूल्य-निर्धारित किया गया, हालांकि विख्यात भांडाफोड तक निवेशकों को यह पता नहीं था कि वर्ष 2010 तक, ये लाभ भंडाखोरी से उपजे थे। 2010 के अंत में, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उन निजी कंपनियों के नामों की सूची प्रदान की गई, जिन्हें 2 जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में कथित मिलीभगत से लाभान्वित किया गया था। रिपोर्ट के जारी होने के समय को चार्ट पर एक ऊर्ध्वाधर रेखा से रेखांकित किया गया है।

चित्र 12: 2जी घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट से पहल और बाद में राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों द्वारा उत्पन्न निवेशक धन



स्रोत: किशोर (2016), एंबिट प्राइवेट लिमिटेड, नोट: 06/2007 में 100 पर दोनों संख्याओं को अनुक्रमित किया गया।

3.22 ऐसा प्रतीत होता है कि जी आवंटन पर सीएजी की रिपोर्ट ने राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों की किस्मत को पलट दिया था। 2011 के शुरू में, सूचकांक के आधार पर यह देखा गया कि राजनीतिक रूप से संबंधित फर्म बाजार से कम प्रदर्शन रही थी। वास्तव में, राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों द्वारा नष्ट किए गए निवेशकों के धन की खाई समय के साथ-साथ चौड़ी होती चली गई, जो इस बात को दर्शाता है कि ऐसी फर्म अपने राजनैतिक संपर्क के

आधार पर भाड़े का निष्कर्षण करके अपने निवेशकों के लिए व्यवस्थिति रूप से मूल्य अर्जित करती हैं। (बीएस 2014) (किशोर 2016)

3.23 यदि किसी निवेशक ने 2007 की शुरुआत में राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों में रु. 100 का निवेश किया हो तो उसका निवेश 2010 की शुरुआत तक रु. 190 हो गया हो। वहीं दूसरी ओर, यदि उसने बीएसी 500 में रु.100 का निवेश किया हो, तो उसका निवेश बढ़कर रु. 150 हो गया हो। इस अवधि के दौरान, राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों के सूचकांक में प्रतिवर्ष 17.5 प्रतिशत का औसत प्रतिफल प्राप्त किया गया, जबकि बीएसई 500 सूचकांक में प्रतिवर्ष 10.5 प्रतिशत के प्रतिफल प्राप्त किया गया। इस प्रकार, राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों ने 2010 तक शेयर बाजार के व्यापक

सूचकांक में औसतन एक वर्ष में 7 प्रतिशत अंक का बेहतर प्रदर्शन किया। अलग तरह से कहें तो 2007 से 2010 तक राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों को अधिक प्रतिस्पर्धी बाजार में जितना लाभ प्राप्त हो सकता था, उससे 7 प्रतिशत अधिक अंक का लाभ प्राप्त हुआ।

3.24 राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों का यह 2010 से पूर्व का प्रदर्शन समाज की लागत के खर्च पर इन फर्मों द्वारा निष्कर्षित भाड़े की संभावित सीमा को दर्शाता है। इसके विपरीत, 2010 के बाद से सीएजी रिपोर्ट के अनुसार इन फर्मों का कम प्रदर्शन इस तथ्य को दर्शाता है कि ऐसी राजनीतिक रूप से संबंधित फर्म अक्षम फर्मों में से हैं। 2007 और 2016 के बीच, राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों ने औसतन बीएसई 500 इंडेक्स की तुलना में 7.5 प्रतिशत कम रिटर्न प्राप्त किया है। अक्षम, राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों द्वारा किराए के निष्कर्षण की यह घटना भले ही अर्थव्यवस्था के लिए अस्वास्थ्यकर है, लेकिन भारत में ये केवल ही नहीं हुई हैं। वास्तव में, कई वैश्विक अध्ययनों से यह स्पष्ट किया गया है कि जब संस्थागत नियन्त्रण और संतुलन कमजोर होते हैं, तब राजनीतिक संबंध और भाड़े के निष्कर्षण की गतिविधियों के बीच के संबंध अधिक मजबूत हो जाते हैं। (बॉक्स 1 देखें)

बाक्स 1 वैश्विक साक्ष्य कि राजनैतिक संपर्क के कारण किराए का निष्कर्षण किया जाता है।

दुनिया भर के कई अध्ययनों से पता चलता है कि राजनीतिक संपर्क के कारण किराए का निष्कर्षण किया जाता है फेसियो (2006) द्वारा 47 देशों में राजनीतिक रूप से संबंधित का अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि उस समय के आसपास जब कोई फर्मों यह घोषणा करती कि उसके प्रबंधक या बड़े शेयरधारक राजनीति में प्रवेश कर रहे हैं, तो स्टॉक मूल्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता था। यह परिणाम इस सिद्धांत के अनुरूप है कि बाजार, फर्म के मौलिक सिद्धांत में कोई बदलाव नहीं होने के बावजूद, राजनीतिक रूप से संबंधित फर्म से लाभ के अतिरिक्त स्रोतों की उम्मीद रखता है। फेसियो और अन्य (2006) द्वारा 35 देशों में राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों में वित्तीय संकट का अध्ययन किया गया और यह पाया गया कि राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों को डूबने से बचाने के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता मिलने की संभावना राजनीतिक रूप से असंबंधित फर्मों की तुलना में अधिक है। क्लाशीन और अन्य (2008) द्वारा यह दर्शाया गया है कि 1998 और 2002 के चुनावों के दौरान ब्राजील के जिन फर्मों ने (चयनित) संघीय प्रतिनिधियों को अंशदान दिया था, उन्हें उन फर्मों की तुलना में उच्च भी पैदा कर सकती हैं। स्टॉक प्रतिफल प्राप्त हुआ जिन्होंने इस तरह का अंशदान नहीं दिया था। इसके अलावा, जिन फर्मों ने अंशदान दिया था, उन्होंने प्रत्येक चुनाव के बाद एक नियंत्रक समूह के सापेक्ष अपने बैंक वित्तपोषण में काफी वृद्धि की, जो यह दर्शाता है कि बैंक वित्त राजनीतिक संबंध के संचालन का एक महत्वपूर्ण चैनल हैं। उन्होंने यह अनुमान किया था कि दो चुनाव चक्रों के बाद किराया निष्कर्षण की आर्थिक लागत प्रति वर्ष सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 0.2% होगी।

यूक्रेन में हाल ही में पक्षपातवाद पर किए गए विश्व बैंक के अध्ययन से पता चलता है कि यदि समस्त राजनीतिक संबंध समाप्त कर दिए जाए तो देश 1 से 2 प्रतिशत की तेजी से विकास करेगा (कहकोनन 2018)! यूक्रेन में राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों का टर्नओवर, समस्त यूक्रेनी कंपनियों के कुल टर्नओवर के 20 प्रतिशत से अधिक

है। अध्ययन में पाया गया है कि ये राजनीतिक रूप से संबंधित फर्मों (प) राजनीतिक रूप से असंबंधित साथी फर्मों से बड़ी हैं, (पप) कम प्रभावी कर दरों का भुगतान करती हैं, (पपप) कुल कारक उत्पादकता (टीएफपी) के संदर्भ में कम उत्पादक हैं, (पअ) कम लाभदायक हैं, और धीमी गति विकास करती हैं (विश्व बैंक, 2018)।

एशिया से प्राप्त साक्ष्य

चीन: फर्थ और अन्य (2009) के अनुसार चीनी कंपनियों को बैंक ऋण के आवंटन में राजनीतिक पैठ (कनेक्शन) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके अनुसार सरकार न्यून अंश हिस्सेदार होने पर भी दन कंपनियों को बैंक साख प्राप्त करने में मदद मिलती है। राजनीतिक पैठ विशेष रूप से कम विकसित बैंकिंग वाले क्षेत्रों में स्थित कंपनियों को लाभ पहुंचाते हैं। दंग, झेंग और झू (2019) इस बात का साक्ष्य देते हैं कि चीन में कंपनियां बाजार में होने वाले घर्षणों की से लागत को कम करने के लिए सक्रिय रूप से राजनीतिक पैठ बनाती हैं। बाजार के गंभीर घर्षणों संकटों का सामना करने वाली कंपनियां आर्थिक रूप से उतनी विवश नहीं है कतिनी इन कंपनियों से ही अपेक्षा की जाएगी; इसका महत्वपूर्ण कारण यह है कि उनके मजबूत राजनीतिक संबंध होते हैं जो इन लागतों को कम करते हैं। चैन और अन्य (2012) के अनुसार चीन में राजनीतिक पैठ रखने वाली कंपनियां को निरपेक्ष रहने वाली कंपनियों की तुलना में बहुत कम वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चैन ने पाया कि ये संबंध चीनी प्रतिभूति नियामक आयोग द्वारा ग्राहकों के आई पी ओ आवेदनों के अनुमोदित किए जाने की संभावना को बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त भाड़ा-व्यवस्था के अनुरूप ऐसी कंपनियों के आईपीओ के बाद के प्रदर्शन में गिरावट का दस्तावेजीकरण होता है, जिसमें यह इंगित किया जाता है कि छोटे शेयरधारकों के साथ समझौता होता है।

थाईलैंड: बंकनवनीका एवं विवाट्टानाकतांग (2009) के अनुसार जब उद्योगपति राजनीतिक सत्ता में आता है तो उसकी कंपनियों का बाजार-मूल्य नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। शीर्ष कार्यालयों में बैठे उद्योगपति अपनी कंपनियों के अनुकूल विनियमों और सार्वजनिक नीतियों को लागू करने के लिए अपनी नीति-निर्धारण शक्तियों का उपयोग करते हैं। सिविलाइज एवं अन्य (2015) ने थाईलैंड में छोटी-बड़ी सभी कंपनियों का एक क्रम में अध्ययन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि राजनीतिक जुड़ाव रखने वाली कंपनियों ने व्यवस्थित रूप से उच्च स्टॉक प्रतिल दिया। इस मत के अनुरूप कि इस तरह के संबंध आर्थिक रूप से अधिक लाभप्रद होते हैं, यह निष्कर्ष विशेष रूप से विनियमित उद्योगों में प्रमुख है। उच्च स्तर की राजनीतिक पैठ के लिए राजनीतिक रूप से जुड़ा प्रीमियम अधिक है और तब भी जब राजनीतिक निकाय कंपनी में इक्विटी हिस्सेदारी रखते हैं।

इंडोनेशिया: फिसमैन (2001) ने इंडोनेशिया में राजनीतिक संबंधों के मूल्य का अनुमान इस बात से लगाया है कि पूर्व राष्ट्रपति सुहार्तो के स्वास्थ्य के बिगड़ने की खबर फैलने के साथ ही विभिन्न कंपनियों के शेयरों की कीमतों में कैसा उतार-चढ़ाव आने लगा। प्रतिकूल स्वास्थ्य रिपोर्टों ने अपेक्षाकृत कम निर्भर कंपनियों की तुलना में राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़ी हुई कंपनियों के प्रतिफलों को अधिक कम किया था।

मलेशिया: जॉन्सन और मिटन (2003) के अनुसार वर्ष 1998 में मलेशिया में पूंजी नियंत्रण के कानून लागू होने से मुख्य रूप से राष्ट्रपति के साथ नजदीकी संबंध रखने वाली कंपनियों को फायदा हुआ था, अतः इससे यह पता चलता है कि पूंजी नियंत्रण ने एक ऐसे पर्दे के रूप में कार्य किया, जिसके पिछे राजनीतिक पैठ रखने वाली कंपनियों ने अपने राजनीतिक संपर्कों का लाभ उठाया। मलेशिया की राजनीतिक तौर पर जुड़ी हुई कंपनियों के एक अध्ययन में पाया गया है कि ऐसी कंपनियों को बाजार, ऑडिट फर्मों और ऋणदाताओं द्वारा अधिक जोखिमपूर्ण माना जाता है। ऐसी कंपनियों के घाटे में रहने, नकारात्मक इक्विटी होने, और ऋणदाताओं द्वारा ऐसी कंपनियों के संबंध में उच्च ब्याज दर वसूल किए जाने की अधिक संभावनाएं हैं (ब्लिस और गुल 2012)

वियतनाम: रैंड (2017) ने 10 साल की अवधि में 2000 से अधिक वियतनामी एस एम ई की जांच की और यह पाया कि राजनीतिक संबंध रखने वाली कंपनियों को ऋण मिलने में परेशानी होने की संभावना में 4 प्रतिशत अंकों तक कम होती है। इसके अलावा, राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई कंपनियां जब क्रेडिट प्राप्त करने की कोशिश करती हैं, तो गैर-संबद्ध एस एम ई जिन्हें औपचारिक वित्तीय बाजारों से बाहर नहीं रखा गया है की तुलना में पूंजी की न्यूनतर लागत का सामना करना पड़ता है और उन्हें औपचारिक वित्तीय बाजारों से बाहर नहीं रखा जाता है।

इन अध्ययनों से एक बात स्पष्ट रूप से साबित होती है कि राजनीतिक रूप से जुड़ी हुई फर्मों अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करती हैं। इन लाभों में, इन फर्मों के शेयरधारकों द्वारा असंबद्ध फर्मों और समाज को व्यापक हानि पहुंचते हुए अनुचित रूप से प्राप्त किए गए लाभ प्रत्यक्षतः या परोक्षतः शामिल होते हैं।

3.25 जब व्यवसायवादी नीतियों बाजारवादी नीतियों की तुलनामें विभिन्न प्रकार की अप्रत्यक्ष लागते भी पैदा कर सकसती हैं। जब अनुचित तरीके से अपने लोगों को लाभ देने का अवसर मौजूद हो, तो फ़र्में प्रतिस्पर्धा एवं नवाचार के जरिए विकास करने के बजाय राजनीतिक पैठ का निर्माण करने में लगी होती हैं। अतः इससे अर्थव्यवस्था द्वारा धन-समृद्धि का सृजन करने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है (बॉक्स 2 को देखें)। इसके अलावा अपने लोगों द्वारा अनुचित तरीके से लाभ की मांग का भुगतान ईमानदार बिजनेसमैन और नागरिकों द्वारा किया जाता है जिन्हें किसी तरह का कोई अधिमान्यतापूर्ण नहीं मिलता है। इस तरह से धन का हस्तांतरण अर्थव्यवस्था में आय की असमानता को बढ़ाता है, क्योंकि राजनीतिक व्यक्तियों से जुड़ी हुई फ़र्में उपलब्ध संपत्ति का विस्तार

करने की बजाय मौजूदा संपत्ति को हड़पने के लिए अपनी राजनीतिक पैठ का इस्तेमाल करती हैं।

नीलामियों के माध्यम से आबंटन की तुलना में प्राकृतिक संसाधनों का मनमाना आबंटन

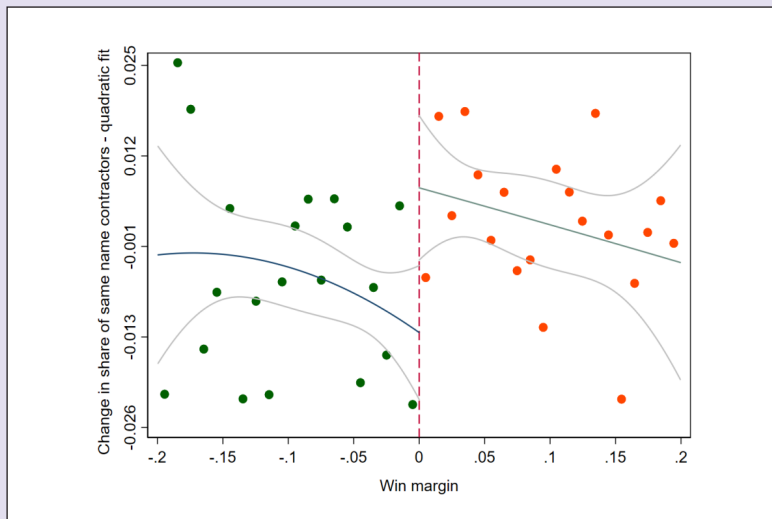
3.26 इस खंड में, हम भारत में प्राकृतिक संसाधन आबंटन प्रक्रिया से एक केस अध्ययन पर विचार कर रहे हैं। भारत में यू एस ए, रूस, चीन और आस्ट्रेलिया के बाद विश्व में कोयले का पांचवां सबसे बड़ा रिजर्व (भण्डार) है। कोयला भारत के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्वदेशी ऊर्जा स्रोत है; और इससे भारत की आधे से अधिक ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी होती हैं। इसलिए, इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के आबंटन से हमें बाजार अनुकूल और व्यापार अनुकूल नीतियों की तुलना करने के लिए एक उत्तम केस अध्ययन प्राप्त होता है।

बाक्स 2 राजनीतिक दबदबा और अनुबंधों का तरजीही आवंटन (2001-13):

भारत में सड़क निर्माण का: एक केस अध्ययन

भारत में विभिन्न व्यवसायी सरकार से परियोजनाओं और संसाधनों का तस्जीही आवंटन प्राप्त करने के लिए अपने राजनीतिक रसूख का उपयोग करते हैं। लेहने, शापिरो और आइंडी ने प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत निर्मित 88,000 से अधिक ग्रामीण सड़कों से संबंधित बिडिंग डाटा (लगाई बोलियों से सम्बंधित आंकड़ों) की जांच की और इस आंकड़ों का मिलान चुनाव परिणामों के साथ किया। वर्ष 2001 से 2013 तक 4058 चुनावों में 8116 उम्मीदवारों का सैंपल के रूप में उपयोग करते हुए और एक समाक्षयण असंतता डिजाइन की सहायता से अध्ययन में यह निष्कर्ष निकला कि चुनावों में जीत हासिल करने के बाद, जीतने वाले राजनेता से जुड़े ठेकेदारों को सड़क परियोजनाएं आवंटित किए जाने की संभावना बढ़ जाती है। नीचे दिए गए चित्र इस परिणाम को ग्राफिक (रेखीय) रूप में दर्शाते हैं। इसमें जीतने वाले राजनेताओं जैसा नाम रखते वाले ठेकेदारों के अंश को उस राजनेता के चुनाव में नीत के अन्तर के साथ दिखाया गया है।

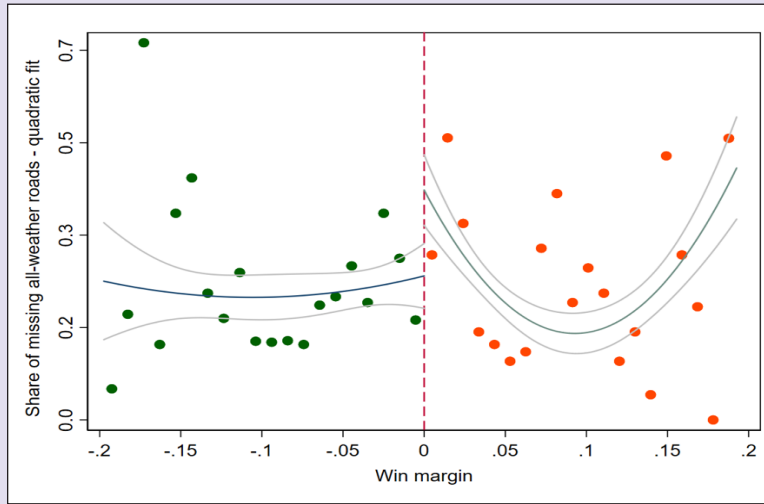
कड़े मुकाबले में चुनावों में जीत हासिल करने के बाद, जीतने वाले राजनेता से जुड़े ठेकेदारों को सड़क परियोजनाएं आवंटित किए जाने की संभावना बढ़ जाती है।



स्रोत: लेहने, शापिरो और आइंडी (2016)

इसके अलावा, लेखक ग्रामीण स्तर पर जनगणना 2011 के आंकड़ों का उपयोग यह जांचने के लिए करते हैं कि क्या पीएमजीएसवाई निगरानी डेटा में तैयार हो गई सड़क के रूप में सूचीबद्ध सड़कों जनगणना के आंकड़ों है या नहीं। शामिल कितनी ही बनी हुई बताई गई सड़कें जनगणना में दिखाई नहीं पड़ी-जिसे पता चलता है कि लगता है वे कभी बनाई ही नहीं गई थीं। या पूरी नहीं की गई थी। पी एम जी स नि. योजना में जनगणना से पूर्व बनी बताई गई 26 प्रतिशत सड़कें 2011 की जनगणना में विलुप्त पाई गई। सड़कों का तरजीही आवण्टन ऐसी विलुप्त सड़कों की संभावना को लगभग 86 प्रतिशत बढ़ादेता है। निम्न चित्र इसी नाटकीय प्रभाव को दर्शा रहा है। लेखकों ने पाया कि वरीयता-प्राप्त आबंटन से ऐसी 497 सकल वर्षीय सड़कों को आवण्टित किया गया जो विलुप्त है। वे 860,000 व्यक्तियों के प्रयोग में आ सकती थीं। इस योजना के अंतर्गत दिए गए वे ठेके जिनमें राजनीतिक प्रभाव की छाप थी उनसे गैर ईष्ट आर्थिक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

चुनाव जीतने के बाद जब ठेकेदारों के राजनीतिज्ञों से संबंध दिखाई देने लगे तब ऑल-वेदर सड़कों के लिए आबंटित किए जाने वाली निधि का किस्सा बढ़ गया



Source: Lehne, Shapiro & Eynde (2016)

लेखक ने पता लगाया कि इसके अतिरिक्त 497 ऐसी ऑल वेदर रोड्स सड़कें थी जिनका निर्माण 8,60,000 लोगों के लिए किया गया था जिसके लिए अधिमाम्य आबंटन खाते बनाए गए थे। स्पष्ट है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना संबंधी करार राजनैतिक रूप से प्रभावित था जिसने इष्टतम आर्थिक निष्कर्ष प्राप्त नहीं हुए।

3.27 वर्ष 1993 से पहले, आबद्ध खानों के आबंटन के लिए कोई विशिष्ट कसौटी विद्यमान नहीं थी। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 में जून, 1993 में किए गए संशोधनों में निजी कंपनियों को अपने सीमित प्रयोग के लिए कोयला खनन करने अनुमति प्रदान की गई। जुलाई, 1992 में आबद्ध खनन में इच्छुक विविध कंपनियों द्वारा किए गए आवेदनों पर विचार करने के लिए और विकास के लिए कोयला क्षेत्रों का आबंटन करने के लिए कोयला सचिव की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया गया। अगस्त, 2012 में, कोयला ब्लॉक आवंटन पर नियंत्रक, महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोयला खंडों के

आबंटन में अपनाई गई प्रक्रियाओं की प्रभावकारिता की जांच की गई। 24 सितम्बर, 2014 को भारत के उच्चतम न्यायालय ने 15 वर्षों की समयावधि के दौरान भारत सरकार द्वारा किए गए 218 आबंटनों में से 214 आबंटनों के रद्द कर दिया। कोयला खान (विशेष प्रावधान) विधेयक, 2014 और इसके परवर्ती नियम दिसम्बर, 2014 में पारित किए गए और कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015 को भारतीय खनन विधायी ढांचे में शामिल किया गया। इस अधिनियम में यह सुनिश्चित किया गया कि कोयला ब्लॉकों का कोई भावी आबंटन केवल प्रतिस्पर्धी नीलामियों के माध्यम से ही किया जाएगा।

² रिपोर्ट यहां पायी जा सकती है (वेबसाइट का पता अंग्रेजी में, यथावत रहेगा)

³ मनोहर लाल शर्मा बनाम प्रधान सचिव एवं अन्य, रिट याचिका सं. 1012 की 120, आदेश की प्रति यहां से प्राप्त की जा सकती है: <http://www.prsindia.org/uploads/media/Coal%20Mines/SC%20order.pdf>

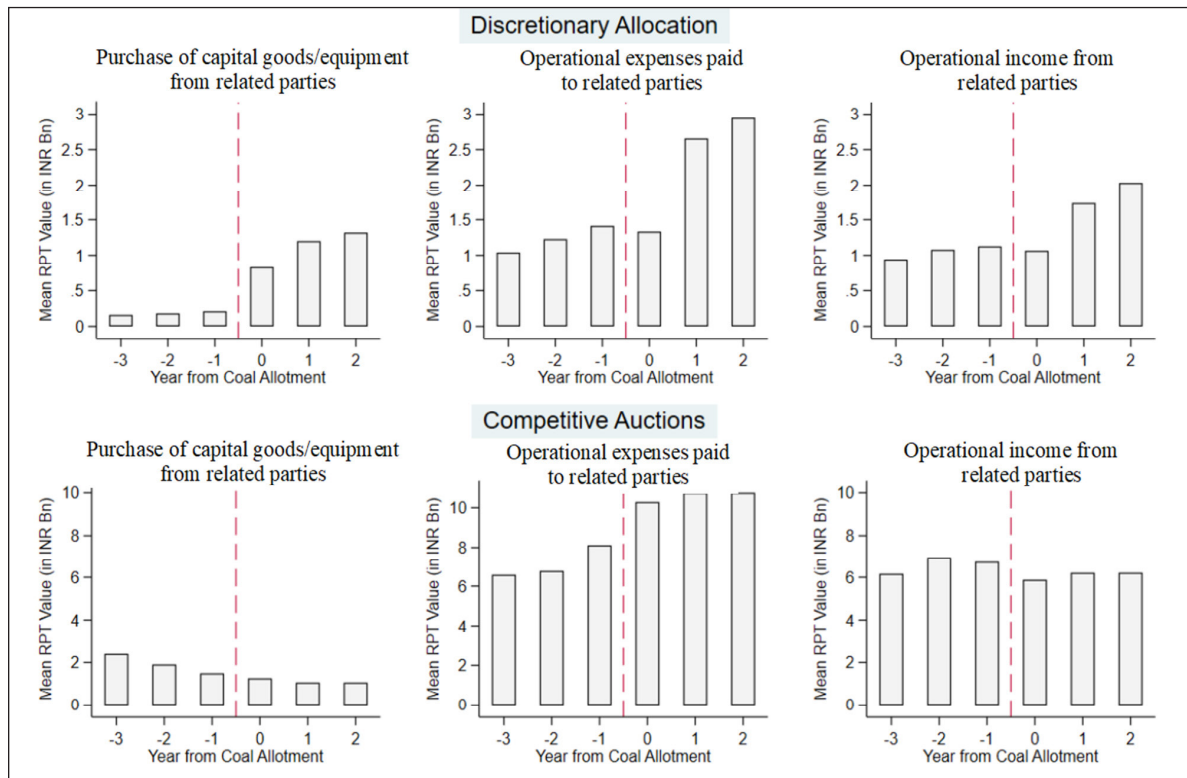
प्राकृतिक संसाधनों के विवेकाधीन में संबंधित पक्ष के लेन देनों का प्रयोग

3.28 अब्राहम, चोपड़ा, सुब्रमणियन एवं तांत्री (2018) को यह साक्ष्य प्राप्त हुआ कि कोयला ब्लॉक आवंटन के स्वरूप का उन फर्मों द्वारा लगाई गई संबंधित पार्टी के लेन-देनों (आर पी टी) के मान पर प्रभाव पड़ता है जो कोयला ब्लॉक आवंटन की लाभार्थी हैं। आवंटन से पूर्व 3 वर्ष की अवधि को आवंटन के बाद 3 वर्ष की अवधि तुलना में, उनको समिति आधारित आवंटन के लाभार्थियों बनाम प्रतिस्पर्धा आधारित आवंटन के लाभार्थियों द्वारा किए गए संबंधित पार्टी लेन-देनों के रूपया मूल्य में काफी भिन्नताएं दिखाई दीं।

3.29 चित्र 13 में ग्राफीय रूप से तीन शीर्षों के अंतर्गत आर पी टी/संबंधित पार्टी लेनदेनों की तुलना को चित्रित किया गया है। पहला शीर्ष, संबंधित पक्षकारों से पूंजीगत सामग्रियों/उपस्कर की खरीद के लिए प्रयुक्त संबंधित पार्टी लेन-देन हैं जिनको “पूंजीगत क्रय” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पूंजीगत क्रय संपदा अंतरण के

लिए एक आदर्श क्रियाविधि प्रदान करते हैं क्योंकि वे वृहद् एक बारगी होने वाले गैर-आवर्ती नकदी प्रवाह होते हैं जिनकी लेन-देनों को विनिसामकों से छिपाने के लिए समयानुकूल मुखोटे के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरा शीर्ष, संबंधित पक्षकारों के लिए किए गए प्रचालनात्मक व्यय हैं जिनको “राजस्व व्यय” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तीसरा शीर्ष, संबंधित पार्टियों से प्राप्त प्रचालनात्मक आय है जिसे “राजस्व आय” के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ये तीनों संबंधित पार्टी लेन-देन (आर पी टी) पूर्ववर्ती तीन वर्षों की तुलना में समिति आधारित आवंटन के माध्यम से कोयला ब्लॉक की प्राप्ति के बाद की तीन वर्षों की अवधि में निश्चित वृद्धि दर्शाते हैं। नीलामी आधारित आवंटन के मामले में इस प्रकार की कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। संबंधित पार्टी लेन-देन (आर पी टी) की अन्य तीन मुख्य किस्में-यथा पूंजीगत बिक्री, दिए गए ऋण और लिए गए और दिए अग्रिमों में समिति आधारित आवंटन के मामले में कोई खास वृद्धि नहीं दर्शायी गई है।

चित्र 13: संबंधित पक्षकर लेनेदेन पर कोयले के ब्लॉक के आवंटन का प्रभाव



स्रोत: अब्राहम, चोपड़ा सुब्रमणियन और तांत्री (2018)

असूचीबद्ध/विदेशी इकाइयों के लिए आर.पी.टी.

3.30 चित्र - 14 असूचीबद्ध/विदेशी इकाइयों वाले आर.पी.टी को दर्शाता है। ये इकाइयां या तो व्यक्ति हैं या असूचीबद्ध घरेलू उद्यम अथवा किसी विदेशी अधिकार क्षेत्र में गठित किए गए उद्यम होते हैं। चूंकि घरेलू प्रवर्तन प्राधिकारियों के लिए इस प्रकार की इकाइयों पर नज़र रखना कठिन है, इसलिए इस प्रकार की इकाइयों वाले आर.पी.टी. का अपारदर्शिता के प्रयोजन से उपयोग होने की संभावना है। जैसाकि यह चित्र दर्शाता है कि पुर्ण काव्यवहार पिछले चित्रों के जैसा है। समिति-आधारित आवंटन प्रक्रिया में कोयले के ब्लॉक के आवंटन के बाद पूंजीगत खरीद उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है जबकि प्रतिस्पर्धी निलामियों के बाद ऐसी किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं देखी गई है।

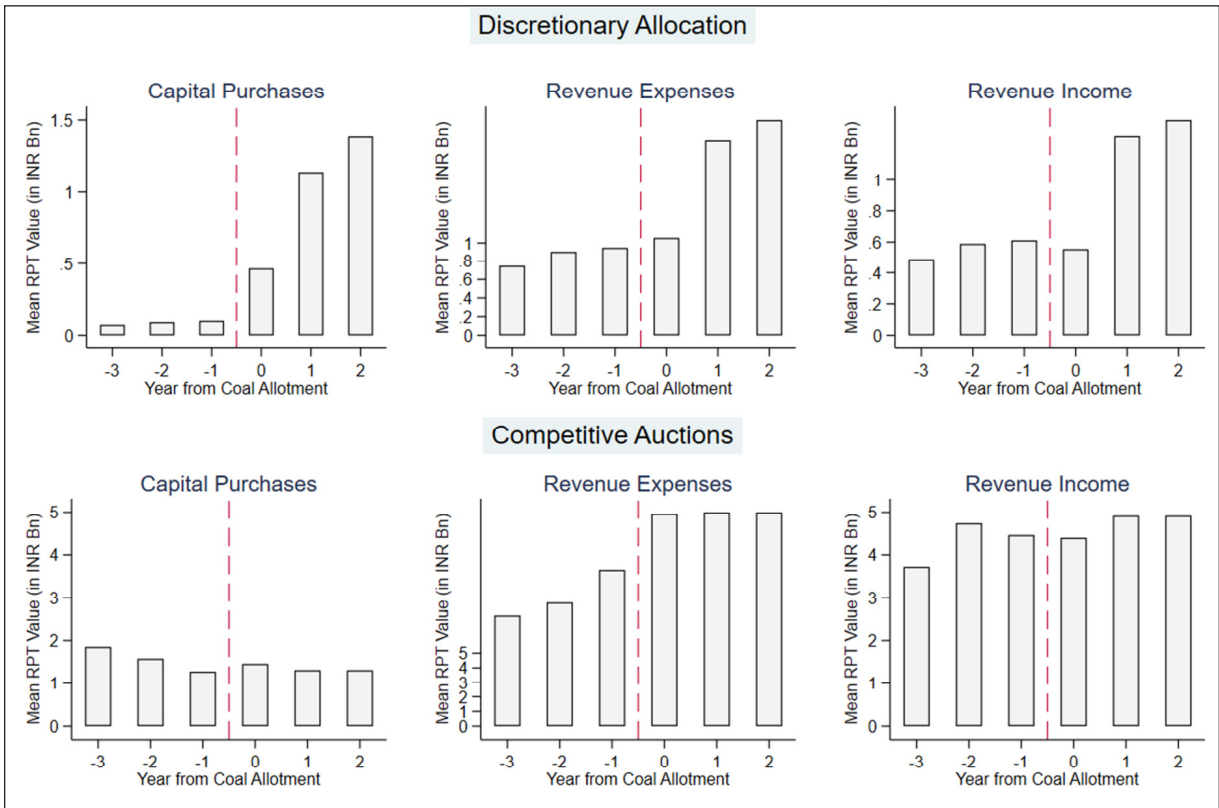
कर मुक्त क्षेत्रों देशों के लिए आर.पी.टी.

3.31 चित्र 15 निजके ऐसे आर.पी.टी. की जांच करता है, संबंधित प्रक्षकार जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त कर मुक्त क्षेत्रों (देशों) में आधारित हैं। इन कर मुक्त क्षेत्रों (देशों) का लक्षण अपारदर्शी प्रकटन विनियम होते हैं और इसीलिए ये अन्य से कॉर्पोरेट सम्यत्ति को हितधारकों से दर ले जाने के लिए एक आदर्श सिंक (कुंड) के रूप में कार्य करती है। हम पाते हैं, कि कोयले के ब्लॉक मिलने के बाद पूंजीगत खरीद और राजस्व आय के आर.पी.टी. उल्लेखनीय वृद्धि होती है इससे इस परिकल्पना अप्रत्याशित लाभ नियंत्रणकारी शेरधारकों द्वारा हड़प लिए जाते हैं।

फर्म की उत्पादकता और निष्पादन

3.32 इस बात के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं कि निदेशकों की कमीशन, अनुलब्धियां और परामर्श शुल्क जैसे

चित्र 14: असूचीबद्ध/विदेशी प्रतिपक्षों के लिए आर.पी.टी. संबंधित पक्षकार लेनदेन पर कोयले के ब्लॉक के आवंटन का प्रभाव



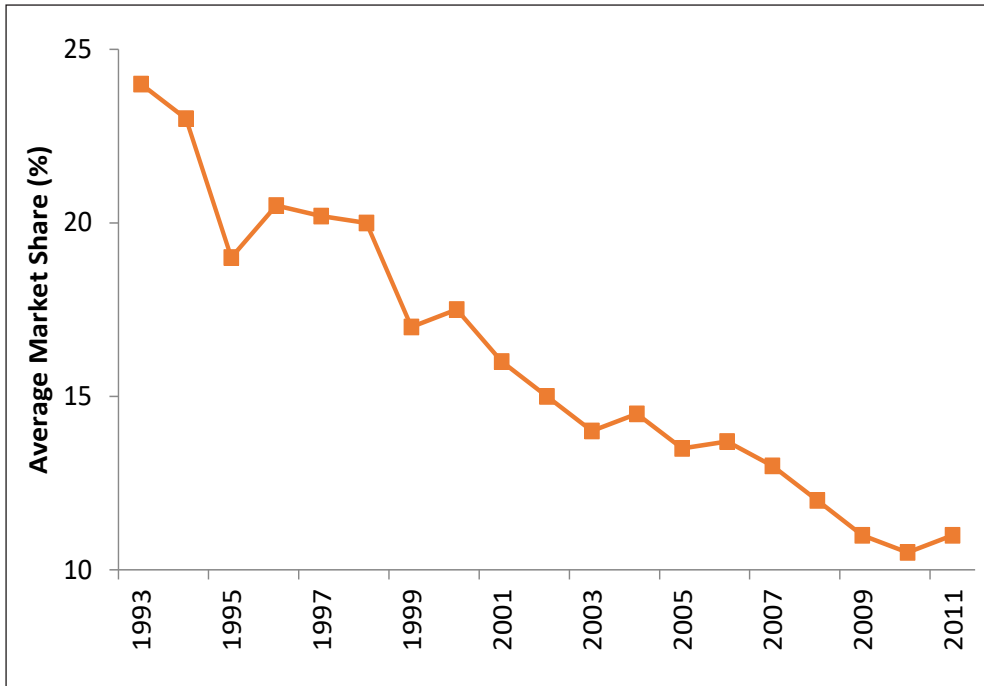
स्रोत: अब्राहम, चोपड़ा सुब्रमणियन और तंत्री (2018)

भुगतान विवेकाधीन आबंटन से बढ़ जाते हैं। निदेशक कमीशन में 12% निदेशक जिसे अनुलब्धियां में 5.7% और अन्य परामर्शी व्यय में 7.6% की वृद्धि होती है। हमें सामान्य कर्मचारियों के वेतन में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं मिली इसका आशय यह है कि विवेकाधीन आबंटन के बाद केवल निदेशकों को लाभ मिला। नीलामी के मामले में हमें इस प्रकार की कोई वृद्धि नजर नहीं आती। वास्तव में हमें ज्ञात हुआ है कि नीलामी आधारित आबंटन के बाद निदेशक का वेतन कम हुआ है।

3.33 चित्र 16 में 1993 से 2011 तक समिति आधारित आबंटन प्राप्त करने वाली फर्मों के औसत

मार्केट अंश का क्रमगत विकास दर्शाया गया है। इन फर्म के बाजार भाग में विवेकाधीन आबंटन के कारण अप्रत्याशित लाभ के बावजूद निरंतर गिरावट हुई है। लगभग मुफ्त संसाधनों का लाभ फर्म की उत्पादकता और व्यवसाय की मूलभूत बातों के लिए सहायक होनी चाहिए था। इसकी बजय बाजार के योगदान में निरंतर कई वर्षों से गिरावट डच व्याधि की आंशका होती है- जिस फर्म को मुफ्त संसाधन मिलते हैं वह अपने प्रयासों को उत्पादक व्यावसायिक गतिविधियों के स्थान पर अप्रत्याशित लाभ प्राप्त करने के मार्ग तलाशने में लगती है।

चित्र 15: कर आश्रय के लिए आरटीपी



स्रोत: अब्राहम, चोपड़ा सुब्रमणियन और तंत्री (2018)

3.34 वास्तव में यह पता चलता है कि जिस फर्म को आबंटन नहीं हुआ है उसकी तुलना में आबंटनी फर्म की कुल आमदनी में आवंटन की तिथि से 3 वर्षों अवधि में 54.9% गिरावट हुई है, इसके कुल खर्चों में 51.1% और पीएटी में 37.8% की कमी आई है। उत्पादक परिसंपत्तियों में भी क्षति नजर आती है - कुल परिसंपत्तियों में 76.2 प्रतिशत, और भूमि एवं भवन में 48.2 प्रतिशत तथा संयंत्र और मशीनरी में 51.1 प्रतिशत

की कमी आई है। उन्हें प्रतियोगी नीलामी के आबंटियों में इस प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आई।

3.35 समग्र रूप से, साक्ष्यों से यह पता चलता है कि समिति द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का विवेकाधीन आबंटन भाड़ाखोरी के लिए रास्ते उपलब्ध करवाता है। बाद में फर्म मालिकों ने अपना ध्यान उत्पादक गतिविधियों को आगे बढ़ाने की अपेक्षा इन से भाड़ा उगाहने की दिशा में केंद्रित किया। संसाधनों के बाजार आधारित आबंटन की ओर परिवर्तन इन भाड़ाखोरी के रास्तों को दूर करता

है, उत्पादकता आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देता है और अधिक सम्पत्ति उत्पन्न करता है।

जोखिम रहित प्रतिफल - जानबूझ कर चूक का मामला

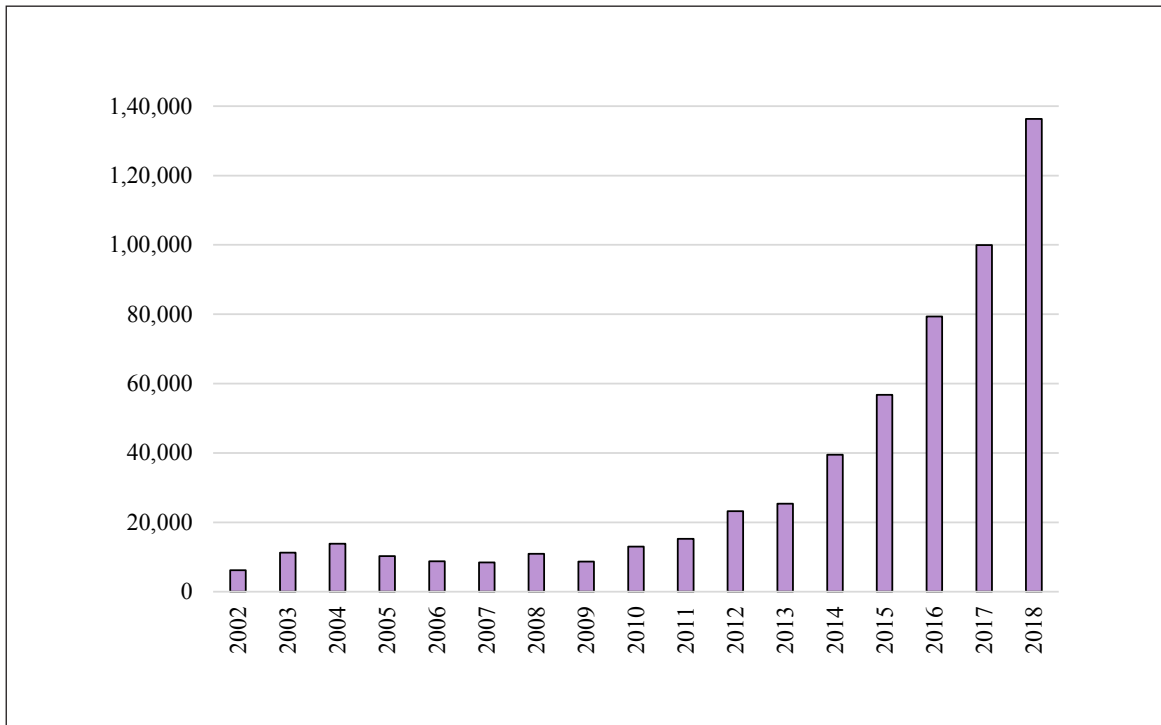
3.36 हालांकि, किसी भी निवेश का प्राथमिक सिद्धांत यह है कि उच्च प्रत्याशित प्रतिफल उच्च जोखिम के साथ आते हैं, कई भारतीय फर्मों ने अनुषांगिक जोखिम के बिना प्रतिफल प्राप्त करने का एक अनोखा तरीका तलाश लिया है। व्यवसाय अच्छे समय में लाभ का उपभोग करते हैं, किन्तु अक्सर खराब समय में स्थिति से उबरने के लिए वे सरकार या अपने वित्त प्रदाताओं के भरोसे रहते हैं। इस तरह के जोखिम रहित रिटर्न का एक विशेष रूप से असाधारण रूप विलफुल डिफॉल्ट (जानबूझ कर चूक) की घटना है - यह एकतरफा जुए का एक उत्कृष्ट तरीका है जिसमें 'हैड्स, आने पर प्रमोटर जीतता है; टेल्स आने पर ऋणदाता हार जाता है। विलफुल डिफॉल्ट उस समय होती है जब फर्म ऋण लेती हैं, फर्म से हुए लाभ को मालिक के निजी लाभ के लिए मोड़ देती हैं, ऋण शोधन में असमर्थता दर्शाती

हैं और स्वयं को दीवालिया घोषित कर देती हैं, जिसके द्वारा हितधारकों - लेंडर(ऋणदाताओं), अल्पसंख्यक शेयरधारक, कर्मचारी, विनियामक और सरकारी देयताओं को हजम कर लिया जाता है।

3.37 आरबीआई विलफुल डिफाल्टर को ऐसी फर्म के रूप में परिभाषित करती है जो अपनी देयताओं को पूरा करने की क्षमता होते हुए भी अपनी पुनर्भुगतान देयताओं को पूरा करने में चूक करती है। किसी फर्म को विलफुल डिफाल्टर नाम दिया जा सकता है, यदि वह अपनी निधियों का उपयोग उन उद्देश्यों से इतर किसी अन्य उद्देश्य के लिए करती है जिसके लिए ऋणदाता ने उसे ऋण स्वीकृत किया गया हो, संबंधित पार्टियों दे देती होया ऋण की प्रतिभूति के रूप में रखी परिसंपत्तियों को हटा देती है।

3.38 विलफुल डिफाल्टर को दिया गया प्रत्येक रुपया वैलथ (संपत्ति) के अपक्षरण का भाग है। वास्तविक व्यवसायी को उधार दी गई राशि से संपत्तियों का निर्माण होता है जिससे प्रतिफल और रोजगार की उत्पत्ति होती है। दूसरी ओर ऐसी फर्म को दी गई ऋण की राशि,

चित्र 16: आबंटित फर्मों का बाजार भाग (समिति आधारित आबंटन)



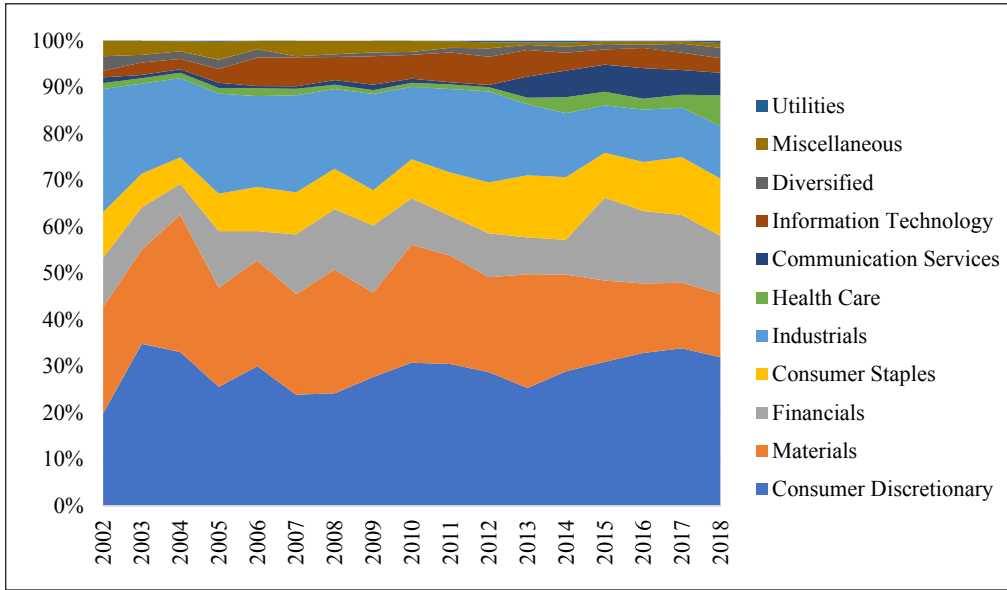
स्रोत: ट्रांस यूनिन सिविल मुकदमों का डाटाबेस

जिसकी पूर्व में ही लाभप्रद परियोजनाओं में निवेश की कोई मंशा न हो, बेकार जाती है। फर्म सम्बन्धियों/ मित्रों को अमीर बनाने के अलावा इनका के अलावा अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं होता।

बाहर निकाल लिया है। 2018 के अनुसार, विलफुल डिफाल्टर पर अपने - अपने ऋण दाताओं के 1.4 लाख रुपए बकाया हैं। चालू दशक के आरंभ से ही इनकी संख्या में वृद्धि हो रही है। ये डिफाल्टर बहुत से क्षेत्रों में व्याप्त हैं जिनमें से विनिर्माण फर्मों का हिस्सा सबसे अधिक संख्या है।

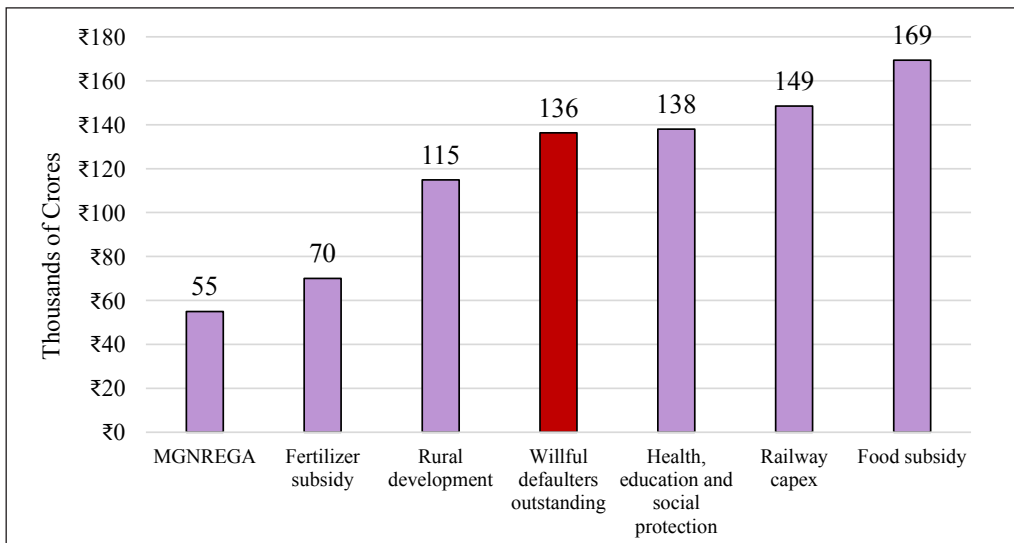
3.39 चित्र 17 और 18 उस राशि को दर्शाता है जिसे विलफुल डिफाल्टर ने भारतीय अर्थव्यवस्था से हटा

चित्र 17: विलफुल डिफाल्टरों से वसूली जाने वाली कुल बकाया राशि (भारतीय रुपए में)



स्रोत: ट्रांस यूनिजन सिविल मुकदमों का डाटाबेस

चित्र 18: जान बूझकर ऋण न चुकाने वालों पर समग्र बकाया राशि का क्षेत्रवार विभाजन

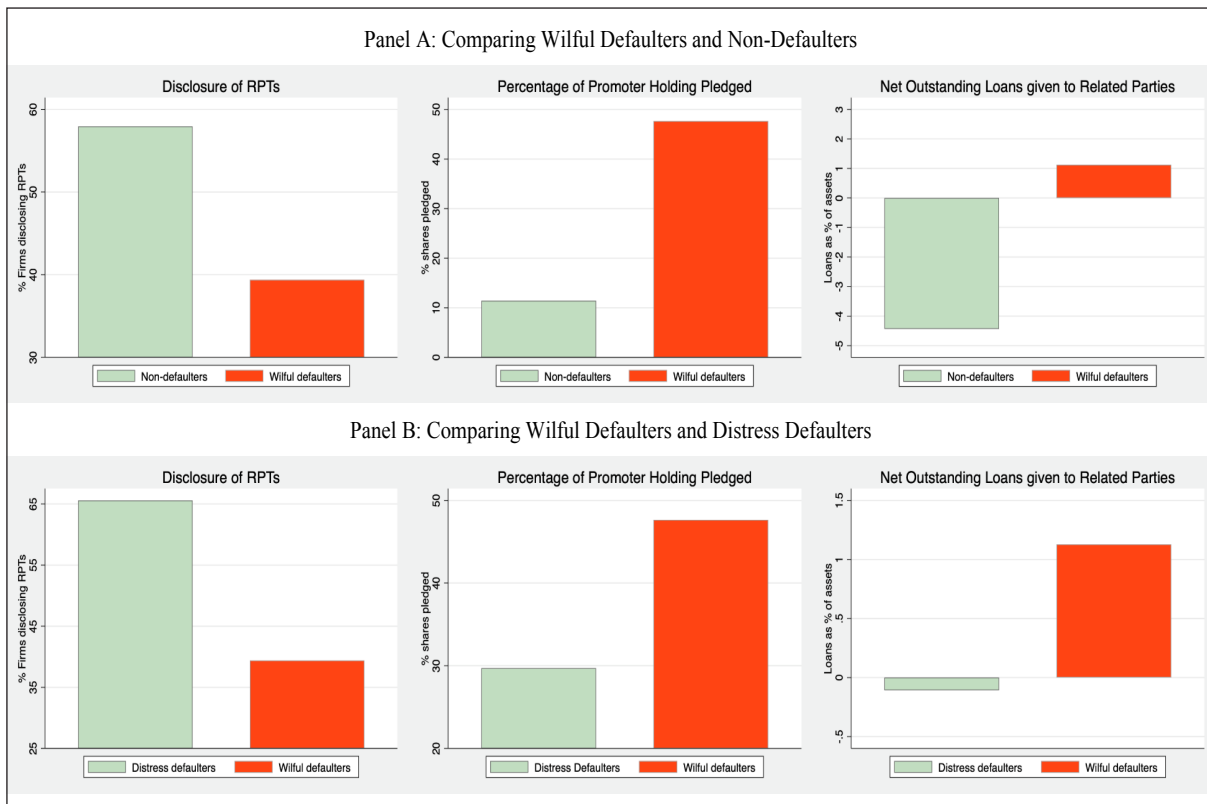


स्रोत: ट्रांस यूनिजन सिविल सूट फाईल्ड डाटाबेस संघीय बजट की रिपोर्ट।

3.40 जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों द्वारा हरी गई संपत्ति परिप्रेक्ष्य में रखने हेतु को चित्र 19 को देखिए इसमें 2018 में जान बूझकर ऋण न चुकाने वालों पर बकाया राशि की तुलना इसी वर्ष में नागरिकों के कल्याण हेतु संघीय बजट आवंटन से की गई है। जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों का धन अर्थव्यवस्था में विद्यमान रहता तो यह स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के आवंटन को दोगुणा, ग्रामीण विकास के आवंटन के दोगुणा, अथवा मनरेगा के आवंटन के तिगुणा करने हेतु आवश्यक राशि के बराबर होता।

3.41 चित्र 20 भारत में जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों के तीन विशिष्ट अभिलक्षण प्रदर्शित करता है। सर्वप्रथम, जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले, गैर-इरादतन चूककर्ता तथा वे फर्म जो वास्तविक तंगी (अब के बाद संकटग्रस्त चूककर्ताओं) में है उनकी अपेक्षा अधिक अपारदर्शी होते हैं। जहां लगभग 60 प्रतिशत अचूककर्ता और संकटग्रस्त-चूककर्ता अपनी वार्षिक रिपोर्ट में भारत में विधिक अपेक्षा के अनुसार संबंधित पक्ष का प्रकटन करते हैं वहीं जानबूझकर ऋण न चुकाने वाले मात्र 40 प्रतिशत भी ऐसा नहीं करते।

चित्र 19: इरादतन चूककर्ता अपने आरपीटी के बारे में अपरदर्शी होते हैं, प्रवर्तकों के शेयरों के बड़े भाग को जिगरवीरखते हैं तथा सम्बन्धित पार्टियों को बड़-बड़े ऋण प्रदान करते हैं।



स्रोत: ट्रांस यूनिन सिविल मुकदमों का डाटाबेस

नोट: यदि एक फर्म के वार्षिक विवरणी में एक आरपीटी खण्ड हो यदि वह कहे कि उसने वर्ष में कोई लेनदेन नहीं किए तो भी तो यह कहा जाता है कि फर्म पे आरपीटी प्रकरण किया है। निवल बकाया ऋण से तात्पर्य फर्म द्वारा संबंधित पार्टियों को दिए गए कुल ऋण के शेष से है, उनके लिए गए ऋण को घटाने के बाद इसे फर्म की कुल परिसंपत्तियों के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इरादतन चूककर्ता वे हैं जिनको सिब्ल सूट्स फाइल्ड डाटा बेस में इस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जबकि दबावग्रस्त चूककर्ता में हैं जिन को प्रतिदर्श अवधि में कम से कम एक बार चूक रेटिंग मिली है परन्तु जो 'इरादतन चूककर्ता' के रूम में वर्गीकृत नहीं किए गए हैं। अचूककर्ता गैर-चूककर्ता अन्य सभी फर्मों हैं आंकड़े 2002-18 हेतु हैं।

3.42 दूसरे यह कि इरादतन चूककर्ता फर्मों के कर्ता-धर्ता प्रवर्तक अपनी पूंजी का औसतन 50 प्रतिशत,

उधारदाताओं के पास, गिरवी रख देते हैं। इसके विपरीत चूककर्ताओं और गैर-इरादतन चूककर्ताओं के

संबंधित आंकड़े क्रमशः 30 प्रतिशत और 11 प्रतिशत हैं। हालांकि विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भी, शेयरों को गिरवी रखना प्रचलित है, वहीं भारत में इसने एक अजीबो-गरीब रूप ले लिया है। प्रवर्तक, विशेषतः जो इरादतन चूककर्ता फर्मों के हैं, शेयरों को गिरवी बाह्य व्यापारों अथवा वैयक्तिक उद्यमों के वित्त पोषण के लिए नहीं करते हैं बल्कि फर्मों की स्वयं की परियोजनाओं के लिए करते हैं। ऐसा व्यवहार ऋणदाताओं के लिए इष्टतम नहीं है चूंकि ऋण प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त संपाश्विक का मूल्य, निधियन (वित्तपोषित) की गई परियोजना के मूल्य के साथ सह-संबंधी नहीं होना चाहिए। जब कोई फर्म संकट में आती है तो उसका शेयरों का मूल्य गिर जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो जब उसकी वास्तव में आवश्यकता होती है तभी संपाश्विक अपना उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाता है। चूंकि प्रवर्तकों पर उनके द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों के अलावा कोई अन्य वैयक्तिक देयताएं नहीं होती हैं अतः जब उनके द्वारा गिरवी रखे गए शेयरों के मूल्य गिरते हैं तो वे उसकी नाम मात्र की चिंता करते हैं क्योंकि उनकी संपत्ति में कोई भी कमी की पूर्ति उस भाड़े से है। अनेक मामलों में प्रवर्तकों को कंपनी का नियंत्रण छूटने की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती क्योंकि वे शेयरों के डूबने से पहले भाड़ा निकाल चुके होते हैं।

3.43 तीसरे यह कि इरादतन चूककर्ता संबंधित पक्षों को बड़े-बड़े ऋण देते हैं। संकटग्रस्त चूककर्ताओं और गैर-चूककर्ताओं के लिए संबंधित पक्षों के दिए गए ऋणों का बकाया शेष नकारात्मक होता है, जिसका तात्पर्य यह कि नमूने में औसत फर्म, संबंधित पक्षों से ऋण की निवल प्राप्तकर्ता होती है। दूसरी तरफ, इरादतन चूककर्ता, निवल ऋण प्रदानकर्ता होता है। अजीब बात यह है कि जहां वे बाह्य ऋणों के प्राप्तकर्ता होते हैं और इन ऋणों पर चूककर्ता होते हैं वहीं दूसरी तरफ वे अपने संबंधित

पक्षों को ऋणों के निवल प्रदाता होते हैं। यह फर्मों के स्वामियों और उनके मित्रों के वैयक्तिक लाभ के लिए राशि को उपयोग करने के लिए कर्ज जारी करने के सिद्धांत के अनुकूल है।

3.44 ऐसे इरादतन चूककर्ताओं की लागत आम आदमी को वहन करनी पड़ती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपनी इक्विटी आम आदमी द्वारा अदा किए गए कर से प्राप्त करते हैं। वे आम आदमी द्वारा की गई जमा राशियों से ऋण प्राप्त करते हैं। जब निर्लज्ज फर्म जानबूझकर चूक करती है, तो आम आदमी को ही हानि होती है। जहां अधिकतर नीतियों का उद्देश्य अमीर से गरीब में संपत्ति का पुनः वितरण होता है वहीं इरादतन चूक से इसका विपरीत होता है। अमीर व्यापारी जो अधिक अमीर होना चाहते हैं, इरादतन चूक का उपयोग गरीब से संपत्ति ले कर और अमीर होना चाहते हैं।

नीतिगत सुझाव

3.45 केवल यह ही नहीं, यदि इरादतन चूककर्ता अनियंत्रित छूट जाए तो यह अन्य सभी के लिए उधार लेने की लागत को बढ़ाता है, इनमें सच्चे व्यापारी जिनके समक्ष लाभदायी निवेश अवसर होते हैं, भी शामिल हैं। वस्तुतः जब ऋण विस्तार (दिख जाने वाले ऋण पर व्याज दर व सर्वाधिक सुरक्षित निवेश पर बयाज दर के मध्य अन्तर) प्रतिकूल चयन सच्चे उधारकर्ताओं को बाजार से एक साथ बाहर कर देता है। इससे बाजार में केवल घोर/नकारात्मक पूंजीपति ही रहे जाते हैं और इसे बाजार असफल हो जाता है जिससे आर्थिक विकास, रोजगार और संपत्ति सृजन क्षमता में मंदी आ जाती है।

3.46 हालांकि बाजार अनुकूल नीतियों से प्रतिस्पर्द्धा में वृद्धि होती है, व्यापार अनुकूल नीतियां कभी-कभी बाजारों के प्रतिकूल बन जाती हैं। ऐसी नीतियों से सीमित व्यवसायिक हितों को तो लाभ पहुंचता है किंतु इससे समाज कल्याण प्रतिकूल रूप से हो सकता है क्योंकि व्यवसाय की आवश्यकता समाज के हित के प्रतिकूल हो सकती हैं। उदाहरणार्थः सरकार पर विभिन्न व्यापारियों द्वारा सम्मिलित रूप से दबाव बनाया जा सकता है कि उनके उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा को कम किया जाए उनसे प्रतिस्पर्द्धा करने

वाली मदों के आयात को प्रतिबंधित किया जाए अथवा नियमों के अनुपालन में कुछ छूट दी जाए। ऐसे प्रयासों से सम्मिलित दबाव बनाने वाले व्यापारी समूह की आय में बढ़ोत्तरी हो जाती है किंतु इससे

बाजार कमजोर हो जाता है और समग्र कल्याण कम हो जाता है। इस प्रकार व्यवसाय-अनुकूल (प्रो-बिजनस) नीतियां अनजाने में बाजार विरोधी बन जाती है।

अध्याय एक नजर में

- व्यवसायिक नीतियां सामाजिक कल्याण की कीमत पर निजी हितों का पक्ष लेती हैं, इस प्रकार धन का क्षय होता है।
- बाजार अनुकूल नीतियां बाजार की ताकत को उन्मुक्त करतीं, रचनात्मक विश्वास को प्रोत्साहित करती हैं और धन पैदा करती हैं।
- प्रभावशाली बाजार - अनुकूल प्रगति के बावजूद, भारत में अभी भी व्यवसाय अनुकूल अर्थशास्त्र प्रवल हैं। राजनीतिक रूप से जुड़ी फर्म जहां भी संभव हो भाड़े की तलाश करती हैं। उदाहरण: राजय द्वारा प्रदत्त ठेकों आदि हेतु राजनीतिक पैठ का उपयोग करना या इरावतन ऋणों के पुनर्भुगतान में चूक करना।
- अधिक बाजार अनुकूल और कम व्यवसाय अनुकूल होने के लिए, सरकार को राजनेता - व्यवसाय की मिली भगत, के लिए रास्ते को सीमित करना चाहिए राजनीतिक संबंध पर कॉर्पोरेट पारदर्शिता, को आवश्यक बनाना चाहिए, परिसंपत्तियों के स्वामित्व में संकेन्द्रण को सीमित करना चाहिए और प्रतिस्पर्धी बाजारों के लिए व्यापक समर्थन बनाएं रखना।

संदर्भ

Abraham, Jefferson Kaduvinal, Yakshup Chopra, Krishnamurthy Subramanian, and Prasanna Tantri. 2019. "Natural resource curse as applied to firms: Evidence from India." *Working Paper*.

B.S., Sunil. 2014. "India's stock market just confirmed: It really pays to have political connections." *Quartz India*, 19 June.

Bae, Kee-Hong, Jun-Koo Kang, and Jin-Mo Kim. 2002. "Tunneling or value added? evidence from mergers by korean business groups." *The journal of finance*.

Bertrand, Marianne, Paras Mehta, and Sendhil Mullainathan. 2002. "Ferreting

Out Tunneling: An Application to Indian Business Groups." *The Quarterly Journal of Economics* 117 (1): 121-148.

Bliss, Mark A., and Ferdinand A. Gul. 2012. "Political connection and cost of debt: Some Malaysian evidence." *Journal of Banking & Finance* 1520-1527.

Bulkanwanicha, Pramuan, and Yupana Wiwattanakantang. 2009. "Big Business Owners in Politics." *The Review of Financial Studies* 22 (6): 2133-2168.

Chan, Kenneth S., Vinh Q.T. Dang, and Isabel K.M. Yan. 2012. "Chinese firms' political connection, ownership, and financing constraints." *Economics Letters* 164-167.

- Chen, Donghua, Yuyan Guan, Tianyu Zhang, and Gang Zhao. 2017. "Political connection of financial intermediaries: Evidence from China's IPO market." *Journal of Banking and Finance* 15-31.
- Cheung, Yan-Leung, P Raghavendra Rau, and Aris Stouraitis. 2006. "Tunneling, propping, and expropriation: evidence from connected party transactions in hong kong." *Journal of Financial Economics*.
- Civilize, Sireethorn, Udomsak Wongchoti, and Martin Young. 2015. "Political Connection and Stock Returns: A Longitudinal Study." *The Financial Review* 89-119.
- Claessens, Stijn, Erik Feijen, and Luc Laeven. 2008. "Political connections and preferential access to finance: The role of campaign contributions." *Journal of Financial Economics* 554-580.
- Deng, Kebin, Haijian Zeng, and Yushu Zhu. 2019. "Political connection, market frictions and financial constraints: evidence from China." *Accounting & Finance* 2377-2414.
- Faccio, Mara. 2006. "Politically Connected Firms." *The American Economic Review* 96 (1): 369-386.
- Faccio, Mara, Ronald W. Masulis, and John J. McConnell. 2006. "Political Connections and Corporate Bailouts." *The Journal of Finance* 2597-2635.
- Firth, Michael, Chen Lin, Ping Liu, and Sonia M.L. Wong. 2009. "Inside the black box: Bank credit allocation in China's private sector." *Journal of Banking & Finance* 1144-1155.
- Fisman, Raymond. 2001. "Estimating the Value of Political Connections." *The American Economic Review* 1095-1102.
- Friedman, Milton. 1999. "Policy Forum: "Milton Friedman on business suicide"." *CATO Institute*. 1 March. <https://www.cato.org/policy-report/marchapril-1999/policy-forum-milton-friedman-business-suicide>.
- IIFL Wealth. 2019. *IIFL Wealth-Hurun India Rich List: Here are India's richest in 2019; Mukesh Ambani tops charts 8th year in a row*. 25 September. Accessed December 15, 2019. https://www.iiflwealth.com/newsroom/in_the_news/iifl-wealth-hurun-india-rich-list-here-are-indias-richest-2019-mukesh-ambani.
- Johnson, Simon, and Todd Mitton. 2003. "Cronyism and capital controls:evidence from Malaysia." *Journal of Financial Economics* 351-382.
- Kahkonen, Satu. 2018. *What Is the Cost of Crony Capitalism for Ukraine?* 15 March. <https://www.worldbank.org/en/news/opinion/2018/03/15/what-is-the-cost-of-crony-capitalism-for-ukraine>.
- Kant, Krishna. 2016. *1991 to 2016: How the Sensex has transformed in 25 years*. 27 July. Accessed November 5, 2019. <https://www.rediff.com/business/report/how-the-sensex-has-transformed-in-25-years/20160727.htm>.
- Khanna, Tarun, and Yishay Yafeh. 2007. "Business groups in emerging markets: Paragons or parasites." *Journal of Economic literature*.
- Kishore, Roshan. 2016. "Does black money boost economic growth?" *Livemint*, 18 November.

Lehne, Jonathan, Jacob N. Shapiro, and Oliver Vanden Eynde. 2018. "Building connections: Political corruption and road construction in India." *Journal of Development Economics* 62-78.

Onder, Zeynep, and Süheyla Ozyildirim. 2011. "Political Connection, Bank Credits and Growth: Evidence from Turkey." *The World Economy* 1042-1065.

Rajan, Raghuram G., and Luigi Zingales. 2003. *Saving Capitalism from the Capitalists*. New Jersey: Princeton University Press.

Rajan, Raghuram. 2014. *Saving Credit (Talk by Dr. Raghuram G. Rajan, Governor, Reserve Bank of India at the Third Dr. Verghese*

Kurien Memorial Lecture at IRMA, Anand on November 25, 2014). 25 November. https://www.rbi.org.in/scripts/BS_SpeechesView.aspx?Id=929.

Rand, John. 2017. "Are politically connected firms less constrained in credit markets?" *UNU-WIDER Working Paper 2017/200*.

Romer, Paul M. 2000. "Should the Government Subsidize Supply or Demand in the Market for Scientists and Engineers?" *NBER Working Paper Series*.

World Bank. 2018. *Crony Capitalism in Ukraine: Impact on Economic Outcomes*. Washington, D.C.: World Bank Group.

बाजार की अनदेखी: जब अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप से लाभ की बजाय नुकसान होता है।

04

अध्याय

क्षणशः कणशश्चैव विद्याम् अर्थं च साधयेत्।
क्षणं नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम्॥

लोगों को प्रत्येक पल विद्ययार्जन का प्रयास करना चाहिए? इसी प्रकार लोगों को संसार के प्रत्येक कण से अर्जन करना चाहिए। यदि आप एक पल भी नष्ट करते हैं, तो ज्ञानार्जन नहीं कर सकते हैं। और यदि आप एक कण भी गंवाते हैं। तो आप धन का अर्जन नहीं कर सकते हैं।?

यद्यपि सरकारी हस्तक्षेप नेक इरादों से किया जाता है प्रायः सम्पदा का सृजन करते समय बाजारों की क्षमता को कम करके आंका जाता है और परिणाम अपेक्षा के अनुरूप नहीं होता है। इस अध्याय में विगत समय अर्थात् एनाक्रोनोटिक सरकार के हस्तक्षेप के चार उदाहरणों का विश्लेषण किया गया है, हालांकि ऐसे और कई उदाहरण दिए जा सकते हैं। प्रथम आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के तहत वस्तुओं पर कुल स्टॉक सीमा पर लगातार और अप्रत्याशित प्रतिबंध से न तो कीमतों में कमी आती है और न ही मूल्य अस्थिरता को कम करने में मदद मिलती है। हालांकि इस तरह के हस्तक्षेप से लाभ प्राप्त करने और उत्पीड़न जैसे कृत्य को बढ़ावा मिलता है। उदाहरण के लिए, सितंबर 2019 में प्याज पर स्टॉक सीमा लागू करने से थोक और खुदरा कीमतों में स्थिरता आने की बजाय अस्थिरता बढ़ गई थी, जो कि कीमतों में ढील देने के अपने उद्देश्य के विपरीत था।

दूसरा, डीपीसीओ 2013 के माध्यम से दवाओं की कीमतों के विनियमन के जरिए विनियमित फार्मास्युटिकल दवा (कॉम्बीफ्लैम) के मूल्य में, तुलनात्मक रूप से जो दवाएं विनियमित नहीं हैं, वृद्धि की गई है (आई एन ए सी)। हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि कीमतों में वृद्धि का मूल कारण तुलनात्मक रूप से खर्चीले निरूपण का सहारा लेना था और खुदरा दुकानों के बजाय अस्पतालों में बेची गई थीं, इससे इस बात को बल मिलता है कि परिणाम डीपीसीओ के उद्देश्य के विपरीत है, जबकि डीपीसीओ का उद्देश्य दवाओं को सस्ती दरों पर आम लोगों को उपलब्ध कराना है।

तीसरा, सरकार खाद्यान्न बाजार में सरकारी संग्रहकर्ता के रूप में एक प्रमुख भूमिका निभाती है, जिसके फलस्वरूप इन बाजारों में प्रतिस्पर्धा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इसके फलस्वरूप एफ सी आई में बफर स्टॉक के अतिप्रवाह होने से खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए जगह की भी कमी पड़ गई, सब्सिडी का बोझ बढ़ गया है, और अनाज की मांग और आपूर्ति के बीच सामंजस्य नहीं। होने के कारण फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलता है।

चौथा, राज्यों/केंद्र द्वारा की गई कर्जमाफी के विश्लेषण से पता चलता है कि पूर्ण लाभप्राप्त करने वाले लोग कम उपभोग करते हैं, कम बचत करते हैं, कम निवेश करते हैं और कर्जमाफी के बाद आंशिक लाभार्थियों की तुलना में कम उत्पादक होते हैं। आंशिक लाभार्थियों की तुलना में पूर्ण लाभार्थियों के लिए औपचारिक ऋण की हिस्सेदारी घट जाती है, जिससे किसानों को प्रदान की गई कर्ज माफी का उद्देश्य समाप्त हो जाता है। अध्याय में निवेश और विकास को बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धी बाजारों के कामकाज को सहज बनाने हेतु एक केस के रूप में अध्ययन किया गया है

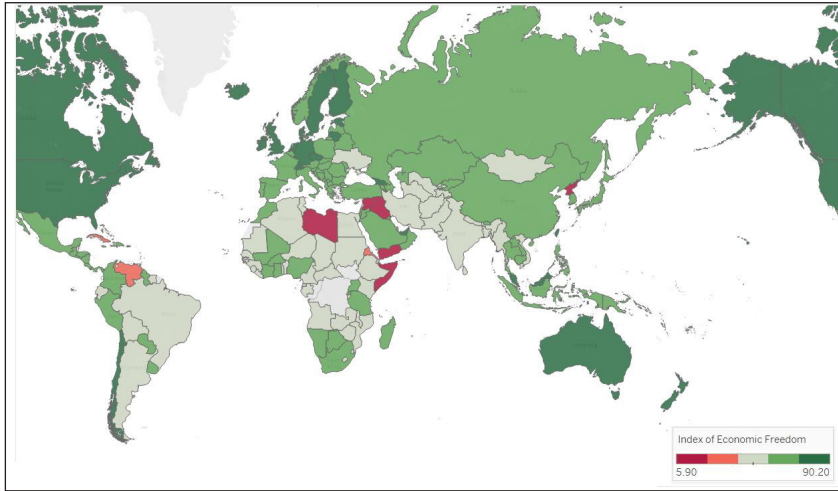
अध्याय इस बात की पुष्टि करता है कि सरकार में प्रत्येक विभाग और मंत्रालय को व्यवस्थित ढंग से उन क्षेत्रों की जांच करनी होगी जहां सरकार अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करती है और बाजार

को नजर अंदाज करती हैं ध्यान दें कि अध्याय यह तर्क नहीं करता कि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बल्कि विभिन्न आर्थिक व्यवस्था में जो हस्तक्षेप उचित थे उन्होंने परिवर्तित अर्थव्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता खो दी है। अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के ऐसे उदाहरणों को दूर करने से प्रतिस्पर्धी बाजार को सक्षम बनाएगा और जिसके चलते निवेश और आर्थिक उन्नति को प्रोत्साहन मिलेगा।

4.1 यद्यपि भारत ने फर्मों और अपने नागरिकों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने की दिशा में काफी महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी इसे दुनिया की जर्जर (जकड़ी हुई) अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता वैश्विक सूचकांकों में, भारत निचले आधे

स्थान पर आता है। हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा लाए गए आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा लाए गए वैश्विक आर्थिक सूचकांक द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता को लोगों द्वारा आर्थिक सम्मान और संसाधनों को प्राप्त करने और उपयोग करने में अपनी पसंद की

चित्र 1: भारत में सापेक्ष वैश्विक आर्थिक

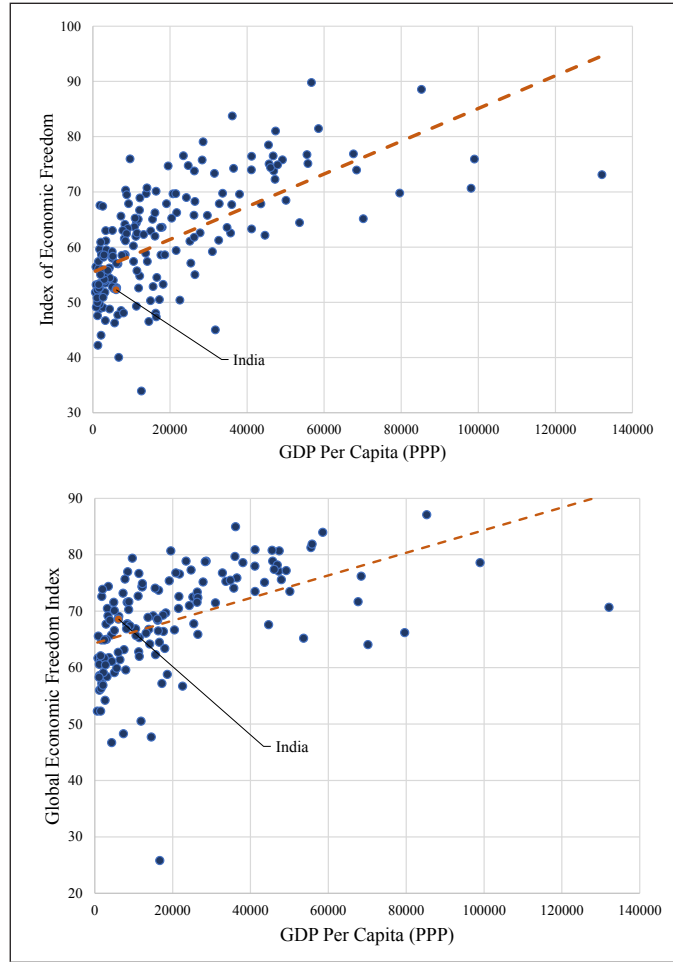


स्रोत: आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक 2019 <http://www.heritage.org/index/> पर देखा जा सकता है।

स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने की आर्थिक आजादी के रूप में मापा जाता है। वर्ष 2019 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को 186 देशों के बीच 5.5 अंकों/स्कोर के साथ 129वें स्थान पर अर्थात् नीचे के 30% देशों में “अधिकांश अस्वतंत्र/अन-‘फ्री’” के रूप में वर्गीकृत किया गया था (चित्र-1)। “निवेश स्वतंत्रता” से संबंधित घटक में, जो आंतरिक रूप से और देश की सीमाओं के पास पूंजी निवेश के सुगम प्रवाह को मापता है, भारत, 0-100 (दमित) के पैमाने पर 58.5 विश्व औसत की तुलना में मात्र 40.0 अंक/स्कोर करता है। वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक में भी, भारत 162 देशों में से व्यापार विनियमन में 108वें स्थान पर होते हुए 79वें स्थान पर है।

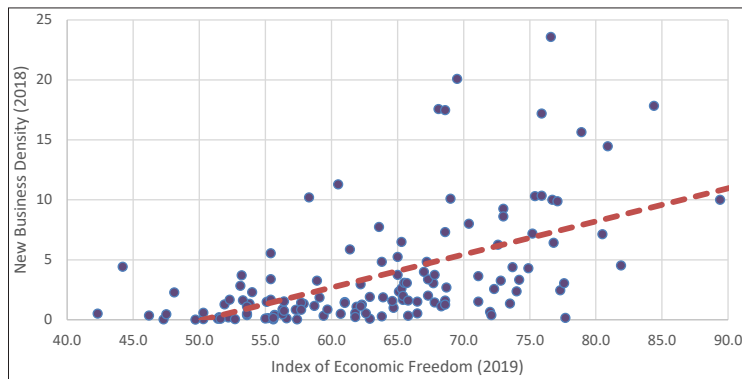
4.2 आर्थिक स्वतंत्रता, उद्यमशीलता संसाधनों के कुशल आवंटन और उत्पादक गतिविधियों के लिए ऊर्जा को सक्षम करके धन सृजन को बढ़ाती है, जिससे आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिलता है। यह देशों के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के साथ आर्थिक स्वतंत्रता के दो संदर्भित सूचकांकों में रैंकों के निकट सहसंबंध के रूप में अभिव्यक्त होता है। (चित्र-2) आर्थिक स्वतंत्रता में निम्न रैंक से यह स्पष्ट होता है कि भारत आने वाले नागरिकों के लिए आर्थिक स्वतंत्रता को झकझोर कर धन सृजन के अवसर प्रदान करता है। चित्र 3-7 में क्रमशः नए व्यापार/व्यवसायों के पंजीकरण की संख्या के साथ आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक के क्षेत्र-पार सहसंबंध, व्यापार करने में आसानी से संकेतकों/सूचकों, किसी देश में लागू पेटेंटों की संख्या

चित्र 2: आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का प्रति व्यक्ति सकल प्राथमिक घाटा (जी डी पी) से परस्पर संबंध



स्रोत: <https://www.heritage.org/undex> पर निर्धारित आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक और <https://www.fraserinstitute.org/> पर निर्धारित वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक

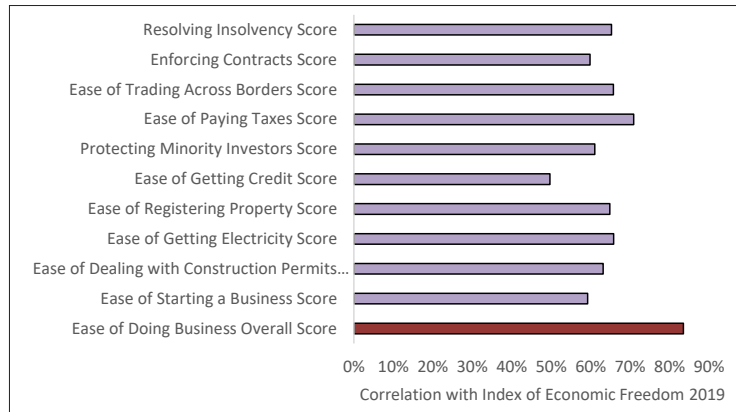
चित्र 3: आई ई एफ से नए व्यवसाय पंजीकरण के घनत्व से परस्पर संबंध नए व्यवसाय का घनत्व (2018)



आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक (2019)

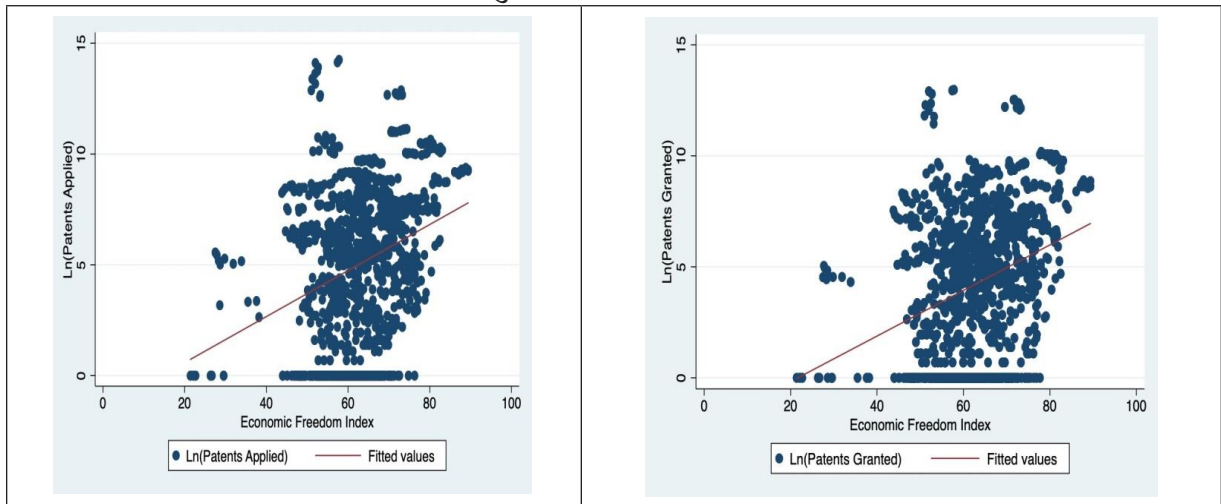
टिप्पणी: नए व्यवसाय में प्रवेश से संबंधित घनत्व को प्रति 1000 कार्य करने वाले व्यक्ति (15-64 वर्ष की आयु के व्यक्ति) हाल ही में पंजीकृत निगमों की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। माप यूनिट, प्राइवेट, सीमित देयता वाली औपचारिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं।

चित्र 4: आर्थिक स्वतंत्रता का व्यापार करने की सुगमता से परस्पर संबंध



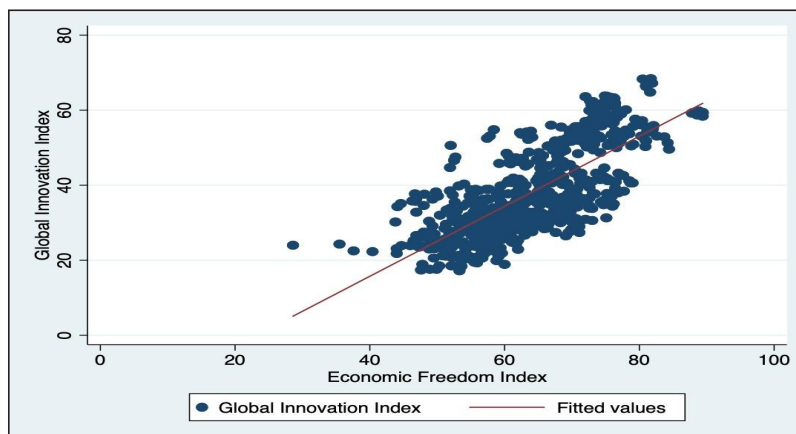
आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक सहसंबंध 2019

चित्र 5: आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक का आवेदन किए गए पेटेंट तथा अनुदत्त पेटेंट के साथ सहसंबंध



स्रोत: एन.बी.ई.आर. डाटा तथा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक
<https://www.heritage.org/index> पर उपलब्ध है।

चित्र 6: आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक का नवाचार सूचकांक के साथ संबंध



स्रोत: विश्व मौद्रिक संपदा संगठन (डब्ल्यू.आई.पी.ओ.) डाटाबेस तथा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक <https://www.heritage.org/index> पर उपलब्ध है।

तथा नवाचार सूचकांक में दर्शाया है इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आर्थिक स्वतंत्रता, धन सृजन के कई पहलुओं को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है।

4.3 आवश्यक वस्तु अधिनियम हालांकि बाजार में अव्यवस्था पैदा कर कृषि बाजारों के कार्यक्षम विकास को प्रभावित करता है (चित्र 8) चूंकि कृषि मौसमी आधारित कार्यकलाप है, इसलिए वर्ष भर स्थिर कीमतों पर उत्पाद की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु गैर-मौसम के लिए उत्पाद का भंडारण आवश्यक है। अतएव, उत्पादक समुदाय फसल के मौसम में इन्वेंटरी तैयार करने तथा मंदी के मौसम में इन्वेंटरी को बाजार में उतारने की अवधि के मध्य की अवधि में व्यापार ठप पड़ जाने की स्थिति का सामना करता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम स्टॉक सीमा के बारंबार तथा अप्रत्याशित अधिरोपण के कारण मालगोदाम और भंडारण सुविधाओं में निवेश को हतोत्साहित करते हुए इस प्रणाली में हस्तक्षेप करता है। चूंकि स्टॉकहोल्डिंग सीमा संपूर्ण कृषि आपूर्ति श्रृंखला पर लागू होता है, जिसमें थोक विक्रेता खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तथा खुदरा खाद्य श्रृंखला शामिल

हैं, यह अधिनियम अपने प्रचालनों की प्रवृत्ति वाले स्टॉक को अपने पास रखने की वास्तविक आवश्यकता वाले फर्मों तथा स्टॉक को अपने पास संचित रखने वाले संभावित फर्मों के मध्य भेद नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, यह अधिशेष क्षेत्रों से उच्च मांग वाले बाजारों में मुक्त व्यापार की प्रभावकारिता तथा वस्तुओं के प्रवाह में कमी लाता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम वस्तु व्युत्पत्ति बाजार को भी प्रभावित करता है, क्योंकि व्यापारी स्टॉक सीमा के कारण विनिमय मंच निर्धारित यात्रा को प्रदान करने के समर्थ नहीं भी हो सकते हैं। यह अधिनियम कृषि विपणन, के क्षेत्र में अनिश्चिता में वृद्धि करके तथा निजी क्षेत्र के बड़े प्रतिस्पर्धियों के प्रवेश को हतोत्साहित करके बाजार में यह अव्यवस्था आगे कृषि वस्तुओं की कीमत अस्थिरता को बढ़ा देती है, जो कि इसके उद्देश्य के विपरीत है।

4.4 जैसा कि हम इस अध्याय में देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था ऐसे उदाहरणों से भरी पड़ी है जहां सरकार बाजार विफलता जोखिम न होने के बावजूद हस्तक्षेप करती है और वास्तव में कुछ उदाहरणों में इसके

बॉक्स 1: आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1995

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 आवश्यक मानी जाने वाले कुछ वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण को नियंत्रित करने तथा उनके मध्य व्यापार और वाजिज्य हेतु अधिनियम किया गया। यह अधिनियम अपने आप में नियमों और विनियमों की व्यवस्था नहीं करता है, बल्कि डीलर को लाइसेंस प्रदान करने, स्टॉक सीमा को निर्धारित करने, वस्तुओं के संचलन को सीमित करने तथा उद्ग्रहण प्रणाली के तहत अनिवार्य खरीद की आवश्यकताओं के संबंध में नियंत्रण आदेश जारी करने हेतु राज्यों को अनुमति प्रदान करता है। यह अधिनियम ज़ब्त किए गए स्टॉक को अधिहरित करने; लाइसेंस को निलंबित/निरस्त करने, यदि कोई है तथा दंड यथा कारावास आरोपित करने हेतु कार्रवाई की व्यवस्था की प्रदान करता है। यह अधिनियम मूल्य निर्धारण की शक्ति भी प्रदान करता है, और किसी वस्तु को निर्धारित मूल्य सीमा से अधिक दाम पर बेचना दंड का कारण बनेगा। इस अधिनियम के अंतर्गत अधिकांश शक्तियों को केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को इस निर्देश के साथ प्रत्यायोजित किया गया है कि वे इन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। राज्यों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों का निस्पादन करेंगे।

इस अधिनियम में शामिल वस्तु समूह निम्नलिखित है

- (i) पेट्रोलियम और इसके उत्पाद जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नाफ्था, विलायक द्रव आदि शामिल है।
- (ii) खाद्य सामग्री जिसमें खाद्य तेल एवं बीज, वनस्पति, दलहन, गन्ना और इसके उत्पाद जैसे खांडसारी तथा चीनी, धान की फसल आदि शामिल हैं
- (iii) कच्चा जूट तथा जूट टेक्सटाइल
- (iv) दवाएं-आवश्यक दवाओं की कीमतें आज भी डीपीसीको द्वारा नियंत्रित की जाती हैं
- (v) उर्वरक-उर्वरक नियंत्रण आदेश उर्वरक की कीमतों के अलावा इसके अंतरण और स्टॉक पर प्रतिबंध का निर्धारण करता है।
- (vi) प्याज और आलू
- (vii) खाद्य फसलों, फलों और सब्जियों के बीज, पशुओं का चारा, जूट के बीज और कॉटन के बीज

हस्तक्षेप से बाजार विफलता की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसा कुछ हद तक स्वतंत्र आर्थिक नीतियों के बाद की वैधता के कारण हो सकता है। परन्तु चूँकि बाजार की भूमिका को पूरे विश्व में स्वीकार किया गया है अतः स्वाभाविक रूप से शीघ्र धन अर्जन के लिए बाजारों को कार्य करने की अनुमति दी गई है ताकि आर्थिक विकास हो।

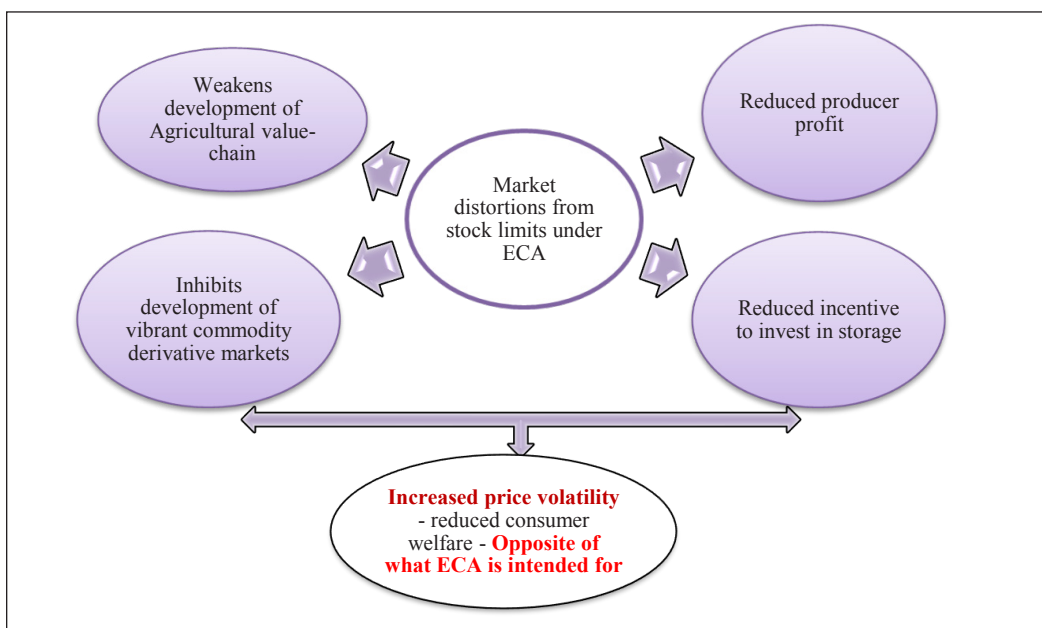
आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई सी ए), 1955

4.5 आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई सी ए), 1955 के अनुसार सब्सिडी, दलहन, खाद्य तेल, चीनी इत्यादि जैसे कुछ खाद्य सामग्रियों में जिसे आवश्यक वस्तुएं मानी जाती हैं, का उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण एवं व्यापार एवं वाणिज्य द्वारा किया जाता है। अधिनियम के अधीन उपबंधों को कार्यान्वित करने की शक्तियों का प्रत्यायोजन राज्यों को किया गया है। इन आवश्यक वस्तुओं में से किसी एक का मूल्य बढ़ने पर स्टॉक रखने की सीमा के संबंध में विनिमय लागू हो सकता है, माल का आवागमन प्रतिबंधित हो सकता है और वसूली की प्रणाली के अंतर्गत अनिवार्य खरीद अधिदेश लागू हो सकता है। इसके परिणामस्वरूप सभी उत्पाद से संबंधित थोक विक्रेताओं, एवं खुदरा व्यापारियों द्वारा अपनी इनवेंटरी कम की जानी चाहिए ताकि वस्तु

रखने की सीमा का अनुपालन हो सके, इस अधिनियम का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगा के गरीबों के लिए आवश्यक वस्तुएं सस्ती दर पर मुहैया सुनिश्चित करना है। यह कृषि विपणन एवं उत्पादन विनियमन का अतिरिक्त विधान है।

4.6 इसीए तथापि बाजार विरूपणों के द्वारा कृषि बाजारों के प्रभावशाली विकास को प्रभावित करता है (चित्र 7)। चूँकि कृषि एक मौसमी गतिविधि है अतः पुरे वर्ष उत्पाद की सततः कीमतों पर आसानी से उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु गैर मौसमी दिनों हेतु उत्पाद का भंडारण आवश्यक है। यही कारण है कि उत्पादक बुआई के मौसम में इन्वेन्टरी तैयार करने और गैर-कृषि मौसम में इन्वेन्टरी से उत्पाद निकालने के बीच एक बुनियादी ट्रेड ऑफ का सामना करते हैं। इसीए भंडारण सीमाओं के लगातार और अप्रत्याशित दबाव के कारण वेअरहाउसिंग और भंडारण सुविधाओं में निवेशों को प्रोत्साहन न देकर इस कार्यपद्धति में हस्तक्षेप करता है। क्योंकि स्टॉक-हॉल्लिडिंग सीमाएं थोक विक्री कर्ताओं खाद्य श्रृंखलाओं सहित संपूर्ण कृषि आपूर्ति श्रृंखला पर लागू होती है। अतः इस अधिनियम के तहत ऐसे फर्मों जिन्हें कि अपने प्रचालनों की प्रकृति के अनुरूप भंडारण रखना होता है और ऐसी फर्म जोकि अनुमान

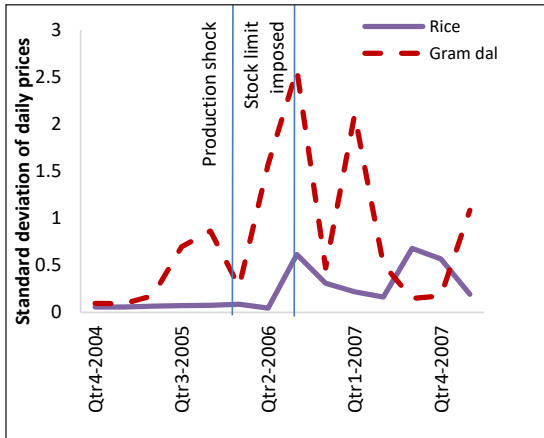
चित्र 7: इसीए के कारण कृषि बाजार संकुचन



के आधार पर भंडारण करती है के बीच अन्तर नहीं रखा जाता। इसके अतिरिक्त ये निशुल्क कारोबार की प्रभावशीलता और अधिकता वाले क्षेत्रों से उच्च मांग वाले बाजारों तक उत्पादों के प्रवाह को कम करता है। इसलिए वस्तु व्युत्पन्न बाजारों को भी प्रभावित करता है क्योंकि व्यापारी भंडारण सीमाओं के कारण वांछित गुणवत्ता अनुरूप लेनदेन के क्रम में वस्तु उपलब्ध न करा सके। यह अधिनियम अनिश्चिता को बढ़ाकर और कृषि बाजारों में बड़े निजी क्षेत्र के खिलाड़ियों के प्रवेश को हतोत्साहित करके बाजारों कुरूप बनाते है। बाजारों का इस प्रकार से सकुंचन आगे और कृषि उत्पादों की कीमत अस्थिरता को बढ़ाता है जोकि इसकी मंशा के विपरित है।

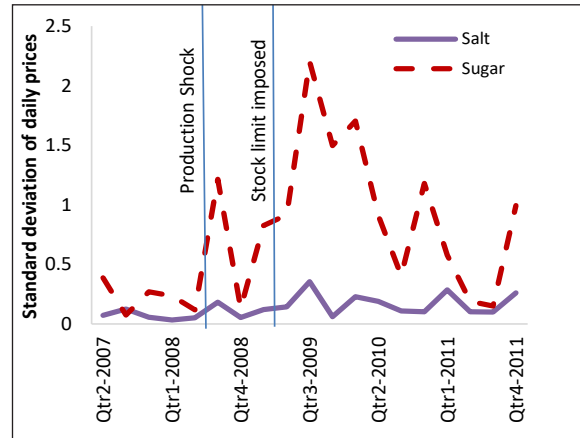
4.7 यह बाजार विरूपण प्रभाव अनेक अनुभवों से स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है कीमतों में अस्थिरता को नियंत्रित करने में स्टॉक सीमा की प्रभाव शून्यता किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष समय अवधि तक सीमित नहीं है। नीचे दी गई आकृति से 'दालों' और चीनी के मूल्यों के मानक अतिक्रम को दर्शाती है जिन पर क्रमशः 2006 तीसरी तिमाही और 2009-पहली छमाही में स्टॉक सीमाओं को अधिसूचित किया गया था। इन सीमाओं की आरोपण के दो से तीन वर्षों के बाद भी मूल्यों में अस्थिरता की रोकथाम में सीमित सफलता मिली (आकृति 8क और आकृति 8ख देखें)।

आकृति 8क: ईसीए के तहत स्टॉक सीमा के 2006-तीसरी तिमाही में लगाए जाने के बाद भी दाल के खुदरा मूल्य में अस्थिरता



स्रोत्र: उपभोगता मामला विभाग से उपलब्ध डॉटा से संगणित

आकृति 8ख ईसीए के तहत 2009-पहली तिमाही में स्टॉक सीमा लगाने के बाद भी चीनी के खुदरा मूल्यों में अस्थिरता



स्रोत्र: उपभोगता मामला विभाग से उपलब्ध डॉटा से संगणित

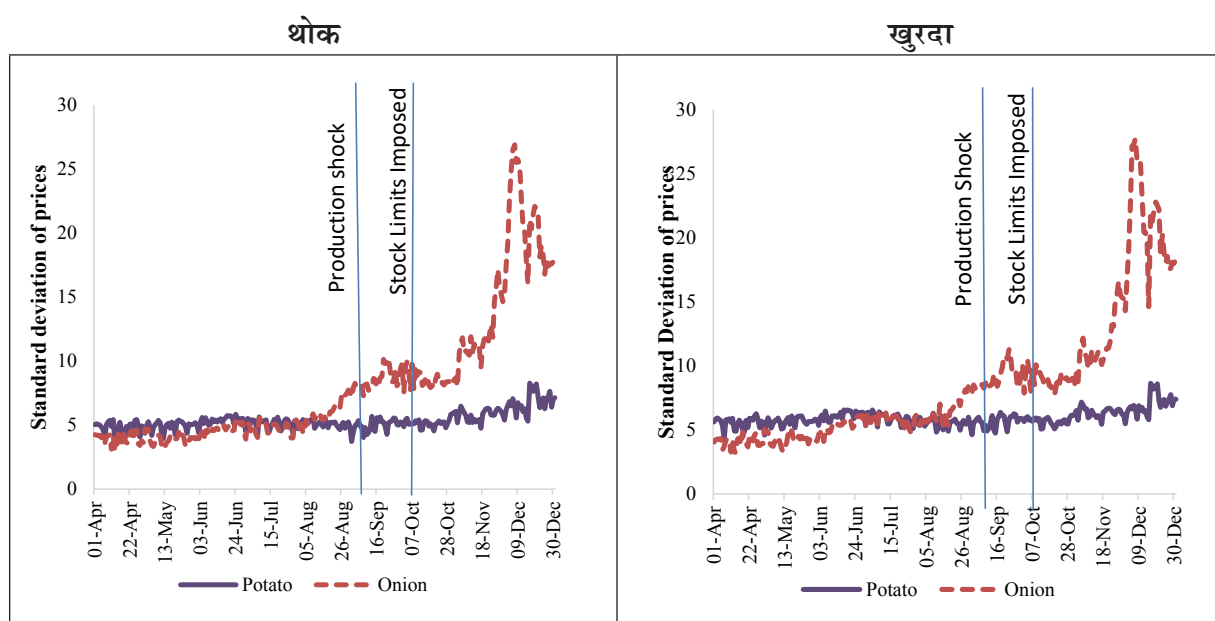
4.8 प्याज के मूल्यों में वृद्धि सहित दाल का अनुभव समान घटना का उदाहरण प्रस्तुत करता है। भारत में प्याज की फसल की कटाई करने के तीन मौसम हैं अर्थात खरीफ (अक्टूबर-दिसंबर), बिलंबित खरीफ (जनवरी-मार्च) और रबी (मार्च-मई)। वर्ष में लगभग मई से सितंबर तक की अवधि होती है जब प्याज की मांग को व्यापारियों/थोक विक्रेताओं द्वारा जमा किए गए स्टॉक से पूरा किया जाता है। अगस्त-सितंबर 2019 में भारी बारिश के परिणामस्वरूप प्याज की खरीफ फसल

पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा जिससे बाजार में कम आवक हुई और प्याज की कीमतों पर ऊपरी दबाव पड़ा। यह खरीफ फसल आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर तक की अवधि तक और बाजार के विलंबित खरीफ फसल से नई प्याज के आने तक मांग को पूरा करती है। लगातार बढ़ती प्याज की कीमतों को देखते हुए, देश भर में 29 सितंबर 2019 को ईसीए के तहत स्टॉक सीमाएं निध रित की गई थीं (खुरदा व्यापारियों के लिए 100 क्विंटल और थोक व्यापारियों के लिए 500 क्विंटल की सीमा

तय की गई थी जिन्हें नाप में क्रमशः 20 क्विंटल और 250 क्विंटल तक कम किया गया था। स्टॉक सीमाएं इस लिए लगाई गई थीं ताकि बाजार में स्टॉक जारी करते हुए प्याज के बढ़ते मूल्य पर नियंत्रण रखा जा सके और व्यापारियों द्वारा जमा खोरी को रोकते जुए बाजार में आपूर्ति बढ़ाई जा सके। यद्यपि स्टॉक सीमा के निर्धारण का सितंबर 2009 के बाद प्याज के थोक

और खुदरा मूल्यों की अस्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा (आकृति 8ग)। कम स्टॉक सीमाओं के कारण ही व्यापारियों और थोक विक्रेताओं के अक्टूबर में ही अधिकतर खरीफ फसल को ऑफलोड कर दिया था जिसके परिणामस्वरूप नवंबर, 2019 के अस्थिरता में तेजी से वृद्धि हुई। खुदरा मूल्यों में आस्थिरता इसे थोक मूल्य में प्रकट करती है।

आकृति 8ग: ईसीए के तहत स्टॉक सीमा निर्धारण के बाद भी 2019 में प्याज के थोक और खुदरा मूल्यों में अस्थिरता



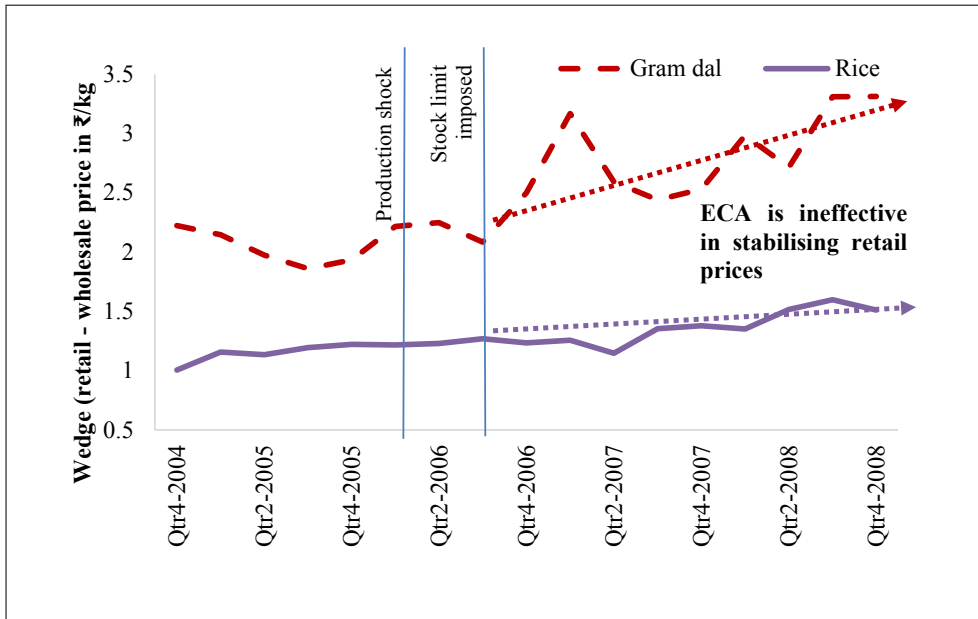
स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) से उपलब्ध आंकड़ों से परिकल्पित

टिप्पणी: प्याज और आलू दोनों ईसीए के तहत शामिल हैं परंतु स्टॉक सीमा 29 सितंबर 2019 से प्याज पर निर्धारित की गई थी, आलू पर नहीं। 2019 and not on potato

4.9 स्टॉक सीमा निर्धारण का यह प्रभाव दालों और प्याज के थोक और खुदरा मूल्यों के बीच ग्राफ के रूझान से भरी उजागर होता है। आकृति 9क और 9ख)/ प्याज के मामले में नवंबर 2019 से ग्राफ में तेज वृद्धि दर्शाई गई है चूंकि अधिकतर खरीफ फसल, जो पहले ही कम थी, को अक्टूबर में ही बाजार में निकालना पड़ा। ईसीए के माध्यम से सरकार के नदारद हस्तक्षेप से व्यापारी अपनी फसल के कुछ भाग का भंडारण कर लेते ताकि पूरे वर्ष में स्थिर मूल्यों पर उत्पाद की आसान उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। थोक और

खुदरा मूल्यों के बीच बढ़ता ग्राफ इस बात को सुदृढ़ करता है कि ईसीए उपभोक्ताओं का कल्याण कम करता है। दीधीवयि में यह कृत्म भंडारण संरचना के विकास को हतोत्साहित करता है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन/उपभोग झटकों के बाद मूल्यों में आस्थिरता बढ़ती है—जिसका उलट होना चाहिए। विभिन्न वस्तुओं और विभिन्न समयावधिन केवल प्याज या चीनी जहां जमाखोरी की अक्सर शैका होती है—के साक्ष्य बताते हैं कि ईसीए की प्रभावहीनता का कारण सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप हैं जो बाजारों को कम आंकते हैं।

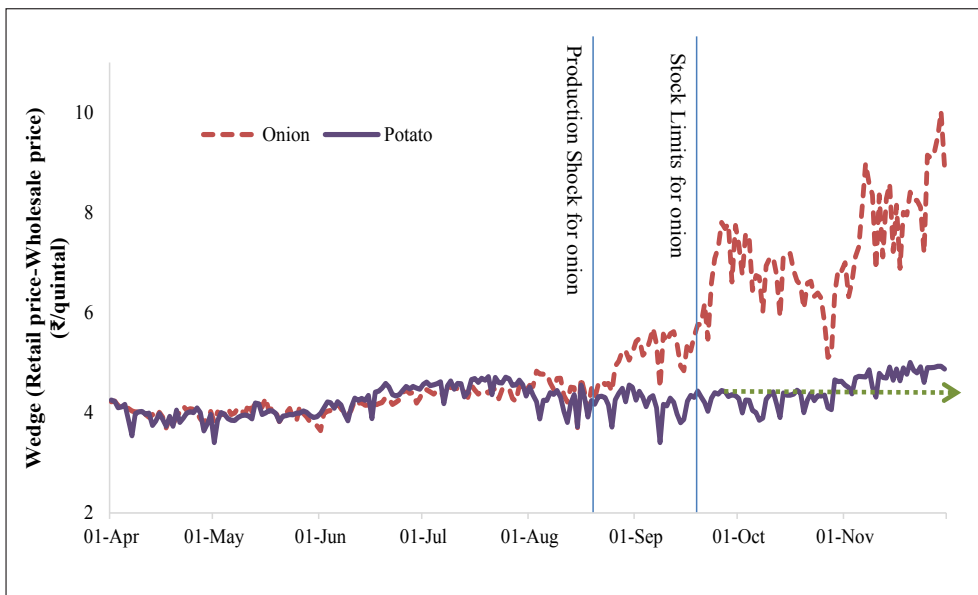
आकृति 9क: ईसीए लागू करने के बाद भी चना दाल के खुरदा और थोक मूल्यों के बीच बढ़ता



स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) से उपलब्ध आंकड़ों से परिकलित।

टिप्पण: चावल और दालों दोनों ईसीए के तहत शामिल हैं, और दालों पर स्टॉक सीमा 28 अगस्त 2006 के लगाई गई थी। चावल पर भी इस चार्ट में ली गई अवधि के अंत में 2008 में भी स्टॉक सीमा निधारित की गई थी।

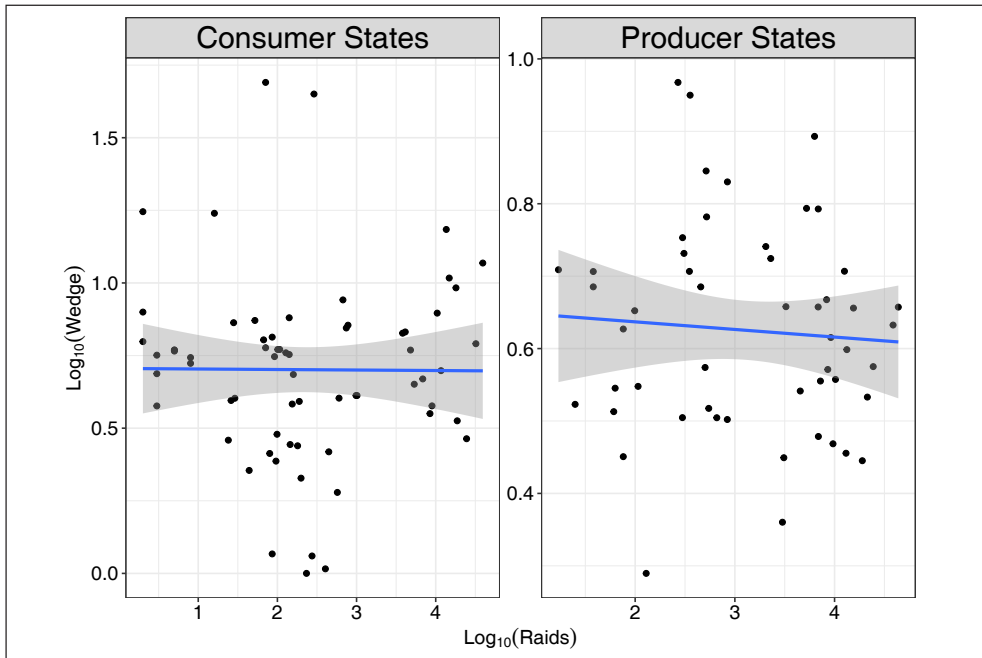
आंकड़े 9 ख: म्ब लागू किए जाने के बाद भी 2019 में प्याज के खुदरा और थोक मूल्यों के बीच बढ़ता ग्राफ



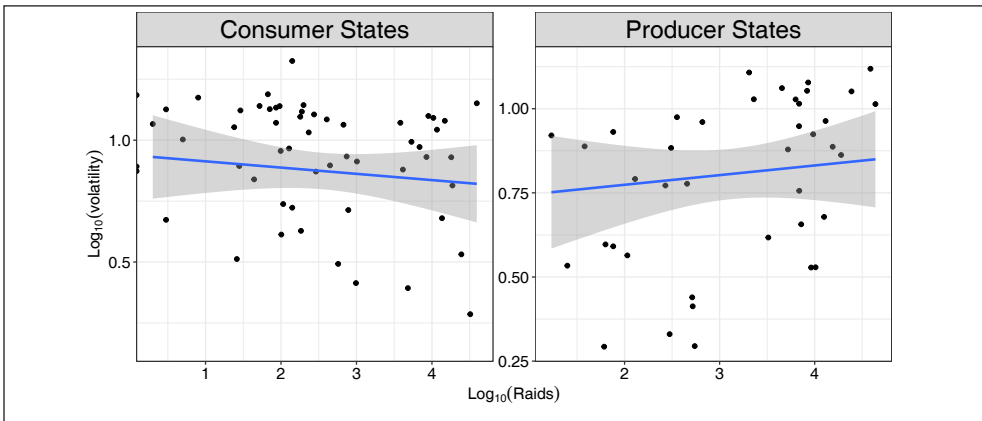
स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग से उपलब्ध आंकड़ों से परिकलित।

टिप्पण: प्याज और आलू दो म्ब के तहत शामिल है परंतु स्टॉक सीमाएं 29 सितंबर 2019 से प्याज पर लागू की गई हैं न कि आलू पर।

चित्र 10क: खुदरा एवं प्याज के मूल्यों के बीच फर्क ईसीए के तहत किए गए छापों के सहसंबंध



चित्र 10ख: खुदरा और थोक प्याज के मूल्यों की अस्थिरता सहित इसीए के तहत किए गए छापों का सहसंबंध

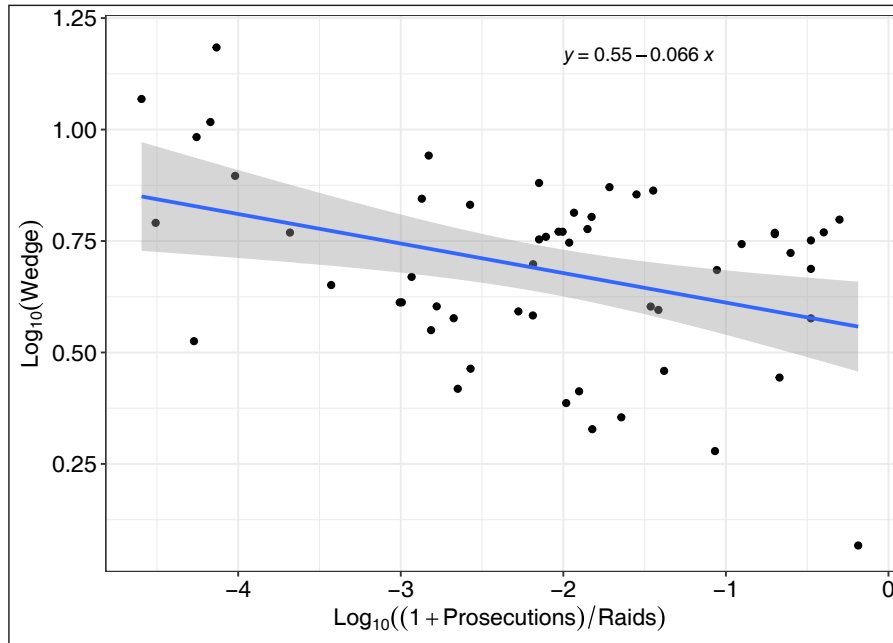


स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग से लिए गए समेकीत आंकड़े

4.10 ईसीए को उस समय लागू किया गया जबकि अनैतिक जमाखोरी एवं कालाबाजारी एक जोखिम होता था क्योंकि कृषि बाजार विखंडित थे और परिवहन अवसंरचना पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। परन्तु अधिनियम में अनैतिक जमाखोरी को दंडित करने के साथ-साथ अत्यधिक वांछनीय सुचारू ढंग से उपभोग करने को भी दंडित किया गया है जिसका

प्रावधान भंडारण के माध्यम से किया जाता है। भारत में कृषि बाजारों के निरंतर और अधिक एकीकृत एवं प्रतिस्पर्धी बनने के साथ इस अधिनियम की उपयोगिता संदिग्ध हो गई है और यह खाद्यान्न के लिए एकीकृत प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय बाजार के विकास के साथ असंगत हो गया है।

चित्र 11: प्याज के खुदरा एवं थोक मूल्यों के बीच वेज के साथ अभियोजन का सह संबंध



स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग (डीसीए) से उपलब्ध आंकड़ों से संकलित

4.11 हमारा विश्लेषण यह दर्शाता है कि जो राज्य अनिवार्य वस्तुओं के प्राथमिक उपभोक्ता हैं, उन राज्यों में खुदरा एवं थोक मूल्यों के बीच पकड़े जाने की संभावना (छापों से अभियोजन के अनुपात द्वारा प्रतिबिंबित) एवं वेज के बीच एक नकारात्मक संबंध है। इससे पता चलता है कि ईसीए केवल तभी प्रभावी होता है जबकि इसका निष्पादन (चित्र 11) उपयुक्त तरीके से किया जाए। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासन से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत दाष सिद्धि की दर बहुत ही कम है जोकि औसतन 2-4 है। दिनांक 16.12.2019 को उपलब्ध आंकड़ों, जोकि उद्यतन है, के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान ईसीए के अंतर्गत कुल 76,033 छापे मारे गए थे जिसमें केवल 2941 व्यक्ति दोषी ठहराए गए थे जोकि मारे गए कुल छापों का मात्र 3.8 प्रतिशत था। यह निर्दिष्ट करता है कि ईसीए के अंतर्गत मारे गए छापों के कारण केवल व्यापारियों का उत्पीड़न हुआ जो कि किसी दी गई मद के विपणन में व्यापार की भूमिका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

4.12 प्याज, आलू एवं दालों जैसी महत्वपूर्ण कृषि मदों के मूल्य की अस्थिरता को विनियमित करने में सहायता करने के लिए वर्ष 2014-15 में मूल्य स्थिरीकरण निधि

(पीएसएफ) की स्थापना के साथ शुरूआत की गई थी। इसको मूल्य अस्थिरता को संतुलित करने के लिए और जमाखोरी तथा अनैतिक सट्टेबाजी को हतोत्साहित करने के लिए उत्तरवर्ती अंशांकित निर्गम के लिए उपयुक्त मदों का युक्तिपूर्ण बफर बनाए रखने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इसको और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है क्योंकि यह बाजार शक्तियों को उनके साथ प्रतिस्थापित करने की अपेक्षा परिपूरित करता है जोकि ईसीए करता है।

4.13 ईसीए को उस समय लागू किया गया जबकि अनैतिक जमाखोरी एवं कालाबाजारी एक जोखिम होता था क्योंकि कृषि बाजार विखंडित थे और परिवहन अवसंरचना पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। परन्तु अधिनियम में अनैतिक जमाखोरी को दंडित करने के साथ-साथ अत्यधिक वांछनीय सुचारू ढंग से उपभोग करने को भी दंडित किया गया है जिसका प्रावधान भंडारण के माध्यम से किया जाता है। भारत में कृषि बाजारों के निरंतर और अधिक एकीकृत एवं प्रतिस्पर्धी बनने के साथ इस अधिनियम की उपयोगिता संदिग्ध हो गई है और यह खाद्यान्न के लिए एकीकृत प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय बाजार के विकास के साथ असंगत हो गया है। ईसीए के जमाखोरी रोधी प्रावधान स्टाक होल्डिंग,

भंडारण क्षमताओं, व्यापार एवं आगे ले जाने की स्थितियों की खुली रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करते हैं। देश में उपलब्ध कुल निजी भंडारण क्षमता के समेकित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं जोकि नीति निर्माताओं को मूल्यों पर किसी भी उत्पादन आघात के प्रभाव का आकलन करने में सक्षम बनाएगा। भंडारण की आधुनिक विधियों में और बाजार आसूचना में निवेश को हतोत्साहित करने के अतिरिक्त, ट्रेडों से संबंधित जानकारी के अभाव में बाजार प्रतिभागियों के लिए भविष्य के लिए सटीक पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। कमोडिटी वायदा बाजारों के विकास का समर्थन करने से बाजार के संभावित भावी मूल्यों की प्रभावी खोज में सहायता मिलेगी जोकि निजी भंडारण के लिए बेहतर आधार प्रदान कर सकती है और मूल्यों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव से बच सकती है। प्रभावी पूर्वानुमान प्रणाली का विकास, स्थिर व्यापार नीतियां एवं कृषि बाजारों का बढ़ता हुआ एकीकरण कृषि बाजारों के मूल्यों के स्थिरीकरण के प्रयोजन को सरकार द्वारा ईसीए के माध्यम से अध्यारोपित आदेश की अपेक्षा अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है।

ईसीए के अंतर्गत औषधि मूल्य नियंत्रण

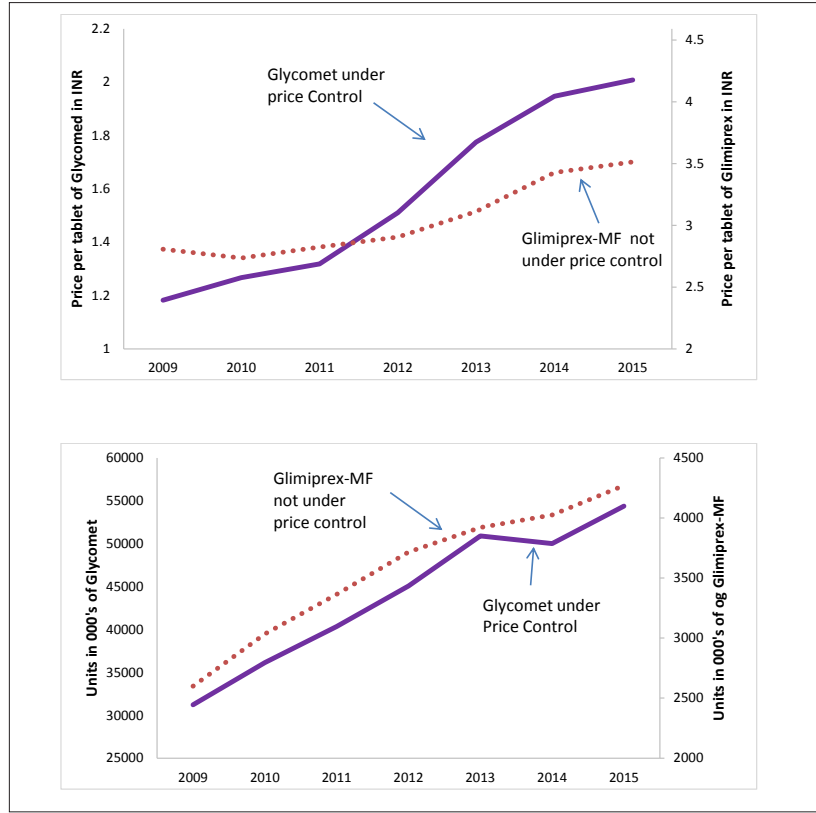
4.14 आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की पहुंच को सुनिश्चित करने और निर्धन परिवारों को गरीब होने से बचाने के महत्वपूर्ण कार्य को देखते हुए प्रायः सरकार औषधियों के लिए मूल्य नियंत्रण का आश्रय लेती है। भारत में, सरकार राष्ट्रीय औषधि मूल्य प्राधि करण (एनपीपीए) एवं औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के माध्यम से औषधियों के मूल्यों को नियमित करने के लिए मूल्यों के नियंत्रण पर महत्वपूर्ण ढंग से निर्भर होती हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तैयार की गई अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) वह सूची होती है जिनको भारत के स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य एवं उच्च प्राथमिकता का माना जाता है। यह जनसंख्या में रोगों की व्यापकता, औषधियों की सुरक्षा एवं प्रभाविकता तथा मौजूदा वहनीयता जैसे पहलुओं पर आधारित है। ईसीए की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा डीपीसीओ जारी किया जाता है जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनईएलएम के अंतर्गत सूचीबद्ध औषधियां आम जनता का उचित मूल्य पर उपलब्ध हों।

4.15 आवश्यक औषधियों के संबंध में डीपीसीओ के प्रभाव की जांच सावधानीपूर्वक करने के लिए हम निम्नलिखित तुलना करते हैं। ग्लाइकोमेट (मेटफॉर्मिन) और ग्लिमप्रेक्स-एमएफ (ग्लिमनपेराइट + मेटफॉर्मिन) दोनों पर विचार कीजिए जिनका प्रयोग उच्च ब्लड शुगर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ग्लाइकोमेट, डी पी सी ओ, 2013 में मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाया गया। ग्लिमप्रेक्स-एमएफ इसके अंतर्गत नहीं लाया गया। इसलिए, ग्लाइकोमेट की तुलना में ग्लिमप्रेक्स-एमएफ के लिए उपयोग की गई मात्रा का मूल्य में परिवर्तन से पहले और बाद के परिवर्तन की है। इस श्रेणी में मांग और पूर्ति जैसे सभी गड़बड़ी फैलाने वाले कारकों के प्रभाव कही तुलना की है। इसलिए, इस तुलना में डी पी सी ओ आदेश के शुद्ध प्रभाव का अनुमान लगाया गया है। चित्र 12 में दर्शाया गया है कि डी पी सी ओ, 2013 के बाद ग्लाइकोमेट की तुलना में ग्लिमप्रेक्स-एमएफ के मूल्य में अधिक वृद्धि हुई। तथापि, उपभोग की गई सामग्री पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो औषधियों के आवश्यक वस्तु होने के कारण स्थिर बना हुआ है क्योंकि मांग मूल्य में परिवर्तन के प्रति परिवर्तनशील या असंवेदनशील नहीं है।

4.16 हमारे आँकलन भी दर्शाते हैं कि डीपीसीओ, 2013 के अंतर्गत आने वाली ड्रग्स की कीमतों में सक्रिय घटकों के प्रति मिली ग्राम 71 रुपये की औसत वृद्धि हुई है। डी पी सी ओ, 2013 द्वारा गैर-प्रभावित ड्रग्स की कीमतों में सक्रिय घटकों के प्रति मिली ग्राम 13 रुपये की वृद्धि हुई है। प्राक्कलनों में अंतर-दर-अंतर सक्रिया घटकों की कीमतों में प्रति मिली ग्राम 58 रुपये की वृद्धि हुई, जो 5 प्रतिशत की दर पर सांख्यिकी तौर पर महत्वपूर्ण था (चित्र 13) प्रमात्राओं में डिफरेंस इन डिफरेंस सांख्यिकीय रूप में शून्य से अप्रभेद्य था।

4.17 आवश्यक वस्तु अधिनियम का हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत स्टॉक सीमाओं और कीमत नियंत्रण से उप इष्टतम परिणाम प्राप्त होते हैं, जो वस्तुतः अधिनियम में की गई अनिवार्यता के प्रतिकूल होते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत बाजारों के कार्य निष्पादन में बाधा पहुँचाई जाती है और उन कार्यों के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है जो संपत्ति सृजन के लिए हानिकारक होते हैं और उसके द्वारा सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम को निरस्त करके

चित्र 12: ग्लाइकोमेट (नियमित) बनाम ग्लिमप्रेक्स-एमएफ (अनियमित) के मूल्यों पर डीपीसीओ 2013 का प्रभाव



स्रोत: आईएमएस स्वास्थ्य, सर्वे गणना

बाक्स 2: औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ)

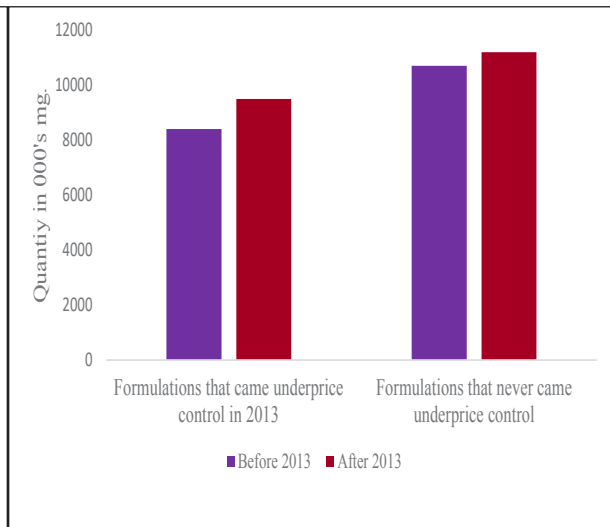
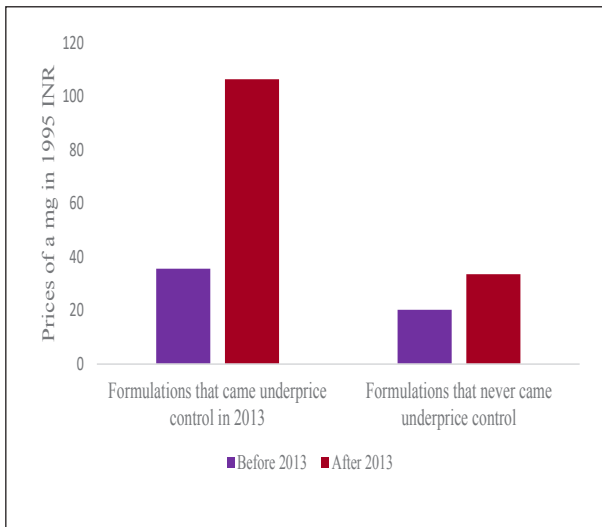
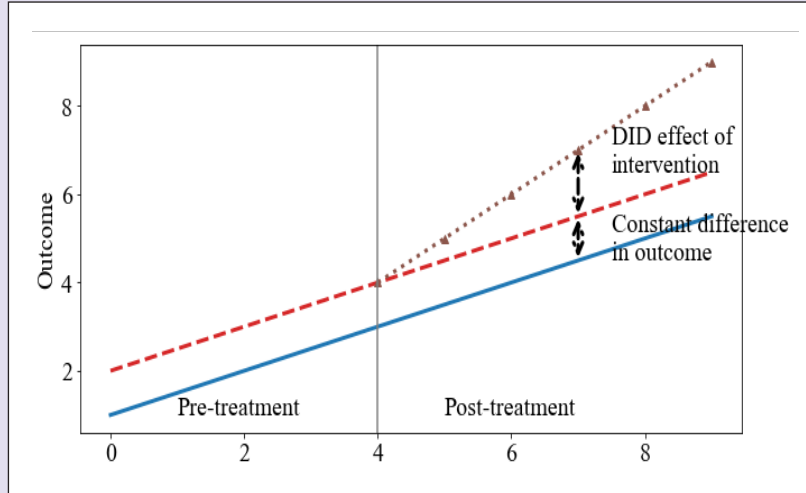
औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 की धारा 3 के अंतर्गत जारी एक आदेश है जिसमें औषधियों के मूल्य को विनियमित किया जाता है। डीपीसीओ अन्य वस्तुओं के साथ-साथ उन औषधियों की सूची को विनिर्दिष्ट करता है जोकि मूल्य सीमा और अधिकतम मूल्य की गणना के फार्मूला के अंतर्गत आती है। अनिवार्य औषधियों की राष्ट्रीय सूची (एनएलईएम) उन औषधियों की सूची है जो मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए डीपीसीओ, 2013 में 27 उपचारात्मक समूहों में 680 अनुसूचित औषधि निरूपण हैं जिनको मूल्य विनियमित है।

राष्ट्रीय औषधालय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन पी पी ए) औषधालय उत्पादों के मूल्य, में संशोधन और डी पी सी ओ के प्रवर्तन के लिए उत्तरदायी है। भारत सरकार ने डी पी सी ओ में अनेक बार संशोधन किए हैं। और हाल में वर्ष 2013 में संशोधन किया है। वर्ष 2013 तक डीपीसीओ ने लागत आधारित मूल्य निर्धारण पद्धति का प्रयोग कर मूल्य की अधिकतम सीमा के विनिर्दिष्ट किया जिसमें अधिकतम मूल्य की गणना लागत के उस गुणक के रूप में की जाती थी जो उत्पादक द्वारा औषधि के प्रोत्साहन और वित्तीय में खर्च होता था। यह गुणक, जिसे अधिकतम अनुदेश पश्च-विनिर्माण व्यय (एमएपीई) कहा जाता था, भारत में आयात किए जाने वाले फार्मुलेशनों के लिए 50 प्रतिशत पर और स्वदेशी रूप में विनिर्मित फार्मुलेशनों के लिए 100 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था।

वर्ष 2013 में भारत ने पहली लागत आधारित मूल्य निर्धारण के स्थान पर बाजार आधारित मूल्य निर्धारण को अपनाया। बाजार आधारित मूल्य निर्धारण में सरकार वह मूल्य का निर्धारण उस अधिकतम मूल्य के रूप में करती है जिसे खुदरा विक्रेता संदर्भ मूल्य पर प्रभारित कर सकता है। जो आई एम एस हैल्थ नामक बाजार अनुसंधान फर्म द्वारा उपलब्ध करवाएं गए बाजार आंकड़ों पर आधारित 01 प्रतिशत या इससे अधिक शेर वाले सभी ब्रांडों के मूल्यों का साधारण औसत होता है। इस आदेश ने एनएलईएम में विनिर्दिष्ट सभी फार्मुलेशनों के 16 प्रतिशत तक अधिकतम मूल्य का निर्धारण किया।

बाक्स 3: डिफरेंस-इन-डिफरेंस की कार्यप्रणाली वर्णन

डिफरेंस-इन-डिफरेंस (डीआईडी) एक सांख्यिकीय तकनीक होती है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट पहल या उपचार (जैसे विधि की सतत् प्रक्रिया, पालिसी का अधिनियमन, या बड़े पैमाने पर कार्यक्रम का कार्यान्वयन) के प्रभाव का आकलन करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक दो अवधियों के बीच की जनसंख्या की तुलना में करती है जो विशिष्ट हस्तक्षेप (उपचार समूह) और जनसंख्या जो विशिष्ट हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं (नियंत्रण समूह) होती है द्वारा प्रभावित की जाती है।



स्रोत: सर्वे गणना

टिप्पणी: 1751 फारमूलेशन निमेकित का आंकड़ा और 49893 बाँडों को आईएमएस स्वास्थ्य को प्रयोग किया गया

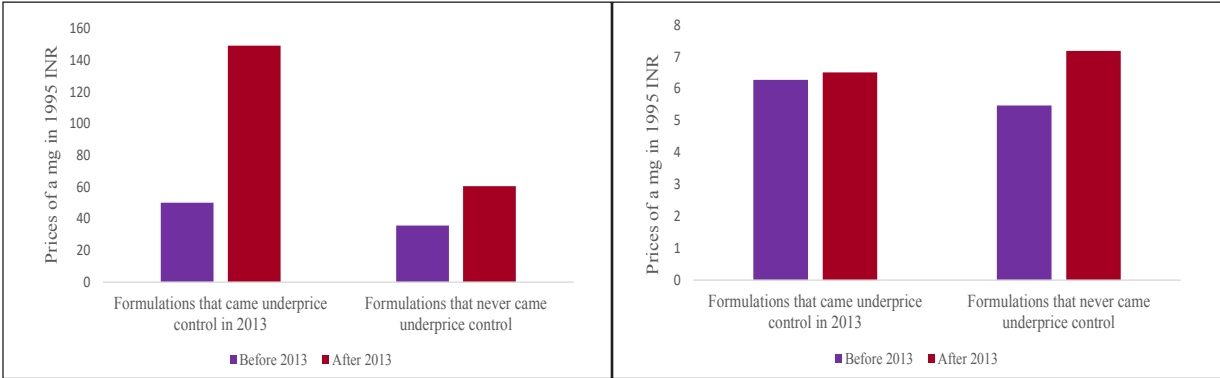
औसतों की गणना उन सभी दवाइयों पर किया गई है जोकि डीपीसीओ 2013 द्वारा अप्रभावित थी पृथक रूप से 2013 से पूर्व और 2013 के बाद की अवधि हेतु

उसके स्थान पर कीमत स्थिरीकरण निधियों, ग्राहकों की सहायता करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी), नवाचारों के लिए प्रोत्साहनों, बाजार एकीकरण में वृद्धि करने और माल एवं सेवाओं के निर्वाहा प्रवाह जैसे बाजार

अनुकूल मध्यसीता के अधिनियम का लाया जाना चाहिए।

4.18 भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत वर्ष 1965

चित्र 13: अस्पतालो बनाम खुदरा बाजारों पर बेचे जा रहे दवाईयो के मूल्यों के पर डीपीसीओ, 2013 के प्रभाव



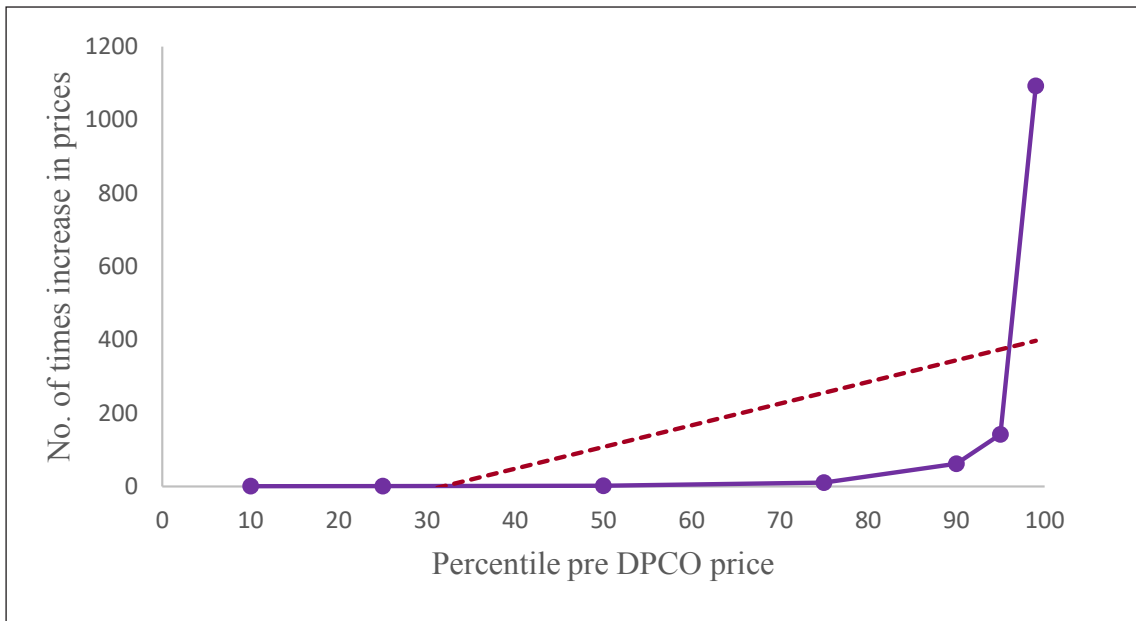
स्रोत: सर्वे गणना

में की गई थी जिसका मुख्य कार्य खाद्यान्नों और अन्य खाद्य सामग्रियों की खरीद करना, उनका भंडारण करना, लाना-ले जाना/ढुलाई, सवितरण करना और उनकी बिक्री करना था। भारतीय खाद्य निगम के मुख्य उद्देश्य (क) किसानों से सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) पर खाद्यान्नों का प्रापण करना; (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों का वितरण करना, विशेषरूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए वहनीय कीमतों पर खाद्यान्नों का वितरण करना विशेषरूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए वहनीय कीमतों पर खाद्यान्नों का वितरण करना;

और (ग) खाद्य सुरक्षा और कीमत स्थिरता के लिए खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव करना हैं। इस प्रकार से, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के समान हितों को सुरक्षित रखने की आवश्यक व्यवस्था की गई है।

4.19 इस अधिदेश के बाद, सरकार खाद्यान्नों की एकल सबसे बड़ी प्राप्त और भंडारण के रूप में उभरी है। सरकार चावल और गेहूं की बाजार आधिक्य कुल 40-50 प्रतिशत मात्रा की खरीद करने से इन खाद्यान्नों की प्रबल खरीददार के रूप में उभर रही है (चित्र 16) । पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में, सरकार द्व

चित्र 15: मूल्यों पर जीपीसीओ 2013 को प्रभाव, प्रतिशत में (कीमतों की)



स्रोत: सर्वे गणना

रा खरीद का यह अनुपात 80-90 प्रतिशत के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है (चित्र 16)। वर्ष 2018-19 में 44.4 मिलियन टन चावल और 34 मिलियन टन गेहूं का कीर्तिमान प्रापण किया गया था। इस प्रकार से चावल और गेहूं के सकल सबसे बड़े क्रेता के रूप में, सरकार घरेलू अनाज मंडल में वस्तुतः एक मात्र खरीदकर्ता है और निजी व्यापार की भीड़ को समाप्त करने वाले एक प्रबल निवेशक है। यह इन वस्तुओं के प्रापण भंडारण और प्रक्रमण में दीर्घकालिक निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को हतोत्साहित करता है।

खाद्यान्न बाजारों (मंडियों) में सरकारी हस्तक्षेप

4.20 भारत के खाद्यान्न बाजारों (मंडियों) में, सरकार ने उत्पादकों के लिए पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और वहनीय कीमतों पर आपूर्तियों उपलब्ध कराके उपभोक्ताओं के हित के रक्षोपाय करते समय खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने की कोशिश की है। इसकी प्राप्ति के लिए कोशिश करने में, राज्य उर्वरक, जल और विद्युत आदि जैसी मदों की इनपुट कीमतों की नियंत्रण करता है, आउटपुट कीमतें नियत करता है, प्रशासनिक मशीनरी के माध्यम से भंडारण और प्रापण करता है, और समग्र देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों का संवितरण करता है।

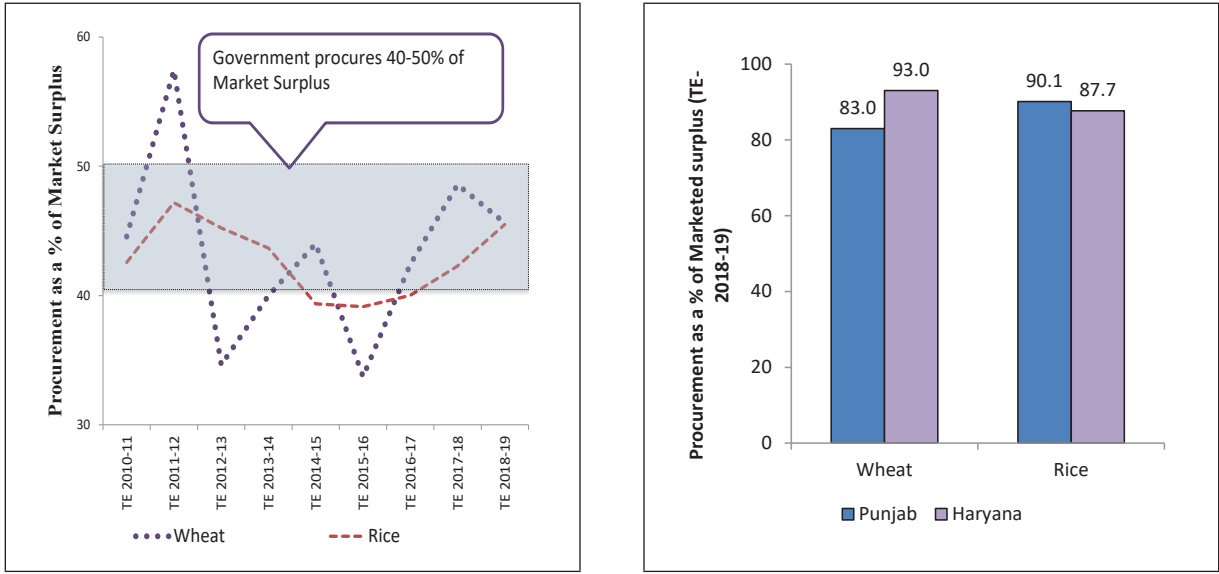
4.21 भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई) की स्थापना खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत वर्ष 1965 में की गई थी जिसका मुख्य कार्य खाद्यान्नों और अन्य खाद्य सामग्रियों की खरीद करना, उनका भंडारण करना, लाना-ले जाना/हुलाई, संवितरण करना और उनकी बिक्री करना था। भारतीय खाद्य निगम के मुख्य उद्देश्य (क) किसानों से सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों (एमएसपी) पर खाद्यान्नों का प्रापण करना; (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों का वितरण करना, विशेषरूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए वहनीय कीमतों पर खाद्यान्नों का वितरण करना; और (ग) खाद्य सुरक्षा और कीमत स्थिरता के लिए खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव करना है। इस प्रकार से, उत्पादकों और उपभोक्ताओं के समान हितों को सुरक्षित रखने की आवश्यक व्यवस्था की गई है।

4.22 इस अध्यादेश के बाद, सरकार खाद्यान्नों की एकल सबसे बड़ी प्राप्त और भंडारक के रूप में उभरी है। सरकार चावल और गेहूं की बाजार आधिक्य कुल 40-50 प्रतिशत मात्रा की खरीद करने से इन खाद्यान्नों की प्रबल खरीददार के रूप में उभर रही है (चित्र 16)। पंजाब और हरियाणा जैसे कुछ राज्यों में, सरकार द्वारा खरीद का यह अनुपात 80-90% के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है (चित्र 16)। वर्ष 2018-19 में 44.4 मिलियन टन चावल और 34 मिलियन टन गेहूं का कीर्तिमान प्रापण किया गया था। इस प्रकार से चावल और गेहूं के सकल सबसे बड़े क्रेता के रूप में, सरकार घरेलू अनाज मंडी में वस्तुतः एक मात्र खरीदकर्ता है और निजी व्यापार की भीड़ को समाप्त करने वाल एक प्रबल निवेशक है। यह इन वस्तुओं के प्रापण भंडारण और प्रक्रमण में दीर्घकालिक निवेश करने के लिए निजी क्षेत्र को हतोत्साहित करता है।

4.23 ये प्रापण कार्रवाइयां न्यूनतम समर्थन मूल्य की बड़े पैमाने पर सहायता करती हैं जो बुआई सत्र के आरंभ में उत्पादकों के लिए सांकेतिक कीमतों और न्यूनतम कीमतों में किसी गिरावट से किसानों के लिए एक बीमा तंत्र के रूप में अभिकल्पित होती है। तथापि, इन कीमतों में दीर्घकालिक वृद्धि के रूझान ने किसानों को ऐसी फसलों का चयन करने का संकेत देने का कार्य किया है जिनमें एक सुनिश्चित प्रापण प्रणाली होती है चित्र 17 स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को उनके उत्पान को सरकार द्वारा मुक्त सिरे के प्रापण सुविधा में परिवर्तित करता है। यह यह भी दर्शाता है कि बाजार मूल्य किसानों के लिए कोई पारितोषक विकल्प प्रदान नहीं करते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य वस्तुतः न्यूनतम कीमत की बजाय अधिकतम मूल्य हो जाते हैं—जो कि इसे निर्दिष्ट उद्देश्य के प्रतिकूल है।

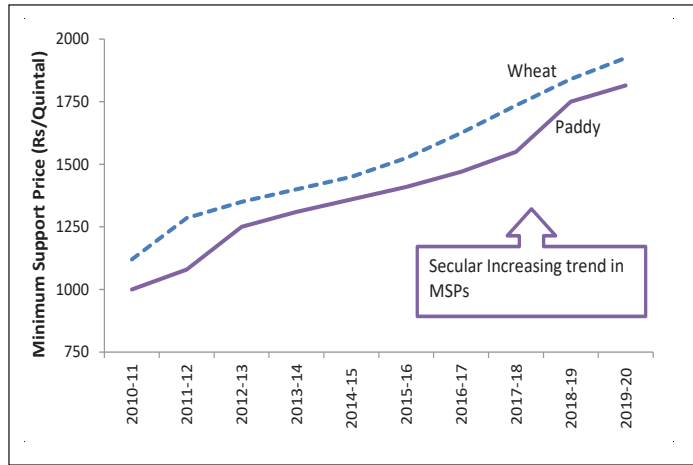
4.24 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के अंतर्गत पिछली और वर्तमान लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत दिए गए दायित्वों के मद्देनजर जिसमें सब्सिडी के खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी आती है, सरकार भी चावल एवं गेहूं की सबसे बड़ी एकल संचयकर्ता के रूप में उभरती है। चावल और गेहूं

चित्र 16: सरकार-चावल और गेहू का एकल सबसे बड़ा प्रापक



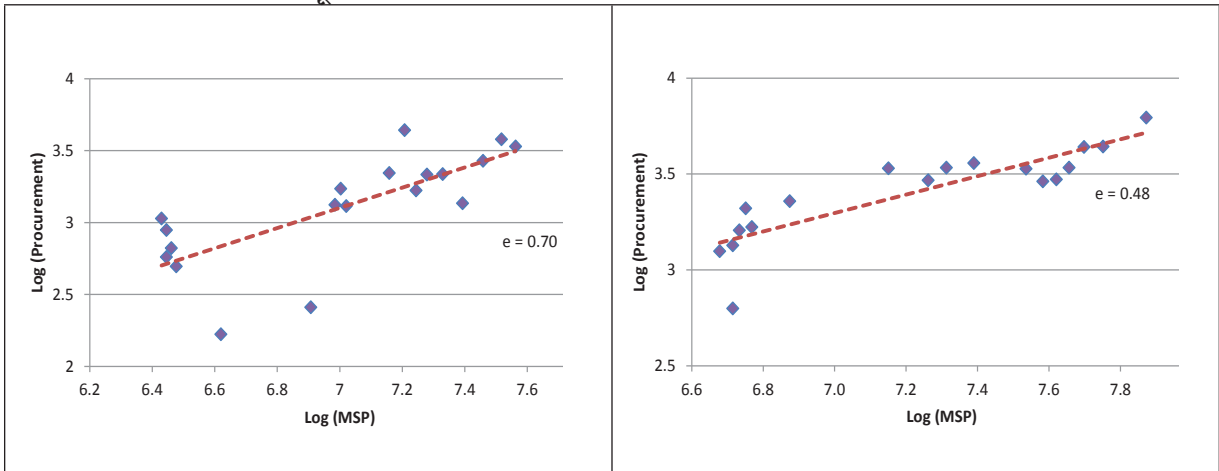
स्रोत: भारतीय खाद्य निगम डी ए सी एफ एवं डब्ल्यू

चित्र 17: उच्चतर प्रापणों के कारक बढ़ते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य



गेहू

चावल

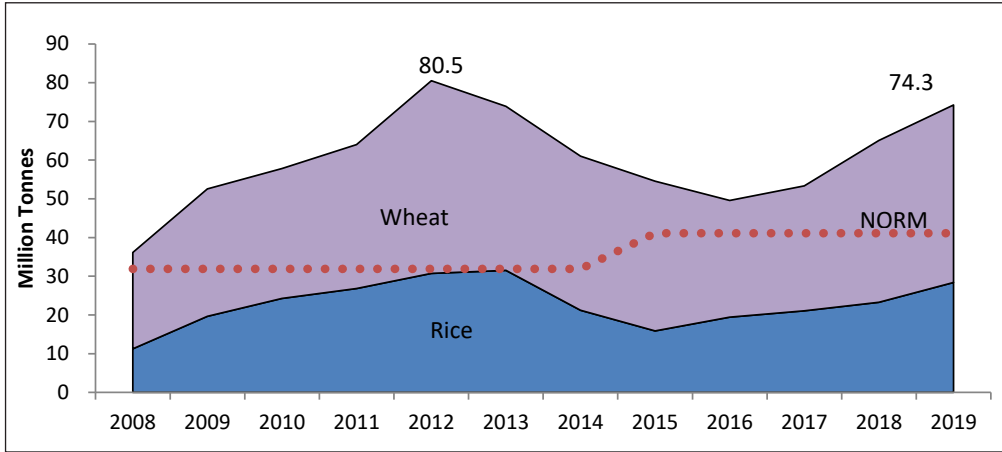


स्रोत: डीएकीएफएवं डब्ल्यू एवं डीएफपीडी

के 41.1 मिलियन टन बफर स्टॉक (प्रत्येक वर्ष की 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार) की तुलना में, 1 जुलाई, 2019 को कुल केंद्रीय पूल स्टॉक 74.3 मिलियन टन थे (चित्र 18) मौजूदा शिखर स्टॉक में गेहू की 45.8

मिलियन टन मात्रा (27.58 मिलियन टन के बफर मानक की तुलना में) और चावल की 28.4 मिलियन टन मात्रा (13.5) मिलियन टन के बफर मानक की तुलना में) शामिल है।

चित्र 18: भारतीय खाद्य निगम में बफर स्टॉक में रूझान



स्रोत: भारतीय खाद्य निगम

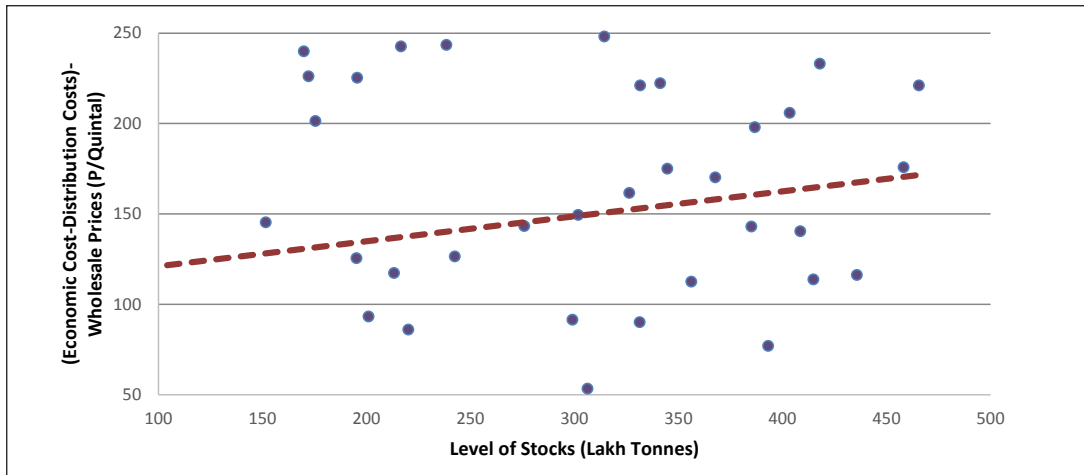
टिप्पणी: स्टॉक और मानक वर्ष की 1 जुलाई की स्थिति के अनुसार है।

4.25 इस तथ्य को मानते हुए कि खाद्यान्नों के अर्जन, भंडारण और वितरण के लिए भारतीय खाद्य निगम की आर्थिक लागत प्रापण कीमत से लगभग 40 प्रतिशत अधिक है, सुनिश्चित प्रापण (न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर), भंडारण (खरीदकर्ता प्रशासनिक सरकारी संगठन के माध्यम से) और लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत वितरण की मौजूदा मिश्रित नीतियों ने उच्च लागत खाद्यान्न अर्थव्यवस्था के सृजन में योगदान किया है। चित्र 19 दर्शाता है कि भारतीय खाद्य निगम की अक्षमता (आर्थिक लागत एक्सल विवरण लागत और औसत थोक कीमतों के मध्य वैज द्वारा आकलित) स्टॉकों के बढ़ते हुए स्तर के साथ साथ बढ़ती है। यह प्रमाणित है कि यदि खाद्यान्नों के बाजार सरकार के साथ साथ निजी निवेशकों की समान निवेशकों के रूप में (न क प्रापण में एकल खरीदकर्ता और भंडारण एवं वितरण में एकाधिकारी के रूप में) भागीदारी के रूप में खोले जाते हैं, तो इस प्रतिस्पर्धा के कारण प्रचालनों में

दक्षता बढ़ेगी और भंडारण एवं मालगोदामों में भंडारण में पर्याप्त अवसंरचना विकसित होगी।

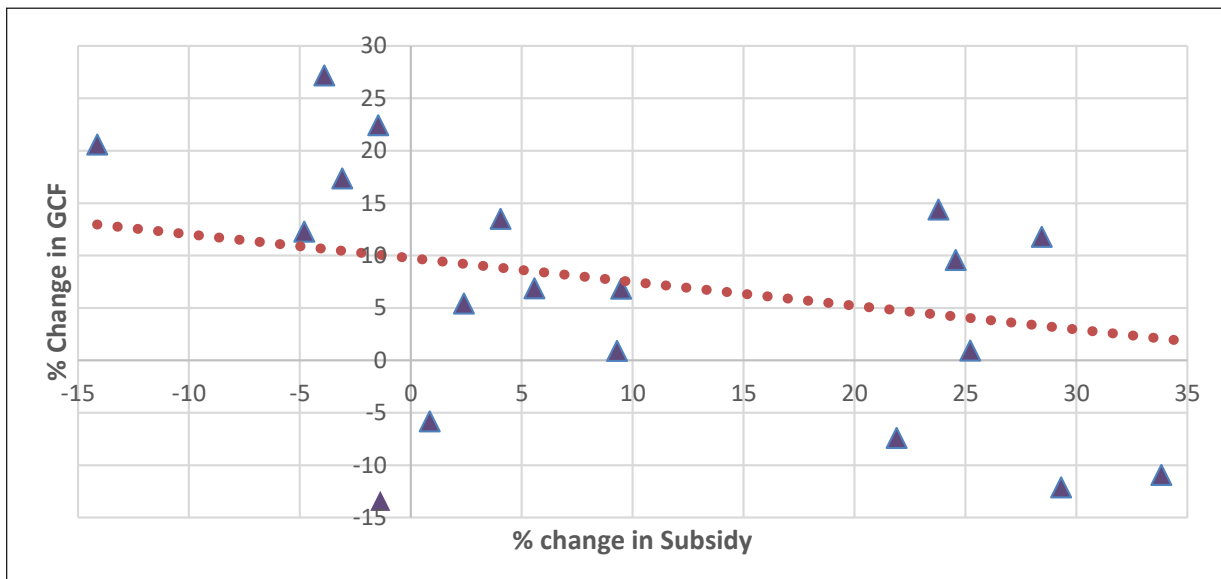
4.26 इन नीतियों के कारण खाद्य सब्सिडी, जिसमें भारतीय खाद्य निगम के अधिप्राप्ति की लागत (सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन न्यूनतम समर्थन मूल्य और केंद्रीय निर्गम मूल्य के बीच का अंतर) और भारतीय खाद्य निगम के वितरण और माल दुलाई की लागत शामिल है, का बोझ बढ़ गया है। राजकोषीय सीमाओं को देखते हुए यह स्पष्ट है कि सब्सिडी के माध्यम से धन आवंटित करने और निवेश बढ़ाने के बीच हमेशा समझौताकारी समन्वयन (ट्रेड ऑफ) होता है। चित्र 20 में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि कृषि में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि नकारात्मक रूप से खाद्य सब्सिडी परिव्यय में वृद्धि से संबंधित है। चूंकि उत्पादकता में वृद्धि के लिए निवेश महत्वपूर्ण इनपुट है, इसलिए सब्सिडी पर बढ़ता फोकस दीर्घ कालिक रूप में कृषि क्षेत्र की वृद्धि को नुकसान पहुंच रहा है। भारतीय

चित्र 19: भारतीय खाद्य निगम की (गेंहू के लिए) बढ़ती हुई दक्षता।



स्रोत: एफसीआई, डीसीए के आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण

चित्र 20: खाद्य सब्सिडी के परिव्यय और कृषि में सार्वजनिक निवेश के बीच प्रतिकूल संबंध



स्रोत: संघीय बजटदस्तावेज से संकलित, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में डाटा

कृषि में सतत विकास और समग्र समावेशी विकास के लिए सब्सिडी और निवेश के बीच के इस असंतुलन को तत्काल ठीक करने की आवश्यकता है।

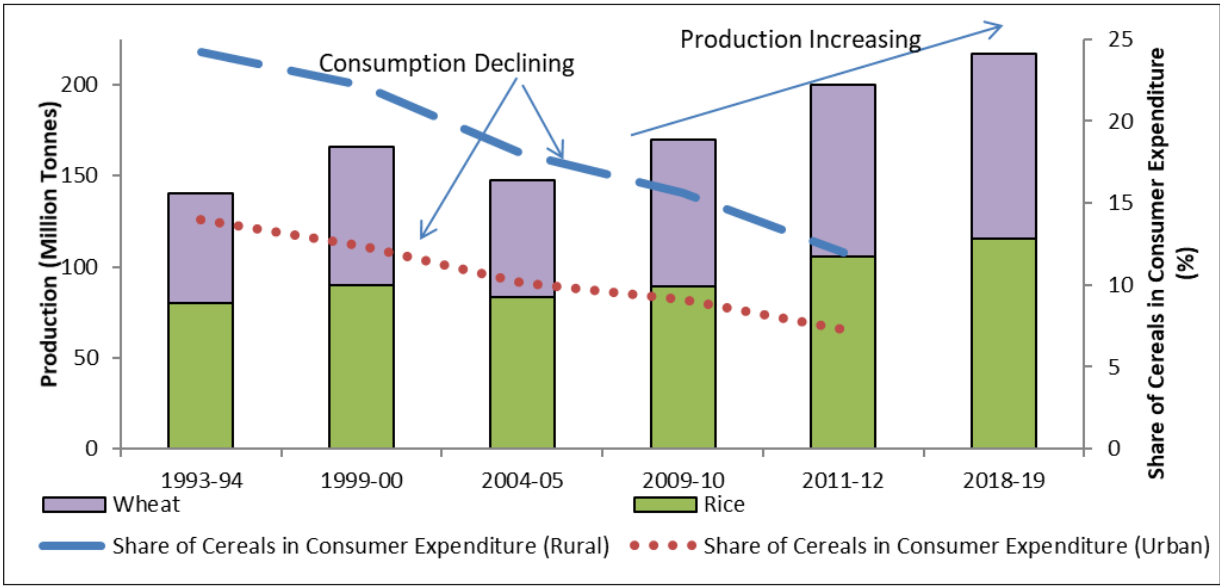
4.27 उपभोक्ता व्यय और अनाजों की मांग के रूझानों के साथ उपर्युक्त रूझानों का सन्निधान किए जाने की जरूरत है। उपभोक्ता व्यय पर एनएसएस के 73वें दौरे प्रदर्शित होता है कि मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) में अनाजों के हिस्से में वर्ष 2004-05 से

2011-12 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 33 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में लगभग 28 प्रतिशत तक की गिरावट और शहरी क्षेत्र में लगभग 28 प्रतिशत की गिरावट हुई है (अद्यतन उपलब्ध प्राक्कलन)। साथ ही एमपीसीई स्तर में वृद्धि होने से अनाजों की हिस्सेदारी में निरंतर गिरावट हुई है जो ग्रामीण भारत की निचली दशमक श्रेणी के संबंध में लगभग 19 प्रतिशत से शीर्ष दशमक श्रेणी के लगभग 5-6 प्रतिशत पर तथा शहरी भारत की निचली दशमक श्रेणी के संबंध में 15 प्रतिशत से

शीर्ष दशमक श्रेणी के 3 प्रतिशत से भी नीचे आ गया। यह आय में वृद्धि के फलस्वरूप खाद्य उपयोग में गिरावट और गैर-खाद्य मदों पर व्यय में वृद्धि के अनुरूप है। चित्र 21 में यह दर्शाया गया है कि चावल और गेहूं के उत्पादन में नए रिकॉर्ड कायम होने के बावजूद उपभोक्ता व्यय में अनाजों की हिस्सेदारी में किस प्रकार से कमी आई है। अनाजों की गिरती मांग और अनाजों की बढ़ती आपूर्ति की यह प्रवृत्ति

दर्शाती है कि उत्पादन की पद्धति मांग की पद्धतियों के अनुरूप नहीं है। किसान अपने लिए संकेत, मांग के पैटर्नों (वास्तविक बाजार कीमतों में परिलक्षित) से नहीं बल्कि अनाजों के प्रापण एवं वितरण के विषय में सरकार की नीतियों से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार, सरकार के हस्तक्षेप से खाद्यान्न बाजारों के अनाजों की मांग एवं आपूर्ति के बीच के संबंध के कमजोर होने के संकेत मिलते हैं।

चित्र 21: भारत में खाद्यान्नों (अनाजों) के उपभोग एवं उत्पादन संबंधी रुझान



स्रोत: डीएसीएफ एवं डब्ल्यू तथा एनएसएस 68वां दौर

टिप्पणी: अनाजों के अंतर्गत चावल, गेहूं और मोटे अनाज शामिल हैं जिनमें कुल अनाज उत्पादन में चावल और गेहूं का भाग 80 प्रतिशत है। उपभोग संबंधी उपलब्धा आंकड़े केवल वर्ष 2011-12 तक के हैं।

4.28 उपर्युक्त विश्लेषण से यह प्रमाणित है कि एफसीआई की स्थापना से लेकर आज तक के बीच खाद्यान्न (अनाज) के संदर्भ में उल्लेखनीय बदलाव होते गए हैं। उत्पादन के मामले में ठोस वृद्धि के साथ भारत एक खाद्यान्न अभाव वाले देश के स्तर से ऊपर उठकर एक खाद्यान्न अधिशेष वाला देश बन गया है और अनाजों के एक विशुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है। सुनिश्चित खरीद और वितरण की सरकारी नीतियों ने उस समय उत्पादन बढ़ाने के लिए सही प्रोत्साहन दिया। हालांकि, वर्तमान खाद्यान्न अर्थव्यवस्था उपर्युक्त विभिन्न आर्थिक अक्षमताओं से त्रस्त है। इसलिए, इन नीतियों को अब विविधीकरण और पर्यावरणीय रूप से स्थायी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए आगे ले जाने की आवश्यकता है।

4.29 किसानों को ऐसी प्रत्यक्ष निवेश सब्सिडी और नकद हस्तांतरण के माध्यम से सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जो फसल तटस्थ/क्रॉप-न्यूट्रल हैं और किसान के फसल संबंधी निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कवरेज को निचले 20 प्रतिशत तक सीमित किया जाना चाहिए तथा अन्य के निर्गम मूल्य को खरीद मूल्यों/दरों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से आय हस्तांतरण करना एक बेहतर विकल्प होगा। यहां यह ध्यान दिया जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खाद्य असुरक्षा और गरीबी की समस्याओं से निपटने और बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर (बॉक्स 4) के प्रति लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से सशर्त नकद हस्तांतरण (सीसीटी) की दिशा में एक कदम

है। इसलिए खाद्यान्न नीति को गतिशील बनाने और खाद्यान्नों के वितरण और नकदी हस्तांतरण/खाद्य कूपन/स्मार्ट कार्ड से वितरण की अनुमति देने की आवश्यकता है। वृहद स्तर पर, कृषि विपणन, व्यापार (घरेलू और

विदेशी दोनों) और वितरण नीतियों को संरेखित करने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को विविधीकरण और स्थायी उत्पादन में विविधीकरण के लिए सही संकेत प्राप्त हों।

बॉक्स 4: सफल सशर्त नकदी हस्तांतरण योजनाओं के उदाहरण

देश	वर्ष	साधन/तौर-तरीके	प्रभाव
ब्राजील: बोलसा फमिलिया	2003	<ul style="list-style-type: none"> • 25 प्रतिशत आबादी को कवर करता है। • +60 से कम आय स्तर वाले पात्र लाभार्थी • अंतरण का आकार-आर + 15-95 • डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए बैंकों, लॉटरी कार्यालयों, फुटकर दुकानों/रीटेल स्टोर्स के माध्यम से भुगतान करें। • शर्तें-न्यूनतम 85 प्रतिशत उपस्थिति तथा महिलाओं व बालकों के लिए स्वास्थ्य जांच में अनिवार्य तौर पर भाग लेना। • योजना की लागत-जीडीपी का 0.5 प्रतिशत 	<ul style="list-style-type: none"> • 80% लाभ, अभिज्ञात लाभार्थियों को पहुंचे। • भोजन की कमी वाले घरों में गिरावट। • कुपोषित बच्चों की संख्या में कमी। • भोजन की खपत में वृद्धि। • 60% से अधिक लेनदेन गैर-बैंक एजेंसी के माध्यम से किए गए।
मेक्सिको: अपोर्चुनीडेड्स फिलीपींस:	1997	<ul style="list-style-type: none"> • भौगोलिक दृष्टि से गरीब क्षेत्रों पर फोकस/इन क्षेत्रों के हाशिए पर सूचकांक को उपयोग करते हुए घरों की पहचान की गई • कुल 20 प्रतिशत को कवर करता है • योजना की लागत - ढक्क का 0.4 प्रतिशत • हस्तांतरण का आकार 235 पीसो(औसत) • भुगतान दो महीनों में किया गया • बैंक शाखाओं और प्राधिकृत गैर-वित्तीय एजेंसियों से लाभ वापिस लिए जा सकते हैं। • शर्तें--न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य और अनिवार्य स्वास्थ्य जांच 	<ul style="list-style-type: none"> • 60 प्रतिशत लाभ आबादी के 20 प्रतिशत सबसे गरीब को मिले • रुग्णता की घटना में 12 प्रतिशत कमी • स्कूलों में बच्चों के दाखिलों में वृद्धि और स्कूल छोड़ने की दर में कमी • संभावना में वृद्धि कि महिलाएं तय करेंगी कि लाभ को कैसे खर्च किया जाए।
फिलीपींस: पैंटाविड पामिलयांग पिलीपीनो प्रोग्राम	2007	<ul style="list-style-type: none"> • कुल 20 प्रतिशत आबादी कवर करता है • लाभार्थियों की पहचान घरेलू सर्वेक्षणों के माध्यम से की गई • योजना की लागत ढक्क का 0.5 प्रतिशत • शर्तें - न्यूनतम उपस्थिति अनिवार्य और अनिवार्य स्वास्थ्य जांच, मासिक सामुदाय आधारित परिवार विकास सत्रों में भागीदारी 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 मिलियन फिलीपीनो लाभान्वित • कार्यक्रम के परिणामस्वरूप प्रतिवर्ष 1.4 प्रतिशत गरीबी में गिरावट आई • CCT से वर्तमान में 10.18 मिलियन बच्चे लाभ ले रहे हैं • 4 पी घरों में मदिरापान में तेजी से गिरावट आई (वाइस पर खर्च 39 प्रतिशत कम हुआ)।

स्रोत: वर्ल्ड बैंक एफ ए क्यू (2017), ICRIER (2017)

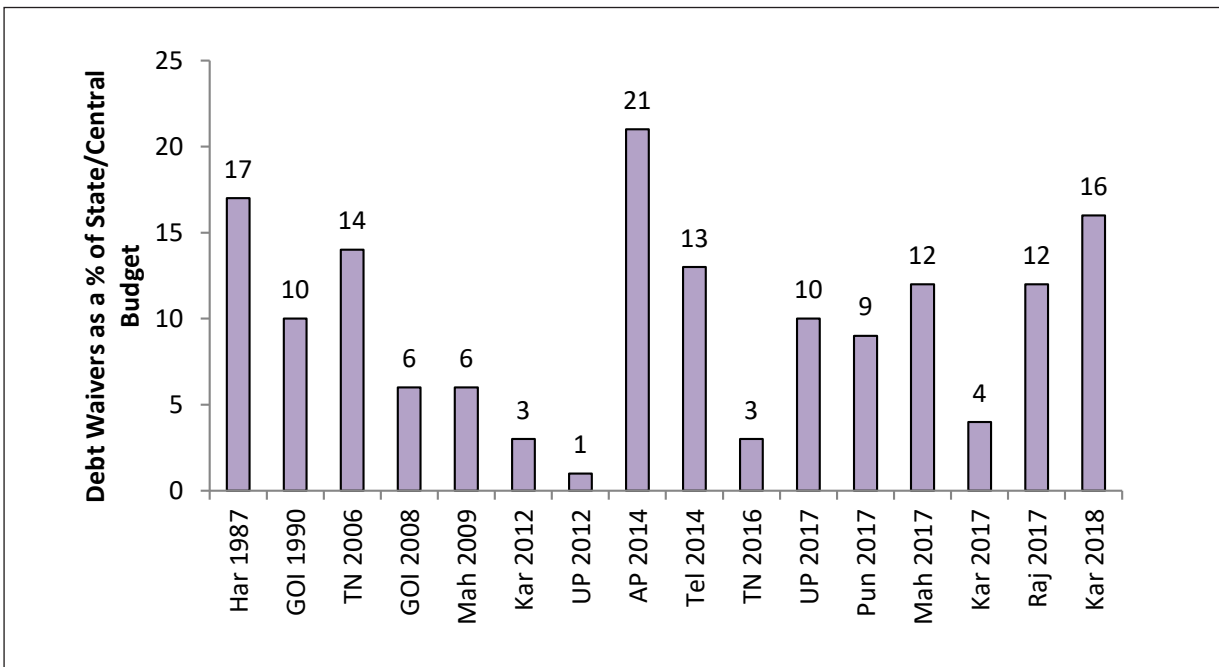
ऋण माफियां

4.30 साख बाजारों में पूर्ण या आंशिक शर्त सहित या बगैर शर्त सहित रूप में सरकारी गतिविधि, ऋण राहत भारत में राज्य स्तर पर आम बनाता जा रहा है। चुनाव से ठीक पूर्व या बाद में किसानों के ऋण माफ करने की परंपरा जो कि चुनाव घोषणपत्र में किए वायदे को पूरा करना से जुड़ा था नब्बे के शुरूआत में समाप्त हो चुका। हालांकि ये दृश्य 2008 में संघ सरकार द्वारा घोषित बृहर-स्तर के कृषि ऋण माफी के बाद ज्यादा व्यापक हुआ। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र और अन्य जैसे राज्यों में ऋण माफी की घोषणा हुई। चित्र 22 में इन माफियों के स्तर को राज्य/केंद्रीय बजटों के अनुपात अनुरूप दर्शाया गया है। भारत में कृषि ऋण राहत के रूप में सरकारी गतिविधि की प्रबलता का देखते हुए सामान्यतया लाभार्थियों और ऋण बाजार दोनों पर उनके प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है।

4.31 भारतीय साख बाजारों में सरकारी हस्तक्षेप के परिणामों की बहुत से सावधानीपूर्वक रूप से अनुसंधान अध्यायनों (कोज (2016), गिने और कांज (2017), मुखर्जी, सुब्रहमणियन और तंत्री (2018), तंत्री (2018) द्वारा जांच की गई है। साधारण घटना पूर्व और घटना पश्चात् तुलनाओं अथवा विस्तृत रूप से किस्सों पर आधारित दृष्टिकोण की तरह ये अध्ययन वास्तविक परिणामों की तुलना में काउंटर तथ्यात्मक के सावधानीपूर्वक प्रस्तुत प्रतिनिधित्व से करते हैं। अन्य शब्दों में यह तुलना करने का प्रयास है कि एक सरकारी हस्तक्षेप के बाद वास्तव में क्या होता है यदि ऐसे हस्तक्षेप नहीं होते तो क्या हुआ होता जो काउंटर-फैक्टुअल का प्रतिनिधित्व करता है। अतः इन अध्ययनों द्वारा किए गए अनौपचारिक दावे नीति उद्देश्यों हेतु विश्वसनीय है।

4.32 जब किसानों पर ऋण माफियों के लाभों पर वार्ता करते हैं तो समर्थनकर्ता यह अनुमान लगाते हैं कि उधार लेने वाले “डैब्ट ओवरहैंग” की समस्या

चित्र 22: राज्य/केंद्रीय बजट के प्रतिशत के रूप में ऋण माफी आवंटन



स्रोत: फडनिस और गुप्ता से लिया गया (2018)

से जूझ रहे हैं इसका तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जहां सब वर्तमान आय एकत्रित ऋण की पुर्नअदायगी में लग जाता है, जिसमें चाहे तो वास्तविक या मानवीय पूंजी में निवेश हेतु बहुत कम प्रोत्साहन राशियां बचती हैं। ये प्रोत्साहन राशियां मंद पड़ जाती हैं क्योंकि भौतिक अथवा मानीय पूंजी में ऐसे निवेश के किसी बढ़ते लाभ ऋणदाताओं तक विद्यमान बाध्यताओं की पुर्नअदायगी के रूप में पहुंचेगा और न कि किसानों तक। ऐसे उधार लेने वालों को या तो इक्विटी या ऋण के माध्यम से या वित्तीय प्राप्त नहीं हो सकेगा क्योंकि उधार लेने वाले की अतिरिक्त ऋण पुर्नअदा करने की अथवा उसका/उसकी व्यवसाय/फार्म विकसित करने की क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। डेब्ट होवरहैंग, अतः लाभकारी निवेश को तजने की ओर अग्रसर होता है और अतः सामाजिक कल्याण में कमी लाता है। इस स्थिति को देखते हुए ऋण राहत के समर्थक यह कहते हैं कि एक ऋण माफी उधार लेने वालों को ऋण जाल से बाहर आने में मदद करता है क्योंकि ये उनकी वहीं खाना को स्पष्ट करता है और ऋण सेक के भार को कम करता है। उधारकर्ताओं के बही खाता की सफाई से नए निवेशों के संभावनाएं बढ़ेंगी साथ ही साथ नए निधि बढ़ोत्तरी को भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि उधारकर्ताओं की पुर्नअदायगी क्षमता तब भी बढ़ेगी यदि आय में कोई बदलाव भी हुआ हो।

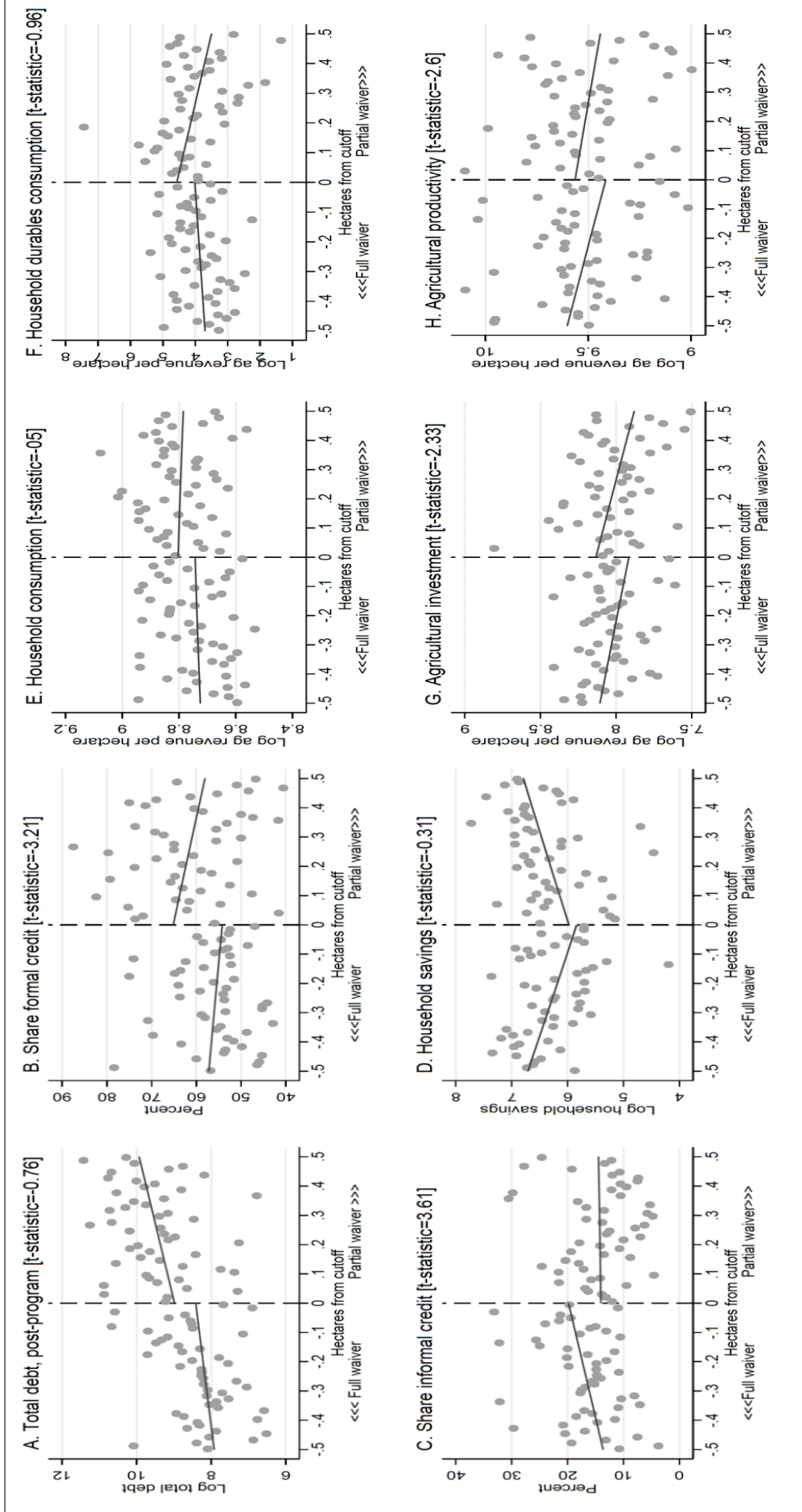
4.33 कान्ज (2016) भारत सरकार द्वारा दिए गए 2008 के ऋण माफी की जांच करता है और यह जांच करता है कि क्या इनमें से किसी प्रभाव से वास्तव में कुछ सिद्ध हो पाता है या नहीं। वो इस तथ्य का उदाहरण देते हैं कि जहां उन किसानों को पूरा फायदा हुआ जिनके पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि थी वहीं उन्हें कम फायदा पहुंचा जिनके पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि थी किसान जिसके पास 1.98 हैक्टेयर भूमि है वो कहीं से भी 2.02 हैक्टेयर भूमि वाले किसानों से अलग नहीं है। तथापि, जिन किसानों के पास 1.98 हैक्टेयर की भूमि है उन्हें पूर्ण राहत मिलती है जबकि 2.02 हैक्टेयर की भूमि प्राप्त करने वाले किसानों को केवल पाक्षित लाभ मिलता है। यदि ऋण राहत से

वास्तव में किसानों को लाभ मिलता है तो पहले किस्म के किसानों को आवश्यक रूप से मदद वाले किसानों से ज्यादा लाभ मिलना चाहिए था। हालांकि इसके परिणाम ठीक उसके उलट है जिस पर कि ऋण माफी के समर्थक विश्वास करते हैं। माफी के बाद ना तो कृषि निवेश का ही उत्पादकता में बढ़ोत्तरी देखी गई। साथ ही इसका खपत पर भी बहुत थोड़ा ही प्रभाव पड़ा है। अन्य शब्दों में एक उत्प्रेरक जिसकी कीमत जीडीपी का 2 प्रतिशत थी का किसानों के जीवन पर कोई अर्थकारी प्रभाव न छोड़ पाई।

4.34 चित्र 23 में इस परिणामों का सारांश दिया गया है जहां प्रत्येक पैनेल Y-अक्ष पर मुख्य परिणाम पर ऋण माफी के पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। क्षेत्रीय अक्षांश जोतों की दृष्टि से 02 हैक्टेयर के कट-ऑफ से दूरी को दर्शाता है। जिन उधारकर्ताओं की दूरी घनात्मक थी उन्हें पाक्षिक माफी मिली चूंकि उनके पास 2 हैक्टेयर से अधिक की जोत वाली जमीन थी। इसके उलट जिन उधारकर्ताओं की दूरी ऋणात्मक थी उनके पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि भी और अतः उन्हें पूरी ऋण माफी मिली। चित्र से यह स्पष्ट है कि ऋण माफी से पूर्व लाभार्थियों को पाक्षिक लाभार्थियों से ज्यादा लाभ नहीं मिलता। वास्तव में आंशिक लाभार्थियों से तुलना करने पर पूर्ण माफी लाभार्थी कम खपत करते हैं, कम निवेश करते हैं और माफी के अनुरूप कम उत्पादक हैं। कृषि निवेश और उत्पादकता हेतु प्रभाव सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय है। इसके साथ ही परेशान कर देने वाला साक्ष्य यह है कि जहां पाक्षित लाभार्थियों की तुलना में पूर्ण लाभार्थियों हेतु औपचारिक साख का अंश घटता है और तदनु रूप किसानों को उपलब्ध कराए गए ऋण माफी का मुख्य उद्देश्य समाप्त हो जाता है।

4.35 ऋण को माफ किए जाने से क्रेडिट मार्केट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बोलस्टैन और रोजेंटहाल (2002) का तर्क यह है कि ऋण से माफी देने की बात केवल उसी स्थिति में लाभदायी हो सकती है जब इसे असाधारण परिस्थितियों में दिया जाय और ये परिस्थितियां अप्रत्याशित बनी रहें। ऐसी परिस्थितियों में ऋण को माफ करने से किसान खेती बंद कर देंगे

चित्र 23: ऋण माफी के लाभार्थियों और तुलनात्मक रूप से गैर लाभार्थियों हेतु ऋण माफी के पश्चात् प्राप्त परिणाम



टिप्पणी: प्रत्येक पेनल में क्षैतिज अक्ष भूमि स्वामित्व की दृष्टि में कमी से दूरी को सूचित करता है। ऐसे लेनदार जिनकी दूरी घनात्मक है (ऋणायुक्त) वे पूर्ण रूप से ऋण माफी (आंशिक) लाभार्थी हैं। प्रत्येक चित्र में उर्ध्वाधर अक्ष एक भिन्न परिणाम दर्शाता है।

और इसके परिणामस्वरूप उत्पादन भी कम हो जाएगा। बहरहाल उनको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि ऋण को अप्रत्याशित रूप से माफ किए जाने से नैतिक ह्रास होगा और क्रेडिट कल्चर नष्ट हो जाएगी। 2008 के ऋण माफी की स्थिति को देखें तो पता चलेगा कि वही परिणाम अब भी आने वाले हैं। जीने और कांज का यह मानना है कि ऋण माफी दिये जाने से भविष्य में ऋण को वापस न किए जाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी और मजदूरी, उत्पादकता या उपभोग में कोई भी सुधार नहीं आएगा। वे सरकार द्वारा 2008 में दी गयी ऋण माफी से प्रभावित जिलों के आधार पर तुलना कर रहे हैं। एक प्रतिशत ऋण की माफी दिये जाने से काम न आने वाली परिसंपत्तियों में लगभग 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाती है। इससे भी अधिक कष्ट की बात तो यह है कि ऋण को लेकर जो स्थिति खराब होती है उसका असर अन्य सभी क्षेत्रों पर पड़ता है जिनके आधार पर हम चुनाव लड़ने जा रहे होते हैं, और ऋण के माफ किए जाने की स्थिति का पूर्वानुमान नहीं लगा पाते हैं। बिडम्बना यह भी है कि ऋण को माफ कर दिये जाने से माफी का लाभ लेने वाले को बैंक से ऋण मिलना कम हो गया है। किसी जिले में 1 प्रतिशत ज्यादा ऋण माफ किए जाने से नए ऋण को प्राप्त करने वालों की संख्या में 4-6 प्रतिशत की कमी आ जाती है और कार्यक्रमपरक ऋण की राशि में भी 14-16 प्रतिशत की कमी आई है।

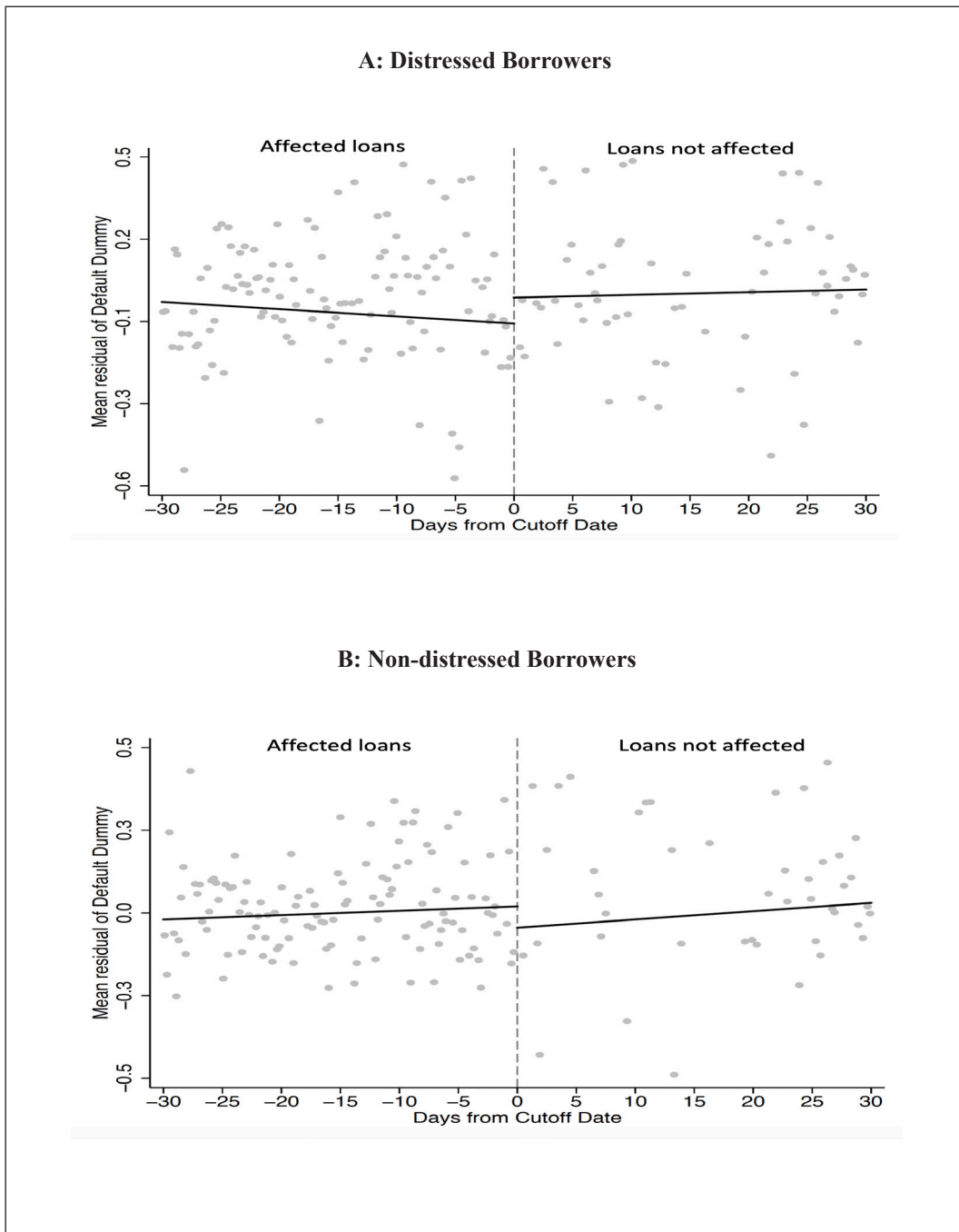
4.36 तंत्री (2008) ने पाया है कि गैर-वित्तीय ऋण में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 2010 में किए गए हस्तक्षेप से क्रेडिट मार्केट के अन्य क्षेत्रों जैसे कि बैंक ऋणों पर संक्रामक प्रभाव पड़ा है। अक्टूबर 2010 में आंध्र प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था जो कि मुख्यतया छोटे-मोटे कर्जदारों से ऋण वसूली की सभी विधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया था। हालांकि व्यष्टिपरक वित्तीय क्षेत्र में ऋण संबंधी अपराध ऐसे हस्तक्षेप के बाद ज्यादा बढ़ गए थे। इस प्रकार के हस्तक्षेप का बैन ऋण पर भी संक्रामक प्रभाव पड़ा था। बैंक ऋणों को अदा न करने और काम न आने वाली परिसंपत्तियों की दर में ऐसे हस्तक्षेप के बाद क्रमशः 12.4 प्रतिशत और 24.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो गयी

थी। अंततः, चूंकि, नए ऋण को देने में की स्थिति कम हो कर आधी हो गयी है, सरकार का यह हस्तक्षेप कि छोटे-मोटे कर्जदारों की मदद की जाय कर्जदारों के लिए नुकसानदेह साबित हुई क्योंकि वे क्रेडिट से वंचित हो गए।

4.37 मुखर्जी, सुब्रमण्ययम और तंत्री (2018), जिन्होंने सरकार द्वारा 2008 में दी गयी ऋण माफी की समीक्षा की थी, ने एक और बारीक बिन्दु की ओर ध्यान दिलाया है। उन्होंने परेशान और गैर-परेशान दोनों प्रकार के कर्जदारों को दी गयी कर्ज-माफी के प्रभाव का फसल-बीमा के दावे और मौसम संबंधी परिस्थितियों के आधार पर अलग-अलग अध्ययन किया है जिससे कि कर्जदारों की आर्थिक विपन्नता का पता लगाया जा सके। उन्होंने पाया है कि, ऋण की माफी दिये जाने से, जो सच-मुच में संकट-ग्रस्त उनके काम-काज में 9 प्रतिशत का सुधार आया है जबकि जो सच-मुच में संकटग्रस्त नहीं थे उनका ऋण माफ किए जाने के कारण उनके काम-काज में 23 प्रतिशत की खराबी आई है। पहचान परक रणनीति के आधार पर ह्रास के समापन का पता लगाने के लिए वे ऋण माफी की पात्रता की कट-आफ तारीख 31 दिसंबर 2007 को मानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना काफी महत्वपूर्ण है कि, लाभानुभोगियों के बारे में निर्णय लेने की कट-आफ 20 फरवरी 2008 मानी गयी थी, और इसी लिए कर्जदार लोगों को 31 दिसम्बर कि कट-आफ डेट होने के बारे में पता नहीं था।

4.38 दो संकटग्रस्त किसान A और B को लें जिनके बारे में मान लेते हैं कि उन्होंने क्रमशः 30 दिसम्बर 2007 को और 1 जनवरी 2008 को अपने फसल रिन को अदा नहीं किया था। अब 31 दिसंबर 2008 को हम ऋण माफी की कट-आफ डेट मान लेते हैं तो A का ऋण माफ हो जाएगा लेकिन B का ऋण माफ नहीं हो पाएगा। अन्यथा दोनों कर्जदार एक जैसे ही होते। इस अध्ययन से पता चलता है कि ऋण माफ किए जाने से कर्जदार A ने ऋण का उपयोग अच्छा किया है। अब दो गैर-संकटग्रस्त किसानों C और D पर विचार करते हैं, जिन्होंने क्रमशः 30 दिसम्बर 2007 और 1 जनवरी

चित्र 24: संकटग्रस्त और गैर-संकटग्रस्त लेनदारों पर ऋण माफी का प्रभाव



स्रोत: मुखर्जी, सुब्रमणियन और तन्त्री (2018) से लिया गया।

2008 को अपने फसल-ऋण का भुगतान करने में चूक की थी।

4.39 चित्र 24 इस अध्याय का मुख्य परिणाम दर्शाता है। सामान्तर एक्सिस माफी की कट-ऑफ पात्रता से दूरी को डिनोट करता है। वर्टिकल

एक्सिस दोष दर को डिनोट करता है। पैनेल ए (बी) हताश (गैर हताश) ऋण लेने वालों के परिणाम को दर्शाता है। जो लोग कट-ऑफ के बाईं और (दाईं) और है ऋण माफी के लाभार्थी हैं (गैर लाभार्थी) है। चित्र से यह स्पष्ट होता है

कि हताश (गैर हताशों) के बीच जिन लाभार्थियों का ऋण माफ किया गया है उनकी संख्या कम है (अधिक) है जब उनकी तुलना ऋण माफी के बाद गैर लाभार्थियों से की जाती है। सामांतर एक्सिस माफी की कट-ऑफ पात्रा से दूरी को डिनोट करता है। वर्टिकल एक्सिस कृषि फसल ऋण पर दोष दर को डिनोट करता है चित्र ए यह दर्शाता है कि हताश ऋण माफी लाभार्थियों से 9 प्रतिशत कम है जब इनकी तुलना गैर लाभार्थियों से की जाए। चित्र बी यह दर्शाता है कि गैर हताश लाभार्थी दोषी गैर हताश गैर लाभार्थियों की तुलना में 23 प्रतिशत अधिक है।

4.40 उपर्युक्त अध्ययन से पता चलता है कि बिना शर्त और अंधाधुंध ऋण-माफी देना एक गलत बात है। इससे लाभानुभोगियों को कोई सार्थक लाभ नहीं मिलता है और राजकोष पर बहुत भार भी पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, ऋण-माफी से पूरी क्रेडिट कल्चर खराब होती है और इससे उनके जैसे अन्य किसानों को ऋण नहीं मिल पाता है जिनको इसकी मदद की जरूरत होती है। जैसाकि मुखर्जी, सुब्रमण्यम और तान्त्री (2018) और बोल्सटन तथा रोजेंटहाल ने पाया है, सच-मुच संकट की अवस्था में सीमित राहल प्रदान की जा सकती। दूसरे शब्दों में कहे शब्दों में कहे तो ऋण-माफी को आपातकालिक दावा के रूप से दिया जा सकता है वो भी एकाध मामलों में और रोग की पहचान किए जाने के बाद। इसे योजना के भोजन की तरह नहीं दिया जाना चाहिए।

क्योंकि अधिकांश मामलों में इसके दुष्प्रभाव तथा अवांछनीय परिणाम देखने को मिलते हैं। इससे केवल अल्पकालिक लाभ ही दिखाई देता है।

सरकारी हस्तक्षेप को कम करने के लिए अपेक्षित विधायी बदलाव-

4.41 उपर्युक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि, भारत अभी भी तरह-तरह के हस्तक्षेप के बीच फंसा पड़ा है जिसका आज कि अर्थव्यवस्था से कोई ताल-मेल नहीं है। अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में आधिपत्य और नियंत्रण कारी अर्थव्यवस्था के मार्ग से हट कर बाजार निर्भर अर्थव्यवस्था में बादल गया है। सारणी 1 से ऐसा कई क्षेत्रों के बारे में पता चलता है जैसे विशेषकर, औद्योगिक उदारीकरण, राज्य के स्वामित्व वाले कई उपक्रमों का निजीकरण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश पर नियंत्रण में कटौती।

4.42 बहरहाल, जैसाकि पिछले भागों में प्रकाश डाला गया है, कई क्षेत्रों में गैरतजरूरी और अकुशल सरकारी हस्तक्षेप बना हुआ है। सारणी 2 में कुछ अधिनियमों को दिया गया है, जो कि शुरूआती दौर पर बहुत नीचे लटके फफल की तरह थे, जिनकी उपयोगिता अब समाप्त हो गयी है और उनाकू समाप्त किए जाने की जरूरत है जैसा कि 1990 के दशक में किया गया था या उनमें संशोधन किया गया था ताकि बाजार में प्रतिस्पर्धा बनी रहे।

सारणी 1 “नियंत्रण” से लेकर “बाजार” तक “संपूर्ण चक्र” को पूरा करना

अधिनियम	बाजार में की गई विकृति	बाजार अर्थव्यवस्था विकसित करने की दिशा में बदलाव
पूँजी संबंधी मुद्दा (नियंत्रण) अधिनियम, 1947	सरकार ने यह तय किया कि कौन सी कंपनी कितनी पूँजी उठा सकती है धनराशि और शेरों के मूल्य पर नियंत्रण रखने के कारण अप्रभावी मूल्यांकन हुआ।	पूँजीगत बाजारों के विनियामक के रूप में भारतीय प्रतिभूमि एवं विनियम बोर्ड (सेबी) अधिनियम, 1992 द्वारा रद्द एवं प्रतिस्थापित करना। सेबी ने मूल्य वापसी प्रतिभूतियों के अभिशासन सुनिश्चित करने, पूँजी का कुशल संग्रहण एवं आर्बटन करने निवेशकों के हित की रक्षा करने, अत्यधिक धन सृजन को उदार बनाने के लिए पूँजीगत बाजार को रास्ते पर लाया। (अध्याय 1 में यथा उल्लिखित)
तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (ओएनजीसी) अधिनियम, 1959	ओएनजीसी का गठन पेट्रोलियम संसाधनों के विकास के लिए योजना बनाने, उस प्रोत्साहित करने, कार्यक्रम आयोजित करने एवं कार्यान्वित करने के लिए अधिदेश के साथ किया गया था।	4 सितम्बर, 1993 को इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया और ओएनजीसी को एक कंपनी में बदल दिया गया। हाइड्रोकार्बन नीति का 1946 में राज्य एकाधिकार से लेकर नामकरण के माध्यम से 1991 में अविनियमन करी शुरूआत तक, नई अन्वेषण लाइसेंस पॉलिसी, 1997 के अंतर्गत प्रतिस्पर्धी बोली एवं लाभ हिस्सेदारी तक, 2014 में गैस मूल्य निर्धारण दिशा-निर्देश तक, 2015 में लघु क्षेत्र नीति अन्वेषण और अंत में 2016 में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण एवं उतपादन तथा राजस्व की हिस्सेदारी के लिए एक समान लाइसेंस तक हुआ।
बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों को अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 तथा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955	गठित कुछ बैंकिंग कंपनियों के उपक्रमों के अधिग्रहण एवं हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए 27 राष्ट्रीयकृत बैंकों का गठन किया गया-निजी क्षेत्र के बैंकों को 1994 के बाद ही अनुमति दी गई।	बैंकों के विलय की घोषणा की गई जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 27 से घटकर 12 हो जाएगी। इसके अलावा, निजी क्षेत्र के बैंकों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच एमसमान प्रतिस्पर्धा क्षेत्र तैयार करने का प्रयास है।
एकाधिकार एवं प्रतिबंधक व्यापार कार्य (एमआरटीपी) अधिनियम, 1969	एमआरटीपीसी का गठन आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण को रोकने, एकाधिकार को नियंत्रित करने, एकाधिकार कार्यों का निषेध करने, प्रतिबंधक एवं अनुचित कार्यों का निषेध करने के लिए किया गया था। इससे कंपनियों का विकास एवं वैश्विक स्तर प्राप्त करना और छोटी कंपनियों का प्रसार प्रतिबंधित हो गया।	2002 में कंपनी अधिनियम का त्याग करने के लिए रद्द कर दिया गया। कंपनी अधिनियम का लक्ष्य “बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा प्रतिस्पर्धी बनाए रखना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना, बाजारों में अन्य भागीदारों द्वारा किए गए व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना और प्रभुत्व स्थितियों के दुरुपयोग का निषेध करना है। ध्यान “प्रभुत्व के निषेध” से हटकर “प्रभुत्व के दुरुपयोग को विनियमित करने” पर हो गया है।
कोकिंग कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 और कोयला खदान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973	सरकार को कोकिंग एवं गैर-कोकिंग कोयला खदानों के प्रबंधन को अपने हाथों में ले लिया क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया।	2018 में रद्द कर दिया गया। निजी कंपनियों को व्यावसायिक कोयला खदान उद्योग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी गई है। खदानों की नीलामी उस कंपनी को दी जाएगी जो सबसे अधिक प्रति टन मूल्य का प्रस्ताव करेगी। उस कदम से व्यावसायिक खनन पर कोल इंडिया लि. का एकाधिकार समाप्त हो गया।

अधिनियम	बाजार में की गई विकृति	बाजार अर्थव्यवस्था विकसित करने की दिशा में बदलाव
जीवन बीमा, 1956 का राष्ट्रीयकरण और सामान्य बीमा व्यवसाय (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972	एलआईसी एवं जीआईसी का सृजन करने के लिए भारतीय बीमा कंपनियों के शेयरों तथा अन्य मौजूदा बीमा कंपनियों के उद्यमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण के कारण सरकार द्वारा विनिश्चित क्षेत्रों में निवेश के लिए संसाधनों का संग्रहण कम हुआ।	अनेक बार संशोधन किया गया। बीमा क्षेत्र को खोलने के लिए भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण, 1999 का अधिनियमन किया गया। यह निजी प्रतिस्पर्धा आरंभ करने के लिए राष्ट्रीयकरण से समाप्त करके एकाधिकार स्थापित करने की दिशा में एक कदम था।
विदेशी विनिमय विनियामक अधिनियम, 1973	कंपनियों में विदेशी इक्विटी पर 40 प्रतिशत की सीमा लगाया गया और यदि उनकी शेयरधारिता अधिक हो तो उन्हें परिचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता थी। इससे विदेशी पूंजी एवं प्रौद्योगिकी तक पहुंच सीमित हो गई।	इसे रद्द कर दिया गया और विदेशी व्यापार एवं भुगताना सरल बनाने के लिए इसे विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 द्वारा बदल दिया गया। फेमा के अंतर्गत जब तक विशेष अनुमति प्राप्त नहीं हो जाती थी, जबकि फेमा के अंतर्गत जब तक विशेष रूप से प्रतिबंधित नहीं किया जाता था या विदेशी विनिमय बाजार का विकास करने के लिए विनियमित नहीं किया जाता था, तब तक सब कुछ की अनुमति थी।
मारुति लिमिटेड (उद्यमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1980	इसका उद्देश्य ऑटोमोबाइल उद्योग का आधुनिकीकरण करना तथा मोटर वाहनों का अधिक उत्पादन सुनिश्चित करना था।	14 मई, 2007 को सरकार ने दो स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से कंपनी को बाहर किया। सार्वजनिक निर्गमन के माध्यम से उसके मौजूदा शेयरों की बिक्री करके 400 करोड़ रुपए का अधिकार निर्गमन किया गया।
एयर कार्पोरेशन अधिनियम, 1953	एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइन्स का गठन करने के लिए नौ एयर लाइन कंपनियों का राष्ट्रीयकरण किया गया-सुरक्षित, कुशल, पर्याप्त, क्रिफायती और समुचित रूप से संचालित एयर ट्रांसपोर्ट सेवाएं, चाहे वह आंतरिक हो, अंतर्राष्ट्रीय हो आवा दोनों हो, मुहैया कराना उसका उद्देश्य था। एक बाजार संचालित, सेवा उन्मुखी, उपभोक्ता केंद्रित व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ।	इसे एयर कार्पोरेशन (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 1994 द्वारा बदल दिया गया जिसमें निजी ऑपरेटरों को एयर ट्रांसपोर्ट सेवाएं मुहैया कराने की अनुमति दी गई। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2003 ने “निजी हवाई अड्डा” पद आरंभ किया और भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण को निजी व्यवसायियों को दीर्घकालिक पट्टा के माध्यम से इसके मौजूदा हवाई अड्डों का परिचालन एवं प्रबंधन हस्तांतरित करने के लिए प्राधिकृत किया। प्रशुल्क एवं अन्य प्रभारों को विनियमित करने और नष्पादन मानकों की निगरानी करने के लिए भारतीय हवाई अड्डा आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ईआरए) अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया गया।
शहरी भूमि सीमांकन एवं विनियमन अधिनियम, 1976	कुछ लोगों के हाथों में शहरी भूमि केन्द्रित होने से रोकने और जनता की भलाई में सहयोगी होने के लिए शहरी समुदायों में अधिग्रहण के लिए खाली भूमि के अधिग्रहण पर अंतिम सीमा निर्धारित करना।	1999 में निरस्त कर दिया गया।
रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एसआईसीए) 1985	औद्योगिक एवं वित्तीय सुधार बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा बीमार, एवं घाटे में जाने वाली कंपनियों का समय पर पता लगाना तथा निवारण, सुधारात्मक उपचारात्मक एवं अन्य उपायों का शीघ्र निर्धारण। इससे एक कर्जदार अनुकूल अवधि की शुरुआत हुई जिसमें चुककर्ता कर्जदार लम्बी अवधि तक समाधान में विलम्ब कर सकते थे और परिसंपत्तियों के मूल्य से वंचित कर सकते थे।	इस अधिनियम को 1 जनवरी, 2004 को निरस्त कर दिया गया और दिवालियापन एवं क्रणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी), 2016 को समाप्त करने के लिए बीआईएफआर को 1 दिसंबर, 2016 को समाप्त कर दिया गया।

सारणी 2: परिवर्तन पूरी करने की आवश्यकता: अधिनियम जिन्हें निरस्त/संशोधन करने की आवश्यकता

अधिनियम	बाजार में की गई विकृति	निरस्त/संशोधन की आवश्यकता
फैक्ट्री अधिनियम, 1948	फैक्ट्रियों एवं बंदरगाहों में व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को विनियमित करता है। यह एक “मुख्य निरीक्षक” को अभियोजन शक्ति प्रदान करता है ऐसे दावों की लागत में वृद्धि करता है और श्रमिकों से पूंजी को दूर करता है। इसका विलय किया जा सकता है।	इसे व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा कोड, 2019 द्वारा सम्मिलित किये जाना प्रस्तावित हुआ है जोकि संसद में है।
अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए), 1955 और चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980	सरकार को उत्पादन नियंत्रण में सक्षम बनाना, आवश्यक वस्तु की आपूर्ति और वितरण जैसे कि दवाईयां, तेल, केरोसीन, कोयला, लोहा, स्टील और दालें। यह स्टॉक सीमा निर्धारित करती है जिसकी वजह से कृषि बाजार में बड़े पैमाने पर निजी विनिवेश कम होता है।	यह अधिनियम कमी और बाजार से अप्रभावी जुड़ाव के समय में अपने प्रभाव में आए बढ़ते हुए उत्पादन और बाजारों के एकत्रीकरण के साथ ये अधिनियम नियंत्रण के साधन बने तथा इन अत्यावश्यक वस्तुओं के बाजार का समुचित कार्य में बाधक है।
भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), 1965	एफसीआई का निर्माण किसानों के हितों का संरक्षण करने हेतु खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण यातायात, वितरण और खाद्यान्नों एवं अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री हेतु किया गया था ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कमजोर और अति-संवेदनशील वर्गों को किफायती कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके।	खाद्यान्न के सुविधाजनक उत्पादन परिदृश्य को देखते हुए 80 मिलियन टनों से अधिक की कुल भंडारण क्षमता के साथ एफसीआई की भूमिका की पुनः जांच की जानी चाहिए। गेहूं, धान और चावल के खरीद संबंधी प्रचालन के कार्य राज्यों को सौंपे जाने चाहिए। एफसीआई को खाद्यान्नों की खरीद से भंडारण, उसकी आवाजाही और अंततः टीपीडीएस में वितरण तक खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में प्रतिस्पर्धा का सृजन करने में प्राथमिक रूप से ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे खाद्य प्रबंधन प्रणाली लागतों में कमी आएगी और इससे जुड़ी गड़बड़ियों पर अंकुश लगेगा।
शहरी भूमि सीमाबंदी एवं विनियम अधिनियम, 1976	शहरी समूह में रिक्त पड़ी भूमि के अधिग्रहण पर सीमाबंदी करना ताकि शहरी भूमि को कुछ लोगों के अधिकार क्षेत्र से बाहर करना और समान अवसर हेतु एकरूपता लाई जा सके। इसके परिणामस्वरूप, शहरी क्षेत्रों में भूमि बाजारों में विकृति आई, मलिन बस्तुओं में वृद्धि, कृत्रिम भूमि अनुपलब्धता सृजन और भूमि के आसमान धूते मूल्य।	1999 में पुनः अपील

रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम, 1985

औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BICR) द्वारा रुग्ण एवं संभावित रुग्ण कंपनियों की समय पर पहचान करना और ताकि निवारणीय, सुधारात्मक, उपचारात्मक और अन्य उपाय। इसने एक उधारकर्ता समर्थक सत्ता स्थापित की जिसमें चूककर्ता उधारकर्ता समाधान को लंबे समय तक बढ़ा सकते हैं और आस्तियों के मूल्य कम कर सकते हैं।

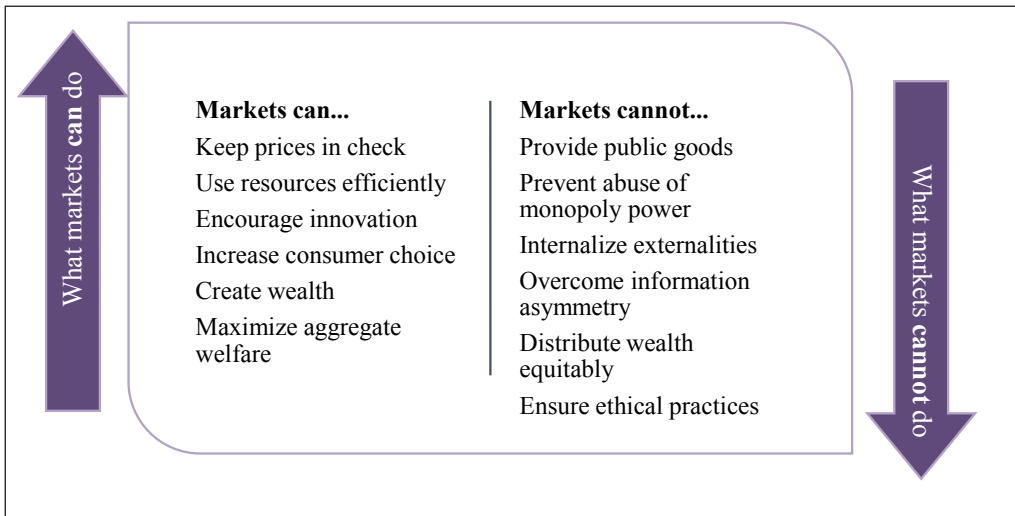
अधिनियम पर 1 जनवरी 2004 को पुनः अपील की गई थी और ठप्पू को 1 दिसंबर 2016 को समाप्त कर दिया था ताकि बेबाकी एवं दिवालियापन कोड (BICR) इसका स्थान ले सके।

निष्कर्ष

4.43 अर्थव्यवस्था में संसाधनों को आबंटित करने में प्रतियोगात्मक बाजार प्रभावी है। तथापि, चूंकि पूर्ण दक्ष बाजार का विचार दुर्लभ है, सरकारी हस्तक्षेप की कीमत लाभों से अधिक भारी हो सकती है जब “बाजार विफलता” शब्द जोकि अर्थशास्त्री उस स्थिति को बतलाते हैं जहां आबंटित होने वाले संसाधनों में अच्छी तरह से कार्य न कर सके तथा वे गंभीर नहीं हों। बेशक, सरकार जहां “बाजार विफलता” विकट हो (सार के लिए चित्र 25 देखें) स्थितियों में हस्तक्षेप करने के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

4.44 यह अध्याय ऐसे मामले बनाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत से क्षेत्र हैं जहां सरकार बिना आवश्यकता के हस्तक्षेप करती हैं तथा बाजार को उपेक्षित करती है। यह ध्यान दे यह अध्याय इस बात में तर्क नहीं करता है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो। इसके बजाय हस्तक्षेप जोकि विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं में उपर्युक्त थे ने परिवर्तित अर्थव्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता को खो दिया हो। अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के ऐसे उदाहरणों को हटाना प्रतियोगिता बाजार को सक्षम बनाएगा तथा जिसके द्वारा निवेश एवं आर्थिक विकास में बढ़ातरी होगी।

चित्र 25 बाजार की ताकत एवं कमजोरी



अध्याय एक दृष्टि में

- भारतीय अर्थव्यवस्था उदाहरणों से भरी हुई है जहां सरकार हस्तक्षेप करती है तथा जिसके द्वारा अनावश्यक रूप से बाजार को अपेक्षित करती है अर्थात ऐसे क्षेत्रों में भी जहां कोई बाजार विफलता नहीं है। यद्यपि ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, यह अध्याय सरकारी हस्तक्षेप को दिखाने के लिए चार उदाहरणों को रेखांकित करता है जिसका परिणाम उल्टा हुआ है जोकि वास्तव में प्राप्त करने के इरादों से था।

- आवश्यक वस्तु अधिनियम (ईसीए) के अंतर्गत वस्तुओं पर ब्लैनकेट स्टॉक लिमिट का बार-बार तथा अप्रत्याशित लागू करना निजी क्षेत्र, कृषि मूल्य श्रृंखला का ऊपर बढ़ना तथा कृषि वस्तुओं के लिए राष्ट्रीय बाजार के विकास द्वारा भंडार अवसंरचना के सृजन के लिए प्रोत्साहनों को बिगाड़ता है। 2006 की तीसरी तिमाही में दाल पर, तथा 2009 की पहली तिमाही में चीनी तथा सितम्बर, 2019 में स्टॉक लिमिट लागू करने का प्याज के खुदरा एवं थोक कीमतों की अस्थिरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था।
- उपभोक्ता कार्य मंत्रालय तथा इससे संबंधित इकाइयों को जरूर जांचना चाहिए कि क्या काल भ्रमित ईसीए जोकि अकाल एवं कमी के बारे में चिन्तित भारत में 1955 में पारित किया गया था क्या वह आज के भारत के लिए प्रासंगिक है। 2019 के दौरान ईसीए के अंतर्गत 76,000 छापे करवाए गए थे। यह मान के चलते हुए कि एक छापे में कम से कम पांच लोग लगे होंगे, काफी प्रशासनिक प्रयास ईसीए को लागू करने में चला गया होगा। तथापि, जिस प्रकार से सजा दर अगाध रूप से कम है तथा छापां का कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं है, ईसीए केवल रेन्ट सीकिंग तथा उत्पीड़न समर्थ बनाने के लिए प्रतीत होता है यह समीक्षा स्पष्ट साक्ष्य प्रदान करती है कि इस काल भ्रमित विधान पर बोझ डालने का मामला मजबूत है।
- डीपीसीओ 2013 के जरिए दवाईयों की कीमतों का विनियमन ने उन समान दवाईयों को जिनकी कीमत विनियमित नहीं की गई थी की तुलना में विनियमित फार्मासिटिकल दवाईयों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। कीमतों में बढ़ोतरी सस्ते फार्मूलेशन की अपेक्षा फार्मूलेशन के लिए बड़ी है तथा उनके लिए जोकि खुदरा दुकानों की अपेक्षा अस्पतालों में बेचा जाता है। ये परिणाम पुनर्वलन देते हैं कि परिणाम बिल्कुल उसके विपरीत है जिसके लिए डीपीसीओ बना था अर्थात दवाईयों को सस्ता करना।
- चूंकि सरकार इसके विभिन्न विभागों जैसे कि सीजीएसएस, रक्षा, रेलवे इत्यादि के जरिए दवाईयों का बहुत बड़ा विक्रेता है, सरकार अपनी सभी खरीदारियों को एक करने के द्वारा सस्ती दवा प्रदान करने के लिए अधिकांश प्रभावी ढंग से हस्तक्षेप कर सकती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और इससे जुड़े विभागों को गैर विरूपनयोग तंत्र को विकसित करने के लिए साक्ष्य को आत्मसात करना चाहिए जिससे कि पारदर्शी तरीके से सरकार की मोलभाव शक्ति का उपयोग किया जा सके।
- खाद्य बाजार में सरकारी नीतियों के कारण, सरकार चावल एवं गेहू के सबसे बड़े उत्पादक की भंडारण कर्ता भंडारकर्ता के रूप में उभरी है। इसने बाजार में तेजी से बढ़ती हुई खाद्य सब्सिडी भार एवं अक्षमता को बढ़ाया है जोकि कृषि क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास को प्रभावित कर रहा है। इस खाद्य नीति को गतिशील बनाए जाने की आवश्यकता है तथा नकद अंतरण/खाद्य कूपन/स्मार्टकार्ड को, खाद्य पदार्थों की वास्तविक निगरानी तथा वितरण से बदलने की अनुमति देता है।
- राज्यों/केन्द्रों द्वारा दिए गए ऋण माफी का विश्लेषण यह दिखाता है कि जब आंशिक लाभार्थियों की तुलना पूरी माफी वाले लाभार्थियों से की जाती है तो छूट के पश्चात् यह कम उपभोग होता है, कम बचता है, कम निवेश करता है तथा कम उत्पादक होता है। ऋण माफी प्रवाह साख संस्कृति को बाधित करता है तथा बहुत एक जैसे किसानों को औपचारिक ऋण कम करके खतम करता है जिसके द्वारा किसानों को दी गई ऋण माफी का उपदेश लोप हो जाता है।
- इस अध्याय में इस मामले का वर्णन है कि सरकार के प्रत्येक विभाग एवं मंत्रालय को व्यवस्थित रूप से उन क्षेत्रों की जांच करनी चाहिए जहां सरकार अनावश्यक हस्तक्षेप करती है बाजारों को उपेक्षित करती है। यह ध्यान दे कि यह अध्याय इस बात में तर्क नहीं करता है कि सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो। इसके बजाए हस्तक्षेप जोकि विभिन्न आर्थिक व्यवस्थाओं में उपयुक्त थे ने परिवर्तित अर्थव्यवस्था में अपनी प्रासंगिकता को खो दिया हो। अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप के ऐसे उदाहरणों को हटाना प्रतियोगिता बाजार को सक्षम बनाएगा तथा जिसके द्वारा निवेश एवं आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होगी।

संदर्भ

- Banerjee, A, and L. Iyer. 2005. "History, institutions, and economic performance: The legacy of colonial land tenure systems in India." *American economic review* 95 (4): 1190–1213.
- Bolton, P, and H. Rosenthal. 2002. "Political intervention in debt contracts." *Journal of Political Economy* 110 (5): 1103–1134.
- Cunningham, S. 2011. *Understanding market failures in an economic development context*. Vol. 4. Pretoria: Mesopartner Press.
- Gine', X, and M. Kancz. 2017. "The economic effects of a borrower bailout: evidence from an emerging market." *The Review of Financial Studies* 31 (5): 1752–1783.
- Gulati, Ashok, Tirtha Chatterjee, and Siraj Hussain. n.d. "Supporting Indian Farmers: Price Support or Direct Income/Investment Support?" *ICRIER WP* 357.
- Hayek, F. A. 1945. "The Use of Knowledge in Society." *The American Economic Review* 35 (4): 519-530.
- High Level Committee Report on Reorienting the Role and Restructuring of Food Corporation of India (FCI)
- Kancz, M. 2016. "What does debt relief do for development? Evidence from India's bailout for rural households." *American Economic Journal: Applied Economics* 8 (4): 66–99.
- Keynes, J M. 1936. *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London: McMillan.
- Mukherjee , Saptarshi , Krishnamurthy Subramanian, and Prasanna Tantri. 2018. "Borrowers' Distress and Debt Relief: Evidence from a Natural Experiment." *University of Chicago Press* 61 (4): 607-635.
- Phadnis, Ajit , and Aishwarya Gupta. 2019. "The Politics of Farm Loan Waivers: A Comparative Study." *Economic and Political Weekly* 54 (23).
- Sahay, Arvind, and Saravana Jaikumar. 2016. "Does Pharmaceutical Price Regulation Result in Greater Access to Essential Medicines? Study of the impact of drug price control order on sales volume of drugs in India." *IIMA Working Papers WP2016-02-01, Indian Institute of Management Ahmedabad, Research and Publication Department*.
- Saini, Shweta, Sameedh Sharma, Ashok Gulati, Siraj Hussain, and Joachim von Braun. 2017. "Indian food and welfare schemes: Scope for digitization towards cash transfers." *SSRN Electronic Journal*.
- Tantri, P L. 2018. "Contagious effects of a political intervention in debt contracts: Evidence using loan-level data." *The Review of Financial Studies* 31 (11): 4556–4592.

नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में निर्यात-विशेषज्ञता द्वारा रोजगार-सृजन और विकास

05

अध्याय

“प्रत्येक मनुष्य का जीवन परस्पर आदान-प्रदान से चलता है।”

-एडम स्मिथ

अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु वर्तमान परिवेश भारत को चीन जैसे श्रम-प्रधान निर्यात पथ का अनुसरण करने का एक अभूतपूर्व अवसर प्रदान करता है और हमारे उदीयमान युवाओं के लिए असीमित रोजगार अवसर सृजित करने का एक अनन्य अवसर प्रदान करता है। “असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड” को ‘मेक इन इंडिया’ के साथ एकीकृत करके, भारत वर्ष 2025 तक 4 करोड़ और वर्ष 2030 तक 8 करोड़ उत्तम वैतनिक रोजगार सृजित कर सकता है। नेटवर्क उत्पादों का निर्यात, जिसके वर्ष 2025 में वैश्विक स्तर पर 7 ट्रिलियन डालर तक पहुंचने की आशा है, वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डालर अर्थव्यवस्था के लिए मूल्य-वर्धित में वृद्धि करते हुए इसके एक चौथाई तक योगदान कर सकता है। इसलिए, इस अध्याय में इस सुअवसर का लाभ उठाने के लिए एक सुविचारित कार्यनीति का उल्लेख किया गया है। भारत की तुलना में चीन का उल्लेखनीय निर्यात कार्यनिष्पादन श्रमप्रधान गतिविधियों, विशेष रूप से “नेटवर्क उत्पादों” के संबंध में, सुविचारित व्यापक विशेषज्ञता से प्रेरित है, जहां उत्पादन का कार्य बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा प्रचालित वैश्विक मूल्य-श्रृंखलाओं (जीवीसी) के माध्यम से होता है। नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर असेंबलिंग कार्यों की समर्थकारी व्यवस्था पर बारीकी से फोकस करने की आवश्यकता है। चूंकि भारत जैसे देश के लिए, जहां व्यापार के मोर्चे पर विभिन्न स्वरूपों वाली असुरक्षा की भावना के कारण इस अवसर का लाभ उठाना अत्यधिक कठिन दिखता है, हमारी व्यापारिक नीति में एक समर्थकारी गुण होना अपेक्षित है। वस्तुतः, वर्तमान भय की भावना के उलट, सभी संबद्ध कारकों को नियंत्रित करने वाले सतर्क विश्लेषण से पता चलता है कि भारत ने व्यापारिक करारों द्वारा, साझेदार देशों से, व्यापार अधिशेष के अंतर्गत विनिर्मित उत्पादों के संबंध में 0.7 प्रतिशत वृद्धि प्रतिवर्ष और कुल व्यापार के संबंध में 2.3 प्रतिशत वृद्धि प्रतिवर्ष की दर से लाभ प्राप्त किया है।

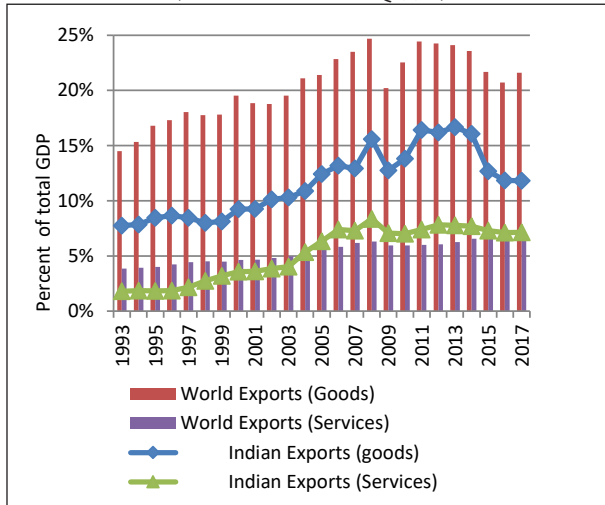
5.1 निर्यातों में वृद्धि भारत में जॉब सृजन के लिए अत्यधिक आवश्यक मार्ग प्रशस्त करती है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2001 से 2006 तक की 5 वर्ष की अवधि में ही, श्रम प्रधान निर्यातों से चीन प्राथमिक शिक्षा के श्रमिकों के लिए 70 मिलियन नौकरियाँ सृजित करने में समर्थ हुआ है (लोस एवं अन्य 2015)। भारत में, बढ़े हुए निर्यातों से यह स्पष्ट होता है कि वर्ष 1999 और 2011 के बीच की अवधि में लगभग 8,00,000 जॉब का अनौपचारिक से औपचारिक में परिवर्तन हुआ है, जो श्रमिक बल के 0.8 प्रतिशत का द्योतक है (अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट, 2019)।

5.2 यूएस-चीन व्यापार संघर्ष के कारण वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में मुख्य समायोजन किया जा रहा है और फर्म अब अपने प्रचालनों के लिए वैकल्पिक स्थानों की तलाश कर रही है। यहां तक कि व्यापार संघर्ष प्रारंभ होने से पहले भी, औद्योगिक उत्पादों की अंतिम असेंबली के लिए निम्न लागव के स्थान के रूप में चीन की छवि श्रम में कमी और मजदूरियों में वृद्धि के कारण तेजी से बदल रही थी। ये घटनाक्रम भारत के समक्ष ऐसी समान निर्यात ट्रेजेक्टरी को प्रगति एवं विकास को सावधानी से और विस्तारपूर्वक जानने का एक अप्रत्याशित अवसर प्रस्तुत करते हैं। जिसका अनुसरण करके चीन

ने अपने युवाओं के लिए असीमित जॉब अवसर सृजित किए। चूंकि अपने श्रमिकों की बाहुल्यता में कोई भी अन्य देश चीन का मुकाबला नहीं कर सकता है, इसलिए, हमको श्रम व्यापी सेक्टरों में रिक्त होने वाले स्थान को हथिया लेना चाहिए। इस अध्याय में इसके लिए एक स्पष्ट रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

5.3 वर्ष 1991 के सुधारों के बाद, व्यापारिक (माल) निर्यातों में भारत की भागीदारी 13.2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से बढ़ी है और यह वर्ष 1991 में 0.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018 में 1.7 प्रतिशत हो गया है। फिर

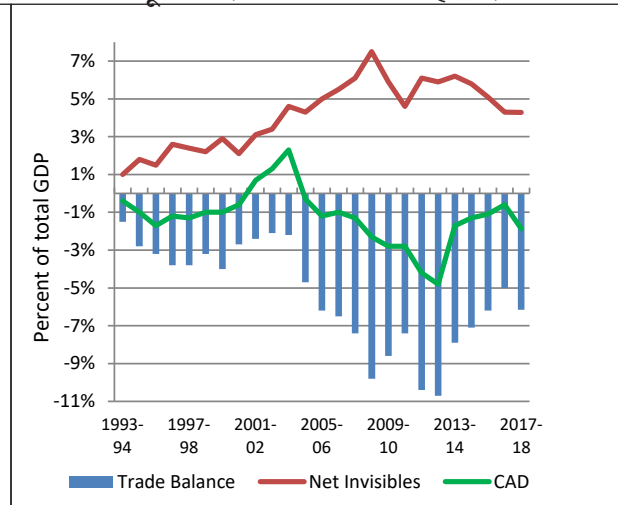
चित्र 1 (क): भारत बनाम विश्व, सकल घरेलू उत्पाद में निर्यातों की हिस्सेदारी



स्रोत: यूएनसीडीएडो सांख्यिकी और समीक्षा परिकलन।

भी, वर्ष 2018 तक भी, भारत की विश्वबाजार में भागीदारी चीन की 12.8 प्रतिशत की भागीदारी की तुलना में नगण्य है। इसके अतिरिक्त, सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यापारिक निर्यात विश्व के औसत की तुलना में भारत के लिए अत्याधिक मात्रा में निरंतर नीचे रहा है (चित्र 1(क))। व्यापारिक आयात निर्यातों की अपेक्षा अधिक तेजी से (वर्ष 1993-2018 के दौरान 14.9 प्रतिशत की दर पर) बढ़ा है, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार घाटा में वृद्धि हो रही है (चित्र 1 (ख))। दूसरी ओर, सेवाओं के निर्यात सामान्यतः आयातों की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़े हैं, जिसके कारण चालू चाता घाटे में कुछ राहत मिली है।

चित्र 1 (ख): भारत बनाम विश्व, सकल घरेलू उत्पाद में निर्यातों की हिस्सेदारी



स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक और सर्वेक्षण परिकलन

5.4 इस संदर्भ में जो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, वे निम्न हैं:- (i) तीव्र निर्यात वृद्धि हासिल करने के लिए किस प्रकार के नीतिगत हस्तक्षेपों से मदद मिलेगी? (ii) क्या नीतियों को विशिष्टीकरण (गहन मार्जिन) अथवा विविधिकरण (व्यापक मार्जिन) के माध्यम से व्यापार वृद्धि के लिए लक्षित किया जाता है? (iii) घरेलू उद्योगों के लिए सबल स्थानीय संपर्कों को बढ़ावा देने के लिए अथवा वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में भागीदारी के लिए जिनमें वैश्विक रूप से फैले होते हैं, क्या यह हमारे हित में हैं? (iv) वे कौन-कौन से उद्योग हैं जिनके पास निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन के लिए सर्वाधिक संभावनाएं हैं? और (v) निर्मुक्त व्यापार करार भारत के लिए लाभकारी हैं?

5.5 इन प्रश्नों पर विचार करते हुए इस अध्याय

में अनवरत और तेजी से निर्यात में वृद्धि और इससे अच्छी आमदनी का कार्य करने के लिए नीति तैयार करने के मार्गदर्शक सिद्धांत दिए गए हैं। भारत को ऐसे औद्योगिक समूहों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें 'नेटवर्क उत्पाद' कहा जाता है, जहां उत्पादन प्रक्रिया वैश्विक रूप से खंडित होती है और अपने 'उत्पादक संचलित' वैश्विक उत्पादन नेटवर्क के भीतर अग्रणी बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा नियंत्रित होती हैं। नेटवर्क उत्पादों के उदाहरण में कंप्यूटर, इलैक्ट्रॉनिक और इलैक्ट्रिकल उपकरण, सड़क के वाहन आदि शामिल होते हैं। चीन के अद्वितीय निर्यात निष्पादन के विपरीत भारत मुख्य रूप से श्रम प्रधान क्षेत्र, विशेष रूप से 'नेटवर्क उत्पादों' में बड़े पैमाने पर अपेक्षित विशेषज्ञता से प्रेरित है, जहां उत्पाद बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा संचालित वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) में होता है। विश्व भर के

लिए चीन में उपकरणों के पुर्जों को आयात करना और इन्हें जोड़ कर (असेंबल कर) उपकरण बनाने का कार्य कर चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर रोजगार सृजित किया है। इसी प्रकार एकीकरण द्वारा मेक इन इंडिया में 'असेंबल इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड' की व्यवस्था शामिल है। इससे भारत अपनी निर्यात बाजार भागीदारी को 2025 तक लगभग 3.5 प्रतिशत और 2030 तक 6 प्रतिशत तक बढ़ा सकता है जो कि पूर्ण रूप से व्यवहार्य है। इस क्रम में भारत 2025 तक अच्छी आमदनी देने वाले लगभग 4 करोड़ और 2030 तक 8 करोड़ रोजगार सृजित करेगा। नेटवर्क उत्पादों के निर्यात, जिसके वर्ष 2025 तक 248 बिलियन डॉलर का होने की आशा है, के लक्ष्य स्तर से अर्थव्यवस्था में सम्मिलित वृद्धिशील मूल्य 2025 तक भारत को \$ 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक वृद्धि का एक-चौथाई हिस्सा होगा।

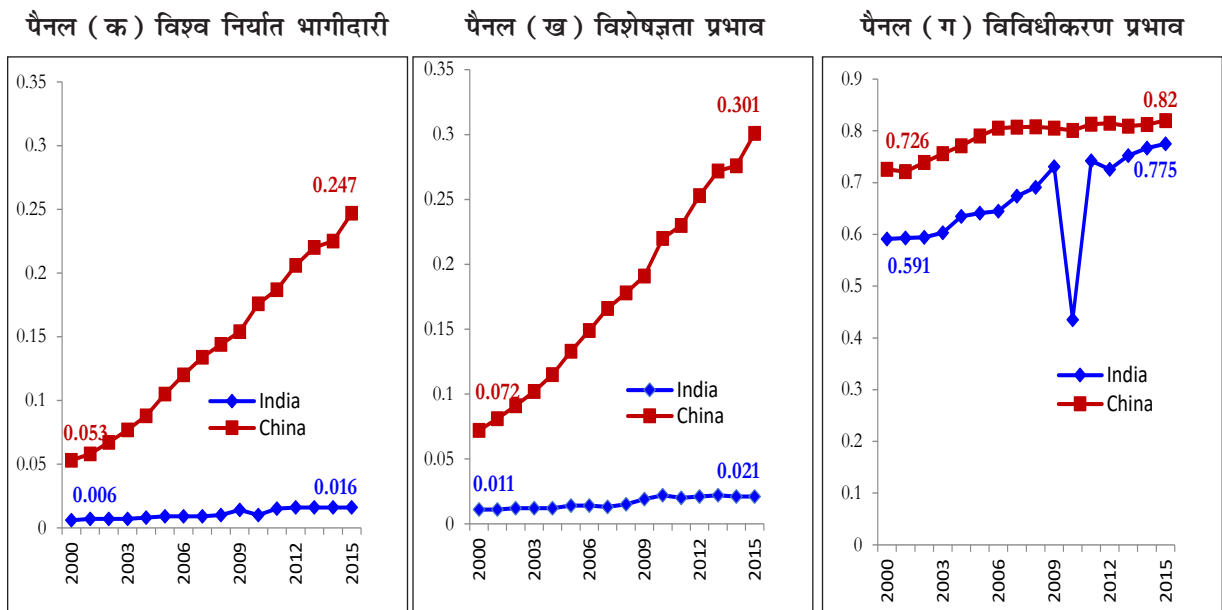
चीन की तुलना में भारत का निर्यात में निम्न-निष्पादन

5.6 निकट भविष्य के लिए नीति तैयार करने से पहले हम चीन की तुलना में भारत का निर्यात में निम्न-निष्पादन करेंगे।

विशेषज्ञता बनाम विविधीकरण

5.7 क्या भारत के निर्यात निष्पादन में फीकापन भारत की निर्यात बास्केट में विविधीकरण की कमी के कारण (अत्यधिक मार्जिन) है या यह विशेषज्ञता की कमी के कारण (गहन मार्जिन) के कारण है। हम इस प्रश्न का जवाब भारत और चीन के इन दो आयामों के आधार पर पाने की कोशिश करेंगे (बाक्स 1 देखें)। प्रत्येक देश के निर्मित उत्पाद का विश्व निर्यात भाग विविधीकरण बनाम संकेंद्रण के प्रभाव में अपघटित हो जाता है (चित्र 2 देखें)। यह देख जा सकता है कि पैनल (क), जो दो देशों के विश्व बाजार भाग को दर्शाता है, पैनल (ख) की मिरर इमेज है जो विशेषज्ञता के योगदान का दर्शाता है। इस प्रकार विश्व बाजार के भाग में चीन-भारत गैप प्रायः विशेषज्ञता प्रभाव से पूर्ण रूप से संचालित होता है। दूसरी ओर उत्पाद और बाजार (पैनल (ग)) के विविधीकरण के रूप में भारत स्पष्ट रूप से लगभग चीन के निकट आ रहा है। समग्र रूप से निम्न विशेषज्ञता के साथ उच्च विविध ीकरण का तात्पर्य यह है कि भारत बहुत से उत्पादों

चित्र 2: विशेषज्ञता और विविधीकरण प्रभाव, 2000 से 2015 तक निर्मित उत्पाद में भारत और चीन के विश्व निर्यात बाजार भाग को अपघटन



स्रोत: यूएन कॉमट्रेड (डब्ल्यूटीटीएस) डाटाबेस के आधार पर बीरामणि, एराथ और गुप्ता (2018)

टिप्पणी: निम्नलिखित, हम्मेल और क्लेनोव (2005), पैनल (क) में भारत और चीन का विश्व बाजार भाग पैनल (ख) में विशेषज्ञ प्रभाव में अपघटन और पैनल (ग) में विविधीकरण। किसी दिए गए देश और वर्ष के लिए विश्व बाजार भाग विशेषज्ञता के संगत मूल्य और विविधीकरण प्रभाव से गुणा कर प्राप्त किया जाता है।

और भागीदारों के संबंध में अपने निर्यात का कम प्रसार करता है जिसका वजह से चीन की तुलना में इसका निष्पादन कम होता है।

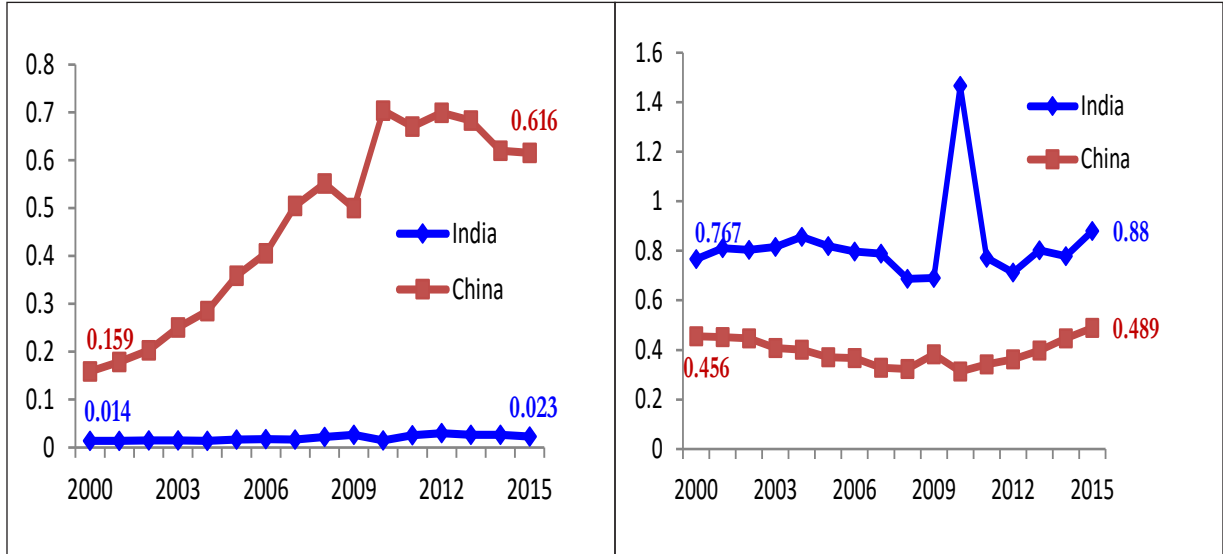
5.8 कई वर्षों की अवधि में विशेषज्ञता प्रभाव निर्यातित माल की मात्रा और/या मूल्य में परिवर्तन के कारण

बदल सकता है। इसलिए, यह विशेष रूप से मात्रा और मूल्य प्रभाव में विशेषज्ञता प्रभाव को विघटित करने के लिए है। चित्र 3 दर्शाता है कि विशेषज्ञता के संदर्भ में भारत-चीन का गैप (अंतराल) मात्रा प्रभाव से पूर्ण रूप से संचालित होता है। निचोड़ की बात यह है कि यदि

चित्र 3: भारत और चीन के संदर्भ में विशेषीकरण प्रभाव का मात्रा और कीमत प्रभावों में विघटन, वर्ष 2000-2015

पैनल (क) मात्रा प्रभाव

पैनल (ख) मूल्य प्रभाव



स्रोत: यूएन-कॉमट्रेड (डब्ल्यू आई टी एस) बेस पर आधारित वीवामणि, एराथ और गुप्ता (2018)

टिप्पणी: हमेल्स और क्लिनो (2005) का अनुसरण करते हुए चित्र 2, पैनल (ख) में, दर्शाए गए विशेषीकरण प्रभाव का विघटन ऊपर पैनल (क) में मात्रा प्रभाव और पैनल (ख) में मूल्य प्रभाव में किया गया है। उल्लिखित देश एवं वर्ष के लिए विशेषीकरण प्रभाव का आकलन मात्रा एवं मूल्य प्रभावों के संगत मूल्यों को गुणा करके किया जाता है।

बॉक्स 1: विशेषीकरण एवं विविधता प्रभावों में विघटन कार्यप्रणाली

अनुसरण हमेल्स और क्लिनो (2005) का अनुसरण करते हुए लक्ष्य ग्रुप D (जिसमें कई साझेदार देश J शामिल हैं) के लिए वर्ष t में उल्लिखित देश! (हमारे मामले में भारत और चीन) का विश्व निर्यात बाजार शेयर का विघटन निम्नानुसार किया जा सकता है। S_{it} लक्ष्य बाजार D में 'विश्व के बाकी देश' के सापेक्ष देश! के निर्यात बाजार में प्रवेश का प्रतीक है।

$$S_{it} = \frac{X_{it}}{X_{rt}} = \frac{\sum_j \sum_{p \in N_{ijt}^p} x_{ijt}^p}{\sum_{j \neq i} \sum_{p \in N_{rjt}^p} x_{rjt}^p}$$

जहां, X_{it} = लक्ष्य D के i से कुल निर्यात का मूल्य; X_{rt} = लक्ष्य ग्रुप D के लिए r से कुल निर्यात मूल्य; x_{ijt}^p = P उत्पाद में i से j के लिए निर्यात मूल्य; N_{ijt}^p = साझेदार-उत्पाद युग्मों का सेट जहां देश! निर्यात संबंधों का रिकार्ड रखता है (अर्थात ऐसा सेट जहां x_{ijt}^p हो) S_{it} को विविधीकरण (व्यापक मार्जिन) और विशेषीकरण किया जा सकता है।

$$S_{it} = \underbrace{\frac{X_{it}}{\sum_{j \neq i} \sum_{p \in N_{ijt}^p} x_{ijt}^p}}_{(1) \text{ Specialization}} \times \underbrace{\frac{\sum_{j \neq i} \sum_{p \in N_{ijt}^p} x_{ijt}^p}{X_{rt}}}_{(2) \text{ Diversification}}$$

उपर्युक्त संख्या (1) हर उन साझेदार-उत्पाद युग्मों में r से कुल निर्यात का माप है जिसमें देश r वर्ष t में निर्यात संबंधों का रिकार्ड रखता है। इसलिए, विशेषीकरण प्रभाव साझेदार-उत्पाद युग्मों के सामान्य सेट में r से कुल निर्यातों से देश i के निर्यातों का अनुपात है। इसका मूल्य हमेशा सकारात्मक होता है अतः यूनियों के ऊपर और नीचे हो सकता है संख्या (2) का हर r से कुल निर्यात को दर्शाता है जबकि अंश उन साझेदार-उत्पाद युग्मों में r के निर्यातों का जोड़ है जिसमें देश i निर्यात संबंधों का रिकार्ड रखता है। इस तरह से विविधीकरण प्रभाव उन साझेदार-उत्पाद युग्मों में r के निर्यातों के भाग का माप है जिसमें देश i सकारात्मक निर्यात मूल्यों की रिपोर्ट देता है। यह देखा जा सकता है कि संख्या (2) का अंश संख्या (1) के हर के बराबर है। जबकि गहन मार्जिन से देश की निर्यात प्रोफाइल की गहराई है और व्यापक मार्जिन में उसकी मात्रा निहित होती है। चूंकि गहन मार्जिन मात्रा एवं मूल्य में परिवर्तन होने के कारण निर्यातों के मूल्य में परिवर्तन को दर्शाता है अतः इसका और विघटन, मूल्य प्रभाव और मात्रा प्रभाव में किया जा सकता है।

$$1M_{it} = P_{it} \times Q_{it}$$

मूल्य प्रभाव r के मूल्यों में से i के कुल भारत अनुपात का माप है, जहां भार साझेदार-उत्पाद युग्मों के सामान्य सेट में i और r के निर्यातों में p उत्पाद के शेयर का लघुगणकीय मान है

$$P_{it} = \prod_{p \in N_{ijt}^p} \left(\frac{uv_{ijt}^p}{uv_{rjt}^p} \right)^{w_{ijt}^p}$$

जहां uv_{ijt}^p और uv_{rjt}^p क्रमशः i और r द्वारा j के लिए निर्यात किए गए उत्पाद p का यूनिट मूल्य (कीमतों के लिए प्रतिपत्र) है और s_{ijt}^p (j के लिए i के निर्यात में उत्पाद p का हिस्सा) और s_{rjt}^p (के लिए r के निर्यातों में p उत्पाद की हिस्सा का लघुगणकीय औसत है। यह कार्यप्रणाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापक साहित्य की रूपरेखा प्रस्तुत करती है (ईवनेट और वेनेबल्स (2002), हमेल्स और क्लिनो (2005), फेलबिर्मeyer और कोहलर (2006) हेल्पमैन एट अल (2008), अमिटी और फ्रेंक (2019), एटन एट अल (2007), बेसेडेस और प्रूसा (2011), वीरामणि, एराथ और गुप्ता (2018)। चित्र 2 और 3 में दिए गए परिणाम वीरामणि, एराथ और गुप्ता (2018) पर आधारित हैं जिन्होंने वर्ष 2000-2015 की अवधि तक 6-अंक स्तर पर विनिर्मित निर्यातों पर डाटा प्रयोग किया है। $x_{ijt}^p > 0$ - होने पर निर्यात संबंध की पहचान की जाती है अर्थात् यदि देश; (भारत अथवा चीन) वर्ष t में उत्पाद P (अर्थात् एच एस 6-अंक स्तर पर) में साझेदार देश j के लिए सकारात्मक निर्यात मूल्य की रिपोर्ट देता है।

वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी का निम्न स्तर पर्याप्त संख्या में श्रमिक होने के बावजूद भारत के गैर-ऑयल व्यापार निर्यातों की हिस्सेदारी में वर्ष 2000 में श्रमव्यापी उद्योगों की हिस्सेदारी में वर्ष 2000 में 30.7% से घटकर वर्ष 2018 में 16.3% करीब हो गया (चित्र 4(क))। भारत की निर्यात प्रणाली में तेजी से बढ़ने वाली वस्तुएं पूंजी एवं कौशलव्यापी हैं। (कोदार एट अल, 2006; पनगरिया, 2007, वीरामणि, 2012, वीरामणि और एराथ, 2020)। वास्तव जी वी सी में भारत की भागीदारी पूर्वी और दक्षिणी एशिया में मुख्य निर्यातक राष्ट्रों की तुलना में कम रही है (अथूकोराला, 2014, वीरामणि एवं धीर, 2017)।

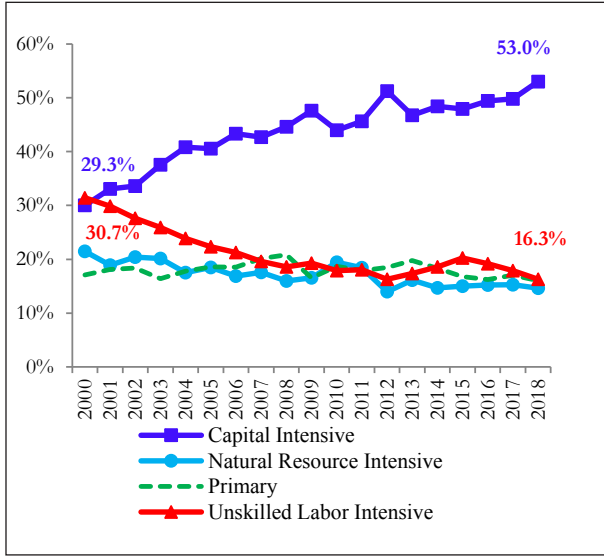
भारत मुख्य निर्यातक बनना चाहता है तो भारत को अपने तुलनात्मक हित के क्षेत्र में अधिकाधिक विशेषज्ञता हासिल करनी होगी और पर्याप्त विस्तार करना होगा।

वैश्विक मूल्य श्रृंखला में भागीदारी का निम्न स्तर

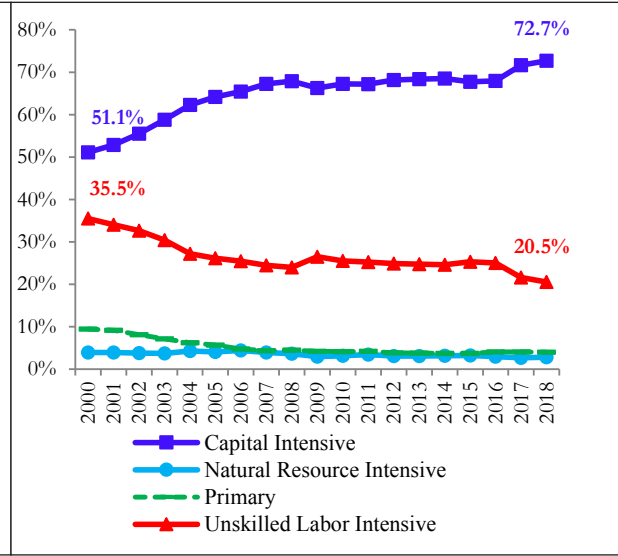
5.9 बड़ी संख्या में श्रमिकों की उपलब्धि के बावजूद, भारत के गैर-तेल व्यापार निर्यात में परम्परागत अकुशल

श्रमिक प्रधान उद्योगों की हिस्सेदारी जो वर्ष 2000 में 30.7 प्रतिशत थी वह वर्ष 2018 में घटकर आधा यानि लगभग 16.3 प्रतिशत रह गई (चित्र 4क)। भारत की निर्यात वस्तुओं में पूंजी और गहन (कोचर एवं अन्य, 2006; पनगढ़िया, 2007, वीरामणि, 2012क, वीरामणि और अन्य, 2020 का भी अवलोकन करें) कौशल दर्ज की गई हैं। वास्तव में, पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया

चित्र 4 (क): भारत के गैर-तेल व्यापारिक निर्यातों का संघटन



चित्र 4 (ख): चीन के गैर-तेल व्यापारिक निर्यातों का संघटन



स्रोत: यूएन-कॉमट्रेड (डब्ल्यू आई टी एस) डाटाबेस और समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: चार श्रेणियों के अंतर्गत व्यापार उत्पादों के वर्गीकरण के संबंध में बाक्स 2 देखें

में जी वी सी में भारत की भागीदारी मुख्य निर्यातक राष्ट्रों की तुलना में, अपेक्षाकृत कम रही (आथुकोराला, 2014; वीरामणि और धीर, 2017; वीरामणि, 2019)।

5.10 इसके विपरीत, चीन का निर्यात संघटन, पूंजी व्यापी उद्योगों (विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक्स और विद्युत मशीनरी में पारंपरिक श्रमिक व्यापी उद्योगों और उत्पादन प्रक्रियाओं के श्रमिक व्यापी अवस्थाओं में अत्यधिक झुकाव को दर्शाता है। कई वर्षों के दौरान इसमें कमी के होते हुए भी अकुशल श्रमिक व्यापी उत्पादन का अनुपात भारत की तुलना में चीन के निर्यात समूह में अधिक है (चित्र 4(ख))। अपने व्यापार उदारीकरण के प्रथम दशक (1980-1990) के दौरान चीन के निर्यात में वृद्धि मुख्यतः अकुशल श्रमिक व्यापी उत्पादों में इसके विशेषीकरण पर आधारित थी; चीन के निर्यात समूह में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 1980 में 27.8 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1990 में 46.5 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर, भारत के निर्यात समूह में अकुशल-श्रमिक व्यापी उत्पादों का

अनुपात वर्ष 2000 से समयपूर्व गिरावट महसूस करने से पहले, वर्ष 1980-2000 की अवधि में लगभग 30 प्रतिशत रहा (वीरामणि, 2012ख)।

5.11 यद्यपि पूंजी व्यापी उत्पादों की चीन के निर्यात समूह में भारत के निर्यात समूह से उच्चतर अनुपात है, फिर भी दो विषम-पैटर्न पर बल देना महत्वपूर्ण है। पहला यह है कि, देश के पारंपरिक अकुशल श्रमिक व्यापी उत्पादों के लगभग दो दशकों (वर्ष 1980-2000) तक, कीर्तिमान-प्रमुख निर्यात वृद्धि के बाद चीन से पूंजी व्यापी उत्पादों के निर्यातों में वर्ष 2000 तक वृद्धि हुई। इसके विपरीत भारत में ऐसी कोई संक्रांति नहीं आई। दूसरा यह है कि, भारत के प्रतिकूल, चीन से पूंजी व्यापी उत्पादों की निर्यात वृद्धि (जी वी सी) में हिस्सेदारी के उच्च स्तर द्वारा हुई है। वर्ष 1990 के दशक तक चीन की निर्यात संवर्धन नीतियां ज्यादातर इसके घरेलू उद्योगों को वैश्विक श्रृंखलाओं के अंतर्गत एकीकृत करने की कार्यनीति पर आश्रित रही हैं।

बाँक्स 2: व्यापार-उत्पादों का घटक संघनता वर्गीकरण

चित्र 4 (क) में सूचित मूल्यों का प्राक्कनल हिनलूपेन और वैनमरेविजिक (2008) द्वारा अनुकूलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र (आईटीसी) के घटक प्रबलता वर्गीकरण का प्रयोग करके किया गया है जो मानक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 अंकीय स्तर पर पांच विस्तृत घटक प्रबलता क्षेत्रों के मध्य अंतर करता है। त्री-अंकीय/3 डिजिट स्तर पर कुल 240 उत्पादों को पांच श्रेणियों

में बांटा गया है:-प्राथमिक (83 उत्पाद), प्राकृतिक संसाधन-प्रधान (21 उत्पाद), अकुशल श्रम-प्रधान (26 उत्पाद), मानव पूंजी-प्रधान (43 उत्पाद), प्रौद्योगिकी-प्रधान (62 उत्पाद), तथा अवर्गीकृत (5 उत्पाद)। विस्तृत वर्गीकरण (<http://www2.ecob.uu.nl/marrewik/eta/intensity.htm>) पर उपलब्ध है। पूंजी-प्रधान श्रेणी में मानव-पूंजी-प्रधान प्लस तकनीकी/टेक्नालजी उत्पाद सम्मिलित हैं।

“रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों” (एसआईटीसी 334) का निर्यात, 4क और 4ख में दिखाए गए चार कारक-प्रधान श्रेणियों में से किसी में भी शामिल नहीं है। ध्यान दें कि, आईटीसी वर्गीकरण के अनुसार, एसआईटीसी-334 “प्राथमिक” श्रेणी का ही एक भाग है। वर्ष 2000 की शुरुआत से ही, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों के कुल व्यापारिक निर्यात में भारत के निर्यात की हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई, जो कि वर्ष 2000 के 3.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018 में 14.6 प्रतिशत हो गई। निर्यात वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2000 3.3 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018 में 14.6 प्रतिशत हो गई। निर्यात वृद्धि मुख्य रूप से भारत की निजी क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों द्वारा संचालित की गई। भारत कच्चे तेल का आयात करता है और इस उद्योग में वैल्यू (मूल्य-निर्माण श्रृंखला) के शोधन चरण में माहिर है। चूंकि पेट्रोलियम शोधन एक अत्यधिक पूंजी-प्रधान प्रक्रिया है, इसलिए इस उत्पाद को प्राथमिक श्रेणी के बजाय पूंजी-प्रधान श्रेणी शामिल करना उचित है (वीरामणि, 2012 ए)। इस प्रकार यदि एसआईटीसी 334 को पूंजी-प्रधान माना जाता है, जो भारत के कुल माल निर्यात में पूंजी-प्रधान उत्पादों का हिस्सा वर्ष 2000 के 31.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2018 में लगभग दोगुना अर्थात 59.9 प्रतिशत हो जाता है। चीन के लिए, यह बहुत फर्क नहीं करता है क्योंकि इसके निर्यात समूह में एसआईटीसी 334 के रूप में एक छोटी सी हिस्सेदारी (लगभग 1 प्रतिशत) है।

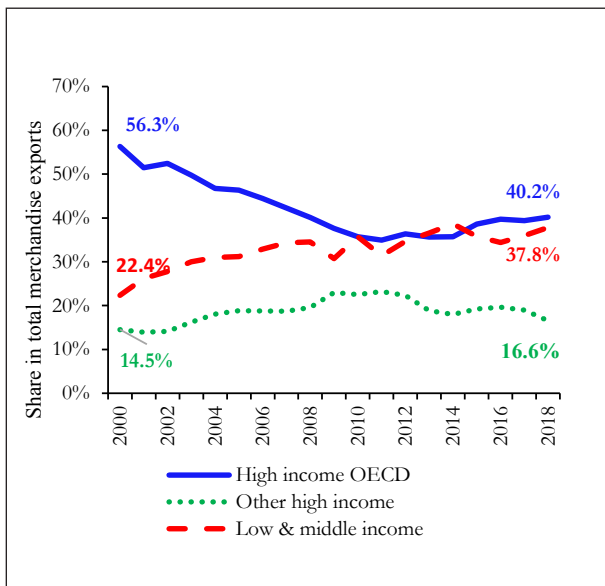
आयातित पुर्जों और अवयवों का प्रयोग करने में, चीन अनेक पूंजी व्यापी उत्पादों के लिए एक प्रमुख असंबली हब के रूप में उभरा है।

उच्च आय देशों में असमान रूप से कम बाजार प्रवेश

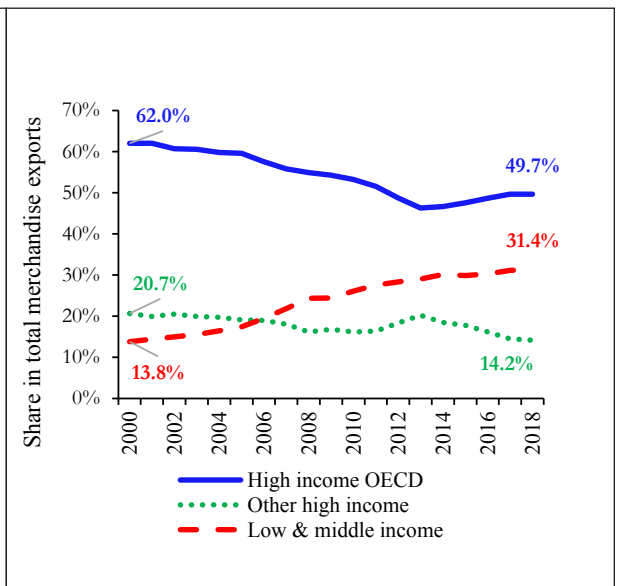
5.12 निर्यात समूह में पूंजी सधन उत्पादों के अधिचत्य

के साथ वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में निम्न स्तर की भागीदारी ने निर्यातों की भारत की भौगोलिक दिशाओं में पारंपरिक अमीर देशों के बाजारों से अन्य गंतव्यों की और असमान रूप से बहलाव हुआ है (बीरमानी, 2012क, वीरमानी और एरथ, 2020)। उच्च-आय ओईसीडी बाजारों में 2018 में चीनी की 49.7 प्रतिशतता रही (चित्र 5 ख) जबकि इसी अवधि के भारत की

चित्र 5(क): आय स्तर के अनुसार व्यापारिक भागीदार, भारत



चित्र 5(ख): आय स्तर के अनुसार व्यापारिक भागीदार, चीन



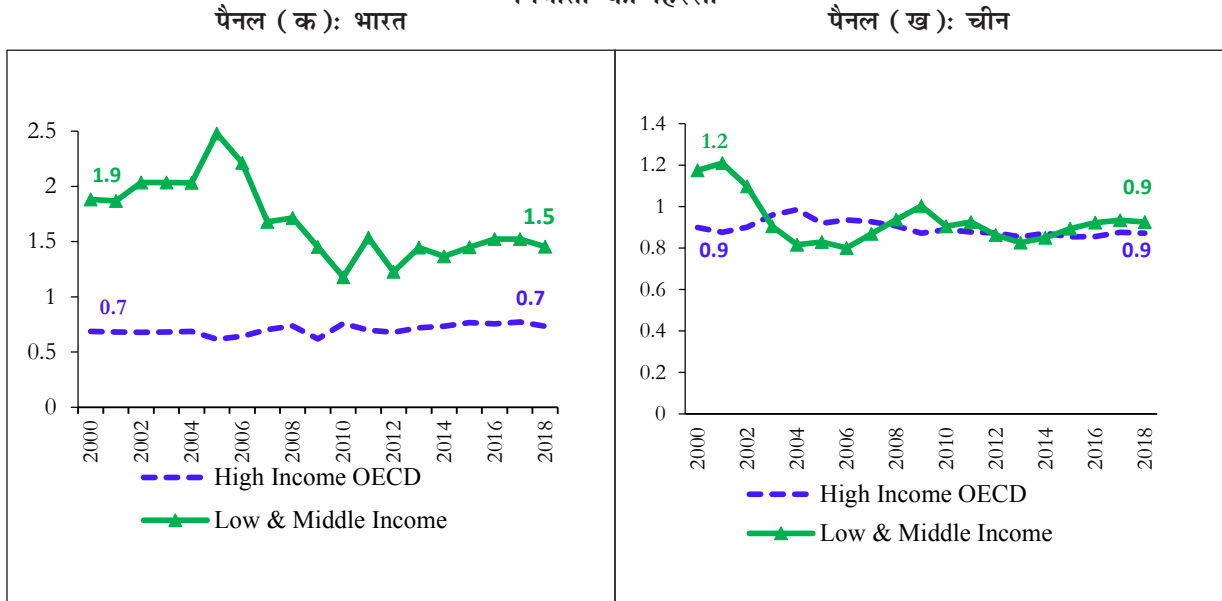
स्रोत: यूएन-कॉमट्रेड (डब्ल्यू आई टी एस)

40.2 प्रतिशत थी (चित्र 5क); इसी प्रकार, उच्च-आय ओईसीडी तथा अन्य उच्च-आय क देशों के चीन का निर्यात 63.9 प्रतिशत रहा जबकि भारत का 56.7 प्रतिशत था।

5.13 उच्च आय वाले देशों के बाजारों में भारत का प्रवेशन स्पष्ट रूप से कम है और हाल के दशकों के दौरान इसमें आनुपातिक अंतर से गिरावट हुई है; इसकी विशेषज्ञता के विकृत पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इस बात को समझना कठिन नहीं है। विकासशील देश,

विशेषकर जीवीसी में कम भागीदारी वाले देश धनी देशों के, गुणवतता/ब्रांड के प्रति जागरूक, बाजारों में अपने पूंजी प्रधान उत्पादों का निर्यात करने में अत्यधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं। पूंजी प्रधान उत्पादों के विपरीत, उच्च आय वाले देश भारत के अकुशल श्रम-प्रधान उत्पादों के लिए सापेक्षिक रूप से एक वृहत्तर बाजार उपलब्ध कराते हैं (चित्र 6, पैनल (क))। वही दूरी ओर, चीनी उत्पाद, चाहे वे पूंजी प्रधान उत्पाद के रूप में ही या अकुशल श्रम-प्रधान उत्पाद के रूप में उच्च आया वाले तथा निम्न मध्यम आय वाले, दोनों

चित्र 6: साझेदार देशों के समूहों में श्रम-प्रधान उत्पादों के हिस्से के अनुपात के रूप में पूंजी प्रधान निर्यातों का हिस्सा



स्रोत: यूएन-कॉमट्रेड (डब्ल्यूआईटीएस) डाटाबेस और सर्वेक्षण-परिकलन

देशों के बाजारों में समान रूप से अपनी पैठ बनाने में सफल होते हैं। (चित्र 6, पैनल (ख))। चीन के संबंध में यह प्रत्याशित भी है क्योंकि क्रेता चाहे कोई भी हो, विश्व बाजारों के लिए यह एक असेंबली सेंअर के रूप में कार्य करता है।

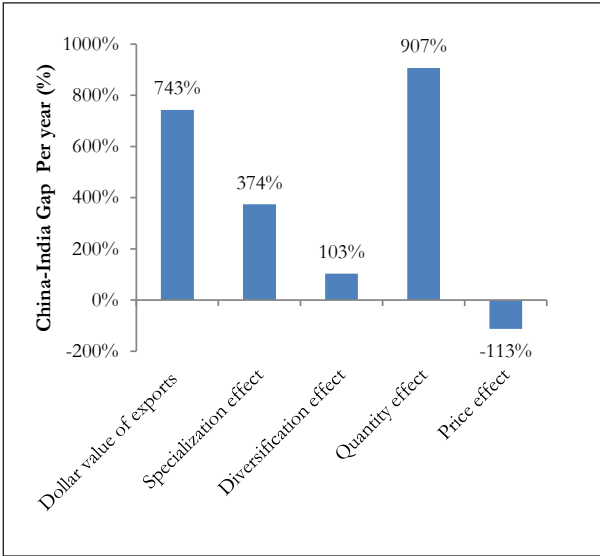
5.14 कुल निर्यातों, विशेषज्ञता प्रभाव, विविधीकरण-प्रभाव, मात्रा-प्रभाव और कीमत-प्रभाव के डॉलर मूल्य के संदर्भ में चीन और भारत के बीच अंतर की सीमा को चित्र 7 (क) में दर्शाया गया है ये प्राक्कलन उस समाक्षयण विश्लेषक से प्राप्त किए जाने हैं जो दो देशों में से प्रत्येक के द्विपक्षीय व्यापार प्रवाहों को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के प्रभावों को नियंत्रित

करता है। वर्ष 2000-2015 के दौरान डॉलर मूल्य में, भारत के मुकाबले चीन का औसत निर्यात लगभग 743 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से, अधिक हुआ है। इस अंतर का अधिकांश भाग विशेषज्ञता और मात्रा-प्रभावों से संबंधित है। तथापि, आश्चर्यजनक रूप से चीन-भारत का यह अंतर तब लगभग पूर्णतः समाप्त हो जाता है जब चीन के उच्च व्यापार अभिविषयास के प्रभाव को धनी व्यापारिक साझेदार के साथ विचार में लिया जाता है (चित्र 7(ख))।

5.15 एक सामान्य अवधारणा यह है कि चीन की निर्यात सफलता में मुख्य तौर पर इसकी विनिमय दर नीति का योगदान है। हालांकि, जैसा कि चित्र 2

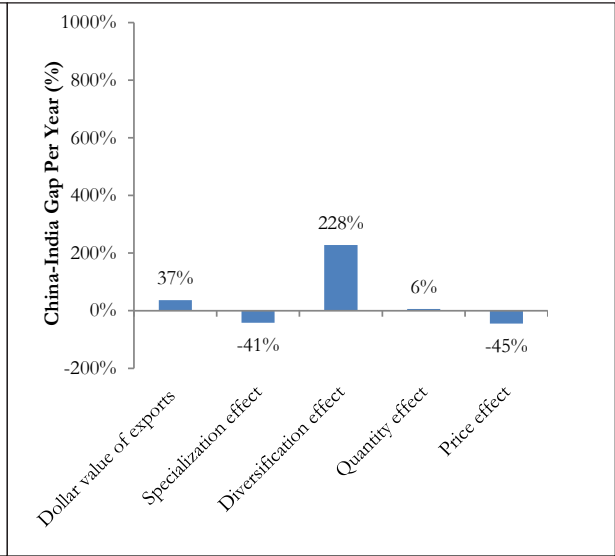
और परवर्ती चित्रों में देखा गया है, भारत के निर्यात कार्य-निष्पादन में गिरावट दो दशक पुरानी उव अवधि से चली आ रही है जब भारत की विनिमय दर में विशेष गिरावट हुई। वास्तव में, बहुभिन्नस्पी समाक्षयण

चित्र: 7 (क) चीन-भारत व्यापार अंतराल का अनुमान (प्रतिशत)



विश्लेषण, जिन्हें लघु समाझकर उपेक्षित कर दिया जाता है, दर्शाते हैं कि विनिमय दर के आधार पर भारत-चीन अंतर की पर्याप्त व्याख्या नहीं की जा सकती। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भारत की तुलना में

चित्र 7 (ख) उच्च आय साझेदार देशों के लिए चीन के निर्यात को नियंत्रित करने के बाद भारत-चीन व्यापार अंतर



स्रोत: वीरामणि, एराथ और गुपता (2018) द्वारा किए गए अध्ययन में समाश्रयण विश्लेषण के परिणामों पर आधारित

नोट: समाश्रयण विश्लेषण वर्ष 2000 से वर्ष 2015 तक की अवधि के भारत-चीन के द्विपक्षीय निर्यात डेटा पर आधारित है। r-अक्ष पर आश्रित चर को रखा गया है। यहां स्वतंत्र चर हैं-सहभागी देशों का वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, व्यापार कहने वाले सहभागियों का वास्तविक प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, वास्तविक द्विपक्षीय विनिमय दर, व्यापार करने वाले सहभागियों से वास्तविक आवब विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, व्यापार करारों के लिए डम्मी वेरिएबल, चीन डम्मी (यदि निर्यातक चीन है तो इसका मान रखा जाता है और यदि निर्यातक भारत है तो इसका मान व रखा जाता है), पार्टनर फिक्सड इफेक्ट और इयर फिक्सड इफेक्ट चीन डम्मी के गुणांक पर भारत-चीन व्यापार अंतराल के अनुमान आधारित हैं।

चीन का उल्लेखनीय निर्यात प्रदर्शन अनेक अंतर्संविंधत कारकों से प्रेरित है जिनमें जीवीसी में उच्चस्तर की भागीदारी, श्रम-प्रधान उत्पादन गतिविधियों में उच्च स्तर की विशेषता, विशेषज्ञता के चयनित क्षेत्रों में व्यापक मान और परंपरागत धनी देशों के बाजारों में उच्च स्तर के निर्यात प्रवेशन का उल्लेख किया जा सकता है।

5.16 संक्षेप में, इसकी विशेषज्ञता बी प्रकृति से प्रेरित होकर भारत ने अपेक्षाकृत कम और मध्यम आय वाले देश के बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त किया है, किंतु ऐसा कुछ समृद्ध देशों। में बहुत बड़े बाजारों के

हिस्सों को खोते हुए किया है यद्यपि भारत उच्च आय वाले बाजारों के साथ अधिक से अधिक व्यापार के संभावित अवसरों का उपयोग करके महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित हो सकता है किंतु इसके लिए हमें अपने ट्रेड-स्पेशलाइजेशन (व्यापारिक विशेषताओं) का पुनरभिमुखीकरण ऐसे उद्योगों की ओर करना होगा जिसमें बड़ी संख्या में श्रामिकों द्वारा उत्पादों का सृजन किया जाता है। ऐसी कार्यसिद्धि निम्नलिखित दोनों क्षेत्रों - (i) पारंपरिक 3 श्रम गहन उद्योग जैसे कि वस्त्र उद्योग, विशेषकर जहां कृत्रिम फाइबर का उत्पादन किया जाता है, (ii) जी.वी.सी. में वर्धित सहभागिता

1 इस बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। भारत के पैसेंजर मोटर वाहन (एस.आई.टी.सी. 7810) जोकि एक पूंजीगत तथा दक्षता-गहन उत्पाद है के निर्यात में वर्ष 2000 से वर्ष 2015 तक बहुत बढ़ोतरी हुई यह 102 मिलियन अमेरिकी डालर से बढ़कर वर्ष 2015 में 5392 मिलिय अमेरिकी डालर हो गया, तभी इसकी वार्षिक वृद्धि दर को 34 प्रतिशत पर रजिस्टर किया गया। वर्ष 2015 में उच्च-आय वाले ओ.ई.सी.डी. देशों में भारतीय पैसेंजर मोटर वाहनों का निर्यात कुल निर्यात का 22 प्रतिशत था जबकि कम और मध्य आय के देशों में यह निर्यात कुल निर्यात का 68 प्रतिशत था। दूसरी ओर भारत के वस्त्र निर्यात (एस.आई.टी.सी. 84) जोकि श्रम गहन उद्योग की श्रेणी में आता है, की वृद्धि बहुत ही कम दर से हुई वर्ष 2000-2015 भी अवधि में प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की दर से। जबकि उच्च-आय वाले ओ.ई.सी.डी. देशों में भारतीय वस्त्रों का निर्यात 64 प्रतिशत तथा कम-मध्य आय वाले देशों में यह निर्यात केवल 12 प्रतिशत था। (वीरामणि और एराथ, 2020)

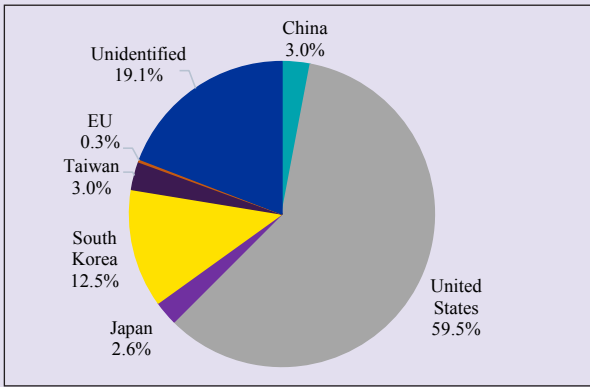
पर ध्यान केंद्रित करके प्राप्त की जा सकती है।

ग्लोबल वेल्यू चेन में भागीदारी से लाभप्राप्त करना।

5.17 क्या देशीय उद्योगों के लिए स्वदेशी स्रोतों से सहायक सामग्री व पण्य अर्था निर्मित माल को प्राप्त करके शक्तिशाली स्थानीय श्रंखला को बढ़ावा दिया जाए अथवा जी.वी.सी. में भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए जिसके स्रोत विश्वभर में फैले हुए हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर कारता है कि उक्त नीतियों में से किस नीति के परिणामों द्वारा देश के व्यापार से होने वाले लाभ में वर्धन होगा तथा देश में रोजगार का सृजन होगा कौन सी नीति करेगी।

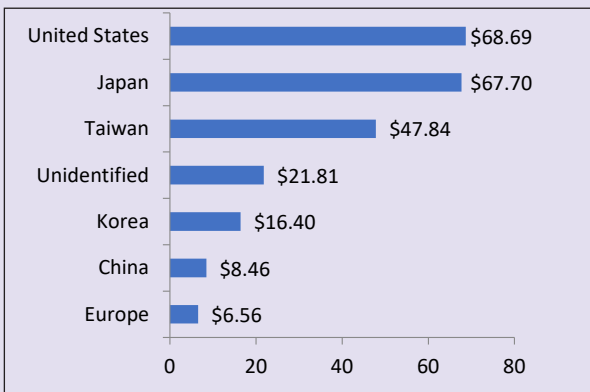
5.18 प्रतिगमन का उपयोग करके बहुचर विश्लेषण से इसकी पुष्टि होती है कि सकल निर्यात के लिए विदेशी विधित मूल्य के क्षेत्रीय अनुपात द्वारा यथा परिमित जी.वी.सी. में सहभागिता सकल निर्यात, घरेलू विधित मूल्य और रोजगार के असीमित स्तरों में वृद्धि का कारण होती हैं (चित्र 9)। यह देखा जा सकता है कि सकल निर्यात के विदेशी विधित मूल्य की हिस्सेदारी में 10 प्रतिशत वृद्धि सकल निर्यात के डॉलर मूल्य में 17.9 प्रतिशत में परिणत होती है [चित्र 9 में पैनल (क)], जो परिणामस्वरूप घरेलू विधित मूल्य (निर्यात से) में 7.7 प्रतिशत तक की वृद्धि का कारण रही है [चित्र 9 में पैनल (ख)]। अंततः घरेलू विधित मूल्य में 7.7 प्रतिशत वृद्धि से रोजगार में 13.2

बॉक्स 3: असेंबली से प्राप्त मुनाफे का उदाहरण: चीन में एप्पल आई. फोन और फोन-7 की असेंबली



एप्पल आई.पॉड में विधित मूल्य का वितरण

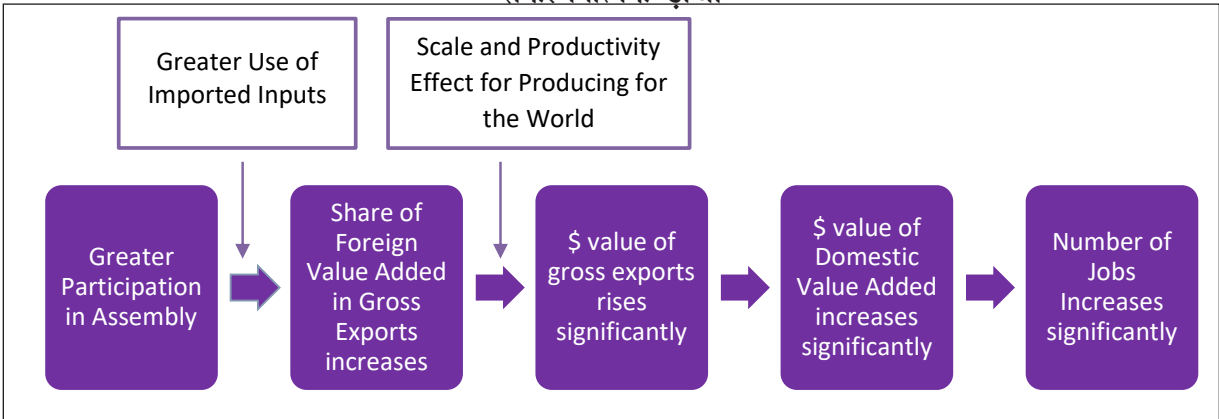
आई-पॉड मूल्य श्रृंखला के भीतर, चीन असेंबली में विशेषज्ञ है जबकि इनके पूजों और घटकों का आयात किया जाता है। असेंबल किए गए एक आई.पॉड की फ़ैक्ट्री-गेट कीमत का 2008 में \$144 आंकलन किया गया था, लेकिन इसके केवल \$114 को चीनी विधित मूल्य में सन्नहित किया गया था (जो फ़ैक्ट्री-गेट कीमत का 3 प्रतिशत है)। हालांकि, चीन ने एप्पल द्वारा बेचे गए लगभग सभी 54.89 मिलियन आई. पॉड्स के असेंबल किया था, जो \$219 मिलियन कुल घरेलू विधित मूल्य का कारण था।



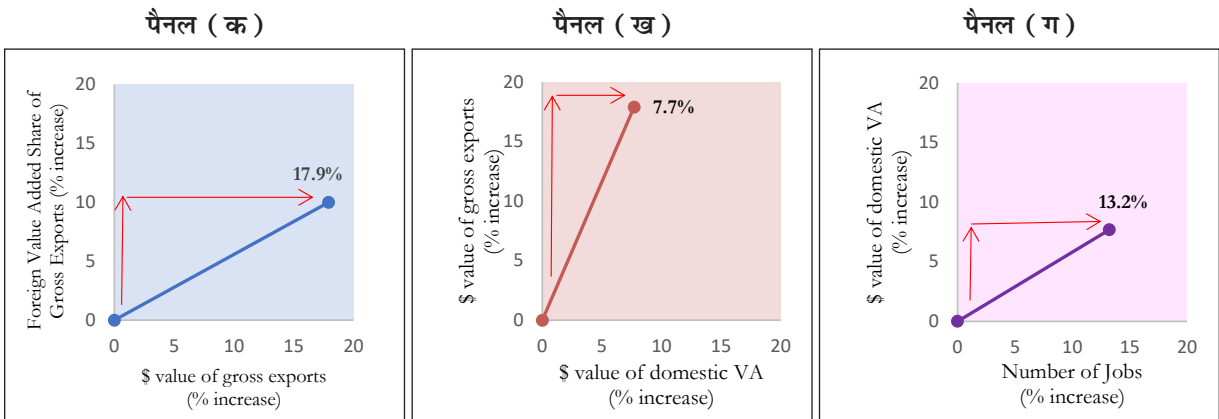
आई. फोन-7 में विधित मूल्य का वितरण

चीन आई. फोन-7 की असेंबली से केवल यू.एस. \$8.46 की प्राप्ति करता है। हालांकि, वह कर कुल विधित मूल्य बहुत बहुत अधिक है (\$8.46 × विश्व में बेचे गए आई. फोन्स की संख्य)। आई पॉड और आई. फोन केवल दो उदाहरण हैं। ऐसे हज़ारों उत्पाद हैं, जहां चीन एक असेंबली सेंटर के रूप में उभरा है।

चित्र 8: “मेक इन इंडिया” के हिस्से के रूप में “असेम्बलींग इन इंडिया” से लाभों के लिए संकल्पनात्मक ढांचा



चित्र 9: भारत के विनिर्माण उद्योगों के लिए जीवीसी के अनुभवजन्य साक्ष्य से भागीदारी से लाभ



स्रोत: वीरमणि और धीर (2019क) और सर्वेक्षण गणना में समाश्रयण विश्लेषण परिणाम के आधार पर

टिप्पणी: चित्र में तीन वाई एक्सिस देखिए बल में प्रतिशत बढ़ोत्तरी के समवर्ती एक्स-एक्सिस वैरिएबल में प्रतिशत बढ़ोत्तरी को दर्शाता है। तीनों ग्राफ एक दुसरे से जुड़े हुए हैं जैसे पैनल (क) का एक्स एक्सिस वैरिएबल पैनल (ख) के वाई एक्सिस के समान है और पैनल (ख) के एक्स एक्सिस का वैरिएबल पैनल (ग) के वाई-एक्सिस के समान है। यहां पर बताया गया अनुमान एक साथ समीकरण मॉडल (3 एसएलएस समाश्रयण विश्लेषण) के आधार पर है और 1999-2000 से 2012-13 की अवधि के दौरान 56 भारतीय विनिर्माण उद्योग के पैनल डाटा सेट पर आधारित है। समाश्रयण विश्लेषण के विनिर्देशन में नियंत्रित वैरिएबल का पूर्ण सेट, जिसमें उद्योग और वर्ष का निश्चित प्रभाव शामिल है।

प्रतिशत की वृद्धि हुई। ये संबंध नियंत्रण परिवर्तियों के पूरे सेट के यथा विभिन्न मॉडल के विनिर्देशों तक सृद्ध हैं। इसकी आधार रेखा यह है कि भारत जी.वीसी. में प्रचुर लाभांश की सहभागिता को सृद्ध करने के लिए लक्ष्य से निर्मित नीतियों को अंगीकृत करके इनसे लाभ प्राप्त कर सकता है।

रोजगार के सृजन हेतु कौन से उद्योगों में भारत को विशिष्टता प्राप्त करनी चाहिए?

5.19 किन उद्योगों पर भारत का ध्यान केंद्रित करना

चाहिए? श्रम-गहन गतिविधियों में हमारे तुलनात्मक लाभ और बढ़ती श्रम शक्ति के लिए रोजगार सृजन की अनिवार्यता को देखते हुए उद्योगों के दो समूह हैं जो निर्यात वृद्धि और रोजगार सृजन की सबसे बड़ी संभावना रखते हैं।

5.20 सर्वप्रथम भारत के पारंपरिक अकुशल श्रमसाध्य उद्योगों, जैसाकि कपड़ा, वस्त्र, फूटवीयर और खिलौना में पर्याप्त अप्रयुक्त निर्यात संभावनाएं मौजूद हैं (वीरमानी एवं धीर, 2016)। इन उद्योगों में जीवीसी

का संचालन “क्रोता संचालित” नेटवर्क द्वारा होता है जिनमें विकसित देशों में स्थित अग्रणी कम्पनियां अधिक मूल्यवर्धन वाले कार्यों, जैसे डिजाइन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ज्यादा ध्यान देती हैं। विकासशील देशों में कम्पनियों द्वारा उप-संविदा व्यवस्थाओं के माध्यम से वास्तविक उत्पादन किए जाते हैं। ऐसे उदाहरणों में वालमार्ट, नाइक, ऐडीदास आदि की उत्पादन श्रृंखलाएं शामिल हैं।

5.21 दूसरा, भारत अनेक उत्पादों जिन्हें “नेटवर्क उत्पाद” के रूप में जाना जाता है, फाइनल असेम्बली के लिए एक बड़े हब के रूप में उभरने की भारी संभावनाएं हैं (आथुकोराला, 2014, वीरामणि एवं धीर, 2017)। इन उद्योगों में जीवीसी पर नियंत्रण “उत्पादक संचालित” नेटवर्कों के अंतर्गत अग्रणी एमएनई जैसेकि एपल, सैमसंग, सोनी आदि का होता है। सामान्यतः इन उत्पादों का उत्पादन किसी निर्दिष्ट देश के भीतर शुरु से अंत तक नहीं किया जाता है, बल्कि देश किसी विशेष कार्य या सामान के उत्पादन श्रृंखला के चरणों

के विशेषज्ञ होते हैं। उत्पादन नेटवर्क के अंतर्गत प्रत्येक देश उत्पादन प्रक्रिया के एक विशेष हिस्से का विशेषज्ञ होता है, यह विशेषज्ञता उस देश के तुलनात्मक लाभ पर आधारित होती है। श्रमिक बहुलता वाले देश जैसे चीन उत्पादन के कम कुशल श्रमसाध्य प्रक्रियाओं जैसे असेम्बल करने के विशेषज्ञ होते हैं जबकि धनी देश पंजीकृत एवं कौशलसाध्य प्रक्रियाओं जैसेकि अनुसंधान एवं डिजाइन के विशेषज्ञ होते हैं। इस प्रकार अग्रणी कम्पनियां अधिक आय वाले मुख्यालयों (जैसे यू.एस.ए., ई.यू. और जापान) में कौशल एवं ज्ञानसाध्य कार्यों को रखती है जबकि असेम्बली से संबंधित कार्य कम आय वाले देशों (जैसे चीन एवं वियतनाम) में रखती हैं। इस अध्याय में शेष चर्चा एनपी में भारत की विकास संभावनाओं पर की गई है।

5.22 आथुकोरला (2011) ने मानक अंतर-राष्ट्रीय व्यापार वर्गीकरण (एसआईटीसी) नामावली पर आधारित एनपी के छः समूहों की पहचान की है जहां वैश्विक उत्पादन साझेदारी सबसे अधिक प्रचलित है (तालिका

तालिका 1: नेटवर्क उत्पादों का वैश्विक निर्यात, 2018

एसआईटीसी कोड	एसआईटीसी का विवरण	वैश्विक निर्यात, 2018 (ट्रिलियन यूएस डॉलर)	कुल वैश्विक निर्यात में हिस्सेदारी, 2018
75	कार्यालय मशीन एवं ऑटोमेटिक डाटा प्रोसेसिंग	0.83	4.37
76	दूरसंचार एवं ध्वनि रिकॉर्डिंग उपकरण	0.65	3.42
77	बिजली मशीन	1.97	10.44
78	सड़क	1.55	8.23
87	पेशेवर एवं वैज्ञानिक उपकरण	0.48	2.53
88	फोटोग्राफिक उपकरण	0.12	0.66
कुल नेटवर्क उत्पाद		5.59	29.6

स्रोत: यूएन कॉमट्रेड (डब्ल्यूआईटीएस) डाटाबेस।

टिप्पणी: 2018 में सभी देशों द्वारा दिए गए आयात डाटा के आधार पर

1)। इसके साथ ही, 2018 में विश्व निर्यात में लगभग 30% एनपी की हिस्सेदारी होती है जिनमें इलेक्ट्रिकल मशीनों (एसआईटीसी 77) 10.4% के साथ सबसे आगे था। विपूजन एवं यूएन-ब्रॉड इकोनॉमिक कोटि की प्रणाली के एक विस्तृत स्तर पर व्यापारिक आकड़ों का उपयोग करके इन एनपी को दो मुख्य उप-कोटियों

पार्ट्स एवं कम्पोनेंट (पी एण्ड सी) और असेम्बल एवं प्रोडक्ट्स (एईपी) में कुल व्यापार को विभाजित करना संभव है।

नेटवर्क उत्पादों का विश्व निर्यात: प्रवृत्ति एवं स्वरूप

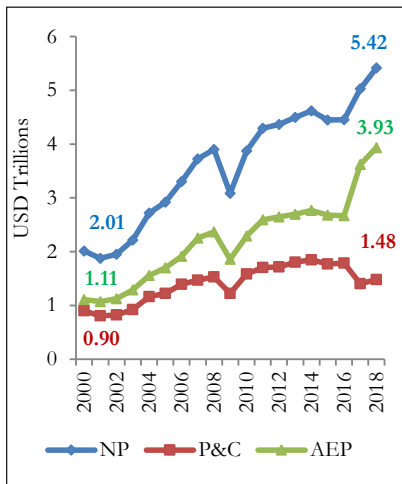
5.23 एन पी का विश्व निर्यात धीरे धीरे वर्ष 2000

के 2.01 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ते हुए वर्ष 2018 में 5.41 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चित्र 10क)। यह वृद्धि मुख्यतः: एईपी द्वारा नियंत्रित हुई जिसका मूल्य 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर से 3.93

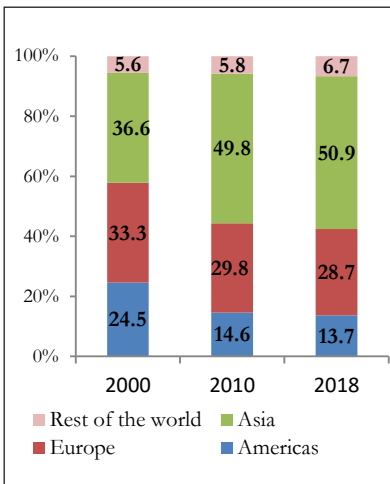
ट्रिलियन यूएस डॉलर हो गया। औसतन, विश्व विनिर्माण निर्यात में एनपी का हिस्सा लगभग 42 प्रतिशत होता है। कुल एनपी निर्यात में एईपी निर्यात का औसत हिस्सा 2000-2016 के दौरान लगभग 59% से बढ़कर पिछले

चित्र 10: वर्ष 2000-18 के नेटवर्क उत्पाद निर्यात की प्रवृत्तियां एवं भौगोलिक वितरण

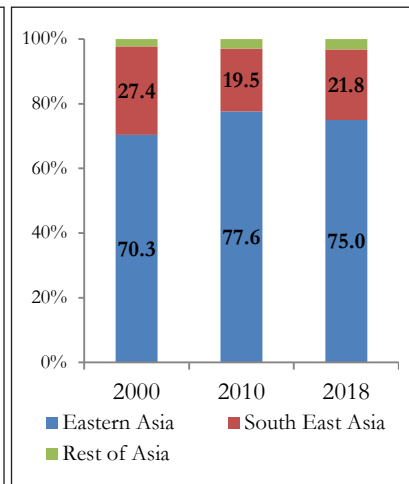
चित्र 10(क): विश्व निर्यात में रूक्षान



चित्र 10(ख): एन पी विश्व निर्यातों का भौगोलिक वितरण



चित्र 10(ग): एशियाई एन पी निर्यातों का वितरण



स्रोत: यूएन कामट्रेड (डब्ल्यू आई टी एल) डाटाबेस एवं सर्वेक्षण परिकल्पना

टिप्पणी: एन पी का अर्थ नेटवर्क उत्पाद, पी एण्ड सी एवं ए ई पी को क्रमशः पार्ट्स एवं संघटकों तथा एसेंबल किए गए तैयार उत्पादों के लिए नेटवर्क उत्पादों के समूह में लिखा जाता है। प्राक्कलन, वर्ष 2000-2018 के बीच प्रतिवर्ष के दौरान 118 देशों के निश्चित समूह के लिए ट्रेडिंग द्वारा (रिपोर्टिड आयात) मिरर सांख्यिकी पर आधारित हैं। वर्ष 2018 में इन 118 देशों का एनपी में कुल वैश्विक व्यापार में 96.8 प्रतिशत हिस्सा है।

दो वर्षों (2017-2018) के दौरान लगभग 72% हो गया। एनपी के वैश्विक निर्यात में एशिया की हिस्सेदारी 2000 के लगभग 37 प्रतिशत से असाधारण रूप से बढ़कर 2018 में लगभग 51 प्रतिशत हो गया जबकि यूरोप एवं अमेरिका दोनों की हिस्सेदारी घट गई (चित्र 10(ख))। कुल एशियाई निर्यात में इस एशिया की हिस्सेदारी थी जिसके बाद दक्षिण-पूर्व एशिया सबसे अधिक थी (चित्र 10 (ग))। कुल एशियाई निर्यात में शेष एशिया की हिस्सेदारी (दक्षिण मध्य और एशिया सहित) मात्र 3 प्रतिशत थी।

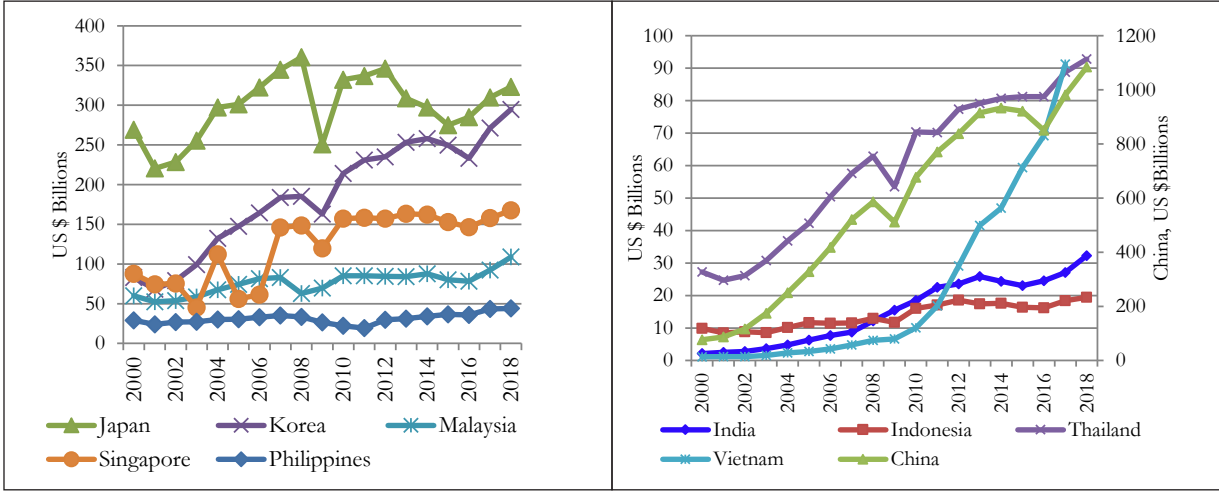
पूर्वी एवं दक्षिणी पश्चिमी एशिया की तुलना में भारत

5.24 जहां तक कि वर्ष 2000 के लगभग 2 बिलियन यू एस डॉलर के एनपी का आयात बढ़कर वर्ष 2018 में 32 बिलियन यू एस डॉलर हो गया परन्तु इस बाजार

इसकी सहभागिता अन्य एशिया देशों की तुलना में कम रही (चित्र 11)। कुल राष्ट्रीय व्यापार में प्रत्येक देश के एन पी उत्पादों का शेयर चित्र 12(क) में दर्शाया गया है। यह स्पष्ट है कि थोड़ी वृद्धि के बावजूद भारत की निर्यात बास्केट में एन पी उत्पादों का शेयर बहुत कम है (2018 में 10%) इसके विपरीत चीन जापान एवं कोरिया के कुल राष्ट्रीय उत्पादों इनका शेयर लगभग आधा है। वर्ष 2000 एवं 2018 के बीच निर्यात बास्केट में एन पी का शेयर वियतनाम के लिए 41% बिंदु एवं चीन के लिए 18% बिंदु बढ़ा है।

5.25 प्रमुख एशियन देशों के बीच भारत एवं इण्डोनेशिया ही वे देश हैं जिनका एन पी में व्यापार घाटा है। (चित्र 12(ख) वर्ष 2017 में भारतीय का आयात मूल्य 68 बिलियन यू एस डॉलर है जो कि थाईलैंड (61 बिलियन यू एस डॉलर) एवं फिलिपिंस (39 बिलियन यू एस

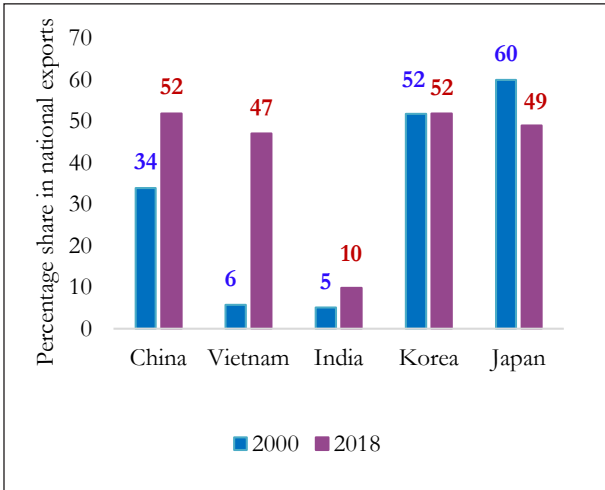
चित्र 11: वर्ष 2000 से 2018, एशियन देशों के एन पी का निर्यात, यू एस डी बिलियन डॉलर में
पैनल (क) नव प्रवेशी **पैनल (ख) विलंब से प्रवेश करने वाले और**
पीछे रहने वाले



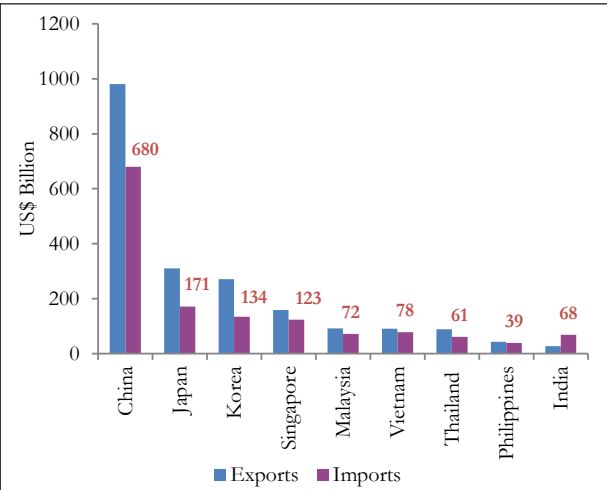
स्रोत: यू एन कामट्रेड (डब्ल्यू आई टी एस) डाटाबेस एवं सर्वेक्षण परिकलन

टिप्पणी: चीन के निर्यात का मूल्य पैनल (ख) में सैकेन्डरी अक्ष पर है। प्राक्कलन प्रत्येक देश द्वारा भेजे गए निर्यात डाटा पर आधारित है। वियतनाम ने वर्ष 2018 के लिए डाटा नहीं भेजा है।

चित्र 12 (क) भारत की निर्यात बास्केट में एन पी का शेयर बहुत कम है



चित्र 12(ख) प्रमुख एशियन देशों में भारत ही वह देश है जिसका एन पी में व्यापार घाटा है



स्रोत: यू एन कामट्रेड (डब्ल्यू आई टी एस) डाटाबेस एवं सर्वेक्षण परिकलन

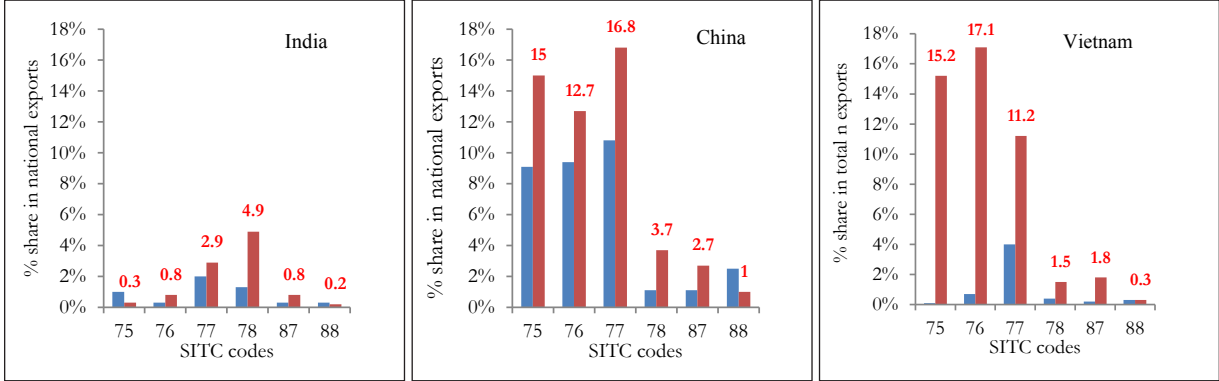
डॉलर) से अधिक है, जबकि बाद वाले दोनों देशों ने निर्यात के क्षेत्र में भारत से काफी अधिक वृद्धि दर्ज की है। भारत की आयात बास्केट में अधिकांशतः इलेक्ट्रॉनिक्स एवं विद्युत मशीनरी होती है, जो मुख्यतः घरेलू अंतिम प्रयोग के लिए बनी होती है (तिवारी और वीरामणि, 2016)।

5.26 भारत के एन पी निर्यातों के उत्पाद समूह संघटक में चार उत्पाद समूहों के प्रतिशत शेयर में वर्ष 2000 की तुलना में वर्ष 2018 में वृद्धि दर्ज की गई है (चित्र 13)। ये हैं: सड़क वाहन (एस आई टी सी 78), विद्युत मशीनरी (एस आई टी सी 77), दूर संचार एवं ध्वनि रिकार्डिंग उपस्कर (एस आई टी सी 76) एवं व्यावसायिक एवं वैज्ञानिक उपस्कर (एस आई टी सी

87) भारत से निर्यात किए गए एन पी उत्पादों की मुख्य श्रेणी सड़क वाहन है जिसमें वर्ष 2018 के कुल

निर्यात में 4.9% की वृद्धि दर्ज हुई है (2000 में 1.3% से) इसके विपरीत, विद्युत मशीनरी, जिसमें चीन की

चित्र 13: राष्ट्रीय निर्यात बास्केट में एन पी उप श्रेणियों का शेयर



स्रोत: यू एन कामट्रेड (डब्ल्यू आई टी एस) डाटाबेस एवं सर्वेक्षण प्राक्कलन

टिप्पणी: एस आई टी सी कोड की व्याख्या: कार्यालय मशीन एवं स्वचालित डाटा प्रोसेसिंग मशीन (एस आई टी सी 75); दूर संचार एवं ध्वनि रिकार्डिंग (एस आई टी सी 76); विद्युत मशीनरी (एस आई टी सी 77); सड़क वाहन (एस आई टी सी 78), व्यवसायिक एवं वैज्ञानिक उपस्कर (एस आई टी सी 87); फोटोग्राफक उपकरण (एस आई टी सी 88)

निर्यात बास्केट (16.8%) एवं कोरिया (30.5%) का सबसे बड़ा शेयर है जो कि भारत के कुल निर्यात के 3% से भी कम है। विद्युत मशीनरी के अलावा, अन्य दो उप-श्रेणियां, जिनमें भारत महत्वपूर्ण निर्यात वृद्धि कर सकता है, वे हैं: (i) कार्यालय मशीन एवं स्वचालित डाटा प्रक्रमण मशीन (एस आई टी एस 75) एवं (ii) दूर संचार एवं ध्वनि रिकार्डिंग (एस आई टी सी 76)

5.27 अनेक अग्रणी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भारत में एसेंबली संयंत्र स्थापित किए हैं तथा उनमें से कुछेक ने अपने उत्पादन नेटवर्क के अंदर भारत को निर्यात बेस के रूप में आरंभ करना शुरू कर दिया है (बॉक्स 4 में चर्चा देखें) वर्ष 2000 की शुरुआत से एसेंबल की गई कारों का भारत से निर्यात (पूर्णतः बिल्ट यूनिट में ऑटोमोबाइल पार्ट्स की तुलना में अधिक गति से वृद्धि हुई है। (आथुकोराला एवं वीरामणि, 2019)। मोबाइल

बॉक्स 4: भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग जी वी सी में एकीकरण से सीख

सन् 1981 में भारत सरकार ने मारुति उद्योग लि० (एम यू एल) की स्थापना के बाद, एम यू एल ने सन् 1982 में सुजुकी मोटर कंपनी लि० से लाइसेंस एवं संयुक्त उद्यम करार किया। नवीनतम प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन व्यवहारों की व्यवस्था करने के बदले में सुजुकी ने 26% स्टैक अर्जित किया। कंपनी ने जापान में पूरी तरह से एसेंबल की गई कारों के आयात से अपना प्रचालक प्रारंभ किया, इसके बाद पहले सुजुका द्वारा भेजे गए सेमी-नॉकड (एसकेडी) तथा इसके बाद पूर्णतः नॉक डाउन (सीकेडी) की एसेंबली की प्रारंभिक चरण में, भारत में कारों की एसेंबली में फीटिंग निम्न प्रौद्योगिकी एवं निम्न मूल्य वाले संघटक एवं उपस्कर आयात की गई कर (हमागुची, 1982) में लगाए। वर्ष 1985-89 के दौरान ऑटो संघटकों का आयात मूल्य तेजी से गिर गया (डि-कोस्टा, 1995)। जापान से भारत में होने वाले ऑटो पार्ट्स का आयात 1980 के 4 मिलियन यू एस डालर से बढ़कर 1986 में 155 मिलियन यूएस डॉलर हो गया है, जो कि भारत के कुल ऑटो पार्ट्स आयात का 77% है। यद्यपि घरेलू ऑटो सहायक उद्योग के विकसित होने से ऑटो पार्ट्स के आयात में सन् 1980 से तेजी से कमी आई है। इसी बीच, सुजुकी संचालित संयुक्त उद्यम में बपने इक्विटी को 1987 में 26% से बढ़कर 40%, 1992 में 50% एवं 2013 में 56.21% करके सफलता अर्जित की है। भारत सरकार ने वर्ष 2007 में अपने शेष 18% शेयर बेच दिए।

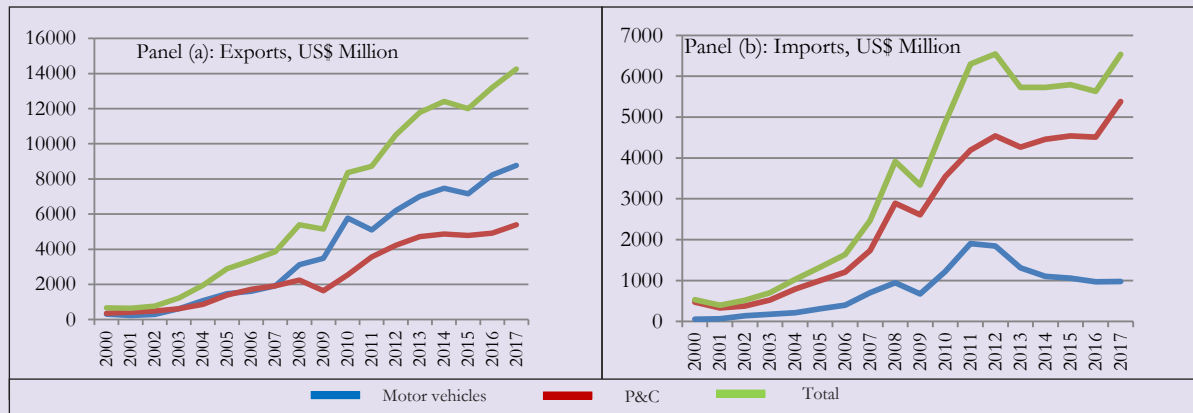
सुजुकी के प्रवेश के बाद, अन्य जापानी ऑटोमोबाइल विनिर्माता टोयटा, मितसुबिसी, निशान एवं मजदा भारत में आए (आथुकोराला

एवं वीरामणि 2019) अनेक टायर ऑटोमोबाइल पार्ट आपूर्तिकर्ता (जैसा डेनसो, आइसिन, सेकी एवं टोयटा बोशुकू) एवं वैश्विक ऑटोमोबाइल पार्ट्स उत्पादक पहुंच गए। देश में 100% सब्सिडटी स्थापित करने वाले पहली ऑटोमोबाइल एनई हुंडई थी। वोल्सवैगन निशान, बीएमडब्ल्यू एवं सुजु मोटर्स ने सूट का अनुकरण किया। पहले संयुक्त उद्यम करने वाली कंपनियां जैसे होण्डा, फोर्ड फिएट एवं रेनोल्ट ने अन्य स्थानीय पार्टर्स के साथ संपर्क स्थापित किए तभी 100% सब्सिडटी स्थापित की।

वर्ष 2000 की शुरुआत से भारतीय आटोमोबाल उद्योग घरेलू बाजार के लिए किए जान वाले उत्पादन से उल्लेखनीय परिवर्तन हुए है। जो कि वैश्विक एकीकरण के लिए आधी सदी तक कार्यप्रणाली बनी रही। देश कपैक्ट कारों के लिए प्रमुख एसेंबली केंद्र बनकर उभरा है। (आथुकोराला एवं वीरामणि, 2019) भारत का पूर्णतः तैयार कारों का निर्यात वर्ष 2001 के 225 मिलियन यूएस डालर से बढ़कर वर्ष 2017 में 8.8 बिलियन यूएस डालर हो गया, जबकि पार्ट्स एवं सहायक पुर्जों का निर्यात दो वर्षों की अवधि के बीच 408 मिलियन यूएस डॉलर से 5.5 बिलियन यूएस डालर रहा। (चित्र में पैनेल (क) देखें) आयात साइड का पैटर्न पार्ट्स एवं सहायक पुर्जों बिल्कुल अलग है जिसमें इस अवधि के दौरान एसेंबल किए गए वाहनों की तुलना में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2017 में, एसेंबल पार्ट्स का आयात पार्ट्स एवं सहायक पुर्जों के 5.4 बिलियन यूएस डालर के आयात की तुलना में 1 बिलियन यू एस डॉलर कम रहा। जबकि एसेंबल किए गए मोटर वाहन का भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात का बहुत बड़ा शेयर है, पार्ट्स एवं सहायक पुर्जों का कुल ऑटोमोबाइल आयात में बड़ा शेयर है।

भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र के मामला अध्ययन से यह महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि घरेलू फर्म महत्वपूर्ण खरीद मिलती है कि घरेलू फर्म पहले निम्न प्रौद्योगिकी से प्रारंभ कर के उत्पादन मूल्य चैन को आगे बढ़ाती है जैसे एसेंबली तथा उसके बाद विनिर्माण एवं संघटकों का कार्य करती है। प्रक्रिया के दौरान संघटकों के आयात में बहुत कम में वृद्धि होगी। आउटसैट से प्रारंभ करके आयात के प्रतिस्थापन की नीति को अपनाने से उत्पादक मूल्य चैन तक के प्रोसेस को पूरा नहीं किया जा सकता।

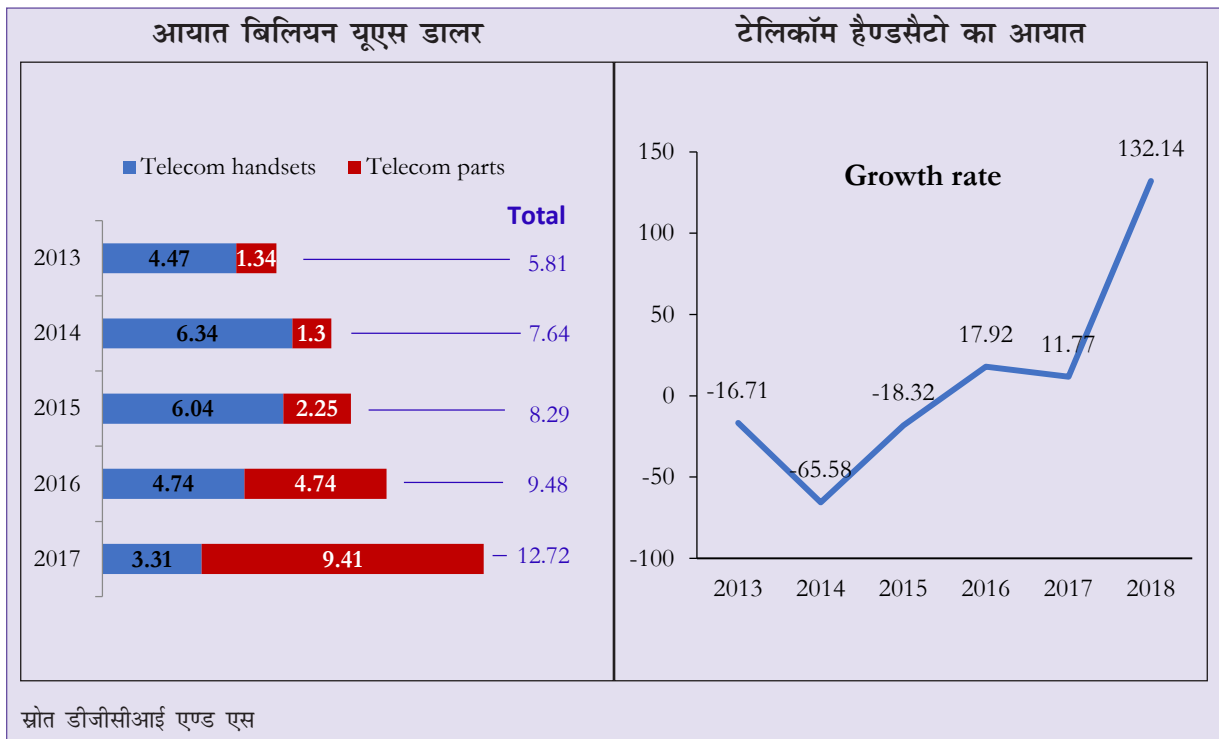
मोटर वाहनों की तुलना में पार्ट्स एवं संघटकों का निर्यात एवं आयात (वीएण्डसी)



स्रोत: यू एन कामट्रेड (डब्ल्यू आई टी एस) डाटा बेस।

बॉक्स 5: भारत में मोबाइल फोन की एसेंबली

भारत ने वर्ष 2018 में वियतनाम को पछाड़ कर चीन के बाद मोबाइल फोन के दूसरे सबसे बड़ा विनिर्माता बन गया है, इसके पास विश्व का 11% शेयर है। भारत 2025 तक विभिन्न खण्डों में लगभग 1.25 बिलियन हैण्डसैट का निर्माण कोगस इससे यह उद्योग लगभग 230 बिलियन यूएस डालर का हो जाएगा। (आईसीईए-मैककिनसे रिपोर्ट, 2018) वर्ष 2013 से 2017 के बीच, जब भारत के टेलिकॉम हैण्डसैट का आयात 4.47 बिलियन यूएस डालर से गिरकर 3.31 बिलियन यूएस डालर रह गया जबकि टेलिकॉम पार्ट्स का 1.34 बिलियन यूएस डालर से बढ़कर 9.41 बिलियन यूएस डालर हो गया। इसी अवधि में टेलिकॉम हैण्डसैट की आयात में पिछले तीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई। टेलिकॉम हैण्डसैट के एसेंबली केंद्र के रूप में भारत की उपस्थिति इस पैटर्न से सुसंगत है।



फोन एसेंबली का मामला भारत की सफलता की कहानी हलही की दूसरी सफलता है। (बॉक्स 5 देखें) ऑटो उद्योग के विपरीत, ऐसी एम एन सी, जिन्होंने भारत के इलेक्ट्रॉनिक एवं विद्युत वस्तु उद्योग में उत्पाद बेस स्थापित किए हैं, मुख्यतः घरेलू बाजार के लिए उत्पादन करती हैं (आथुकोराला, 2014, तिवारी एवं वीरामणि, 2016)।

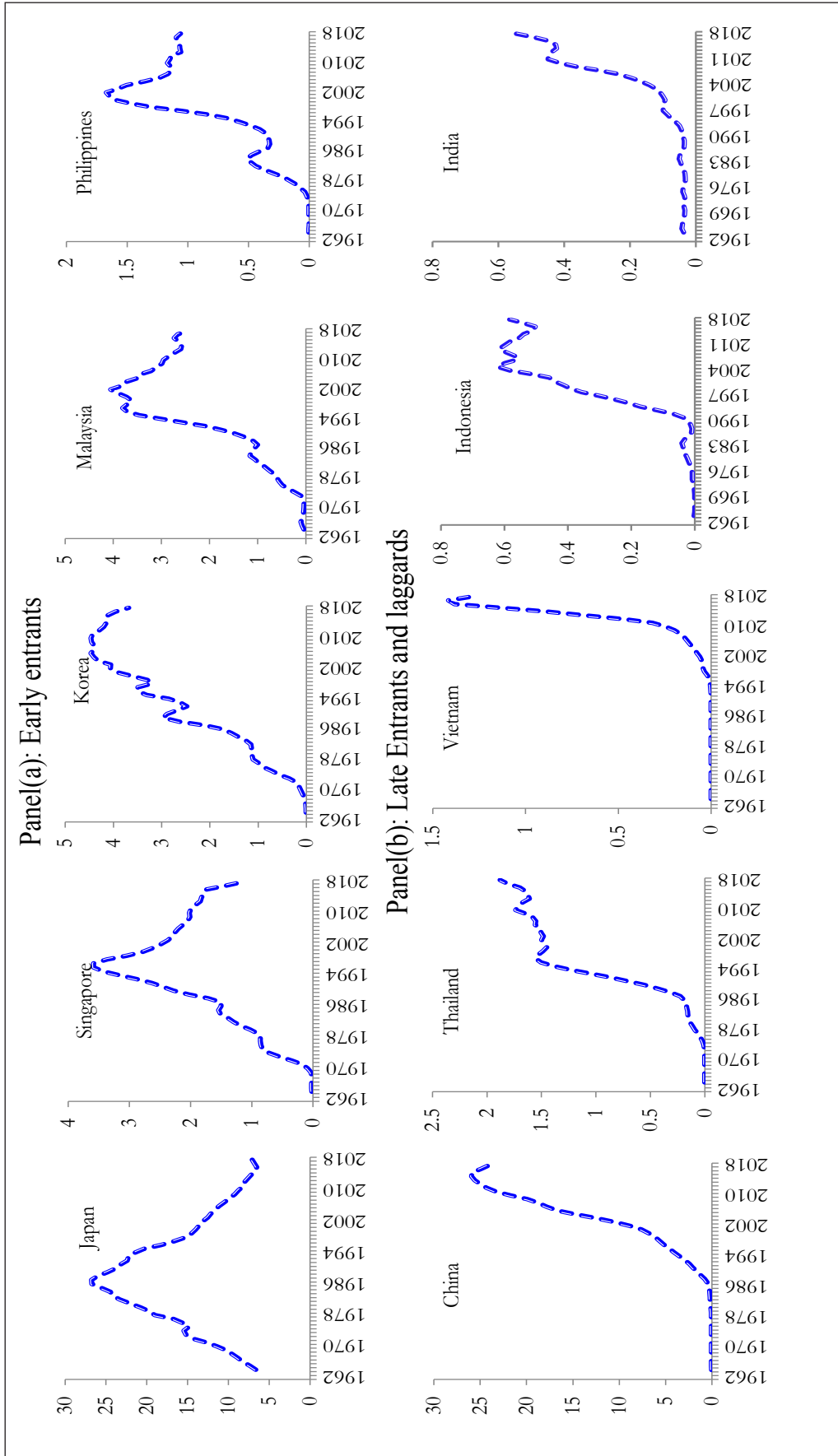
प्रवेश का पैटर्न

5.28 एनपी के लिए निर्यात बाजार में देशों का प्रवेश, उभारत, उत्तरजीविता एवं सापेक्ष गिरावट वर्ष 1960 के दौरान हुए जापानी अर्थशास्त्री का ना में अकामसू द्वारा बनाए गए “वाइल्ड-गीज फ्लाईंग मॉडल” से सूसंगत है। एनपी के लिए निर्यात बाजार में प्रवेश करने वाला पहला एशियन देश जापान था, इसके बाद अनेक पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिमी एशियन देशों ने इसका अनुसरण किया। प्रवर्तक के रूप में जापान ने पूर्वी एवं दक्षिण पश्चिमी एशिया के अनुसरणकर्ता एवं प्रबंधकीय जानकारी की व्यवस्था की। जगेली हंस वी आकार बनाते हुए नियमित उड़ान भरते हैं, जैसे कि वायुयान फामेशन में उड़ान भरते हैं। (अकामसू, 1962, पृ. 11)। वर्षों से अनेक एशियन

देशों की निर्यात बाजार सहभागिता वास्तव में। चित्र में दी गई उलटी वी (अ) (चित्र 14 देखें) को चित्रित करती है। चित्र की पैनल (क) प्रारंभिक प्रवेशकों -जापान, कोरिया, सिंगापुर, मलेशिया एवं मिलिथिंस पैनल (ख) में बाद के प्रवेशकों (चीन, थाइलैण्ड एवं वियतनाम) एवं लैगाडैस (भारत एवं इण्डोनेशिया) के पैटर्न को दर्शाती है। बाद वाले प्रवेशकों में चीन उलटी “वी” के पी वतेन बिंदु पर पहुंच गया है तथा थाइलैण्ड एवं वियतनाम वक्र के आरोही पार्ट पर है। चार्टस की तुलना में यह दर्शाया गया है कि एनपी निर्यात में टेक ऑफ प्रक्रिया भारत में प्रारंभ हो सकती है।

5.29 जापान एवं चीन जैसे बड़े देश, जो लंबी अवधि से बाजार में कारोबार कर रहे हैं, ने एसेंबल किए गए तैयार उत्पाद (ईपी) के विस्तार किया है जबकि पुर्जे एवं संघटक (पीएण्डसी) ने सूट का अनुसरण किया (चित्र 15) ईपी में उलटी वी (अ) मार्ग पर जापान की गिरावट 1985 में भी प्रारंभ हुई थी, इसके बाद पीएण्डसी सिरका 1993 में। चीन ईपी सिरका 2015 के लिए उलटी वी वक्र के परिवर्तन बिन्दु तक पहुंच गया है जबकि इसका पीएण्डसी में वैश्विक बाजार शेयर

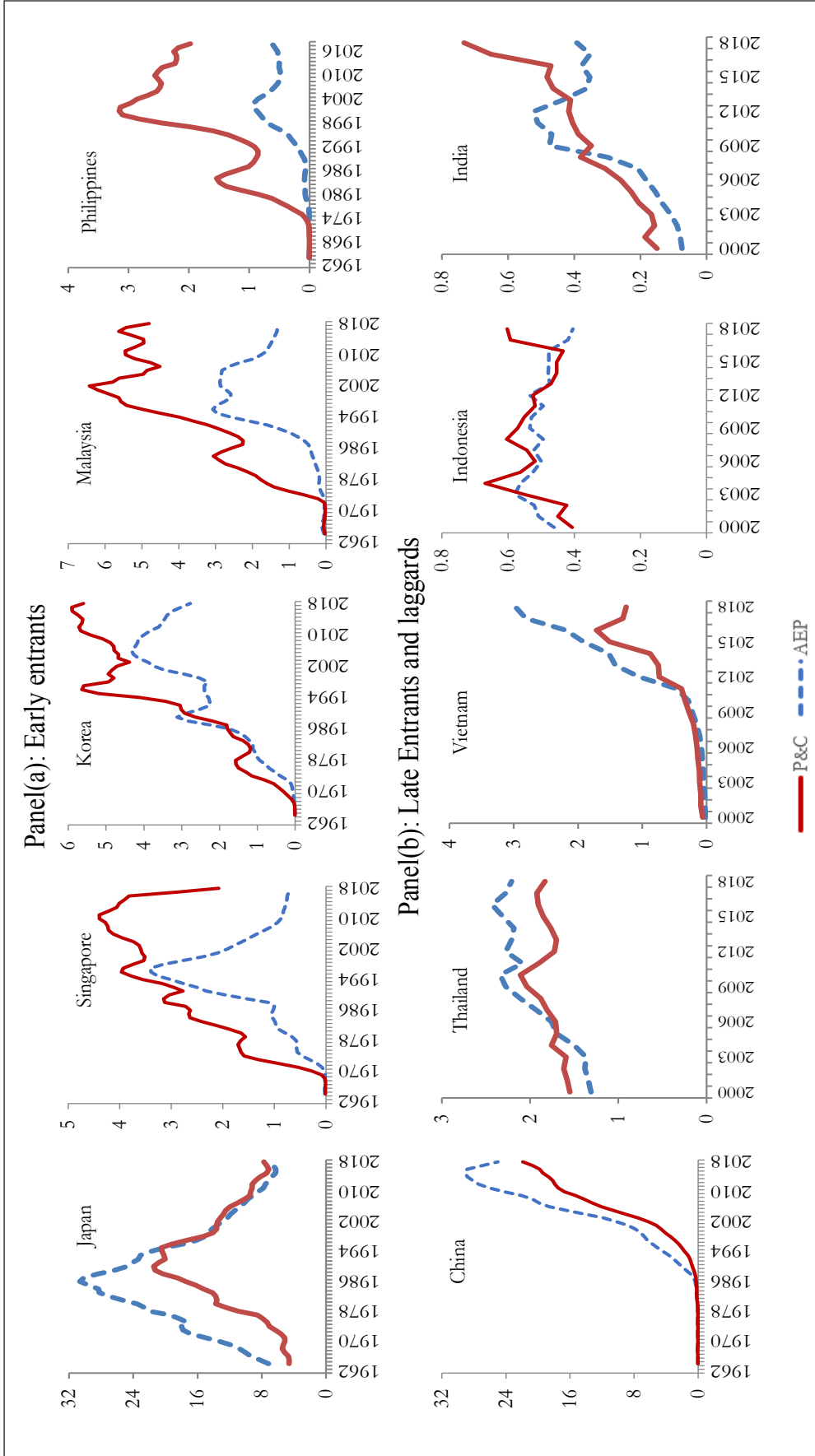
चित्र 14: नेटवर्क उत्पाद में निर्यात का जंगली हंस पैटर्न 1962-2018



स्रोत: वीरमणि और धीर (2019 ख)

टिप्पणी: उर्ध्वोर्ध्व अक्ष पर दर्शाए गए मान संबंधित देश का विश्व निर्यात बाजार शेयर (तीन वर्ष कर औसत) को दर्शाता है। आभसी सख्खिकी पर 28 देशों के निश्चित सेट के आधारित प्राक्कलन (ट्रेडिंग पार्टनरों द्वारा दी गई रिपोर्टनुसार प्रत्येक एशियन देश से आयात) जिन्होंने वर्ष 1962-2018 के दौरान प्रतिवर्ष के लिए आयात डाटा की रिपोर्ट भेजी है विश्व निर्यात में इनका शेयर लगभग 55% है।

चित्र 15: एनपी उत्पादों का जंगली हंस उड़ान चैटर्न एसेंबल किए गए तैयार उत्पाद (एईपी) की तुलना में पुर्जे एवं संघटक (पीएण्डसी)



स्रोत: यूएन कामट्रेड (डब्ल्यू आई सी एस) डाटा बेस पर आधारित सर्वेक्षण परिकलन।

टिप्पणी: उध्वीधर अक्ष पर दर्शाए गए मान संबंधी देश के विश्व निर्यात बाजार शेयर को दर्शाते हैं। प्राक्कलन आभासी सांख्यिकी पर आधारित है। (ट्रेडिंग पार्टनरों द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक एशियन देश के आयात के आधार पर प्राक्कलन प्रारंभिक नवांगतु को एवं चीन के समूह के लिए, उन 28 देशों के निश्चित सैट द्वारा की गई रिपोर्ट किए गए आयात प्रवाह के आधार पर प्राक्कलन तैयार किए गए हैं, जिन्होंने 1962-2018 की अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष डाटा प्रस्तुत किया है। नवांगतुओं एवं लैगार्ड (चीन को छोड़कर) उन 118 देशों, जिन्होंने 2000-2018 के बीच की अवधि में प्रत्येक वर्ष आयात डाटा भेजा है, के निश्चित सैट के लिए आभासी सांख्यिकी के आधार पर प्राक्कलन तैयार किए गए हैं।

बढ़ता रहा। हाल ही के अधिकांश नवांगतक, थाइलैंड एवं वियतनाम ने आईपी निर्यात के विस्तार के साथ प्रारंभ किया है जबकि पीएण्डसी सूट का अनुसरण कर रही है। भारत के लिए पीएण्डसी ने हाल ही के वर्षों में कुछ प्रगति की है जबकि आईपी में यात्री कारों एवं टेलीकॉम हैण्डसैटों जैसे अपवादों के साथ गिरावट दर्ज की गई।

रोजगार एवं जीडीपी का संभावित लाभ

5.30 एन पी को विशेष तरजीह देने की नीति से रोजगार सृजन एवं जीडीपी दोनों में महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। आओ हम ऐसे परिदृश्य की संकल्पना करें जिसमें भारत चीन के निर्यात विस्तार के प्रारंभिक अवधि के समान प्रक्षेप-पथ का अनुसरण करता है। अपनी

उड़ान के प्रथम 10 वर्षों के दौरान चीन ने एन पी के विश्व निर्यात में अपने वर्ष 1987 के 0.7% शेयर को बढ़ाकर वर्ष 1998 में 6.1% कर लिया। यदि भारत देश चीन के प्रारंभिक निर्यात वृद्धि निष्पादन - अर्थात् मान लो कि भारत में एन पी के लिए अपने विश्व निर्यात शेयर को 0.6% से बढ़ाकर वर्ष 2030 में 6% से ज्यादा कर सकता है, की नकल करता है तो इससे देश की जी डी पी एवं रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत से एन पी निर्यात की त्वरित वृद्धि से होने वाले संभावित लाभों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधि एवं अवधारणाओं की विस्तृत चर्चा बॉक्स 6 में दी गई है।

5.31 तालिका 2 यह दर्शाती है कि “सामान्य परिदृश्य के रूप में कारोबार” के अधीन एन पी निर्यात का वैश्विक निर्यात वर्ष 2018 के 5.6 ट्रिलियन यू एस

तालिका 2: विश्व एवं भारत के लिए एन पी निर्यात के पूर्वानुमानित मूल्य, 2020-2030

वर्ष	एन पी का वैश्विक निर्यात (ट्रिलियन यू एस डॉलर)	भारत का एन पी निर्यात (बिलियन यू एस डॉलर)	विश्व निर्यातों में भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)
2020	5.94	69.4	1.2
2025	6.92	248.2	3.6
2030	8.06	490.7	6.1

स्रोत: सर्वेक्षण परिकल्पना

टिप्पणी: मूल्यों के पूर्वानुमान के लिए प्रयुक्त अवधारणाओं के लिए बॉक्स 6 देखें।

डॉलर के वर्तमान वास्तविक मूल्य के बढ़कर वर्ष 2025 में 6.9 ट्रिलियन यू एस डॉलर तथा 2030 में 8.1 ट्रिलियन डॉलर के पूर्वानुमानित मूल्य तक पहुंच जाएगा। इस अवधि के दौरान भारत के एन पी का निर्यात वर्ष 2018 के 32.3 बिलियन यू एस डॉलर (विश्व निर्यात का 0.6%) के वास्तविक मूल्य से बढ़ाकर वर्ष 2025 में 248.2 बिलियन यू एस डॉलर (विश्व निर्यात का 3.6%) तथा वर्ष 2030 में 490.7 बिलियन डॉलर (विश्व निर्यात का 6.1%) करने का लक्ष्य है।

5.32 भारत के पूर्वानुमानित निर्यात में घरेलू मूल्य योजित (डीवीए) वर्ष 2025 में 166.5 बिलियन यूएसडॉलर तथा वर्ष 2030 में 304.7 बिलियन यू एम डॉलर अनुमानित है। (तालिका 3) एन पी क्षेत्र में निर्यात रोजगार से मिलने वाले जॉब्स के साथ एन पी क्षेत्र के आपूर्ति करने वाले अन्य क्षेत्रों के परीक्ष संपर्कों से

मिलने वाले जॉब्स की कुल संख्या वर्ष 2020 की 4.4 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2025 में 14.3 मिलियन एवं वर्ष 2030 में 25.5 मिलियन हो जाएगी। अतः विचारार्थ परिदृश्य के प्रथम चरण के प्रभावों के आधार पर अगले 5 वर्षों में 10 मिलियन तथा अगले दस वर्षों में 20 मिलियन जॉब्स अतिरिक्त निर्यात संबंधित जॉब्स सृजित होने की संभावना है।

5.33 यद्यपि यह भी आवश्यक है कि कामगारों द्वारा होने वाली खपत की वृद्धि के दूसरे क्रम के प्रभावों को भी ध्यान में रखना होगा। जॉब्स पर पड़ने वाले समग्र प्रभाव (प्रथम क्रम के साथ दूसरे क्रम के आदेश के प्रभाव) काफी अधिक है। (तालिका 4 देखें) हमारे अनुमान में यह सुझाव दिया गया है कि वर्ष 2025 तक एनपी के विश्व निर्यात में भारत के शेयर को 3.6% तक बढ़ाने से अगले 5 वर्षों के दौरान देश में 38.5 मिलियन अतिरिक्त जॉब्स सृजित होने की संभावना है। इसके

तालिका 3: भारत में रोजगार एवं जीडीपी पी एनपी निर्यात के त्वरित वृद्धि का प्रभाव, प्रथम एवं द्वितीय चरण के प्रभाव

वर्ष	प्रथम चरण प्रभाव			द्वितीय चरण प्रभाव		
	निर्यातों से घरेलू मूल्य वर्धित (बिलियन यू एस डॉलर)	एनपी निर्यातों से जुड़ी नौकरियाँ# (मिलियन)	वैतनिक आय (बिलियन यू एस डॉलर)	वैतनिक आय (बिलियन यू एस डॉलर)	घरेलू मूल्य वर्धित (बिलियन यू एस डॉलर)	नौकरियाँ# (मिलियन)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	50.1	4.4	24.8	82.5	117.9	25.7
2025	166.5	14.3	88.4	294.4	420.4	83.0
2030	304.7	25.5	174.5	580.9	829.6	148.0

स्रोत: सर्वेक्षण परिकलन

टिप्पणी: प्रभाव के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधियाँ एवं अवधारणाओं के लिए बॉक्स 6 देखें।

तालिका 4: समग्र प्रभाव (प्रथम एवं द्वितीय चरण) रोजगार एवं जीडीपी

वर्ष	नौकरियाँ# (मिलियन)	मूल्य वर्धित (बिलियन यू एस डॉलर)
2020	30.1	168
2025	97.3	586.9
2030	173.5	1134.3

स्रोत: सर्वेक्षण परिकलन

टिप्पणी: प्रभाव के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधियों एवं अवधारणाओं के लिए बॉक्स 6 देखें।

बॉक्स 6: नेटवर्क उत्पादों के क्षेत्र में भारतीय निर्यात के बढ़ने जीडीपी एवं रोजगार में होने वाले संभावित लाभ के निर्धारण के लिए प्रयुक्त विधियाँ एवं अवधारणाएँ।

तालिका 2 में दर्शाए गए विश्व निर्यात का पूर्वानुमानित मूल्य 'साधारण कारोबार' परिदृश्य पर आधारित है, जिसमें यह माना गया है कि वर्ष 2010-2018 के दौरान एन पी के विश्व निर्यात की प्रचलित वृद्धि दर (3.1% प्रतिवर्ष) पूर्वानुमानित अवधि (2019-2030) के लिए भी जारी रहेगी। वर्ष 2020-2030 के लिए भारत के निर्यात का पूर्वानुमानित मूल्य यह मान कर लगाया जा रहा है कि भारत चीन के एन पी में निर्यात बाजार के प्रवेश के पहले दशक (1988-1998) के दौरान वैश्विक बाजार में चीन के निर्यात निष्पादन की नकल कर सकता है।

एनपी के लिए डीवीए एवं सकल निर्यात के अनुपात का प्रयोग करके निर्यात के घरेलू योजित मूल्य (डीवीए) का अनुमान लगाया गया है। (कॉलम 1, तालिका 3) आगत-निर्गत (आई-ओ) तालिकाओं का प्रयोग करके इन अनुपातों का प्राक्कलन किया गया है। आई-ओ ढांचे का लाभ यह है कि इससे हम किसी प्रदत्त क्षेत्र से निर्यात के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभावों (पश्चवर्ती संपर्क) को अलग कर सकते हैं। वर्ष 2017-18 के लिए डीवीए (प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) का शेर एन पी के भारतीय सकयल निर्यात में 74.1% था। हम मानते हैं कि इस शेर में प्रति वर्ष 1% की कमी आएगी, (आयातित इनपुट के संवर्धित प्रयोग से संचालित) ताकि यह वर्ष 2025 तक 67.1% तथा वर्ष 2030 तक 62.1% हो जाए।

इसी प्रकार, एन पी निर्यातों (कॉलम 2 तालिका 3) से मिलने वाले जॉब्स की संख्या उन उपलब्ध प्राक्कलनों का प्रयोग करके प्राप्त की जा सकती है जिनमें आई-ओ क्रियाविधि का प्रयोग किया जाता है। यह अनुमानित है कि वर्ष 2017-18 में भारत के एनपी निर्यात की एक मिलियन यूएस डालर से 67.6 मिलियन जॉब पैदा हुए। हम मानते हैं कि इस संख्या में प्रतिवर्ष 2% की क्रमिक गिरावट (श्रम उत्पादकता सुधारा द्वारा संचालित) आएगी ताकि यह वर्ष 2.25 तक 57.5 तथा वर्ष 2030 तक 52 हो जाए। प्रत्येक वर्ष निर्यात द्वारा सृजित जॉब्स की कुल संख्या की वार्षिक वृत्तियों एवं वेतनों (यू एस डालर में) को गुण करके कामगारों

की वार्षिक वृत्ति आय प्राप्त की जा सकती है। (कालम 3, तालिका 3) यू एन आई डी ओ की औद्योगिकी सांख्यिकी ने कामगारों की वृत्तियों एवं वेतन प्राप्त किए गए हैं। वर्ष 2017 में भारत के एनजी उद्योगों की वार्षिक वृत्तियां एवं वेतन 5287 यू एस डालर था। हम मानते हैं कि इसमें प्रतिवर्ष 2% की क्रमिक वृद्धि होगी, (श्रम उत्पादकता सुधारों से संचालित) ताकि यह वर्ष 2025 में 6194.5 यू एस डालर तथा वर्ष 2030 में 6839.3 यू एस डॉलर हो जाए।

आई. ओ विश्लेषण में टाईप-I गुणकों (प्रत्यक्षा एवं पश्चवर्ती संपर्क) का प्रयोग करके प्रथम चरण के प्रभावों का अनुमान लगाया जाता है कामगारों की संवर्धित वृत्ति आय के मूलस्वरूप अतिरिक्त घरेलू खर्च से दूसरे क्रम का प्रभाव पैदा होता है भारतीय परिवार के लिए उपभोक्त की सीमांत प्रवृत्ति (एम पीसी) का लगभग 0.7 रहने का अनुमान है। तदनुसार, आय गुणक के मूल्य (1/1-एम पी सी) का 3.33 के रूप में अनुमान लगाया गया है। प्रारंभिक वृत्ति आय (कालम 3, तालिका 5) पर इस गुणक को लगाकर हम वृत्ति आय पर होने वाले द्वितीय चरण के प्रभावों का पता लगा सकते हैं। (कालम 4, तालिका 3)

घरेलू याजित मूल्य के द्वितीय चरण का प्रभाव निम्नानुसार प्राप्त किया जाता है।, सबसे पहले, अंतिम वृत्ति आय से प्रारंभिक वृत्ति आय (प्रथम चरण प्रभाव) को घटा कर वृत्ति आय के अंतर (डवेज) का पता लगाया जाता है। इसके बाद, भारतीय अर्थ व्यवस्था के एकीकृत योजित मूल्य प्राप्त करने के लिए डीवेज को एकीकृत श्रम आय से भाग करके हमें घरेलू योजित मूल्य के द्वितीय चरण का प्राक्कलन प्राप्त होता है। भारत के एल ई एम एस का प्रयोग करके वर्ष 2016 के लिए श्रम आय एवं योजित मूल्य का अनुपात 0.49 लगाया गया है

जॉब्स पर होने वाले द्वितीय चरण के प्रभावों का पता करने के लिए सबसे पहले हमें घरेलू योजित मूल्य के द्वितीय चरण प्राक्कलन को निम्नानुसार सकल निर्गत (आउटपुट) में परिवर्तित किया जाता है

सकल उत्पादन = घरेलू मूल्य वर्धित (द्वितीय क्रम प्राक्कलन)/भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सकल उत्पादन के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) का अनुपात।

उत्पादन के जीवीए का प्राक्कलित अनुपात वर्ष 2015-16 के लिए 0.5 है (स्रोत: आपूर्ति उपयोग तालिका, सीएसओ)।

समीक्षा प्राक्कलन दर्शाते हैं कि वर्ष 2017-18 में भारत में 1 मिलियन यूएस डॉलर के मूल्यों के उत्पादन से 116 नौकरियों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) का सृजन हुआ। हमारा मानना है कि यह संख्या प्रतिवर्ष क्रमिक रूप से 2 प्रतिशत तक कम होगी जो श्रम उत्पादकता में सुधार का प्ररिलक्षण होगा।

अतिरिक्त, वर्ष 2030 में 6.1% तक इस शेयर को बढ़ाने से अगले 10 वर्षों के दौरान 82.2 मिलियन अतिरिक्त जॉब्स पैदा होने की संभावना है। कुल घरेलू योजित मूल्य (मूल कीमत) वर्ष 2020 के 168 बिलियन यूएस डॉलर बढ़कर वर्ष 2030 तक 1134.3 बिलियन यू एम डालर हो जाएगा। वर्ष 2019 एवं 2025 के बीच योजित अतिरिक्त मूल्य 485.5 बिलियन यूएस डालर है, जो कि वर्ष 2025 तक भारत की अर्थव्यवस्था की 5 ट्रिलियन डालर बनाने के लिए अपेक्षित जीडीपी में होने वाली वृद्धि (मूल कीमतों में) का एक चौथाई है।

क्या व्यापार समझौता लाभकारी है?

5.34 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक सहभागिता (आर सी ई पी) में भारत की भागीदारी संबंधी हाल ही चर्चा को लेकर मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की समान्य दक्षता के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं। एक अदांजा यह है कि अधिकांश एफ टी ए, जिन पर विगत में भारत ने हस्ताक्षर किए हैं, भारत के पक्ष में नहीं रहे हैं। तर्क यह है कि समझौते को आगे बढ़ाने से सहभागी देशों,

जिनके साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, के साथ भारत की व्यापारिक घाटे की दशा खराब हुई है। यह व्यापार से लाभ मूल्यांकित करने का व्यापारिक रास्ता है। मूल व्यापार सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि देश को मुक्त व्यापार से लाभ होता है जो इस तथ्य से पैदा होता है कि इससे देश के संसाधनों का अधिक प्रभावी आवंटन होता है।

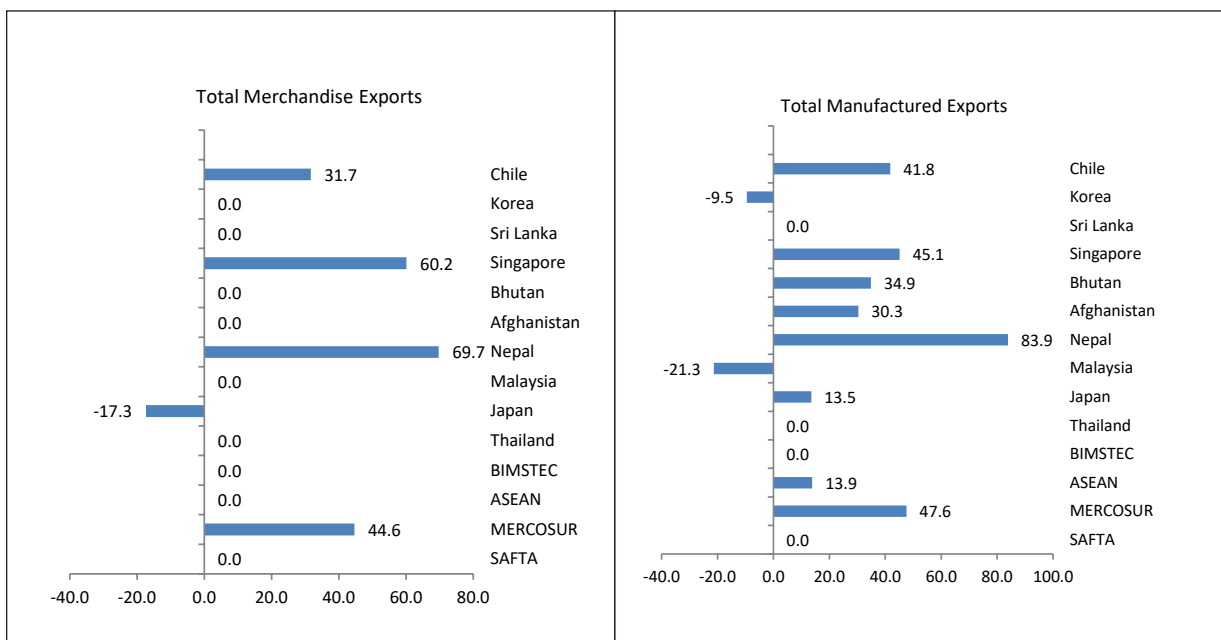
5.35 तालिका 5 में वर्ष 1993 से 2018 के बीच भारत के व्यापार समझौते दर्शाए गए हैं। चित्र 16 में भारत के निर्यात एवं आयात के डालर मूल्यों के प्रतिशत अंतरों पर इन समझौते के प्रभाव को दर्शाया गया है। ये परिणाम प्रत्यावर्तन विनिर्देशनों पर आधारित हैं जिसमें जीडीपी एवं व्यापारिक सहभागियों प्रति व्यक्ति आय, सहभागी देश निश्चित प्रभाव एवं वर्ष के निश्चित प्रभावों समेत असम्मति घटकों के संपूर्ण सेर को लिया जाता है। असम्मति घटकों को नियंत्रित किए बिना साधारण पहले एव बाद की तुलना से भ्रामक निष्कर्ष निकल सकते हैं।

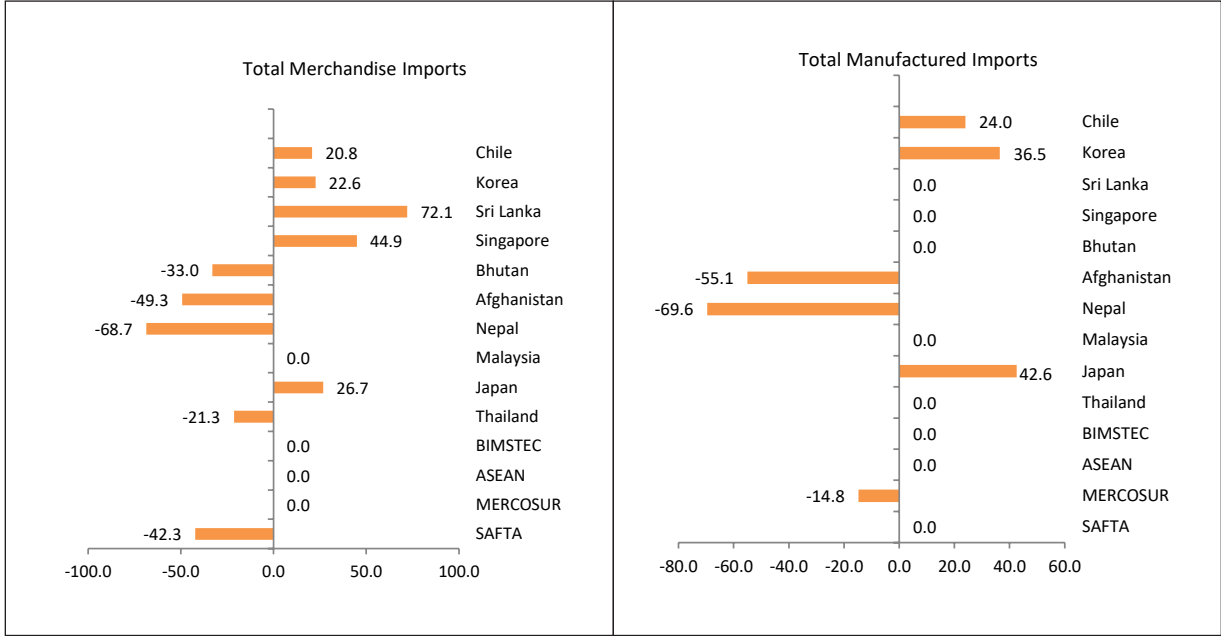
5.36 यह देखा जा सकता है कि भारत के विनिर्मित उत्पादों में भारत ने यहाँ विचारार्थ 14 में से 8 व्यापार समझौतों से स्पष्ट लाभ अर्जित किया है। ये हैं: एम ई आर सी ओ एस यू आर , एशियन, नेपाल, सिंगापुर, चिली, भूटान, अफगानिस्तान एवं जापान। चार समझौतों (एस ए एम टी ए बी आई एम एस टी ई सी) थाईलैंड एवं श्रीलंका) का विनिर्मित उत्पादों के निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं हुआ जबकि कोरिया एवं जपान के साथ हुई द्विपक्षीय समझौतों से ऋणात्मक प्रभाव पड़ा है। समग्र व्यापारिक निर्यात की दृष्टि से केवल चार व्यापारिक समझौतों (एमईआरसीओएसयूआर, नेपाल, सिंगापुर एवं चिली) का सकारात्मक प्रभाव रहा। विनिर्माता सबसैट की तुलना में समग्र व्यापारिक निर्यात का विभेदीय प्रभाव आश्चर्यजनक नहीं है चूंकि अनेक प्राथमिक उत्पाद आमतौर पर व्यापार समझौते के ऋणात्मक/संवेदनशील सूची में शामिल है। अतः अधिकांश व्यापारिक समझौतों ने समग्र व्यापारिक निर्यात पर कोई प्रभाव नहीं डाला। विनिर्मित निर्यात की तुलना में, बहुत कम व्यापारिक समझौतों ने भारत के विनिर्माण आयात पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। भारत के आयात पर सकारात्मक

प्रभाव डालने वाले समझौता में विनिर्मित उत्पादों के लिए जापान, कोरिया एवं चिली तथा समग्र व्यापारिक आयात पर जापान, कोरिया, चिली, सिंगापुर एवं श्रीलंका शामिल है। यहां तक कि कुछेक समझौतों से अधिकांश मामलों में आयात में वृद्धि प्रतिशत से अधिक है। कोरिया जापान एवं श्रीलंका के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते इसका अपवाद हैं जहां आयात की प्रतिशत वृद्धि निर्यात से अधिक है।

5.37 जिन साझेदारों के साथ भारत ने करार किए हैं उनका भारत के निर्यातों समग्र प्रभाव विनिर्मित उत्पादों के संबंध में 13.4 प्रतिशत तथा कुल व्यापार के संबंध में 10.9 प्रतिशत पड़ा है, जैसाकि चित्र 17 में दर्शाया गया है। आयातों पर समग्र प्रभाव विनिर्मित उत्पादों के संबंध में 12.7 प्रतिशत और कुल व्यापारिक माल के संबंध में 8.6 प्रतिशत के निम्नतर स्तर पर पाया जाता है। इसलिए, व्यापार संतलन के परिप्रेक्ष्य से भारत ने, विनिर्मित उत्पादों के संबंध में व्यापार अधिशेष में प्रतिवर्ष 0.7 प्रतिशत तथा कुल व्यापारिक माल के संबंध में व्यापार अधिशेष में प्रतिवर्ष 2.3 प्रतिशत का “लाभ” स्पष्ट तौर पर प्राप्त किया है।

चित्र 16: 1993 से 2018 के दौरान भारत के निर्यात एवं आयात पर व्यापार समझौतों का प्रभाव (प्रति वर्ष यूएस डॉलर का परिवर्तन प्रतिशत)

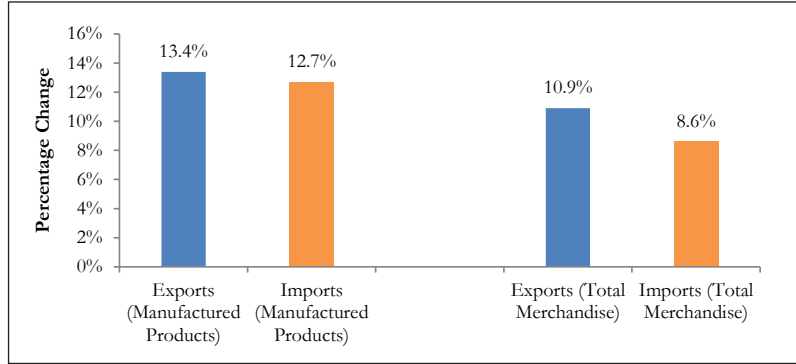




स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: यहां प्रस्तुत परिणाम गुरुत्वाकर्षण माडल आधारित प्रत्यावर्तन विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें निर्भर चर में वर्ष 1993-2018 की अवधि के लिए द्विपक्षीय आधार पर भारत के निर्यात का मूल्य डॉलर मुक्त चर में सहभागी देशों की जीडीपी, व्यापारिक सहभागियों की प्रति व्यक्ति जीडीपी, विभिन्न व्यापारिक समझौते निज सहभागी निश्चित प्रभाव एवं वर्ष निश्चित प्रभाव शामिल होते हैं। निर्यात एवं आयात में हुए प्रतिशत अंतरों का प्राक्कलन (एफटीए में प्रवेश के बाद) तदनुसूची एफटीए डमिज के गुणांक पर आधारित है।

चित्र 17: निर्यात एवं आयात पर व्यापारिक समझौता का समग्र प्रभाव



स्रोत: चित्र 16 में प्रस्तुत प्राक्कलनों पर आधारित

तालिका 5: भारत के व्यापार समझौते

करार	जिस वर्ष भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे	ब्लॉक में देश	प्रारंभ वर्ष	शुरूआती साल
बिम्सटेक	1997	बांग्लादेश, भूटान (2004), भारत, म्यांमार, नेपाल (2004), श्रीलंका, थाईलैंड	1997 (भूटान 2004, नेपाल 2004 के सिवाय)	2018
श्री लंका	2001	भारत, श्रीलंका	2001	2005
अफगानिस्तान	2003	भारत, अफगानिस्तान	2003	2010

थाईलैंड	2004	भारत, थाईलैंड	2004	2009
सिंगापुर	2005	भारत, सिंगापुर	2005	2009
भूटान	2006	भारत, भूटान	2006	2018
साफ्टा	2006	अफगानिस्तान (2011), बांग्लादेश, भूटान, भारत, माल्दीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका	2006 (अफगानिस्तान 2011 के सिवाय)	2018
विल	2007	भारत, चिली	2007	2018
मेर्कोसुर/मेरोसुर	2009	भारत (2009), अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे, उरूग्वे	2009	2018
नेपाल	2009	भारत, नेपाल	2009	2018
कोरिया	2010	भारत, कोरिया	2010	2018
आसियान	2010	भारत (2010), ब्रूनेई, दारास्सलाम (1984), कंबोडिया (1999), इंडोनेशिया, लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक (1997), मलेशिया, म्यांमार (1997), फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम (1995)	2010	2018
मलेशिया	2011	भारत, मलेशिया	2011	2018
जापान	2011	भारत, जापान	2011	2018

स्रोत: डब्ल्यूटीओ क्षेत्रीय व्यापार करार डाटाबेस

भावी परिदृश्य

5.38 ऐसे देशों के अनुभव, जिन्होंने त्वरित एवं संधारणीय प्रगति की है, से पता चलता है कि भारत नेटवर्क उत्पादों के निर्यात बाजार में अपनी सांझीदारी को मजबूत करने के लिए लक्षित नीतियों को अपना कर भारी लाभांश अर्जित कर सकता है। अपेक्षाकृत निम्न कौशल वाली व्यापक जनशक्ति के साथ भारत की वर्तमान ताकत एनपी एसेंबली में प्रमुख भूमिका रखती है। जबकि लघु से मध्यम अवधि उद्देश्य एसेंबली गतिविधियों का बड़े पैमाने पर विस्तार करना है, ऐसा करने के लिए पार्टस एवं संघटकों (जीवीसी के अंदर उन्नयन करके) के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करके आयातित पार्टस एवं संघटकों का प्रयोग करना दीर्घावधि उद्देश्य होना चाहिए। एसेंबली एक उच्च श्रम केंद्रित कार्य है, जो कि भारी मात्रा में जॉब देसकती है, जबकि पार्टस एवं संघटकों के घरेलू उत्पादन से उच्च कौशल वाले जॉब सृजित होंगे।

5.39 भारत के निर्यात बाजार शेयर को बढ़ाने का उच्च प्राप्य लक्ष्य वर्ष 2025 तक लगभग 3.5 प्रतिशत एवं 2030 तक 6 प्रतिशत होने से वर्ष 2025 में लगभग 38.5 मिलियन अतिरिक्त जॉब तथा 2030 तक 82 मिलियन अतिरिक्त जॉब सृजित होंगे। नेटवर्क उत्पादों के निर्यात के लक्षित स्तर से प्राप्त अतिरिक्त योजित मूल्य वष 2025 तक भारत की 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपेक्षित वृद्धि का एक चौथाई होगा।

5.40 एक महत्वपूर्ण सरोकार यह है कि जीवीसी में सहभागिता यह इंगित करती है कि निम्न वृद्धि वाले देश उत्पादन प्रक्रियाओं के निम्न सिरे पर स्थायी रूप से बने रहेंगे। भारत के ऑटोमोबाइल क्षेत्र का मामला अध्ययन इसकी व्यवस्था करता है, ऐसा पूर्वाभास बेबुनियाद है।

5.41 एसेंबली गतिविधियों के लिए आकर्षक स्थान बनने किसी भी देश के लिए यह आवश्यक है कि मध्यवर्ती इनपुट्स के लिए आयात टैरिफ पर शून्य या नगण्य हो। पारिस्थितिक माहौल तैयार करना भी

आवश्यक है जिससे श्रम व्यापक प्रक्रियाओं एवं उत्पाद लाइनों की ओर भारत के विशेषज्ञ पैटर्न का पुनः सरेखन हो। श्रम बाजार में चलाए जा रहे चालू सुधारात्मक उपाय रहने चाहिए। प्रो. एक्टिव एफडीआई नीति भी महत्वपूर्ण है चूंकि वैश्विक उत्पादन नेटवर्क में देश को प्रवेश करने के लिए एमएनई अग्रणी वाहन है। एसेंबली प्रक्रियाओं के लिए न केवल प्रशिक्षण योग्य निम्न लागत वाला अकुशल श्रम की आवश्यकता होगी, बल्कि बड़े स्तर के पर्यवेक्षण जनशक्ति की भी आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए जब एप्पल ने चीन में 7,00,000 फ़ैक्टरी कामगारों को रोजगार दिया, इससे उन कामगारों को रोजगार दिया, इससे उन कामगारों को कार्यस्थल पर के पर्यवेक्षण के लिए 30000 इंजीनियरों की भी नियुक्ति की। (ईसाकान, 2011)

5.42 सेवा से जुड़ी लागतों (किसी देश में दूसरे देशों के साथ समन्वय गतिविधियों के संबंध में परिवहन, संचार और अन्य कार्यों से जुड़ी लागतें) के स्तर का कम होना देश के लिए जी वी सी में उनकी सहभागिता सुदृढ़ करने के लिए पूर्व शर्त है। किसी स्थान पर नौवहन में देरी, विद्युत आपूर्ति न होने, (राजनीतिक अस्थिरता श्रमिक विवाद आदि के कारण विद्युत आपूर्ति में व्यवधान से पूरी उत्पादन श्रृंखला बाधित हो जाती है। नीतिगत उपायों में अदान (इनपुट) के प्रशुल्क को कम करने, मुख्य बाजार सुधार कारकों के कार्यान्वयन, देश में प्रमुख फर्मों के प्रवेश के अनुकूल माहौल बनाने तथा सेवा से जुड़ी लागतों को कम करने पर बल दिया जाना चाहिए।

अध्याय एक नजर में

- अंतरराष्ट्रीय व्यापार हेतु वर्तमान परिवेश भारत के लिए चीन के समान, श्रम-गहन, निर्यात प्रक्षेपपथ तैयार करता है और तद्वारा जिसके द्वारा हमारे युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है।
- 'मेक इन इंडिया' में कार्यक्रम के अंतर्गत "असेम्बल इन इंडिया फार द वर्ल्ड" को शामिल करके भारत अपने निर्यात बाजार हिस्से को वर्ष 2025 तक लगभग 3.5% तक और वर्ष 2030 तक 6% तक बढ़ा सकता है। इससे वर्ष 2025 तक 4 करोड़ तथा वर्ष 2030 तक 8 करोड़ अच्छे रोजगार सृजित होंगे जिनमें अच्छे वेतन मिलेंगे।
- वर्ष 2025 तक भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक वर्धित मूल्य में वृद्धि का एक चौथाई भाग नेटवर्क उत्पादों के निर्यात से आ सकता है।
- इसलिए यह अध्याय इस अवसर को हाथ से न जाने देने के लिए एक सुविचारित कार्यनीति स्पष्ट राजनीति के बारे में स्पष्ट रूप से बताता है।
- भारत की तुलना में चीन का उल्लेखनीय निर्यात निष्पादन मुख्य रूप से श्रम-ग्रहण क्षेत्रों, विशेष रूप से "नेटवर्क उत्पादों" में बड़े पैमाने पर सुविचारित विशेषज्ञता से प्रेरित है, जहां बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा संचालित पूरे ग्लोबल वैल्यू चेन (जी सी सी) में उत्पादन होता है। चीन ने इस विशेषज्ञतायुक्त राजनीति का उपयोग संपन्न देशों के बाजारों में निर्यात के लिए किया। इसी प्रकार, भारत को चाहिए कि नेटवर्क उत्पादों में बड़े पैमाने पर समन्वयोजन (असेंबलिंग) प्रचालनों को समर्थकारी बनाने के लिए बारीकी के साथ फोकस में रखना होगा।
- चूंकि भारत में व्यापार के मोर्चे पर अनिश्चित रूपों वाली असुरक्षा की भावना देखी जाती है और इस कारण इस अवसर को भुनाना असंभव लगता है अतः हमारी व्यापार नीति में एक सामर्थ्यकारी गुण होना चाहिए। जब हम समस्त अवरोधी तत्वों को ध्यान में रखते हुए समग्र व्यापार संतुलन पर भारत के व्यापारिक करारों के प्रभाव का आकलन करते हैं तो पाते हैं कि निर्यातों के संदर्भ में, भारत के विनिर्मित उत्पादों के निर्यातों में 13.4 प्रतिशत की और कुल व्यापारिक माल के निर्यात में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि आयातों के संदर्भ में विनिर्मित उत्पादों के आयात में 12.7 प्रतिशत और कुल व्यापारिक माल के आयात में 8.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इस प्रकार, भारत ने, विनिर्मित उत्पादों के संबंध में व्यापार अधिशेष में 0.7 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा कुल व्यापारिक माल के संबंध में 2.3 प्रतिशत प्रतिवर्ष का "लाभ" स्पष्ट तौर पर प्राप्त किया है।

संदर्भ

- Akamatsu, K. 1962. "Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries". *The Developing Economies*, 1, 3–25.
- Amiti, M., Freund, C. 2010. "An Anatomy of China's Export Growth", in Feenstra, R. C. and Wei, S., (eds.), *China's Growing Role in World Trade*, The University of Chicago Press.
- Athukorala, Prema-Chandra. 2011. "Production Networks and Trade Patterns in East Asia: Regionalization or Globalization?" *Asian Economic Papers*, 10(1): 65–95.
- Athukorala, Prema-Chandra. 2014. "How India Fits into Global Production Sharing: Experience, Prospects and Policy Options," *India Policy Forum 2013/14*, 57-116.
- Athukorala, Prema-Chandra and Veeramani, C. 2019. "From Import Substitution to Integration into Global Production Networks: The Case of Indian Automobile Industry", *Asian Development Review*, Vol 36 (2).
- Basu, Anwesha and Veeramani, C 2020. "Declining Labour Share in Indian Economy: Role of Structural Transformation?" in S Mahendra Dev (ed), *India Development Report 2020*, Oxford University Press, New Delhi (forthcoming).
- Besedes, T., Prusa, J.T. 2011. 'The Role of Extensive and Intensive Margins and Export Growth', *Journal of Development Economics*, 96, 2, 371-379.
- D'Costa, Anthony. 1995. "The Restructuring of the Indian Automobile Industry: Indian State and Japanese Capital." *World Development* 23 (3): 485–502.
- Dedrick, Jason., Kenneth L. Kraemer, and Greg Linden. 2010. Who Profits from Innovation in Global Value Chains? A study of the iPod and notebook PCs". *Industrial and Corporate Change* 19(1), 81–116.
- Dedrick, Jason., Greg Linden and Kenneth L. Kraemer .2018. "We Estimate China only Makes \$8.46 from an iPhone – and that's why Trump's Trade War is Futile" *The Conversation*, July (<https://theconversation.com/we-estimate-china-only-makes-8-46-from-an-iphone-and-thats-why-trumps-trade-war-is-futile-99258>)
- Eaton, J., Eslava, M., Kugler, M., Tybout, J., 2007. 'The Margins of Entry into Export Markets: Evidence from Colombia', in *Globalization and the Organization of Firms and Markets*, Munich, Germany, Centre for Economic Policy Research.
- Felbermayr, G.J., Kohler, W. 2006. "Exploring the Intensive and Extensive Margins of World Trade", *Review of World Economics*, 142, 4, 642-674.
- Grossman, G.M. and Rossi-Hansberg. 2008. "Trading Tasks: A Simple Theory of Offshoring" *American Economic Review*, 98 (5), 1978–1997.
- Hamaguchi, T. 1985. "Prospects for Self-Reliance and Indigenization in Automobile Industry: Case of Maruti-Suzuki Project." *Economic and Political Weekly* 20 (35): M115–M122.
- Helpman, E., Melitz, M., Rubinstein, Y. 2008. 'Estimating Trade Flows: Trading Partners and Trading Volumes', *Quarterly Journal of Economics*, 123, 2, 441-487.
- Hinloopen, J., Marrewijk C. 2008. "Empirical Relevance of the Hillman Condition for Revealed Comparative Advantage: 10 Stylized Facts," *Applied Economics*, 40, 18, 2313-2328.
- Hummels, D., Klenow, P.J. 2005. "The Variety and Quality of a Nation's Exports", *American Economic Review*, 95, 3, 704-723.
- International Labour Organization. 2019. "Exports to Jobs Boosting the Gains from Trade in South Asia"
- Isaacson, Walter. 2011. "Steve Jobs", New York: Simon & Schuster

- Kochhar, K., Kumar, U., Rajan, R., Subramanian A., Tokatlidis, I. 2006. "India's Pattern of Development: What Happened, What Follows?", *Journal of Monetary Economics*, 53, 5, 981-1019.
- Los, Bart, Marcel P. Timmer, and Gaaitzen J. de Vries. 2015. "How important are exports for job growth in China? A demand side analysis," *Journal of Comparative Analysis*, 43(1), 19-32.
- Panagariya, A. 2007. "Why India Lags Behind China and How It Can Bridge the Gap", *World Economy*, 30, 2, 229-248.
- Silva, Santos J M C and Tenreyro, Silvana. 2006. "The Log of Gravity", *Review of Economics and Statistics*, 88(4): 641-658.
- Tewari, Meenu and Veeramani, C. 2016. "Network Trade and Development: What do the Patterns of Vertically Specialized Trade in ASEAN Tell Us About India's Place in Asian Production Networks" *Global Economy Journal*, De, Vol 16(2).
- Veeramani, C. 2012a. "Anatomy of India's Merchandise Export Growth, 1993-94 to 2010-11", *Economic and Political Weekly*, Vol XLVII (1), pp 94-104.
- Veeramani, C 2012b. "The "miracle" still waiting to happen: performance of India's manufactured exports in comparison to China", in S Mahendra Dev (ed), *India Development Report*, Oxford University Press, New Delhi, p. 132-150.
- Veeramani, C and Dhir, Garima. 2016. "India's export of unskilled labor-intensive products: a comparative analysis" in C. Veeramani and R Nagaraj (ed) *International Trade and Industrial Development in India: Emerging Trends, Patterns and Issues*, Orient Blackswan.
- Veeramani, C and Dhi, Garima. 2017. "Make What in India?" in S Mahendra Dev (ed), *India Development Report 2017*, Oxford University Press, New Delhi.
- Veeramani, C., Aerath, Lakshmi and Gupta, Prachi. 2018. "Intensive and Extensive Margins of Exports: What can India Learn from China", *The World Economy*, Vol 41 (5).
- Veeramani. 2019. "Fragmentation Trade and Vertical Specialisation: How Does South Asia Compare with China", *Journal of Asian Economic Integration*, Vol 1(1), 2019.
- Veeramani, C and Dhir, Garima. 2019a. "Reaping Gains from Global Production Sharing: Domestic Value Addition and Job Creation by Indian Exports", *IGIDR Working Paper No WP-2019-024*, Mumbai (<http://www.igidr.ac.in/pdf/publication/WP-2019-024.pdf>)
- Veeramani, C and Dhir, Garima. 2019b. "Dynamics and Determinants of Fragmentation Trade: Asian Countries in Comparative and Long-term Perspective" *IGIDR Working Paper No WP-2019-040*, Mumbai. (<http://www.igidr.ac.in/working-paper-dynamics-determinants-fragmentation-trade-asian-countries-comparative-long-term-perspective/>)
- Veeramani C and Dhir, Garima. 2020. "Impact of Free Trade Agreements on India's Exports and Imports: A Quantitative Assessment", *IGIDR Working Paper*, Mumbai
- Veeramani, C and Aerath, Lakshmi. 2020. "Emerging Trends and Patterns of India's Trade Flows in A Comparative Asian Perspective", in Suresh Chand Aggarwal, Deb Kusum Das, Rashmi Banga (eds), *Accelerators of India's Growth: Industry, Trade and Employment*, Springer (forthcoming).

भारत में व्यवसाय को सुगम बनाने का लक्ष्य

“राजा (अर्थात् राज्य) सड़क द्वारा और जलीय मार्गों द्वारा और बाजार तथा बंदरगाहों की स्थापना कर व्यापार के मार्ग संस्थापित कर व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देगा”

कौटिल्य का अर्थशास्त्र, चौथी सदी ईसा पूर्व

उद्यमिता, नवाचार और धन-वृद्धि के प्रयास में व्यवसाय सुगमता (ईज ऑफ़ डुइंग बिजनेस) एक महत्वपूर्ण घटक है। हाल के वर्षों में, विश्व बैंक द्वारा घोषित की जाने वाली, व्यवसाय सुगमता संबंधी रैंकिंग में भारत ने महत्वपूर्ण सुधार किया है, परंतु ऐसी कई श्रेणियां हैं जिनमें में भारत अभी पीछे है, जैसे, व्यवसाय प्रारंभ करना, संपत्ति का पंजीकरण करना, करों के भुगतान करना और सविदाओं का प्रवर्तन करना। इस अध्याय में इन्हीं प्राचलों पर फोकस किया गया है और भारत के कार्यनिष्पादन की तुलना इसके समकक्षों तथा सर्वोत्तम श्रेणी धारकों के साथ की गई है। उदाहरण के लिए, दिल्ली और मुंबई में संपत्ति के पंजीकरण में क्रमशः 49 और 68 दिन लगते हैं, जबकि चीन में इस प्रक्रिया में 9 दिन और न्यूजीलैंड में 3.5 दिन लगते हैं। कार्यनिष्पादन संबंधी ये मैट्रिक्स, सुधार के लिए गुंजाइश का एक पैमाना भी उपलब्ध कराते हैं। आगे यह अध्याय, किसी विनिर्माण या सेवा व्यवसाय (विशेष रूप से रेस्तरां के क्षेत्र में) द्वारा कानूनों, नियमों और अन्य सांविधिक अपेक्षाओं के अनुपालन की गहनता का भी अन्वेषण करता है।

निर्यात संबंधी प्रतियोगितात्मकता न केवल उत्पादन की लागत पर बल्कि संभरण की दक्षता पर भी निर्भर करती है। कारखाने के दरवाजे से निकलकर बाहरी ग्राहक के भंडारगृह तक पहुंचने में विशिष्ट व्यापारिक मर्दों के लिए प्रत्येक चरण में लगने वाले समय का विश्लेषण करने के अंतर्गत अनेक केस अध्ययनों का सहारा लिया गया है। उदाहरण के लिए, अध्ययनों से यह पाया गया कि दिल्ली से मैन (संयुक्त राष्ट्रीय) भेजे जाने वाले वस्त्रों के प्रेषण में मोटे तौर पर 41 दिन लगते हैं, परंतु इनमें से 19 दिन, पारगमन में विलंब, सीमा-शुल्क क्लियरेंस, ग्राउंड हैंडलिंग और बंदरगाहों पर लदान के कारण, भारत में ही खर्च हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश से संयुक्त राज्य को किए जाने वाले कालीनों के निर्यातों के अध्ययन से भी इसी प्रकार के नतीजे प्राप्त हुए। विडंबना यह है कि आयात के लिए प्रवाह, निर्यात की तुलना में अधिक कुशल है। हालांकि, बेगलुरु हवाई अड्डे के माध्यम से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान के आयात और निर्यात, दोनों ही विश्वस्तरीय पाए गए अतः भारतीय हवाई अड्डों पर की जाने वाली कार्यवाहियों का अनुसरण करते हुए इन्हें बंदरगाहों के संबंध में भी अपनाया जाना चाहिए।

परिचय

6.1 वर्ष 2024-25 तक भारत की पांच ट्रिलियन डॉलर-अर्थव्यवस्था की दिशा में छलांग लगाने के लिए एक व्यवसाय के अनुकूल विनियामक परिवेश तैयार करने और उसे सरल बनाए रखने की आवश्यकता होगी। व्यापार करने में शामिल बियामक प्रक्रिया में दवाबों और अंतराल को समाप्त करने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि विभिन्न प्राचलों पर अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के साथ तुलनात्मक रूप में देश की प्रगति का मापन किया जाए।

6.2 विश्व बैंक की, व्यवसाय सुगमता वाले देशों की रैंकिंग में, भारत ने वर्ष 2014 में 142 वें स्थान से आगे बढ़ते हुए वर्ष 2019 में 63वां स्थान हासिल करके इस संबंध में सुधार की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई है। भारत ने 10 में से 7 प्राचलों पर प्रगति दर्ज की है। माल और सेवा कर (जीएसटी) और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) और सुधारों की सूची में शीर्ष पर हैं जिन्होंने रैंकिंग में भारत की प्रगति को प्रेरित किया है। पिछले एक दशक में भारत के प्रदर्शन का प्रक्षेपण तालिका 1 में दिखाया गया है।

6.3 तथापि, भारत कुछ प्राचलों के मामले में पिछड़ी स्थिति में हैं, जैसाकि, व्यवसाय प्रारंभ करने की सुगमता (रैंक-136), संपत्ति का पंजीकरण (रैंक-154), करों का भुगतान (रैंक-115), और सविदाओं का प्रवर्तन (रैंक-163)। संपत्ति का पंजीकरण कराने में लगभग 58 दिनों का समय लगता है और संपत्ति के मूल्य का औसतन 7.8 प्रतिशत खर्च आता है तथा किसी स्थानीय प्राथमिक न्यायालय के माध्यम से किसी व्यापारिक विवाद के समाधान में एक कंपनी के 1,445 दिन खर्च हो

जाते हैं। ये आंकड़े न केवल समय की दृष्टि से बड़े हैं बल्कि ओईसीडी उच्च आय-अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अकसर खर्च की दृष्टि से भी बड़े हैं और इसलिए, धन-समृद्धि के मार्ग में इनसे अड़चनें उत्पन्न होती हैं।

6.4 इस अध्याय में व्यवसाय सुगमता (डुइंग बिजनेस) रिपोर्टों में प्रयुक्त प्राचलों पर भारत के कार्यनिष्पादन का विश्लेषण किया गया है और इसकी समकक्षों तथा इस श्रेणी में सर्वोत्तम, न्यूजीलैंड, से तुलना की गई है जिसने विगत अनेक वर्षों के दौरान नंबर एक की रैंक हासिल की है।

तालिका 1: व्यवसाय सुगमता रैंकिंग में भारत की एक की यात्रा का वितरण।

पैरामीटर	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
व्यवसाय प्रारंभ की सुगमता	169	165	166	173	179	158	155	155	156	137	136
निर्माण परमिट संबंधी कार्य	175	177	181	182	182	184	183	185	181	52	27
विद्युत प्राप्त करना	-	-	98	105	111	137	70	26	29	24	22
संपत्ति पंजीकरण	93	94	97	94	92	121	138	138	154	166	154
व्यवसाय हेतु ऋण-प्राप्ति	30	32	40	23	28	36	42	44	29	22	25
लघु निवेशकों के हितों का रक्षण	41	44	46	49	34	7	8	13	4	7	13
करों का भुगतान	169	164	147	152	158	156	157	172	119	121	115
सीमा पार व्यापार	94	100	109	127	132	126	133	143	146	80	68
सविदाओं का प्रवर्तन	182	182	182	184	186	186	178	172	164	163	163
दिवालियापन का समाधान	138	134	128	116	121	137	136	136	103	108	52
समग्र रैंक	133	134	132	132	134	142	130	130	100	77	63

स्रोत: व्यवसाय सुगमता डाटाबेस, विश्व बैंक

6.5 इसके अतिरिक्त, इस अध्याय में ऐसे अनेक अध्ययनों और सर्वेक्षणों के विवरणों को भी प्रस्तुत किया गया है जो व्यापारिक निर्यात और आयात के संभरण तंत्र, रेस्तरां आदि की शुरुआत करने के लिए आवश्यक अनुज्ञाओं, इत्यादि सहित, देश में व्यवसाय करने के व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के उद्देश्य से आयोजित किए गए। इससे व्यावसायिक परिवेश के ताने-बाने को नजदीक से देखने का मौका मिलता है। व्यापारिक निर्यात के मामला अध्ययन में यह पाया गया कि भारतीय समुद्री पत्तन में लॉजिस्टिक्स व्यापक रूप से अपर्याप्त है।

विडंबना यह है कि आयात के लिए प्रवाह, निर्यात की तुलना में अधिक कुशल है। फिर भी किसी को किसी विशिष्ट मामला अध्ययन से सीधे सामान्यीकृत करते हुए सावधान रहने में आवश्यकता है यह स्पष्ट है कि कस्टम क्लियरेंस, ग्राउंड संचलन और समुद्री पत्तन पर लदाई के कार्य में कई दिन लग जाते हैं जिन कार्यों में कुछ घंटे लगने चाहिए। इलैक्ट्रॉनिक निर्यात और आयात के मामला अध्ययन में बैंगलूरों एअरपोर्ट एक ऐसा उदाहरण है जो दर्शाता है कि भारत की लॉजिस्टिकल प्रक्रिया किस प्रकार विश्व स्तरीय हो सकती है इसलिए इस अध्याय

का मुख्य लक्ष्य, विश्व बैंक के सर्वेक्षणों में अपनाए गए उपागम से भी आगे जाकर, भारत में व्यवसाय सुगमता का मूल्यांकन करते समय पाठक को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने में मदद करना है।

वैश्विक तुलना

6.6 इस खंड में, भारत के कार्य-निष्पादन की तुलना इसके समकक्ष देशों (चीन, ब्राजील एवं इंडोनेशिया) के साथ-साथ ईओडीबी में सर्वश्रेष्ठ श्रेणी, न्यूजीलैंड में की अर्थव्यवस्था से की गई है। संक्षेप में, उन्हीं प्राचलों तक तुलनाएं सीमित है कि भारत किस प्रकार से वर्ष 2009 से 2019 के दशक के दौरान ईओडीबी के केवल उन्हीं मापदंडों पर कितना खरा उतरा जिनमें वह पिछड़ता है, जैसे, व्यवसाय प्रारंभ, करना संपत्ति पंजीकरण करना, करों का भुगतान करना तथा अनुबंध लागू करना आदि। यह तुलनाएं उस अंतराल को प्रदर्शित करती है जिसको भारत को सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को हासिल करने के लिए भरने की आवश्यकता है।

6.7 भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं की संख्या पिछले 10 वर्षों के दौरान 13 से घटाकर 10 कर दी गई है (तालिका 2)। मौजूदा समय में, भारत में व्यवसाय स्थापित करने के लिए औसतन 18 दिन लगते हैं जबकि वर्ष 2009 में 30 दिन थे। दूसरी ओर न्यूजीलैंड में व्यवसाय निगमन की एक समेकित प्रक्रिया है जोकि एक एजेंसी के साथ एकल विंडो के माध्यम से पूरी हो जाती है। न्यूजीलैंड में व्यवसाय स्थापित करने के लिए एकल फार्म एवं न्यूनतम लागत के साथ मात्र आधा दिन लगता है। हालांकि, भारत ने व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए समय एवं लागत को काफी कम किया है, फिर भी इस दिशा में और अधिक प्रयास अपेक्षित है। अभी हाल ही में, कुछ और सरलीकरण किया गया है परन्तु इसके प्रभाव का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी।

6.8 संपत्ति पंजीकरण एक अन्य रोचक उदाहरण है। इसके लिए नौ प्रक्रियाएं हैं और इसमें कम-से-कम 49 दिन लगते हैं और भारत में किसी को अपनी संपत्ति के पंजीकरण के लिए संपत्ति के मूल्य का 7.4-8.1 प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, पिछले दस वर्षों में प्रक्रियाओं की संख्या, समय एवं लागत में काफी बढ़ोतरी हो गई है। जबकि, न्यूजीलैंड में केवल दो प्रक्रियाएं हैं और संपत्ति के मूल्य का 0.1 प्रतिशत निम्नतम लागत है।

6.9 करों का भुगतान करने के मामले में, पिछले दशक के दौरान करों के भुगतानों की संख्या काफी कम होने अर्थात् 59 से 12 होने के बावजूद, इस क्रियाकलाप में लगने वाले समय में कोई विशेष कमी नहीं आई है। जहां एक ओर भारत में करों का भुगतान करने के लिए प्रतिवर्ष 250-254 घंटे लगते हैं, वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड में वर्ष में 140 घंटे लगते हैं। एक रोचक तथ्य यह है कि न्यूजीलैंड में करों का भुगतान करने में लगने वाला समय वर्ष 2009 से 2019 के दौरान दुगना हो गया है।

6.10 अनुबंधों को लागू करना एक ऐसा मानदण्ड है जिसमें पिछले कुछ वर्षों में भारत का कार्य-निष्पादन काफी खराब रहा है। जहां एक ओर भारत में एक औसत विवाद के समाधान में 1445 दिन लगते हैं, वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड में इसका 1/7वां भाग अर्थात् 216 दिन लगाता है। पिछली आर्थिक समीक्षा¹ में यह तर्क दिया गया था कि भारत में व्यवसाय करने में सुगमता में सबसे बड़ी बाधा अनुबंधों को लागू करने और विवादों के समाधान में इसकी अक्षमता है। एक अच्छे प्रकार से कार्य कर रही विधिक प्रणाली के संभावित आर्थिक एवं सामाजिक गुणकों को ध्यान में रखते हुए भारत इस दिशा में एक अच्छा निवेश कर सकता है।

6.11 जब भारत के कार्य-निष्पादन की तुलना समान प्राचलों पर उसमें समकक्ष देशों जैसे चीन, ब्राजील एवं इंडोनेशिया से की जाती है तो यह देखा जा सकता है चीन ने वस्तुतः समस्त प्राचलों पर भारत से बेहतर कार्य-निष्पादन किया है। (तालिका 3)

6.12 अन्य देशों के साथ तुलना पूर्णतः एकतरफा नहीं हो सकती। किसी उद्यमी को भारत में कोई व्यवसाय आरंभ करने के लिए 10 प्रक्रियाओं को पूरा करना होता है जिनमें 17 से 18 दिन लगते हैं। दूसरी ओर इंडोनेशिया और ब्राजील में व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भारत से एक अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। हालांकि इनको पूरा करने में इंडोनेशिया को भारत से चार दिन कम लगते हैं। ब्राजील में लगभग भारत के बराबर समय लगता है। वस्तुतः पाकिस्तान, तुर्की एवं श्रीलंका (जिन्हें व्यवसाय प्रारंभ करने के प्राचलों में क्रमशः 72वां, 77 वां एवं 85वां रैंक प्रदान किया गया है) में व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भारत की तुलना में कम जटिल प्रक्रिया है।

¹ आर्थिक समीक्षा 2018-19 अध्येयन 5, खंड 1 देखें

**तालिका 2: ईओडीबी मानदंडों के संबंध में न्यूजीलैंड का खाका तैयार करना
जिनमें भारत का कार्य-निष्पादन काफी खराब है**

	भारत		न्यूजीलैंड	
	2009	2019	2009	2019
व्यवसाय प्रारंभ करना				
प्रक्रियाओं की संख्या	13	10	1	1
समय - दिनों की संख्या	30	17/18*	1	0.5
लागत (प्रति व्यक्ति आय की प्रतिशतता)	66.1	5.3/ 9.3*	0.4	0.2
संपत्ति का पंजीकरण				
प्रक्रियाओं की संख्या	5	9	2	2
समय - दिनों की संख्या	44	49/ 68*	2	3.5
लागत (संपत्ति के मूल्य का प्रतिशत)	7.4	8.1/ 7.4*	0.1	0.1
करों का भुगतान				
भुगतान की संख्या	59	10/ 12*	8	7
समय (प्रतिवर्ष घंटे)	271	250/ 254*	70	140
कुल देय कर (सकल लाभ की प्रतिशतता)	64.7	49.7 [#]	32.8	34.6
अनुबंधों को लागू करना				
समय - दिनों की संख्या	1,420	1,445	216	216
लागत (ऋण की प्रतिशतता)	39.6	31	22.4	27.2

स्रोत: व्यवसाय करने के डाटाबेस

*: दिल्ली/मुंबई के लिए निर्दिष्ट मूल्य क्योंकि ये भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा कवर किए गए दो केन्द्र हैं।

रु : भारत द्वारा अपने निगमित कर को 30 से 25 प्रतिशत करने के पूर्व

तालिका 3: ईओडीबी प्राचलों पर भारत विरुद्ध समकक्ष देश (2019)

	भारत	चीन	ब्राजील	इंडोनेशिया
व्यवसाय प्रारंभ करना				
प्रक्रियाओं की संख्या	10	4	11	11
समय-दिनों की संख्या	17/18*	9	17	13
लागत (प्रति व्यक्ति आय की प्रतिशतता)	5.3/ 9.3*	1.1	4.2	5.7
अपनी संपत्ति का पंजीकरण करना				
प्रक्रियाओं की संख्या	9	4	14	6
समय-दिनों की संख्या	49/ 68*	9	31	31
लागत (संपत्ति के मूल्य की प्रतिशतता)	8.1/ 7.4*	4.6	3.6	8.3
करों का भुगतान				
भुगतानों की संख्या	10/ 12*	7	10	26
समय (प्रतिवर्ष घंटे)	250/ 254*	138	1,501	191
कुल देय कर (सकल लाभ की प्रतिशतता)	49.7 [#]	59.2	65.1	30.1
अनुबंधों को लागू करना				
समय-दिनों की संख्या	1,445	496	801	403
लागत (ऋण) की प्रतिशतता)	31	16.2	22	70.3
व्यवसाय करने का समग्र रैंक	63	31	124	73

स्रोत: व्यवसाय करने की रिपोर्ट, 2020

टिप्पणी #: भारत भी संख्या क्रमशः दिल्ली/मुंबई के लिए हैं क्योंकि में भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा कवर किए गए दो केन्द्र हैं।

टिप्पणी *: भारत द्वारा अपने निगमित कर को 30 से 25 प्रतिशत करने से पूर्व

6.13 इसी तरह, जबकि भारत में किसी की संपत्ति का पंजीकृत करने के लिए ब्राजील (14) की तुलना में पांच कम प्रक्रियाएं हैं, भारत (49-68 दिन) की तुलना में ब्राजील (31 दिन) में ऐसा करने में बहुत कम समय लगता है। दूसरी ओर, इंडोनेशिया में केवल छह प्रक्रियाएं हैं और का पंजीकृत करने के लिए ब्राजील के समान समय लगता है।

6.14 करों का भुगतान करने के मामले में, हालांकि इंडोनेशिया में (26) भारत (10-12) की तुलना में प्रतिवर्ष भुगतान की संख्या दुगुनी से अधिक होती है जबकि इसके नागरिक भारत की तुलना में भुगतान करने में कम समय लगाते हैं। ब्राजील की स्थिति इस खंड में विशेष रूप से खराब है।

6.15 अनुबंधों को लागू करने में भारत का कार्यनिष्पादन उसके समकक्ष देशों से तुलना करने पर काफी खराब प्रतीत होता है। जहां एक ओर भारत में किसी अनुबंध को लागू करने के लिए लगभग चार वर्ष लगते हैं, वहीं ब्राजील और इंडोनेशिया में इसको लागू करने के लिए क्रमशः 2.2 एवं 1.1 वर्ष की समयावधि लगती है। अनुबंध को लागू करने में 190 देशों में से 163 रैंक

पर अफगानिस्तान, मोजाम्बिक एवं जिंबाबवे जैसे केवल कुछ देश भारत से भी खराब कार्य-निष्पादन करते हैं।

6.16 व्यवसाय करने के विनियमों को सुगम बनाने के लिए एक समग्र मूल्यांकन और व्यवसाय को पनपने के लिए एक परिवेश प्रदान करने के लिए सतत प्रयास एक मुख्य संरचनात्मक सुधार होगा जोकि भारत को 8-10 प्रतिशत की वार्षिक दर से सतत विकास करने में सक्षम बनाएगा। इसके लिए प्राप्त प्रतिपुष्टि के व्यावहारिक दृष्टिकोण, मॉनीटरन एवं सतत समायोजन की अपेक्षा होगी। अगला खंड, कुछ ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण करता है, जहाँ महत्वपूर्ण दक्षता लाभ की गुंजाइश है।

विनिर्माण में विधिक जटिलता एवं सांविधिक अनुपालन की आवश्यकता

6.17 अधिकांश कंपनियों के समक्ष आने वाली एक बड़ी चुनौती विधिक जटिलता और सांविधिक अनुपालन की अपेक्षाओं सहित भारतीय संविधान के ढांचे की जटिल संरचना है। विनिर्माण इकाइयों द्वारा अनुपालन किए जाने वाले इस प्रकार के

तालिका 4: विनिर्माण के लिए लागू नियम और सांविधिक कानून

क्रम सं०	अधिनियम का नाम (क)	धाराओं की संख्या (ख)	नियमों इत्यादि की संख्या (क+ख)	जोड़
1.	शिक्षु अधिनियम 1961	37	14	51
2.	वायु (प्रदूषण का नियंत्रण एवं निवारक) अधिनियम 1981	54	-	54
4.	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम 1944	40	90	130
5.	केंद्रीय उत्पाद प्रशुल्क अधिनियम 1985	5	-	5
6.	केंद्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956	26	9	35
7.	कंपनी अधिनियम, 2013	470	19	489
8.	ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970	35	83	118
9.	सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962	161	53	214
10.	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975	13	-	13
11.	निक्षेपागार अधिनियम 1961	31	-	31
12.	कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923	36	52	88
13.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948	100	211	311
14.	सेवा योजना कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम 1959	10	8	18

15.	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986	26	88	114
16.	कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952	22	156	178
17.	समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976	18	6	24
19.	कारखाना अधिनियम 1948	120	128	248
20.	विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999	49	102	151
21.	विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992	20	18	38
22.	वित्त अधिनियम 1994	36	43	79
23.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के दिशानिर्देश	-	6	6
24.	आयकर अधिनियम 1961	298	125	423
25.	भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899	78	22	100
26.	भारतीय बायलर अधिनियम 1923	34	626	660
27.	भारतीय विद्युत अधिनियम 2003	185	-	185
28.	भारतीय बेतार अधिनियम 1933	11	13	24
29.	निम्नलिखित के प्रयोग का भारतीय मानक कोड	-	16	16
30.	सुवाह्य प्रथमोपचार अग्नि शामको का चयन, अधिनियम एवं अनुरक्षण	40	80	120
31.	औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947	15	22	37
32.	औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946	57	64	121
33.	विधिक मापविज्ञान अधिनियम, 2009	30	-	30
34.	प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961	31	32	63
35.	न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948	217	164	381
36.	मोटर यान अधिनियम 1939	51	68	119
37.	मादक दवा ओर मनोवैज्ञानिक पदार्थ अधिनियम 1985	15	17	32
38.	उपदान संदाय अधिनियम 1972	161	139	300
39.	पेटेंट अधिनियम 1970	26	13	39
40.	मजदूरी सदाय अधिनियम 1936	40	5	45
41.	बोनस संदाय अधिनियम 1965	31	202	233
42.	पेट्रोलियम अधिनियम 1934	9	-	9
43.	विष अधिनियम 1919	31	334	365
44.	भारतीय प्रतिभूति ओर विनियम बोर्ड अधिनियम 1992	31	21	52
45.	प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956	58	6	64
46.	जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1974)	64	-	64
48.	जल (प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम 1977)	17	9	26
49.	दुकान और प्रतिष्ठा अधिनियम	State-wise	State-wise	State-wise
51.	व्यापार बाजार अधिनियम 1999	159	185	344
Total		3,214	3,582	6,796

स्रोत: एफ आई सीसीआई

टिप्पणी: यह व्यापक सूची नहीं है और न ही प्रत्येक निर्माता के लिए हर नियम लागू होता है। यह मात्र नियमों के व्यापक श्रेणी का एक उदाहरण है जिसका निर्माता सामना करता है।

अधिनियमों की धाराओं/नियमों की संख्या के साथ लागू अधिनियमों के नामों की सूची तालिका 4 में दी गई है। विनिर्माण इकाइयों को 6,796 अनुपालन मदों की पुष्टि करनी होगी जोकि एक थकाऊ एवं समय लगने वाला कार्य है। यह भी नोट किया जाना चाहिए क यह कोई विस्तृत सूची नहीं है और न ही प्रत्येक विनिर्माता पर प्रत्येक नियम लागू होता है। यह केवल उस क्षेत्र द्वारा अनुपालन किए जाने वाली भातिपूर्ण विस्तृत रेंज के नियमों का मात्र एक उद्धरण है।

व्यवसाय शुरू करना: रेस्टोरेंट चलाने में नियामक बाधाएं

6.18 सेवा क्षेत्र में तो सामान्य से व्यवसाय में भी कई नियामक बाधाएं आती हैं। बार और रेस्टोरेंट क्षेत्र विश्व में हर जगह रोजगार एवं विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। स्वभाव से यह एक ऐसा व्यवसाय भी है जिसमें पुराने व्यवसाय को बंद करके बार बार नए व्यवसाय शुरू करने की मजबूरी होती है।

6.19 एक सर्वेक्षण से यह प्रदर्शित हुआ है कि भारत में एक रेस्टोरेंट (भोजनालय) खोलने के लिए अपेक्षित लाइसेंसों की संख्या कहीं अधिक है। जबकि चीन और सिंगापुर को केवल चार लाइसेंसों की जरूरत होती है, भारत को कई और अनिवार्य लाइसेंसों एवं अनुमोदन की जरूरत होती है (यह तुलना तालिका 5 में है और कुछ भारतीय अनिवार्यताएं तालिका-6 में सूचीबद्ध की गई हैं)।

6.20 नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) के अनुसार, बेंगलुरु में रेस्टोरेंट खोलने के लिए कुल 36 अनुमोदन की, दिल्ली में 26, और मुंबई में 22 अनुमोदन अपेक्षित हैं। इसके अलावा, दिल्ली और कोलकाता के लिए एक 'पुलिस ईटिंग हाऊस लाइसेंस' की भी आवश्यकता होती है। दिल्ली पुलिस से यह लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों की संख्या 45 है जो नए हथियारों और अत्यधिक मात्रा में पटाखों की खरीद-फरोख्त करने के लिए लाइसेंस हेतु अपेक्षित दस्तावेजों की संख्या की तुलना में कहीं अधिक है, जो क्रमशः 19 और 12 है (तालिका 7)।

6.21 इसके अलावा, भारत में, केवल किसी सरकारी पोर्टल या सूचना केंद्र से केवल लाइसेंसों और अनुमतियों की सूची प्राप्त की जा सकती है। दूसरी ओर, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड काउंसिल की वेबसाइट (एक निजी थर्ड-पार्टी एजेंसी द्वारा प्रचालित) में एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए अनुमतियों, फीस और घटनाक्रम (टाइमलाइन) के बारे में व्यवसाय के पैमानों के बावजूद विभिन्न व्यवसायों पर उपयोग करने के लिए तैयार व्यवसाय योजना संबंधी टेम्प्लेट्स और व्यापक सूचना से भी सुसज्जित है। यह व्यतिरेक सरकारी नियंत्रण बनाम क्यूरेशन/साझेदारी जैसे दृष्टिकोण में भिन्नता प्रतिबिंबित करता है।

तालिका 5: रेस्टोरेंट खोलने के लिए अपेक्षित लाइसेंस

देश	बाजार का आकार (बिलियन यूएस डॉलर)	लाइसेंसों की संख्या	लाइसेंसों की प्रकृति
भारत	61	12-16*	जैसा कि तालिका-6 में दिया गया है। फूड शॉप का लाइसेंस शराब का लाइसेंस
सिंगापुर	8.3	4	आयात की जाने वाली खाद्य सामग्री का लाइसेंस हलाल प्रमाण पत्र
चीन	815	4	स्वच्छता लाइसेंस पर्यावरण लाइसेंस फायर लाइसेंस बिक्री लाइसेंस

स्रोत: नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई)

टिप्पणी: ये महत्वपूर्ण लाइसेंस हैं/व्यवहार में, प्रत्येक शहर को और अधिक अनुमोदन अपेक्षित हैं जैसा कि टेक्सर (पाठ) में उल्लिखित हैं।

तालिका 6: भारत में रेस्टोरेंट खोलने के लिए मुख्य अनिवार्य लाइसेंस

S. No.	लाइसेंस	प्राधिकारी	दिल्ली	मुंबई	बैंगलुरु	कोलकाता
1.	खाद्य सुरक्षा	एफ.एस.एस.ए.आई.	हां	हां	हां	हां
2.	स्वास्थ्य/व्यापार	नगरपालिका निगम	हां	हां	हां	हां
3.	पुलिस इटिंग हाऊस लाइसेंस	पुलिस कमिश्नर प्राधिकारी	हां	हां	हां	हां
4.	फायर एन.ओ.सी.	अग्निशामक विभाग	हां	हां	हां	हां
5.	दूकानें एवं स्थापना संबंधी लाइसेंस शराब संबंधी	श्रम विभाग	हां	हां	हां	हां
6.	लाइसेंस (यदि शराब सर्व किया जाता है)	उत्पाद शुल्क विभाग	हां	हां	हां	हां
7.	पर्यटन लाइसेंस (शराब परोसने)	पर्यटन विभाग	हां			
8.	ग्रीस ट्रेप/ईटीपी के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी हेतु (जल प्रदूषण अधिनियम)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	हां			हां
9.	जेन सेट्स के लिए पर्यावरण संबंधी मंजूरी हेतु (वायु प्रदूषण अधिनियम)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	हां			हां
10.	भारत और माप	विधिक माप-पद्धति विभाग	हां	हां	हां	हां
11.	संगीत संबंधी लाइसेंस	भारत सरकार द्वारा पंजीकृत कॉपीराइट सोसाइटियां	हां	हां	हां	हां
12.	चेतावनी या निर्देशक लाइसेंस	नगरपालिका निगम	हां	हां	हां	हां
13.	जी.एस.टी./वैट पंजीकरण लाइसेंस	जी.एस.टी./कर संबंधी प्राधिकारियां	हां	हां	हां	हां
14.	कर्मचारी राज्य बीमा पी. एफ. (भविष्य निधि)	श्रम/भविष्य निधि आयुक्त	हां	हां	हां	हां
15.	लिफ्ट संबंधी लाइसेंस (यदि लिफ्ट लगाया गया हो)	विद्युत निरीक्षक	हां	हां	हां	हां
16.	डिलिवरी बाइक्स संबंधी लाइसेंस (यदि नियोजित हैं)	एफ.एस.एस.ए.आई.	हां	हां	हां	हां

स्रोत: नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एन.आर.ए.आई.)

तालिका 7: दिल्ली पुलिस से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज

लाइसेंस का प्रकार	अपेक्षित दस्तावेजों की संख्या
खाने और अस्थाई आवास की स्थापना से संबंधित लाइसेंस	45
नए हथियार संबंधी लाइसेंस	19
पटाखों से संबंधित लाइसेंस	12

स्रोत: दिल्ली पुलिस लाइसेंसिंग.

निर्माण अनुज्ञा

6.22 तालिका 8 यह दर्शाता है कि दिल्ली में फ़ैक्ट्री/वेयर हाउस इमारत को स्थापित करने के लिए प्रक्रिया में शामिल समय और लागत के अतिरिक्त लाइसेंस और परमिट प्राप्त करना, निर्माण पूरा होने पर उससे संबंधित अधिसूचना एवं निरीक्षण और उपयोगिता कनेक्शन प्राप्त करना आवश्यक है।

6.23 जब श्रेणियों में उत्तम के साथ तुलना की जाती है-निर्माण परमिट शीघ्र प्राप्त करने के मामले में विश्व बैंक की रैंकिंग के अनुसार हॉंगकॉंग सबसे ऊपर है, जो कि केवल दो महीने से कुछ अधिक समय

निर्माण कार्य से सम्बन्धित परमिट देने में करता है, जबकि दिल्ली में निर्माण कार्य सम्बन्धित परमिट प्राप्त करने में लगभग चार महीने लगते हैं) साफ़ ही पानी एवं सीवर कनेक्शन मिलने में 35 दिनों का समय और लगता है।

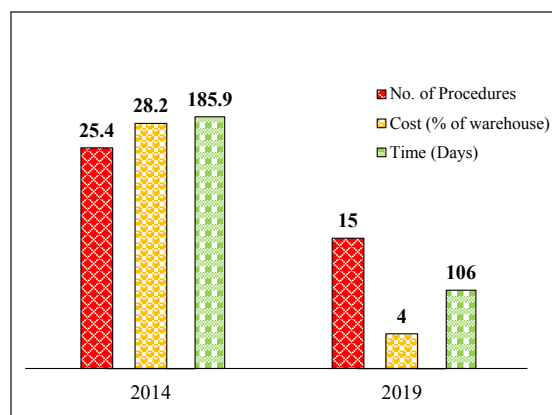
6.24 हॉलाकि फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले पांच वर्षों में भारत ने निर्माण कार्य से सम्बन्धित परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर सुधार किया है। 2014 की तुलना में वेयरहाउस (गोदाम) लागत 186 दिन और 28.2 प्रतिशत थी; वही 2019 में वेयरहाउस लागत (चित्र 1) 98-113.5 दिन और 2.8-5.4 प्रतिशत रही है।

तालिका 8: निर्माण परमिट - दिल्ली बनाम हॉंग काँग

DELHI, INIDA (RANK 27)	Days	Days	HONG KONG (RANK 1)
Submit online Common Application Form along with requisite building permit fees and drawings	0.5	45	Obtain approval by submitting applications to the One Stop Center
Request & obtain release of building sanction plans	30	1	Receive inspection by Building Dept. on foundation strata
Submit online notice of completion up to the plinth level and get inspection done	15.5	1	Request and receive inspection on the superstructure construction
Submit notice of completion, receive final inspection & obtain Fire NOC	2.5	1	Receive an audit inspection by the Building Department
Obtain completion/occupancy permit	30	1	Submit notification of project completion and relevant applications
Request water and sewer connection approval and inspection	35	18	Obtain relevant certificates through the One Stop Center
		1	Receive joint & final inspection of licensing authorities; Obtain Water & Sewerage connection
113.5 Days		Time Taken	69 Days
2.8		Cost (% of Warehouse)	0.3

स्रोत: व्यवसाय डाटाबेस

चित्र 2: भारत में निर्माण कार्य से सम्बन्धित परमिट मिलने की लागत



स्रोत: व्यवसाय डाटाबेस

व्यापार के बड़े पैमाने को प्राप्त करना

6.25 भारत में व्यवसाय कार्य क्षमता से सम्बन्धित मामले में मुख्य समस्या पैमानों (स्केल) की है। अधि तर निर्माण इकाईयों की क्षमता कम होती है, और इस तरह कम निर्माण क्षमता होने की हानि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर पड़ती है। बंगलादेश, चीन, वियतनाम जैसे देशों ने घरेलू उत्पादन क्षमता और सुपुर्दगी करने के समय को बेहतर किया है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा के द्वारा अपनी महत्ता को बढ़ाया है।

6.26 बांग्लादेश, चीन और वियतनाम की तुलना में बड़े उद्यमों द्वारा किए जा रहे निर्यात का बाजार मूल्य 80 प्रतिशत से अधिक है, और भारत में छोटे उद्यमों का 80 प्रतिशत है। हालांकि भारत में माल पत्तन तक पहुंचने में 7-10 दिनों का समय लगता है, जबकि चीन, बंगलादेश और वियतनाम जैसे देशों में पत्तन तक पहुंचने में एक दिन से कम का समय लगता है (तालिका 9)। इस तरह भारतीय आपूर्ति श्रृंखला में बड़ी मात्रा में छोटे खेप अपर्याप्त माल मार्ग के कारण रुके पड़े होते हैं। समय लगने की साथ तुलना (जो कि आदेश से सुपुर्दगी तक का समय है) नीचे दी गया है।

तालिका 9: साजो समान (संयारिकी) और पैमाने (स्केल) की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के साथ तुलना

	बंगलादेश	चीन	भारत	वियतनाम
कार्यका पैमाना	80% बड़े उद्यम	80% से अधिक बड़े उद्यम	80% छोटे उद्यम	80% से अधिक बड़े उद्यम
लगा समय (दिनों में) (ऑर्डर से डिलीवरी तक)	50	31	63	46
पत्तन तक पहुंचने के लिए लिया गया, समय दिनों में	1	0.2	7-10	0.3

स्रोत: उच्च स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी) रिपोर्ट

सीमापार व्यापार

6.27 सीमापार व्यापार संकेतक सामग्रियों (माल) के निर्यात और आयात की दुलाई संबंधी प्रक्रिया से संबद्ध समय और लागत का अभिलेख दर्शाते हैं। वैश्विक रूप से, पत्तनों द्वारा माल की दुलाई सर्वाधिक पंसदीदा साधन है और उसके बाद रेलवे और फिर सड़के को तरजीह दी जाती है, जबकि भारत में इसकी स्थिति विपरीत है।

6.28 इटली सीमापार व्यापार में ईओडीपी रैंकिंग में सबसे ऊपर है। तालिका 10 में भारत से इसकी तुलना की गई है। जहां भारत से क्रमशः मामले में निर्यातों और आयातों के लिए सीमा पर और दस्तावेजीय अनुपालन में क्रमशः 60-68 और 88-82 घंटे का समय लगता है, वहीं इटली में प्रत्येक के लिए केवल एक घंटे का ही समय लगता है। इसके अलावा, इटली में अनुपालन लागत शून्य आती है भारत के मामले में, इसकी लागत क्रमशः निर्यातों और आयातों के लिए 260-281 यूएस डॉलर और 360-373 यूएस डॉलर आती है।

6.29 यह नोट किया जाना चाहिए कि लगभग 70

प्रतिशत विलंब (निर्यातों और आयातों दोनों में) पत्तन अथवा सीमा की ऐसी हैंडलिंग प्रक्रियाओं के कारण होता है जो अनिवार्यतः प्रक्रियात्मक जटिलताओं (व्यापार के लिए अपेक्षित प्रक्रियाओं की अनेकता और विविधता), विविध दस्तावेजीय प्रक्रियाओं तथा अनुमोदन और अनुमति के लिए विविध एजेंसियों की कार्रवाई से संबंधित होती है। यह भी देखा गया है कि समय विलंब और प्रक्रियात्मक अक्षमताओं से अंततः व्यापार की लागत में वृद्धि होती है।

6.30 यद्यपि भारत ने डिजिटलीकरण में वृद्धि करके और विविध एजेंसियों का एकल डिजीटल प्लेटफार्म में संधि रहित रूप में एकीकरण करके प्रक्रियात्मक और दस्तावेजीय अपेक्षाओं को पहले ही कम कर दिया है किंतु इन प्रक्रियात्मक अक्षमताओं को और भी कम किया जा सकता है और प्रयोक्ता अनुभव में अत्यधिक सुधार लाया जा सकता है। संलग्न बॉक्स में उस प्राथमिक आर्थिक प्रचालक स्कीम पर चर्चा की गई है जिसे पंजीकृत निर्यातकों/आयातकों के लिए प्रक्रिया को खरल बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है।

तालिका 10: सीमापार व्यापार: दिल्ली और इटली

INDIA (RANK 68)	Hours		Hours	ITALY (RANK 1)
	Delhi	Mumbai		
EXPORT 1: Border Compliance	54	50	0	EXPORT 1: Border Compliance
2: Documentary Compliance	6	18	1	2: Documentary Compliance
IMPORT 1: Border Compliance	70	60	0	IMPORT 1: Border Compliance
2: Documentary Compliance	18	22	1	2: Documentary Compliance
INDIA (RANK 68)	Cost (US\$)		Cost (US\$)	ITALY (RANK 1)
	Delhi	Mumbai		
EXPORT 1: Border Compliance	195	231	0	EXPORT 1: Border Compliance
2: Documentary Compliance	65	50	0	2: Documentary Compliance
IMPORT 1: Border Compliance	260	273	0	IMPORT 1: Border Compliance
2: Documentary Compliance	100	100	0	2: Documentary Compliance

स्रोत: व्यापार करने से संबंधित डाटाबेस

टिप्पणी: भारत की संख्या क्रमशः दिल्ली/मुंबई के लिए हैं क्योंकि ये भारत के लिए विश्व बैंक द्वारा कवर किए जा रहे दो केन्द्र हैं।

बॉक्स 1: प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (ईओ)

प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (ईओ) वैश्विक व्यापार को सुरक्षित करने और सुविधाजनक बनाने के लिए विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्ल्यूसीओ) सुरक्षित मानक फ्रेमवर्क के तत्वावधान में संचालित एक कार्य क्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा में वृद्धि करना और माल के आवागमन को सुकर बनाना है। ईओ अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में अनेक कारोबारी शामिल हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लगे प्रतिष्ठान को सीमा शुल्क द्वारा आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा मानकों के अनुपालनकर्ता के रूप में अनुमोदित किया जाता है और उसे प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक की हैसियत प्रदान की जाती है। प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक की हैसियत रखने वाले प्रतिष्ठान को एक 'सुरक्षित' व्यापारी और एक विश्वसनीय व्यापारी परिसर के रूप में माना जाता है। ईओ एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है। यह भारतीय सीमाशुल्क को अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला के मुख्य पणधारियों, अर्थात्, आयतकों, निर्यातकों, कर्मचारियों और माल की व्यवस्थाकर्ताओं, संरक्षकों अथवा सीमा तक प्रचालकों, सीमा शुल्क दलालों और माल गोदाम प्रचालकों के उचित सहयोग के माध्यम से कार्गो सुरक्षा में वृद्धि करने और उसे सरल एवं कारगर बनाने में समर्थ करता है, जो सीमा शुल्क के प्राधिकारियों से अधिमान्य व्यवहार की दृष्टि से लाभ पहुंचाते हैं। इन लाभों में क्लियरेंस समय में शीघ्रता, कम जांच, आपूर्ति चेन के भागीदारों के मध्य उन्नत सुरक्षा और संप्रेषण जैसे लाभ और अन्य लाभ शामिल हैं। परिपत्र संख्या ईओ प्रोग्राम-सीमा शुल्क दिनांक 22 जुलाई, 2016 में ईओ कार्यक्रम के लिए सांविधिक ढांचा दिया गया है। वर्ष 2018 में, सीमा शुल्क प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (ईओ) की प्रक्रिया को और भी उदारीकृत, सरलीकृत और युक्तिसंगत किया है। आयातों और निर्यातों के लिए नए प्राधिकृत, आर्थिक प्रचालक (ईओ) कार्यक्रम में प्रमाणन के तीन स्तर हैं,

1. ईओटी 1-केवल दस्तावेज प्रस्तुतीकरण के आधार पर सत्यापित।
2. ईओटी 2-दस्तावेज सत्यापन के अतिरिक्त, स्थल सत्यापन भी किया जाता है।
3. ईओटी 3-उन ईओटी2 कारकों के लिए जिन्होंने दस्तावेज सत्यापन के आधार पर केवल दो वर्ष के लिए इस हैसियत का लाभ उठाया है और उन ईओटी 2 धारकों के लिए जिन्होंने इस हैसियत का लगातार लाभ नहीं उठाया है अथवा जिन्होंने कारोबार लगातार लाभ नहीं उठाया है अथवा जिन्होंने कारोबार में बड़े परिवर्तन किए हैं, आवेदक प्रत्यक्ष सत्यापन के अधीन होता है।

कर्मचारियों और माल के व्यवस्थाकर्ताओं, संरक्षकों, अथवा सीमा तक प्रचालकों, सीमाशुल्क दलालों और मालगोदाम प्रचालकों के लिए केवल एक स्तर ही है;

ईओ एलओ-यहां दस्तावेज सत्यापन के अतिरिक्त स्थल सत्यापन भी किया जाता है।

ईओ/प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक प्रमाणन के लिए कौन हकदार होता है

अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में शामिल कोई ऐसा व्यक्ति जो लागत में सीमा शुल्क से जुड़ी गतिविधियां निष्पादित करता है, कारोबार के आकार पर ध्यान दिए बिना ईओ हैसियत के लिए आवेदन कर सकता है। इनमें निर्यातक, आयातक कर्मचारी और माल की व्यवस्थाकर्ता (उदाहरण के लिए कैरियर, एयरलाईस, माल अग्रेषक आदि), संरक्षक अथवा सीमांतक प्रचालक, सीमाशुल्क ग्रह के एजेंट और माल गोदामों के स्वामी शामिल हो सकते हैं। अन्य जो इसके लिए अर्हक हो सकते हैं, उनमें पत्तन प्रचालक, प्राधिकृत कोरियर, जहाज का माल उतारने-चढ़ाने वाले शामिल हैं। यह सूची संपूर्ण नहीं है।

पात्रता:

कोई ऐसा विधिक प्रतिष्ठान जो सीमाशुल्क से संबद्ध कार्य निष्पादित करता है, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता है तो प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक (ईओ) कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं।

1. उन्होंने पिछले वित्त वर्ष में 25 आयात अथवा निर्यात दस्तावेजों को हैंडल किया हो।
2. उनकी कारोबारी गतिविधियां पिछले तीन वर्ष से चल रही हो (इस शर्त को पात्र मामलों में छोड़ा जा सकता है)।
3. आवेदक पिछले तीन वित्त वर्षों से वित्तीय रूप से सुदृढ़ रहा होना चाहिए।
4. आवेदक को धोखाधड़ी, जालसाजी, प्रत्यक्ष तस्करी, उत्पादशुल्क योग्य माल को अवैधरूप से ले जाने अथवा ऐसे मामलों के लिए जहां सेवा कर की उगाही ग्राहकों से ऐसे मामलों के लिए जहां सेवा कर की उगाही ग्राहकों से की गई है किंतु पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान सरकार के पास जमा नहीं की गई है, आदि के मामले में सम्मिलित होने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया होना चाहिए।

कोई प्रतिष्ठान हमारी वेबसाइट <http://www.aecoindia.gov.in> द्वारा 'ईओटी 1 प्रमाणन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।

17 जनवरी, 2020 की स्थिति के अनुसार भारत में ईओ प्रमाणित प्रतिष्ठान

ईओ स्तर	ईओ हैसियत धारकों की संख्या
ईओटी 1	2,842
ईओटी 2	491
ईओ 3	8
ईओ एलओ	745
कुल	4,086

स्रोत: सीबीआईसी

विशिष्ट खंडों में संभारतंत्र में भारत के निष्पादन का केस अध्ययन

6.31 इस खंड में आपूर्ति-श्रृंखला में उन विशिष्ट बिन्दुओं को समझने के उद्देश्य से जिनमें अपसामान्य विलंब और व्यवधान का अनुभव किया जाता है, गुणता परिषद अक्टूबर-दिसंबर, 2019 में किए गए प्रकरण अध्ययन और उद्योग समीक्षा के परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं।

I-परिधान निर्यात करने का प्रकरण अध्ययन

6.32 इस केस अध्ययन के अंतर्गत दिल्ली में एक गैर ईओ परिधान फैक्ट्री से प्रेषणों पर दृष्टि रखी जाती है,

जो कि (बॉक्स 1), जो अपने उत्पादों को मैन यूएस को न्हावा शेवा, महाराष्ट्र जो कि भारत का सबसे बड़ा सागर पत्तन है, के माध्यम से निर्यात करता है।

6.33 अध्ययन से पता चला है कि खेप के दिल्ली में फैक्ट्री गेट से बाहर निकलने के पश्चात् जेएनपीटी पहुंचने में पांच दिन का समय लगता है। न्हावा शेवा में तो छः प्रक्रियाओं से गुजरने में 14 दिन तक का समय लग सकता है, जिसमें से एक या दो दिन का समय पोर्ट पर स्थान की उपलब्धता के आधार पर केवल सामान उतारने में लग जाता है। इसके बाद तीन दिन का समय 'सीमा शुल्क निकासी' में अन्य तीन दिन 'कंटेनरों के भरने में तथा पांच दिन तक का समय 'शिप में प्रवेश

हेतु' कतार में लग जाता है। ऐसा आंशिक रूप से कंटेनरों के अंतर्वाह को संभालने हेतु पोर्ट पर अपर्याप्त अवसंरचना, सड़कों की कम भार वहन क्षमता के कारण है। हालांकि,

इसमें अधिक विलंब कार्य प्रक्रियाओं के सही दिशा में नहीं होने के कारण होता है जिससे "तत्काल" प्रोटोकॉल की अनुमति नहीं मिल पाती है। प्रत्येक चरण को पूरा

तालिका 11: दिल्ली से मेन, युनाइटेड स्टेट्स जाने के दौरान किसी ऐम्पेरल एक्सपोर्ट परिधान निर्यात खेप का विवरण

	स्थान	कार्रवाई	दिन	दिनों की संख्या
भारत				
19 दिन भारत में	दिल्ली	फैक्टरी में तैयार शिपमेंट	दिन 1	
	दिल्ली हरियाणा गुजरात महाराष्ट्र न्हावा शेवा, महाराष्ट्र	ट्रक/ट्रेन के द्वारा जेएनपीटी तक खेप का यातायात	दिन 1-5	5 दिन
	न्हावा शेवा, महाराष्ट्र	खेप का जेएनपीटी पहुंचना (क) उतराई (ख) सीमा शुल्क निकासी (ग) कंटेनर में (घ) शिप में प्रवेश हेतु कतार में लगना (ङ) शिपिंग लाइन को हैंडओवर करना (च) शिप का प्रस्थान	दिन 5	14 दिनों तक
			दिन 5/6	
			दिन 6/7-8	
			दिन 8/9-12	
			दिन 12/13-17	
			दिन 17/18	
दिन 18/19				
19 दिन खुले सागर में	खुला सागर	समुद्र में शिप की यात्रा	दिन 18/19-दिन 38	19 दिन
	युनाइटेड स्टेट्स			
3 दिन संयुक्त राष्ट्रीय में	ह्यूस्टन, यूएसए	पोर्ट पर पहुंचना	दिन 38	3 दिन
		सीमा शुल्क विभाग द्वारा अनापत्ति (यह देखते हुए कि सभी विलेख सही हैं और निरीक्षण का परिणाम उपयुक्त रहा है।	दिन 38/39	
		लदान और प्रस्थान	दिन 39	
	मेन, यूएसए	यूएस में क्रेता के पास पहुंचना	दिन 40/41	

स्रोत: क्यूसीआई संगणना

करने हेतु आवश्यक समय की अनिश्चिता का अर्थ है कि निर्यातकों को इंतजार में समय व्यतीत करने हेतु तैयार रहना पड़ता है। इससे पोर्ट पर स्थान अवरूद्ध होता है।

6.34 एक बार शिप के पोर्ट से निकल जाने के बाद, खेप 19 दिनों तक समुद्र के रास्ते चलकर 38वें दिन ह्यूस्टन, यू.एस. पहुंचता है। यहां सीमा शुल्क विभाग को सभी कागजात और विनियामक अपेक्षाएं पूरी होने

की स्थिति में रूप को क्लीयर करने में अधिकतम एक दिन का समय लगता है। इसके बाद वह दो दिनों के भीतर खरीदार के मालगोदाम में पहुंचता है।

6.35 संक्षेप में, फैक्ट्री से मालगोदाम तक पहुंचने में लगे कुल 41 दिनों में 19 दिन भारत में खर्च हुए, 19 दिन समुद्री यात्रा में तथा 3 दिन यूनाइटेड स्टेट्स में लगे। इसमें सुधार की स्पष्ट गुंजाइश है।

तालिका 12: मिर्जापुर से न्यूजर्सी पहुंचने के दौरान कॉर्पेट निर्यात खेप का विवरण

स्थान	कार्यकलाप	दिन	दिनों की संख्या	
भारत (कंटेनर लोड से कम (एलसीएल) शिपमेंट) -एईओ				
भारत में 13 दिन	मिर्जापुर, उ.प्र.	खेप का फैक्ट्री में तैयार होना	दिन 1	दिन 1
	मिर्जापुर, उ.प्र. पियाला हरियाणा	खेप को ट्रक के द्वारा आईसीडी, पियाला, ले जाना	दिन 1-3	2 दिन
	पियाला (हरियाणा)	खेप का पियाला पहुंचना	दिन 3	4 दिन
		सीमा शुल्क द्वारा अनापत्ति	दिन 3/4	
		ट्रेन द्वारा मुंधरा बंदरगाह के लिए प्रस्थान	दिन 4-7	
	रेल यातायात	रेल यातायात	दिन 7	
	रेल यातायात	खेप को ट्रेन द्वारा मुंधरा की कतार	दिन 7-10/11	दिन 3-4
मुंधरा बंदरगाह (गुजरात)	मुंधरा बंदरगाह गुजरात	दिन 11 (6-7 घंटे)	2 दिन	
	पोत की लोडिंग	दिन 11-13		
	पोत का प्रस्थान	दिन 13		
22 दिन हाइ-सी	हाइ-सी	पोत का प्रस्थान	दिन 13-दिन 35/36	22/23 दिन
संयुक्त राज्य अमेरिका				
अमेरिका में 5 दिन	न्यू यॉर्क बन्दरगाह	बंदरगाह/पोर्ट	दिन 36	4-5 दिन
		सीमा शुल्क (सभी दस्तावेजों के ठीक पाए जाने पर और निरीक्षण के सुरक्षित परिणाम आने पर)	दिन 36-39	
	सड़कमार्ग द्वारा	न्यू जर्सी गोदाम से परिवहन	दिन 39/40	
	न्यू जर्सी	खेप, ब्यावर स्थित फैक्ट्री पहुंचता है।	दिन 40	

स्रोत: क्यूसीआई परिकलन

II निर्यात होने वाले कार्पेट का केस अध्ययन

6.36 इसी प्रकार का एक प्रयास कार्पेट विनिर्माताओं के संबंध में किया गया था, जो मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से न्यू जर्सी, यू.एस. को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों के एईओ हैं (तालिका 12)

6.37 शिपमेंट के मिर्जापुर में फैक्ट्री से निकलने के पश्चात् इसे पियाला, हरियाणा में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आईसीडी) में पहुंचने में दो दिनों का समय लगता है। आईसीडी में सीमा शुल्क विभाग द्वारा कंसाइनमेंट को क्लीयर करने में एक दिन का समय लगता है। अगले तीन दिनों में कंसाइनमेंट को कंटेनरों में भरकर मुंधरा भेज दिया जाता है।

6.38 शिपमेंट को ट्रेन द्वारा मुंधरा बंदरगाह ले जाने में तीन से चार दिनों का समय लगता है। इसके अलावा, 6-7 घंटे का समय बंदरगाह में प्रवेश हेतु कतार में लग जाता है। अगले दो दिनों में पोत का लदान किया जाता है और शिप 13वें दिन प्रस्थान करता है। शिप को न्यूयार्क बंदरगाह पर पहुंचने में लगभग 23 दिनों का समय लगता है और वह 36 वें दिन पहुंचता है। इसके बाद सीमा-शुल्क द्वारा अनापत्ति प्राप्त होने और क्रेता तक पहुंचने में 4-5 दिनों का समय लगता है।

6.39 संक्षेप में, इन 40 दिनों में से भारत में 13 दिनों का समय व्यतीत होता है, अन्य 22 दिनों का समय समुद्र में यात्रा के दौरान लगता है तथा 4-5 दिनों का समय खेप के न्यू जर्सी में अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने से पूर्व यू.एस. में लगता है। यद्यपि भारत से किसी शिपमेंट में लगने वाले दिनों की संख्या में एईओ के रूप में उल्लेखनीय कमी (पूर्व के मामले की तुलना में) आने के बाद भी इसमें अब भी अत्यधिक समय लगता है।

III आयातित कालीनों के -मामले का अध्ययन

6.40 माल के प्रवाह प्रक्रिया को समझने का एक और तरीका यह है कि इसे उल्टा करके देखें। यह केस अध्ययन मिलन, इटली से ब्यावर, राजस्थान के एक गोदाम में कालीनों का आयात करते समय सम्मिलित समयवधि का विवरण है। (तालिका 13)

6.41 मिलान में फैक्ट्री के गेट पर शिपमेंट तैयार होने के बाद, 773 किलोमीटर दूर नेपल्स तक खेप के परिवहन/

में केवल 10 घंटे लगते हैं। कस्टम क्लीयरेंस में सिर्फ दो घंटे खर्च होते हैं और फिर जहाज को लोड करने में केवल एक घंटे का समय लगता है। इसका मतलब यह है कि खेप को फैक्ट्री से जहाज तक पहुंचाने में एक दिन से भी कम समय लगता है। आसानी से/ “सही समय पर” चलने वाली प्रक्रियाओं के कारण ऐसा करना संभव है। इसके बाद जहाज 23 दिनों तक खुले सागर में बिताता है तथा 24वें दिन गुजरात में मुंधरा बंदरगाह पर पहुंचता है। अगले छह दिन मुंधरा बंदरगाह पर बिताए जाते हैं, जिनमें से लगभग दो दिनों का उपयोग बंदरगाह के बाहर खड़े रहकर, प्रवेश के इंतजार में किया जाता है, इसके बाद कस्टम क्लीयरेंस में और दो दिन लगते हैं और बंदरगाह से बाहर निकलने के लिए 6/7 घंटे तक कतार लगती है। अंत में, खेप, सड़क मार्ग से यात्रा के दो दिनों सहित, 31 वें दिन अपने अंतिम गंतव्य स्थल, ब्यावर, राजस्थान तक पहुँचता है। इस प्रकार, भारत में सीमा अनुपालन का पालन करने और खेप, खरीदार तक पहुंचने से पहले यात्रा अवधि में 8 दिन लगते हैं।

6.42 यदि संक्षेप में कहा जाए तो, जहां पर इटली में परिवहन और सीमा अनुपालन और प्रलेखन कार्य को पूरा करने में केवल एक दिन का समय लगता है, वहीं दूसरी ओर भारत में आयात प्रक्रिया को पूरा करने में आठ दिन लग जाते हैं (ध्यान दें कि इस अध्ययन के लिए आयातक एक अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर थे)। बहरहाल, यह दिलचस्प बात है कि आयात प्रक्रिया में निर्यात प्रक्रिया की तुलना में कम समय लगता है।

6.43 परिभाषा के अनुसार, एक केस स्टडी दृष्टिकोण के परिणाम, नमूना आकार द्वारा सीमित होते हैं, लेकिन उपरोक्त परिणाम, क्यूसीआई द्वारा आयातकों और निर्यातों के एक विस्तृत समूह से बात करके सत्यापित किए गए थे ताकि यह पुष्टि हो सके कि एकत्र किए गए डेटा मोटे तौर पर उनके अनुभव के अनुरूप हैं। इसने निम्नलिखित की पुष्टि की: (क) भारतीय समुद्री बंदरगाहों में लदान और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं में अत्यधिक देरी, (ख) विडम्बना से आयात-प्रक्रियाएं, निर्यात-प्रक्रियाओं से बेहतर हैं, (ग) प्रक्रिया अवधि में बड़े अंतर का मतलब यह है कि प्रतीक्षा अवधि में अनावश्यक विस्तार की वजह से निर्यात में अनिश्चितता आ जाती है। इसका मतलब यह है कि विश्वसनीयता में सुधार किए बिना केवल “औसत/एवरेज” में सुधार करना पर्याप्त नहीं है।

6.44 यह ध्यान देने योग्य है कि भारत में जहाजों के वापसी समय में निरंतर कमी हो रही है। यह 2010-11 के 4.67 दिन से 2018-19² में घट कर 2.48 दिन हो गई है। इससे स्पष्ट है कि बन्दरगाहों के मामले में

महत्वपूर्ण दक्षता लाभ संभव है। यद्यपि चैनई बन्दरगाह का पूर्ण अध्ययन तो नहीं किया गया किन्तु आंशिक जानकारी यही सुझाती है कि यहां प्रक्रियाएं ऊपर चर्चित बन्दरगाहों की अपेक्षा अधिक सुचारू हैं।

तालिका 13: मिलान से ब्यावर तक एक कालीन आयात खेप पर नज़र रखना

	स्थान	कार्रवाई	समय	दिनों/घंटों की संख्या	
इटली					
इटली में 13 घंटे	मिलान	मिलान में फैक्टरी/कारखाने पर शिपमेंट तैयार			
	मिलान बोलोगना रोम नेपल्स (773 किमी)	खेप को नेपल्स ले जाना	दिन 1	10 घंटे	
	नेपल्स	कस्टम क्लियरेंस दस्तावेजी अनुपालन	दिन 1	2 घंटे	
		जहाज का प्रस्थान समुद्र में यात्रा करने वाला	दिन 1	1 घंटा	
23 दिन हाइ-सी	हाइ-सी	समुद्र में यात्रा करने वाला	दिन 2-24	23 दिन	
भारत-प्राधिकृत आर्थिक प्रचालक/ऑपरेटर					
भारत में 8 दिन	मुंधरा बन्दरगाह (गुजरात)	मुंधरा सी-बन्दरगाह खेप समुद्र किनारे	दिन 24	6 दिन	
		पोत प्रवेश से पहले बंदरगाह के बाहर प्रतीक्षा	दिन 24-26		
		बंदरगाह पर लदान उतारना	दिन 26		
		कस्टम क्लीयरेंस	बन्दरगाह पर खेप को संभालना		दिन 27
			बन्दरगाह अधिकारियों द्वारा किए गए सुरक्षा निरीक्षणों को क्लीयर करना		दिन 28
		ट्रक द्वारा खेप, व्यावर राजस्थान भेजना	दिन 29 (6-7 घंटे)		
	सड़क मार्ग से	ट्रक द्वारा खेप, व्यावर राजस्थान भेजना	दिन 29	2 दिन	
	ब्यावर (राजस्थान)	खेप, ब्यावर स्थित फैक्ट्री पहुंचता है।	दिन 31		

स्रोत: क्यूसीआई परिकलन

IV इलेक्ट्रॉनिक्स केस स्टडी

6.45 यद्यपि समुद्री-बंदरगाहों पर कार्यविधियां बहुत ही अदक्ष हैं, लेकिन ठीक इसके उलट हवाई अड्डों पर कार्यविधियों में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है। वास्तव में, बैंगलुरु स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी पर एक केस अध्ययन किया गया। उक्त इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आईओ-टी2 प्रमाणित है। अध्ययन में यह पाया गया कि भारतीय प्रणाली विश्व स्तर की हो सकती है। अध्ययन से इस बात की भी जानकारी मिलती है कि कैसे 2016 में ए ई ओ नीति के लागू होने के बाद कुछ क्षेत्रों में कारोबारी माहौल बदल गया है।

6.46 सारणी 14(क) और (ख) में बैंगलुरु से हांगकांग को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करने में लगने वाले समय की तुलना आईओ पंजीकरण के साथ और

बगैर-आईओ पंजीकरण के साथ की गई है। एक बार बैंगलुरु में कारखाने में शिपमेंट तैयार हो जाने के बाद, इसे कम्पेगौड़ा हवाई अड्डे तक ले जाने में तीन घंटे लगते हैं। अब तक, आईओ और बगैर-आईओ के बीच कोई अंतर नहीं है। हालांकि, सीमा-शुल्क और जांच प्रक्रिया के लिए हवाई अड्डे पर बिताया गया कुल समय आईओ-टी 2 ऑपरेटरों के लिए सिर्फ दो घंटे का है। बगैर आईओ-टी 2 ऑपरेटरों को 6 घंटे का समय लगता है।

6.47 वास्तव में आईओ को लागू करने के बाद हांग-कांग (सात घंटे) की तुलना में भारत (छह घंटे) में बिताए गए कुल समय की अवधि कम होती है। इससे पता चलता है कि सही नीतियों की सहायता से भारत अंतर्राष्ट्रीय मानक हासिल कर सकता है या उससे भी बेहतर कर सकता है।

तालिका 14 (क): बंगलौर से हांगकांग तक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात खेप का विवरण (गैर-ए ई ओ)

	स्थान	कार्रवाई	समय
भारत: गैर-प्राधिकृत इकोनोमिक ऑपरेटर			
भारत में 10 घंटे	बैंगलुरु, कर्नाटक	कारखाने में खेप	
	गोदाम से कम्पेगौड़ा हवाई अड्डे बैंगलुरु (दूरी - 70 कि.मी)	ट्रक के माध्यम से हवाई अड्डे के लिए खेप का परिवहन	3 घंटे
	शिपमेंट हवाई अड्डे पर पहुंचा	निर्यात टर्मिनल एंट्री	1 घंटे
		कस्टम-पंजीकरण	2 घंटे
		जांच एवं शिपिंग बिल का निर्यात	4 घंटे
5 घंटे फ्लाइट	एयर ट्रेवल		5 घंटे
हांगकांग			
7 घंटे में हांगकांग	हांगकांग	हांगकांग हवाई अड्डा पर पहुंचा	
	कस्टम क्लियरेंस	जांच पास आउट आदेश	4 घंटे
	सड़क यात्रा	हवाई अड्डे से गोदाम तक परिवहन	3 घंटे

स्रोत: समीक्षा-परिकलन

2. आर्थिक समीक्षा 2019-20 अध्याय 9, खंड-2

तालिका 14 (ख): बंगलौर से हांगकांग तक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात खेप का विवरण (गैर-एईओ)

	स्थान	कार्रवाई	समय
भारत: गैर-प्राधिकृत इकोनोमिक ऑपरेटर 2			
भारत में 6 घंटे	बैंगलूरु, कर्नाटक	कारखाने में खेप	
	गोदाम से केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे, बैंगलूरु (दूरी - 70 कि.मी)	ट्रक के माध्यम से हवाई अड्डे के लिए खेप का परिवहन	3 घंटे
	खेप हवाई अड्डे पर पहुंचा	निर्यात टर्मिनल एंट्री	1 घंटे
		कस्टम-पंजीकरण	1 घंटे
		जांच एवं शिपिंग बिल का निर्यात	1 घंटे
5 घंटे फ्लाइट	एयर ट्रेवल		5 घंटे
हांगकांग			
7 घंटे फ्लाइट	हांगकांग	हांगकांग हवाई अड्डा पर पहुंचा	
	कस्टम क्लियरेंस	जांच पास आउट आदेश	4 घंटे
	सड़क यात्रा	हवाई अड्डे से गोदाम तक परिवहन	3 घंटे

स्रोत: समीक्षा-परिकलन

6.48 पुनः, प्रक्रिया प्रवाह का विपरीत अध्ययन किया गया। सारणी 15(क) और (ख) में चीन से बैंगलौर में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात करने में लगने वाले समय की तुलना एईओ पंजीकरण के साथ और बगैर-एईओ पंजीकरण के साथ किया गया है। एक बार शेनझेन में कारखाने में खेप तैयार हो जाने के बाद, इसे हांग-कांग हवाई अड्डे तक ले जाने में तीन घंटे लगते हैं।

6.49 हवाई अड्डे पर, निर्यात घोषणा में एक घंटे, सीमा शुल्क-निकासी पर दो घंटे और टर्मिनल पर विमान में लदाई करने में अतिरिक्त चार घंटे का समय लगता है। हवाई यात्रा में पांच घंटा व्यतीत करने के पश्चात प्रेषित माल केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर पहुंचता

है। इसके पश्चात प्रेषित माल को बैंगलौर के मालगोदाम में एईओ पंजीकरण के साथ और बगैर-एईओ पंजीकरण के साथ पहुंचने में क्रमशः 14 और 11 घंटे लगते हैं।

6.50 इस केस अध्ययन से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं: (क) भारतीय एयर पोर्ट पर प्रक्रिया आयात और निर्यात दोनों के लिए समुद्र पत्तन की अपेक्षा बहुत उत्तम है' (ख) एईओ में कमी थी जिसकी प्रक्रिया में काफी सुधार किया लेकिन गैर-एईओ ऑपरेटरों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात/निर्यात करने के लिए यह काफी हद तक निर्विध्न है; (ग) भारतीय प्रक्रिया अंतरराष्ट्रीय मानको को पछाड़ सकती है।

तालिका 15 (क) चीन से बेंगलोर (गैर-एईओ) इलैट्रॉनिक्स के आयात के प्रेषित माल का विवरण

	स्थान	कार्रवाई	समय
चीन			
चीन में 2 दिन और सात घंटे	शेनझेन, चीन	फैक्टरी पर खेप तैयार	
	शेनझेन में भंडार गृह से हांग कांग एयर पोर्ट के लिए	ट्रक से एअर पोर्ट के लिए खेप का परिवहन	2 दिन
	नौवहन एअरपोर्ट पर पहुंचा	निर्यात घोषणा	1 घंटा
		कस्टम क्लियरेंस	2 घंटे
		टर्मिनल पर फ्लाइट की स्वीकृति	4 घंटे
5 घंटे	एयर ट्रेवल		5 घंटे
भारत: गैर - प्राधिकृत इकॉनॉमिक प्रचालक			
भारत में 14 घंटे	खेप बेंगलुरु में एअर पोर्ट पर पहुंचा	माल की बांडिंग/मालसूची	3 घंटे
		कस्टम क्लियरेंस	6 घंटे
		खेप सुपुर्दगी प्रक्रिया	1 घंटे
	सड़क द्वारा यात्रा	एअरपोर्ट से भंडारगृह तक परिवहन	4 घंटे

स्रोत: समीक्षा गणना

तालिका 15 (ख) तालिका 15 (क) चीन से बेंगलोर (एईओ) इलैट्रॉनिक्स के आयात के प्रेषित माल का विवरण

	स्थान	कार्रवाई	समय
चीन			
चीन में 2 दिन और सात घंटे	शेनझेन, चीन	फैक्टरी पर खेप तैयार	
	शेनझेन में भंडार गृह से हांग कांग एयर पोर्ट के लिए	ट्रक से एअर पोर्ट के लिए खेप का परिवहन	2 दिन
	नौवहन एअरपोर्ट पर पहुंचा	निर्यात घोषणा	1 घंटा
		कस्टम क्लियरेंस	2 घंटे
		टर्मिनल पर फ्लाइट की स्वीकृति	4 घंटे
5 घंटे	एयर ट्रेवल		5 घंटे
भारत: गैर - प्राधिकृत इकॉनॉमिक प्रचालक			
भारत में 11 घंटे	खेप बेंगलुरु में एअर पोर्ट पर पहुंचा	माल की बांडिंग/मालसूची	3 घंटे
		कस्टम क्लियरेंस	3 घंटे
		खेप सुपुर्दगी प्रक्रिया	1 घंटे
	सड़क द्वारा यात्रा	एअरपोर्ट से भंडारगृह तक परिवहन	4 घंटे

स्रोत: समीक्षा गणना

निष्कर्ष:

6.51 इस अध्याय में विभिन्न पहलुओं से भारत में व्यवसाय की सुगमता पर चर्चा की गई है। सबसे पहले इसमें विश्व बैंक की ईओडीबी रैंकिंग में भारत की उसके समकक्ष देशों और साथ ही सबसे उत्तम श्रेणी के देशों से निष्पादन की तुलना की गई है। यह विश्लेषण चार प्राचलों पर ध्यान केंद्रित करता है जहां भारत व्यापार आरंभ करने संपदा रजिस्ट्रकरण में, करों का भुगतान करने में और संविदाओं को लागू करने में पिछड़ा है। इसके निष्कर्ष हर श्रेणी में स्पष्टता सुधार की व्यापक संभावना दर्शाते हैं। जहां भारत को संविदा किसी लागू करने में लगभग 4 वर्ष लगे वहीं न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया, चीन और ब्राजील को क्रमशः 06, 1.2, 1.3 और 2.2 वर्ष का समय लगता है। संविदा को लागू करने में 190 देशों में से भारत 163 वें रैंक पर है अफगानिस्तान, मोजांबिक और जिंबावे ने भारत से खराब निष्पादन किया है। इसी प्रकार अन्य श्रेणियों के लिए भी तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

6.52. दूसरा यह अध्याय कानून की भूलभुलैया, निर्माण और सेवा (विशेष रूप से रैस्टोरेट) क्षेत्र पर प्रकाश डालता है। जहां चीन और सिंगापुर में रैस्टोरेट खोलने में केवल चार की आवश्यकता

होती है भारत में और बहुत से लाइसेंस और अनुमोदनों की आवश्यकता होती है: दिल्ली में 26, बेंगलूरु में 36 और मुंबई में 22 की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त दिल्ली में दिल्ली पुलिस से 'पुलिस ईटिंग हाउस लाइसेंस' के लिए बंदूक के लिए आवश्यक 19 की तुलना में 45 दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। इसे व्यवस्थित करने का गुंजाइश स्पष्ट है।

6.53 कारखाने के गेट से लेकर विदेशी ग्राहक के मालगोदाम तक विशिष्ट व्यापारिक मदों के लिए आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में लगने वाले समय का मूल्यांकन करने के लिए, अंततः केस अध्ययन और औद्योगिक सर्वेक्षणों की श्रृंखला का उपयोग किया जाता है। ये निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं: (क) भारतीय समुद्री-पत्तनों में भरण और सीमाशुल्क प्रक्रिया, में अत्यधिक विलंब (ख) इसके विपरीत आयात की प्रक्रिया, निर्यात की प्रक्रिया से अपेक्षाकृत बेहतर होती है (ग) प्रक्रिया समय में बड़े अंतर का अभिप्राय यह है कि निर्यात में अतिरिक्त प्रतीक्षा समय के होने की अनिश्चिता मुख्य कारक है। इसके विपरीत, बेंगलूरु हवाई अड्डे के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात और निर्यात विश्व स्तर का पाया गया।

अध्याय एक नजर में

- वर्ल्ड बैंक डूईंग बिजनेस रैंकिंग में 79 अंकों की छलांग लगाते हुए वर्ष 2014 में 142 वीं रैंक में सुधार करते हुए 63वीं रैंक हासिल की है। हालांकि, कुछ प्राचलों में यह स्थिति निरंतर बनी हुई है जैसे आरंभिक कारोबार की सुविधा (रैंक 136), सम्पत्ति के पंजीकरण में (रैंक 154), कर भुगतान (रैंक 115), और संविदाओं को लागू करने में (रैंक 163)।
- ख संविदा को प्रवर्तित करने में भारत में औसत 1445 दिन का समय लगता है जबकि ऐसी ही संविदा को प्रवर्तित करने में न्यूजीलैंड में औसत 216 दिन और चीन में 991 दिन का समय लगता है। करों के भुगतान में भारत में 250 घंटों से अधिक समय लगता है जबकि न्यूजीलैंड में करों के ऐसे ही भुगतान के लिए 140 घंटों, चीन में 138 और इंडोनेशिया में 191 घंटों का समय लगता है।
- भारत में सेवाओं या व्यापार उत्पादन की स्थापना और प्रचालन के लिए विधियों, नियमों और विनियमों की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसी कई एक जटिलताएं स्थानीय अपेक्षाएं होती हैं जैसे किसी रैस्टोरेट की स्थापना के लिए पुलिस की अनुमति के लिए भारी-भरकम प्रलेखन। इसे युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए।

- व्यापारिक निर्यात के मामले के लिए किए गए अध्ययनों से पता चलता है कि भारतीय समुद्री पत्तनों में संभार तंत्र अत्यधिक अपर्याप्त है। विडम्बना से, आयात के लिए प्रक्रिया प्रवाह निर्यात के प्रक्रिया प्रवाह से बेहतर पाए गए। हालांकि, विशिष्ट मामलों के अध्ययन में सामान्य मामले से अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। यह बात स्पष्ट है कि समुद्री पत्तनों में सीमाशुल्क निकासी, बुनियादी हैंडलिंग और भरण में कई दिन लगते हैं जबकि ये सब काम घंटों में किए जा सकते हैं। बैंगलुरु हवाई अड्डे के माध्यम से होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात और आयात के अध्ययन से पता चलता है कि कैसे भारतीय संचार तंत्र प्रक्रिया विश्व स्तरीय हो सकती है।
- इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि भारत में समुद्री जहाजों का प्रतिवर्तन काल में निरंतर कमी आ रही है जो 2010-11 में 4.67 दिन थे अब 2012-19 में 2.48 दिन हैं। यह दर्शाता है कि समुद्री पत्तनों के मामले में विशिष्ट दक्षता प्राप्त करना संभव है। हालांकि चैनई पत्तन का पूर्व मामला अध्ययन नहीं किया गया इसके आंशिम डाटा बताते हैं कि इसकी प्रक्रिया उत्तर बताए गए पत्तनों की तुलना में सरल है।
- समुद्र पत्तन पर लॉजिस्टिक प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के लॉजिस्टिक प्रभाग, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, पोत परिवहन मंत्रालय और विभिन्न पत्तन प्राधिकरणों के मध्य पूर्व समन्वय आवश्यक होता है। तथापि पर्यटन, या विनिर्माण जैसे अलग-अलग क्षेत्रों के व्यापार करने की सुगमता के परिदृश्य की सुगमता के लिए अत्यधिक लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो प्रत्येक घटक के लिए विनियामक और बॉटल जैक प्रक्रिया का खाका तैयार करता है। जब एक बार प्रक्रिया का खाका तैयार हो जाता है तो सरकार-केन्द्र, राज्य या नगर पालिका के समुचित स्तर पर इसमें संशोधन किए जा सकते हैं।

संदर्भ

World Bank. "Doing Business." The World Bank Group. (Various Editions). <https://www.doingbusiness.org/en/doingbusiness>

Department of Commerce. "Logistics Ease Across Different States (LEADS Index)." New Delhi, 2019. https://commerce.gov.in/writereaddata/UploadedFile/MOC_637051086790146385_LEAD_Report.pdf

Department of Commerce. "High-Level Advisory Group (HLAG)." New Delhi, 2019. https://commerce.gov.in/writereaddata/uploadedfile/MOC_637084607407371826_HLAG%20Report%20.pdf

Niti Aayog. "Ease of Doing Business: An Enterprise Survey of Indian States." New Delhi, 2017. https://niti.gov.in/writereaddata/files/document_publication/EoDB_Single.pdf

बैंक राष्ट्रीयकरण की स्वर्ण जयंती: एक समीक्षा

07

अध्याय

“देश के पूंजी परिवर्धन ही नहीं, बैंकिंग गतिविधियों के सर्वाधिक न्यायसंगत उपयोग से मौजूदा पूंजी के बड़े भाग को सक्रिय करके और उसकी उत्पादकता बढ़ाकर देश की औद्योगिक अभिवृद्धि की जा सकती है।”

-एडम स्मिथ

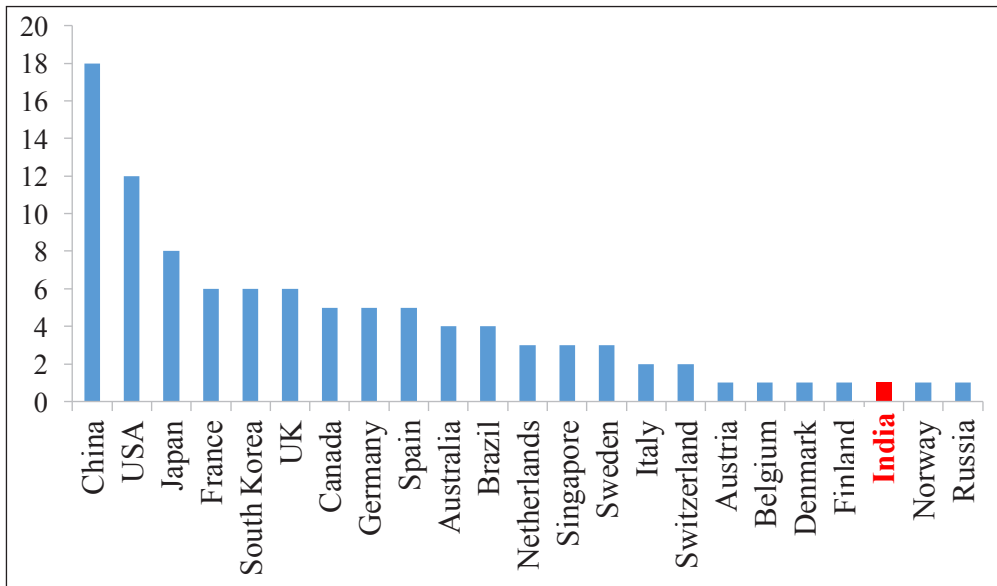
वर्ष 2019 में, भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का 50वां वर्ष पूर्ण हुआ। इसलिए यह उचित ही होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कार्य करने वाले 389,956 अधिकारियों, 295,380 लिपिकों और 121,647 सहायक कर्मचारियों की कार्यासिद्धियों की खुशी मनायी जाए। साथ-ही-साथ, यह भी उचित होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन किया जाए, वर्ष 1969 से ही, भारत दिन दूनी और रात चौगुनी प्रगति करते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। तो भी, अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से भारत का बैंकिंग क्षेत्र समानुपात में विकसित नहीं हो पाया है। उदाहरण के तौर पर, विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में भारत का केवल एक ही बैंक आता है और यह स्थिति भारत को उन अनेक देशों की श्रेणी में ले जाती है जिनकी अर्थव्यवस्था का आकार भारत के मुकाबले में कई-कई गुना तक कम है जैसेकि-फिनलैंड (लगभग 1/11वां भाग), डेनमार्क (1/8वां भाग), नार्वे (1/7वां भाग), आस्ट्रिया (लगभग 1/7वां भाग) और बेल्जियम (लगभग 1/6वां भाग)। स्वीडन और सिंगापुर जैसे देशों, जिनकी अर्थव्यवस्था का आकार भारतीय अर्थव्यवस्था के क्रमशः 1/6वें और 1/8वें भाग के बराबर है, के विश्व स्तरीय बैंकों की संख्या भी भारत से तीन गुनी अधिक है। एक विशाल अर्थव्यवस्था की सवृद्धि में सहायता देने के लिए एक दक्ष बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता होती है। ऐतिहासिक रूप से पिछले 50 वर्षों में शीर्ष पांच अर्थव्यवस्थाओं को सदैव उनके बैंकिंग की ओर से उचित सहारा मिला है। चूंकि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को सहारा देने और इसके आर्थिक विकास का पोषण करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर है। परंतु, यदि कार्यानिष्पादन के प्रत्येक पैरामीटर के हिसाब से देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अपने समकक्ष समूहों की तुलना में दक्षता का अभाव है। विगत में, नरसिम्हन समिति (1991, 1997), राजन समिति (2007) और पी जे नायक समिति (2014) ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की दक्षता बढ़ाने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं। इस समीक्षा में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की दक्षता के संवर्धन हेतु बैंकिंग कार्यों में वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) के और समस्त स्तरों पर कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व के उपयोग का सुझाव दिया गया है। इनसे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को और अधिक दक्षता प्राप्त होगी और वे 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की दिशा में राष्ट्र की यात्रा में कुशलतापूर्वक सहयोग करने में समर्थ हो सकेंगे।

7.1 भारत वर्ष 1969 में चलाए गए बैंक राष्ट्रीयकरण कार्यक्रम के वर्ष 2019 में 50 वर्ष पूरे हो गए। इसलिए यह उचित ही है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कार्य करने वाले 389,956 अधिकारियों, 295,380 लिपिकों और 121,647 सहायक कर्मचारियों की कार्यसिद्धियों की खुशी मनाई जाए। चूंकि भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत है अतः भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की स्थिति का एक मूल्यांकन करना उपयुक्त होगा। यद्यपि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख भूमिका निभाते हैं तथापि, जब इनकी तुलना इनके समवर्तियों से की जाती है तो कार्यनिष्पादन के मानकों पर ये काफी पिछड़ी स्थिति में पाए जाते हैं।

7.2 चित्र 1 दर्शाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था के आकार की दृष्टि से इसके बैंक आनुपातिक रूप से छोटे

हैं। वर्ष 2019 में, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमारा सर्वोच्च श्रेणीप्राप्त बैंक भारतीय स्टेट बैंक-विश्व में 55वें स्थान पर है जोकि काफी नीचे है तथा विश्व के 100 बैंकों में कोई स्थान पाने वाला एकमात्र बैंक है। विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में भारत का केवल एक बैंक है जिसे इस विशेषता के कारण उन देशों के समूह में रखा जाता है जिनकी अर्थव्यवस्था के आकार भारत की अर्थव्यवस्था के न्यून अंश के समान ही है जैसे फिनलैंड (1/11वां), डेनमार्क (1/8वां), नार्वे (1/7वां), आस्ट्रिया (1/7वां) और बेल्जियम (1/6वां)। स्वीडन और सिंगापुर जैसे देश, जिनकी अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था के आकार के क्रमशः लगभग 1/6वें और 1/8 वें भाग के बराबर है, वैश्विक स्तर पर भारत की तुलना में तीन गुना अधिक बैंक वाले देश हैं।

चित्र 1: वैश्विक शीर्ष 100 बैंकों में बैंकों की संख्या (2019)



स्रोत: विकिपीडिया

7.3 चित्र 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में भारतीय बैंकों के इस विषयानुपाती बौनेपन को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है। विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में कई बैंकों की मौजूदगी नहीं होना तथा भारत की अर्थव्यवस्था का आकार स्पष्ट तौर पर इंगित करता है कि यह नकारात्मक पक्ष पर एक महत्वपूर्ण बाह्यशायी है। सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में समानुपातिक रूप से

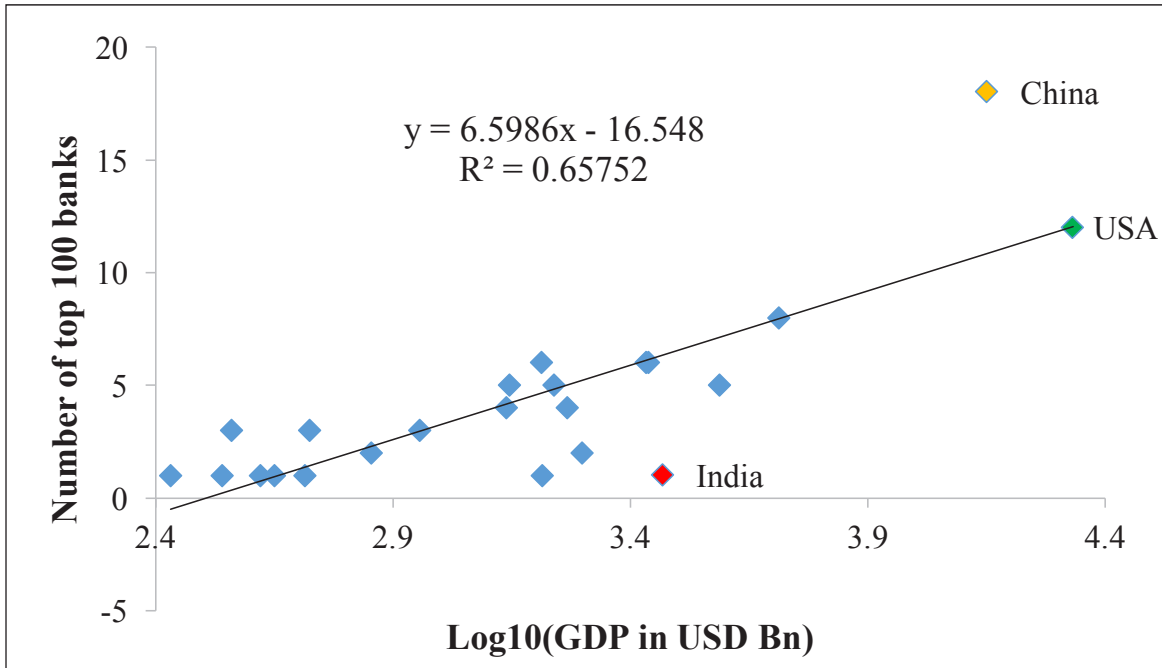
बड़े बैंक हैं तथा विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में चीन के 18 बैंकों का होना सकारात्मक पक्ष पर उसका बाह्यशायी होना दर्शाता है। इसी प्रकार चित्र-3 दर्शाता है कि निजी क्षेत्र में बैंक साख की पैठ का देश की जीडीपी के अनुसार अंकन करने से भारत में साख की पैठ का आंकलन हो जाता है। क्योंकि भारत में बैंक साख की पैठ का अपंकलन हो जाता है। क्योंकि भारत

¹ स्रोत: आरबीआई डाटा

में यह साख मुख्यतः बैंक ही प्रदान करते हैं। रेखाचित्र 4 बताता है कि यह अतिन्यून आनुपातिक पैठ केवल हमारी विशाल जन संख्या के कारण नहीं हैं यह सत्य है कि अधिक जनसंख्या के कारण साख पैठ का आकार कम हो जाता है किन्तु भारत में तो यह न्यूनता जनसंख्या की

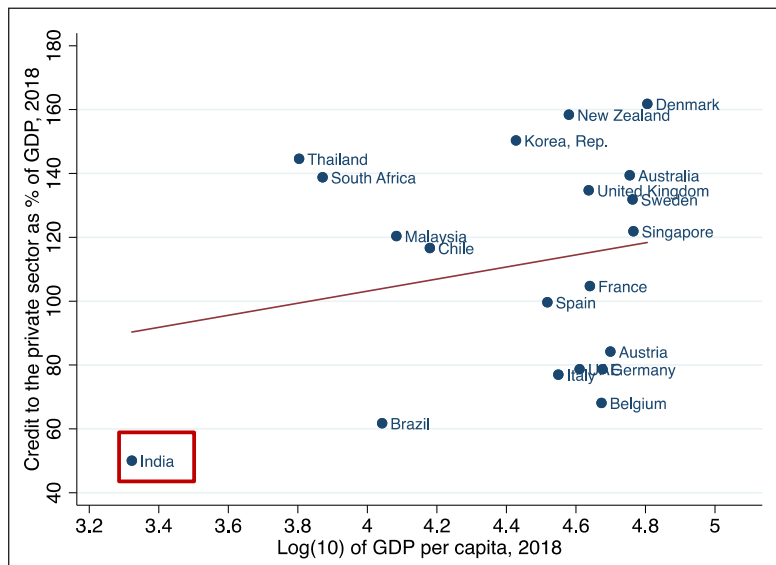
तुलना में अत्याधिक न्यून हो गई है। संक्षेप में, चित्र 1-4 देश की अर्थव्यवस्था के आकार खजीडीपी,, अर्थव्यवस्था के विकास ख्रति व्यक्ति जीडीपी, और जनसंख्या जैसा विशेषताओं की तुलना में हमारे देश के बैंक क्षेत्र के बौनेपान को स्पष्ट कर रहे हैं।

चित्र 2: देश की जीडीपी तथा विश्व के शीर्ष 100 में उसके बैंकों की संख्या



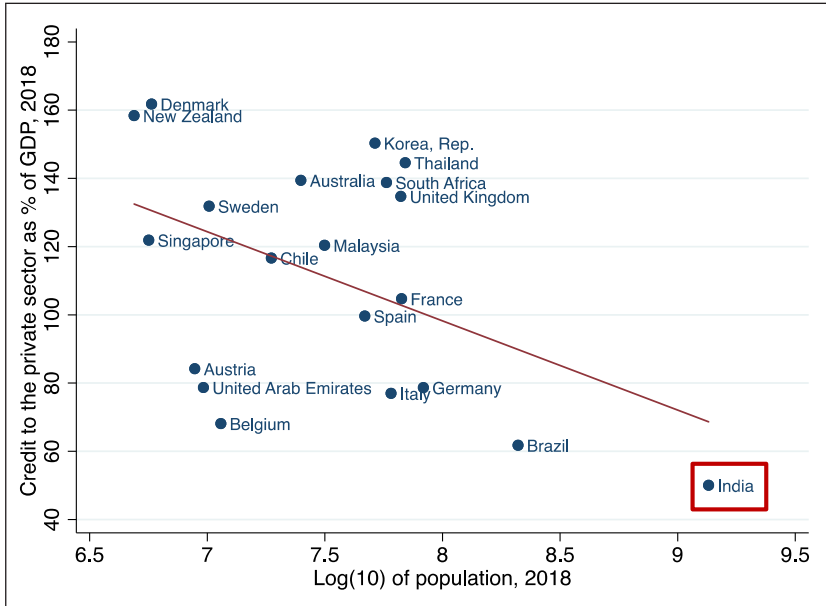
स्रोत: शीर्ष 100 बैंकों के लिए विकिपीडिया और आईएमएफ से प्राकलित जीडीपी 2019

चित्र 3: देश की प्रतिव्यक्ति जीडीपी और साख की पैठ



स्रोत: विश्व बैंक डब्ल्यूडीआई डाटाबेस

चित्र 4: देश की जनसंख्या और साख की पैठ

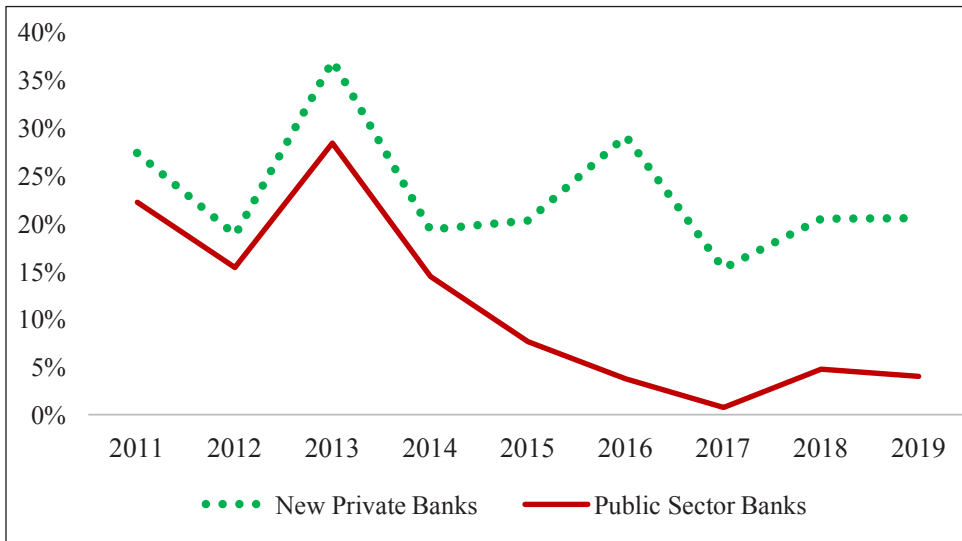


स्रोत: विश्व बैंक डब्ल्यूडीआई डेटाबेस

7.4 एक बड़ी अर्थव्यवस्था को अपनी वृद्धि को अपनी वृद्धि का समर्थन करने के लिए एक कुशल बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता होती है। चित्र-3 दर्शाता है कि पीएसबी के बीच ऋण वृद्धि में वर्ष-2013 के बाद से न केवल तेजी से गिरावट आई है, बल्कि वर्ष 2016 के बाद से तो यह क्षेत्र जोशरहित भी हो गया है। भले ही वर्ष 2010 और 2019 के बीच एनपीबी ने प्रति वर्ष 15 प्रतिशत और 29 प्रतिशत के बीच साख वृद्धि दर्ज की परंतु फिर भी वर्ष 2014 के बाद पीएसबी की साख वृद्धि अवरुद्ध होकर वर्ष 2019 में एकल अंकों, 4.03 प्रतिशत तक

पहुंच गई, जबकि वर्ष 2010-2013 में यह 15 प्रतिशत से 28 प्रतिशत रही थी। जैसा कि इस समीक्षा के खंड-2 के अध्याय-1, भाग-2 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, दुर्बलतापूर्ण साख वृद्धि ने आर्थिक विकास को प्रभावित किया है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि अर्थव्यवस्था के लिए पीएसबी द्वारा अपनी पूरी क्षमता से निष्पादन करने और ऋण देना बंद करने के बजाय आर्थिक विकास का समर्थन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऋण देना बंद का संवृद्धि और कल्याण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

चित्र 5: बैंक ऋण वृद्धि (प्रतिशत)



स्रोत: आरबीआई डेटा व समीक्षा परिकलन

7.5 ऐतिहासिक रूप से पिछले 50 वर्षों में, शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं को हमेशा उनके बैंकों द्वारा पूरी तरह से समर्थन/सहयोग प्रदान किया गया है। अमेरिका को आर्थिक महाशक्ति बनाने में अमेरिकी बैंकिंग प्रणाली का सहयोग अच्छी तरह से प्रलेखित है। इसी प्रकार अस्सी के दशक में, जापानी अर्थव्यवस्था की समृद्धि के उत्कर्ष के दौरान तत्कालीन सबसे बड़े 25 बैंकों में जापान के 15 बैंक आते थे। हाल के दिनों में, चीन एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा है, इसे अपने बैंकों द्वारा समर्थन दिया गया है—वैश्विक रूप से शीर्ष चार सबसे बड़े बैंक, चीनी बैंक ही हैं। विश्व का सबसे बड़ा बैंक, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना (चीन का औद्योगिक और व्यावसायिक बैंक), चौथे या पांचवें बृहत् बैंक से लगभग दो गुना बड़ा है, जो क्रमशः जापानी और अमेरिकी बैंक हैं। उपर्युक्त संबंध का उपयोग करते हुए हम अनुमान लगाते हैं कि यदि भारतीय बैंक भी भारतीय अर्थव्यवस्था के अनुपात में बड़े हों तो विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में कम से कम छः बैंक हमारे होने चाहिए। इसी तरह, 5 ट्रिलियन डॉलर/अर्थव्यवस्था बनने वाले भारत को विश्व स्तर पर शीर्ष 100 में शामिल हो सकने वाले कम से कम 8 भारतीय बैंकों की आवश्यकता होगी। इसलिए, भारत में बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

7.6 चूंकि भारतीय बैंकिंग से बाजार हिस्सेदारी का 70 प्रतिशत पीएसबी के पास है, अतः भारतीय अर्थव्यवस्था का समर्थन/सहयोग करने और इसके आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का दायित्व भी उन्हीं का बनता है। हालांकि वर्ष-2019 में पीएसबी की सामूहिक हानि मुख्यतः अशोध्य ऋण की वजह से 66,000 करोड़ से अधिक है जो कि एक ऐसी राशि है जो शिक्षा के लिए देश के बजटीय आवंटन को लगभग दोगुना कर सकती है। बैंक धोखाधड़ी के 85 प्रतिशत प्रतिवेदित मामले पीएसबी के कारण ही हैं जबकि उनकी सकल अनर्जक परिसंपत्तियां (एनपीए) 7.4 लाख करोड़ की हैं जो वर्ष 2019 के कुल अवसंरचना व्यय के 150 प्रतिशत से अधिक है। पूंजी पर प्रतिप्राप्ति का 2019 का अनुपात स्पष्ट करता है कि पीसीबी में सरकार द्वारा निवेशित प्रत्येक रूपये में 23 पैसे का क्षरण हो रहा है। बाजार और खाता मूल्यांकनों का अनुपात, जो बैंक के प्रशासन की गुणवत्ता को दर्शाता है, 20 जनवरी, 2020 को पीएसबी के लिए 0.8 रहा

जबकि एनपीबी में यह 4 था। पीएसबी को दत्त बनाने और इस प्रकार आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने योग्य बनाने के लिए संरचनात्मक समाधान अनिवार्य हो गए हैं।

7.7 लगभग 4,30,000 करोड़ करदाताओं का धन सरकारी पूंजी के रूप में पीएसबी में निवेश किया हुआ है। वर्ष 2019 में पीएसबी में निवेश किये गये करदाताओं के प्रत्येक रूपये में से औसतन 23 पैसे की हानि हुई। इसके विपरीत 1991 में भारत में उदारीकरण के बाद लाइसेंस दिए गए “नए प्राइवेट बैंकों (एनपीबी) में निवेश किए गए प्रत्येक रूपये में 9.6 प्रतिशत लाभ हुआ। चूंकि पीएसबी और एनपीबी एक ही घरेलू बाजार में परिचालित होते हैं, इसलिए पीएसबी की कार्यकुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है।

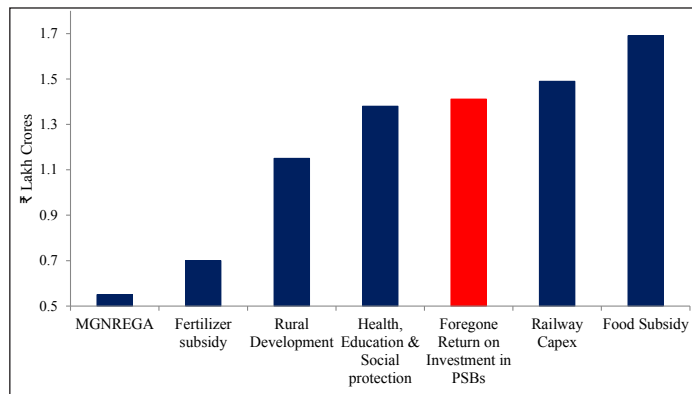
7.8 पीएसबी में कार्यक्षमता में कमी के स्तर को समझने के लिए हम पीएसबी में करदाता के निवेश पर प्रतिफल में परिवर्तन से संभावी लाभ का अनुमान लगा रहे हैं। एक औसत एनपीबी में किसी निवेशक द्वारा अर्जित प्रतिफल उस बेंचमार्क का प्रतिनिधित्व करता है जिसका उपयोग करदाता द्वारा पीएसबी में उसके निवेश पर हुई हानि का अनुमान लगाने के लिए किया जाना चाहिए। चित्र 6 दर्शाता है कि इस बेंचमार्क का प्रयोग कर पीएसबी में करदाता के निवेश पर पूर्वमानित घाटा सबसे बड़ी सब्सिडी अर्थात् 1.4 लाख करोड़ की राशि से अधिक की खाद्य सब्सिडी के लिए दी गई राशि से तुलनीय है।

7.9 कार्यकुशलता में कमी के पैमाने को समझने के लिए दूसरा तरीका निम्नलिखित प्रश्न पूछना है: पीएसबी में निवेश से करदाता कुल कितना मूल्य प्राप्त करता है? इस प्रयोजन से हम प्राइवेट सेक्टर के नए बैंकों (एनपीएसबी) की तुलना में स्टॉक मार्केट से पीएसबी के बही मूल्य के अनुपात का प्रयोग करते हैं। 20 जनवरी, 2020 को हम पाते हैं कि करदाताओं के धन का प्रत्येक रूपया 71 पैसे का बाजार मूल्य लाता है। इसकी तुलना में एनपीबी में निवेश किये गये प्रत्येक रूपये से 3.70 का बाजार मूल्य प्राप्त होता है अर्थात् पीएसबी में निवेश किए गए रूपये के मूल्य से पांच गुना। इससे स्वाभाविक प्रश्न उठता है। यदि प्रत्येक पीएसबी के बाजार से बही अनुपात दोगुना हो पाए, जिसमें अत्यधिक सामान्य स्पष्ट वृद्धि की परिकल्पना की गई है, क्योंकि औसत पीएसबी तब भी एनपीबी द्वारा औसतन पैदा करने वाले मूल्य के

एक तिहाई मूल्य ही पैदा करेगा। चित्र 7 दर्शाता है कि लाभ 5.2 लाख करोड़ रुपए होगा। यह राशि वर्ष 2019 के लिए विनिवेश हेतु बजट में प्रावधान की गई राशि से पांच गुना है और यथार्थपरक पर बहुत ही कम परिदृश्य यह अनुमान लगाना होगा कि प्रत्येक पीएसबी का बाजार से बही अनुपात दूसरे निकृष्टतम निष्पादक एनपीबी के समकक्ष तो हो जाए। यह यथार्थपरक परिदृश्य है क्योंकि सबसे खराब निष्पादन करने वाले एनपीबी का बाजार से बही अनुपात पीएसबी के लिए माध्य से अधिक है। इस प्रकार, यहां हमारा अनुमान है कि प्रत्येक पीएसबी में करदाता का निवेश कम से कम निम्नतम एनपीबी के बाजार से वही अनुपात के समकक्ष तो होगा। इस परिवर्तन से सरकार को 9.1 लाख करोड़ रु का लाभ होगा जो वर्ष 2019 के लिए विनिवेश में किए गए बजट

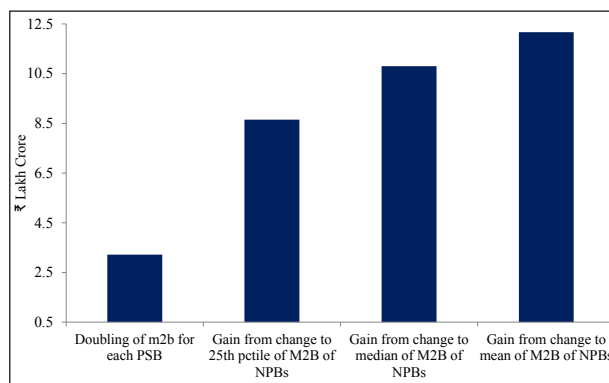
अनुमान से लगभग 8.5 गुना अधिक है। प्रत्येक पीएसबी के बाजार से बही अनुपात में परिवर्तन कर एनपीबी के माध्य के बराबर करने पर सरकार को 10.2 लाख करोड़ की प्राप्ति होगी, जो वर्ष 2019 के लिए निवेश के लक्ष्य से नौगुना है। अंत में, प्रत्येक पीएसबी के बाजार से बही अनुपात में एनपीबी के माध्य से सरकार को 11.8 लाख करोड़ लाभ होगा, जो वर्ष 2019 के लिए विनिवेश से 11 गुना है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, पीएसबी और एनपीबी में प्राथमिक अंतर कार्यकुशलता में अंतर और उससे उत्पन्न होने वाले अंतरों से आस्तित्व में आता है। इस दृश्य विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पीएसबी की कार्यक्षमता में कमी से उत्पन्न होने वाली लागतें बहुत अधिक हैं।

चित्र 6: पीएसबी में निवेश से करदाता की धनराशि की हानि की बड़ी सब्सिडी मदों से तुलना (2019)



स्रोत: बजट दस्तावेज, आरबीआई बुलेटिन और समीक्षा आंकलन

चित्र 7: पीएसबी में दक्षता वृद्धि से करदाता को संभावी लाभ



स्रोत 7: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: एम2बी अनुसूचित बैंक का बाजार और वही मूल्य अनुपात दर्शाता है

7.10 भारत को यह पहचानने की आवश्यकता है कि सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति बड़े पैमाने पर अन्य वित्तीय मध्यस्थता मॉडलों का उपयोग करते हुए की जा सकती है। व्यक्तिगत (माइक्रो फाइनेंस) के घातांकीय वृद्धि और इसके प्रभाव ने इस बिन्दु को विशेषरूप से दर्शाया है (बॉक्स 1 को देखें)। इसके अलावा, जैसे कि बाद में स्पष्ट किया गया है, अन्य व्यावसायिक मॉडलों - एम पी बी या व्यक्तिगत (माइक्रो फाइनेंस) संस्थाओं (एम एफ आई) की कुछ कमजोरियों को रेखांकित करते हुए जिस प्रकार पी एस बी की यथास्थिति बनाए रखने का समर्थन किया जाता है, वह दो विषम चीजों की तुलना करते हुए निष्कर्ष देने के समान है। किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप में निष्पादन में विषमता का होना अनिवार्य है। चूंकि पी एस बी निष्पादन में काफी भिन्नता है, कुछ पी एस बी अन्य की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार एनपीबी और एमएफआई के प्रदर्शन में भी कुछ भिन्नता होनी चाहिए। हालांकि, औसत प्रदर्शन करने वाले पी एस बी की तुलना सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले एन पी बी/एम एफ आई के साथ करना गलत है, क्योंकि इसमें दो सांख्यिकीय उपायों - औसत और बेहतर कार्य-निष्पादन - का मिश्रण कर दिया जाता है, जो कि अंततः दो विषम चीजों की तुलना करते हुए निष्कर्ष देने के समान है। संक्षेप में, यह पीएसबी में कार्यनिष्पत्ति में सुधार करने से अत्यंत आवश्यक है।

7.11 भारत (i) एक सकारात्मक जनसांख्यिकीय लाभांश; (ii) लगभग 100 प्रतिशत वित्तीय समावेशन वाली जैम “ट्रिनिटी” द्वारा समर्थित आधुनिक डिजिटल अवसंरचना

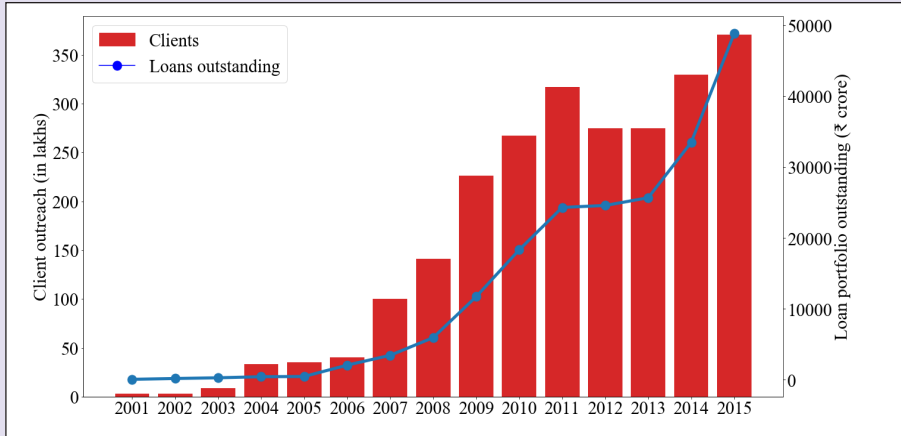
जिसमें बायोमेट्रिक्स-आधारित विशिष्ट पहचान प्रणाली और मोबाइल नेटवर्क संरचना भी है और (पपप) एक समान नए सिरे से बनाया गया जी एस टी नेटवर्क जो कि सम्पूर्ण भारत में इलेक्ट्रॉनिक अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली है, के कारण विभिन्न कारकों के विशिष्ट सह प्रवाह के कारण अपने संवृद्धि-पथ के महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। ये निवेश आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एक मंच प्रदान करते हैं जिसमें दस करोड़ लोग एवं व्यवसाय का औपचारिक वित्तीय प्रणाली में समावेश हो रहा है।

7.12 भारत की वर्तमान जनसांख्यिकी और संवृद्धि अवसरों को ध्यान में रखते हुए अब हमें एक उन्नतिशील बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता है। एक उद्यमी बैंकिंग प्रणाली ही वह सहयोग कर सकती है और गुणात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकती है तथा भारत के संवृद्धि पथ को एक सकारात्मक दिशा में स्थायी रूप से ले जा सकती है। इसके विपरीत, अदक्ष पीएसबी, उन विशेष अवसरों का विदोहन करने की देश की क्षमता को गंभीर क्षति पहुंचा सकते हैं, जिन्हें वह आज उपयोग में ला सकता है। ऐसी परिणति होने पर देश की आर्थिक संवृद्धि पीढ़ियों पीछे जा सकती है। जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है एक दक्ष बैंकिंग व्यवस्था की सहायता के बिना कोई भी देश प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्था नहीं रह पाया है। जहां तक एक 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य की दिशा में भारत की यात्रा का संबंध है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जोकि हमारी बैंकिंग प्रणाली में प्रभाविता रखते हैं, को और दक्ष होना जरूरी है।

बॉक्स 1 सामाजिक प्रभाव हेतु निजी क्षेत्र में वित्तीय मध्यस्थता: व्यक्तिगत (माइक्रो फाइनेंस) का केस

व्यक्तिगत वित्त क्षेत्र, विशेष रूप से वर्ष 2000 से इसके कायाकल्प को देखते हुए, पीएसबी के व्यावसायिक मॉडलों से भिन्न मॉडलों के उपयोग के स्तर पर सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का एक उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करता है। अधिकांश व्यक्तिगत वित्त (एमएफआई) ने अलाभार्थी संस्थाओं के रूप में अपनी शुरुआत की है। वर्ष 2000 के बाद, यद्यपि एमएफआई का उद्देश्य यही बना रहा कि समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन के माध्यम से गरीबी उन्मूलन किया जाए तथापि साथ-ही-साथ इन्होंने सामाजिक लक्ष्य के अनुसरण के विशुद्ध लक्ष्य से होकर, सामाजिक और वित्तीय लाभ प्राप्त करने की दोहरी अंतर्निहित संकल्पना का अनुसरण प्रारंभ कर दिया है। कुछ अग्रणी एमएफआई संस्थाओं द्वारा अर्जित उत्तम वित्तीय प्रतिलाभों के साथ ‘सबसे निचले स्तर’ पर सामाजिक प्रभाव डालने पर फोकस से, इस क्षेत्र में मुख्यधारा की अनेक वाणिज्यिक संस्थाओं का प्रवेश हुआ। उदाहरण के लिए, कुछ बैंक इस वर्ग के लिए आगे और धन उधार देने के लिए एमएफआई को ऋण देते हुए इनके साथ साझेदारी करते हैं और इनकी प्राथमिकता वाली ऋण देनदारियों को पूरा करते हैं। वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र की व्यक्तिगत वित्त (माइक्रो फाइनेंस) घोषणा में गरीबी उन्मूलन के संबंध में एमएफआई संस्थाओं की भूमिका को रेखांकित किया गया। कुछ एमएफआई ने स्वयं को बैंकों के रूप में परिवर्तित भी कर लिया है। चित्रक में, वर्ष 2000 से एमएफआई के प्रभाव में होने वाली घातांकीय वृद्धि को दर्शाया गया है। वर्ष 2016 की स्थिति के अनुसार, 97 प्रतिशत ऋण धारक महिलाएं थीं और लगभग 30 प्रतिशत ऋण धारक अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से और 29 प्रतिशत अल्पसंख्यक वर्ग से थे। यह दर्शाता है कि इन एमएफआई द्वारा दिये जाने वाला ऋण प्राथमिक तौर पर समाज के सीमांत वर्गों की जरूरतों को पूरा करता है।

चित्र क: ग्राहकों तक एमएफआई की पहुंच में घातांकी वृद्धि



स्रोत: भारत माइक्रो फाइनेंस रिपोर्ट 2012 और 2015

बैंकिंग संरचना: राष्ट्रीयकरण से अब तक

7.13 भारत में बैंकिंग हजारों वर्षों से चली आ रही है। वैदिक काल में भारत के कई प्राचीन ग्रंथों में बैंक ऋण कार्यों का उल्लेख है। भारत में आधुनिक बैंकिंग प्रणाली की जड़ें 1800 के दशक से शुरू होने वाले औपनिवेशिक युग में हैं। भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) अनिवार्य रूप से औपनिवेशिक काल से चले आ रहे विरासत वाले बैंक हैं, जिनका बाद में राष्ट्रीयकरण किया गया। उदाहरण के लिए, भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जो वर्तमान में विश्व स्तर पर 55वां सबसे बड़ा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की स्थापना 1806 में बैंक ऑफ कलकता के रूप में की गई थी, 1921 में इसका नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया और 1955 में यह राज्य के स्वामित्व के अधीन आ गया। शेष भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का गठन राष्ट्रीयकरण की दो लहरों, 1964 और 1980 के बाद हुआ। 1980 के राष्ट्रीयकरण के बाद, राष्ट्रीय बैंकिंग बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का शेयर 91 प्रतिशत है, जबकि शेष 9 प्रतिशत उन “पुराने निजी बैंकों” (ओपीबी) का है, जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था।

7.14 1969 के राष्ट्रीयकरण के बाद के 50 वर्षों में बैंकिंग क्षेत्र की बाजार संरचना विकसित हुई है। मार्च,

2019 तक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास जमा राशि में 80 लाख करोड़ थी, सरकारी बांड में 20 लाख करोड़ थे, और उनके द्वारा 58 लाख करोड़ का ऋण और अग्रिम प्रदान किया गया, जो इस बात को दर्शाता है कि यह भारत में परिचालित समस्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की कुल राशि का 65 प्रतिशत और 70 प्रतिशत के बीच की राशि है।² उनके पास सरकारी ऋण का लगभग 20 लाख करोड़ रुपये है, इसका एक बड़ा हिस्सा न्यूनतम “सांविधिक चलनिधि” अनुपात की आवश्यकताओं से संबंधित है। इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की आज बाजार में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी तो है ही, इसके साथ इनका महत्वपूर्ण पदचिन्ह भी मौजूद है, जो 1980 के राष्ट्रीयकरण के बाद 91 प्रतिशत से कुछ कम हो गया है। बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयर में गिरावट का मुख्य कारण उन “नए निजी बैंकों” (एनपीबी) का आगमन रहा है, जिन्हें 1990 के दशक की शुरुआत में लाइसेंस प्रदान करने के नियमों, के उदारीकरण के बाद, लाइसेंस प्रदान किए गए थे।

7.15 पीएसबीएस, ओपीबीएस और एनपीबीएस वर्तमान में अपने समस्त कामकाज, जिसमें शाखा निर्माण और ऋण देने संबंधी प्राथमिक कार्य-क्षेत्र शामिल है, के लिए समान बैंकिंग नियमों के अधीन हैं। राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी बैंकों के बीच

² समग्र बैंकिंग आंकड़े आरबीआई द्वारा अनुरक्षित भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाटाबेस से लिये गए हैं। <https://dbie.rbi.org.in/> देखें

मुख्य अंतर यह है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अधिकांशतः सरकार के स्वामित्व के कारण अपेक्षाकृत कम रणनीतिक और परिचालन संबंधी स्वतंत्रता का आनंद ले पाते हैं। सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समस्त कार्यों पर महत्वपूर्ण नियंत्रण रखती है, जिसमें भर्ती से संबंधित नीति से लेकर निवेश एवं वित्तपोषण को भुगतान करने और बोर्ड एवं शीर्ष प्रबंधन की नियुक्ति सहित बैंक प्रशासन पर नियंत्रण रखना भी शामिल है। सरकार के अधिकांश मालिकाना हक और बैंक की कार्यप्रणाली पर इसके परमादेश के कारण ही बैंक की देयता के बेलआउट पर सरकारी अंतर्निहित वचनबद्धता रहती है, जिसके कारण करदाताओं पर एक अंतर्निहित बोझ पड़ता है। सरकार के अधिकांश स्वामित्व के कारण भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अधिकारियों के निर्णय केंद्रीय सतर्कता आयोग और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के जांच के अधीन होते हैं। इस बात के प्रतिबंध के बिना कि किस परिस्थिति में, क्या जांच की जाए, सतर्कता जांच के आवरण में उत्पीड़न की आशंकाओं के कारण सरकार द्वारा संचालित बैंकों के अधिकारी ऋण देने या अशोध्य ऋण की वार्ता में जोखिम लेने से सावधान रहते हैं।

राष्ट्रीयकरण के लाभ

7.16 राष्ट्रीयकरण से क्या लाभ हुआ? बैंकिंग संसाधनों की ग्रामीण क्षेत्रों, कृषि और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आवंटन बढ़ी है। 1969 के राष्ट्रीयकरण बाद से पहले दशक में कुछ कच्चे आंकड़ों पर विचार करें। ग्रामीण बैंक शाखाओं की संख्या, 1969 में लगभग 1,443 से 1980 में 15,105 शाखाओं के साथ दस गुणा वृद्धि हुई। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 5,248 से 13,300 शाखाएं यानि दो गुना वृद्धि रही। ग्रामीण क्षेत्रों में क्रेडिट बीस गुणा वृद्धि के साथ 115 करोड़ रुपए से बढ़कर 3,000 करोड़ रुपए हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जमा राशि 306 करोड़ रुपए से बढ़कर 5,939 करोड़ रुपए हो

गई, यह भी 20 गुना वृद्धि हुई। 1969 और 1980 के बीच कृषि का ऋण चालीस गुणा बढ़कर 167 करोड़ से 2,767 करोड़ हो गया, जो जीडीपी के 2 प्रतिशत के शुरूआती बिंदु से 13 प्रतिशत तक पहुंच गया। यह घटनाक्रम इस बात को दर्शाता है कि किसानों को ऋण की कम आपूर्ति की समस्या में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, राष्ट्रीयकरण के कारण इसमें गति आई है। ग्रामीण बैंक जमा राशि संग्रहण और ग्रामीण ऋण दोनों में 1969 के राष्ट्रीयकरण के बाद काफी वृद्धि हुई है।

7.17 हालांकि, उपरोक्त प्रवृत्तियों की व्याख्या में यह सावधानी बरतना आवश्यक है कि राष्ट्रीयकरण ही उपरोक्त प्रवृत्तियों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी नहीं है। इस तरह की व्याख्या में एक मुख्य सहवर्ती घटक अन्य दखलों की भूमिका भी है। उदाहरण के लिए, सरकार ने 1969 और 1977 के बीच एक “हरित क्रांति” शुरू की। इसके अलावा, कई गरीबी-निरोधी कार्यक्रम भारत की चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं में चिन्हित रहे हैं जो इसके राष्ट्रीयकरण पर आश्रित रहे हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद आरबीआई द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण सहवर्ती प्रभाव प्रारंभ हो गए। इसके निर्देशित उधार कार्यक्रमों के अधीन मूल्य निर्धारण फार्मूला, जिसके माध्यम से बाजारों की अर्थव्यवस्थाओं के बजाय केंद्रीय योजना के आधार पर ऋण पर बैंकों द्वारा वसूल किए जाने वाले ब्याज की दरों को निर्धारित की जाती है, के एक जटिल मिश्रण का उपयोग करके प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आरबीआई ने अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने हेतु औपचारिक साधन और नैतिक प्रोत्साहन का उपयोग किया। इस बात को देखते हुए कि बैंक अनिवार्य रूप से एक बंद बाजार व्यवस्था में परिचालित थे, यह स्पष्ट है कि इन कारकों ने इसे विशेष बल प्रदान किया है।

बॉक्स 2: राष्ट्रीयकरण के प्रभाव पर साक्ष्य आधारित अनुसंधान

राष्ट्रीयकरण से किस चीज़ की प्राप्ति हुई है उसके बारे में निष्कर्ष से इस बात की प्रतितथ्यात्मक स्थिति पर विचार करना चाहिए कि किस चीज़ की प्राप्ति की जा सकती है और क्या किसी भी प्रकार का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए था। इस प्रतितथ्यात्मकता का उपयोग करके राष्ट्रीयकरण के लाभ केवल आंकलन ही किया जा सकता है। कुछ ऐसे चिंताशील अध्ययन रहे हैं, जिनसे इस चिंताशील शीशे का प्रयोग करके बैंक के राष्ट्रीयकरण के प्रभाव का पर्यवेक्षण किया गया है। ये नतीजे मिश्रित हैं।

बर्गस और पांडे (2005) में आर.बी.आई के 4:1 सूत्र का अध्ययन किया गया है जहां किसी बैंक के लिए वर्ष 1977 और 1991 के बीच एक शहरी शाखा खोलने के लिए लाइसेंस लेने के लिए 4 ग्रामीण शाखाएं खोलना अपेक्षित

था। उन्होंने यह पाया कि यह नीति वित्तीय रूप से कम विकसित राज्यों में गरीबी में महत्वपूर्ण कमी का कारण रही है। हालांकि कोचर (2005) ने यह तर्क दिया है कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई.आर.डी.पी.), जो कि सरकार का एक सर्वोत्कृष्ट गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, उसे वित्तीय रूप से कम विकसित राज्यों में अत्यधिक गहनता से इस अवधि के दौरान तत्परता से कार्यान्वित किया गया था। अतः यह निष्कर्ष निकालना प्रायः असम्भव है कि सरकारी बैंक की शाखा में विस्तार गरीबी में कमी आने का कारण रहा है। यह तर्क देते हुए कि यहां तक कि राष्ट्रीयकरण से पहले समान तीव्रता (गहनता) वाला शाखा विस्तार कार्यक्रम मौजूद था, पनगढ़िया (2006) ने भी बर्गेस और पांडे (2005) में मौजूद नतीजों को असवीकृत किया था, और इसीलिए शाखा विस्तार के संबंध में 1977-1991 की अवधि विशेष नहीं है। अन्य शब्दों में, 1977-1991 के दौरान देखा गया गरीबी पर विभेदक प्रभाव राष्ट्रीयकरण का कारण नहीं हो सकता है। अंततः, कोले (2007) ने वर्ष 1980 में आरंभ किए गए बैंक राष्ट्रीयकरण के दूसरे तरंग के प्रभाव का सावधानी से जांच की। कतिपय शुरुआती आकार वाले उक्त बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था उन्होंने इस तथ्य का लाभ उठाते हुए जो बैंक राष्ट्रीयकरण दहलीज (द्वार) को सीमांत तौर पर पार किया है, उन उच्चतर अनुपात वाले बैंक के क्षेत्रों का जो बैंक अत्यंत कठिनाई से इस दहलीज को पार करने से चूक गए हैं, उन उच्चतर अनुपात वाले बैंकों के क्षेत्र की तुलना किया है। इस अध्ययन से वास्तविक अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीयकरण के किसी भी महत्वपूर्ण लाभ का पता नहीं चलता। वस्तुतः उन्होंने यह दर्शाया है कि व्यापार और सेवा में रोजगार में कमी आई है और वित्तीय मध्यस्थता बिगड़ गई है। केवल क्रेडिट की गुणवत्ता में ही वृद्धि हुई थी।

इन अध्ययनों से परे, हमें यह भी ज्ञात है कि राष्ट्रीयकरण के बावजूद 2014 तक गरीबों का एक बड़ा हिस्सा बड़ा हिस्सा बैंकों से वंचित था। बड़े हिस्से में, वित्तीय समावेश अगस्त 2014 में प्रधान मंत्री जन धन योजना (पी. एम. जे. डी. वाई.) के माध्यम से हुआ था, जिसके पहले सप्ताह में 18 मिलियन से अधिक बैंक के खाते खोले गए थे, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड्स में एक रिकार्ड है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का कमजोर होना

7.18 पी एस बी से संबंधित 2019 निष्पादन के आंकड़े संयत करने वाले हैं। 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सकल और निवल एन पी ए क्रमशः 7.4 लाख करोड़ और 4.4 लाख करोड़ दर्ज किए जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली का लगभग 80 प्रतिशत है। पी एस बी के सकल एन पी ए उनके सकल अग्रिम का 11.59 प्रतिशत रहे, यद्यपि थोड़ा बहुत उत्साहवर्धक प्रवृत्ति यह रही कि एन पी ए अनुपात 2018 के 14.58 प्रतिशत अनुपात से कम रहा जिसने यह आशा जगाई कि गैर-निष्पादन परिसंपदा समस्या अपने शीर्ष तक पहुंच चुकी है और यह अब नीचे आ रही है। इसके अतिरिक्त, 2019 में, पी एस बी ने अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के 421 बिलियन के लाभों अथवा एन पी बी के 390 बिलियन लाभों की तुलना में 661 बिलियन की हानि वहन की। एन पी से होने वाली हानियों के साथ-साथ, कपट भी पी एस बी की चिंता का एक और विषय है। भारतीय रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षी विवरणी से पता चलता है कि 2017-2018³ में रिपोर्ट किए गए कपट के 5835 मामलों में से 92.9 प्रतिशत और लगभग 41,000

करोड़ की कपट राशि में से 85 प्रतिशत पी एस बी की हैं। विगत में पी एस बी की उपलब्धियों के बावजूद भी, जैसा इस अध्याय में पहले काफी बताया जा चुका है, पी एस बी आज स्पष्टतः कार्यक्षम नहीं है।

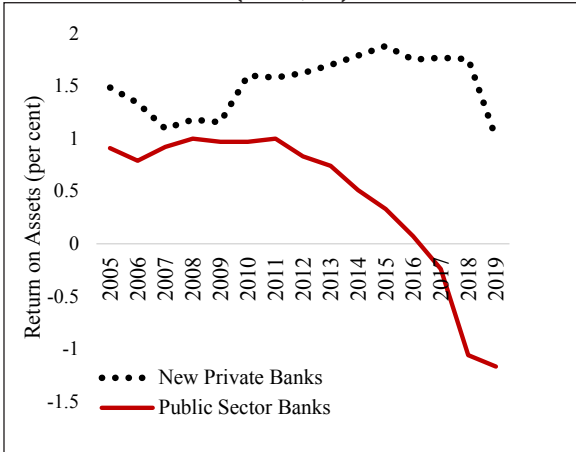
औसत की तुलना करना

7.19 सामयिक रुझान, जो पी एस बी और एन पी बी की “अंतर-में-अंतर” से तुलना करता है उससे पता चलता है कि पी एस बी की कमजोरियां अचानक विकसित नहीं हुईं। चित्र 8 2005 से 2019 के बीच पी एस बी और एन पी बी के लिए परिसंपदाओं पर प्रतिलाभ (आर.ओ.ए.) उल्लिखित करती है। जहां 2009 से पहले पी एस बी और एन पी बी की एक समान आर ओ ए हुआ करती थी, वहीं 2009 में पी एस बी की आर ओ ए ने गिरना आरंभ कर दिया तथा 2019 तक यह गिरती ही रही। एन पी बी की आर ओ ए 2013 तक बढ़ती रही, तत्पश्चात गिरने लगी, जो 2013 से सभी बैंकों में एक समान प्रवृत्ति ही परिलक्षित करता है। यद्यपि, पी एस बी की आर ओ ए कहीं अधिक तीव्र गति से गिरी है।

³ 29 अगस्त, 2018 को जारी आर बी आई की वार्षिक रिपोर्ट के अध्याय VI से लिए गए आंकड़े, प्राप्त किए जा सकते हैं <https://rbi.org.in/Scripts/AnnualReportPublications.aspx?id=1233>

7.20 चित्र 9 इक्विटी पर प्रतिलाभ (आर ओ ई) में इसी प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाता है। चित्र 10 और 11 सकल अग्रिम पर सकल और निवल एन पी ए के अनुपात को दर्शाता है। दोनों अनुपात 2010 के बाद पी एस बी के लिए काफी तेजी से बढ़ते चले गए परंतु एन पी बी के लिए यह वृद्धि हाल ही तक कम तीव्र अथवा यहां तक कि सपाट भी रही। चित्र 10 और 11 स्पष्टतः संकेत देते हैं कि विगत कुछ वर्षों में विकसित परिसंपदा गुणता समस्या पी एस बी के निष्पादन की गिरावट का कारण है। चित्र 12 दो प्रकार के बैंकों के कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात प्रदर्शित करता है जबकि चित्र 13 कोर 'टियर 1' पूंजी

चित्र 8: बैंकों की परिसंपदाओं पर परिलाभ (प्रतिशत)

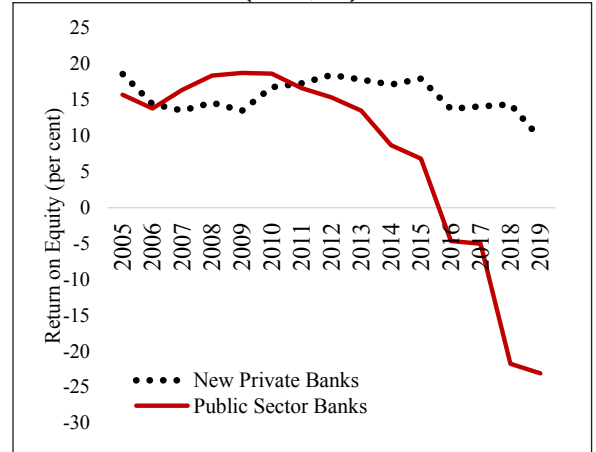


स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

अनुपात प्रदर्शित करता है। ये अनुपात दर्शाते हैं कि बैंक की हानियों ने पीएसबी के पूंजी आधारों को उनके निजी सह-संगणकों की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचाया है।

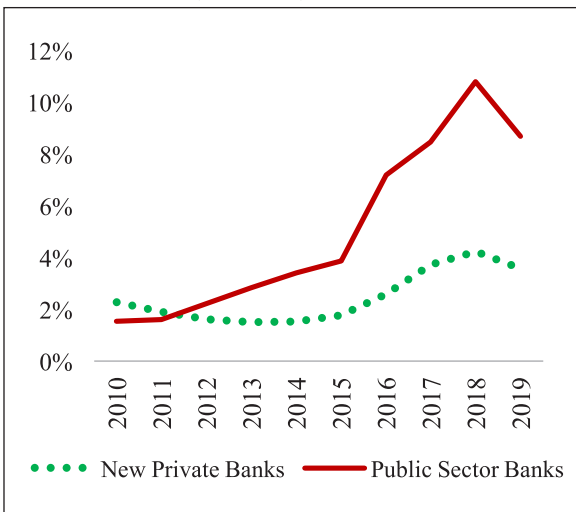
7.21 पीएसबी की एनपीए समस्याओं की एक संभाव्य व्याख्या यह है कि वर्ष 2004 और 2011 के बीच भारतीय अर्थ-व्यवस्था की वृद्धि के चरण में पीएसबी ने अपने ऋण संविभाग (पोर्ट फोलियो) को तो विकसित किया परंतु यह ऋण वृद्धि संदिग्ध गुणता की थी। जब अर्थव्यवस्था की गति धीमी हुई, तो बैंकिंग प्रणाली में एनपीए में आकस्मिक वृद्धि हुई।

चित्र 9: बैंकों की इक्विटी पर परिलाभ (प्रतिशत)



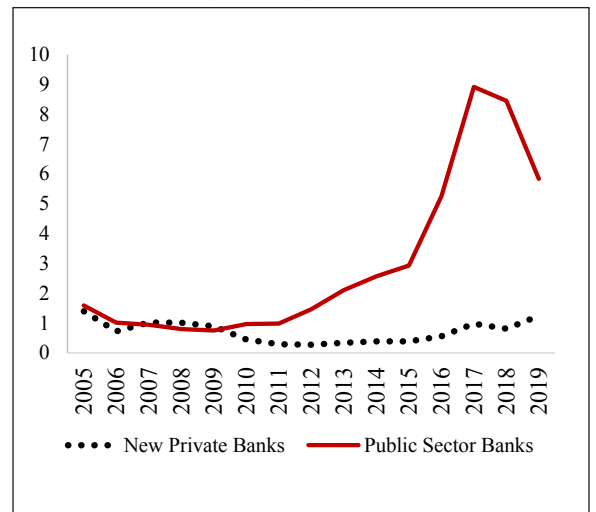
स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

चित्र 10 सकल गैर-निष्पादन परिसंपदा अनुपात (प्रतिशत) अग्रिम



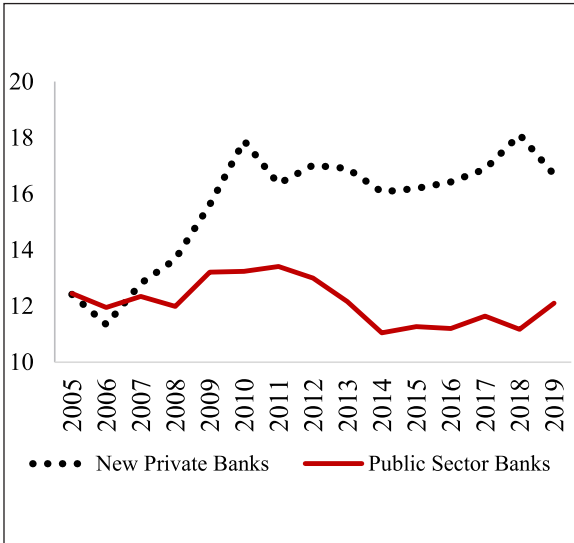
स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

चित्र 11: निवल गैर-निष्पादन परिसंपदा अनुपात (प्रतिशत) अग्रिम



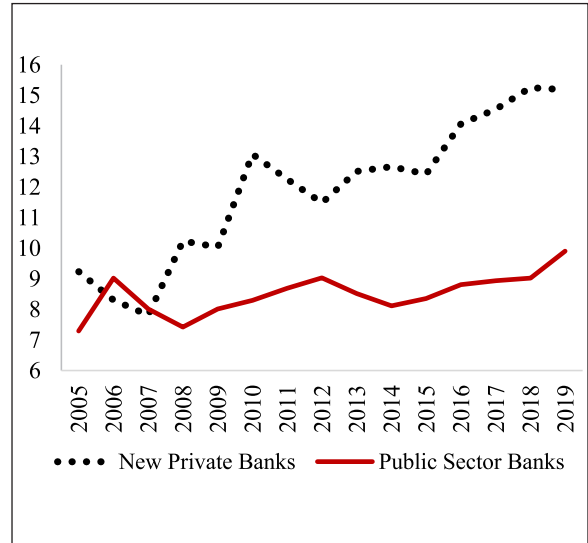
स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

चित्र 12 कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात (प्रतिशत)



स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

चित्र 13 स्तर-1 पूंजीगत पर्याप्तता अनुपात (प्रतिशत)



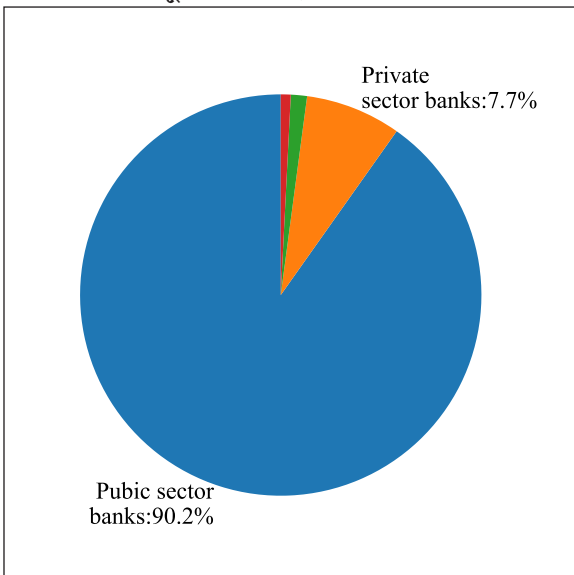
स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

7.22 चित्र 14क: इस तथ्य को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि धनराशि के आधार पर बैंक धोखाधड़ी के 90 प्रतिशत से अधिक मामले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में हुए। धोखाधड़ी के कुल मामलों में निजी बैंकों का अंश 8 प्रतिशत से कम है। इन धोखाधड़ी मामलों का बड़ा हिस्सा (90.2 प्रतिशत) अग्रिम राशियों से संबंधित है

(चित्र 14ख)। चक्रवर्ती (2013)। इस बात पर प्रकाश डालता है कि अग्रिम के लगभग 90 प्रतिशत मामलों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि होती है। इसलिए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अंगीकृत ऋणनीति में स्क्रीनिंग और मानिटरन प्रक्रिया की गुणवत्ता पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

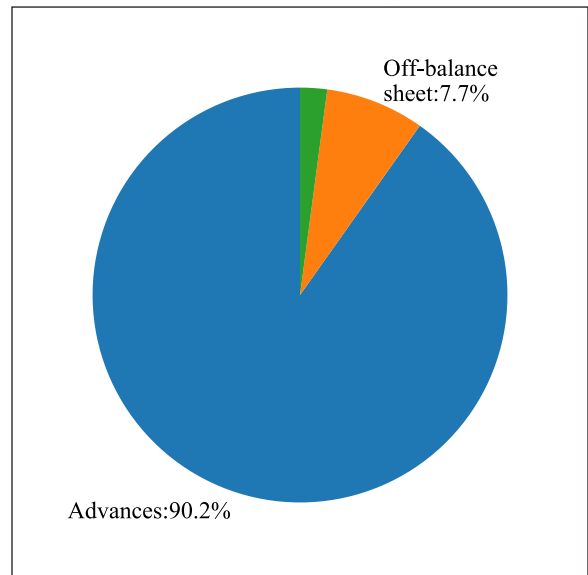
चित्र 14: बैंकों में धोखाधड़ी (प्रतिशत)

क. अंतर्निहित राशि के आधार पर धोखाधड़ी की समूह-वार संक्षिप्त जानकारी



स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

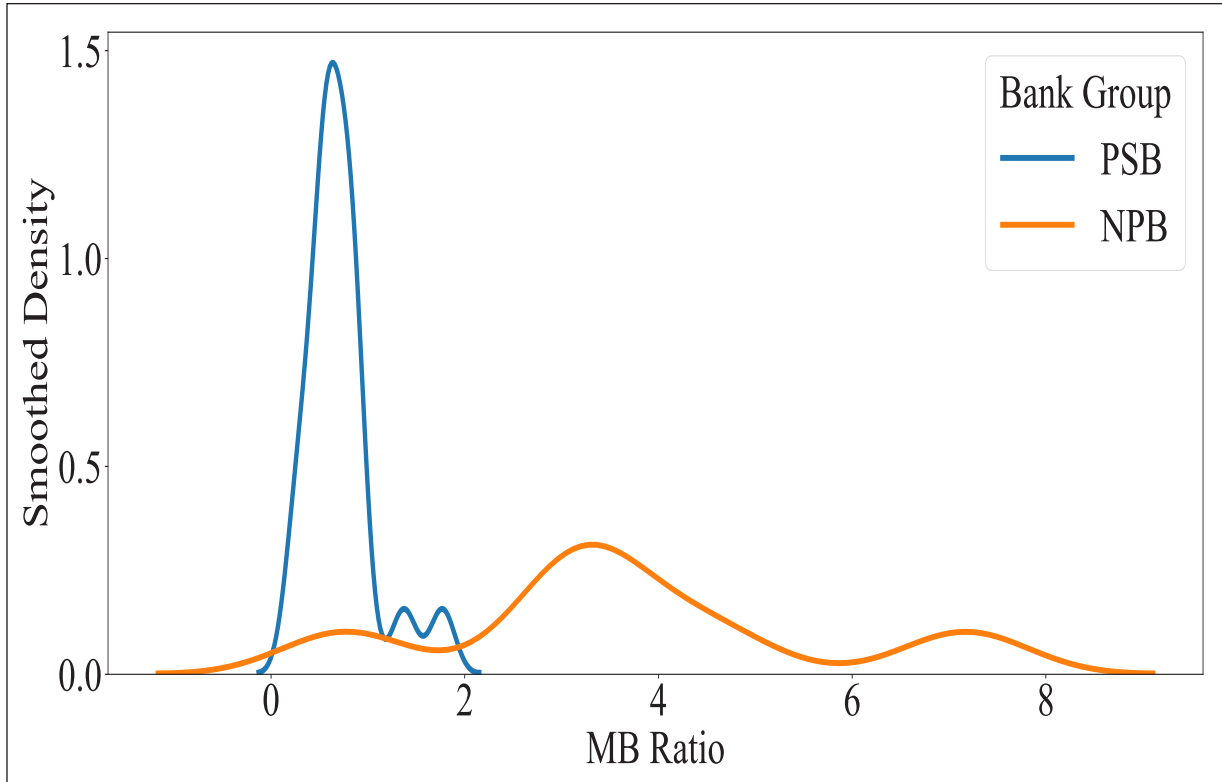
ख. अंतर्निहित राशि के आधार पर धोखाधड़ी मामलों की प्रचालन-वार संक्षिप्त जानकारी



7.23 मैट्रिक्स की श्रृंखला में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का खराब प्रदर्शन उनके इक्विटी मूल्यों में भी परिलक्षित होता है। चित्र 15 में दो प्रकार के बैंकों के लिए इक्विटी के बुक किए गए मूल्य के मुकाबले इक्विटी के बाजार

मूल्य के अनुपात को दर्शाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का औसत बाजार से बही अनुपात 0.64 के तुल्य है, जो एन पी बी के लिए 3.33 की माध्यिका 1/5 से भी कम होता है।

चित्र 15: बैंकों के मार्केट-टू-मार्किट अनुपात का संवितरण



स्रोत: मनी कंट्रोल से प्राप्त आंकड़े

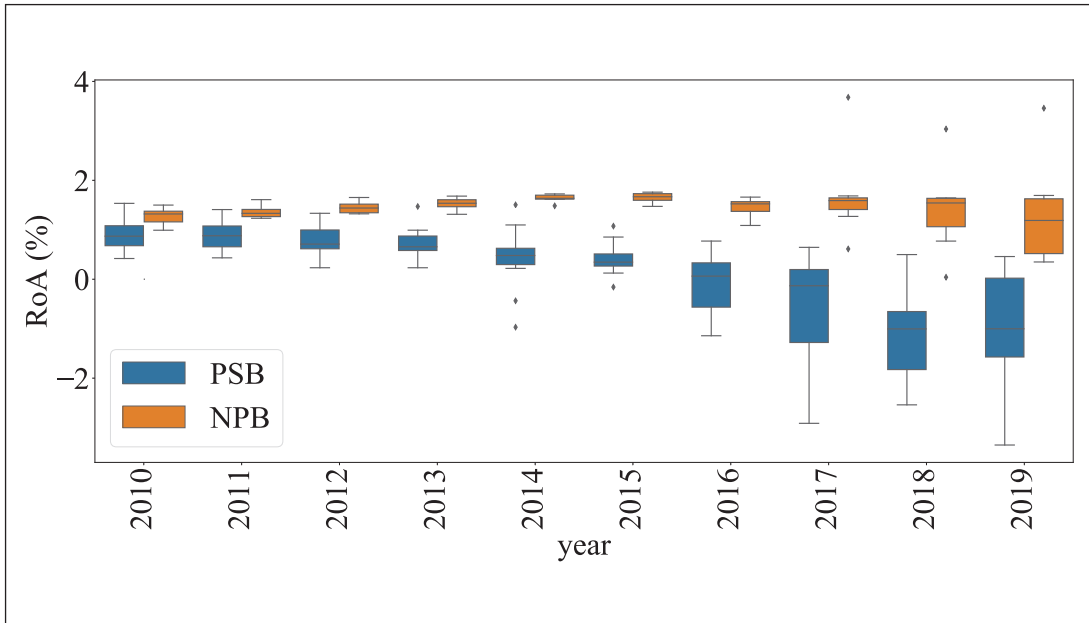
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मध्य और नए निजी बैंकों के मध्य विविधता तुलना

7.24 इस बात का सावधानी पूर्वक उल्लेख किया जाना चाहिए कि क्यों सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के औसत निष्पादन और नए निजी बैंकों में औसत निष्पादन के बीच तुलना एक उपयुक्त, 'सेब से सेब' तुलना होती है। किसी भी आर्थिक क्रियाकलाप के साथ, निष्पादन में विविधता का होना अवश्यम्भावी होता है। क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच भी उनके निष्पादन में बड़ा अंतर होता है, सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों का निष्पादन अन्य बैंकों की तुलना में बेहतर होता है; इसी प्रकार, नए प्राइवेट बैंकों के निष्पादन में भी ऐसा ही अंतर होता है। किंतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के औसत निष्पादन की साथ तुलना और किसी नए प्राइवेट बैंक के कमजोर निष्पादन के साथ तुलना सही नहीं है क्योंकि इसमें दो सांख्यिकी उपाय-औसत एवं इनके विचलन को शामिल

किया जाता है तथा "एप्पल-से-औरेंज" तुलना की ओर अग्रसर होता है। इसी प्रकार, नए प्राइवेट बैंकों के निष्पादन में भी ऐसा ही अंतर होता है। किंतु, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के औसत निष्पादन की नए प्राइवेट बैंक के बेहतर निष्पादन के साथ तुलना और किसी नए प्राइवेट बैंक के निकृष्ट निष्पादन के साथ तुलना सही नहीं है क्योंकि इसमें दो सांख्यिकीय मापकों - औसत एवं इनके विचलन को मिश्रितकर लिया जाता है तथा यह "सेब से संतरे की" तुलना की ओर ले जाता है।

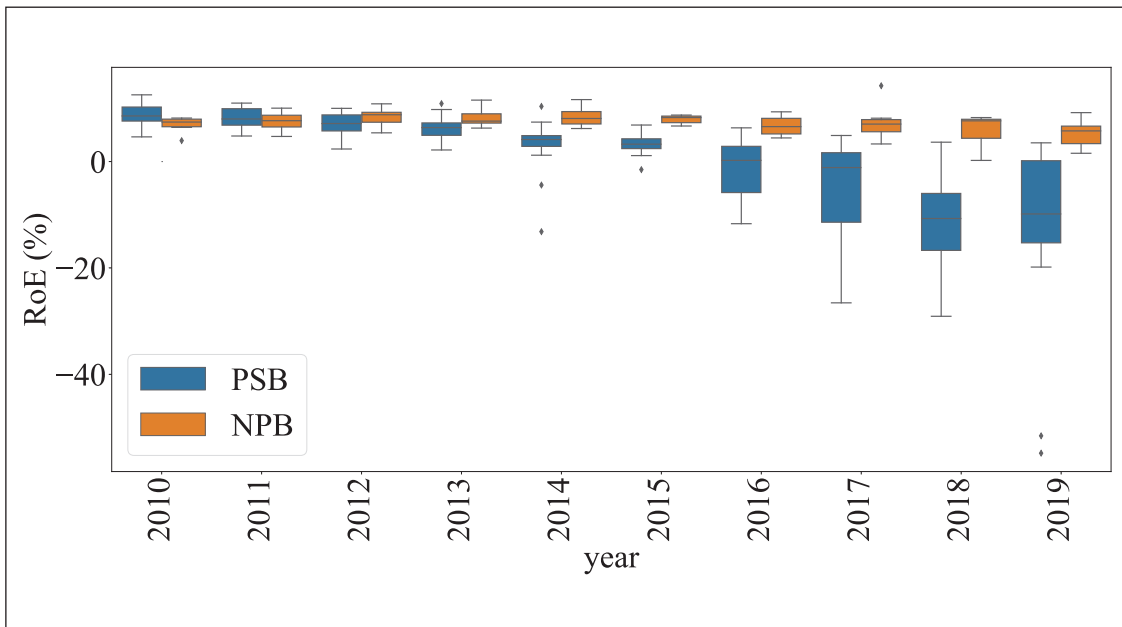
7.25 निष्पादन में विविधता के लेखाकरण द्वारा तुलना करने के लिए हम चित्र 16 के बाक्स प्लॉटों में पीएसबी तथा एनपीबी के लिए आरओए के वितरण का निरीक्षण करते हैं। बाक्स प्लॉट को समझने के लिए बॉक्स 3 देखें। इस चित्र से यह स्पष्ट है कि वर्ष 2013 से प्रत्येक वर्ष के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले पीएसबी का आरओए खराब प्रदर्शन करने वाले एनपीबी के आरओए से कम है। इसी प्रकार का दृश्य, यद्यपि कुछ कम, आरओई में भी दिखाई दिया है।

चित्र 16क: परिसपत्तियों पर प्रतिप्राप्ति में विविधता



स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

चित्र 16ख: इक्विटी पर प्रतिप्राप्ति में विविधता



स्रोत: आरबीआई आकड़े और समीक्षा परिकलन

बॉक्स 3: बॉक्स प्लॉट की व्यवस्था

बाक्स प्लॉट में (क) न्यूनतम को क्षैतिजाकार रेखा से निरूपित किया गया है, (ख) आयत के निचली रेखा द्वारा निरूपित प्रथम चतुर्थांश (ग) आयत के अंदर की रेखा द्वारा निरूपित माध्यिका, (घ) आयत की शीर्ष रेखा पर द्वारा निरूपित तीसरा चतुर्थांक (ड.) सबसे ऊपरी क्षैतिजाकार रेखा द्वारा अधिकतम को निरूपित किया जाता है।

7.26 ये सांख्यिक विरोध रूप में प्रभावकारी हैं चूँकि दोनों, एनपीवी एवं पीएससी, एक ही घरेलू बाजार में प्रचालित होते हैं। फिर भी, हमें बैंक निष्पादन में अनियमितता दिखाई देती है जिससे पिछले दशक में इन्हें विशेषरूप में विभाजित किया है। यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि स्थितियाँ निश्चित रूप से पिछले दशक में बैंकों द्वारा लिए गए खराब निर्णयों को निरूपित नहीं करती। विश्व में वित्तीय संकट का इतिहास यह दर्शाता है कि खराब अधिशासन का प्रभाव केवल खराब समय में दिखाई देता है, कभी-भी अच्छे समय में नहीं। जैसा कि 2014 पी.जे. नायक समिति रिपोर्ट में दर्शाई गई पीएसबी की संचालक कमजोरी उनके खराब निष्पादन को ही व्यक्त करती है।

7.27 कुछ लोग तर्क देते हैं कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान इस कमजोर कार्य निष्पादन का दौर अब जा रहा है। हालाँकि, इस व्याख्या में आवश्यक रूप से बैंकिंग क्षेत्र के संकट के पूर्व काल के बारे में सारभूत ज्ञान की कुछ उपेक्षा प्रतीत होती है, जिससे हमें यह पता चलता है कि बैंकिंग क्षेत्र का खराब कार्य निष्पादन अपरिहार्य रूप से अनेक प्रणालीगत कारकों से उत्पन्न हुआ है। जैसा कि लेवेन (2011) रेखांकित करते हैं कि बैंकिंग संकट के कारणों में अवहनीय समष्टि अर्थशास्त्रीय नीतियों, बाजारीय विफलताओं, विनियामक विकृतियों एवं पूंजी आवंटन में सरकारी हस्तक्षेप का एक संयुक्त रूप शामिल है। इसके अलावा जिन संकटों का प्रभावी तरीके से और तत्परता से समाधान न किया जाए वे समाज को व्यापक हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं।

पीएसबी की दक्षता बढ़ाना: भावी परिदृश्य

7.28 अब भारत की संवृद्धि संभाव्यता के महत्वपूर्ण चालक (क) अनुकूल जनसांख्यिकी 15 से 29 वर्ष के बीच की 35 प्रतिशत आबादी; (ख) आधुनिक एवं आधुनिक डिजिटल अवसंरचना जिसमें 'जेएएम' त्रिमूर्ति वित्तीय समावेशन आधार विशिष्ट पहचान प्रणाली एवं सुविकसित मोबाइल फोन नेटवर्क को शामिल किया गया है एवं (ग) अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली हैं ताकि विखण्डित, जटिल राज्य स्तरीय प्रणाली को प्रतिस्थापित

किया जा सके।¹³ भारत की प्रगति का मार्ग इस पर निर्भर करता है कि सुविकसित वित्तीय प्रणाली का प्रयोग कर इन विकास लीवरों का कितना त्वरित एवं उत्पादकता पूर्ण ढंग से नियोजन किया जाता है।

7.29 पहले पीएसबी की दक्षता में वृद्धि करने के लिए नरसिंहा समिति (1991, 1997) राजन समिति (2007) एवं पीजे नायक समिति के अनेक सुझाव प्राप्त हुए हैं। अतः समीक्षा में पीएसबी दक्षता को बढ़ाने के लिए दो विचारों पर बल दिया गया है जिन पर अभी कार्य नहीं किया गया है।

कृत्रिम आसूचना एवं मशीन शिक्षण का प्रयोग करके साख विश्लेषण

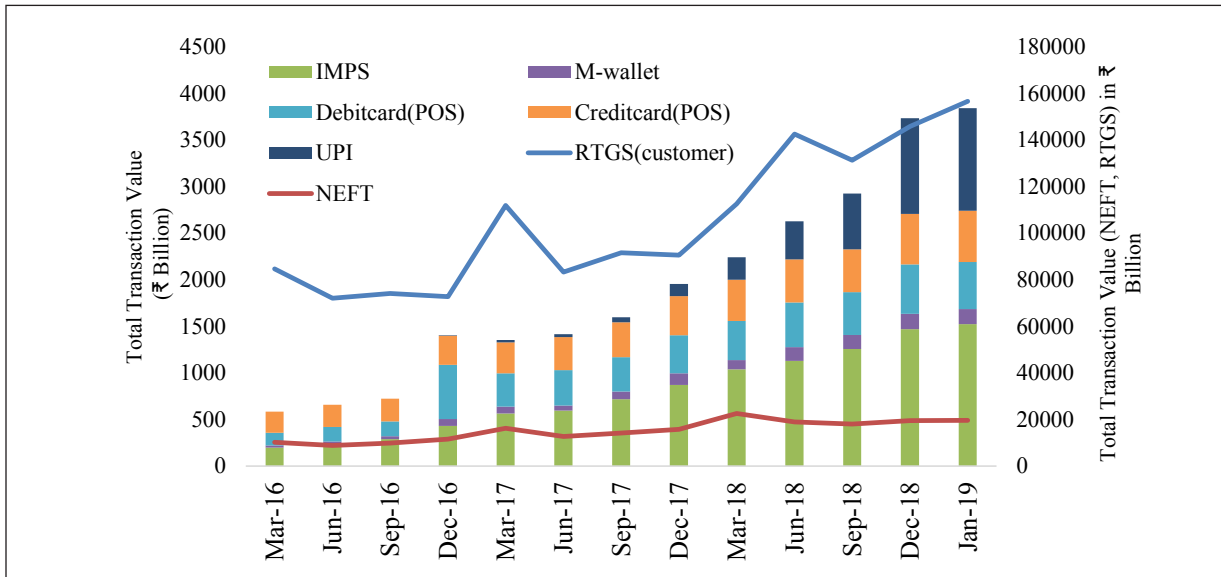
7.30 आज भारत के विकास अवसर जो कि अनेक सकारात्मक स्थितियों के अनोखे संगम से उपजता है जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक फिन टेक का सही अर्थों में उपयोग करने की स्थिति में आते हैं। इनमें से एक भारत का जनसांख्यिकी अंश है। भारत की 62 प्रतिशत आबादी 15 और 60 के बीच में है। इसके अतिरिक्त आबादी का 30 प्रतिशत 15 से नीचे की है। अतः भारत लंबे समय तक महत्वपूर्ण कार्यशील आयु वर्ग के लाभों को लेने के लिए तैयार है। भारत के विकास अवसरों को गति देने के लिए जो दूसरा कार्यबल है वो जेएएम "ट्रिनीटी" है उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री जन धन योजना बैंक खाता कार्यक्रम, विशिष्ट पहचान पत्र कार्यक्रम और मोबाइल फोन अवसंरचना जिनमें से प्रत्येक को व्यवहारिक तौर पर पूरे देश को शामिल करने के लिए क्रियान्वित किया गया। इन दो कारकों के परिणामस्वरूप डिजिटल लेन-देनों में वृद्धि उल्लेखनीय रही। (चित्र 17)। सापेक्ष लाभ अंतरणों जोकि गत पांच वर्षों में तेजी से बढ़ा है (चित्र 18), से बैंकिंग प्रणाली में सात और जमा दोनों ही सम्पूर्ण भू-भाग में लाने में सहायता मिली (चित्र 19)। ग्रामीण, अर्धशहरी, और महानगर (चित्र 19) में सभी भू-भाग पर दर्शायी गई उच्च लोच सरकार द्वारा डीबीटी के अधिकतम उपयोग से लाभ प्राप्त करने हेतु भारतीय बैंकों के लिए मौजूदा अवसरों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

¹³ जेएएम ट्रिनीटी डिजिटल अवसंरचना का समर्थन करती है। "प्रधानमंत्री जन धन योजना" बैंक खाता में 37.8 करोड़ लाभार्थियों ने नामांकन किया जिनके बैंक बैलेंस 1.11 लाख करोड़ के पार हो गया। 120 करोड़ से अधिक विशेष पहचान पत्रों को जारी किया गया। 137 करोड़ की भारत की जनसंख्या के लिए 128 करोड़ मोबाइल फोनों और यूटीफाइड पेमेंट इंटरफेस को दिए गए।

7.31 उपर्युक्त सभी संभावनाएँ यह दर्शाती हैं कि भारतीय बैंक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के स्तर के

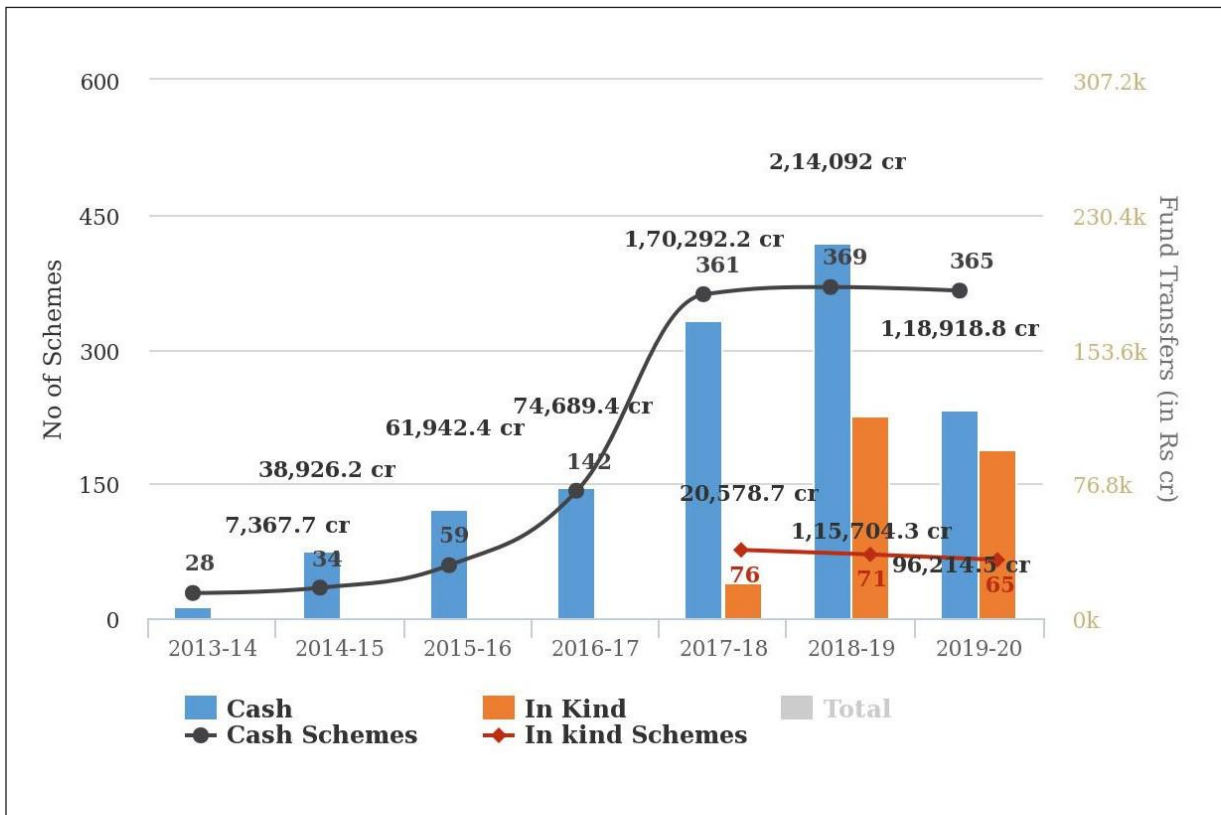
अनुपात में विकास करे। नए कार्यक्रम औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाये जा रहे व्यक्तियों एवं व्यापार के

चित्र 17: मार्च 2016 - जनवरी 2019 के बीच डिजिटल लेनदेन का कुल मूल्य



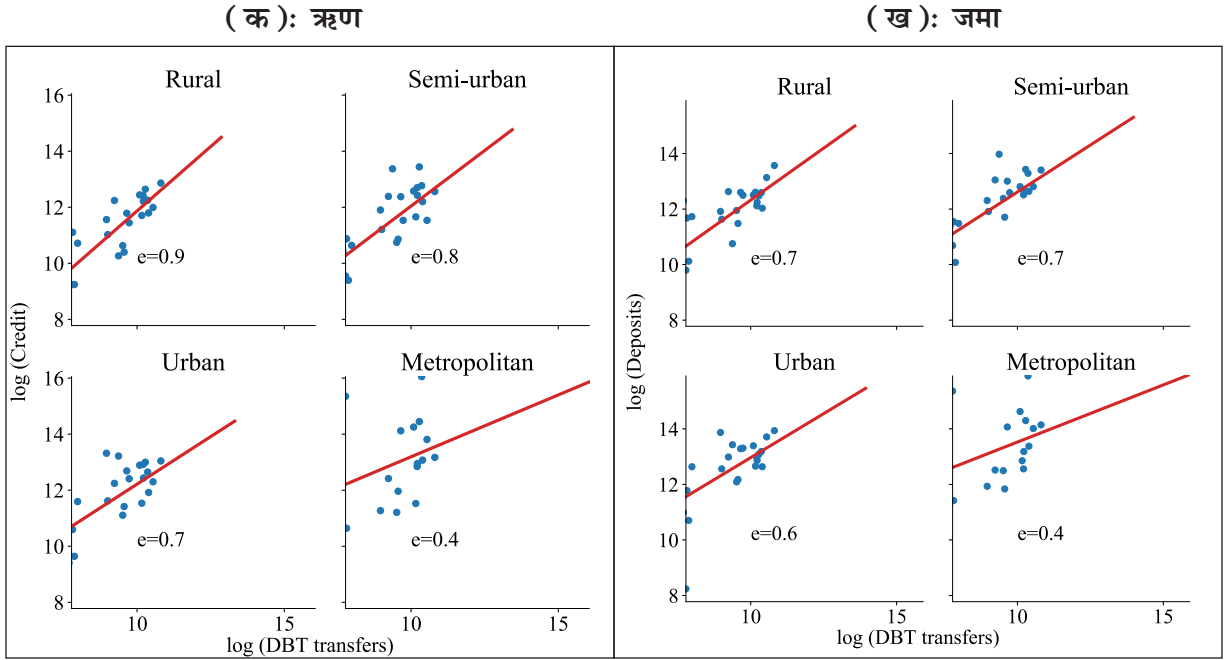
स्रोत: भुगतान प्रणाली सूचकांक, आरबीआई

चित्र 18: अंतरित राशियों के रूझान तथा डीबीटी स्कीमें



स्रोत: डीबीसी

चित्र 19: बैंकिंग सिस्टम के लिए डीबीटी के लाभ



स्रोत: डीबीटी, आरबीआई और समीक्षा परिकलन

आवेश परिणामस्वरूप है। यद्यपि अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अत्याधुनिक डिजिटल अवसंरचना जो कि सभी फर्मों के आर्थिक गतिविधियों पर बहुतायत में उच्च गुणवत्ता संरचनात्मक आंकड़ों को सृजित और एकत्रित करता है। ऐसे आंकड़े आवश्यक ही 21वीं सदी की आर्थिक वृद्धि के लिए सोने की खान है। विशेषरूप से फर्मों और व्यक्तियों जो परंपरागत रूप से वित्तीय प्रक्रिया से अलग किए गए हैं उनके लिए अनिवार्य असीमित और गैर सूचित संभावनाएं प्रदान करते हैं।

7.32 पीएसबी के पा अनेक महत्वपूर्ण पदार्थ है जिनसे नई मांगों को पूर्ण किया जा सकता है? उदाहरण के लिए, उनके पास स्थानीय बाजार नजर और अनेक दशकों की ऐतिहासिक परिचालन पर आधारित है। उनकी भौगोलिक पदचिन्ह बहुत बड़े हैं। यद्यपि, पीएसबी को भारत में आने वाले महत्वपूर्ण विनिवेशों की योग्यता की आवश्यकता है। बाजार पर आधारित विश्लेषण आंकड़े कापरेट तलाव को सही अनुमानित करने में सक्षम है। इस प्रकार की पहुंच उपभोगता ऋण और व्यवसायिक

एवंम औद्योगिक ऋण को पकड़ने का कदम रखते हैं।

7.33 वह आंकड़े जो कि ऋण विश्लेषण के लिए आवश्यक है वह संरक्षित और असंरक्षित रूप दोनों में ही उपलब्ध है। संरक्षित रूप में उपलब्ध आंकड़े ऋण सूचना और ऋण स्कोर ऋण के अनुमोदन पर आधारित है और पुर्नभुगतान ऋण रजिस्ट्री या ऋण ब्यूरो में होता है। पर्याप्त, हालांकि असंरक्षित, सूक्ष्म आंकड़े विषय, भू-चिन्हित आंकड़े, सोशल नेटवर्क आंकड़े, मोबाइल एप, साथ ही साथ वर्तमान और भावी ग्राहकों के अन्य छोटे या गहरे डिजिटल फूटप्रिन्ट है। इन आंकड़ों का लाभ उठाने के लिए नये आंकड़ों, विश्लेषण और मॉडलिंग तरीके की आवश्यकता है। इसी तरह, बैंक को ऋण की वसूली अवसंरचना में निवेश करने की आवश्यकता है। इन नई तकनीकों के प्रयोग से आंकड़े से भरा हुआ माहौल को अतिरिक्त विनिवेश जैसे कि विशिष्ट मानव पूंजी की तरफ झुकाव है। ऐसी तकनीकों से रूकावट अजेय नहीं होती है। हालांकि ऐसे कुछ उदाहरण है जहां पीएसबी में कुछ ढीलापन, तकनीकी

विरोध पीएसबी को कोई अन्तर्भूत विशेषता नहीं लगती है। उदाहरण के लिए, जब ऋण ब्यूरो को भारत में लाया गया था तब पीएसबी पूर्णतः बहुत तेजी से नए ग्राहकों को लपकने में उत्तेजित था। (मिश्रा, राजन और प्रभाला, 2019)

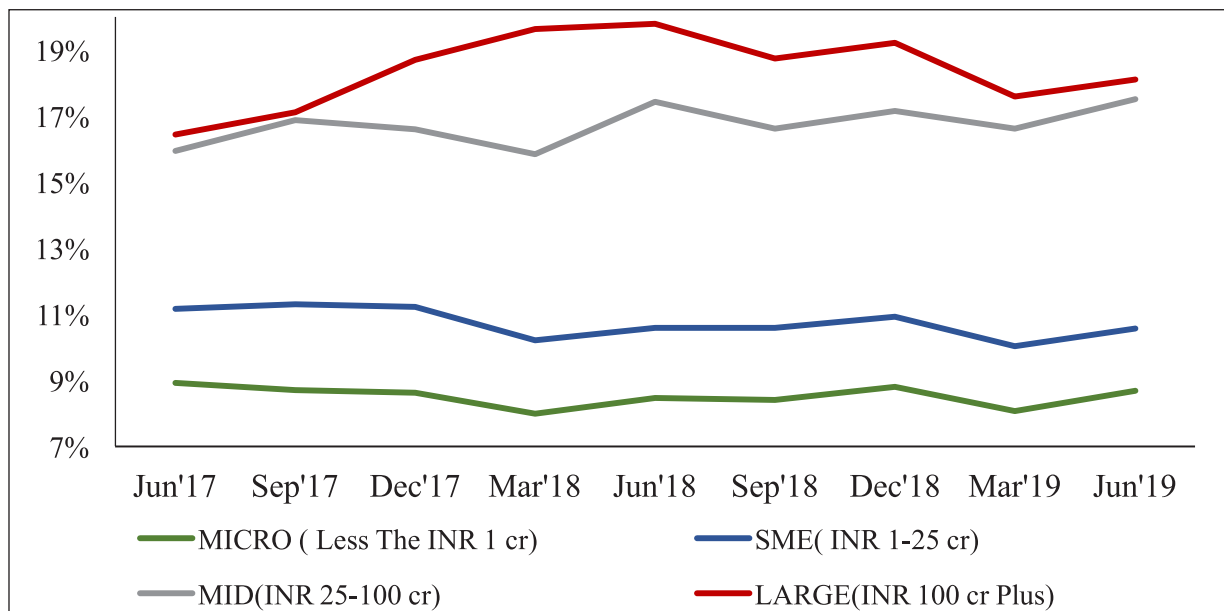
ऋण विश्लेषण के लाभ

7.34 भारतीय बैंकों के एनपीए के बहुत बड़े भाग को बचाया जा सकता था यदि आंकड़े और विश्लेषण को कॉरपोरेट ऋण में नियोजित किया जाता। चित्र 10 यह दर्शाता है कि दोषपूर्ण ऋण की दर बहुत बड़े ऋणों (100 करोड़ से बड़े उच्चतर है। चित्र 21-24 विभिन्न मुख्य संकेतकों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है जो आंकड़े

और विश्लेषण का प्रयोग कर जानबूझ वाले दोषियों को दिखा सकता था। चित्र 21 यह दर्शाता है कि संबंधित पार्टी अंतरण के खुलासे में चरणबद्ध अंतर, प्रोत्साहकों का शेयर की शपथ संबंधित पार्टियों के जानबूझकर दोषी और हताश दोषी के बीच है यह बड़े सरल मात्रानिर्धारक उपाय है जो कि एक मजबूत साख विश्लेषणात्मक संकेत प्रणाली देती है।

7.35 भारतीय रिजर्व बैंक ने जून, 2017 में 12 कंपनियों की पहचान की, जिनके पास भारत के कुल गैर निष्पादित संपत्ति का 25 प्रतिशत जमा था। ये 'डर्टी डजन' जैसे रेखा चित्र 22 में दिखाया है,

चित्र 20: गैर-निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) ऋण के आकार का रेट



स्रोत: ट्रांस यूनियन सिविल सिडबी

2012, 2013 और 2014 में अन्य समान सूचीबद्ध कॉरपोरेट्स के माध्य लेखा गुणवत्ता से इनकी लेखा गुणवत्ता बहुत कम है। चूंकि लेखा गुणवत्ता आसानी से मापी जा सकती है, एक ठोस ऋण वैश्लेषिकी प्लैटफॉर्म आसानी से इसकी पहचान करके चेतावनी

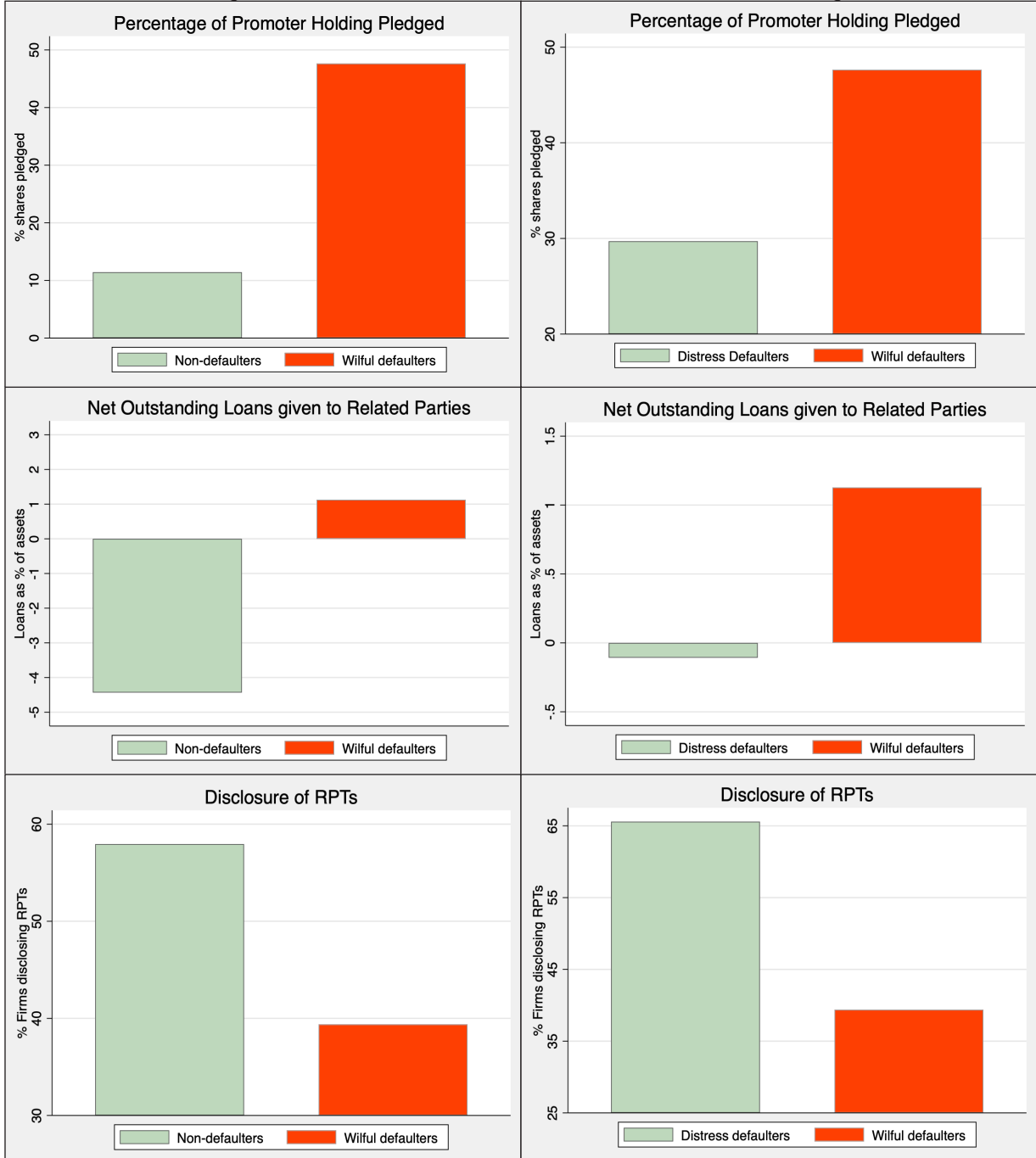
दे सकते हैं।

7.36 इन बड़े दोषियों की वार्षिक रिपोर्ट का विश्लेषण यह सूचित करता है कि इन कंपनियों की लेखा परीक्षा प्रकटीकरण बहुत कमजोर है। जैसे रेखाचित्र 23 में देखा

चित्र 21: संबद्ध पक्ष लेनदेन, संस्थापकों के शेयर गिरवी रखे जाने तथा संबद्ध पक्षों को बड़े ऋण आदि के प्रमुख संकेतक।

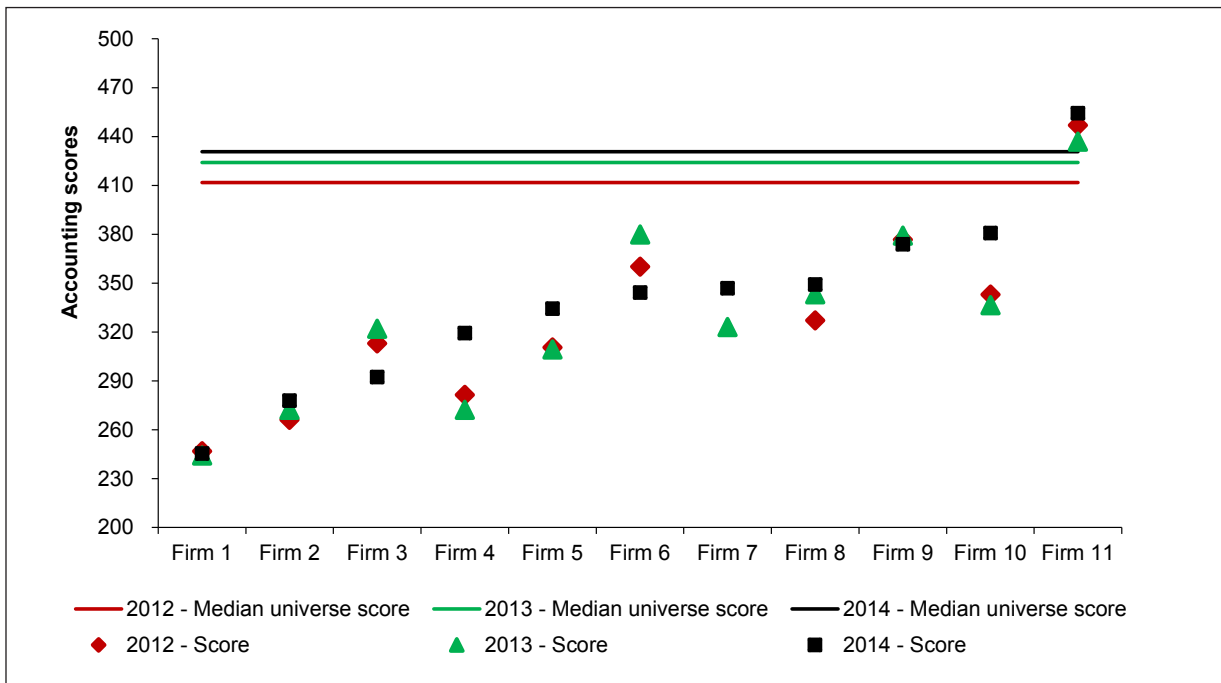
पैनल 'क' जनाबूझकर तथा विवश दोषियों की तुलना

पैनल बी: जानबूझकर दोषियों और गैर-विवरण दोषियों की तुलना



स्रोत: सीएमआईई कौशल, ट्रांसयूनियन सीबीएल सूटस फाईड डाटाबेस, टिप्पणी: एक फर्म को एक आरपीटी खुलासा बनाना है यदि इसके वार्षिक फाईलिंग में आरजीपी सेक्शन निहित हैं (भले ही कोई फर्म यह कहती है कि उसने वर्ष में कोई भी अंतरण नहीं किया है) कुल बकाया ऋण, फर्म द्वारा उनकी संबंधित पार्टी को दिए गए ऋण के कुल शेष को दर्शाता है। जानबूझकर दोषी वह कहलाते हैं जो कि सीबीएल सूटस फाईड डाटाबेस में वर्गीकृत किए गए हैं। जबकि हताश दोषी वह हैं जो किसी सैपल अवधि में दोषपूर्ण क्रेडिट रेटिंग में केवल एक बार दोषी पाए गए लेकिन वह जानबूझकर दोषी की श्रेणी में नहीं हैं। गैर दोषी अन्य फर्म हैं। यह आंकड़े 2002-18 तक विस्तारित हैं।

चित्र 22: बड़े दोषियों के लिए लेखा गुणवत्ता उपायों से स्पष्ट प्रमुख सूचक



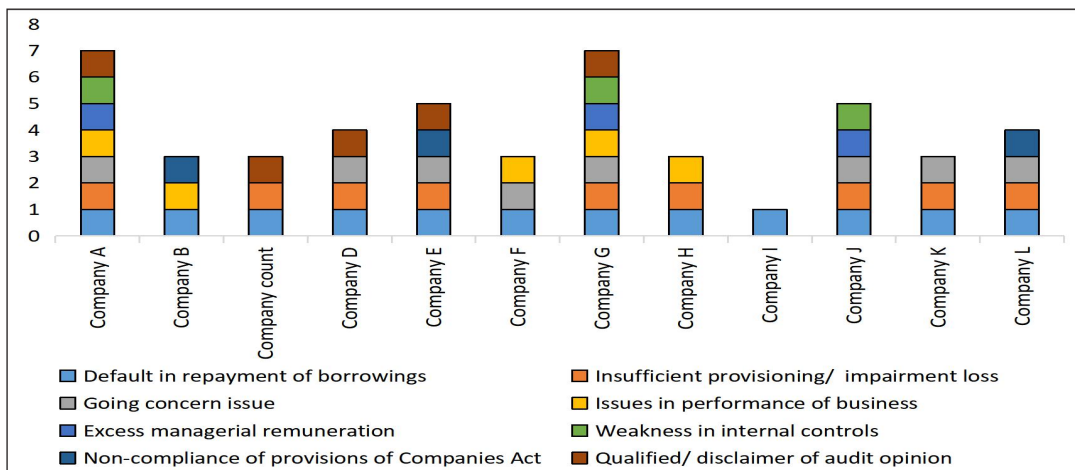
स्रोत: कंपनी वित्तीय, दिवाला और दिवालियापन बोर्ड ऑफ इंडिया

जा सकता है, इनमें से एक का सिर्फ एक संकेतक का प्रकाशन हुआ है जबकि तीन से चार संकेतकों वाले अन्य लोगों ने अग्रणी और विलंबित संकेतकों का खुलासा किया है। पुनः यह एक आसानी से नापने योग्य

लक्षण है, जिसकी पहचान एक ठोस ऋण वैश्लेषिकी प्लैटफार्म आसानी से कर सकता है।

7.37 रेखाचित्र 24 दर्शाता है कि 2014 तक उधरदाताओं के बीच एनपीए पर जानकारी साझाकरण

चित्र 23: बड़े दोषियों के वित्तीय विवरण से उदघाटित अग्रणी और पिछड़ा संकेतक

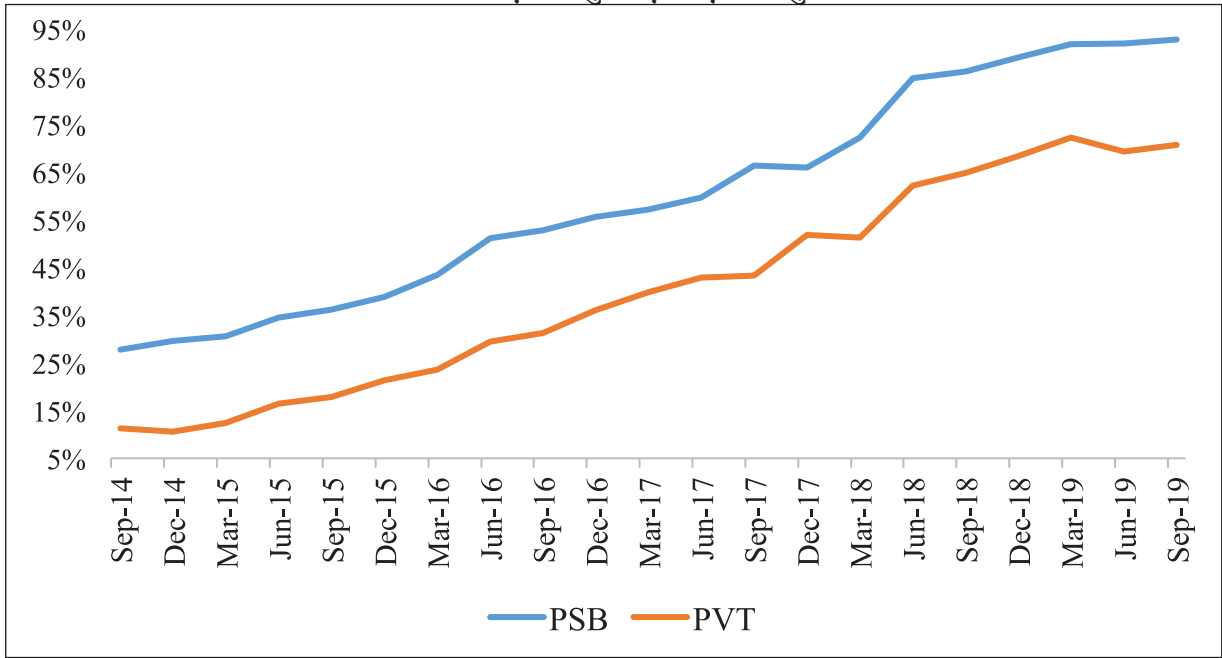


स्रोत: कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट तथा समीक्षा परिकलन

न्यूनतम था। जबकि पीएसबी में जानकारी साझाकरण एनपीवी से ज्यादा बेहतर था, अन्य बैंकों द्वारा एनपीए घोषित बैंक खातों में से लगभग एक चौथाई, एनपीए के

रूप में वर्गीकृत थे। कुछ ही सालों में इस अनुपात में नाटकीय वृद्धि हुई है और यह 95 प्रतिशत तक पहुंच गई है।

चित्र 24: अन्य बैंकों द्वारा अपनी बहियों में एनपीए घोषित ऋणदाताओं का पहले से ही घोषित किए जा चुके एनपीए से अनुपात



बॉक्स 4: लेनदारों की कोलिट्रल बचाने के लिए लेवरेजिंग आंकड़ों पर एक नोट

बॉक्स 4: अधिकतर कारपोरेट अवधि ऋण सुरक्षित होते हैं और ऋणदाताओं के पास अपनी संपत्ति को ऋण की गैर अदायगी की स्थिति में शपथ पर रखते हैं। हालांकि, जब जानबूझ कर की गई गैर अदायगी से सरोकार रखा जाता है तो ऋणदाता अपने हाथों को बंधा हुआ महसूस करता है चाहे वह शपथ परिसंपत्तियों ही क्यों न हों। जब जानबूझ कर की गई चूक वाले लोगों के पास एक आसान तरीका होता है अपनी कोलिट्रल की कीमत को गलत बताने का। अधिक खराब मामलों में, यह लोग झूठी कोलिट्रल की शपथ लेते हैं। यदि ये वास्तविक कोलिट्रल की शपथ लें तो उनके पास उन संपत्तियों को बिना ऋणदाता के जानकारी के निपटा देने का नियंत्रण होता है या अपनी संपत्तियों से नियंत्रण को चूक की स्थिति में खो देते हैं।

इन मामलों में आंकड़े ऋणदाताओं के पास आते हैं। उदाहरण के लिए जीओ टैगिंग - छवियों, वीडियो या अन्य मीडिया में चौड़ाई और लंबाई जैसी भौगोलिक पहचान को लगाने की प्रक्रिया - जो कि ऋणदाताओं को परिसंपत्तियों की लोकेशन को पकड़े रखने में सहायता देती है। यदि ऋणियों को सम-समायिक रूप से अपने कोलिट्रल संपत्तियों की जीओ टैग प्रमाण अपने ऋणदाताओं से साझा करनी पड़े तो उनके लिए इन परिसंपत्तियों को चोरी से हटाना मुश्किल होगा। विभिन्न सरकारी विभागों ने पहले से ही जीओ टैगिंग में बढ़त ले ली है; ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मनरेगा संपत्तियों को जीओ टैग करता है और भूमि संसाधन विभाग में वाटरशेड परियोजनाओं में जीओ टैग किया है। इन उदाहरणों से ऋणदाता अपनी कोलिट्रल की निगरानी करना सीख सकते हैं। जीओ टैग शपथ की गई भूमि या संपत्ति की कीमत को जांच सकती है। भूमि की सही लोकेशन को पकड़ सकती है, ऋणदाता इन संपत्तियों की बाजारी कीमत को बढ़िया तरीके से मूल्यांकित कर सकती है, और ये सब सूचनाएं लोकेशन से प्राप्त हो सकती हैं।

जीपीएस प्रणाली से और अधिक निगरानी की जा सकती है। जीपीएस उपकरणों को जब मशीनों या उपकरणों से जोड़ा जाता है तब यह ऋणदाताओं को संपत्तियों को हटने की स्थिति में सावधान करती है। यह नजर रखने वाली प्रणालियों यह सुनिश्चित करती हैं कि संपत्तियां ऋणदाताओं की नजरों से गायब न हों। उदाहरण के लिए किराये पर देने वाली

कंपनियों लैपटॉप, उपकरणों इत्यादि को लीज पर देती हैं, ने इस जीपीएस निगरानी का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से किया है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण अधिकांश एक ऐसे रिमोट स्विच के साथ आते हैं जिसको यदि किरायेदार खराब करने की कोशिश करे, निपटान करने की कोशिश करे या किराया देने में देरी करे तो उसकी सभी कार्यप्रणाली को बंद किया जा सकता है। वास्तव में यह ऋणदाताओं के लिए बहुत ही अच्छा उपकरण है क्योंकि यदि ऋणदाता ऋण का जानबूझ कर भुगतान न करे तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किंगफिशर एअरलाईन ने ऋण प्राप्ति के लिए कुछ हैलीकॉप्टरों की (अन्य संपत्तियों के साथ) शपथ लिया था। जब ऋणदाता इन संपत्तियों का अधिकार लेना चाहता है तो क्या वह यह महसूस करता है कि हैलीकॉप्टर की स्थिति खराब हो चुकी है और यह केवल कबाड़ी कीमत से कुछ ज्यादा ही निकाल पायेगी। इन सब में कम खर्च वाली तकनीक को संपत्ति की उपस्थिति के इस्तेमाल और गुणवत्ता को जानने के लिए किया जाता है।

किसी क्षेत्र में सभी ऋणदाताओं की संपार्श्विकता परसमेकित डाटा विशेषरूप से उसके दोबार गिरवी रखने की संभावना को कम करने में सहायक है उदाहरण के लिए के पक्षकार एक ही संपार्श्विक संपत्ति को एक ही परियोजना के लिए कई बार उधार लेने के लिए कई ऋणदाताओं या खरीददार या दोनों को अलग-अलग एक ही व्यापार के लिए उनके संबंधित ऋणदाताओं को एक ही बीजक पर उसनी संपार्श्विक संपत्ति गिरवी रख सकता है। जब तक ऋणदाता, व्यापारियों का सत्यापन करने के लिए मानवीय नियंत्रण प्रक्रियाओं या दस्तावेज आधारित प्रलेखन पर निर्भर रहेंगे तब तक इस प्रकार की दोहरा गिरवी रखना जारी रहेगा। स्विफ्ट इंडिया जिस मैसजिंग प्लेटफार्म का पंजाब नेशनल बैंक ने नीवर मोदी मामले में संदेश संप्रेषित करने के लिए किया था उसमें एक ऐसी प्रायोगिक ब्लॉक चेन प्रयास की घोषणा की गई है जो ऋणदाताओं को उन्हें ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए ई-बिल तथा बीजक लॉक करने की अनुमति प्रदान करता है तथा अल्प ऋणदाताओं को यह सत्यवित करने में सक्षम बनाता है कि वे जिस व्यवसाय के लिए वित्त पोषण करना चाहते हैं क्या वह पहले से ही वित्त पोषित तो नहीं है या उसमें निहित संपार्श्विक संपत्ति पहले से ही बंधक तो नहीं पड़ी है। इस प्रकार की एकीकृत डाटा प्रणाली ऋणदाताओं के संरक्षण प्रदान करने के लिए निवार्य है।

जहां ये प्रौद्योगिकी सशक्त हैं वहीं दूसरी ओर इनके साथ एक महत्वपूर्ण जोखिम भी जुड़ा रहता है अर्थात् उधारकर्ताओं की प्राइवसी और सम्मान के अंतर्गत का जोखिम। ऋणों के दायित्वों को लागू करने में उधारकर्ता के निजी क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए जब तक कि उधारकर्ता को उसके जानबूझ कर चूक करने का संदेह न हो। इसलिए जो भी डाटा एकत्रित किए जाएं, कैसे, किसके द्वारा और कब तक के, अनेक संबंध में प्रबल और स्पष्ट दिशानिर्देशों की आवश्यकता होती है।

सारांश रूप में जानबूझ कर चूक का अर्थव्यवस्था की मजबूती पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि उधारदाता गिरवी रखी गई परिसंपत्तियों को बेच कर अपनी देय राशि को पूरी तरह वसूल कर ले। प्रौद्योगिकी और डाटा का इन परिसंपत्तियों को सुरक्षित और बिक्री योग्य बनाए रखने के लिए प्रबलता से उपयोग किया जा सकता है। वास्तव में मूल्यवान परिसंपत्तियों को लोन का खतरा प्रथम दृष्ट्या जानबूझ कर चूक रोकेगा क्योंकि ये फर्म अक्सर तभी जानबूझ कर चूक करती हैं जब उन्हें अपनी मूल्यवान गिरवी रखी परिसंपत्तियों पर नियंत्रण खो देने का भय नहीं होता।

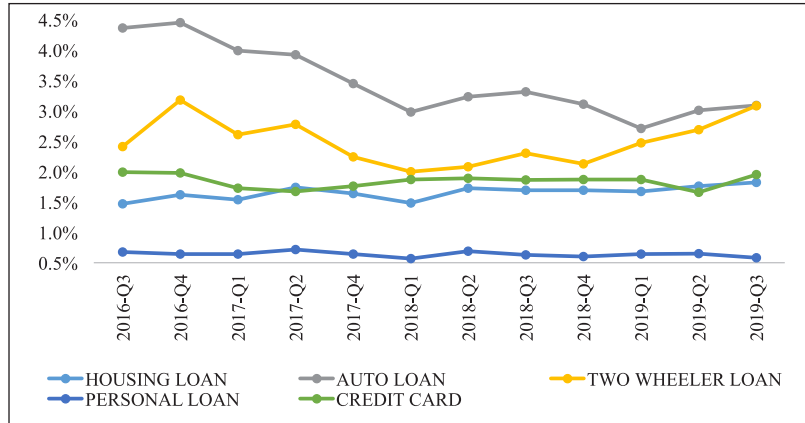
खुदरा ऋणों पर कॉरपोरेट उधार हेतु ऋण विश्लेषणात्मक उपायों का प्रयोग सीखना

7.38 भारत में खुदरा उधार देने के संबंध में वर्ष 2007-2008 के बाद काफी कष्टदायक और अनुभव से सीख भरा रहा है। खुदरा ऋणों में एनपीए ने प्राथमिक तौर पर एनपीबी द्वारा दिए असुरक्षित शामिल हैं। यद्यपि एनपीए का आकार एक प्रणालीगत परिप्रेक्ष्य से उल्लेखनीय था, इस क्षेत्र ने इससे काफी अनुभव प्राप्त किया है। जैसाकि चित्र 25 में देखा गया है, विभिन्न खुदरा उत्पादों में एनपीए स्तर वर्ष 2016-19 के दौरान 5 प्रतिशत से कम रहा। जहां विश्लेषकों के

प्रयोग और बकायों में कमी आई है, उनसे महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त होते हैं जो कि भारत में कॉरपोरेट लेन-देन में कार्यान्वित की जा सकती है।

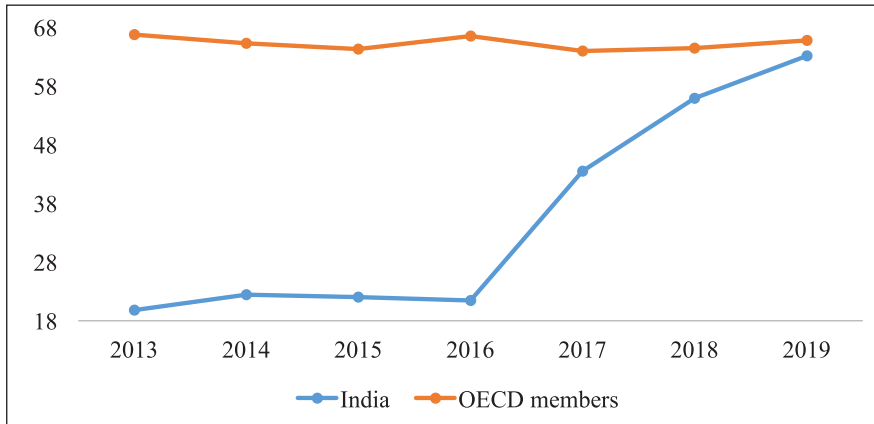
7.39 वास्तव डाटा और साख विश्लेषणों, जैसे कि ग्राहक साख ब्यूरो डाटा से खुदरा उधारी में उल्लेखनीय रूप से विकास को बढ़ावा मिला है। जैसा कि चित्र 26 में दर्शाया गया है, भारत में क्रेडिट ब्यूरो डाटा का उपयोग करते हुए शामिल की गई आबादी 1 अनुपात में ओईसीडी अर्थव्यवस्थाओं के निकट पहुंच गया है। यहां 2006 से साख ब्यूरो के आंकड़ों में महत्वपूर्ण वृद्धि दर है (चित्र 27)

चित्र 25: मुख्य उत्पादों के आधार पर (2016-19) द्वारा खुदरा ऋणों में एनपीए स्तर



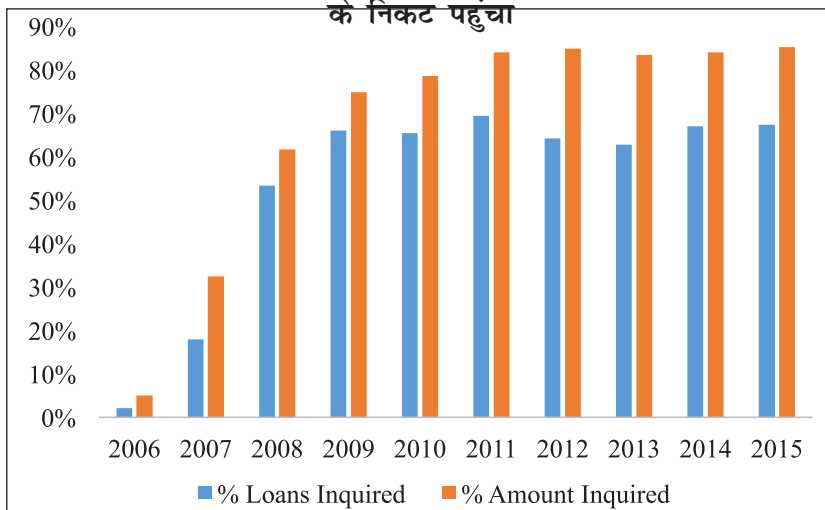
स्रोत: सिबिल डाटा

चित्र 26: भारत ओईसीडी क्रेडिट ब्यूरो कवरेज (प्रौढ़ आबादी का प्रतिशत) के साथ



स्रोत: विश्व बैंक-ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2019

चित्र 27: नए निजी क्षेत्र के बैंकों में क्रेडिट ब्यूरो डाटा के उपयोग में भारत ओईसीडी देशों के निकट पहुंचा



स्रोत: मिश्रा, प्रभाला, राजन, 2019

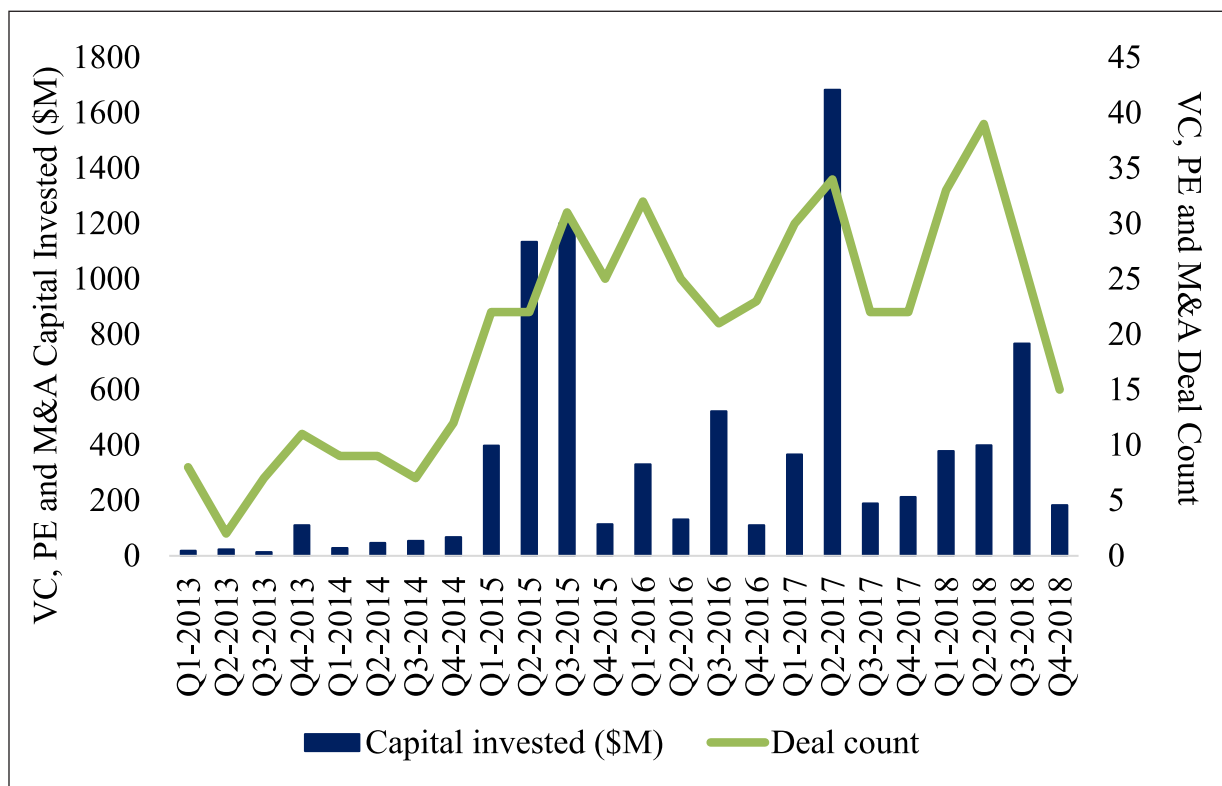
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों हेतु फिन टैक हब का निर्माण: सार्वजनिक क्षेत्र बैंकिंग नेटवर्क (पीएसवीए)

7.40 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ब्यूरो द्वारा (मिश्रा, राजन और प्रभला, 2019) क्रेडिट स्कोर अपनाने में तीव्र रहे। इसी प्रकार से उन्हें फिन टैक अपनाने की आवश्यकता होगी जो कि वैश्विक वित्तीय परिदृश्य में क्रांति ला रहा है। फिन टैक पारंपरिक बैंकों को प्रभावशाली, निम्न-लागत, बैंकिंग समाधानों के साथ आकर उनके समय के साथ पुराने पड़ चुके व्यावसायिक आदर्शों की समीक्षा करने हेतु उन पर दबाव डाल रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को फिन टैक से अधिकाधिक लाभ लेना होगा क्योंकि उनका पारंपरिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग भी कुछ महत्वपूर्ण बैंकिंग समाधानों को छोड़कर उतन व्यापक नहीं है। अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में प्रौद्योगिकी का उपयोग मुख्यतः एमआईएस और रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है जबकि ऋण से संबंधित अधिकांश सूचना प्रसंस्करण व्यक्तिगत आधार पर ही किया जाता है जिससे प्रभावहीनता, धोखाधड़ियों और ऋण दोष उत्पन्न होते हैं। सूचना प्रक्रमण में

संभावित लेनदारों की प्रत्याशित जांच और निगरानी पश्चात् उनके व्यवहार से संबंधित सभी गतिविधियां शामिल है।

7.41 फिनटेक ने बैंकों द्वारा संसाधित की जाने वाली सूचना को मौलिक रूप से बदल दिया है। उदाहरणार्थ कारपोरेट ऋण देने में, गुणात्मक आंकड़ों की बड़ी मात्रा जैसे कि कंपनी के वित्तीय एवं मात्रात्मक आंकड़े जैसे फाइलिंग एवं विश्लेषण कॉल रिपोर्टों को निरीक्षित एवं अनिरीक्षित अधिगम कुलनविधियों, दोनों का उपयोग करते हुए मशीन विश्लेषित किए जाते हैं। उपकरण जैसे कि मशीन अधिगम (एमएल), आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए आई) और बिग डेटा तथा मशीन बैंकों को बड़े डेटाबेस का विश्लेषण करने के द्वारा पैटर्न को तेजी से पहचानने के लिए योग्यता प्रदान करते हैं, एक गतिविधि जो कि पारंपरिक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए मानव के लिए आभासी रूप से असंभव होगी। यह विचार नया नहीं है क्योंकि मानक अर्थमितिपरक मॉडल भी पैटर्न पहचानने के लिए उपकरण ही है। नवीनता एल्गोरिथम उनका उपयोग करते हुए आंकड़ों के अत्यंत बड़े समुच्चयों का विश्लेषण करने में ही नवीनता निहित होती है। जैसाकि चित्र 28 दर्शा रहा है, भारत में फिनटेक में अच्छा निवेश हुआ है। अतः

चित्र 28: भारत में फिनटैक में वीसी, पीई और एम एवं ए निवेश गतिविधियां



स्रोत: पल्ल ऑफ फिनटेक 2018, फिनटेक में निवेश का द्वि वार्षिक वैश्विक विश्लेषण, केपीएमजी इंटरनेशनल

पीएसबी इस क्षेत्र में सुलभ विशेषज्ञ ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं।

7.42 वर्तमान में, पीएसबी उच्च प्रचालन लागत, हस्तचालित प्रचालनों से अलग प्रक्रिया प्रवाह तथा अधिकरण संबंधी निर्णय लेने से अलग प्रक्रिया प्रवाह जैसी बहुत सी चुनौतियों का सामना करते हैं ये चुनौतियां संभावित उधारकर्ताओं के पूर्वानुमान का मूल्यांकन तथा संपार्श्विक का मूल्य जिसे ये भेज सकते हैं, करने के द्वारा पीएसबी की सख्ती के साथ प्रत्याशित उधारकर्ताओं की क्षमता को जानने में अड़चन डालती है। इन्हें चूककर्ता होने की स्थिति में हानि को कम करने के समर्थकारी अनुबंध को संभावित रूप से लागू करके उधार देने के संबंध में पूरी अवधि के साथ ऋण पश्चात उधारकों की निगरानी करने की भी आवश्यकता है। फिनटेक का उपयोग बैंक को उधारकर्ताओं की बेहतर जांच करने की अनुमति देता है, तथा ब्याज दर निर्धारित करता है जो कि ऋण पश्चात ऋणी के प्रदर्शन का भली भांति पूर्वानुमान लगा सकता है। (राजन, 2015)

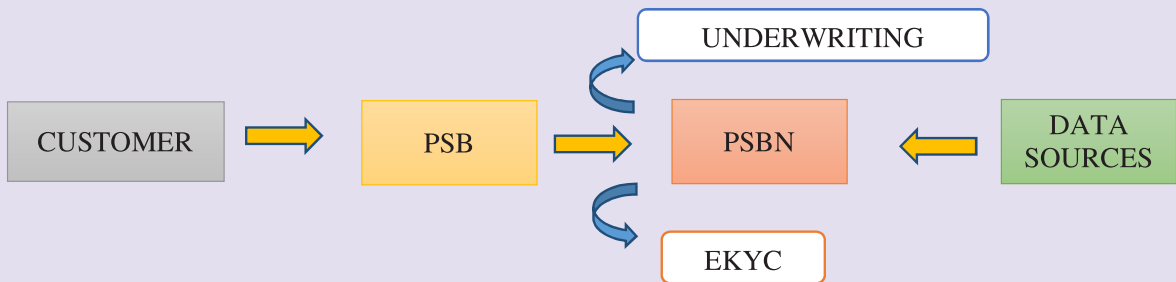
7.43 पीएसबी प्रतिनिधि को अपनी मानीटरन भूमिका सौंप कर अपनी क्षमता बढ़ाने में समर्थ होंगे यदि सभी पीएसबी अपने आंकड़े एक निकाय में साझा कर सकेंत हैं। उनके कारपोरेट उधारकर्ता द्वारा धारित निजी सूचना समस्या को कम करने से अनुबंध समस्याएं पैदा होती हैं, क्योंकि उधार देने के पश्चात उधारकर्ता की शोधन क्षमता का मूल्यांकन करना महंगा होता है। (स्टिगलिज एवं वेसस, 1981) इसके अलावा, बैंकों की जांच एवं निगरानी का प्रतिनिधि एक दक्ष तंत्र होना चाहिए।

(डायमंड, 1984) यह दक्षता विभिन्न पीएसबी द्वारा सभी सूचना को एक निकाय में इकट्ठा करने के साथ आगे और बढ़ायी जा सकती है। यह जांच एवं निगरानी की लागत को कम करने का अतिरिक्त लाभ होगा।

7.44 चूंकि सरकार सभी पीएसबी की स्वामी है इसलिए यह पीएसबी को इस आंकड़े को साझा करने का अधिशेष दे सकती है ताकि मितव्ययता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग (ए.आई.एम.एल) का उपयोग करते हुए विश्लेषणात्मक कारोबार में आवश्यक निवेश करने में बड़े पैमाने की मितव्ययता का उपयोग किया जा सकता है। समीक्षा व्यापक एवं विस्तृत रूप से उधारकर्ताओं की जांच एवं निगरानी करने के लिए प्रोद्योगिकियों का उपयोग करने हेतु जीएसटीएन जैसा निकाय जिसे पीएसबीएन (पीएसबी नेटवर्क) कहा जाता है, को स्थापित करने का प्रस्ताव करती है। सभी पीएसबी से आंकड़ों का उपयोग करने जो उल्लेखनीय सूचना लाभ प्रदान करेंगी के अलावा पीएसबीएन कारपोरेट के लिए एआईएमएल रेटिंग विकसित करने हेतु अन्य सरकारी स्रोतों एवं सेवा प्रदाताओं का उपयोग करेगा। एआईएमएल मॉडल को न सिर्फ तब लगाया जा सकता है जब नए ऋण के लिए कारपोरेट की जांच करनी होती है बल्कि कारपोरेट उधारकर्ता की सतत निगरानी के लिए भी लगाया जा सकता है ताकि पीएसबी प्रत्यायोजित मॉनीटर के रूप में सही तरीके से कार्य कर सके। बाक्स 3 वैयक्तिक, एसएमई एवं बड़े कारपोरेशन सहित बैंक ग्राहकों के सभी प्रकारों हेतु प्रस्तावित पीएसबीएन हेतु स्थापत्य तथा सूचना प्रवाह प्रदान करता है।

बाॅक्स 5: पीएसबी में फिनटेक के लिए सुझाया गया आर्किटेक्चर तथा समाधान प्रवाह

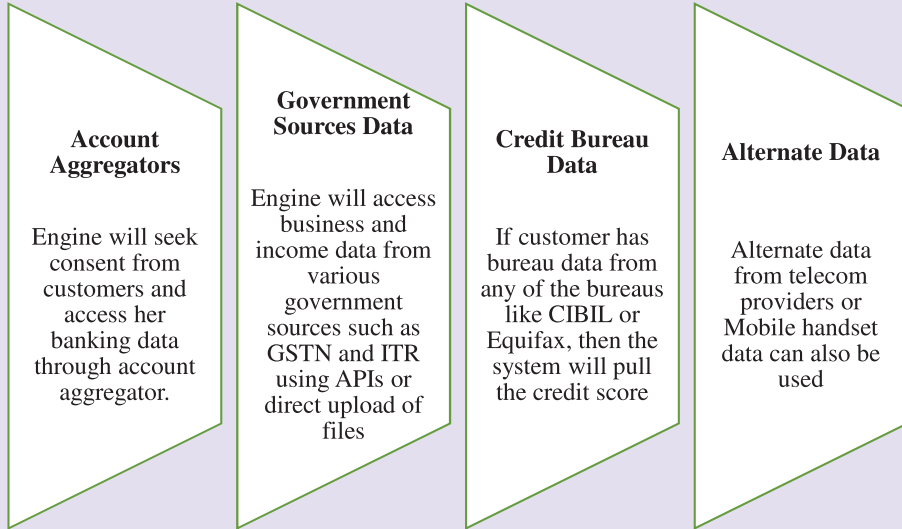
स्टेमेटिक आर्किटेक्चर



सॉल्यूशन फ्लो:

1. **ग्राहक संपर्क:** ग्राहक पीएसबी के पास पहुंचता है तथा वह उधार लेने के लिए ऋण की राशि और उसके प्रकार की इच्छा जाहिर करता है।

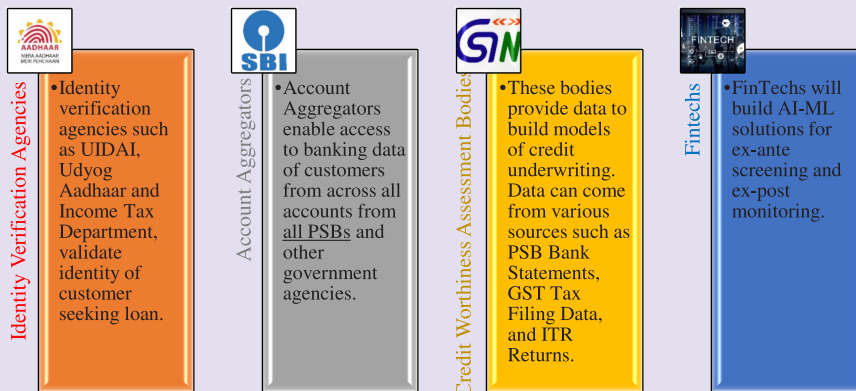
- के वाई सी सत्यापन:** पीएसपी उपयुक्त सूचना निकाय को स्थांतरित करता है। निकाय पहचान सत्यान एजेंसियों अर्थात आधार आधारित ईकेवाईसी द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के आधार पर ग्राहकों के लिए मार्गनिर्देशों के अनुसार, के वाईसी प्रक्रिया पूरी करेगा। ग्राहकों के लिए के वाईसी की पीएसबी के जरिए ऋण प्रावधान हेतु बैंकों द्वारा पुष्टि की जानी चाहिए। अतः इंजिन आंकड़ों को मिलाएगा तथा के वाईसी संपुष्टि हेतु पीएसबी को देगा।
- आंकड़ा संग्रहण:** इंजिन आगे ग्राहक प्रोफाइल पर आधारित विभिन्न आंकड़ों को सहित स्रोतों से आंकड़ों से मिलाएगा। आंकड़ों को इनसे एकत्रित किया जाएगा



प्रणाली में संपूर्ण क्रेडिट जोखिम का अंकन होगा जो निर्मित मॉडल के आधार पर सभी उपलब्ध डाटा का विश्लेषण करने के बाद ग्राहक की क्रेडिट रूपरेखा (प्रोफाइल) तैयार करेगा। व्यक्ति, एसएमई विभिन्न एआई-एमएल जोखिम अंकन मॉडल तैयार किए जाएंगे।

- ऋण प्रावधान:** केवाईसी एवं जोखिम अंकन के आधार पर प्रणाली ऋणों के लिए ग्राहक की पात्रता का निर्धारण करेगी तथा सभी प्रकार की सूचना पीएसबी को अंतरित करेगी। प्राप्त सूचना के आधार पर पीएसबी रशि एवं दिए जाने वाले ऋण की दर के बारे में निर्णय लेगा।

महत्वपूर्ण सहभागी:



7.45 पीएसबीएन का लाभ यह होगा कि यह उस डाटा का उपयोग कर सकेगा जिसका का विगत 50 वर्षों के दौरान बेहतर जोखिम अंकन समाधान का सृजन करने के लिए उपयोग किया है और जो डाटा उनकी धरोहर

है। पीएसबीएन का उपयोग करते हुए, वे अपने कारपोरेट ग्राहकों को ऋण के लिए बेहतर जोखिमअंकन करने में संक्षम होंगे। क्रेडिट अंडरराइटिंग (जोखिम अंकन) पर बेहतर निर्णय लेने से अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का

भार कम होगा, तथा इसके साथ-साथ धोखाधाड़ी के प्रत्येक पीएसबी की उच्च प्रचालन लागत उन्हें उधार देने की समग्र प्रक्रिया “एंड-टू-एंड” को स्वचालित करने में मदद करेगी। यह प्रक्रिया अपनाए जाने से पीएसबी यथाशीघ्र निर्णय लेने में सक्षम होगा, ऋण अनुप्रयोगों को शीघ्रता से संसाधित करेगा, और इस प्रक्रिया को पूरा करने में लगने वाली समय अवधि को कम करेगा (टीएटी)। इस प्रक्रिया के बेहतर अनुपालन से एनपीबी के साथ पीएसबी बेहतर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। वास्तव में, पीएसबीएन सूचना संबंधी लाभ प्रदान कर सकते हैं, जिनका लाभ चाहकर भी एनपीबी नहीं उठा सकते।

पीएसबी में कर्मचारी हिस्सेदारी का प्रश्न

7.46 कर्मचारियों को मुख्यतः पर वेतन के रूप में भुगतान किया जाता है। क्योंकि वर्तमान में पीएसबी कर्मचारियों के ऐसे भी दावे हैं जो ऋण अनुबंध से मिलते-जुलते हैं कि उनका भुगतान बैंकों द्वारा किया जाना है। ऐसी निर्धारित प्रति संविदाओं के माध्यम से कर्मचारियों को किए जाने वाले भुगतान के संदर्भ में कर्मचारी, राज्य द्वारा बैंक के संकट के समय में अपने उनके (और सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन) के संबंध में कल्याणकारी वायदे पर भरोसा करते हैं। वित्त अर्थशास्त्रियों की भाषा में ऐसे कर्मचारियों के आन्तरिक देनदारियाँ” होती है जो उनको अनुदारवाद के प्रति प्रेरित करती है तथा यहां तक कि वरिष्ठ कार्यपालकों में भी जोखिम लेने के प्रति सुरक्षित मार्ग अपनाने को महत्त्वपूर्ण बना देती है। (अर्थात् एडमन्स एवं ल्यू, 2011) कर्मचारियों की वर्तमान सपाट प्रतिकर संविदाओं एवं सतर्क एजेंसियों द्वारा कार्योत्तर मॉनीटरन से होने वाले दबाव को देखते हुए यह शायद ही आश्चर्यजनक है कि राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों के कर्मचारी जोखिम लेने एवं नवाचार की बजाए सुरक्षा एवं संरक्षणवाद को तरजीह देते हैं। इस समस्या का दीर्घावधि समाधान कर्मचारीओं को पीएसबी में स्टॉक देकर सक्षम बनाना है।

7.47 कर्मचारियों को बैंकों में स्वामी बनने में सक्षम बनाने एवं सतत् रूप में जोखित उठाने एवं नवीकरण को अपनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी पण के एक हिस्से को कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना (ईएसओपी) के माध्यम से संगठन के सभी स्तरों पर अच्छा निष्पादन करने वाले कर्मचारियों को अंतरित किया जा सकता है।

7.48 कर्मचारियों की पीएसबी में आंशिक-सहभागिता से एजेंसी समस्याओं में कमी आएगी। ऐसा इसीलिए होगा चूंकि कर्मचारी, जिनके शेयर हैं, को इक्विटी के बाजार मूल्य को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, चूंकि उनकी प्रत्येक प्रतिप्राप्ति शेयर मूल्य पर निर्भर करती है। अन्य लाभों में कर्मचारी से मालिक वाली मनोदशा में परिवर्तित करना शामिल है। कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व योजना (ईएसओपी) के माध्यम से पीएसबी के नए मालिकों के किसी एक ब्लॉक, जो कर्मचारी के निष्पादन पर निर्भर है, का गठन कर सकते हैं। संगठन के सभी स्तरों पर प्रेरित, सक्षम कर्मचारियों का स्वामित्व उन कर्मचारियों को मूल्य संवर्धन के लिए वित्तीय इनाम देगा, यह प्रोत्साहन पीएसबी के लाभ से समन्वित होगा तथा कर्मचारियों के लिए उपक्रम स्वामित्व की मनोदशा सृजित करेंगे।

प्रौद्योगिकी पर आधारित बेहतर प्रतिभा एवं संगठन की आवश्यकता

7.49 एक संबंधित विषय बैंक पदाधिकारियों की भर्ती की प्रक्रिया लेकर है। उदाहरण के लिए पीएसबी परिसरों से सीधे व्यवसायिक एमबीए की भर्ती नहीं कर सकते। ऊपर दिए गए फिनटैक विच्छेदों को देखते हुए पीएसबी को अत्याधुनिक भर्ती व्यवहारों में सक्षम बनने की आवश्यकता है जिसमें व्यावसायिकों के पारशिवक प्रवेश एवं प्रौद्योगिकी, डाटा विज्ञान, वित्त एवं अर्थशास्त्र विषयों में कौशल प्राप्त व्यावसायिक स्तर पर प्रशिक्षित प्रतिभाओं को प्रवेश स्तर पर अनुमति दी गई हो। कर्मचारियों के लिए उपलब्ध बड़े स्वामित्व स्टैक उद्योग में बेहतर प्रतिभा को आकर्षित करने में रूकावट नहीं होगी। फिनटैक एवं डाटा विज्ञान में हुई प्रगति से परीक्षण के लिए नवाचार, प्रयोगशालाएं, प्रेरक, वेन्चर आर्म्स एवं सैण्डवॉक्स जैसे समग्र रूप से नए विषय उपलब्ध हैं जो बड़े औषध और जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्पष्ट हुए हैं।

7.50 विघटनकारी प्रक्रियाओं के माध्यम से विघटनकारी नवाचारों को अपनाना मुश्किल है। इसके लिए सभी स्तरों पर जोखिम उठाने वाली एक डिग्री, एक लचीली मानव शक्ति अधिग्रहण रणनीति की आवश्यकता होती है, और पूरक प्रोत्साहन अवसंरचनाओं की भी, जो उदाहरण के लिए जो अधिक उच्च-शक्ति वाले प्रोत्साहन की पेशकश करती है जो सफलता के लिए अधिक वेतन

का प्रस्ताव करती हैं। पीएसबी के कर्मचारियों को सरकार द्वारा एक उदार स्वामित्व का प्रस्ताव उन्हें उच्च गुणवत्ता वाले बैंकिंग पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन संरचना प्रदान करने में सहायता करेगा और जिसके कारण उनकी मानव संसाधन अधिग्रहण रणनीतियों में सुधार होगा।

निष्कर्ष

7.51. आज भारत का बैंक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के अनुपात में बहुत छोटा है। बड़ी अर्थव्यवस्था की संवृद्धि में सहयोग के लिए एक दक्ष बैंकिंग क्षेत्र आवश्यक है। ऐतिहासिक रूप से पिछले 50 वर्षों में विश्व की 5 विशालतम अर्थव्यवस्थाओं को सदैव अपनी बैंक व्यवस्था का सक्रिय सहयोग मिला है। भारत की संवृद्धि में आवश्यक सहयोग देने में समर्थ होने के लिए कम से कम 6 बैंकों को विश्व के विशाल 100 के वर्ग में अपना अच्छा स्थान बनाना होगा। पी.एस.बी. का देश के बैंकिंग क्षेत्र में 70 प्रतिशत अंश होने

के नाते देश के अर्थतन्त्र को बढ़ावा देने और विकास के संपोषण का दायित्व भी इन्हीं पर आता है। किन्तु सभी निष्पादन कसौटियों पर या बैंक अपने समकक्षों की तुलना में निकृष्ट ही पाए गए हैं। नरसिंहन समिति (1991-1997), राजन समिति 2007 और पी.जे. नायक समिति (2014) ने पीएसबी की दक्षता सुधारने के लिए अनेक सुझाव दिए हैं ये इन्हें देश की 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की ओर यात्रा में सहायता करने के लिए अधिक सक्षम बना पाएंगे। इन सभी समीक्षा ने सभी बैंक कार्यों में फिनटेक तथा कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व का सुझाव पीएसबी में सभी स्तरों पर दक्षता बढ़ाने के लिए दिया है। सुझावों पर गंभीरता पूर्वक विचार कर एक समय बद्ध कार्य-योजना बनाई जानी चाहिए। बैंकिंग व्यवस्था में स्वच्छता लाने के साथ आईबीसी जैसी विधिक रचना का समावेश होना चाहिए तथा बैंक व्यवस्था को विस्तृत होकर देशकी अर्थव्यवस्था में सहायक होना चाहिए।

CHAPTER AT A GLANCE

- वर्ष 2019 में भारत ने बैंक राष्ट्रीयकरण की 50वीं वर्षगांठ संपन्न की है। अतः सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में कार्य करने वाले 3,89,956 अधिकारियों 2,95,380 लिपिकों एवं 1,21,647 सब-स्टॉक, के प्रयासों का उत्सव मनाया उचित है तथापि पीएसबी की वस्तुपरक समीक्षा भी आवश्यक है।
- भारत ने वर्ष 1969 से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए बहुत त्वरित गति से तरक्की की है। फिर भी, भारत के बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के आकार के अनुरूप असंगत रूप से अविकसित रहा है। उदाहरण के लिए विश्व के 100 शीर्ष बैंकों में से भारत में केवल एक बैंक है किसी ऐसे देश के अनुरूप जो इसके आकार की तुलना में बहुत छोटे हैं फिनलैंड (लगभग 1/11वां), डेनमार्क (1/8वां), नार्वे (1/7वां) आस्ट्रिया (1/8 वां) एवं बेल्जियम (लगभग 1/6)। स्वीडन (1/6वां) एवं सिंगापुर (1/8वां) जैसे देशों में वैश्विक बैंकों की संख्या भारत में उपलब्ध ऐसी बैंक संख्या से तीन गुणा है।
- बड़ी अर्थव्यवस्था में प्रगति करने के लिए प्रभावी बैंकिंग क्षेत्र की आवश्यकता है। ऐतिहासिक रूप में, पिछले 50 वर्षों में शीर्ष पांच-अर्थव्यवस्थाओं को सदैव उनके बैंकों ने सहायता प्रदान की है।
- चूंकि भारतीय बैंकिंग में पीएसबी के पास बाजार शेयर का 70 प्रतिशत हिस्सा है, अतः भारतीय अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करने एवं इसकी आर्थिक संवृद्धि को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी भी इनकी है। फिर भी, प्रत्येक निष्पादन मानदंड के स्तर में पीएसबी अपने सहयोगी समूहों की तुलना में अक्षम है। वर्ष 2019 में, पीएसबी में निवेश कर दाता की राशि के प्रत्येक रूप में, औसतन 23 पैसे की क्षति हुई है। इसकी तुलना में एनपीबी में निवेशित कर दाता की राशि के प्रत्येक रूप में, औसतन 9.6 पैसे का लाभ हुआ है। इसके अलावा, पिछले काफी वर्षों से पीएसबी की प्रगति एनपीबी की तुलना में काफी धीमी रही है।

- समीक्षा में ऐसे सुझाव दिए गए हैं जो पीएसबी को अधिक सक्षम बना सकते हैं ताकि वे 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते राष्ट्र की अच्छी तरह से सहायता कर सकें।
- कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने तथा उनके हितों का बैंक के साथ शेयर धारकों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए बैंक कर्मचारियों को कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व के माध्यम से हिस्सेदारी देने के साथ-साथ कर्मचारियों के ब्लॉकों के अनुपात में बोर्ड में उनको अनुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- बड़े स्तर के डाटा, कृत्रिम आसूचना एवं क्रेडिट निर्णयों में मशीन लर्निंग, विशेषकर बड़े ऋण दाताओं संबंधी, का प्रयोग करने के लिए जीएसटीएन प्रकार का एक प्रतिष्ठान स्थापित किया जाना चाहिए। चूंकि सरकार सभी पीएसबी की मालिक है, अतः सरकार को पीएसबी द्वारा अपने कारोबार के दौरान पैदा किए गए डाटा को प्रयोग करने का अधिकार है। अतः प्रायोजक के रूप में सरकार को इस प्रतिष्ठान की स्थापना करनी चाहिए जिससे बड़ी डाटा तकनीकों का प्रयोग करके निर्णय लेने में सक्षम बनकर सभी पीएसबी से लिए डाटा को समाकलित हो। त्रुटिपूर्ण पैटर्न, जिनका खुलासा शक्तिशाली तकनीक कर सकती है। बचने वाले किसी भी बेईमान प्रायोजक की क्षमता से परे हैं। अतः ऋणदाताओं, विशेषकर बड़े स्तर वाले, के बेहतर मूल्यांकन एवं देखरेख को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निवेश महत्वपूर्ण हैं।
- बैंकिंग प्रणाली और आवश्यक विधिक फ्रेम वर्क तथा दिवालिया और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) को स्वच्छ बनाते हुए बैंकिंग प्रणाली को अर्थव्यवस्था के समर्थन में दक्षता उन्नयन पर अवश्यमेव ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

संदर्भ

Chakrabarty, K.C., (2013), Two decades of credit management in banks: Looking back and moving ahead (Address by Dr. K. C. Chakrabarty, Deputy Governor, Reserve Bank of India).

Diamond, Douglas W. "Financial Intermediation and Delegated Monitoring." *The Review of Economic Studies* 51, no. 3 (1984): 393-414. Accessed January 25, 2020. www.jstor.org/stable/2297430.

Edmans, Alex and Liu, Qi, Inside Debt (June 29, 2011). *Review of Finance*, Vol. 15, No. 1, pp. 75-102, January 2011; EFA 2007 Ljubljana Meetings Paper. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=758508>.

Mishra, Prachi and Prabhala, Nagpurnanand and Rajan, Raghuram G., The Relationship Dilemma: Organizational Culture and the Adoption of Credit Scoring Technology in Indian Banking (March 5, 2019). Johns Hopkins Carey Business School Research Paper No. 19-03. Available at SSRN: <https://Ssrn.com/Abstract=3347299>.

Narasimhan Committee I (1991), Report of the Committee on Financial Systems, Reserve Bank of India.

Narasimhan Committee II (1998), Report of the Committee on Banking Sector Reforms, Reserve Bank of India.

Nayak Committee (2014), Report of the Committee to Review Governance of Boards of Banks in India, Reserve Bank of India.

Rajan Committee (2007), Report of the Committee on Financial Sector Reforms, Government of India.

Rajan, U., Seru, A., and Vig, V. (2015). The Failure of Models That Predict Failure: Distance, Incentives, and Defaults. *Journal of Financial Economics*, 115, 237-260.

Stiglitz, Joseph E., and Andrew Weiss. "Credit Rationing in Markets with Imperfect Information." *The American Economic Review* 71, no. 3 (1981): 393-410. Accessed January 25, 2020. www.jstor.org/stable/1802787.

एनबीएफसी सेक्टर में वित्तीय भंगुरता

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथा॥

3.11 (श्रीमद् भगवद् गीता)

संधारणीय प्रणालियों के सृजन के लिए पारस्परिकता और निर्भरता के मूलभूत सिद्धांत की अच्छी समझ अपेक्षित है।

इंफ्रॉस्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड लीजिंग सर्विसेज़ (आईएल एंड एफएस) की सहायक कंपनियों एवं दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) द्वारा भुगतान चूक के बाद लिक्विड डेब्ट म्यूचुअल फंड्स (एलडीएमएफ) की सहायक कंपनियों एवं दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) द्वारा भुगतान चूक के बाद लिक्विड डेब्ट म्यूचुअल फंड्स (एलडीएमएफ) में निवेशकों ने सामूहिक रूप से अपने निवेश भुनाए। वस्तुतः इस चूक के कारण एनबीएफसी-फाइनेंसों के समग्र समूह में भय फैल गया जिसके कारण एनबीएफसी सेक्टर में निधीयन (तरलता) संकट उत्पन्न हो गया। इस अध्याय में एनबीएफसी के समक्ष उत्पन्न उन कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया है जो कि लिक्विड डेब्ट म्यूचुअल फंड (एलडीएमएफ) से अल्पावधि बड़े वित्तपोषण पर अत्यधिक निर्भरता से उत्पन्न हुई थी। हालांकि, इस प्रकार की निर्भरता बेहतर समय में ठीक है, परन्तु दबाव के दौरान अल्पावधि वित्त पोषण में रोल ओवर में असमर्थता से आवर्तन एनबीएफसी के लिए काफी अधिक जोखिमपूर्ण है। परिसंपत्ति पक्ष की ओर का आघात न केवल एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट (एएलएम) की समस्या को बढ़ाता है अपितु एलडीएमएफ में निवेशकों को आशंकित करता है जिसके कारण भुनाने का एक दबाव उत्पन्न होता है जिसकी परिणति “बैंक रन” यह रूल एडीएमएफ में यह रन की स्थिति एनबीएफसी के लिए पुनः वित्तपोषण (रोल ओवर) के जोखिम को अवक्षेपित करती है जिसके कारण परिसंपत्ति पक्ष में उत्पन्न प्रारंभिक कठिनाइयों में बढ़ोतरी होती है। हमने एक गतिशील स्वास्थ्य सूचकांक (हेल्थ स्कोर) तैयार किया है जो इन जोखिमों को दर्शाता है और जिसका प्रयोग एनबीएफसी में तरलता के जोखिम का पूर्वानुमान लगाने के लिए एक पूर्व चेतावनी प्रणाली के रूप में किया जा सकता है। नीति निर्माता इस साधन का प्रयोग एनबीएफसी सेक्टर में वित्तीय भंगुरता की निगरानी, विनियमन एवं उसको टालने के लिए सकते हैं।

8.1 भारत में आभासी (शैडो) बैंकिंग प्रणाली (बॉक्स 1) में तरलता की कमी प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा ऋण दायित्वों में की गई चूक के कारण उत्पन्न हुई। इंफ्रॉस्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की दो सहायक कंपनियों ने जून से सितंबर, 2018 की अवधि में भुगतान में चूक की जबकि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) ने जून से अगस्त, 2019 की अवधि में भुगतान में चूक की। इन दोनों इकाइयों ने अपरिवर्तनीय

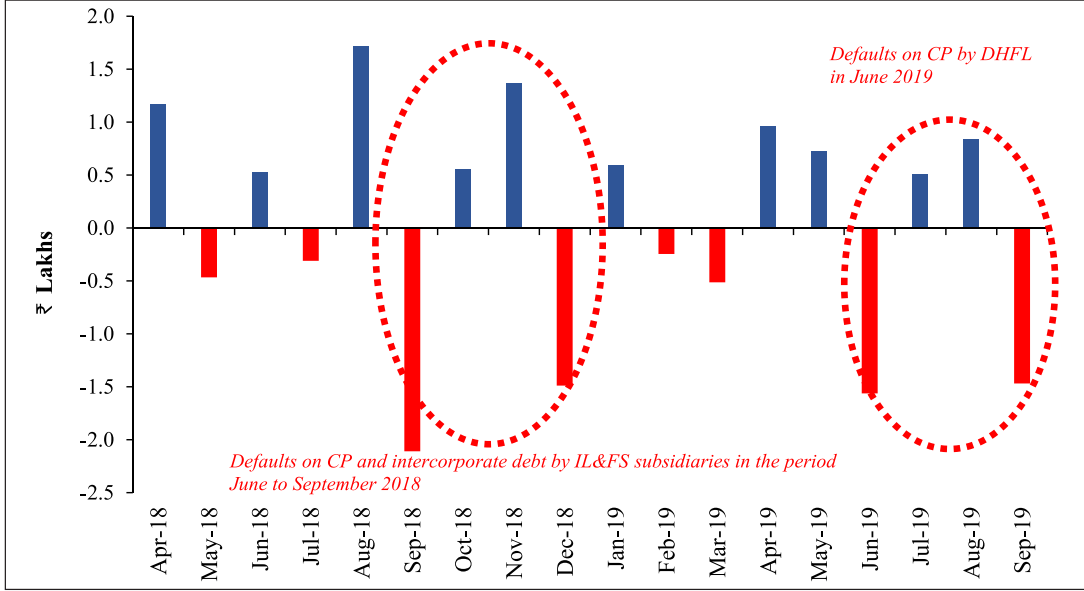
डिबेंचरों और वाणिज्यिक दस्तावेज की बाध्यताओं ने लगभग 1500-1700 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान की चूक की।

8.2 भुगतान की इन चूकों के कारण म्यूचुअल फंडों ने दबाव में चल रही एनबीएफसी की अपने कुल निवेश को कम करने के लिए एनबीएफसी सेक्टर में अपने निवेश की बिक्री करनी प्रारंभ कर दी। ऐसा एक मामला डीएसपी म्यूचुअल फंड का सितंबर, 2018 (1) में

अत्यधिक छूट पर डीएचएफएल के ₹300 करोड़ रुपये के वाणिज्यिक दस्तावेज की बिक्री करना था। ऋण वाले म्यूचुअल फंडों के भयग्रस्त निवेशकों ने इन म्यूचुअल फंडों से बड़ी तेजी से अपना निवेश निकालना प्रारंभ कर दिया। आईएल एंड एफएस एवं डीएचएफएल द्वारा

चूक का समाचार संयोगवश इसी समय बाजार में आने से चित्र 1 में दर्शाए अनुसार सितंबर, 2018 एवं जून, 2019 में एलडीएमएफ और मुद्रा बाजार से फंडों का सबसे अधिक बहिर्गमन हुआ।

चित्र 1: शुद्ध अंतर्वाह - तरल ऋण म्यूचल फंड (एलडीएमएफ) एवं मुद्रा बाजार फण्ड निधियां (करोड़ रुपये)



स्रोत: प्रमुख एलडीएमएफ के प्रदर्शन पर आधारित एसी-एमएफ डाटाबेस

8.3 भुगतान में चूक का समाचार सार्वजनिक² होने पर 4 जून, 2019 को उन ऋण निधियों डीएचएफएल द्वारा जारी किए गए ऋण विलेखों जिनके पास की शुद्ध संपत्ति के मूल्य में, एक दिन में 53 प्रतिशत की गिरावट आ गई थी। ऋण म्यूचुअल फंडों द्वारा दबावयुक्त एनबीएफसी में अपने निवेश को आहरित करने के कारण और अप्रत्याशित उच्च विमोचन को पूरा करने के लिए जल्दबाजी में काफी कम कीमतों पर संपत्तियों की बिक्री करने के दोहरे प्रभाव के कारण शुद्ध परिसंपत्ति के मूल्य में यह कमी आई।

8.4 इन चूकों का प्रभाव ऋण बाजार तक ही सीमित नहीं रहा। डीएचएफएल के इक्विटी मूल्यों में बड़ी तेजी से कमी आई क्योंकि इक्विटी बाजार के प्रतिभागियों ने फर्मों में प्रत्याशित पुनर्भुगतान संबंधी कठिनाइयों वास्तविक चूक से कुछ माह पहले ही अंदाजा लगा लिया

था। जैसा कि चित्र 2 में दर्शाया गया है डीएचएफएल के इक्विटी मूल्यों में निरंतर कम होने की प्रवृत्ति मई, 2018 से ही थी। रोचक तथ्य यह है कि चित्रित रूपरेखा दर्शाती है कि सितम्बर, 2018 में इक्विटी मूल्यों में आश्चर्यजनक रूप से कमी आयी है।

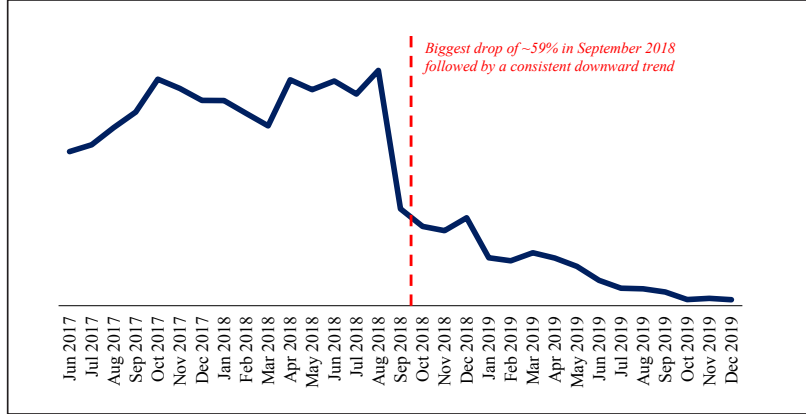
8.5 इसलिए ऋण और इक्विटी, दोनों निवेशकों को भुगतान में इस चूक के कारण संपत्ति में काफी घाटा सहन करना पड़ा। क्षतियों की मात्रा का एक अंदाजा लेने के लिए, निवेश आईएल एंड एफएस वाले ऋण म्यूचल फंडों को भुगतान में चूक के बाद की वसूली समायोजित करने के पश्चात भी लगभग 4000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ³। ऋण म्यूचुअल फंडों में निरंतर विमोचन होने से वे एनबीएफसी सेक्टर में वित्त पोषण से झिझक रहे थे। इसके परिणामस्वरूप, एनबीएफसी को वित्त जुटाने में कठिनाई हो रही थी जिसका भारतीय

¹ इकोनॉमिक टाइम्स का दिनांक 22 सितंबर, 2018 का लेख जिसका शीर्षक था 'डीएसपी द्वारा डीएचएफएल के पेपर की बिक्री से भय फैला'।
² न्यूजक्लिक ने 06 जून, 2019 को "हाउसिंग फर्म डीएचएफएल द्वारा ऋण का भुगतान नहीं करने पर म्यूचुअल फंड्स परेशानी में" शीर्षक से लेख निकाला।
³ लाइवमिंट ने 29 अप्रैल, 2019 को "डेंट म्यूचुअल फंड्स: क्वांटम ऑफ लॉस एंड सोलेस" शीर्षक से लेख निकाला।

अर्थव्यवस्था में समग्र साख में बढ़ोतरी पर बुरा प्रभाव पड़ा और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में कमी आ गई।

8.6 घरेलू अर्थव्यवस्था पर तरलता संकट के महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए यह जांच करना लाभदायक होगा कि क्या एनबीएफसी सेक्टर में संकट के पूर्व चेतावनी

चित्र 2 संकटग्रस्त एनबीएफसी के इक्विटी मूल्यों में प्रवृत्ति (जुलाई - दिसंबर, 2019) डीएचएफएल



स्रोत: ब्लूमबर्ग

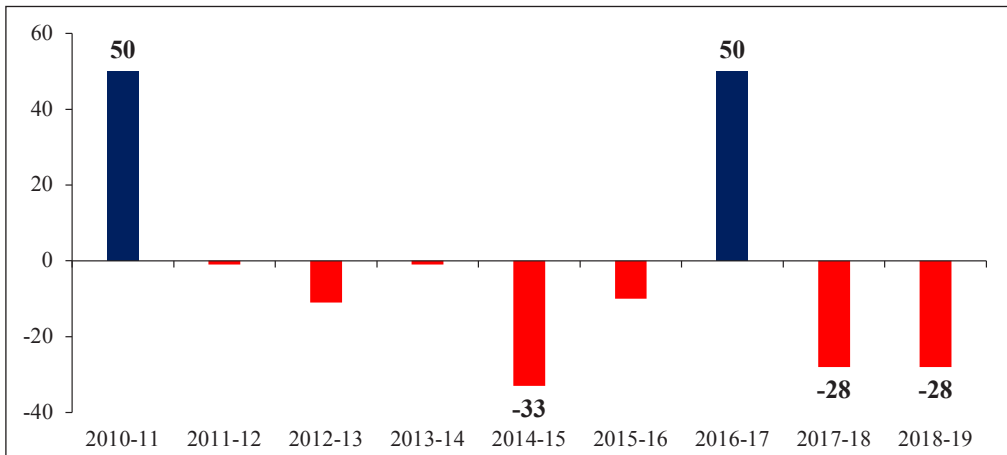
टिप्पणी: दरों के रूझान पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए वार्ड एक्सिस पर वास्तविक दर छोड़ी गई हैं।

के कोई संकेत थे। हमने एनबीएफसी सेक्टर में वित्तीय भंगुरता का प्राक्कलन करने के लिए एक सूचकांक तैयार किया और यह पाया कि इसकी सहायता से हम एनबीएफसी फर्मों के समक्ष आ रही बाह्य वित्त पोषण की बाधाओं (या पुनः वित्तपोषण जोखिम) का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। हम इस सूचकांक को स्वास्थ्य सूचकांक कहते हैं। इसकी रेंज - 100 से +100 की तथा उच्चतर स्कोर फर्म/सेक्टर की उच्चतर वित्तीय स्थिरता को निर्दिष्ट करता है। स्वास्थ्य सूचकांक में एैसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट (एएलएम) की समस्याओं, अल्पावधि थोक निवेश (वाणिज्यिक पत्र) पर अत्यधिक

निर्भरता और एनबीएफसी के तुलन-पत्र जैसे पुनः वित्त पोषण के जोखिमों के मुख्य चालकों से संबंधित जानकारी पर आधारित है।

8.7 स्वास्थ्य सूचकांक एनबीएफसी सेक्टर में समस्याओं के लिए एक बेहतर निदान प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, चित्र 3 दर्शाता है कि डीएचएफएल का स्वास्थ्य सूचकांक वर्ष 2011-19 की समग्र अवधि के दौरान निरंतर नीचे रहा था जिसमें वित्त वर्ष 2017-2018 में बड़ी तेजी से गिरावट दर्ज की गई थी। इसलिए, डीएचएफएल की वित्तीय स्थिति का स्वास्थ्य सूचकांक आठ वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए डीएचएफएल की संसाधन

चित्र 3: संकटग्रस्त एनबीएफसी का स्वास्थ्य सूचकांक



स्रोत: वार्षिक रिपोर्टें

उगाहने में अक्षमता के महत्वपूर्ण पूर्व चेतावनी संकेत प्रदान कर रहा था।

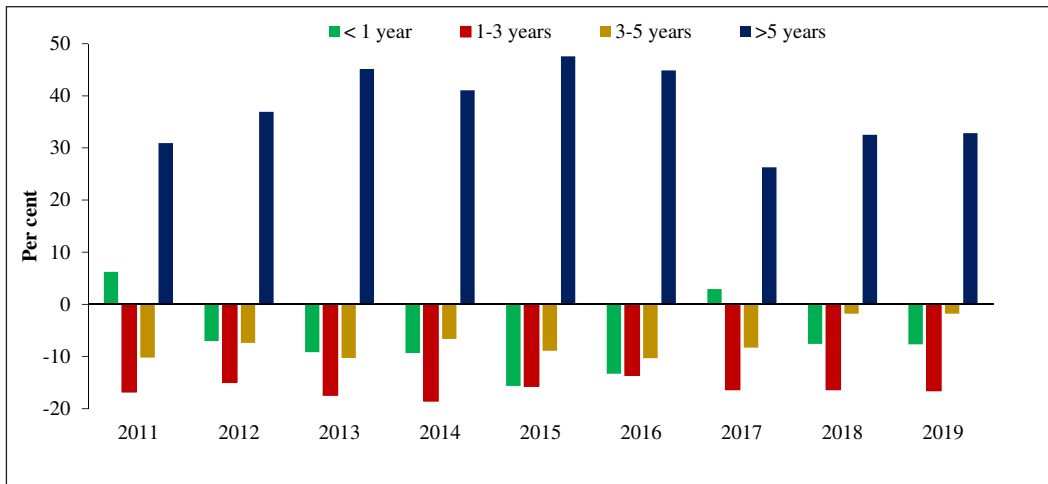
8.8 चित्र 4 जो कि डीएचएफएल में एएलएम को दर्शाता है और चित्र 5 जोकि अल्पावधि थोक निधीयन में डीएचएफएल पर अति निर्भरता को दर्शाता है, जोकि डीएचएफएल के समक्ष आ रहे पुनः वित्त पोषण के जोखिम में प्रतिकूल प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। वर्ष 2011 एवं 2017 को छोड़कर, चित्र 4 यह दर्शाता है कि अल्पावधियों हेतु एएलएम का असंतुलन उन सभी वर्षों के लिए नकारात्मक था जिनमें डीएचएफएल का स्वास्थ्य सूचकांक निम्न था।

8.9 चित्र 5 यह उजागर करता है कि 2015 से पूर्व

की अवधि की तुलना में 2015 के बाद की अवधि हेतु अल्पावधिक थोक डीएचएलएफ फंडिंग (वित्तपोषण) पर औसत निर्भरता में 200% से अधिक की बढ़ोतरी हुई थी। डीएचएलएफ की परिसंपत्तियों की दीर्घकालिकता के मद्देनजर से अधिक वाणिज्यिक पत्र पर इस अति निर्भरता के परिणामस्वरूप डीएचएलएफ हेतु पुनः वित्त पोषण जोखिम उत्पन्न हो गई। यह डीएचएलएल स्वास्थ्य स्कोर के भी अनुरूप है जो वर्ष 2015 के बाद के चार में से तीन वर्षों में बहुत कम रहा है।

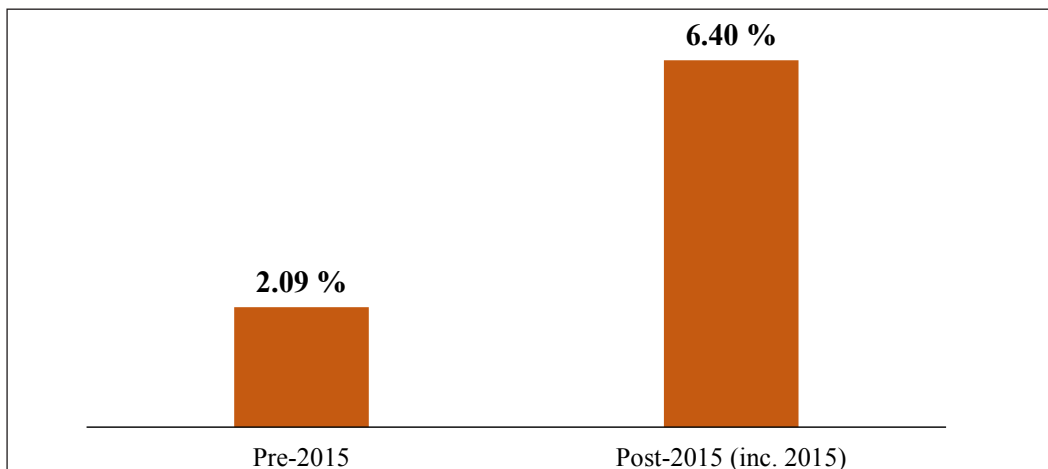
8.10 चित्र 6 हैल्थ स्कोर को और भी मान्यता देता है क्योंकि यह दर्शाता है कि यह एनबीएफसी पर संकट का एक अग्रगामी संकेतक है। यह देखा गया कि यदि हैल्थ

चित्र 4: संकटग्रस्त एनबीएफसी की एएलएम रूपरेखा (कुल परिसंपत्तियों की प्रतिशतता के रूप में परिसंपत्तियां-देयताएं)



स्रोत: वार्षिक रिपोर्टें

चित्र 5: संकटग्रस्त एनबीएफसी का अल्प कालिक थोक वित्तपोषण पर निर्भरता (ऋण के प्रतिशित के रूप में वाणिज्यिक पत्र)



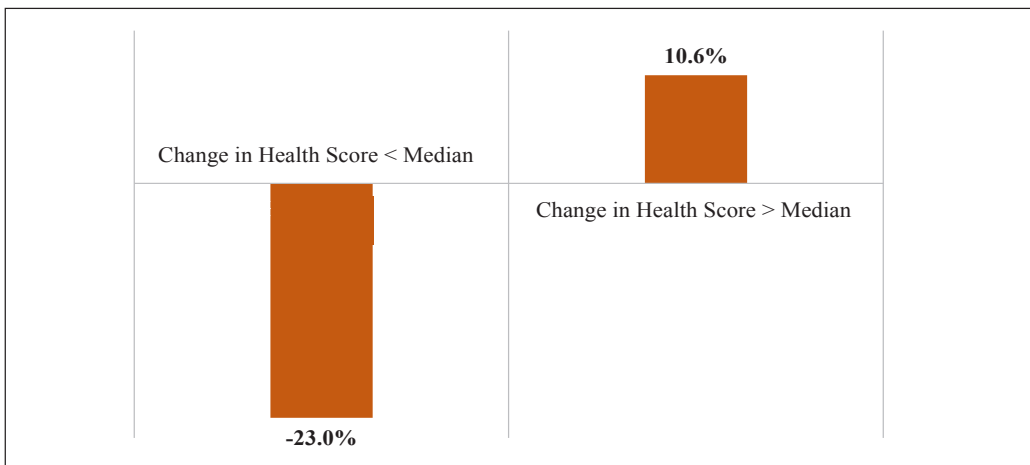
स्रोत: वार्षिक रिपोर्टें

स्कोर में साल-दर-साल परिवर्तन माध्यमिक की अपेक्षा उच्चतर (निम्नतर) होता है तो एनबीएफसी स्टॉक के लिए संचयी असामान्य रिटर्न उच्च (निम्न) था। संचयी असामान्य रिटर्न स्टॉक बाजारों को प्रभावित करने वाले अन्य भ्रमित कारकों के प्रभाव से बाहर निकलता है और इस प्रकार किसी विशेष स्टॉक या स्टॉक के सेट से संबंधित घटनाओं के शुद्ध प्रभाव को पकड़ने में सक्षम

होता है। यह दर्शाता है कि हेल्थ स्कोर में सुधार पर ईक्विटी बाजार ने अनुकूल प्रतिक्रिया दी।

8.11 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) की ओर रुख करने पर हम पाते हैं कि एचएफसी क्षेत्र के हेल्थ स्कोर में भी वित्त वर्ष 2013-14 के बाद गिरावट की प्रवृत्ति देखी गई है जैसा कि चित्र 7 में दर्शाया गया

चित्र 6: संचयी अपसामान्य रिटर्न बनाम हेल्थ स्कोर-डीएचएफएल में परिवर्तन मध्य

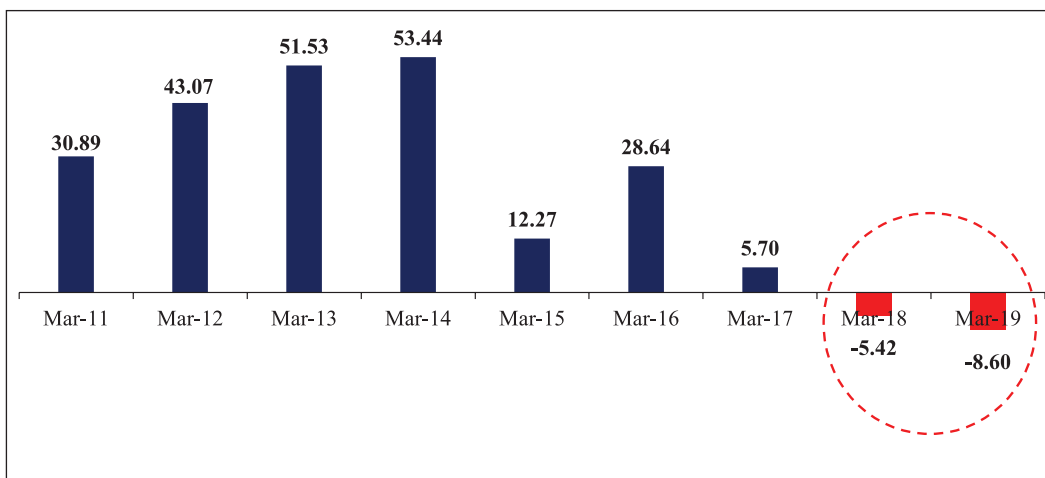


स्रोत: ब्लूमबर्ग

है। हेल्थ स्कोर के रुख ने, वित्त वर्ष 2017-18 के बाद से बाह्य वित्तपोषण के संबंध में एचएफसी क्षेत्र के कमी का सामना करने से पहले, चेतावनी के संकेत दे दिए थे। इससे यह पुनः पुष्ट होता है कि हेल्थ स्कोर एचएफसी क्षेत्र में दबाव का अग्रगामी संकेतक है।

8.12 डीएचएफएल और एचएफसी क्षेत्र के हेल्थ स्कोर के संबंध में नैदानिक आरेख दर्शाते हैं कि हेल्थ स्कोर वित्तीय फर्मों के सामने आने वाले पुनः वित्तपोषण संबंधित दबाव की भविष्यवाणी करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भविष्य में ऐसी समस्याओं से बचाव के

चित्र 7: एचएफसी सैक्टर का हेल्थ स्कोर



स्रोत: प्रमुख एचएफसी के नमूने के आधार पर एचएफसी की वार्षिक रिपोर्टें: 2011-2019

लिए महत्वपूर्ण निगरानी प्रक्रिया की भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा घटकों से विभाजन और उनके रूख की जांच एनबीएफसी को किस प्रकार विनियमित की जाए इस पर प्रकाश डाल सकती है।

8.13 एनबीएफसी क्षेत्र में दबाव के अग्रगामी संकेतक के रूप में उपयोगिता के अतिरिक्त हैल्थ स्कोर का उपयोग नीति निर्माताओं के द्वारा तरलता संकट को दूर करने के लिए दबावग्रस्त एनबीएफसी की अल्प पूंजी को इष्टतम तरीकों से आवंटित करने के लिए किया जा सकता है।

8.14 सार रूप में ऋण अन्योन्य निधियों (डेब्ट म्यूच्युअल फण्ड) के सामने चल रहा विमोचन दबाव 'बैंक रन' के सदृश्य है जो वित्तीय क्षेत्र में किसी भी संकट का

लक्षण होती है। विमोचन दबाव एनपीएफसी के लिए पुनः वित्तपोषण जोखिम (रोलओवर जोखिम) को जन्म देता है जिससे वास्तविक क्षेत्र प्रभावित होता है। पुनः एन बी एफ सी के सामने मौजूद पुनः वित्त पोषण जोखिम मूल रूप से उनकी अल्पकालिक थोक वित्तपोषण पर निर्भरता के कारण होता है। इस अध्याय में ऐसी क्रियाविधियों का विश्लेषण किया गया है जिनके द्वारा अल्पकालिक थोक वित्तपोषण पर निर्भरता स्पष्ट होती है। ताकि एनबीएफसी क्षेत्र में दबाव का अनुमान लगाया जा सके।

आवर्ती जोखिम (रोल ओवर रिस्क) का संकल्पनात्मक ढांचा

8.15 वित्तीय संस्थान दीर्घकालिक निवेशों के वित्तपोषण

बॉक्स 1: आभासी बैंकिंग सिस्टम

घोष व अन्य, 2012 के अनुसार'' आभासी बैंकिंग में वे गतिविधियां, बाजार, संविदाएं और ऐसी संस्थाएं शामिल होती हैं जो आंशिक रूप से (या पूर्ण रूप से) पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकिंग क्षेत्र के बाहर से प्रचालन करती हैं या तो हल्के रूप से विनियमित होती हैं या बिल्कुल विनियमित नहीं होती। आभासी बैंकिंग प्रणाली में कोई ऐसी एक इकाई हो सकती है जो निधियों के अंतिम आपूर्तिकर्ताओं व अन्तिम उपयोगकर्ता के मध्य मध्यस्थता करती है या इसमें बहुत सी श्रृंखला बद्ध ईकाइयां शामिल हो सकती है। आभासी बैंक तंत्र की केंद्रीय बल चल निधि तक कोई प्रत्यक्ष पहुंच नहीं होती। आभासी बैंकिंग सिस्टम पर जोखिम भारी और अंतराल परिसंपत्तियों का भारी भारी दबाव है जबकि इसकी देयताएं बैंक रन की स्थिति पैदा कर सकती है।

इस पेपर में हमारा ध्यान भारत में आभासी बैंकिंग सिस्टम के तीन महत्वपूर्ण भागों पर केंद्रित है नामतः नॉन-बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी), रिटेल नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियाँ (रिटेल एनबीएफसी) और लीक्विड डेब्ट म्यूच्युअल फंड (एलडीएमएफ) हैं। एनबीएफसी सेक्टर पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान शामिल होते हैं, की तुलना में हल्के तौर पर विनियमित होता है तथापि एनबीएफसी क्षेत्र में विनियमन में समय के साथ काफी निकास हुआ है जिसके तहत प्रूडेंशियल मानदण्डों द्वारा एनबीएफसी द्वारा जमा लेने को हतोत्साहित किया गया (भारतीय रिजर्व बैंक 1998) और जमा न लेने वाली एन बी एफ सी को प्रोत्साहित किया गया (आरबीआई 2006) दोनों के मिले जुले प्रभाव के परिणामस्वरूप एन बी एफ सी के वित्तपोषण के स्रोतों में जमाओं की हिस्सेदारी घटी है और थोक वित्तपोषण में वृद्धि हुई है। एनबीएफसी के थोक बिक्री वित्तपोषण स्रोतों में मुख्य रूप से बैंक (प्राथमिक तौर पर सावधि ऋण के माध्यम से और शेष अपरिवर्तनीय डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र के माध्यम से) तथा ऋण म्यूच्युअल फंड (नॉन कंवर्टिबल डिबेंचर और वाणिज्यिक पत्र द्वारा) शामिल होते हैं।

के लिए अल्पावधि वित्तपोषण पर निर्भर रहते हैं। अल्पावधि वित्तपोषण पर इस प्रकार की निर्भरता परिसंपत्ति देयता प्रबंधन (ए एल एम) समस्या उत्पन्न करती है क्योंकि पार्टिसंपत्ति पक्ष के आघातों से वित्तीय संस्थानों के समक्ष अपने व्यवसायों का वित्तपोषण न कर पाने की जोखिम पैदा हो जाती है।

8.16 और विशेष रूप से, एनबीएफसी क्षेत्र में तरलता संकट के संदर्भ में, हमने निम्नलिखित अंतदृष्टि के आधार पर संकल्पनात्मक फ्रेमवर्क तैयार किया है।

(i) एनबीएफसी दीर्घकालिक (5-10 वर्ष) गैर परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) बाजार की तुलना में अल्पकालिक (1-3 माह) वाणिज्यिक का पेपर (सीपी) मार्किट में निम्न लागत पर पूंजी जुटाती हैं किंतु इसमें कुछ महीनों की अल्प आवृत्तियों में पर सीपी ऋण के रोल ओवर करने की जोखिम का सामना करना पड़ती है। बारंबार मूल्य परिवर्तन के कारण एनबीएफसी को उच्च वित्तपोषण लागत और सबसे खराब स्थिति में क्रेडिट का सामना करना पड़ता है और हम इस

- प्रकार के पुन-वित्तपोषण जोखिम को रोल ओवर जोखिम कहते हैं।
- (ii) जब परिसंपत्ति पक्ष आघात के कारण एनबीएफसी प्रत्याशित भावी नकद प्रवाह में गिरावट है तो यह एनबीएफसी में एएलएम समस्या और इसकी वजह से एनबीएफसी के बारे में जोखिम बोध को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं।
- (iii) इस प्रकार के आघात एनबीएफसी की समस्याओं को उस स्थिति में बढ़ा देते हैं जब इसकी देयता संरचना वाणिज्यिक पेपर, जिसके लिए बार बार पुनः वित्तपोषण आवश्यक होता है, जैसे अल्प आवधिक थोक बिक्री वित्तपोषण पर अतिनिर्भर होती है।
- (iv) एलडीएमएफ क्षेत्र एनबीएफसी क्षेत्र में अल्प अवधि थोक निधियों का प्राथमिकता स्रोत है। इस प्रकार एनबीएफसी क्षेत्र 5 लीक्विड डेब्ट म्युच्युअल फंड (एलडीएमएफ) क्षेत्र से जटिल रूप संबद्ध है।
- (v) इस प्रकार की परस्पर संबद्धता एनबीएफसी क्षेत्र से एलडीएमएफ क्षेत्र को तंत्रगत जोखिम के प्रसारण के लिए एक चैनल होती है। एनबीएफसी क्षेत्र में आघात के कारण फॉयर सेल (जल्दबाजी से बेचने पर मिलने वाली निम्न कीमत) पर एलडीएमएफ में निवेशकों के द्वारा सम्मिलित विमोचन हो सकता है। इस स्थिति में एलडीएमएफ पुनः वित्तपोषण देय होने के समय एनबीएफसी क्षेत्र का वित्त पोषण वापस ले सकता है। इस प्रकार का प्रबलन चक्र (रीइंफोर्सिंग साइकिल) तत्काल दुष्चक्र (वीसिअस साइकिल) में परिवर्तित हो सकता है जिसकी वजह से एनबीएफसी क्षेत्र में चल विधि का संकट उत्पन्न हो सकता है। और तकनीकी रूप से तंत्रगत जोखिम एनबीएफसी क्षेत्र से एलडीएमएफ क्षेत्र में और फिर विपरीत दिशा में प्रसारित हो जाता है अर्थात् परस्पर संबद्धता के कारण एनबीएफसी क्षेत्र और एलडीएमएफ क्षेत्र के मध्य तंत्रगत जोखिम प्रसारण होता है।
- (vi) सामान्य तौर पर, यदि चूक की मात्रा बहुत अधिक हो (जैसा कि आईएल एण्ड एफएस और डीएचएफएल के मामले में था) तो यह व्यावसायिक पत्र में निवेशकों के मध्य डर फैला सकती है जिसके कारण एल डी एम एफ क्षेत्र में सम्मिलित विमोचन (एलडीएमएफ) क्षेत्र के अन्दर तंत्रगत जोखिम हो सकता है। इसके अलावा एक एनबीएफसी में चल निधि का संकट में अन्य एनबीएफसी के संबंध में जोखिम अवधारणा भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है जब वे अपने सीपी देयताओं को रोल ओवर करने जा रहे हों। इस प्रकार प्रारंभिक तौर पर कुछ एनबीएफसी में निहित रोल ओवर जोखिम संपूर्ण एनबीएफसी क्षेत्र (एनबीएफसी क्षेत्र में तंत्रगत जोखिम) में प्रसारित हो सकती है और इसे प्रभावित सकती है।
- (vii) एलडीएमएफ में विमोचन की समस्या और इसके द्वारा एनबीएफसी में रोल ओवर रिस्क (जोखिम) समस्याएं के महत्वपूर्ण संचालक त्रिअयामी हैं: प्रथम जोखिम एनबीएफसी में एएलएम समस्या की मात्रा से उत्पन्न होता है। दूसरा जोखिम एलडीएमएफ क्षेत्र से एनबीसी के परस्पर अन्तसम्बन्धित होने से उत्पन्न होता है। यह जोखिम उस सीमा तक निर्भर करता है जिस तक कोई एनबीएफसी विमोचन दबाव को अवशोषित करने के लिए अल्पकालिक थोक वित्तपोषण पर और एलडीएमएफ में तरलता बफर तक भरोसा करता है। तीसरा जोखिम में एनबीएफसी के निहित लचीलेपन से बनता है जैसा कि बैलेंस शीट (तुलन पत्र) की मजबूती पुनः वित्तपोषण परिलक्षित होता है तथा जो इसे सबसे पहले आघातों को अवशोषित करने देता है।
- (viii) ये तीनों जोखिम मिला कर रोल ओवर जोखिम उत्पन्न करते हैं। सीपी दायित्वों के समय, सुदृढ़ बैलेंसशीट वाले एन बी एफ सी अपनी सीसीपी को रोल कर पाते हैं। हालांकि

⁴ बारंबार मूल्य परिवर्तन के कारण एनबीएफसी को उच्च वित्तपोषण लागत और का सामना करना पड़ता है और सबसे खराब स्थिति में क्रेडिट राशनिंग और हम इस प्रकार के पुन-वित्तपोषण जोखिम को रोल ओवर जोखिम कहते हैं।

⁵ समस्त वर्गों के अंशदाताओं में, म्युचुअल फंडों द्वारा किए गए अंशदानों में एनबीएफसी द्वारा निर्गत सीपी की हिस्सेदारी सर्वोच्च) 31 मार्च, 2019 को यथास्थिति 79.7%) थी (रिटेल एनबीएफसी क्रेडिट रुझान: आईसीआरए रिपोर्ट, जुलाई, 2019)। म्युचुअल फंडों में, सीपी में निवेश में एलडीएमएफ का हिस्सा सर्वाधिक है (औसतन 80%), जोकि चित्र 11, उपधारा 3.2 में रेखांकित है। ये दोनों तथ्य मिलाकर दर्शाता है कि एनबीएफसी सेक्टर में एलडीएमएफ क्षेत्र अल्पकालिक थोक निधियों का प्राथमिक स्रोत है।

उच्चतर लागत पर। कमजोर बैलेंस शीट वाले अन्य एनबीएफसी उच्चतर चूक संभावनाओं का सामना करते हैं और या तो सीपी मार्किट में किफायती दरों पर राशि जुटाने में दिक्कतों का सामना करते हैं या राशि जुटाने में बिल्कुल असमर्थ रहते हैं अर्थात् वे चूक से बचने में असमर्थ रहते हैं।

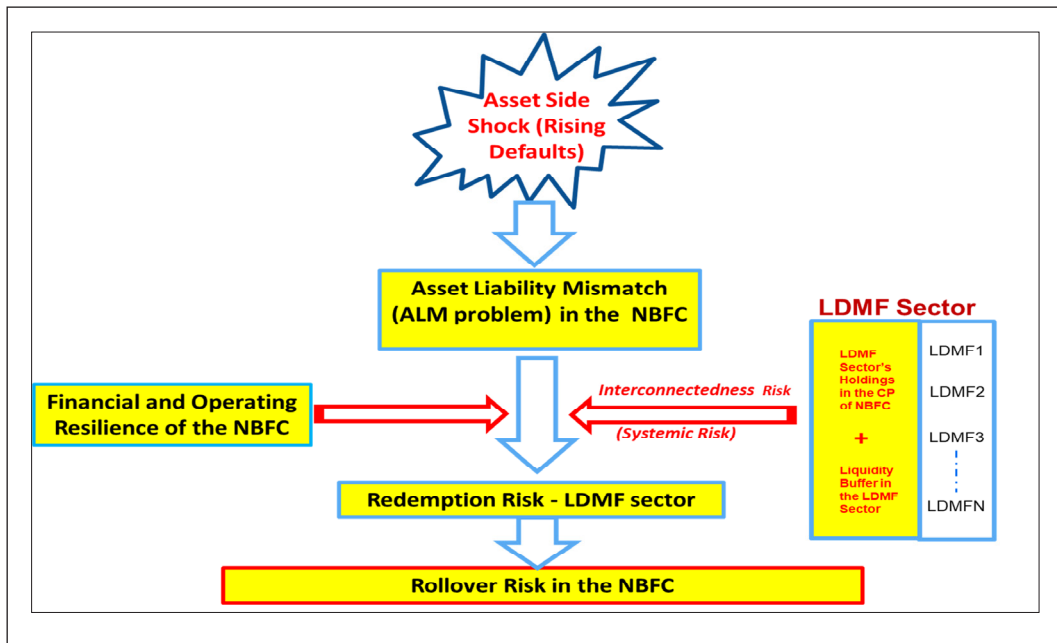
(ix) बिल्कुल मूलभूत स्तर पर एनबीएफसी क्षेत्र में चल निधि के संकट का मूल कारण अल्पकालिक थोक) वित्त पोषण बाजार पर एनबीएफसी पर अतिनिर्भरता माना जा सकता है। यह घटक दो चैनलों के माध्यम से कार्य करता है, पहला प्रत्यक्ष चैनल और दूसरा अप्रत्यक्ष चैनल। पहला, अल्पकालिक थोक बिक्री फंडिंग में वृद्धि बारंबार मूल्यनिर्धारण के अध्याधीन राशि होती है और की बढ़ाकर एक प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। दूसरा, अप्रत्यक्ष जोखिम भी होते हैं इसलिए रोलओवर जोखिम जिनमें अल्पकालिक थोक फंडिंग में वृद्धि रोल ओवर जोखिम के दो महत्वपूर्ण संचालकों को प्रभावित करती है - यह एएलएम असंतुलन समस्या का और अधिक बिगाड़ देती है और एलडीएमएफ सैक्टर के साथ एनबीएफसी की परस्पर संबद्धता की हद को और बढ़ा देती है।

इनके अलावा यदि एनबीएफसी की बैलेंस शीट सामर्थ्य संदिग्ध होती है तो रोल ओवर जोखिम और अधिक बढ़ जाता है। सक्षिप में यह कहा जा सकता है कि अल्पकालिक थोक फंडिंग पर आतिनिर्भरता का रोल ओवर जोखिम पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है।

8.17 एनबीएफसी क्षेत्र में रोल ओवर जोखिम के कारकों को चित्र 8 में दर्शाया गया है। एलडीएमएफ क्षेत्र में विमोचन दबाव तब और अधिक उग्र हो जाते हैं जब एनबीएफसी परिसम्पत्ति-पक्ष से जुड़े आघात का सामना करत हैं और एएलएम की समस्या का अनुभव करते हैं यह समस्या परस्पर संबद्धता के कारण और तुलन-पत्र लचीलेपन की कमी के कारण और बढ़ जाती है। विमोचन संबंधी दबावों का सामना करते हुए एलडीएमएफ क्षेत्र एनबीएफसी क्षेत्र से ऋणों को रोल ओवर करने में अनिच्छुक होता है (रोल ओवर जोखिम), जिसके कारण एनबीएफसी क्षेत्र में तरलता की कमी हो जाती है।

8.18 नीतिगत निहितार्थों के विकास के लिए हम वित्तीय मात्रों की सहायता से आवर्ती (रोल ओवर) जोखिमों के संचालकों प्राक्कलन करते हैं तथा रोलओवर जोखिम

चित्र 8: आवर्ती (रोल-ओवर) जोखिम आरेख (एनबीएफसी क्षेत्र)



स्रोत: वी. रवि अंशुमन और राजदीप शर्मा के “फायनेंसियल फ्रेजिलिटी इन हाऊसिंग फायनेंस कंपनीज”, II एमबी वर्किंग पेपर, 2020 से संकलित

में उनके सापेक्ष योगदान के आधार पर उन्हें उपयुक्त रूप से भारित करते हैं। इस प्रक्रिया से हमें किसी एनबीएफसी के स्वास्थ्य का मापन ज्ञात करने में सहायता मिलती है। इस माप को हम स्वास्थ्य प्राप्तांक (हेल्थस्कोर) कहते हैं जो किसी एनबीएफसी के समक्ष संभावित आवर्ती जोखिम संबंधी मुद्दों का एक संकेतक होता है। भावी मार्यनिष्पादन के एक पूर्वकथक के रूप में इस संकेतक की वैधता का परीक्षण भी बाजार संबंधी आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

एचएफसी तथा खुदरा-एनबीएफसी के बीच अंतर

8.19 एनबीएफसी क्षेत्र का विश्लेषण दो उप-क्षेत्रों हेतु किया जाता है—(प) आवास वित्त कंपनियां (एचएफसी) और (पप) खुदरा एनबीएफसी एचएफसी क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए हम ऐसी पांच सबसे बड़ी एचएफसी के समूह का चयन करते हैं जिनका 31 मार्च, 2019 को 8.6 लाख करोड़ रुपयों के बहीकृत (ऑन बुक) पोर्टफोलियों के साथ गैर बैंकिंग आवासीय वित्त क्षेत्र के औसतन लगभग 82 प्रतिशत पर नियंत्रण करती है। इसलिए ये पांच एचएफसी कंपनियां भारत में गैर-बैंकिंग आवास वित्त क्षेत्र की प्रतिनिधि हैं। खुदरा एनबीएफसी क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए हम अपने विश्लेषण के लिए खुदरा क्रेडिट खण्ड के अंतर्गत कार्य करने वाली पंद्रह निजी क्षेत्र की एनबीएफसी कंपनियों, के एक समूह का चयन करते हैं। इन पंद्रह एनबीएफसी कंपनियों, की 31 मार्च, 2019 को प्रबन्धनाधीन परिसम्पत्तियाँ रु. 6.8 लाख करोड़ रु. थीं जबकि, पीएसयू सहित इस उद्योग की कुल प्रबन्धनाधीन आस्तियाँ 9.1 लाख करोड़ रु. थीं। इसलिए ये पंद्रह खुदरा एनबीएफसी कंपनियां बाजार के 75 प्रतिशत का नियंत्रण करती हैं और खुदरा-एनबीएफसी क्षेत्र के एक उत्तम प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती हैं। फर्म के आकार के प्रभावों का विश्लेषण करने हेतु रु. इन पंद्रह खुदरा एनबीएफसी को हम विशाल, मध्यम और लघु आयाम वाली खुदरा एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत करते हैं रु. (एयूएम) रु. इनकी प्रबन्धनाधीन परिसम्पत्तियों के आधार पर

8.20 प्रथमतः हम देखते हैं कि अधोलिखित कारणों से एचएफसी और खुदरा एनबीएफसी कंपनियों के आवर्ती (रोल ओवर) जोखिमों के कारण अलग-अलग हैं। पहला, एचएफसी कंपनियां खुदरा एनबीएफसी कंपनियों के मुकाबले अधिक लंबी अवधि के आस्तियां आवास ऋण, विकासकर्ता ऋण आदि) धारण करती हैं जबकि खुदरा एनबीएफसी कंपनियां मध्यम अवधि

वाली आस्तियां (ऑटो, उपभोक्ता वस्तु, स्वर्ण ऋण आदि) रखती हैं। एचएफसी कंपनियां अपनी आस्तियों और देयताओं की औसत परिपक्वता के खुदरा एन बी एफ सी की तुलना में एक बड़े अंतर का सामान करती हैं। खुदरा एनबीएफसी कंपनियां मुख्यतः एमएसएमई को कार्यशील ऋण, ऑटोमोबाइल वित्तपोषण ऋणों या स्वर्ण ऋणों के रूप में लघुतर अवधि के ऋण प्रदान करती हैं। इस प्रकार, आस्ति पक्ष के आघात एचएफसी की आस्ति देयता के असन्तुलन को काफी बिगड़ते हैं, परंतु खुदरा एनबीएफसी के मामले में आस्ति देयता असन्तुलन पर इनका कम प्रतिकूल प्रभाव होता है।

8.21 दूसरा, खुदरा एनबीएफसी कंपनियां एचएफसी कंपनियों की तुलना में अल्पकालिक थोक वित्तपोषण बाजार पर अधिक निर्भर होती हैं। हमारे मार्च, 2015 से मार्च, 2019 तक एचएफसी के अंतर्गत उधारियों के प्रतिशत के रूप में सीपी का औसत स्तर 8.50 प्रतिशत था जबकि खुदरा एनबीएफसी की यह 12.74 प्रतिशत था। इस प्रकार एचएफसी को परस्पर संबद्धता संबंधी जोखिम कम है जबकि खुदरा एनबीएफसी को ये जोखिम अधिक होते हैं। खुदरा एनबीएफसी के रोल ओवर जोखिमों की संगणना करने के लिए हम, मार्च, 2014 से मार्च, 2019 तक, खुदरा एनबीएफसी क्षेत्र में शीर्ष पंद्रह एलडीएमएफ के माह-दर-माह पोर्टफोलियों पूंजी और इनके समग्र कॉर्पस से संबंधित आंकड़े एकत्र करते हैं। इन पंद्रह एलडीएमएफ का एलडीएमएफ क्षेत्र की प्रबन्धनाधीन आस्तियों के 70 प्रतिशत पर नियंत्रण है और ये खुदरा एनबीएफसी तथा एलडीएमएफ क्षेत्र से उत्पन्न परस्पर संबद्धता संबंधी जोखिमों का प्रतिनिधि त्व करते हैं। एलडीएमएफ क्षेत्र में विमोचन संबंधी जोखिम की संगणना के लिए हम, आस्तियों की श्रेणी (यथा नकद, सरकारी प्रतिभूतियों, टी-बिल, सीपी, सीडी, एनसीडी और कॉर्पोरेट ऋण) के आधार पर एलडीएमएफ की पोर्टफोलियों पूंजी से संबंधित आंकड़े एकत्र करते हैं। एलडलएमएफ के लिए हमारे आंकड़ों का स्रोत एसीई म्युचुअल फंड डाटाबेस है।

8.22 इन दो अंतरों (भिन्नताओं) को ध्यान में रखते हुए हमारा तर्क है कि एलडीएमएफ क्षेत्र में शोधन समस्या के मुख्य कारक (और एनबीएफसी के लिए रोल ओवर समस्या के संचालक) एचएफसी और खुदरा एनबीएफसी के अंतर्गत अलग-अलग हैं। इन कारकों का निहितार्थ यह है कि एचएफसी में रोल ओवर जोखिम के मुख्य कारक एलएम जोखिम और वित्तीय तथा प्रचालनिक लचीलापन से संबंधित हैं जबकि खुदरा एनबीएफसी के मामले में परस्पर संबद्धता जोखिम तथा

वित्तीय और प्रचालिक लचीलापन रोल ओवर जोखिम के मुख्य कारण हैं। इन तर्कों के समर्थन में नीचे एक अधिक विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) विषमता से जोखिम

8.23 अधिकांश वित्तीय संस्थाओं में यह जोखिम आस्तियों और देयताओं की अवधि में विषमता के कारण उत्पन्न होती है। आस्तियों की तुलना में देयताओं की समयावधि लघुतर होती है तथा विशेष रूप से आवासीय क्षेत्र को प्रदान किए गए ऋणों की अवधि दीर्घतर होने की प्रवृत्ति होती है। इस विषमता का निहितार्थ यह है कि एम एनबीएफसी को अपनी अल्पावधिक आबद्धताओं को पूरा करने के लिए नकदी या नकद समलुल्य आस्तियों की एक न्यूनतम राशि (मात्रा) का रखनी चाहिए।

8.24 यदि दीर्घावधि आस्तियों से नकदी का प्रवाह इसकी तात्कालिक ऋण आबद्धताओं को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हो तो एक एनबीएफसी के नया सीपी जारी करके अपनी आबद्धताओं का पुनर्भुगतान फिर भी कर सकती हैं। तथापि, ऐसी पुनर्वित्तपोषण रणनीति तभी ठीक से कार्य करती है जब आस्ति पक्ष आघातोंया देयता पक्ष आघातों का जोखिम न हो।

8.25 दबाव की अवधियों के दौरान सामान्यतः एन बी एफ सी के दीर्घ अवधि आस्तियों से होने वाले आवधिक नकदी प्रवाहों में काफी गिरावट हो सकती है। यह आवर्ती (रोल ओवर) जोखिम को बढ़ाती है। एनबीएफसी कंपनियां जोकि पर्याप्त नकदी बफर रखती हैं और आस्ति देयता सन्तुलन संबंधी किसी समस्या का सामना नहीं करती, संकट की अवधि में टिके रहने में समर्थ हो जाती हैं क्योंकि वे थोक वित्त पोषण बाजार में का उपयोग किए बिना अपनी आबद्धताओं को पूरा कर सकती हैं। इसका निहितार्थ यह है कि इनका रोल ओवर जोखिम बहुत कम होता है।

8.26 पर्याप्त रूप एच एफ सी हेतु, जो कि दीर्घतर अवधि (15 से 20 वर्ष) वाली आस्तियों में निवेश करती हैं, के लिए रोल ओवर जोखिम का सबसे प्रमुख कारक एएलएम का जोखिम होता है। एएलएम जोखिम तब उत्पन्न होता है जब ऋण आस्तियों से भावी संविदात्मक नकदी अंतर्प्रवाह ऋण आबद्धताओं से भावी संविदात्मक नकदी बर्हिप्रवाहों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो। आस्तियों और देयताओं की अवधि के आधार पर नकदी प्रवाहों को अनेक खंडों में विभाजित

किया जाता है और प्रत्याशित अंतर्प्रवाहों और बर्हिप्रवाहों के बीच के अंतरों का मापन किया जाता है। इस अंतर का समस्त वर्षोंके साथ समर्थक परस्पर तुलना के लिए कुल आस्तियों से विभाजित करके सामान्यीकरण किया जाता है। यदि आस्ति/देयता पक्ष का कोई आघात लग जाए तथा फर्म अपनी ऋण आबद्धताओं को रोल ओवर करने में असमर्थ होती है। तो लघु अवधि खंडों (समूहों) में ऋणात्मक आस्ति/देयता अंतर से चूक की संभावना बढ़ जाती है

8.27 चित्र 9 (क एवं ख) में दर्शाया गया है कि एचएफसी और खुदरा-एनबीएफसी क्षेत्र के लिए एएलएम में रूझानों की तिमाही-दर-तिमाही तुलना के आधार पर, एएलएम जोखिम एएएफसी के लिए अधिकांश समस्याजनक है। एचएफसी कंपनियों की अल्पावधिक देयताएं (3 वर्ष तक की परिपक्वता वाली) इन परिपक्वता खंडों में इनकी आस्तियों की अपेक्षा स्पष्टतः अधिक बड़ी हैं। इसलिए, अपनी एएलएम विषमता समस्या के कारण एचएफसी काफी रोलओवर जोखिम का सामना करती हैं। इसके विपरीत, खुदरा-एनबीएफसी के संदर्भ में, समस्त परिपक्वता खंडों के संबंध में नकदी प्रवाहों की प्रोफाइल के बावत इनकी अस्तियां इनकी देयताओं की अपेक्षा अधिक बड़ी होती हैं। इस प्रकार से एएलएम विषमता से उत्पन्न होने वाला रोल ओवर जोखिम खुदरा 5 एनबीएफसी के संदर्भ में निम्नतर होता है।

परस्पर संबद्धता से जोखिम

8.28 परस्पर संबद्धता किसी एनबीएफसी और एलडीएमएफ क्षेत्र के बीच प्रणालीगत जोखिम के संचरण की एक माप है जो दो कारकों द्वारा उत्पन्न होती है। प्रथम, यदि किसी विशिष्ट 'संकटग्रस्त' एनबीएफसी के सीपी में, एलडीएमएफ क्षेत्र औसतन संकेंद्रित स्थितियां रखता है तो इससे उनके अपने उन निवेशकों से अपेक्षाकृत बड़ा शोधन जोखिम हो सकता है जिनकी उस एनबीएफसी की अस्ति-गुणवत्ता के अवहास के कारण चूक की संभावना बढ़ने का है। इस कारक का मापन हम एनबीएफसी द्वारा जारी सीपी की एलडीएमएफ क्षेत्र की औसत यार्थता करते हैं।

8.29 दूसरे, एलडीएमएफ अपने निवेशकों की ओर से रन-जोखिम या शोधन (विमोचन) जोखिम में होते हैं यदि उनकी नकद पूंजी को अत्यधिक खराब स्थितियों मुताबिक रखा जाए। इस प्रकार, एलडीएमएफ क्षेत्र में नकद पूंजी के निम्न स्तर सामान्यतः शोधन दबावों को झेलने के लिए उस एलडीएमएफ क्षेत्र की योग्यता का

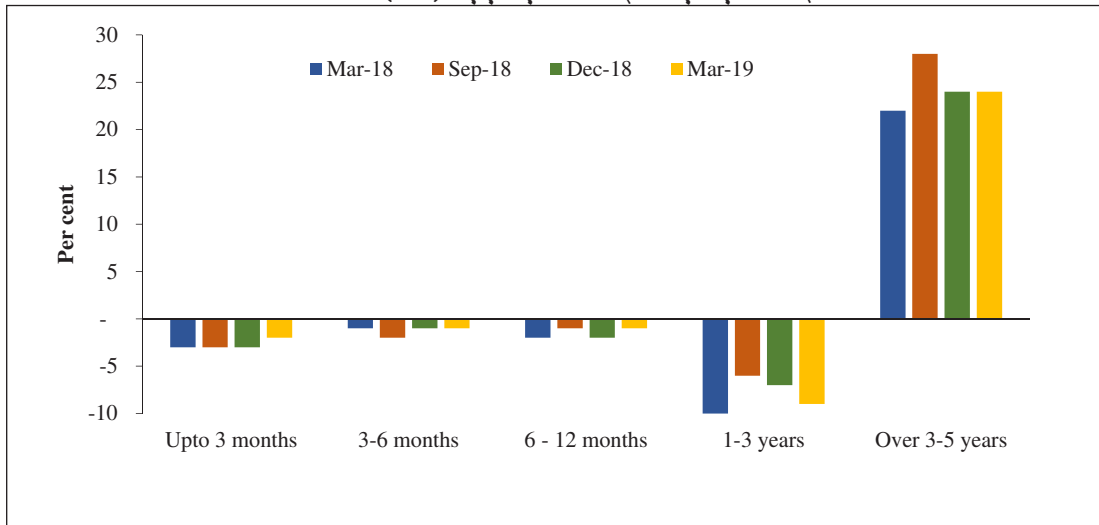
ह्रास करते हैं।

8.30 हम इन दो कारकों के सम्मिलित प्रभाव को परस्पर संबद्धता को जोखिम कहा जाता है, जो संपूर्ण एलडीएमएफ क्षेत्र में निवेशकों किए जाने वाले सामूहिक विमोचन की संभावना को बढ़ाता है जिससे एलडीएमएफ

आस्तियों का तीव्रतर विक्रय (फायर सेल्स) थे विमोचन होता है। योजन (शोधन) संकटग्रस्त एनबीएफसी के दुष्चक्र में में रोल ओवर जोखिम को बढ़ाते हैं।

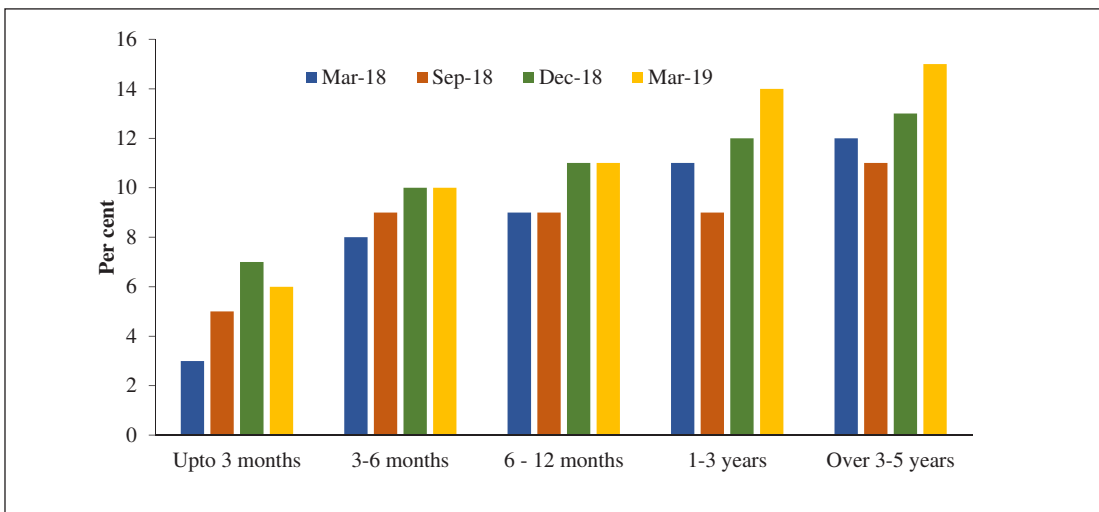
8.31 परस्पर संबद्धता संबंधी जोखिम को उत्पन्न चलाने वाले प्रथम कारक पर प्रकाश डालने के लिए में, एल डी

चित्र 9: (क) एएलएम प्रोफाइल एचएफसी क्षेत्र



स्रोत: इंडियन मॉर्गेज फाइनेंस मार्केट: आई सी आर ए रिपोर्ट, जून-2019, मार्च 2019, नवंबर-2019

(ख) खुदरा एनबीएफसी क्षेत्र



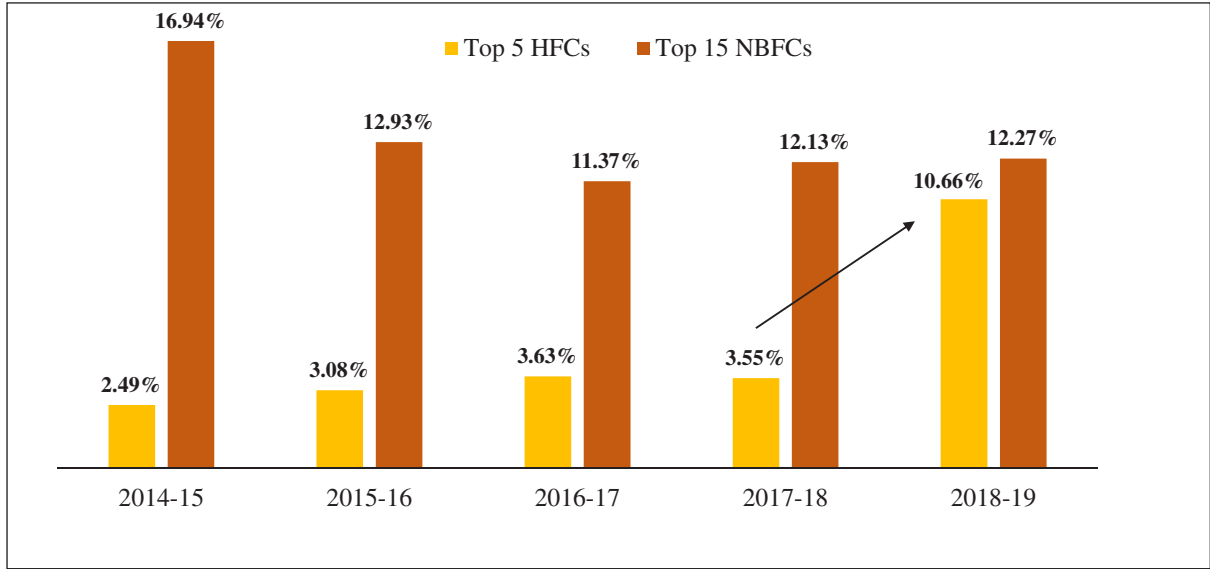
स्रोत: खुदरा एन बी एफ सी क्रेडिट रूझान: आई सी आर ए रिपोर्ट जुलाई -2019

एमएफ क्षेत्र पर एचएफसी क्षेत्र और खुदरा-एनबीएफसी क्षेत्र की औसत निर्भरता की तुलना को चित्र 10 में दर्शाया गया है। इस निर्भरता का मापन, एलडीएमएफ द्वारा धारित उस विशिष्ट एचएफसी/खुदरा-एनबीएफसी क्षेत्रों के वाणिज्यिक प्रपत्र तथा एलडीएमएफ द्वारा धारित संपूर्ण एचएफसी/ खुदरा-एनबीएफसी क्षेत्र के कुल

वाणिज्यिक पत्र औसत की गणना करके किया जाता है। फिर हम एचएफसी/खुदरा-एनबीएफसी क्षेत्रों पर औसत आश्रितता (निर्भरता) ज्ञात करते हैं और इसके लिए वर्ष 2014 से 2019 तक के आंकड़ों को देखते हैं।

8.32 मार्च, 2014 से मार्च, 2019 तक एचएफसी क्षेत्र

चित्र 10: एलडीएमएफ सेक्टर पर एचएफसी/खुदरा-एनबीएफसी सेक्टर की वर्ष दर वर्ष औसत निर्भरता



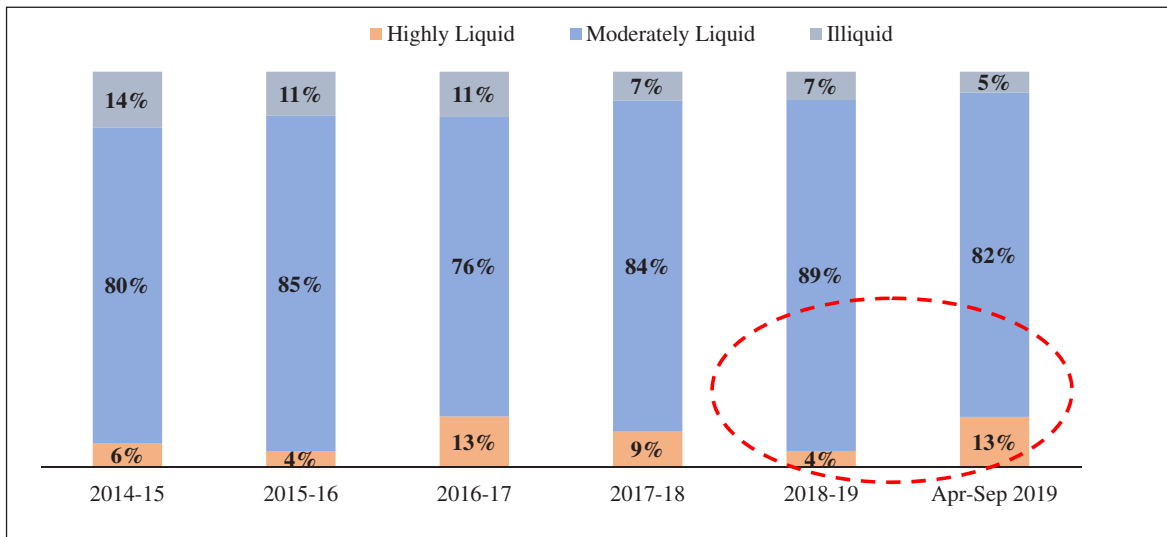
स्रोत: एसीई-एमएफ डेटाबेस

की औसत निर्भरता 4.68% थी, जबकि इसी अवधि में खुदरा-एनबीएफसी क्षेत्र की औसत निर्भरता 13.13% थी। यद्यपि एचएफसी की औसत निर्भरता वित्तीय वर्ष 2019 में बढ़ गई थी, तथापि यह निर्भरता इस अध्याय

में वर्णित 5 में से 4 वर्षों में खुदरा-एनबीएफसी की तुलना में कम थी।

8.33 पारस्परिक संबद्धता जोखिम को चलाने वाले

चित्र 11: शीर्ष 15 एलडीएमएफ का चलनिधि बफर (प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों का प्रतिशत)



स्रोत: एसीई-एमएफ डेटाबेस

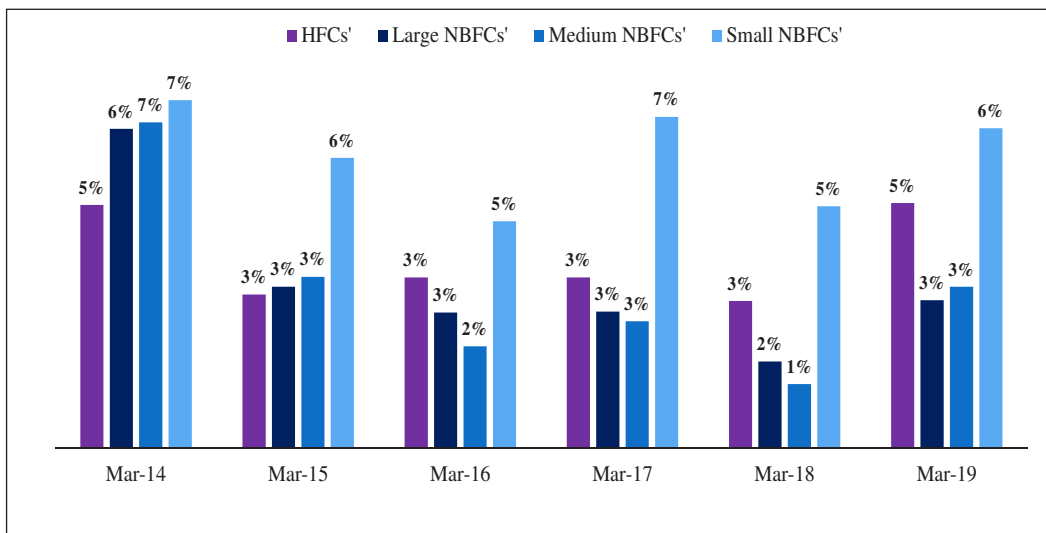
*टिप्पणी: अत्यधिक चलनिधि निवेशों में नकद और नकद समकक्ष, जी-सेक, टी-बिल, बिल रिडिस्काउंटिंग और नकद प्रबंधन बिल शामिल हैं। ये सर्वाधिक चलनिधि निवेश हैं, जिनमें सबसे कम चलनिधि जोखिम होती है। मध्यम तौर पर चलनिधि निवेशों में जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) शामिल हैं। शून्य चलनिधि निवेशों में कॉर्पोरेट ऋण, (एनसीडी), जमाएं, परिवर्तनशील दर वाले लिखत और पास-थ्रू प्रमाण-पत्र/प्रतिभूतिकृत ऋण शामिल हैं।

द्वितीय कारक को देखे तो चित्र 11 में मार्च 2014 से मार्च 2019 तक अपने नमूने में शामिल एलडीएमएफ की परिसंपत्ति वर्ग वार धार्यता दर्शायी गई है। अत्यधिक तरल निवेश जैसे नकदी, सरकारी प्रतिभूतियों आदि का अनुपात एलडीएमएफ सेक्टर में चलनिधि सरलता बफर का माप है। जितना अधिक चलनिधि बफर होगा, उतना ही कम मोचन जोखिम का सामना एलडीएमएफ द्वारा किया जाएगा और एचएफसीएस/खुदरा-एनबीएफसीएस

द्वारा के सामने वाला आवर्ती (रोलओवर) जोखिम भी उतना ही कम होगा। एलडलएमएफ के अत्यधिक चलनिधि निवेश के औसत स्तर में आईएल व एफएस और डीएचएफएल के द्वारा चूक छलांग के बाद देखी गई। शायद सह छलांग सामान्य से अधिक मोचन अधिक की प्रत्याशा में थी।

वित्तीय और परिचालन लचीलापन

चित्र 12: नकद (उधार का प्रतिशत)



स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2014-2019, एचएफसी और खुदरा-एनबीएफसी

8.34 ऋण के बाजार में चलनिधि की कमी से प्रायः ऋण की राशनिंग होती है। जब मजबूत वित्तीय और परिचालन निष्पादन वाली फर्मों को ऋण का लाभ प्राप्त होता है, जबकि कम मजबूत वित्तीय और परिचालन निष्पादन वाली फर्मों को ऋण से वंचित कर दिया जाता है, तब इसके परिणाम स्वरूप ऋण की राशनिंग होती है। मजबूत वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन वाली फर्म यदि ऋण म्यूचुअल फंड से निधि नहीं जुटाती हैं तो वे लंबे समय तक चलनिधि की कमी का मुकाबला कर सकती हैं।

8.35 उधार के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र (सीपी) तथा, पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) और प्रावधान नीति एनबीएफसी के वित्तीय लचीले के माप है, जबकि उधार के प्रतिशत के रूप में नकद, ऋण की गुणवत्ता और परिचालन व्यय अनुपात (ओपेक्स अनुपात) परिचालन लचिले के माप है। एक उदाहरण के रूप में, हम उधार के प्रतिशत के रूप में नकदी जो एनबीएफसी

के परिचालन लचीले का माप है को आरेखित करते हैं, जैसा कि चित्र 12 में दिखाया गया है।

8.36 उधार के प्रतिशत के तौर पर नकद द्वारा मापे गए लचीलेपन का स्तर वित्त वर्ष 2015-16 से, एचएफसीएस और छोटे आकार के एनबीएफसी की तुलना में नकद राशि के प्रतिशत के रूप में मापे गए बड़े और मध्यम आकार के खुदरा-एनबीएफसी में कम था।

अल्पकालिक थोक वित्तपोषण पर निर्भरता

8.37 जैसा कि पहले बताया गया है, यह तर्क दिया जाता है कि वह मौलिक कारक जो आवर्ती (रोलओवर) जोखिम को प्रभावित करते हैं, उसे अल्पकालिक थोक वित्त पोषण बाजार पर एनबीएफसी क्षेत्र की अत्यधिक निर्भरता के रूप में जाना जा सकता है। सबसे पहले, बृहतर अल्पकालिक वित्त पोषण से जोखिम पुनर्मूल्यन की संभावना अधिक हो जाती है (प्रत्यक्ष चैनल)।

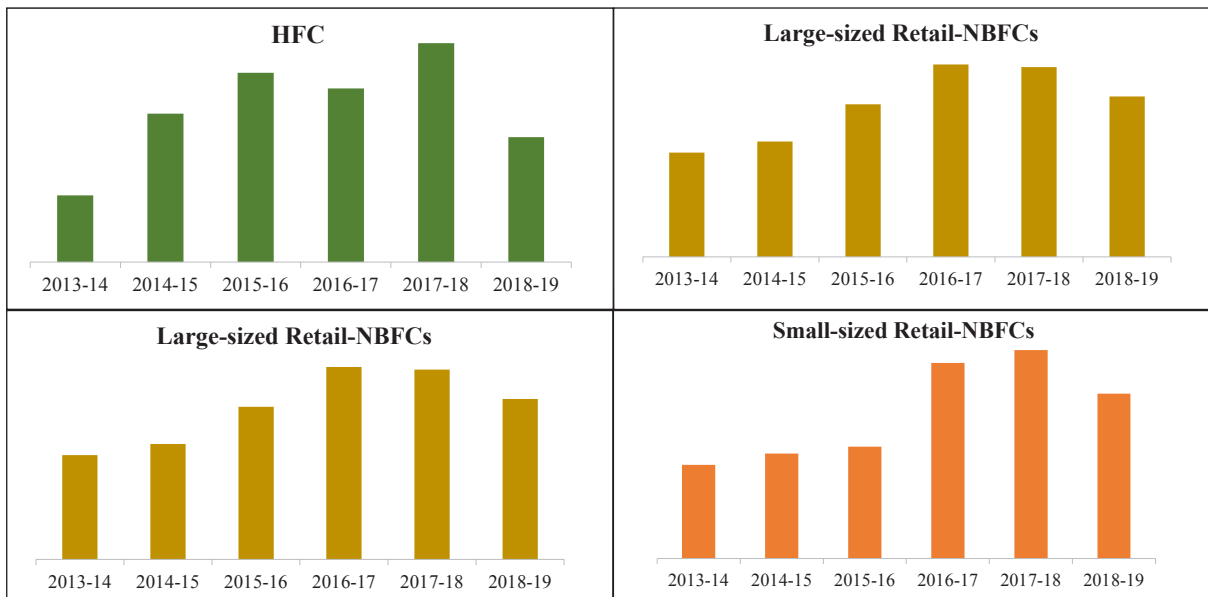
दूसरा, जब अल्पकालिक वित्तपोषण में वृद्धि होती है तब आवर्ती जोखिम, एएलएम जोखिम और परस्पर संबंधित जोखिम के दोनों प्रमुख ड्राइवर में वृद्धि हो जाती है (अप्रत्यक्ष चैनल)।

8.38 हम एचएफसीएस और खुदरा-एनबीएफसी के अल्पकालिक थोक वित्तपोषण (सीपी के रूप में देयता के प्रतिशत) पर निर्भर की तुलना करके इस मामले की जांच करते हैं, जैसा कि चित्र 13 में दिखाया गया है। हम देखते हैं कि एचएफसी सेक्टर और बड़े आकार के खुदरा-एनबीएफसी के वित्तपोषण के स्रोतों में वाणिज्यिक पत्र का औसत स्तर 5-6.5% था, जबकि मध्यम और छोटे आकार के खुदरा-एनबीएफसी के लिए यह 115-12.5% था। चूंकि एचएफसी क्षेत्र अल्पकालिक थोक वित्तपोषण के कम एक्सपोज में है, इसलिए यह समझना चाहिए कि उनकी परिसंपत्ति की लंबी अवधि

को देखते हुए, एएलएम जोखिम को प्रभावित करने के लिए न्यून 5-6.5% जोखिम पर्याप्त है लेकिन यह इतना अधिक नहीं है कि यह पारस्परिक रूप से संबंधित जोखिम को प्रभावित कर सके। इसके विपरीत, लघु और मध्य खुदरा-एनबीएफसी का अल्पकालिक थोक वित्तपोषण के प्रति उच्च एक्सपोजन है, जो एएलएम समस्या उत्पन्न किए बिना पारस्परिक संबंधित जोखिम को आवर्ती जोखिम का एक महत्वपूर्ण ड्राइवर बना देता है। बड़े खुदरा-एनबीएफसी बेहतर स्थिति में हैं, क्योंकि अल्पकालिक थोक वित्तपोषण के प्रति उनका एक्सपोजर इतना कम है कि वह एएलएम जोखिम और पारस्परिक संबंधित जोखिम दोनों को युक्तिसंगत स्तर के भीतर रख सकें।

8.39 हैम, शिन और शिन (2013) ने पाया है कि जमा वित्तपोषण पर अधिक निर्भर करने वाले विरासत

चित्र 13: देयता के प्रतिशत के रूप में वाणिज्यिक पत्र



स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 2014-2019, एचएफसी और खुदरा-एनबीएफसी

बैंक उन बैंकों की तुलना में अधिक सुरक्षित हैं जो थोक वित्तपोषण पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। सितंबर 2018 में इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) द्वारा थोक वित्तपोषण दायित्वों में चूक को उजागर किया गया और हाल ही में जून 2019 में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) द्व

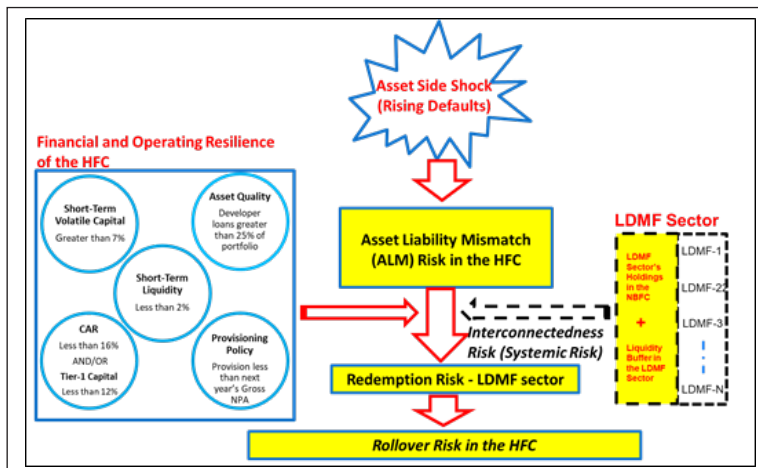
ारा, हैम, शिन व शिन (2013) के निष्कर्षों के अनुरूप थोक वित्तपोषण स्रोतों पर भारी निर्भरता के जोखिमों को उजागर किया गया है।

एचएफसीएस/खुदरा-एनबीएफसी की आवर्ती जोखिम का प्रणाली मानचित्र

8.40 चित्र 14 और 15 में एचएफसी और खुदरा-एनबीएफसी सेक्टरों में आवर्ती जोखिम के प्रचालकों के आधारभूत संकल्पनात्मक ढांचे के संशोधित प्रणाली मानचित्र दिया गया है। ये मानचित्र उन क्रियाविधियों के मध्य उजागर करते हैं जिसके माध्यम

से परिसंपत्ति से संबंधित नुकसान क्रमशः एचएफसीएस और खुदरा-एनबीएफसीएस के स्वास्थ्य स्कोर को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से, एचएफसी सेक्टर का मानचित्र एएलएम जोखिम और वित्तीय और परिचालन

चित्र 14: आवर्ती जोखिम मानचित्र (एचएफसी)

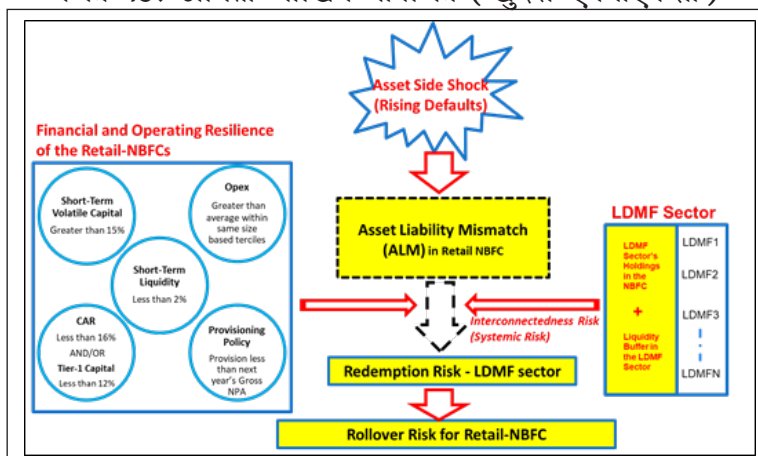


स्रोत: वी. रवि अंशुमन और राजदीप शर्मा के “फायनेंसियल फ्रेजिलिटी इन हाऊसिंग फायनेंस कंपनीज”, II एमबी वर्किंग पेपर, 2020 से संकलित

मोट लाल तीर - मजबूत प्रभाव

बिंदु वाले काले तीर - कमजोर प्रभाव

चित्र 15: आवर्ती जोखिम मानचित्र (खुदरा-एनबीएफसी)



स्रोत: वी. रवि अंशुमन और राजदीप शर्मा के “फायनेंसियल फ्रेजिलिटी इन हाऊसिंग फायनेंस कंपनीज”, II एमबी वर्किंग पेपर, 2020 से संकलित

मोट लाल तीर - मजबूत प्रभाव

बिंदु वाले काले तीर - कमजोर प्रभाव

लचीलेपन को मजबूत प्रभावों व पारस्परिक सम्बद्धता जोखिम को कमजोर प्रभाव के रूप में उजागर करता है। वहीं दूसरी ओर, खुदरा-एनबीएफसी क्षेत्र के मानचित्र में, एएलएम जोखिम को एक कमजोर प्रभाव के रूप में लेकिन पारस्परिक सम्बद्धता जोखिम और वित्तीय और परिचालन लचीलेपन को मजबूत प्रभावों के रूप में उजागर किया गया है।

परिसंपत्ति वित्तीय भंगुरता आकलन हेतु निदान

8.41 इस खण्ड में, किसी एनबीएफसी के गत्यात्मक स्वास्थ्य सूचकांक का आकलन करने की कार्यप्रणाली विकसित की गई है (हम इस अंक को स्वास्थ्य स्कोर के रूप में संदर्भित करते हैं) हमारे प्रतिदर्श में मार्च 2011 से मार्च 2019 तक एचएफसीएस और मार्च 2014 से मार्च 2019 तक खुदरा-एनबीएफसीएस के आंकड़े शामिल हैं। हम अपने प्रतिदर्श में पंद्रह खुदरा-एनबीएफसी को उनकी ऋण पुस्तिका के आकार के आधार पर तीन समान आकार के समूहों में विभाजित करते हैं, क्योंकि इन पंद्रह फर्मों की ऋण पुस्तिका के आकार में काफी अंतर है। यह ऋण पुस्तिका के आकार को नियंत्रित करते हुए उनके स्वास्थ्य स्कोर के पदों में खुदरा-एनबीएफसी के बीच अंतर स्थापित करने में सहायता पहुंचाता है। हमारे नमूने में शामिल पांच एचएफसी के आकार में बहुत अधिक भिन्नता नहीं है और इस प्रकार हम इन पांचों एचएफसी को एचएफसी सेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में मानते हैं।

8.42 हमारा समग्र निष्कर्ष यह है कि एसएचएफसी क्षेत्र के स्वास्थ्य स्कोर 2014 के बाद गिरावट की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वर्ष 2018-2019 के अंत तक, समग्र क्षेत्र का स्वास्थ्य स्कोर काफी खराब हो गया था। खुदरा-एनबीएफसी क्षेत्र का स्वास्थ्य स्कोर 2014 से 2019 की अवधि में लगातार सामान्य से नीचे था। इसके अलावा, हम यह भी पाते हैं कि बड़े खुदरा-एनबीएफसी में स्वास्थ्य स्कोर उच्चतर था। किन्तु मध्यम और लघु रिटेल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से मध्यम आकार की रिटेल-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों मार्च का स्वास्थ्य 2014 से मार्च 2019 तक की समग्र

अवधि के दौरान निम्नतर था।

8.43 अंततः, हम प्रमाणित करते हैं कि हैल्थ स्कोर में परिवर्तन इन स्टॉकों/पोर्टफोलियों की भावी असामान्य प्रतिफलों का एक महत्वपूर्ण भविष्य सूचक है। अतः हैल्थ स्कोर इन फर्मों के भावी कार्य निष्पादन के एक सामयिक संकेतक के रूप में कार्य कर सकता है।

स्वास्थ्य स्कोर/हैल्थ स्कोर (हाउसिंग फाइनेंस कंपनी)

8.44 आवर्ती जोखिम में सापेक्षिक योगदान के आधार पर, हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए आवर्ती जोखिम के महत्वपूर्ण संचालकों को एक समेकित मापवाई (हैल्थ स्कोर) में संयोजित करते हैं। आस्ति देयता प्रबंधन जोखिम और वित्तीय तथा प्रचालन लचीलापन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के हैल्थ स्कोर के सर्वाधिक महत्वपूर्ण संघटक हैं, जैसा कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के लिए हैल्थ स्कोर के मानचित्र में पहले दर्शाया गया था। जैसा कि चर्चा की गई थी, अंतः संबद्धता जोखिम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के लिए कम था और, इसलिए, यह इन फर्मों के लिए आवर्ती जोखिम का महत्वपूर्ण संचालक नहीं था।

8.45 मैट्रिक 1 में आस्ति देयता प्रबंधन जोखिम है, जब कि मैट्रिक 2-6 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का वित्तीय और प्रचालन लचीलापन शक्ति है। मैट्रिक 2,5 और 6 में लचीलेपन की माप हैं और मैट्रिक्स 3 एवं 4 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के प्रचालन लचीलेपन की माप हैं।

8.46 बॉक्स 2 में, हमने ऐसी प्रत्येक मैट्रिक की परिभाषा दी है जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के हैल्थ स्कोर का प्रभावित करती हैं। यहां विचार की गई मैट्रिकों के अलावा ऐसी भी मैट्रिक हो सकती हैं जिनसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के हैल्थ स्कोर की समझाया जा सके, किन्तु हमने इस अध्याय में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मैट्रिकों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की है। बॉक्स 3 में उस विधि का संक्षिप्त विवरण दिया गया है जिसके द्वारा हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के सेक्टर के लिए हैल्थ स्कोर का परिकलन करते हैं।

8.47 हैल्थ स्कोर की रेंज-100 से लेकर +100 है

बॉक्स 2: हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के हैल्थ स्कोरों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मैट्रिक

मैट्रिक 1: आस्ति देयता प्रबंधन प्रोफाइल-आस्ति देयता प्रबंधन प्रोफाइल की माप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की कुल परिसंपत्तियों द्वारा सामानीयकृत की जाए गए प्रत्येक नकदी प्रवाह खण्ड में आस्तियों और देयताओं के मध्य अंतर द्वारा की जाती है।

मैट्रिक 2: अल्पकालिक अस्थिर पूंजी-इसकी माप/हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की कुल उधारी में की सीपी की प्रतिशतता के रूप में की जाती है।

मेट्रिक 3: आस्ति गुणवत्ता-इसकी माप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के कुल ऋण प्रोर्टफोलियो में खुदरा ऋणों के अनुपात द्वारा की जाती है।

मेट्रिक 4: नीति अल्पकालिक चल निधि-इसकी माप हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के कुल ऋणों में नकदी की प्रतिशतता द्वारा की जाती है।

मेट्रिक 5: प्रावधान नीति - इसकी माप किसी वित्त वर्ष में अशोध्य ऋणों के लिए की गई व्यवस्था और अनुवर्ती वित्त वर्ष में कुल गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) के बीच के अंतर द्वारा की जाती है।

मेट्रिक 6: पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)-यह जोखिम-भारित आस्तियों (आरडब्ल्यू ए) के प्रतिशत के रूप में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा धारित टीयर I व टीयर II स्तर पूंजी को योगफल है।

जिसमें उच्चतर स्कोर निम्न आवर्ती जोखिम का संकेत देता है। 0 का हैल्थ स्कोर उदासीन होता है: जोखिमपूर्ण नहीं पर सुरक्षित भी नहीं। हम 50 के बेंचमार्क का प्रयोग

करते हैं, जिसके ऊपर किसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी/सेक्टर को पर्याप्त रूप से सुरक्षित माना जा सकता है।

8.48 चित्र 16 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के लिए

बॉक्स 3: हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के हैल्थ स्कोर का निर्धारण करने के लिए भरण पद्धति

हम बॉक्स 2 में परिभाषित छः मेट्रिक में से प्रत्येक के मापांक (भार) नियत करते हैं। नियत किए गए मापांक व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, और मापांकों का योगफल 100 बिन्दु (प्वाइंट्स) हैं। स्वास्थ्य स्कोर में प्रत्येक मैट्रिक का सापेक्षिक योगदान शामिल करने के लिए, हम आस्ति देयता प्रबंधन (मेट्रिक 1) के लिए 50 प्वाइंट का अधिकतम मापांक नियत करते हैं और वित्तीय एवं प्रचालन लचीलेपन (मेट्रिक 2-6) के लिए 50 प्वाइंट नियत करते हैं। वित्तीय और प्रचालन लचीलेपन के लिए 50 प्वाइंटों को आगे और विभाजित करके मैट्रिक 2 के लिए 20 प्वाइंट, मेट्रिक 3-4 के लिए प्रत्येक को 10 प्वाइंट और मेट्रिक 5-6 के लिए प्रत्येक को 5 प्वाइंट दिए जाते हैं।

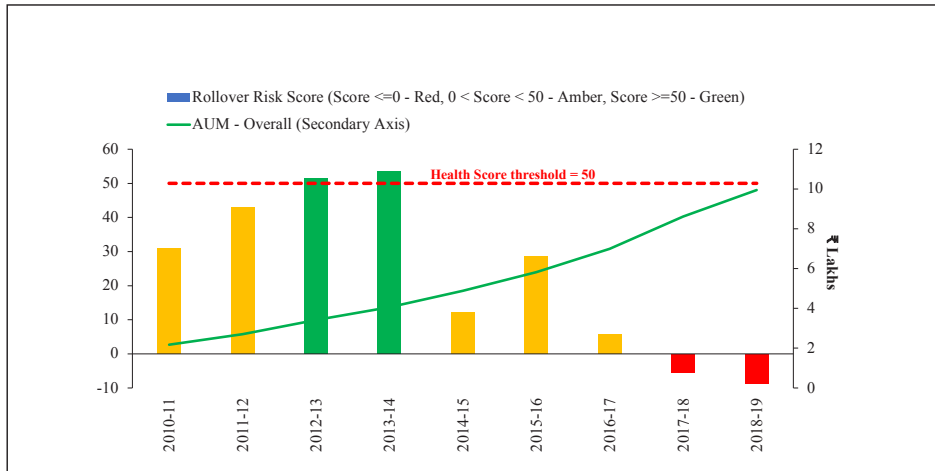
पांचों हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में प्रत्येक के लिए, हम मैट्रिक 1-6 पर आधारित हैल्थ स्कोर की संगणना करते हैं। प्रत्येक मैट्रिक को परिभाषित करने वाले चरों की तुलना पूर्व परिभाषित अवसीमाओं से की जाती है, जो औसत आवर्ती जोखिम का सामना करने वाली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के चर के स्तर को प्रतिबिंबित करती हैं। किसी मैट्रिक के लिए अधिकतम संभव स्कोर उस मैट्रिक के लिए (उदाहरण के लिए आस्ति देयता प्रबंधन जोखिम के लिए 50 स्कोर) नियत किया गया है।

हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के लिए किसी वित्त वर्ष में 31 मार्च के स्वास्थ्य स्कोर की संगणना के लिए, हम प्रत्येक मेट्रिक 1-6 में से प्रत्येक के लिए प्राप्त स्कोर के ए यू एम (प्रबंधन के अंतर्गत आस्तियां) मापित औसत की संगणना करते हैं और योग निकालते हैं। इस विधि का प्रयोग करके, हम समग्र हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के लिए मार्च 2011 से मार्च 2019 तक प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में हैल्थ स्कोर की संगणना करते हैं।

वर्ष 2011 से वर्ष 2019 तक की प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार स्वास्थ्य स्कोर में रूझान को चित्रित किया गया है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के लिए हैल्थ स्कोर में गिरावट का दौर रियल एस्टेट क्षेत्र की वर्ष 2013-14 में मंदी के शीघ्र बाद शुरू हुआ। हैल्थ स्कोर की वैधता को चित्रित करने के लिए डीएचएफएल हैल्थ स्कोर में परिवर्तनों को चित्र 3 में दिया गया है। चित्र 3 से यह स्पष्ट है कि कि

हैल्थ स्कोर में वर्ष 2015 से आगे काफी गिरावट हुई। तथापि, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के प्रबंधन के अंतर्गत आस्ति (एयूएम) में इस अवधि के दौरान काफी बढ़ोत्तरी होती रही है। इन रूझानों को एक साथ लेने पर हमें संकेत मिलता है कि एक जोखिम धीरे-धीरे बढ़ रही है जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के लिए कोई जोखिम उत्पन्न होने का संकेत नहीं है।

चित्र 16: हैलथ स्कोर ओर पोर्टफोलियों रूझान (हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर)



स्रोत: शीर्ष 5 हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट (2011-2019)

हैलथ स्कोर (रिटेल-गैर बैंकिंग फाइनेंस कंप. नियां)

8.49 आवर्ती जोखिम के सापेक्षिक योगदान के आधार पर, हम हैलथ स्कोर की संगणना करने के लिए रिटेल-गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों के लिए आवर्ती जोखिम के महत्वपूर्ण संचालकों को संयुक्त करते हैं। गैर बैंकिंग कंपनियों और नकद ऋण म्यूचुअल फंड सेक्टर के मध्य परस्पर संयोजित जोखिम और वित्तीय एवं प्रचालक समुत्थान शक्ति रिटेल-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हैलथ स्कोर के महत्वपूर्ण संघटक हैं, जैसाकि पीछे रिटेल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के लिए हैलथ स्कोर आरेख में दर्शाया गया है। परस्पर संयोजित जोखिम रिटेल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी सीपी पर नकद ऋण म्यूचुअल फंड क्षेत्र के प्रभाव (मैट्रिक्स 1) और नकद ऋण म्यूचुअल फंड (एलडीएमएफ)

क्षेत्र में चल निधि बफर स्तरों (मैट्रिक्स 2) दोनों से उत्पन्न होता है। हमने यह भी दर्शाया है कि प्रबंधन के अंतर्गत आस्ति (ए एल एम) जोखिम रिटेल-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के लिए कम था और इसलिए, यह इन फर्मों के लिए आवर्ती जोखिम का एक महत्वपूर्ण संचालक नहीं है।

8.50 मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2 में परस्पर संयोजित जोखिम दर्शाया गया है और मैट्रिक्स 3-7 रिटेल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तीय और प्रचालक समुत्थान शक्ति को दर्शाते हैं। मैट्रिक्स 3, 6 और 7 में वित्तीय समुत्थान शक्ति की माप की गई है जबकि मैट्रिक्स 4 एवं 5 में हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए प्रचालक समुत्थान शक्ति की माप की गई है। समेकित रूप में, वे रिटेल-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के वित्तीय एवं प्रचालक समुत्थान को प्रतिबिंबित करने हैं।

बाक्स 4: रिटेल-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हैलथ स्कोर को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण मैट्रिक्स

मैट्रिक्स 1: रिटेल-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा जारी सीपी पर नकद ऋण म्यूचुअल फंड (एलडीएमएफ) क्षेत्र के प्रभाव इसकी माप एल डीएमएफ क्षेत्र द्वारा धारित किसी विशिष्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी/ रिटेल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वाणिज्यिक दस्तावेज और समग्र हाउसिंग फाइनेंस कंपनी/रिटेल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में एलडीएमएफ क्षेत्र के धारित कुल वाणिज्यिक दस्तावेज के अनुपात के औसत द्वारा की जाती है।

मैट्रिक्स 2: एलडीएमएफ क्षेत्र में चलनिधि बफर स्तर-इसकी माप नकदी, जी-सेक्टर आदि जैसे ऐसे अत्यधिक चल निधि निवेशों के औसत अनुपात द्वारा की जाती है जो एलडीएमएफ द्वारा धारित होते हैं।

मैट्रिक्स 3: अल्पकालिक अस्थिर पूंजी-इसकी माप सी पी द्वारा रिटेल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऋणों की प्रतिशतता के रूप में की जाती है।

मैट्रिक्स 4: प्रचालक व्यय अनुपात (ओपेक्स रेशियो)-इसकी माप चालू वित्त वर्ष के अंत में और विगत वित्त वर्ष के अंत में बकाया ऋणों के औसत द्वारा विभाजित किसी वित्तीय वर्ष में प्रचालक व्ययों द्वारा की जाती है। ओपेक्स अनुपात रिटेल-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी की दक्षता का संकेतक होता है।

मैट्रिक 5: अल्पकालिक चल निधि इसकी माप रिटेल-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के कुल ऋणों की नकदी के प्रतिशत द्वारा की जाती है।

मैट्रिक 6: व्यवस्था नीति— इसकी माप किसी वित्त वर्ष में अशोध्य ऋणों के लिए की गई व्यवस्था और परवर्ती वित्त वर्ष में कुल गैर निष्पादन आस्तियों (एन पी ए) के मध्य अंतर द्वारा की जाती है।

मैट्रिक 7: पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर)—यह जोखिम मापित आस्तियों (आरडब्ल्यू ए) के प्रतिशत के रूप में रिटेल-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा धारित प्रथम स्तरीय और द्वितीय स्तरीय राशि है।

बॉक्स 5: रिटेल-एनबीएफसी के स्वास्थ्य प्राप्तांक का निर्धारण करने के लिए विशिष्ट योजना

हमलोग बॉक्स 4 में परिभाषित सात मैट्रिक्स में से प्रत्येक को महत्व देते हैं। निर्धारित मापांक व्यक्तिपरक होता है और मापांक का योग 100 अंक है। हम स्वास्थ्य प्राप्तांक में मैट्रिक्स के प्रत्येक के सापेक्ष योगदान को अधिकृत करने के लिए, 50 अंक इंटरकनेक्टेडनेस जोखिम (मैट्रिक्स 1 एवं 2 अर्थात् प्रत्येक 25 अंक) और 50 अंक वित्तीय और प्रचालनिक लचीलापन (मैट्रिक्स 3-7) प्रदान करते हैं। वित्तीय और प्रचालनिक लचीलापन को पुनःविभाजित किया जाता है जिसमें 20 अंक मैट्रिक 3 को, मैट्रिक्स 4 को 10 अंक एवं मैट्रिक्स 5 को 10 अंक जबकि मैट्रिक्स 6 एवं 7 में से प्रत्येक को 5 अंक प्रदान किए गए।

हम पंद्रह खुदरा एन बी एफ सी में से प्रत्येक के लिए मैट्रिक्स 1-7 के प्राप्तांक के आधार पर स्वास्थ्य प्राप्तांक की गणना करते हैं। प्रत्येक मीट्रिक को परिभाषित करने वाले चर की तुलना पूर्व-निर्धारित थ्रेसहोल्ड से की जाती है, जो खुदरा-एनबीएफसी के लिए चर के स्तर को दर्शाते हैं जो औसत आवर्ती (रोलओवर) जोखिम का सामना कर रहा है।

एक मीट्रिक के लिए अधिकतम संभावित प्राप्तांक (स्कोर) उस मीट्रिक को सौंपा गया मापांक है (उदाहरण के लिए, 50 अंतर्संबंध जोखिम)। रिटेल-एनबीएफसी से संबंधित सभी सात मैट्रिक्स के लिए प्राप्त प्राप्तांक (स्कोर) का योग इसका स्वास्थ्य है। हम 2014-15 से लेकर 2018-19 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्वास्थ्य प्राप्तांक की गणना अपने सैंपल में प्रत्येक पंद्रह रिटेल-एनबीएफसी में से प्रत्येक के लिए करते हैं। यद्यपि रिटेल-एनबीएफसी और एचएफसी के लिए कुछ मैट्रिक्स समान हैं, लेकिन आमतौर पर इन मैट्रिक्स के लिए थ्रेसहोल्ड अलग हैं। इस प्रकार, हम अपने स्वास्थ्य प्राप्तांक की गणना में एचएफसी और रिटेल-एनबीएफसी की परिसंपत्तियों एवं देनदारियों की विभिन्न प्रकृति के लिए जिम्मेदार हैं।

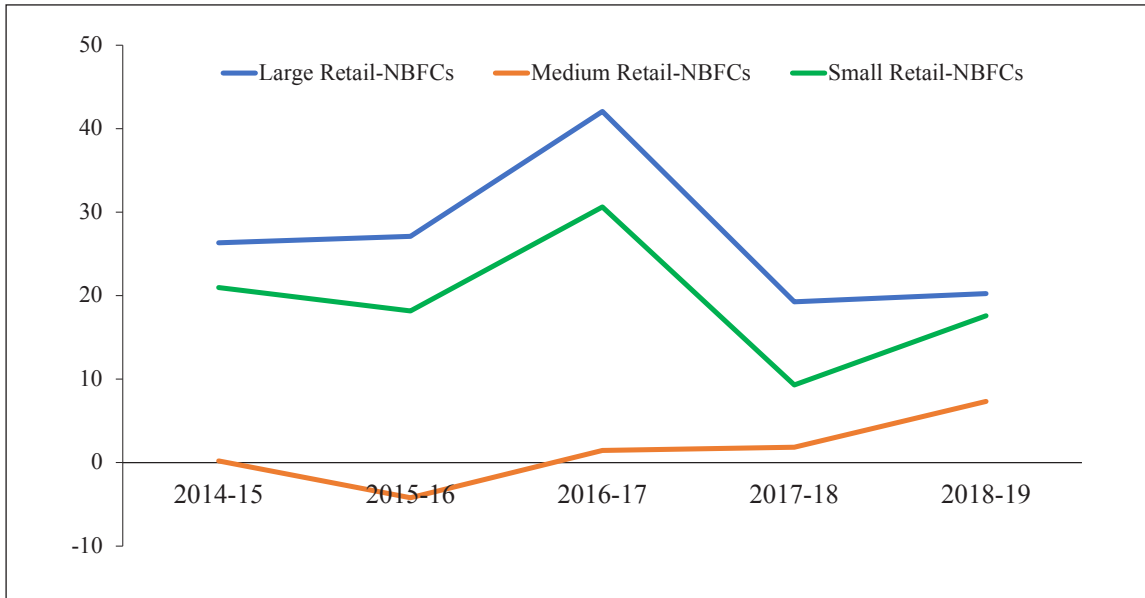
8.51 बॉक्स 4 में प्रत्येक मैट्रिक्स की परिभाषाएँ प्रदान की गई हैं जो खुदरा-एनबीएफसी के स्वास्थ्य-प्राप्तांक को प्रभावित करती हैं। यहाँ पर विचार किए जाने वाले लोगों के अलावा अन्य मैट्रिक्स भी हो सकते हैं जो खुदरा-एनबीएफसी क्षेत्र के संबंध में स्वास्थ्य-प्राप्तांक प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पद्धति का संक्षिप्त विवरण किया गया है।

8.52 हम रिटेल-एनबीएफसी के प्रत्येक उप-वर्ग के भीतर स्वास्थ्य प्राप्तांक की जांच करने के लिए ऋण पुस्तिका के आकार के आधार पर पंद्रह रिटेल-एनबीएफसी के आकार के आधार पर पंद्रह रिटेल-एनबीएफसी के सैंपल को तीन बराबर आकार के समूहों में भी विभाजित करते हैं। हम समूह के भीतर पांच फर्मों के औसत स्वास्थ्य प्राप्तांक की गणना प्रत्येक समूह के लिए करते हैं। एचएफसी के मामले में, रिटेल-एनबीएफसी का स्वास्थ्य प्राप्तांक (हेल्थ स्कोर) - 100 से + 100 तक हो सकता है, जिसमें निम्नतम आवर्ती जोखिम का संकेत मिलता है। शून्य (0) स्वास्थ्य प्राप्तांक एक तटस्थ प्राप्तांक है अर्थात् यह जोखिमपूर्ण नहीं है, लेकिन बहुत

सुरक्षित भी नहीं है। हम 50 अंक को एक बेंचमार्क के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इससे अधिक व्यक्तिगत रिटेल-एनबीएफसी/सेक्टर को पर्याप्त रूप से सुरक्षित माना जा सकता है। चित्र 17 में रिटेल-एनबीएफसी के तीन आकार-आधारित समूहों के औसत स्वास्थ्य प्राप्तांक में रुझान को दर्शाया गया है। हम देखते हैं कि सम्पूर्ण अवधि के दौरान तीन आकार-आधार समूहों के बीच मध्यम आकार के रिटेल-एनबीएफसी में स्वास्थ्य प्राप्तांक कम था। वित्त वर्ष 2017 के बाद बड़े आकार के रिटेल-एनबीएफसी के स्वास्थ्य प्राप्तांक में गिरावट शुरु हो गई।

8.53 चित्र 17 में यह दर्शाया गया है कि आकार हमेशा आवर्ती जोखिम की संभावना से विपरीत नहीं होता है। इस अवधि के दौरान, हमें इस बात के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि औसतन छोटे आकार के खुदरा-एनबीएफसी में मध्यम आकार के लोगों की तुलना में अधिक स्वास्थ्य प्राप्तांक। इसलिए, आकार के आधार पर तरलता बढ़ाने को लक्षित करना, उपइष्टतम पूंजी आवंटन रणनीति होगी।

चित्र 17: औसत स्वास्थ्य प्राप्तांक (खुदरा-एन बी एफ सी)



स्रोत: टॉप 15 रिटेल-एनबीएफसी की वार्षिक रिपोर्ट (2014-2019)

स्वास्थ्य प्राप्तांक का अनुमानित मूल्य

हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एन एफ सी)

8.54 हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्या व्यक्ति-विशेष के एचएफसी के स्वास्थ्य प्राप्तांक में साल-दर-साल (वाई ओ वाई) परिवर्तन भविष्य में इन फर्मों के असामान्य स्टॉक रिटर्न पर किसी तरह का अनुमानित प्रभाव है यह परीक्षण प्रारंभिक चेटावनी संकेत के रूप में स्वास्थ्य प्राप्तांक को मान्य करने में उपयोगी है। आमतौर पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जुलाई से अगस्त तक की अवधि में जारी की जाती है। हालांकि, रिलीज की तारीखें प्रत्येक एचएफसी के लिए भिन्न-भिन्न होती हैं। एचएफसी के स्वास्थ्य स्कोर पर अंतर्दृष्टि प्रदान करने वाली वार्षिक रिपोर्टों में जानकारी धीरे-धीरे कुछ महीनों के क्षितिज पर शेयर के मूल्य में प्रतिबिंबित होनी चाहिए क्योंकि यह जानकारी सक्रिय व्यापारियों द्वारा आवश्यकित की जाती है। यदि हमारा स्वास्थ्य प्राप्तांक एच एफ सी की संभावनाओं का एक भावी उपाय है, तो स्वास्थ्य प्राप्तांक में होने वाले परिवर्तन को उनके स्टॉक के भविष्यगत असामान्य रिटर्न के बारे में बताना चाहिए।

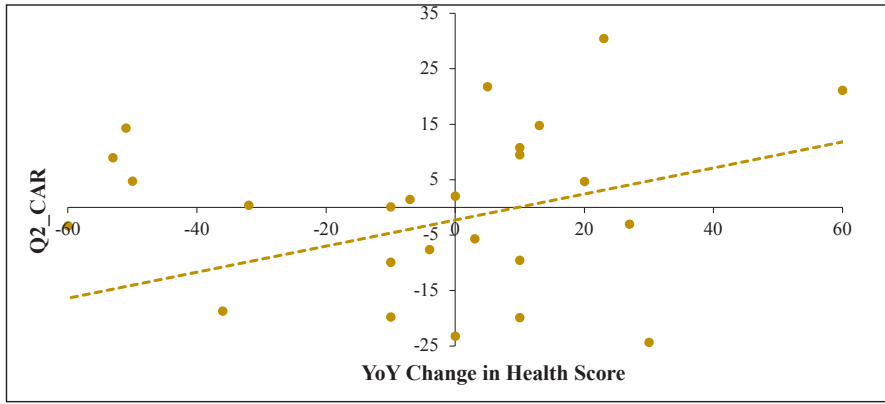
8.55 एचएफसी की वार्षिक रिपोर्टों के जारी होने की तारीख अनिश्चितता, और इन फर्मों के भविष्य के स्टॉक मूल्य में उतार-चढ़ाव/विवरणियों में प्रतिबिंबित होने के लिए अपेक्षित समय को देखते हुए, हम 2011 से 2018 तक प्रत्येक वर्ष की जुलाई से सितंबर (दूसरी तिमाही)

से संबंधित एनबीएफसी के स्टॉक के संचायी मुनाफा (रिटर्न) का उपयोग करते हुए मूल्य प्रभाव का अनुमान लगाते हैं। हम साप्ताहिक आधार पर असामान्य रिटर्नस (विवरणियों) की गणना करने के लिए समकालीन निफ्टी 500 इंडेक्स रिटर्नस (विवरणियों) को घटाते हैं। जुलाई से सितंबर तक संचयी असामान्य मुनाफा (दूसरी तिमाही का पूंजी पर्याप्तता अनुपात) की गणना प्रत्येक हफ्ते साप्ताहिक असामान्य रिटर्नस (विवरणियों) को जोड़कर की जाती है (वर्ष में 12 सप्ताह)।

8.56 वर्ष 2011-2018 तक प्रत्येक वर्ष के लिए समस्त पांच एचएफसी हेतु दूसरी तिमाही के पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी ए आर) की गणना इसी तरह से की जाती है हमारे सैंपल में पांच एचएफसी की सूचीबद्ध वर्ष के आधार पर, हम 32 दूसरी तिमाही के पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सी ए आर) मूल्य के एक सेट और व्यक्तिगत एच एफ सी से संबंधित स्वास्थ्य प्राप्तांक को प्राप्त करते हैं।

8.57 चित्र 18 में हमारे सैंपल से संबंधित एचएफसी क्षेत्र के स्वास्थ्य प्राप्तांक की दूसरी तिमाही एवं साल-दर-साल परिवर्तित एवं बिखरे हुए विषय को दर्शाया गया है। परिवर्तित एवं बिखरे हुए विषय में सकारात्मक रूप से ढलान वाली ट्रेड लाइन वास्तविक आंकड़ों की बजाय हमारे अनुमान की ही पुष्टि करती है कि साल-दर-साल स्वास्थ्य प्राप्तांक में सुधार से भविष्य में एचएफसी स्टॉक के अल्पकालिक संचयी असामान्य रिटर्न में वृद्धि हो सकती है।

चित्र 18: स्वास्थ्य प्राप्तांक (एच एफ सी) से संबंधित संचयी असामान्य विवरणी (रिटर्नस)



स्रोत: ब्लूमबर्ग से प्राप्त डाटा पर आधारित

रिटेल-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां

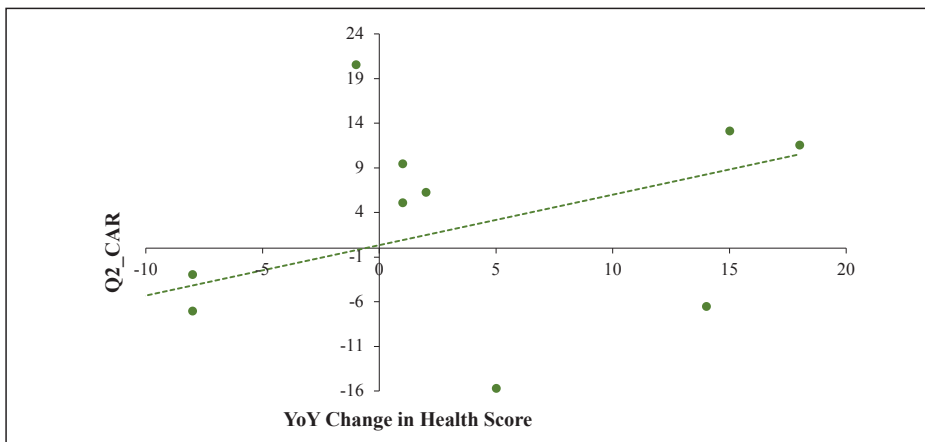
8.58 हम समझने का प्रयास करेंगे कि प्रत्येक रिटेल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हेल्थ स्कोर वर्ष परिवर्तन में संबंधित इन फर्मों के भावी असामान्य स्टॉक से संबंधित कोई भविष्य सूचक प्रभाव है। पंद्रह रिटेल-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए दूसरी तिमाही के सीएआर का परिकलन पूर्णतः उसी तरह से किया जाता है जैसा कि हमने वर्ष 2015-2019 की अवधि में प्रत्येक वर्ष के लिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (उप खंड में चित्रित) के लिए किया है।

8.59 पंद्रह रिटेल: गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से प्रत्येक कंपनी के लिए हम दूसरी तिमाही के सीएआर मूल्यों एवं संवात हेल्थ स्कोर का एक सेट प्राप्त करते हैं। पंद्रह रिटेल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का वर्गीकरण व्यापक, मध्यम और लघु और तीन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में किया गया है। हम आकार आधारित

गैर बैंकिंग बैंकिंग वित्तीय कंपनी के स्टॉक के समान रूप से मापित पोर्टफोलियों तैयार करके वर्ष 2015 से 2019 तक के प्रत्येक वर्ष के लिए तीन आकर आधारित पोर्टफोलियों से संबंधित दूसरी तिमाही के सीएआर का परिकलन करते हैं। तीन पोर्टफोलियों के लिए प्रत्येक दूसरी तिमाही के सीएआर के अनुसार हम रिटेल-गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के घटक सेट के औसत हेल्थ स्कोर का परिकलन करते हैं।

8.60 चित्र 19 में दूसरी तिमाही के सीएआर की रूपरेखा और तीन आकार पर आधारित पोर्टफोलियों के हेल्थ स्कोर में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन को चित्रित किया गया है। रूपरेखा में सकारात्मक रूप से तिरछी खींची गई रेखा हमारी इस प्रत्याशा की पुष्टि करती है कि वर्ष दर वर्ष के हेल्थ स्कोर में सुधार के परिणामस्वरूप तीन पोर्टफोलियों के भावी अल्पकालिक कुल असामान्य प्राप्तियों में वृद्धि होनी चाहिए।

चित्र 19: संचयी असामान्य प्राप्ति (दूसरी तिमाही के सीएआर) बनाम हेल्थ स्कोर (रिटेल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन



स्रोत: ब्लूमबर्ग से प्राप्त डाटा पर आधारित

नीतिगत विवक्षाएं

8.61 उपर्युक्त विश्लेषण से यह पता चलता है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में फर्म उस समय आवर्ती जोखिम के प्रति अतिसंवेदनशील होती है जब वे रियल सेक्टर में अपने निवेशों के वित्त पोषण के लिए लघु अवधि से संबंधित थोक बिक्री निधि बाजार पर अत्यधिक निर्भर होती है। आभासी बैंकिंग प्रणाली में वित्तीय शिथिलता को रोकने के लिए निम्नलिखित नीतिगत पहल की जा सकती है।

(i) नियामक इस विश्लेषण में प्रस्तुत हेल्थ कार्यप्रणाली का प्रयोग कर सकते हैं ताकि एकल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में आसन्न आवर्ती जोखिम से संबंधित समस्याओं के पूर्व चेतावनी संकेतों का पता चल सके। हेल्थ स्कोर में अधोगामी रुझान का प्रयोग गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के अधिक मॉनीटरन को प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हेल्थ स्कोर के घटकों में रुझानों के विश्लेषण से ऐसे उचित दोषनिवारक उपायों में बाधा उत्पन्न हो सकती है जिनका प्रयोग प्रतिकूल रुझान को पलटने के लिए किया जाना चाहिए।

(ii) जब अत्यधिक नकदी कमी की स्थिति उत्पन्न होती है जैसा कि हम अभी अनुभव करते आ रहे हैं, नियामक योग्य गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए इष्टतम पूंजी निवेश का निर्देश देने के लिए आधार के रूप में हेल्थ स्कोर का प्रयोग कर सकते हैं। ताकि पूंजी अभाव का कुशल आबंटन सुनिश्चित हो सके।

(iii) उपर्युक्त विश्लेषण का उपयोग थोक विक्रय वित्तपोषण की मात्रा पर ऐसी विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है, जिनकी आभासी बैंकिंग प्रणाली में फर्मों के लिए अनुमति प्रदान की जा सकती है। ऐसा मानदंड उन अत्यधिक विवेकपूर्ण विनियमों के अनुसार होगा जिसकी आवश्यकता प्रत्येक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तपोषण की नीति के कारण उत्पन्न होने वाली व्यवस्थित जोखिम समस्याओं को हृदय से स्वीकार करने के लिए होती है। इन मानदंडों को प्रति चक्रिय रूप से समायोजित किया जा सकता है क्योंकि नकदी की कमी के मूलकारणों अच्छे दिनों के समय में ही शुरू हो जाते हैं।

अध्याय एक नजर में

- गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के वर्तमान नकदी की कमी के प्रभाव के कारण इस अध्याय में भारत में आभासी बैंकिंग प्रणाली से संबंधित आवर्ती जोखिम के मुख्य घटकों की जांच की गई है।
- आवर्ती जोखिम के मुख्य घटक निम्नानुसार हैं: आस्ति देयता प्रबंधन (एएलएम) जोखिम, अंतरसंयोगकता जोखिम और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के वित्तीय एवं प्रचालन लचीलापन है।
- अल्पावधि थोकविक्रय वित्त व्यवस्था पर अतयधिक आश्रित रहने से आवर्ती जोखिम बढ़ता है।
- प्रभावशाली स्कोरिंग कार्यप्रणाली के उपयोग से हम हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और रिटेल गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (जो अपने संबंधित क्षेत्रों की प्रतिनिधि होती हैं) के प्रतिचयन के लिए आवर्ती जोखिम की मात्रा निर्धारित करते हैं और उसके द्वारा नैदानिक (हेल्थ स्कोर) की संगणना करते हैं।
- हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्षेत्र के लिए हेल्थ स्कोर में वर्ष 2014 के बाद घटते हुए रुझान को प्रदर्शित किया गया है। वित्त वर्ष 2019 के अंत तक समग्र क्षेत्र का हेल्थ स्कोर काफी अधिक खराब रहा।
- रिटेल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र के हेल्थ स्कोर वर्ष 2014 से 2019 तक की अवधि तक संगतरूप से काफी कम था।
- दीर्घ रिटेल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास अधिक हेल्थ स्कोर था परंतु मध्यम और लघु रिटेल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास मार्च, 2014 से मार्च, 2019 तक की अवधि तक हेल्थ स्कोर कम था।
- उपर्युक्त निष्कर्षों से यह पता चलता है कि हेल्थ स्कोर से आसन्न नकदी समस्याओं का पूर्व चेतावनी संकेत मिलता है।

- हमें पर्याप्त प्रमाण मिलता है कि इक्विटी बाजार प्रत्येक हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों एवं रिटेल गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के हेल्थ स्कोर में अनुकूल वृद्धि करने की प्रतिक्रिया हैं ताकि हेल्थ स्कोर की वैद्यता के अनुरूप पूर्व चेतावनी संकेत मिल सकें।
- इस तरह से हमारे विश्लेषण में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में फर्मों के निवेश एवं वित्तपोषण संबंधी निर्णयों के समष्टिमूलक बहिर्मुखी तत्वों का समावेश करते हुए इनकी वित्तीय हेल्थ से संबंधित विविध महत्वपूर्ण संकेत मिलते हैं।
- विकास के आभासी बैंकिंग चैनल की बहाली के लिए इच्छुक नीति निर्माता गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्षेत्र में फर्म के अंतर्गत चल निधि वृद्धि का दक्षता पूर्वक नियतन करने और उसके द्वारा पूंजीक्षम तरीके से वित्तीय संकट को रोकने के लिए इस विश्लेषण का प्रयोग कर सकते हैं।

संदर्भ

“Chernenko, S., and Sunderam A., ‘Frictions in Shadow Banking: Evidence from the Lending Behavior of Money Market Mutual Funds’, *The Review of Financial Studies*, 2014,”

“Hahm, Shin and Shin, ‘Non-Core Bank Liabilities and Financial Vulnerability’, *Journal of Money, Credit and Banking*, 2013,”

“Acharya V.V., Khandwala H., and Oncu T.S., ‘The Growth of a Shadow Banking System in Emerging Markets: Evidence from India’, *Journal of International Money and Finance*, 2013,”

“Ghosh, S., Del Mazo I.G., and Inci O. R.,

‘Chasing the Shadows: How Significant Is Shadow Banking in Emerging Markets?’, *Economic Premise*, Washington, World Bank, 2013,”

“M.T Kusy and W.T Ziemba, ‘A Bank Asset and Liability Model’, *Working Paper*, 1983,”

“S. Bokhari, D. Geltner and A. Minne, ‘A Bayesian Structural Time Series Approach to Constructing Rent Indexes: An Application to Indian Office Markets’, *Working Paper*, 2017,”

V. Ravi Anshuman and Rajdeep Sharma, “Financial Fragility in Housing Finance Companies”, *IIMB Working Paper*, 2020

V. Ravi Anshuman and Rajdeep Sharma, “Financial Fragility in Retail-NBFCs”, *IIMB Working Paper*, 2020

निजीकरण और धन सृजन

मुक्त उद्यम ने मनुष्य की रचनात्मकता और अर्जनशीलता की तीव्र इच्छाओं को इस रूप में अभिव्यक्त करने के लिए सक्षम बना दिया है जो समाज के सभी लोगों को लाभान्वित करता है। अब मुक्त उद्यम को संघर्ष करने दें, अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो स्वतंत्रता में आस्था रखते हैं।

- मार्गरेट थैचर

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में सामरिक विनिवेश के हाल के अनुमोदन ने बीपीसीएल के शेयरधारकों की इक्विटी के मूल्य में 33,000 करोड़ रु. की वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाई। यह बीपीसीएल की दक्षता में अहम सुधारों से प्रत्याशित लाभ सहित कंपनी के कुल मूल्य में वृद्धि दर्शाता है, जब इसकी एचपीसीएल से तुलना की जाती है, जो सरकार के नियंत्रणाधीन बनी रहेगी। इसलिए यह अध्याय भारतीय परिप्रेक्ष्य में निजीकरण से सहित दक्षता लाभ की जांच करने का प्रयास करता है। यह 11 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के पूर्व-पश्चात निष्पादन का विश्लेषण करता है, जिनमें 1999-2000 से 2003-04 तक कार्यनीतिक विनिवेश किया गया है। अंतर में अंतर कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए सावधानीपूर्वक तुलना करने के लिए इन सीपीएसई की तुलना समान उद्योग समूह में समकक्ष कंपनियों से की गई है। हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि निजीकृत सीपीएसई की निवल संपत्ति, शुद्ध लाभ और परिसंपत्तियों पर लाभ निजीकरण के पश्चात अवधि में औसतन काफी बढ़ा है। इस अवधि के दौरान इन सीपीएसई ने अपनी समकक्ष कंपनियों से औसतन कहीं बेहतर निष्पादन भी किया है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि RoA समकक्ष कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए नकारात्मक से सकारात्मक में परिवर्तित हुआ है, जो यह दर्शाता है कि निजीकृत सीपीएसई समान संसाधनों से अधिक धन जुटाने में सफल रहे हैं। कर्मचारियों की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, चूंकि निजीकरण की अवधि के पश्चात प्रति कर्मचारी सभी परिवर्तीकारकों जैसे प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ, प्रति कर्मचारी सकल राजस्व और प्रति कर्मचारी निवल संपत्ति में वृद्धि हुई है। निष्पादन में यह सुधार प्रत्येक सीपीएसई में व्यक्तिगत रूप से भी लागू होता है। हमारा विश्लेषण स्पष्ट रूप से दावे के साथ कहता है कि सीपीएसई की कार्यनीतिक बिक्री के माध्यम से विनिवेश इन उपक्रमों को निवल संपत्ति, लाभप्रदता, विक्रय वृद्धि, दक्षता और अपने हितधारकों को लाभ देने की शर्तों पर बेहतर निष्पादन द्वारा प्रदर्शित संपत्ति सृजन के सामर्थ्य के द्वार खोल देता है। इसलिए यह अध्ययन सामरिक बिक्री के मार्ग के माध्यम से आक्रमक विनिवेश के विषय को बल देता है।

9.1 नवंबर, 2019 में भारत ने एक दशक से अधिक समय में अपना सबसे बड़ा निजीकरण अभियान शुरू किया है। चुनिंदा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में भारत सरकार के प्रदत्त पूंजी भाग को 51% से कम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। चुनिंदा सीपीएसई में से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

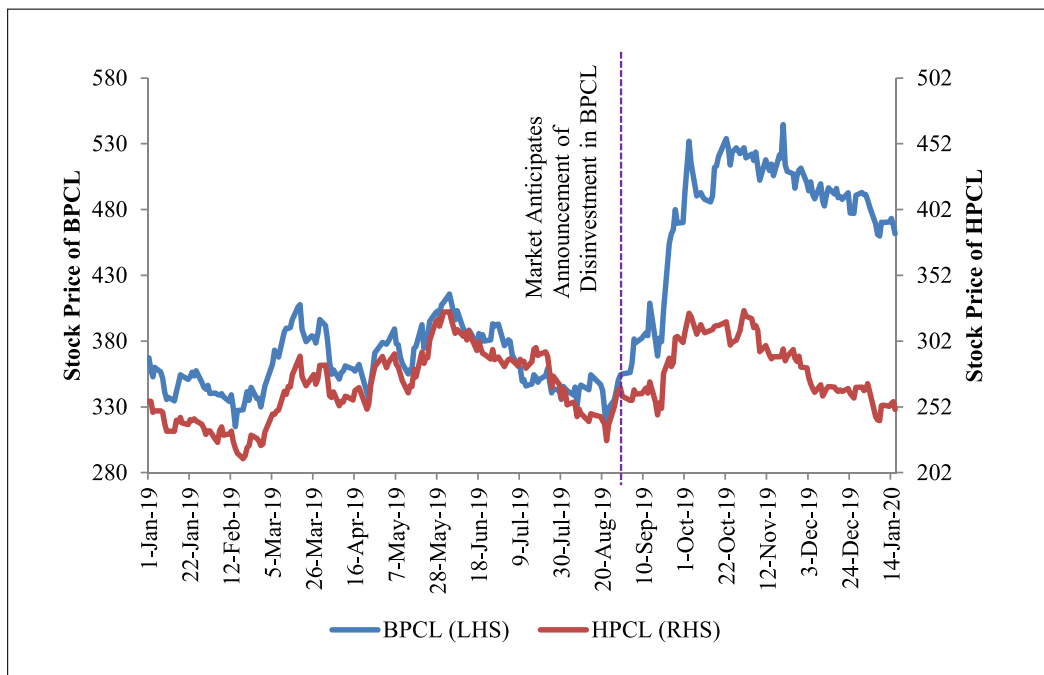
(बीपीसीएल) में सरकार की 53.29% शेयरधारिता के सामरिक विनिवेश को मंजूरी दे दी गई। आकृति 1 में अपनी समकक्षी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की तुलना में बीपीसीएल का शेयर मूल्य दर्शाया गया है। हम सितंबर 2019 से बीपीसीएल और बीएचसीएल के मूल्यों में अंतर पर अपना ध्यान केन्द्रित

करेंगे जब बीपीसीएल के निजीकरण की खबर पहली बार सामने आई थी।¹ बीपीसीएल और एचपीसीएल की तुलना यह सुनिश्चित करती है कि शेयर बाजार में या तेल उद्योग में कोई व्यापक उठापटक को दूर किया जा सके। हम आकृति 1 में यह देखते हैं कि एचपीसीएल ओर बीपीसीएल के शेयर मूल्यों की सितंबर तक एक समान गति थी। तथापि, बीपीसीएल के विनिवेश की घोषणा के पश्चात उनके शेयर मूल्यों में विचलन आरंभ हुआ। समान अवधि में बीपीसीएल के शेयर मूल्य में वृद्धि की जब एचपीसीएल के मूल्य में परिवर्तन से करते हैं तो बीपीसीएल के शेयरधारिता इक्विटी के मूल्य

में लगभग 38000 करोड़ रु. की वृद्धि पाते हैं। चूंकि समान अवधि के दौरान कर्मचारियों और ऋणदाताओं सहित अन्य शेयरधारकों के मूल्यों में बदलाव की कोई सूचना नहीं मिली, इसलिए 33,000 करोड़ रु. की वृद्धि, बीपीसीएल के समग्र कंपनी मूल्य में स्पष्ट वृद्धि और जिसके चलते राष्ट्रीय संपत्ति में समान राशि की वृद्धि दर्शाती है।

9.2 चूंकि शेयर बाजार किसी कंपनी के वायदा नकदी प्रवाह के मौजूदा मूल्य को प्रदर्शित करता है, मूल्य में वृद्धि बीपीसीएल की दक्षता में सुधार से प्रत्याशित लाभ

चित्र 1: बीपीसीएल और एचपीसीएल के शेयर मूल्यों की तुलना



स्रोत: बीएसई

प्रकट करती है जब उसकी तुलना एचपीसीएल से की गई, जो सरकार के नियंत्रणाधीन रहेगी। सामरिक विनिवेश का मार्गदर्शन आधारभूत आर्थिक सिद्धांत द्वारा किया जाता है कि सरकार को विनिर्माण/माल उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में अपनी संलिप्तता समाप्त कर देनी चाहिए जहां प्रतिस्पर्धी बाजारों ने विकास की

पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है। विभिन्न कारकों के कारण ऐसी कंपनियों के निजी हाथों में बेहतर निष्पादन करने की संभावना है जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन और कार्यक्षम प्रबंधन पद्धतियां; और इस प्रकार संपत्ति का सृजन करेंगे तथा देश की आर्थिक प्रगति में योगदान करेंगे। इसलिए एचपीसीएल के साथ तुलना करने

¹ <https://www.livemint.com/market/mark-to-market/why-privatization-of-bpcl-will-be-a-good-thing-for-all-stakeholders-1568309050726.html>

पर बीपीसीएल के मूल्य वृद्धि इन प्रत्याशित लाभों को प्रकट करती है। अनेक देशों में फैली वित्तीय अर्थव्यवस्थाओं में विस्तृत साहित्य स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है कि निजीकरण ऊपर उल्लिखित

स्रोतों से महत्वपूर्ण दक्षता लाभ लाता है (बॉक्स 2 देखें)। इस परिप्रेक्ष्य में सुश्री मार्गरेट थैचर के नेतृत्व में यू के का अनुभव विशेषरूप से विचारणीय है। (बॉक्स 1 देखें)।

बाक्स 1 यूके का निजीकरण मॉडल

ब्रिटिश निजीकरण कार्यक्रम 1980 में यूनाइटेड किंगडम (यूके) की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के प्रबंधन में शुरू किया गया था। आरंभिक चरण (1979-80) में, राजस्व में वृद्धि करने और इस प्रकार ब्रिटिश एयरोस्पेस एंड केबल एंड वायरलेस जैसी कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी कम करने के लिए पहले से लाभप्रद कंपनियों के निजीकरण पर फोकस था। अगले चरण (1982-86) में, मूल उपादेयताओं के निजीकरण की ओर फोकस स्थानांतरिक हो गया और सरकार ने जगुआर, ब्रिटिश टेलीकॉम, केबल एंड वायरलेस ब्रिटिश एयरोस्पेस, ब्रिट ऑयल तथा ब्रिटिश गैस के शेष हिस्से को बेच दिया। सबसे आक्रामक चरण (1987-91) में, ब्रिटिश स्टील, ब्रिटिश पेट्रोलियम, रोल्स-रॉयश, ब्रिटिश एयरवेज, वाटर एंड इलैक्ट्रोसिटी को बेच दिया गया।

कंपनी के सभी या कुछ शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से मुख्य पद्धति थी। ब्रिटिश एयरोस्पेस का निजीकरण 1981 में इसके 52 प्रतिशत शेयरों के आईपीओ द्वारा किया गया था जिसके शेष शेयरों को बाद के वर्षों में बेचा गया था। 1984 में दि ब्रिटिश टेलीकॉम (आईपीओ) का आईपीओ बड़े पैमाने पर शेयर की पेशकश थी और उस तारीख तक विश्व इतिहास में सबसे बड़ी शेयर पेशकश में दो मिलियन से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। दि ओईसीडी (2003:24) ने बीटी निजीकरण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर “बड़े पैमाने पर निजीकरण की शुरूआत का अग्रदूत” कहा था। बाद के वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश गैस, ब्रिटिश स्टील, इलॉक्ट्रिक उपादेयताओं, और अन्य कंपनियों में बड़े पैमाने पर शेयर की पेशकश की। दूसरी निजीकरण की पद्धति प्रत्यक्ष बिक्री या व्यापार बिक्री, जिसमें बातचीत या प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मौजूदा निजी कंपनी को कोई अन्य कंपनी बेचना शामिल है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश एरोस्पेस को रोबर ऑटो मोबाइल और रॉयल आर्डनेंस की बिक्री की थी। निजीकरण की दिशा में जो अन्य सीधी बिक्री हुई है उनमें ब्रिटिश शिपबिल्डर्स, सीलिंग फेरीज और दी टोटे आते हैं। ब्रिटेन के नेशनल फ्रंट कॉर्पोरेशन को 1982 में कम्पनी के कर्मचारियों को बेच दिया गया था और लंदन की बस सेवाओं को 1994 में कम्पनी के प्रबंधकों और कर्मचारियों को बेच दिया गया था।

अधिकतर मामलों में ब्रिटेन में निजीकरण के विनियामक संरचनाओं में सुधार लाये जाने के साथ-साथ ही किया गया था। सरकार इस बात को समझती है कि जहां भी सम्भव हो निजीकरण को खुली प्रतियोगिता के साथ किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश टेलीकॉम पोस्ट ऑफिस से अलग हो गया था और इसके पहले कि इसके शेयर्स जनता में बेचे जाते, सरकार से दूरी बनाते हुए इसकी स्थापना एक निगम के रूप में कर दी गयी थी। फिर उसके बाद कुछ समय बीत जाने पर सरकार के इसके प्रतिस्पर्धास्वरूप बीटी की स्थापना की थी। प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने 1980 में इंटरसिटी बस सेवा शुरू की थी। इस अभियान के बाद राज्य के स्वामित्व वाली बस लाइन जैसे कि नेशनल एक्सप्रेस का भी निजीकरण कर दिया गया था। 1980 के दशक में ढेर सारे ब्रिटिश सीपोर्ट्स का निजीकरण हुआ था और सरकार ने उन श्रमिक संघ कानूनों में सुधार किया था जिनके कारण उद्योगों का कामकाज ठप पड़ गया था। फ्लोरिया (2004) ने यूके में किये गये निजीकरण में किये अपने व्यापक अनुसंधान में यह पाया है कि इस प्रकार पर्दाफाश से शेयर होल्डरों और कर्मचारियों (विशेषकर प्रबंधकों) को लाभ मिला है तथा फर्मों और अन्य कर्मचारियों पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। किये गये क्षेत्र विशिष्ट अध्ययन (एफ्फ्यूसो, एंगेरिज, और पोल्लिट्ट, 2009) में यह पाया गया है कि यूके में रेल कम्पनियों का जो निजीकरण हुआ था उससे कार क्षमता में काफी वृद्धि हुई थी। पार्कर (2004) ने पाया है कि निजीकरण से प्रतिस्पर्धापरक बाजार पैदा हो सकेंगे।

बाक्स 2 निजीकरण के लाभ के प्रमाण

ब्राउन एट एल (2015) ने पाया है कि निजीकरण का औसत प्रभाव खासतौर से सकारात्मक रहा है जो कि अनुमानतः लगभग 5-12% होता है लेकिन इनमें देश-दर-देश और समयावधि के साथ-साथ अंतर भी देखा गया है। इसका सकारात्मक प्रभाव फर्मों की बेहतर गुणवत्ता और समष्टिगत अर्थव्यवस्था और संस्थापरक परिवेश के रूप में भी देखा

गया है। छिब्वर और गुप्ता (2017) ने बताया है कि विनिवेश का श्रमिक उत्पादकता पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की सम्पूर्ण क्षमता भी बढ़ी है। ओ टूले एवं अन्य (2016) ने वियतनाम में किये अपने अध्ययन में यह पाया है कि निजीकरण किये जाने और साझेदारी से पूंजी के आवंटन में सुधार आया है और आर्थिक क्षमता भी बढ़ी है। चेन एवं अन्य (2008) ने बताया है कि चीनी कम्पनियों के कामकाज में, विशेषकर जब इनके नियंत्रण स्वामित्व का अंतरण हुआ था में खास सुधार देखा गया है जो कि मुख्य रूप से लागत में कमी किये जाने के कारण आयी थी लेकिन ऐसा तभी हुआ जब इनका नया मालिक कोई गैर सरकारी व्यक्ति था। सब्रमणियन, के. और मेगिनसन, डब्ल्यू (2018) ने पाया है कि सख्त रोजगार संरक्षण कानूनों (EPL) से निजीकरण नहीं हो पाता है और इसईपीएल का निजीकरण पर प्रभाव उद्योग के क्षेत्र में बहुत व्युत्क्रमानुपाती होता है जहां दरें जितनी ज्यादा होती हैं उत्पादन उतना ही कम होता है। मेगिनसन और नेट्टर (2001), बोर्डमेन और विनिंग (1989), ला पोर्टा और लोपेज डे सिलेंस (1999) ने पाया है कि निजीकरण के बाद के दौर में फर्मों को अधिक लाभ मिला है उनकी क्षमता भी बढ़ी है, सामान्य रूप से निवेश का स्तर बढ़ा है, परिणाम भी ज्यादा आये हैं, लाभांश भी ज्यादा मिले हैं और निजीकरण के बाद इसका लाभ भी कम लिया गया है। गुप्ता (2005) के अनुसार लाभ प्रदाता, श्रमिक उत्पादकता और निवेश खर्च के स्तर और वृद्धि दर दोनों में विशेष सुधार आया है जो कि आंशिक निजीकरण के कारण हुआ है। मजूमदार (1996) ने कहा है कि राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों की अपेक्षा यहां की कार्य क्षमता का स्तर काफी ऊंचा है जिससे यह प्रकट होता है कि इस क्षमता अभियान के दौरान केवल कमी आयी है ऐसा 1973-89 की अवधि के भारतीय फर्मों के अध्ययन से पता चलता है।

बोरीसोवा और मेगिनसन (2010) ने संकेत दिया है कि औसतन सभी फर्मों में सरकारी स्वामित्व में एक प्रतिशत की जो कमी आयी है उसका संबंध उस क्रेडिट के प्रसार से है जिसका प्रयोग ऋण पर आने वाले खर्च के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। यह संगणना तीन तिमाही को आधार मानकर की गयी है। स्प मज सं (2016) के अनुसार ऋणात्मक सूचीकरण प्रभाव के समायोजन के बाद नयी निजीकरण कम्पनियों के लाभ में खास वृद्धि (23 प्रतिशत पॉवरइन्टस) देखी गयी है। ट्रिपल डिफ्रेंस-इन-डिफ्रेंस परीक्षण के आधार पर भी पूंजीगत का संबंध कामकाज में महत्वपूर्ण और व्यापक सुधार से रहा है जो 7 वर्ष की अवधि (-3 से + वर्षों तक) में देखा गया है Oum at al (2006) के अनुसार इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि वे एयरपोर्ट्स जो कि ज्यादातर सरकारी स्वामित्व में हैं और बहुस्तरीय सरकारी स्वामित्व में हैं, कार्य क्षमता की दृष्टि से उन एयरपोर्ट्स से कम स्तर के हैं जो निजी स्वामित्व में काम कर रहे हैं। ग्राहकों की बढ़ती हुई संतुष्टि, टेरिफ में होने वाली कटौती, दूर संचार के क्षेत्र में डाटा के बढ़ते उपयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में फैलती बैंकिंग सेवाओं और रेलवे के ग्राहकों की अपेक्षा हवाई जहाज के भाड़े में की जाने वाली कटौती के रूप में होता है।

9.3 निजीकरण की लाभ क्षमता की जांच परख करने और यह देखने की भारतीय संदर्भ में निजीकरण के लाभ दिखाई भी दे रहे हैं, क्या नहीं, इस बात का विश्लेषण इस अध्याय में किया गया है। उन 11 सीपीएसई के कामकाज के देखते हुए किया गया

है जिनमें 1999-2000 से 2003-04 में विनिवेश किया गया था। वर्तमान विनिवेश अभियान के लिए ऐतिहासिक संदर्भ जुटाने के लिए नीचे बॉक्स 3 में भारत के विनिवेश नीति के प्रगति का मूल्यांकन किया गया है।

बाक्स 3 भारत की विनिवेश नीति का क्रमिक विकास

1991 में शुरू किये गये उदारीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के निजीकरण/निवेश की मांग बढ़ गयी है। प्रारम्भिक चरण में नीलामी के माध्यम से, सामूहिक रूप से छोटे-छोटे स्टेक की बिक्री करके किया गया था। इसके बाद आने वाले वर्षों में प्रत्येक कम्पनी की अलग-अलग बिक्री की गयी थी। यह प्रक्रिया 1999-2000 तक चली। भारत ने 1999-2000 में एक नीतिगत उपाय के तौर पर बिक्री की प्रक्रिया शुरू की जिसके अंतर्गत कुछ अभिज्ञात केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में सरकार के 50% या इससे अधिक की हिस्सेदारी का काफी हिस्से बेचा गया और साथ ही प्रबंधनपरक नियंत्रण का अंतरण किया गया। यह प्रक्रिया मॉडर्न फूड इन्डस्ट्रीज लि. (एमएफआईएल) में सरकार की हिस्सेदारी के 74% की बिक्री से शुरू की हुई थी। इसके पश्चात 12 सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों (जिनमें इन सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों के सहायक उपक्रम भी शामिल थे) और 17 होटल्स जो कि इण्डियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आईटीडीसी) की निजी क्षेत्र को बिक्री कर दी गयी थी और साथ ही में सरकार ने प्रबंधनपरक

नियंत्रण का भी अंतरण कर दिया था। इसके अलावा इंडो ब्राइट पेट्रोलियम (आईबीपी) में 33.58% की भागीदारी इण्डिया ऑयल कॉर्पोरेशन को कर दी गयी थी। हालांकि इस रणनीतिक बिक्री के बावजूद भी आईबीपी एक सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान बना रहा क्योंकि आईओसी ने अपनी पेट-इक्विटी 53.58 बनाए रखी। विनिवेश की नीति में दूसरा प्रमुख बदलाव 2004-05 में आया। जब यह निर्णय लिया गया था कि सरकार अपनी इक्विटी को तरल कर सकती है और अपने संशोधनों को बढ़ा सकती है जिससे कि जनता की सामाजिक जरूरतें पूरी की जा सकें। यह बात पहले की रणनीति बिक्री से स्पष्ट रूप से हटकर हुई है।

रणनीतिक बिक्री के कार्य में 2014 के बाद से नया मोड़ आया था। 2016-17 से 2018-19 के दौरान औसतन विनिवेश से प्राप्त होने वाली कुल राशि के लगभग 28.2% की बिक्री हुई थी। इस दिशा में विनिवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने मई, 2016 में एक व्यापक दिशा निर्देश तैयार किये हैं। जिन्हें "सीपीएसई की पूंजी पुर्नसंख्या" के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समाधान किये गये थे जैसे कि लाभांश का भुगतान, शेयरों की वापस खरीद, बोनस शेयर को जारी करना और शेयरों को अलग-अलग भागों में तोड़ना। सरकार ने निम्नलिखित तरीकों से सीपीएसई में विनिवेश सक्रिय नीति अपना रही है:

- i. अनुसूचित सीपीएसई में छोटी-माटी भागीदारी का विनिवेश जिससे कि 25% के न्यूनतम सार्वजनिक भागीदारी के मानक को प्राप्त किया जा सके।

सीपीएसई का विनिवेश करते समय सरकार मुख्य हिस्सेदारी अर्थात् 51% और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखेगी।

- ii. लोगों को स्वामित्व की सुविधा देने हेतु और उसके स्ट्रेकधारकों को जवाबदेगी के माध्यम से कंपनियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सीपीएसई को लिस्टिंग की गई है-57 पीएसयू को अब तक सूचीबद्ध किया जा चुका है जिनका कुल बाजार पूंजीकरण 13 लाख करोड़ से अधिक है।

- iii. स्ट्रेटिजिक विनिवेश;

- iv. बड़े पीएसयू द्वारा जिनके बहुत अधिशेष हैं, शेयरों का बायबैक;

- v. एक ही क्षेत्र में पीएसयू के बीच विलयन और अधिग्रहण;

- vi. एकसचेंज ट्रेडेडफंड (ईटीएफ) का आरंभ-एक इक्विटी इंस्ट्रुमेंट है जो एक विशेष इंडेक्स को ट्रैक करता है। सीपीएसई ईटीएफ भारत की मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे ओएनजीसी, आरईसी, कोल इंडिया, कंटेनर कॉर्प, ऑयल इंडिया, पावर फाइनेंस, गेल, बीईएल, ईआईएल, इंडियन ऑयल और बीईएल, ईआईएल, इंडियन ऑयल और एनटीपीसी में इक्विटी निवेशों से बना है; और

- vii. सीपीएसई की चयनित परिसंपत्तियों का मुद्राकरण किया जाए ताकि उनकी बैलेंस शीट को बेहतर किया जा सके। उन के ऋण को कम किया जा सके और उनके पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं के एक हिस्से का पूरा किया जा सके।

नीति आयोग ने स्ट्रेटिजिक विनिवेश हेतु पीएसयू की पहचान को अनिवार्य कर दिया है। इस उद्देश्य हेतु, नीति आयोग ने पीएसयू को "उच्च प्राथमिकता" और "निम्न प्राथमिकता" में वर्गीकृत किया है जोकि (क) राष्ट्रीय सुरक्षा (ख) कम से कम सरकारी हस्तक्षेप और (ग) बाजार अपूर्णता और लोक प्रयोजन के आधार पर किया गया है। त्वरित निर्णय लेने को सुकर बनाने, सीपीएसई के स्ट्रेटिजिक विनिवेश के सभी मामलों में निम्नलिखित पर निर्णय लेने की शक्तियां एक वैकल्पिक तंत्र को प्रत्यायोजित की गई हैं जहां आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल संबंधी (सीसीईए) ने स्ट्रेटिजिक विनिवेश के लिए सिद्धांततः अनुमोदन दिया गया है।

- (i) लेन-देन किए जाने वाले शेयरों की मात्रा, बिक्री का माध्यम और लेन-देन का अंतिम न्यूनन अथवा ऐसे मूल्य हेतु नियमों दिशानिर्देशों को रखना; और स्ट्रेटिजिक पार्टनर/खरीदार का चयन; बिक्रर के नियम एवं शर्तें; और

(ii) विनिवेश के कोर समूह (सीजीडी) के प्रस्तावों पर समय, मूल्य बिक्री के नियम एवं शर्तों और लेन-देन से संबंधित अन्य मुद्दों के संबंध में निर्णय लेना।

20 नवंबर, 2019 को सरकार ने घोषणा की कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल), भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एससोआई) और भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) और भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) के खरीदारों को पूर्ण प्रबंधन नियंत्रण सौंप दिया जाएगा। 8 जनवरी 2020 को मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमडीसी), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी), एमईसीओएन और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के लिए स्ट्रैटिजिक विनिवेश को मंजूरी दी गई।

निजीकरण का प्रभाव: फर्म स्तर का विश्लेषण

9.4 निजीकरण के पहले और बाद में चयनित सीपीआई पर स्ट्रैटिजिक विनिवेश/निजीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हमने 11 पीएसई का अध्ययन किया जिनका 199-2000 से 2003-2004 तक स्ट्रैटिजिक विनिवेश हुआ था जिनके संबंध में

निजीकरण के पहले और बाद में डाटा उपलब्ध है। डिफरेंस-इन-डिफरेंसिस पद्धति का प्रयोग करते हुए, सावधानी से तुलना करने हेतु, इन सीपीआई की उसी इंडस्ट्री समूह (तालिका 1) में उनकी समकक्ष कंपनियों के साथ तुलना की गई है। बॉक्स 4 में डिफरेंस-इन-डिफरेंसिस पद्धति का स्पष्टीकरण दिया गया है।

सारणी 1: चयनित सीपीएसई और समकक्ष कंपनियों की सूची

उद्योग समूह	निजीकृत सीपीएसई	समकक्ष कंपनी
धातु-अलॉय	हिन्दुस्तान जिंक	टिनप्लेट का. ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान कॉपर, वेदांता
अल्युमीनियम एवं अल्युमीनियम उत्पाद	भारत अल्युमीनियम कंपनी लि. (बीएलसीओ)	नालको, हिंडालको, पीजी फॉइलस
कम्प्यूटर, पेरिफेरल्स एवं एटोरेज डिवाइस	कंप्यूटर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लि. (सीएमसी)	मोसरबेयर, जेनिथ कम्प्यूटर्स, इजमो लिमिटेड
ऑटोमोबाइल	मारुति सुजुकी	अशोक लेलैंड लि., टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लि.
पेट्रोकेमिकल्स	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि. (आईपीसीएल)	केमप्लास्ट सन्मार, भंसाली इंजिनियरिंग पॉलीमर्स, इनियोस स्टायशैन्यूशन इंडिया लि.
दूर संचार सेवाएं	दूर संचार सेवाएं	टाटा टेलिसर्विसेस, एनटीएनएल, जीटीएस इफ्रा
हेवी इंजिनियरिंग	लगान इंजिनियरिंग	गुजरात टूलरूम, गुजरात टेक्सट्राॉनिक्स, इंडिया इंजिनियरिंग इंडिया लि.

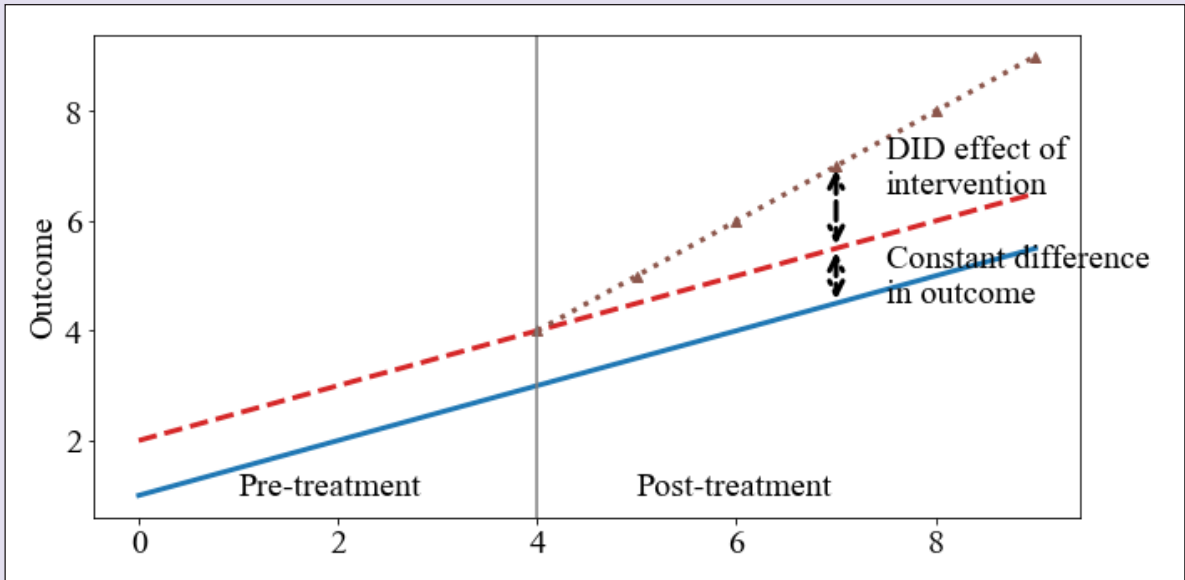
² वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक कर अवधि में निजीकरण की जाने वाली 30 सी.पी.एस.ई. में से 18 एंटरप्राइज भारतीय पर्यटन विकास निगम लि. की सब्सिडी एंटरप्राइज थीं और एक एंटरप्राइज होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एच.सी.आई) की सब्सिडी थी। हमारे विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, हमें प्रत्येक विनिवेशित कंपनी की निजीकरण पूर्व और पश्चात् 10 वर्ष की अवधि के सभी वित्तीय कार्यानिष्पादन सूचकों की सूचना की आवश्यकता थी। तथापि आई.टी.डी.सी. की 18 तथा एच.सी.आई. की एक एंटरप्राइज के विनिवेशित सब्सिडियों के मामले में वित्तीय विवरण को 'मूल कंपनी' के समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित कर दिया गया था। विनिवेश के पश्चात् इन सब्सिडियों को क्रेता कंपनियों के साथ जोड़ दिया गया था और वित्तीय विवरण को फिर से 'नई मूल कंपनी' के समेकित विवरण प्रस्तुत किया गया था। इस समस्या के कारण इन सब्सिडी एंटरप्राइज को हमारे विश्लेषण में सम्मिलित नहीं किया जा सका। इंडोब्रिटिश पेट्रोलियम (आई.बी.पी.) प्राइवेट लि. का विलय इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओ.सी.) के साथ किया गया था जोकि एक सरकारी उद्यम है और इसलिए विश्लेषण में इस पर विचार नहीं किया गया।

मीडियम एवं लाइट इंजिनियरिंग	जेसोप एंड कॉ.	इलिंग अल्ट्रा, दिसा इंडिया, अल्फा लवल, किल्ट्रॉन इंजिनियर्स
बेकरी उत्पाद	माडर्न फूड इंडिया लि.	ब्रिटानिया
वायर्स एच केबल्स	हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स (एचटीएल)	अनामिका कंडक्टर्स, डेल्टन केबल्स, फॉर्ट गल्लेस्टर लि.
केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	पारादीप फोस्फेट्स	जीएसएफसी, फर्टिलाइजर्स एंड कमिकल्स-त्रावणकोर, गोदावरी के मिक्ल्स एंड फार्टिलाइजर्स
कुल	11	32

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

बाक्स 4 डिफरेंस-इन-डिफरेंस पद्धति

डिफरेंस-इन-डिफरेंस (डीआईडी) एक सांख्यिकीय तकनीक है जिसका प्रयोग विशिष्ट हस्तक्षेप अथवा व्यवहार (जैसे कि कानून का परित्र होना, नीति का अधिनियमन, अथवा बडे पैमाने पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन) कर आकलन करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक एक जनसंख्या जोकि विशिष्ट हस्तक्षेप (एक व्यवहार समूह) द्वारा प्रभावित हैं एवं एक जनसंख्या जोकि (एक नियंत्रण समूह) नहीं है, के मध्य समयावधि के दौरान परिणामों में परिवर्तनों की तुलना करती है। डीआईडी का उपयोग आमतौर पर किसी हस्ताक्षेप के अनुमानित प्रभाव को प्रभावित करने वाले किसी भी बाहरी कारकों की संभावना को कम करने के लिए किया जाता है।

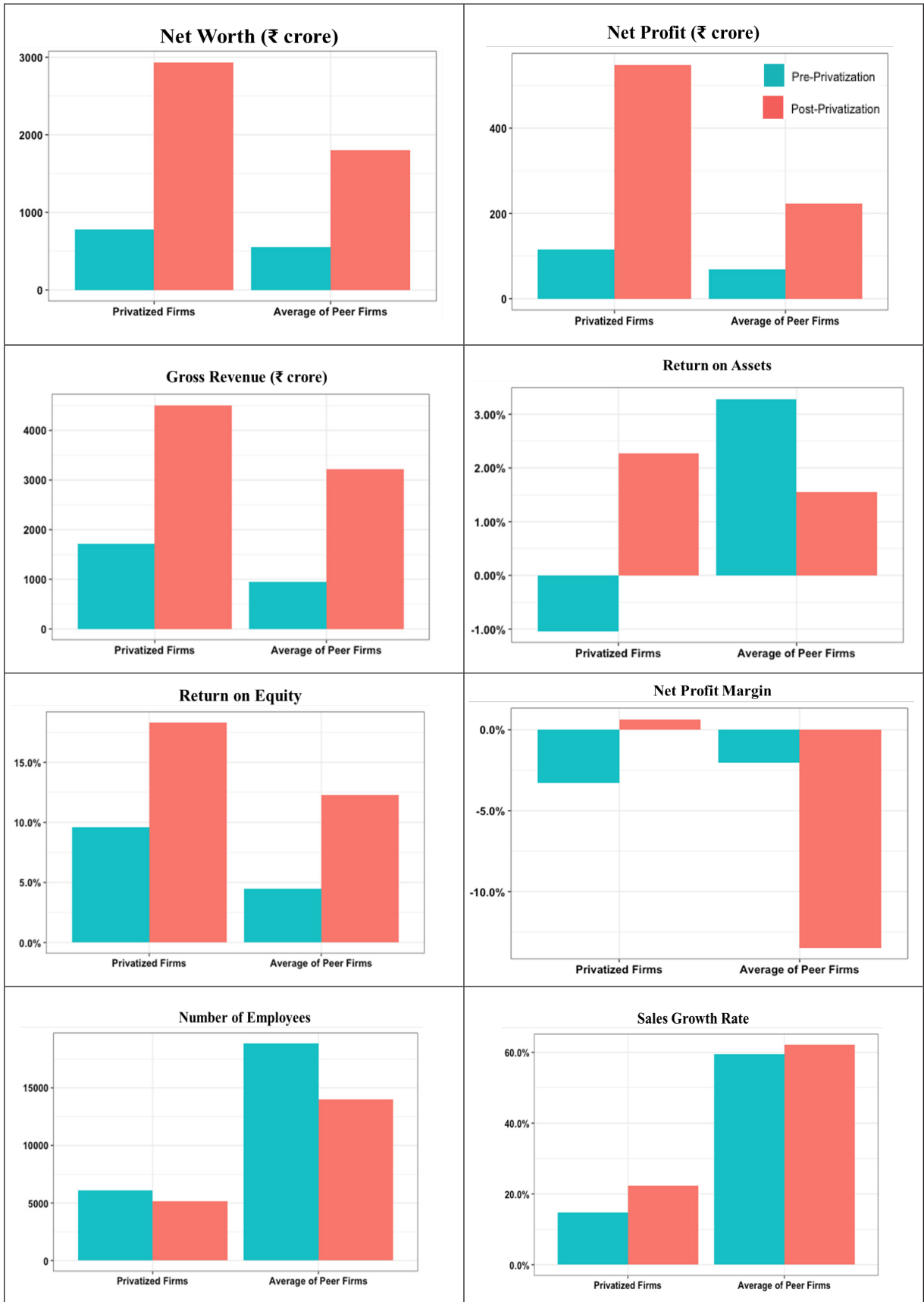


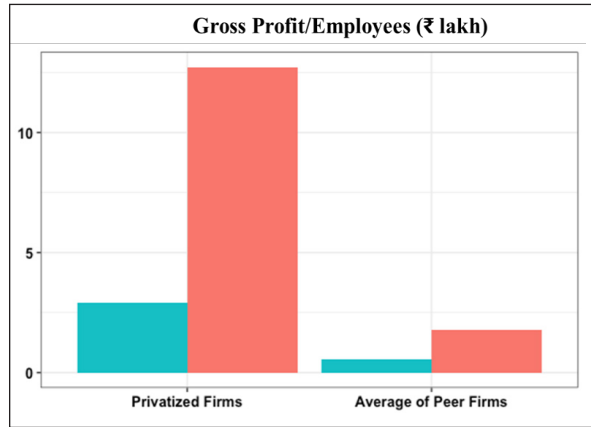
9.5 आकृति 2 विशिष्ट सीपीएसई के निजीकरण के वर्ष के पहले और बाद के दस वर्षों के लिए विभिन्न वित्तीय संकेतकों का प्रयोग करते हुए उनकी समकक्ष कंपनियों से तुलना करते हुए उनकी समकक्ष कंपनियों से तुलना करते हुए उनकी समकक्ष कंपनियों से तुलना करते हुए इन सीपीएसई का औसत कार्य-निष्पादन दर्शाती है। आकृति 2 से यह स्पष्ट है कि निजीकृत फर्मों के कार्य-निष्पादन में निजीकरण के

बाद उसी अवधि के दौरान समकक्ष फर्मों के कार्य निष्पादन में अंतर का प्रयोग करते हुए भ्रमित करने वाले अन्य कारकों को नियंत्रित करने के बाद काफी सुधार आया है। चित्र 2 से यह स्पष्ट होता है कि निजी फर्मों के निष्पादन में उसी समय में सहयोगी फर्मों के निष्पादन के अंतर में अन्य उलझाने वाले कारकों को नियंत्रण करने के बाद निजीकरण को अपनाते हुए उल्लेखनीय सुधार हुआ।

³ डाटा सीमाओं को मानते हुए एमएफआईएल और आईपीसीएल को उनके विनिवेश के पश्चात 10 वर्षों से कम समय तक लिया गया है।

चित्र 2: निजी फर्मों के साथ-साथ सहयोगियों के वित्तीय संकेतकों का तुलनात्मक





स्रोत: सीएमआईसी कौशल पर आधारित सर्वे गणना

9.6 अब हम प्रत्येक मीट्रिक की भिन्नताओं का विस्तार में व्याख्या करेंगे।

i) कुल मूल्य: कंपनी का कुल मूल्य उसकी इक्विटी शेयरहोल्डर है। इसमें शेचयरहोल्डरों द्वारा किया गया पूंजी भंडारणों के रूप में, सृजित लाभ के कंपनी के औसतन

निजी फर्मों में निजीकरण से पूर्व 700 करोड़ से बढ़कर निजीकरण के बाद 2992 करोड़ वृद्धि हुई, वित्तीय स्वास्थ्य बढ़कर महत्वपूर्ण सुधार हुआ और शेयरहोल्डरों के लिए धन संपत्ति सृजन में वृद्धि हुई (तालिका 2) *निजीकरण के कारण अंतर में अंतर विश्लेषण का आकलन में 803.3 करोड़ रु. की वृद्धि हुई।

तालिका 2: कुल मूल्य (करोड़ रु. में)

निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	656.25	1921.60	1265.35
2 सीएमसी	35.28	275.41	240.13
3 मारुति	1426.02	8191.98	6765.96
4 जेसोप	-212.07	77.19	289.26
5 लगान इंजीनियरिंग	5.15	6.30	1.15
6 आईपीसीएल	2258.52	3106.69	848.17
7 एचटीएल	33.35	-145.98	-179.33
8 हिंदुस्तान जिंक	818.06	12874.57	12056.51
9 मॉडल फूड इंडिया	10.63	-79.34	-89.97
10 पारादीप फासफेट	-3.98	214.12	218.1
11 टाटा कम्यूनिकेशंस	2683.82	6468.49	3784.67
12 सभी निजी फर्मों का संयुक्त औसत	701.00	2991.91	2290.91
13 सहयोगी फर्मों का संयुक्त औसत	551.61	1802.14	1250.53
14 निजी फर्म घटा कर सहयोगी फर्म	149.39	1189.77	DiD = 1040.38

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

ii) कुल लाभ: यह कंपनी का कर के बाद का कुल लाभ है। सभी प्रचालन खर्चों को मिलाने के बाद कंपनी को कुल लाभ में वृद्धि कंपनी की बहुत अधिक वसूली को दर्शाता है। सहयोगी कंपनियों की तुलना में औसतन

निजी फर्मों का कुल लाभ निजीकरण से पहले 100 करोड़ रु. से बढ़कर निजीकरण के बाद 555 हो गया (तालिका 3 निम्नलिखित। निजीकरण के कारण अंतर में अंतर विश्लेषण आकलन में 244.3 करोड़ की वृद्धि हुई।

तालिका 3: कुल लाभ (करोड़ रु. में)

निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	45.47	348.94	303.47
2 सीएमसी	6.77	73.22	66.45
3 मारुति	205.28	1321.99	1116.71
4 जेसोप	-36.44	7.87	44.31
5 लगान इंजीनियरिंग	-0.49	0.18	0.67
6 आईपीसीएल	238.48	606.42	367.94
7 एचटीएल	3.16	-43.84	-47
8 हिंदुस्तान जिंक	72.47	3237.04	3164.57
9 मॉडल फूड इंडिया	-1.2	-18.4	-17.2
10 पारादीप फास्फेट	-53.93	114.83	168.76
11 टाटा कम्यूनिकेशंस	620.34	452.25	-168.09
12 सभी निजीकृत फर्मों का संयुक्त औसत	100	554.6	454.6
13 समकक्ष फर्मों का संयुक्त औसत	68.51	222.84	154.33
14 निजीकृत फर्मों में से समकक्ष फर्मों को घटाकर	31.49	331.76	DiD=300.27

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

iii) सकल राजस्व: औसतन, निजीकृत फर्मों का सकल राजस्व, जो निजीकरण से पहले 1560 करोड़ रूपये था निजीकरण के बाद बढ़कर 4653 करोड़ रूपये हो गया। निजीकरण के बाद, माल की बिक्री और अन्य गैर-वित्तीय गतिविधियों से आय में वृद्धि का संकेत मिला (तालिका 4)। डीआईडी विश्लेषण, निजीकरण को सकल राजस्व में 827.65 करोड़ रूपये की वृद्धि का श्रेय देता है।

iv) आस्तियों पर लाभ (आरओए): आरओए, प्रतिशत के रूप में व्यक्त की गई कंपनी की कुल औसत संपत्ति

पर करों के अधिरोपण (पीएटी) के बाद मुनाफे की दर को अभिग्रहण करता है। निजीकृत फर्मों के लिए औसतन, आरओए (-) 1.04 प्रतिशत से बढ़कर 2.27 प्रतिशत हो गया है, जो कि पीयर फर्मों से भी अधिक है, जो यह इंगित करता है कि निजीकृत फर्म अपने संसाधनों का अधिक उत्पादक ढंग से उपयोग करने में सक्षम हैं (तालिका 5)। डीआईडी विश्लेषण, आरओए में 5.04 प्रतिशत की वृद्धि का श्रेय निजीकरण को देता है।

तालिका 4: कुल राजस्व (करोड़ रु. में)

निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	747.84	2858.48	2110.64
2 सीएमसी	261.55	792.88	531.33
3 मारुति	6013.28	22958.8	16945.52
4 जेसोप	79.76	178.33	98.57
5 लगान इंजीनियरिंग	6.52	12.87	6.35
6 आईपीसीएल	3791.56	9341.25	5549.69
7 एचटीएल	141.21	126.89	-14.32
8 हिंदुस्तान जिंक	999.16	7923.77	6924.61
9 मॉडल फूड इंडिया	77.21	192.6	115.39
10 पारादीप फास्फेट	824.52	2692.56	1868.04
11 टाटा कम्यूनिकेशंस	4219.51	4106.69	-112.82
12 सभी निजीकृत फर्मों का संयुक्त औसत	1560.19	4653.19	3093
13 समकक्ष फर्मों का संयुक्त औसत	945.42	3210.77	2265.35
14 निजीकृत फर्मों में से समकक्ष फर्मों को घटाकर	614.77	1442.42	DiD=827.65

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

तालिका 5: परिसंपत्तियों की वसूली (प्रतिशत)

निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	4.62	6.84	2.22
2 सीएमसी	-0.89	8.7	9.59
3 मारुति	8.24	10.29	2.05
4 जेसोप	-35.95	4.34	40.29
5 लगान इंजीनियरिंग	-2.19	0.78	2.97
6 आईपीसीएल	4.34	6.74	2.4
7 एचटीएल	-3.12	-24.17	-21.05
8 हिंदुस्तान जिंक	5.29	26.7	21.41
9 मॉडल फूड इंडिया	3.35	-39.5	-42.85
10 पारादीप फास्फेट	-8.78	2.57	11.35

11 टाटा कम्यूनिकेशंस	13.4	4.03	-9.37
12 सभी निजीकृत फर्मों का संयुक्त औसत	-1.04	2.27	3.31
13 समकक्ष फर्मों का संयुक्त औसत	3.28	1.55	-1.73
14 निजीकृत फर्मों में से समकक्ष फर्मों को घटाकर	-4.32	0.72	DiD=5.04

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

v) इक्विटी पर रिटर्न (आरओई): इक्विटी पर रिटर्न औसत निवल मूल्य के रूप में कर पश्चात् प्राप्त लाभ (पीएटी) है। औसतन, निजीकृत फर्मों का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) निजीकरण से पूर्व 9.6 प्रतिशत था जो निजीकरण के पश्चात् बढ़कर 18.3 प्रतिशत हो गया,

जिससे शेयरधारकों की इक्विटी की प्रत्येक इकाई से लाभ कमाने की फर्म की क्षमता को पता चलता है। औसत सहकर्मी समूह के संबंध में निजीकरणपूर्व की प्रत्येक अवधि के लिए आरओई में वृद्धि 7.8 प्रतिशत थी (तालिका 61)। डीआईडी विश्लेषण में आरओई में 0.89 की वृद्धि का श्रेय निजीकरण को दिया गया है।

तालिका 6: इक्विटी पर रिटर्न (प्रतिशत)

निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	6.1	16.9	10.8
2 सीएमसी	11.2	26.6	15.4
3 मारुति	19	16.6	-2.4
4 जेसोप	5	12.9	7.9
5 लगान इंजीनियरिंग	-4.5	1.4	5.9
6 आईपीसीएल	11.2	17.9	6.7
7 एचटीएल	9.8	2.3	-7.5
8 हिंदुस्तान जिंक	9.2	28.8	19.6
9 मॉडल फूड इंडिया	11.4	27.8	16.4
10 पारादीप फास्फेट	3.5	-0.1	-3.6
11 टाटा कम्यूनिकेशंस	-44.8	7.3	52.1
12 सभी निजीकृत फर्मों का संयुक्त औसत	9.6	18.3	8.7
13 समकक्ष फर्मों का संयुक्त औसत	4.5	12.31	7.81
14 निजीकृत फर्मों में से समकक्ष फर्मों को घटाकर	5.1	5.99	DiD=0.89

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

vi) *निवल लाभ मार्जिन (गुंजाइश)*: किसी कंपनी का निवल लाभ मार्जिन उसकी कुल आय का करोत्तर प्रतिशत होता है। औसतन, निजीकृत फर्मों के निवल लाभ मार्जिन में वृद्धि हुई है, निजीकरण से पूर्व यह मार्जिन (गुंजाइश)-3.24: था और निजीकरण के पश्चात् यह 0.65: हो गया है जो प्रतिबिम्बित करता है कि आय के रूप में सृजित होने वाले रुपये के करोत्तर

लाभ के अंश में वृद्धि हुई है। समकक्ष कंपनियों के समूहों के निवल लाभ मार्जिन, निजीकरण पूर्व अवधि की तुलना में निजीकरणोत्तर अवधि में -2.03 प्रतिशत से घटकर -13.47 हो गए हैं। (तालिका 7)। डिफ्रेंस इन डिफ्रेंस विश्लेषण से पता चलता है कि निजीकरण के कारण निवल लाभ मार्जिन में 15.26: की वृद्धि हुई है।

तालिका 7: निवल लाभ मार्जिन (प्रतिशत)

निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	5.8	10.1	4.3
2 सीएमसी	1.9	9.1	7.2
3 मारुति	6.5	34.3	27.8
4 जेसोप	2.9	-66.9	-69.8
5 लगान इंजीनियरिंग	6.7	5.9	-0.8
6 आईपीसीएल	-65	5.8	70.8
7 एचटीएल	-3.1	-0.2	2.9
8 हिंदुस्तान जिंक	3.7	5.9	2.2
9 मॉडल फूड इंडिया	-2.1	-9.8	-7.7
10 पारादीप फास्फेट	-6.6	1.8	8.4
11 टाटा कम्यूनिकेशंस	13.7	11.1	-2.6
12 सभी निजीकृत फर्मों का संयुक्त औसत	-3.24	0.65	3.89
13 समकक्ष फर्मों का संयुक्त औसत	-2.03	-13.4	-11.37
14 निजीकृत फर्मों में से समकक्ष फर्मों को घटाकर	-1.21	14.05	DiD= 15.26

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

vii) *विक्रय वृद्धि*: औसतन, निजीकृत फर्मों के विक्रय वृद्धि दर पूर्व निजीकरण अवधि की तुलना में निजीकरण पश्चात् अवधि में 14.7 प्रतिशत से बढ़कर 22.3 प्रतिशत हो चुकी है। (तालिका 8) डिफ्रेंस-इन-डिफ्रेंस विश्लेषण से पता चलता है कि निजीकरण किए जाने के कारण विक्रय वृद्धि में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

viii) *प्रति कर्मचारी सकल लाभ*: चित्र 2 में दिखाया गया है कि औसतन, फर्मों के दोनों समूहों में, कर्मचारियों

की संख्या में कमी हुई है, किंतु समकक्ष फर्मों की तुलना में अन्य फर्मों में, इस कमी का परिमाण कुछ कम है। प्रति कर्मचारी सकल लाभ का आकलन चयनित 11 सीपीएसई फर्मों में से केवल 8 फर्मों का किया गया है, क्योंकि इनका डाटा ही उपलब्ध था। डिफ्रेंस इन डिफ्रेंस विश्लेषण से पता चलता है कि निजीकरण के कारण प्रतिकर्मचारी 21.34 लाख रुपये की वृद्धि सकल लाभ में हुई है। (तालिका 9)

तालिका 8: विक्रय वृद्धि वर्ष दर वर्ष (प्रतिशत में)

निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	7.87	22.25	14.38
2 सीएमसी	20.19	4.66	-15.53
3 मारुति	20.26	16.18	-4.08
4 जेसोप	-2.45	17.26	19.71
5 लगान इंजीनियरिंग	0.22	17.05	16.83
6 आईपीसीएल	14.33	23.90	9.58
7 एचटीएल	19.29	82.10	62.81
8 हिंदुस्तान जिंक	10.44	28.34	17.90
9 मॉडल फूड इंडिया	18.36	4.02	-14.34
10 पारादीप फास्फेट	6.41	32.39	25.99
11 टाटा कम्प्यूनिक्शंस	46.58	-2.94	-49.52
12 सभी निजीकृत फर्मों का संयुक्त औसत	14.68	22.29	7.61
13 समकक्ष फर्मों का संयुक्त औसत	59.37	62.09	2.72
14 निजीकृत फर्मों में से समकक्ष फर्मों को घटाकर	-44.69	-39.80	DiD = 4.89

तालिका 9: सकल लाभ/कर्मचारी (लाख रूपये में)

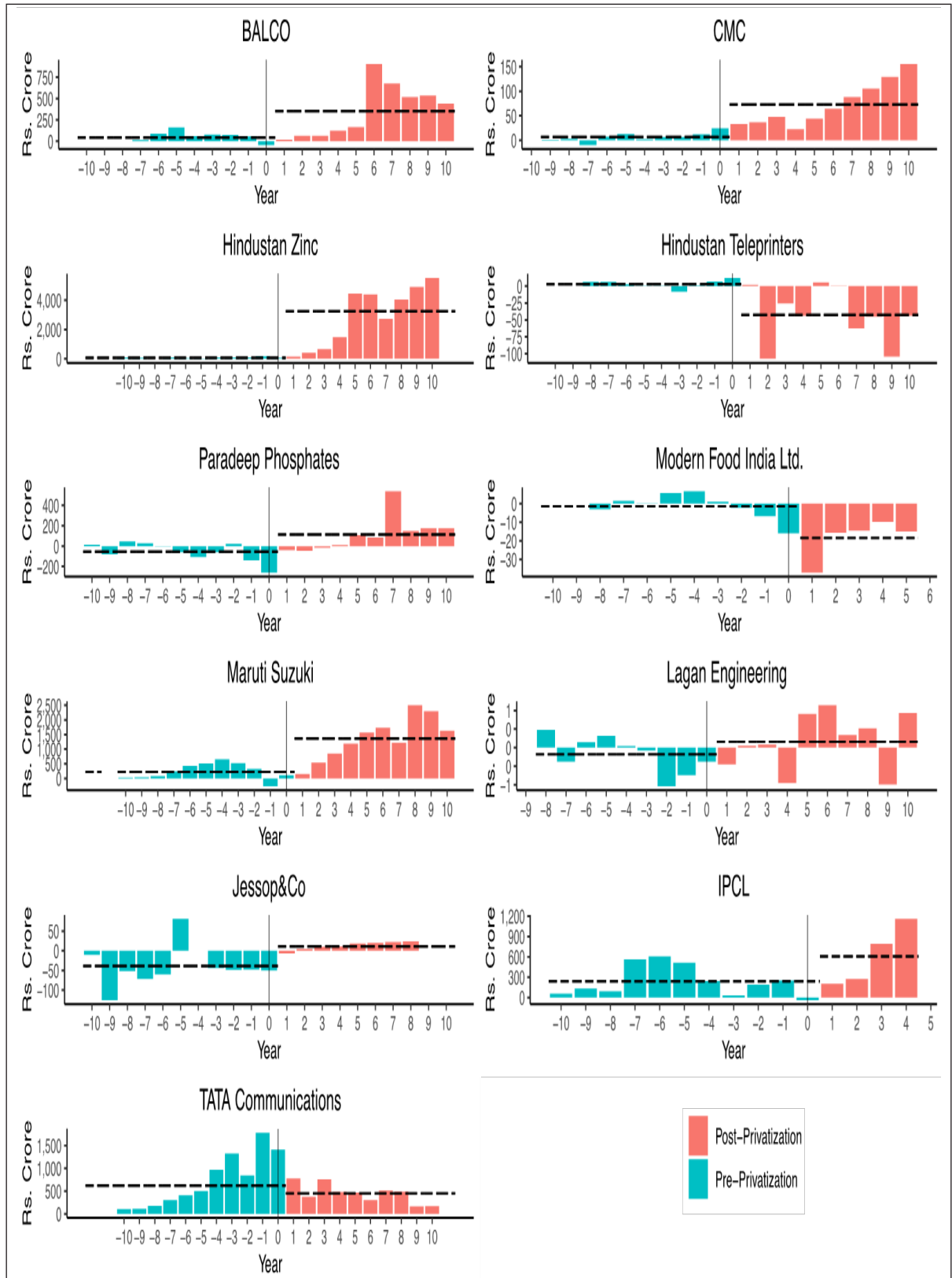
निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	0.46	10.87	10.42
2 सीएमसी	0.17	1.49	1.32
3 मारुति	4.75	21.01	16.26
4 जेसोप	-1.06	0.77	1.82
5 आईपीसीएल	1.89	4.14	2.26
6 हिंदुस्तान जिंक	0.26	166.66	166.40
7 पारादीप फास्फेट	-6.02	-14.96	-8.94
8 टाटा कम्प्यूनिक्शंस	22.28	13.42	-8.85
9 सभी निजीकृत फर्मों का संयुक्त औसत	2.84	25.43	22.58
10 समकक्ष फर्मों का संयुक्त औसत	0.54	1.78	1.24
11 निजीकृत फर्मों में से समकक्ष फर्मों को घटाकर	2.30	23.65	DiD = 21.34

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

9.7 सर्वेक्षण में प्रत्येक व्यक्तिगत सीपीएसई के निष्पादन में बदलाव का जांच करेगा। चित्र 3 से 10 में दस वर्ष के पहले प्रमुख फर्म और रणनीतिक विनिवेश/निजीकरण के बाद मुख्य वित्तीय संकेतकों से होने वाले संचलन को दर्शाता हैं। व्यक्तिगत रूप से, प्रत्येक निजीकृत सीपीएसई

ने कुल कीमत, निवल लाभ, सकल राजस्व, निवल राजस्व अन्तर निजीकरण के बाद की अवधि बनाम निजीकरण से पहले की अवधि में बिक्री वृद्धि को दर्शाता है (हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर, एम एफ आई एल और कुछ संकेतकों के मामले में घटा कम्प्युनिकेशन के सिवाय)

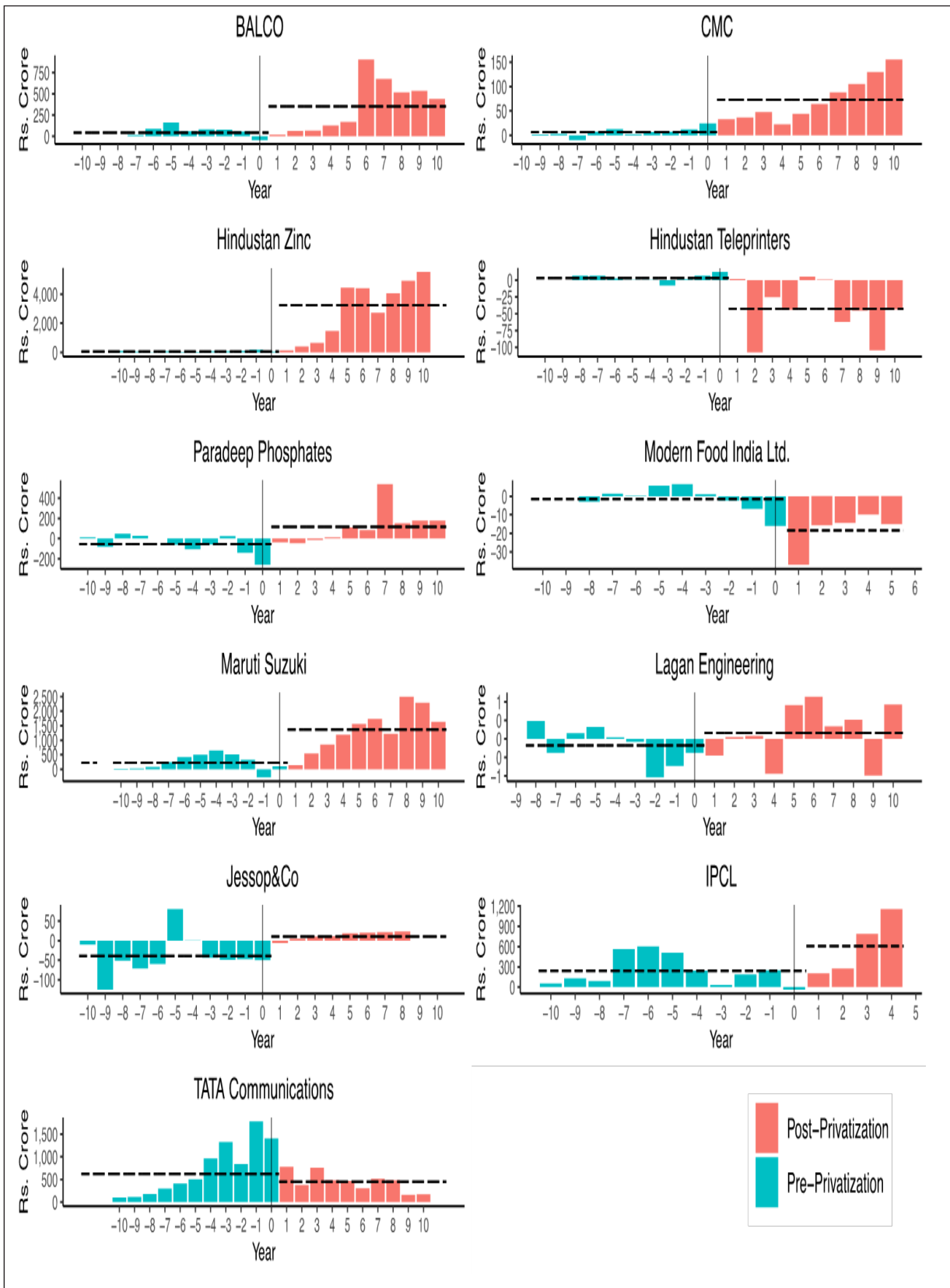
चित्र 3: निजी फर्मों का कुल मूल्य (पूर्व एवं पश्चात निजीकरण)



स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

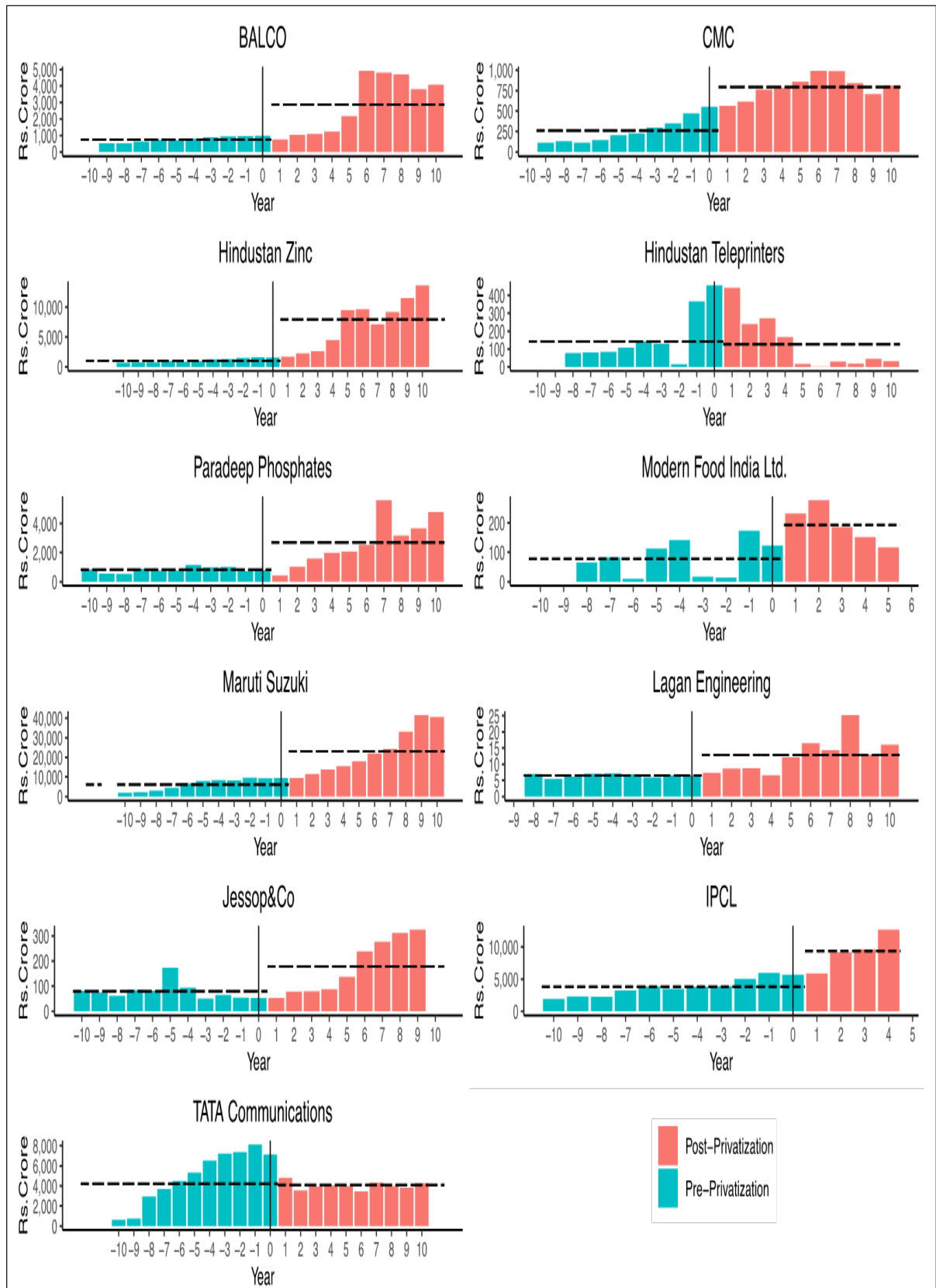
चित्र 4: निजी फर्मों का कुल लाभ (पूर्व एवं पश्चात निजीकरण)



स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

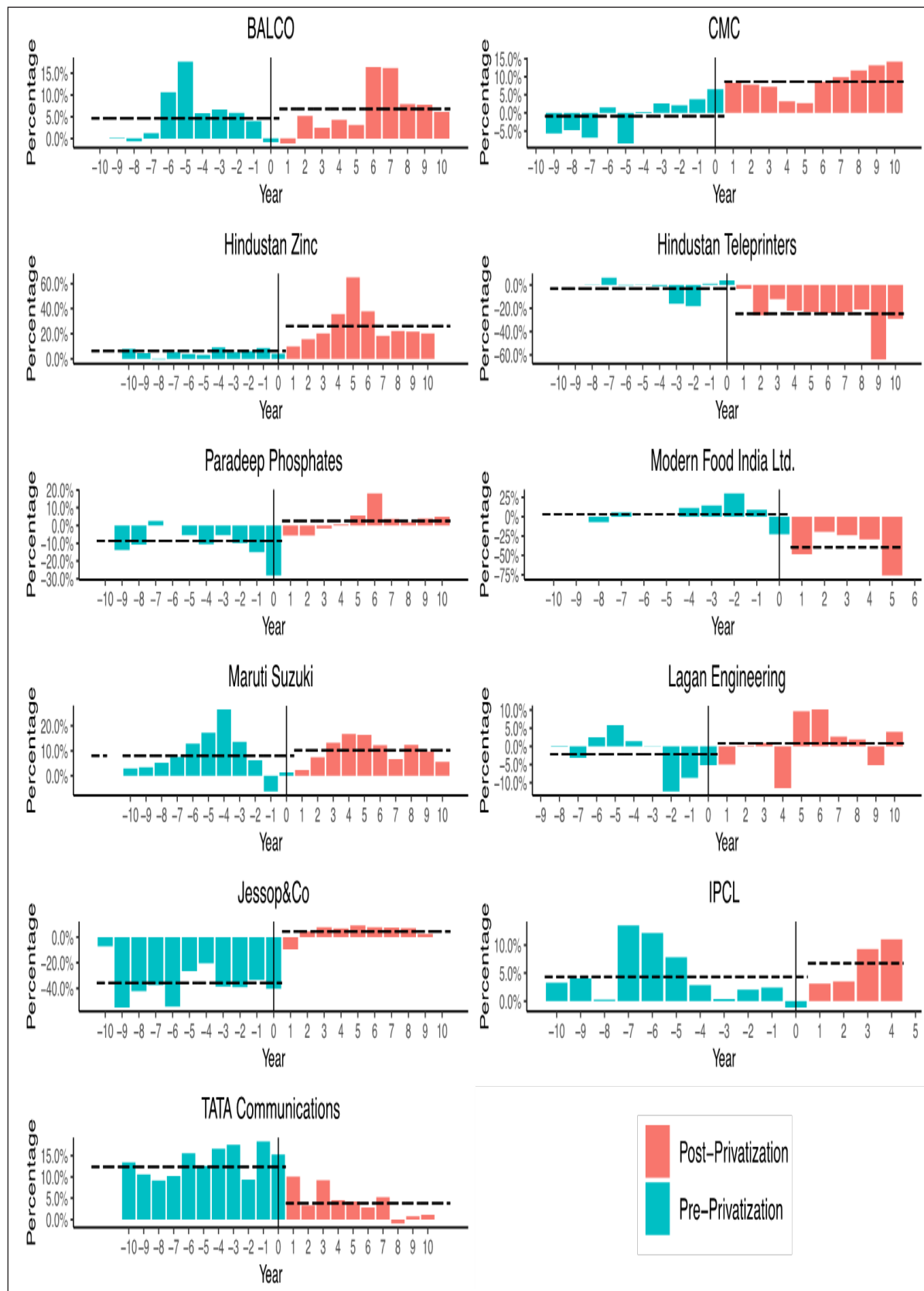
चित्र 5: निजी फर्मों का कुल राजस्व (पूर्व एवं पश्चात निजीकरण)



स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

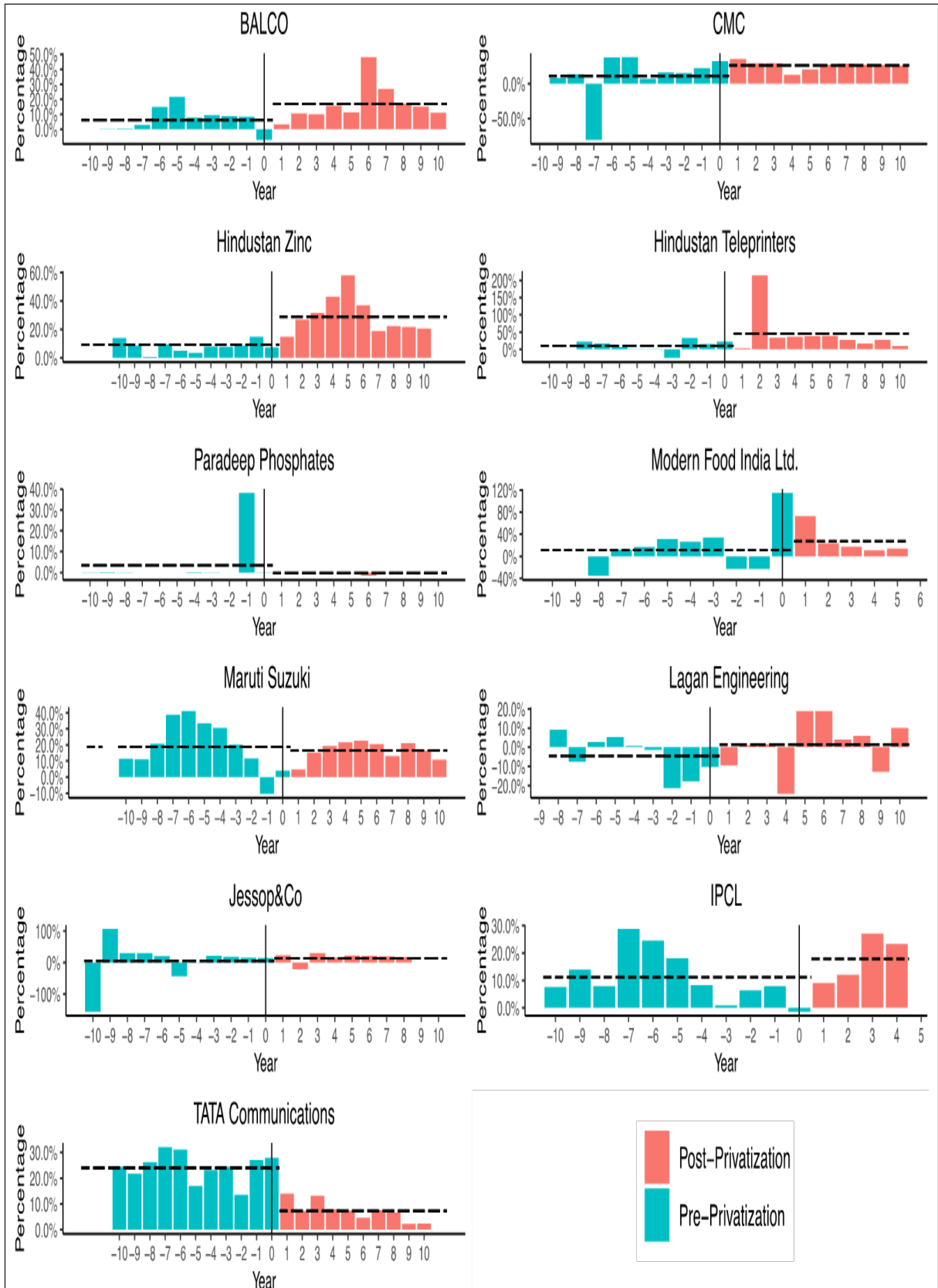
चित्र 6: निजी फर्मों के परिसंपत्तियों की वसूली (आरओए) (पूर्व एवं पश्चात निजीकरण)



स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

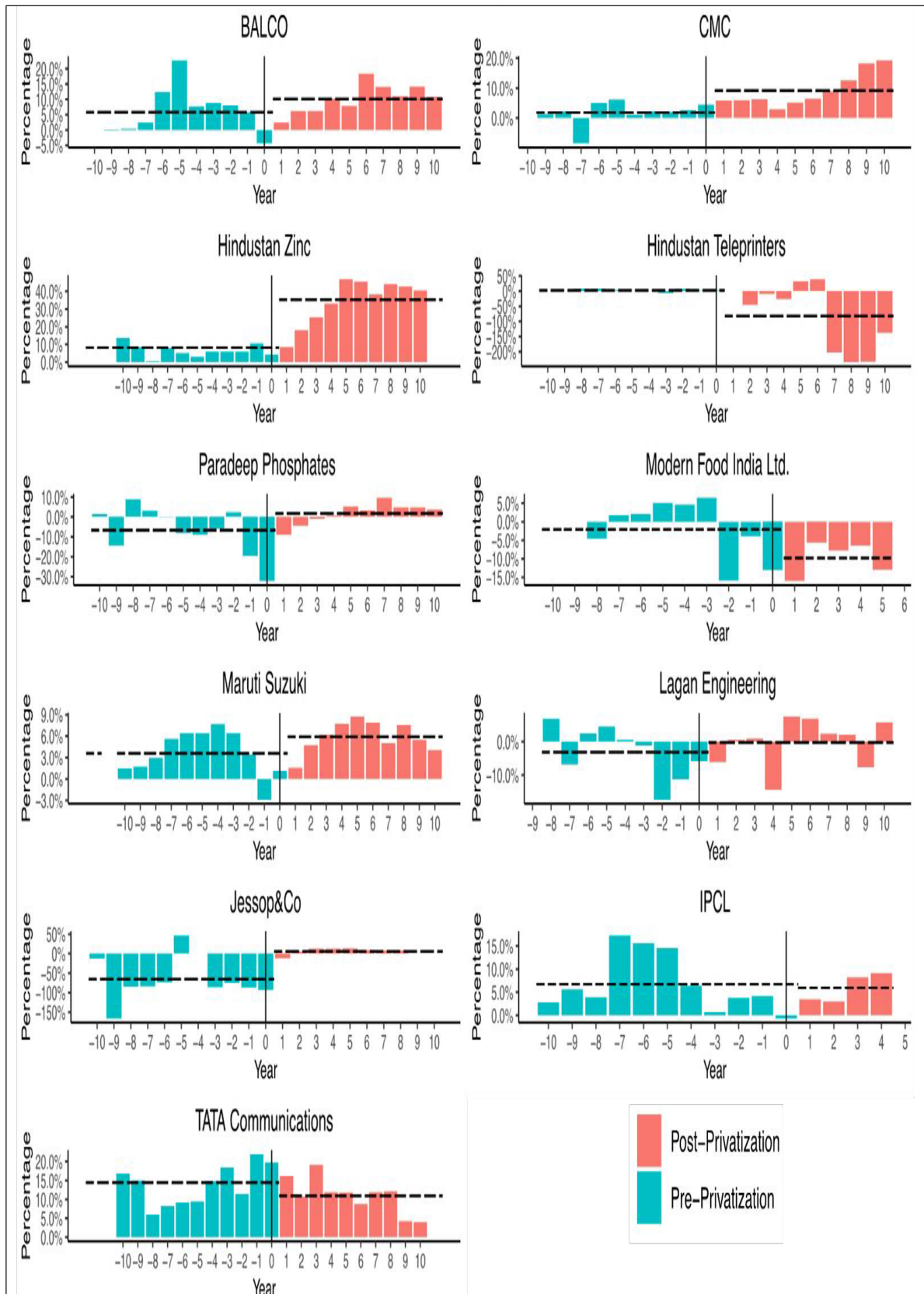
चित्र 7: निजी फर्मों के इक्विटी पर वसूली (पूर्व एवं पश्चात निजीकरण)



स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

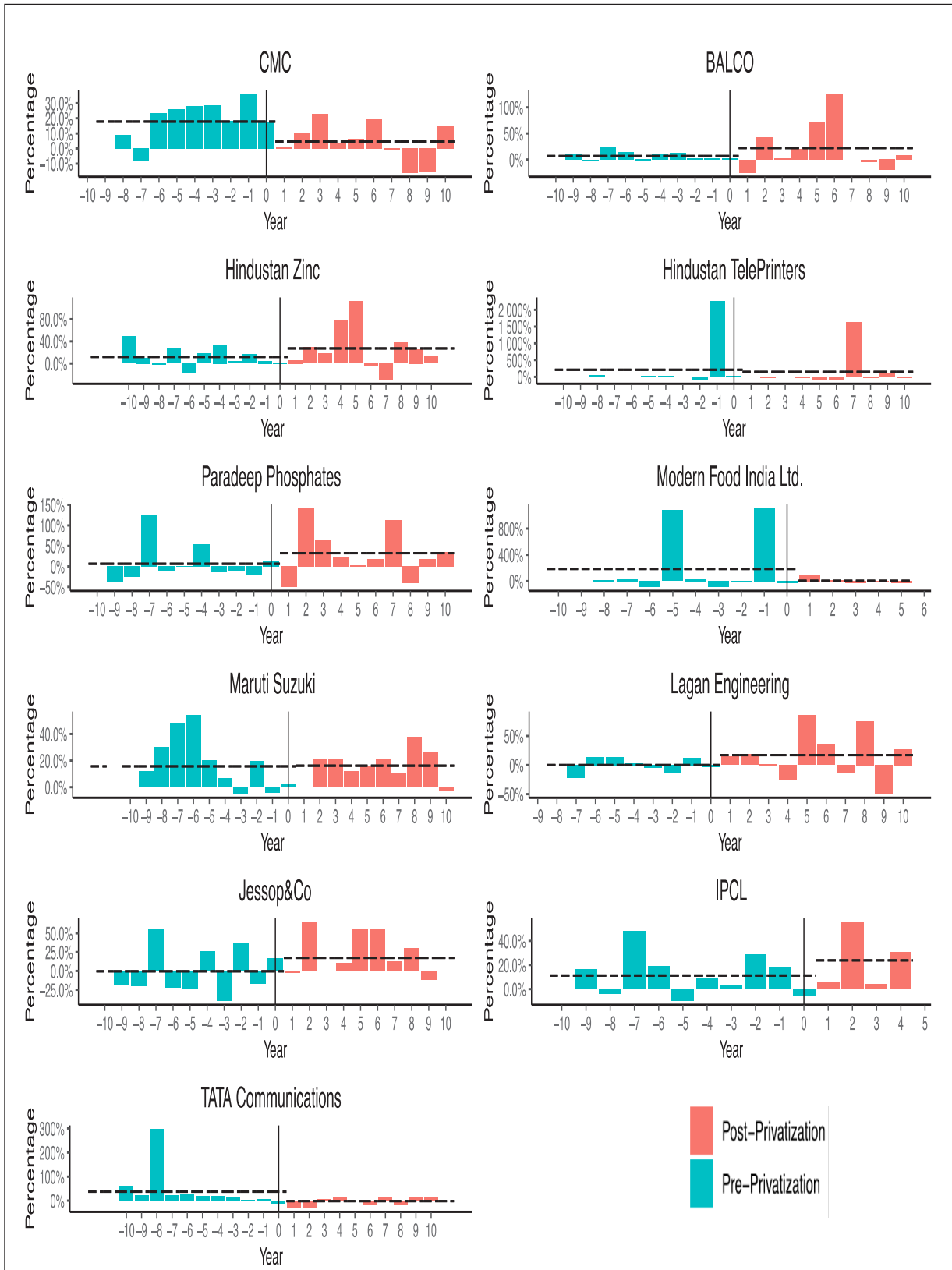
चित्र 8: निजी फर्मों का कुल लाभ मार्जिन (पूर्व पश्चात निजीकरण)



स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

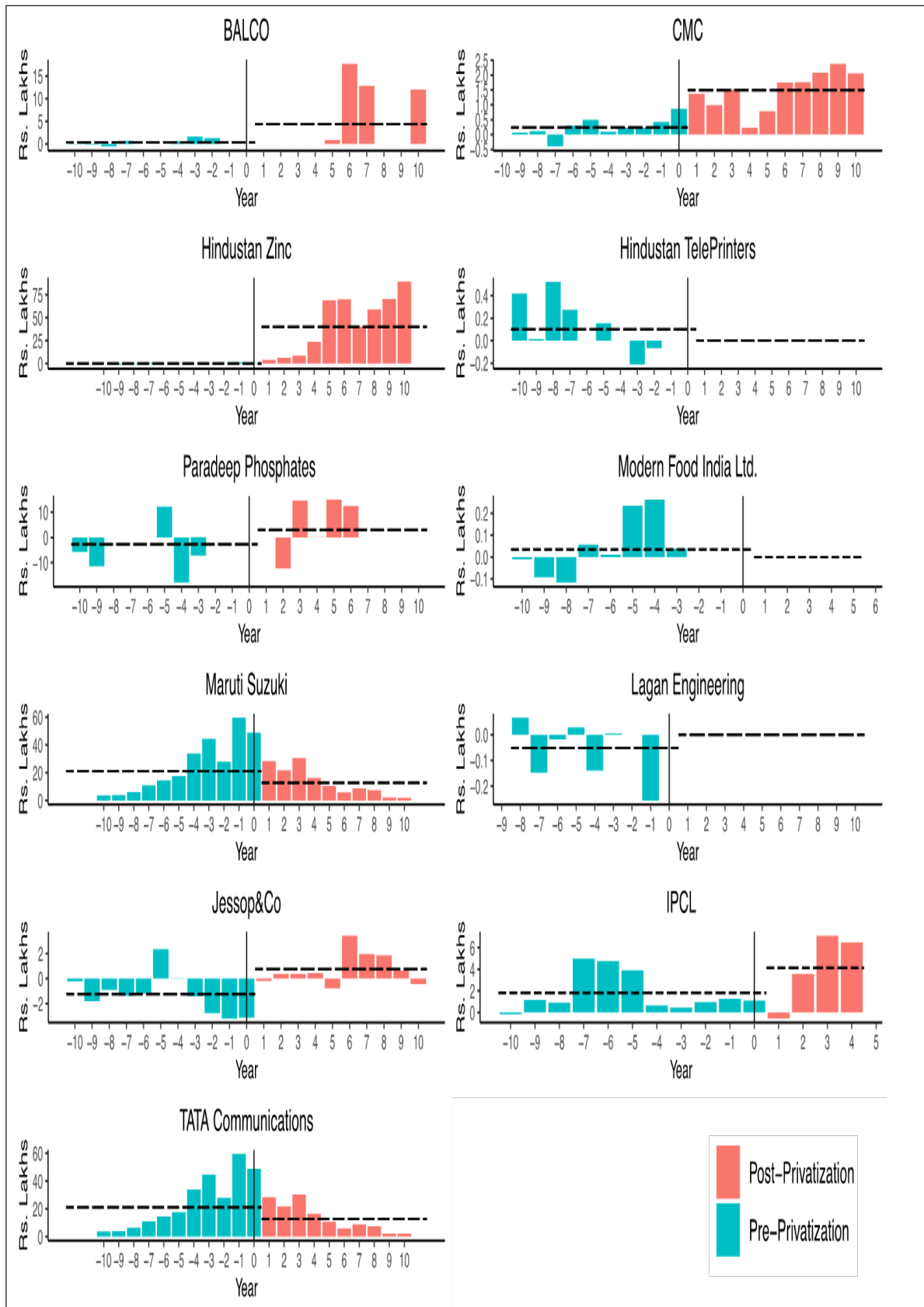
चित्र 9: निजी फर्मों का बिक्री ग्रोथ रेट (पूर्व एवं पश्चात निजीकरण)



स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

चित्र 10: निजी फर्मों के प्रति कर्मचारी का सकल लाभ (पूर्व एवं पश्चात निजीकरण)



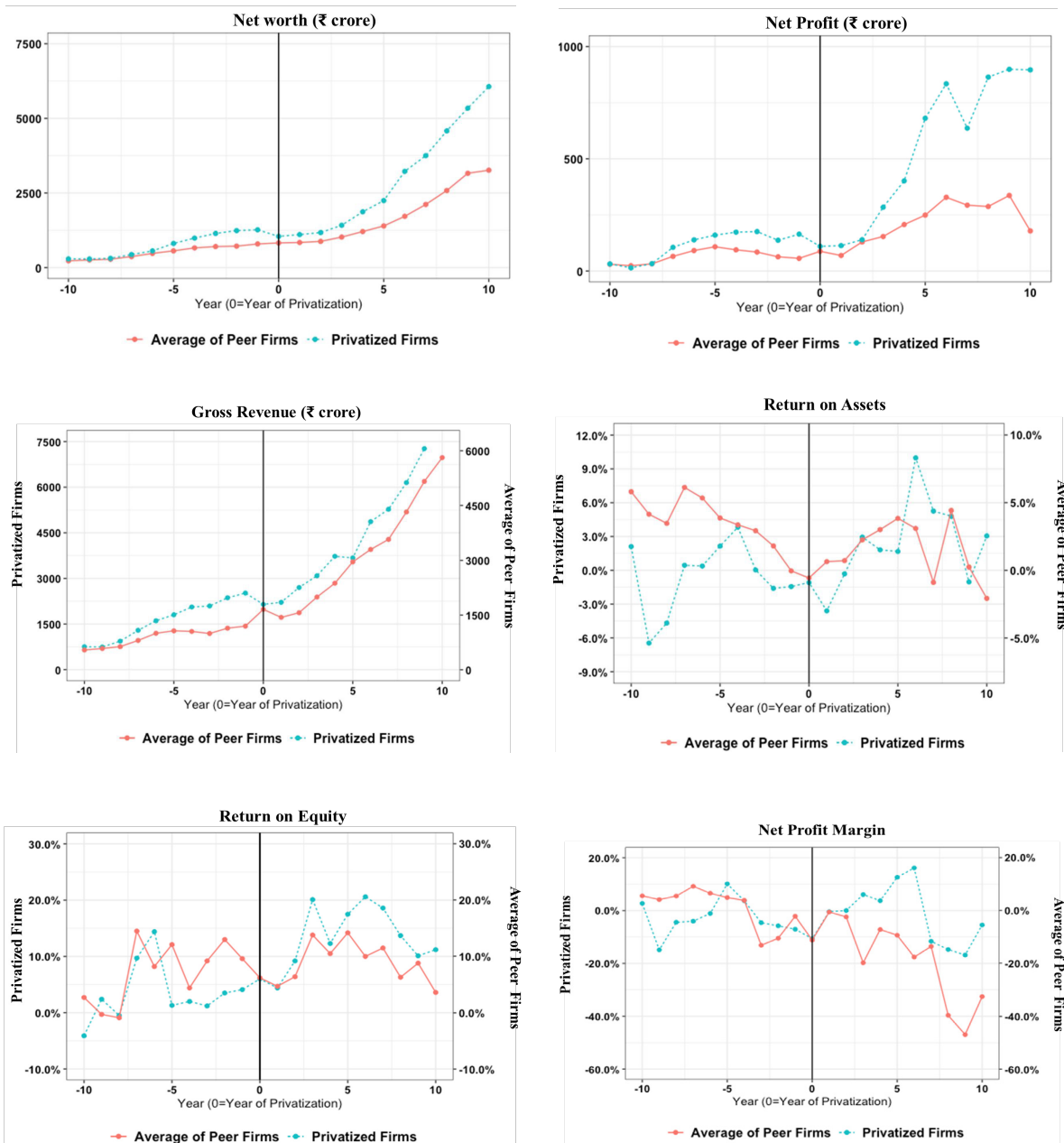
स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

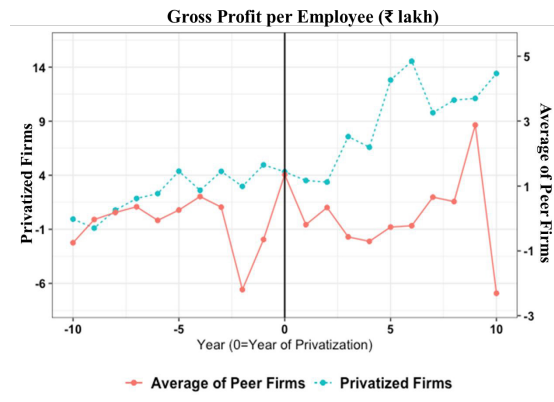
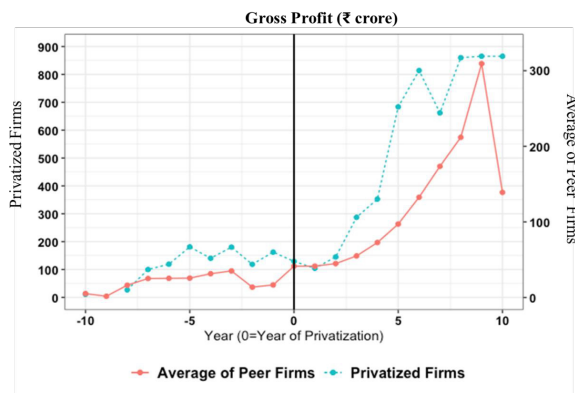
टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

9.8 चित्र 10 नीचे निजी सीपीएसई के निष्पादन के रुझान को दर्शाता है। विशिष्ट सीपीएसई के निजीकरण के पूर्व और पश्चात के 10 वर्षों के समय के उनके सहयोगियों की तुलना में औसत है। इस रुझान से हमें

निजीकरण के बाद निजी संस्थाओं के निष्पादन में यदि इनकी अपने सहयोगी फर्मों से तुलना की जाए तो परिवर्तन के पहलुओं को समझने में आसानी होती है।

चित्र 11: निजी फर्मों बनाम सहयोगी फर्मों के निष्पादन





स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

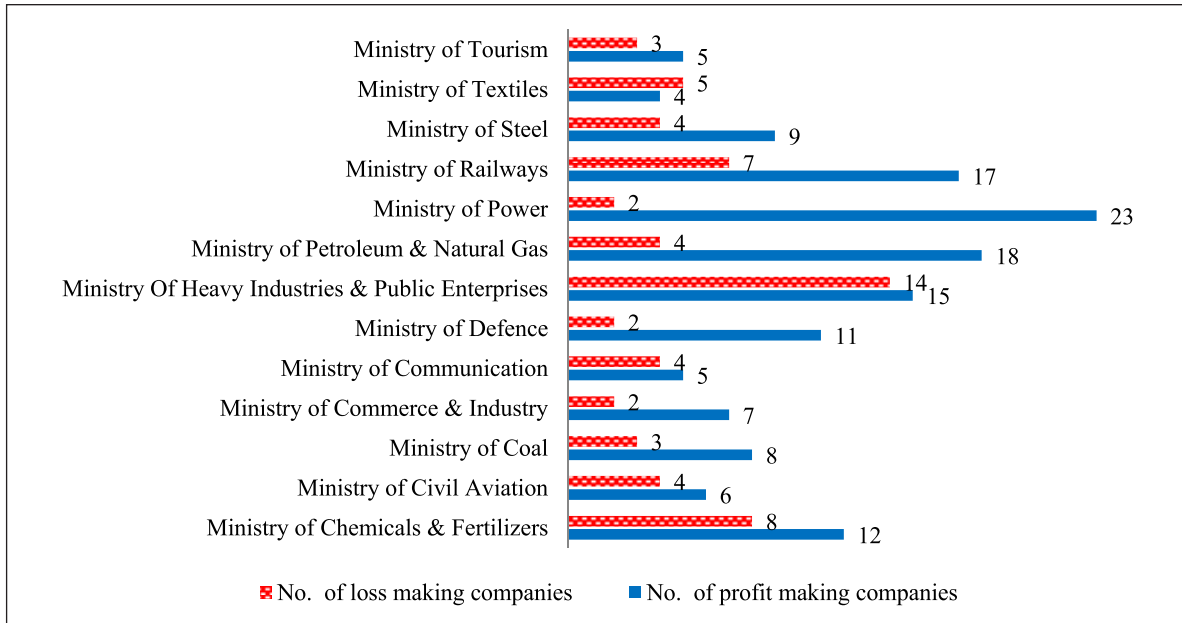
भावी परिदृश्य

9.9 इस अध्याय में हमारा विश्लेषण स्पष्ट रूप से यह पुष्टि करता है कि सीपीएसईएस की रणनीतिक बिक्री के माध्यम से विनिवेश फर्म के प्रदर्शन और समग्र उत्पादकता में सुधार करता है, और धन सृजन के लिए अपनी संभावना को अनलॉक करता है जिसका अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। रणनीतिक बिक्री के मार्ग के माध्यम से अत्यधिक विनिवेश के संदर्भ में “आसानी से हासिल किए जाने वाले लक्ष्य” का उपयोग संभावित उच्च लाभ लाने में, दक्षता को बढ़ावा देने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और चयनात्मक सीपीएसईएस में प्रबंधन में व्यावसायवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। रणनीतिक विनिवेश का ध्यान गैर-रणनीतिक व्यापार से हटाए जाने और पहचाने गए सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम में दक्षता और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देकर आर्थिक क्षमता का इष्टतम उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद, अन्य जगहों पर, विशेष रूप से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली पारेषण लाइन, सीवेज प्रणाली, सिंचाई प्रणाली, रेलवे और शहरी बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए पूंजी को अनलॉक करेगा। यह उत्साहजनक है कि डीआईपीएम द्वारा समर्थकारी प्रावधान पहले से ही लागू किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने विभिन्न सीपीएसई (अध्ययन के अनुबंध में यथा विस्तृत) में विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राजकोषीय गुंजाइश के सृजन

को सुविधाजनक बनाने और सार्वजनिक संसाधनों के कुशल आवंटन में सुधार लाने के लिए इन पर ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।

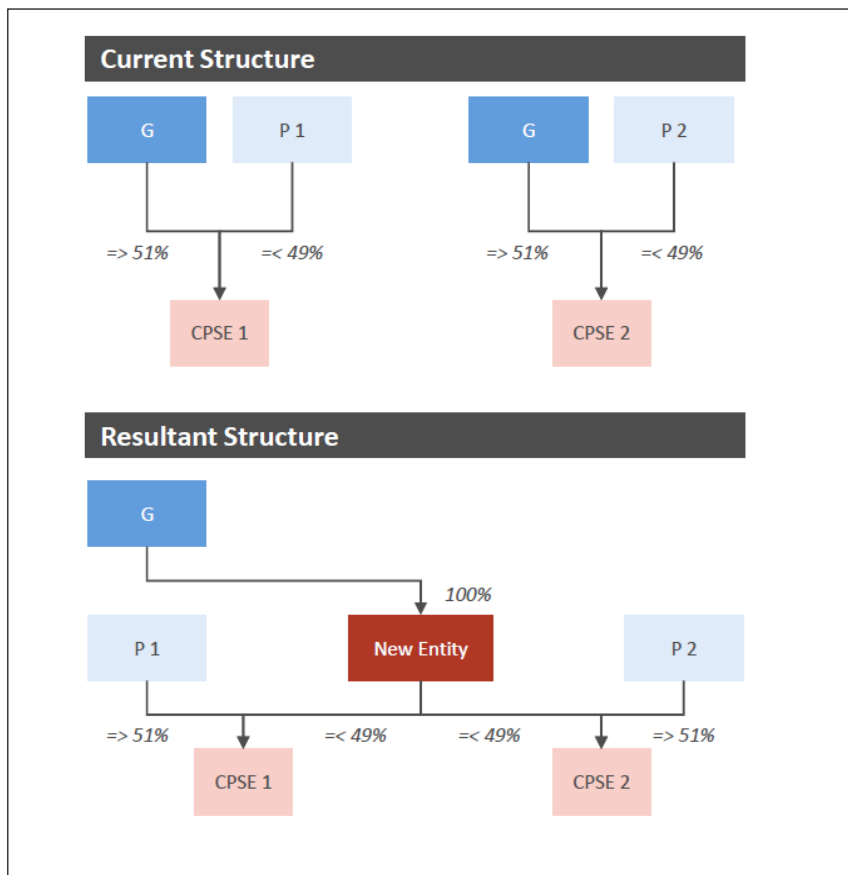
9.10 38 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत 264 सीपीएसई हैं। इनमें से 13 मंत्रालयों/विभागों के अधिकार क्षेत्र में लगभग 10 सीपीएसई है। चित्र 11 से ज्ञात हो रहा है कि अनेक सीपीएसई लाभ की स्थिति में है। हालांकि सामान्यतः बाजार में सीपीएसई ने कमजोर प्रदर्शन किया है तथा यह 2014-2019 की अवधि के दौरान ज्ञात हुआ कि सीएसई सीपीएसई इंडेक्स का औसत रिटर्न केवल 4 प्रतिशत था जबकि बीएसई का सूचकांक का रिटर्न 38 प्रतिशत था। विनिवेश कार्यक्रम का किसी भी तरह का निजीकरण करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी इक्विटी स्टैक वैल्यू को अधिक बढ़ाना है। इस संदर्भ (बॉक्स 4) के लिए तेमासेक होल्डींग कम्पनी के अनुभवों से सीखना लाभदायक होगा। सरकार सूचीबद्ध सीपीएसई में अपनी हिस्सेदारी एक अलग कॉर्पोरेट इकाई को हस्तांतरित कर सकती है (चित्र 12)। इस इकाई का प्रबंधन एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा किया जाएगा। और समय-समय पर इन सीपीएसई में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए अनिवार्य किया जाएगा। यह विनिवेश कार्यक्रम को व्यवसायिकता और स्वायत्तता प्रदान करेगा, जो बदले में सीपीएसई के आर्थिक प्रदर्शन में सुधार करेगा।

चित्र 11: विभिन्न मंत्रालयों के अधीन लाभकारी सीपीएसई की संख्या



स्रोत: लोक उद्यम विभाग

चित्र 12: विनिवेश निगमीकरण हेतु प्रस्तावित संरचना



बॉक्स 4: टेमारोक होल्डिंग्स लिमिटेड- सिंगापुर का निजीरिण मॉडल

25 जून 1974 को सिंगापुर सरकार द्वारा एक निजी वाणिज्यिक सत्व के रूप में इसकी सरकारी-संबद्ध कम्पनियों (जी.एल.सी.) में इसकी निवेश को धारण कर प्रबंधित करने के लिए टेमासे का होल्डिंग्स को निगमित किया गया था। टेमासेक होल्डिंग्स वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है और जो सिंगापुर कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रचालित होता है। टेमासेक बोर्ड के 13 सदस्य हैं जिनमें से अधिकांश सदस्य निजी क्षेत्र के गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र व्यावसायिक नेता हैं। तन से इस कम्पनी ने दूरसंचार, मीडिया, वित्तीय सेवा, ऊर्जा, आधारिक संरचना, इंजीनियरी, फार्मास्युटिकल्स और जीव-विज्ञान जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय के मुख्य क्षेत्रों को कबर करने के लिए अपने प्रचालन में विस्तार किया है।

टेमासेक ने ऐसे कई मूल निवेशों का प्रबंधन किया है, जिनमें शिपिंग फर्म्स (एन.ओ.एल. कम्पल, सेम्बावंग), एक बैंक (डी.बी.एस. बैंक) और सिस्टम्स इंजीनियरी-समूह (सिंगापुर टेक्नोलॉजी, सिंगापुर टेलीकॉम) जैसी राष्ट्रीय सम्पत्तियां सम्मिलित हैं। टेमासेक ने इन सभी जी.एल.सी. में इनके मूल स्टेक्स को सम्मिलित करते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निवेश को बरकरार रखा है। मार्च 2002 से, टेमासेक ने सिंगापुर से बाहर अपने पोर्टफोलियो को चित्रित करना प्रारंभ कर दिया था ऐसा है कि इसके निवेश का एक तिहाई हिस्सा विकसित बाजारों का है, एक तिहाई हिस्सा विकासशील देशों और एक तिहाई हिस्सा सिंगापुर का है। विदेशी कम्पनियों में कम्पनी के कुद प्रमुख निवेशों में स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आइ.सी.आई.सी.आई. बैंक (भारत), बैंक, एस.एम.आर.टी., एस.टी.इंजीनियरिंग, मीडियाकॉर्प और सिंगापुर पॉवर शामिल है।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार यह 230 बिलियन यू.एस. डॉलर से अधिक निवल पोर्टफोलियो का प्रबंध करता है। 1974 के आरम्भ से, इसका चक्रवृद्धि वार्षिक कुल शेयरहोलडर प्रतिफल सिंगापुर डॉलर में 15 प्रतिशत है।

अध्याय एक नजर में

- भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में 53.29 प्रतिशत की सरकार शेयरधारिता के रणनीतिक विनिवेश के अनुमोदन से एचपीसीएल की तुलना में बीपीसीएल के शेयरधारकों के इक्विटी मूल्य में लगभग 33,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसकी परिणति बीपीसीएल के समग्र फर्म मूल्य में एक स्पष्ट वृद्धि के रूप में हुई, और इससे राष्ट्रीय संपदा में इतनी ही राशि तक की बढ़ोतरी हुई।
- वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक किए गए रणनीतिक निवेश से 11 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से पहले-बाद के तुलनात्मक विश्लेषण से यह पता चलता है कि समकक्ष फर्मों की तुलना में निजीकृत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निवल मूल्य, निवल लाभ और आस्तियों के प्रतिफल (आरओए) में निजीकरण की अवधि के बाद, औसतन, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह बेहतर निष्पादन प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए व्यक्तिगत रूप से भी सच बैठता है। आस्तियों का प्रतिफल समकक्ष फर्मों को पीदे छोड़ते हुए ऋणात्मक से लगभग धनात्मक हो गया है जो यह संकेत देता है कि निजीकृत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपने संसाधनों का और अधिक उत्पादक रूप से उपयोग करने में समर्थ रहे हैं। कर्मचारियों की उत्पादकता भी बढ़ी है, क्योंकि सभी प्रति कर्मचारी अंतर, जैसेकि प्रति कर्मचारी निवल लाभ, प्रति कर्मचारी सकल राजस्व और प्रति कर्मचारी निवल मूल्य में निजीकरण के बाद की अवधि में बढ़ोतरी हुई है।
- हमारा विश्लेषण स्पष्ट रूप से यह अभिपुष्टि करता है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की रणनीतिक बिक्री के जरिए विनिवेश निवल मूल्य, लाभपरकता, बिक्री में वृद्धि, इसके शेयरधारकों के लिए दक्षता और प्रतिफल की दृष्टि से बेहतर निष्पादन के फलस्वरूप संपदा सृजित करने के लिए इन उद्यमों की संभावना के द्वारा खोल देता है।
- रणनीतिक बिक्री के मार्ग के जरिए अत्यधिक विनिवेश की दृष्टि से 'आसानी से हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों' का उपयोग पहले से अधिक लाभपरकता, दक्षता संवर्धन, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा ऐसे चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन में व्यवसायवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

संदर्भ

- Affuso, L., A. Angeriz, and M. Pollitt. 2009. "The impact of privatization on the efficiency of train operation in Britain". CGR Working Paper No. 28. Centre for Globalization Research School of Business and Management. Queen Mary University of London.
- Berkman, Henk, Rebel A. Cole, and Jiang Lawrence Fu. 2012. "Improving Corporate Governance Where the State is the Controlling Block Holder: Evidence from China". *SSRN Electronic Journal*.
- Borisova, Ginka, and William L. Megginson. 2011. "Does Government Ownership affect the Cost of Debt? Evidence from Privatization". *Review of Financial Studies* 24 (8): 2693-2737.
- Boubakri, Narjess, Sadok El Ghouli, Omrane Guedhami, and William L. Megginson. 2018. "The Market Value of Government Ownership". *Journal of Corporate Finance* 50: 44-65.
- Brown, David J., John S. Earle, and Almos Telegdy. 2015. "Where Does Privatization Work? Understanding The Heterogeneity in Estimated Firm Performance Effects". *Journal of Corporate Finance* 41: 329-362.
- Brown, J. David, John S. Earle, and Almos Telegdy. 2006. "The Productivity Effects of Privatization: Longitudinal Estimates from Hungary, Romania, Russia, And Ukraine". *Journal of Political Economy* 114 (1): 61-99.
- Chen, Gongmeng, Michael Firth, Yu Xin, and Liping Xu. 2008. "Control Transfers, Privatization, And Corporate Performance: Efficiency Gains in China's Listed Companies". *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 43 (1): 161-190.
- Choi, Seung-Doo, Inmoo Lee, and William Megginson. 2010. "Do Privatization IPOs Outperform in The Long Run?". *Financial Management* 39 (1): 153-185.
- Conway, Paul, and Richard Herd. 2009. "How Competitive Is Product Market Regulation in India?". *OECD Journal: Economic Studies* 2009 (1): 1-25.
- Dinc, I. Serdar, and Nandini Gupta. 2011. "The Decision to Privatize: Finance and Politics". *The Journal of Finance* 66 (1): 241-269.
- Florio, Massimo. *The great divestiture: Evaluating the welfare impact of the British privatizations, 1979-1997*. MIT press. 2004.
- Gan, Jie, Yan Guo, and Chenggang Xu. 2014. "Decentralized Privatization and Change of Control Rights in China". *The Review of Financial Studies* 31 (10): 3854-3894.
- Ghosh, Saibal. 2011. "R&D in Public Enterprises". *Science, Technology and Society* 16 (2): 177-190.
- Gupta, Nandini. 2005. "Partial Privatization and Firm Performance". *The Journal of Finance* 60 (2): 987-1015.
- Li, Bo, William L. Megginson, Zhe Shen, and Qian Sun. 2016. "Do Share Issue Privatizations Really Improve Firm Performance in China?". *SSRN Electronic Journal*.
- Makhija, Anil K. "Privatization in India." *Economic and Political Weekly* 41, no. 20 (2006): 1947-951.

- Meggison, William L, and Jeffrey M Netter. 2001. "From State to Market: A Survey of Empirical Studies On Privatization". *Journal of Economic Literature* 39 (2): 321-389.
- Meggison, William L. 2007. "Introduction to The Special Issue On Privatization". *International Review of Financial Analysis* 16 (4): 301-303.
- Meggison, William L. 2017. "Privatization, State Capitalism, And State Ownership of Business in The 21St Century". *Foundations and Trends® In Finance* 11 (1-2): 1-153.
- Meggison, William L., Robert C. Nash, Jeffrey M. Netter, and Annette B. POULSEN. 2004. "The Choice of Private Versus Public Capital Markets: Evidence from Privatizations". *The Journal of Finance* 59 (6): 2835-2870.
- Meggison, William. 2010. "Privatization and Finance". *Annual Review of Financial Economics* 2 (1): 145-174.
- Meher, Kishor & Samiran, Jana. (2012). Bottom line of Divested PSE's in Post Privatization Scenario. 4D *International Journal of Management & Science*. III.
- Ministry of Finance, Department of Disinvestment, Government of India. 2007. Dipam.Gov.In. https://dipam.gov.in/sites/default/files/white_paper.pdf.
- Muhlenkamp, Holger. 2013. "From state to market revisited: a reassessment of the empirical evidence on the efficiency of public (and privately-owned) enterprises". *Annals of Public and Cooperative Economics* 86 (4): 535-557.
- OECD. 2008. "Improving Product Market Regulation in India". OECD Economics Department Working Papers.
- O'Toole, Conor M., Edgar L.W. Morgenroth, and Thuy T. Ha. 2016. "Investment Efficiency, State-Owned Enterprises and Privatization: Evidence from Viet Nam in Transition". *Journal of Corporate Finance* 37: 93-108.
- Oum, Tae H., Nicole Adler, and Chunyan Yu. 2006. "Privatization, Corporatization, Ownership Forms and Their Effects On the Performance of the World's Major Airports". *Journal of Air Transport Management* 12 (3): 109-121.
- Parker, David. 2004. "The UK's Privatization Experiment: The Passage of Time Permits A Sober Assessment". Cesifo Working Paper No. 1126.
- Stiglitz, Joseph E. *Privatization: Successes and Failures*. Edited by Roland Gerard. Columbia University Press, 2008.
- Subramanian, Krishnamurthy, and William L. Meggison. 2018. "Employment Protection Laws and Privatization". *SSRN Electronic Journal*.
- Tran, Ngo My, Walter Nonneman, and Ann Jorissen. 2015. "Privatization of Vietnamese Firms and Its Effects On Firm Performance". *Asian Economic and Financial Review* 5 (2): 202-217.
- Wolf, Christian O. H., and Michael G. Pollitt. 2008. "Privatizing National Oil Companies: Assessing The Impact On Firm Performance". *SSRN Electronic Journal*.

सीपीएसई की सूची जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की 'सैद्धांतिक रूप से' स्वीकृति प्राप्त कर चुकी है

क्रम सं.	सीपीसीई का नाम	सीसीईए अनुमोदन की तारीख
सतत्		
1	एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट (एनएसपी)	27.10.2016
2	सेल की तीन यूनितें: वीआईएसपी, भद्रावती, एसएसपी, सलेक एवं एएसपी, दुर्गापुर	27.10.2016
3	फेरा स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)	27.10.2016
4	सेंट्रल ईलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (सीईएल)	27.10.2016
5	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल)	27.10.2016
6	सीमेंट कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) का नयागांव यूनित	27.10.2016
7	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (आई) लिमिटेड (बी एंड आर)	27.10.2016
8	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडया) लिमिटेड (ईपीआईएल)	27.10.2016
9	स्कूटर इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)	27.10.2016
10	भारत पम्पस एंड कंप्रेसर लिमिटेड (बीपीसीएल)	27.10.2016
11	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)	27.10.2016
12	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बनस लिमिटेड (एचएफएल)	27.10.2016
13	पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल)	27.10.2016
14	प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल)	27.10.2016
15	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल)	27.10.2016
16	हिंदुस्तान एंटी बायोटेक्स लिमिटेड (फार्मास्यूटिकल्स विभाग)	28.12.2016
17	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (फार्मास्यूटिकल्स विभाग)	28.12.2016
17	एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनियां	28.06.2017
19	इंडिया मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कोरपोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	01.11.2017
20	कर्नाटक एंटी बायोटेक्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)	01.11.2017
21	एचएलएललाइफ केयर लिमिटेड (एचएलएल)	01.11.2017
22	कामराज पोर्ट लिमिटेड (केपीएल)	28.02.2019
23	शिपिंग कोरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई)	20.11.2019
24	भारत पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	20.11.2019
25	कंटेनर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कोनकोर)	20.11.2019
26	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल)	20.11.2019
27	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कोरपोरेशन लिमिटेड (निपको)	20.11.2019
28	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)	08.01.2020
लेन-देन हुआ		
29	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	19.07.2017
30	ग्रामीण विद्युतीकरण कोरपोरेशन लिमिटेड (आरईसी)	06.12.2018
31	हॉस्पिटल सर्विसेस कंसल्टेंसी कोरपोरेशन लिमिटेड (एचएससीसी)	27.10.2016
32	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कोरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी)	27.10.2016
33	ड्रेजिंग कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल)	01.11.2017

टिप्पणी: सरकार ने पिछले दो वर्षों में कार्यानीतिक उपाय के तहत पहले ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) (इंडियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड/आईओसी को), ग्रामीण विद्युतीकरण कोरपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) (पावर फाइनेंस कोरपोरेशन/पीएफसी को), ड्रेजिंग कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) (चार पोर्टों के एक कंसोर्टियम को), हॉस्पिटल सर्विसेस कंसल्टेंसी कोरपोरेशन लिमिटेड (एचएससीसी) (एनबीसीसी को) और नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कोरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी) (डब्ल्यूएपीसीओएस को) जैसे 5 सीपीएसई में अपनी हिस्सेदारी बेचकर रुपये 52,869 करोड़ राशियां प्राप्त की है।

स्रोत: निवेश और सार्वजनिक सम्पदा प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) और प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)

क्या भारत की जीडीपी वृद्धि को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया जाता है? नहीं।

“सहसंबंध अंधविश्वास का आधार है जबकि कार्यकरण संबंध विज्ञान का मूलाधार है।”

-अज्ञात

चूंकि अर्थव्यवस्था में निवेश करने वाले देश की जीडीपी वृद्धि को ध्यान में रखते हैं अतः यदि इसके परिणाम के विषय में किसी प्रकार की अनिश्चितता हो तो ऐसे निवेश की मात्रा भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए, वर्ष 2011 में भारत की जीडीपी के प्राक्कलन की पद्धति में बदलावों के उपरांत भारत की जीडीपी वृद्धि दर को लेकर हालिया बहस का महत्व, विशेष रूप से विकास दर में हालिया मंदी को देखते हुए, बढ़ जाता है। एक सतर्क सांख्यिकीय और अर्थमितीय विश्लेषण का उपयोग करते हुए, ताकि इस विषय के महत्व को उचित न्याय मिल सके, यह अध्याय ऐसा कोई प्रमाण इस विषय में नहीं पाता कि भारत की जीडीपी वृद्धि का गलत प्राक्कलन किया जाता है। अध्याय की शुरुआत इस आधार-वाक्य से होती है कि विश्व के देशों में प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः अनेक तरह की परस्परिक भिन्नताएं होती हैं। अतएव, ऐसी अंतर्निहित भिन्नताओं से उत्पन्न होने वाले अनेक चौकाने वाले कारकों की वजह से, विभिन्न देशों की तुलना करने में गलत अनुमति के जोखिम भी होंगे। फलतः देशों के बीच परस्पर विश्लेषण का कार्य सावधानीपूर्वक करना होगा ताकि सहसंबंध और कार्य-करण संबंध को अलग-अलग रखा जा सके। जो प्रतिमान वर्ष 2011 के बाद भारत के बारे में 2.77 प्रतिशत तक जीडीपी वृद्धि का गलत तरीके से अति-प्राक्कलन करते हैं वही, हमारे निदेशों/मॉडल में शामिल 95 देशों में से 51 के बारे में भी समान अवधि के दौरान जीडीपी वृद्धि के गलत प्राक्कलन प्रस्तुत करते हैं। त्रुटिपूर्ण ढंग से विनिर्दिष्ट मॉडल में गलत-प्राक्कलन का यह परिणाम +4 प्रतिशत से लेकर -4.6 प्रतिशत तक की सीमा में है, जिसके अंतर्गत यूके का +1.6 प्रतिशत तक, जर्मनी का +1.0 प्रतिशत तक, सिंगापुर का -2.3 प्रतिशत तक, दक्षिण अफ्रीका का -1.2 प्रतिशत तक और बेल्जियम का -1.3 प्रतिशत तक गलत प्राक्कलन शामिल हैं। भारत की अपेक्षा यूके और जर्मनी की कम वृद्धि दर को देखते हुए त्रुटिपूर्ण विनिर्दिष्ट मॉडल में भारत (40 प्रतिशत) की अपेक्षा यूके (76 प्रतिशत) और जर्मनी (71 प्रतिशत) के लिए प्रतिशतता का दोषपूर्ण आकलन कहीं अधिक है। तथापि, जब विभिन्न देशों की समस्त अप्रत्यक्ष परस्पर भिन्नताओं को तथा देशों के बीच जीडीपी वृद्धि में विभेदी रुझानों (प्रवृत्तियों) को सम्मिलित करते हुए इन प्रतिमानों के आधार पर प्राक्कलनों की त्रुटि को सुधारा जाता है तो इन 52 देशों (भारत सहित) में से अधिकांश की जीडीपी वृद्धि न तो अति-प्राक्कलित है और न ही अल्प-प्राक्कलित दिखाई देती है। कुल मिलाकर, भारत की जीडीपी को लेकर अति-प्राक्कलन संबंधी चिंताएं निराधार हैं

इस अध्याय में कही गई बड़ी बात का, अध्याय 2 में दिए गए सूक्ष्म-स्तरीय साक्ष्यों के साथ इसके निष्कर्षों को योगवाही तरीके से समझने की जरूरत है, जहां भारत के 504 जिलों में औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत नई फर्मों के सृजन से संबंधित विश्लेषण किया गया है। इस संदर्भ में किए गए दो प्रेक्षण महत्वपूर्ण हैं। प्रथम, सूक्ष्म साक्ष्य दर्शाता है कि किसी नवीन फर्म-सृजन में 10 प्रतिशत वृद्धि से जिला स्तर की जीडीपी में 1.8 प्रतिशत वृद्धि होती है। चूंकि औपचारिक क्षेत्र में नवीन फर्म-सृजन की गति में वर्ष 2014 के बाद विशेष रूप से वृद्धि हुई है अतः जिला स्तरीय वृद्धि पर

और तद्वारा देश-स्तरीय वृद्धि पर पड़ने वाली परिणामी प्रभाव को किसी भी विश्लेषण में विचार का विषय बनाया जाना चाहिए। इन बातों के साथ, पूर्णानंद्य (2019) दर्शाते हैं कि पौष्टिकता और बिजली की उपलब्धता जैसे संकेतकों में भारत के सुधार से, पद्धतिमूलक परिवर्तन के बाद भारत की जीडीपी में उच्चतर वृद्धि दर को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। द्वितीय, नवीन फर्म-सृजन के विषय में सूक्ष्म साक्ष्य दर्शाते हैं कि सेवा क्षेत्र में नवीन फर्मों का सृजन विनिर्माण, अवसंरचना या कृषि क्षेत्र के मुकाबले बहुत अधिक है। यह सूक्ष्म स्तरीय साक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के सापेक्षिक महत्व संबंधी चिरपरिचित समष्टिगत तथ्य से पूरी तरह से मेल खाता है। भारत की सांख्यिकीय अवसंरचना को बढ़ाने में निवेश की आवश्यकता असंदिग्ध में इस संदर्भ में, भारत के भूतपूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् की अध्यक्षता में 28 सदस्यीय, आर्थिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति (एससीईएस) का गठन किया जाना महत्वपूर्ण है। तथापि, जब भारतीय आंकड़ों की गुणवत्ता का आकलन किया जाए तो इस समीक्षा में सतर्कतापूर्वक निर्मित साक्ष्यों को ध्यान में अवश्यक रखा जाए

परिचय

10.1 वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक सुदृढ़ निवेश वातावरण तैयार किया जाना अति आवश्यक है। वर्ष 2018-19 की आर्थिक समीक्षा में, मांग बढ़ाने, क्षमता निर्माण करने नई प्रौद्योगिकी अपनाने, रचनात्मक विध्वंस की अनुमति देने और रोजगार सृजन करने की भूमिका का उल्लेख किया गया था। निःसंदेह, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक लाभकारी व्यवस्था में ढालने की प्रक्रिया में निवेश का स्थान सबसे ऊपर है।

10.2 वर्तमान में, चाहे एफडीआई मानकों को शिथिल करने, कार्पोरेट कर की दरों में कटौती करने, मुद्रास्फिति को नियंत्रित करने, व्यवसाय में सुगमता लाने की बात हो या फिर कराधान संबंधी सुधारों की बात हो, भारत ने निवेश बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार की पहल की है। निवेशक, जिनमें अंतरराष्ट्रीय निवेशक भी शामिल हैं, भारत में एक विशेष अवसर देखते हैं क्योंकि यह विश्व में तेजी से विकसित हो रही विशाल अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर निवेश संबंधी निर्णय का एक पूर्ववर्ती प्रेरक तत्व है। इसके अलावा, किसी भी देश की जीडीपी का स्तर और उसकी वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के आकार और स्वास्थ्य के लिए बैरोमीटर का कार्य करते हुए अनेक महत्वपूर्ण नीतिगत पहलों को अनुप्राणित करने का कार्य करती है।

10.3 वर्ष 2011-12 में जीडीपी प्राक्कलन विधि के परिवर्तन के पश्चात् हाल के दिनों में इस दौरान प्राप्त विभिन्न जीडीपी वृद्धि दरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते

हुए भारत की जीडीपी वृद्धि दरों की सत्यता के बारे में काफी बहस होती रही है (संशोधन संबंधी टिप्पणी के लिए बॉक्स 1 देखें)। भारत में जीडीपी वृद्धि दर शुद्धता से प्राक्कलित की जाती है या नहीं, इस विषय पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों स्तरों पर खूब चर्चा हुई है जिसमें भल्ला (2019), गोयल एवं कुमार (2019), राय एवं सप्रे (2019), पनगड़िया (2019), पूर्णानंद (2019), सुब्रमण्यन (2019) और वैद्यनाथन (2019) के नाम उल्लेखनीय हैं। चूंकि भारत की जीडीपी वृद्धि दरों की सत्यता के बारे में चिंताएं भी बढ़ सकती हैं अतः यह आवश्यक है कि इस विषय की एक सतर्कतापूर्ण जांच की जाए। हाल की तिमाहियों के दौरान जीडीपी वृद्धि दर की गिरावट को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए ऐसी परीक्षा किया जाना महत्वपूर्ण है। यदि निवेशक, गलती से ही सही, किसी निभातर वृद्धि दर पर किसी “बट्टे” के लिए आवेदन करे तो इससे निवेशक-भावना पर वास्तव में प्रभाव पड़ सकता है।

10.4 इस अध्याय का उद्देश्य, सुब्रमण्यन (2019) और पूर्णानंदन (2019) में यथाकार्यान्वित अंतर-दर-अंतर पद्धति का उपयोग करते हुए जीडीपी वृद्धि दर में अशुद्धता का अंकित न करना है। किसी भी अशुद्धता का आकलन करते समय “शुद्धप्राक्कलन” के लिए एक बेंचमार्क की आवश्यकता होती है जो पारिभाषिक रूप से “प्रति-तथ्यात्मक” को निरूपित करता है, यानी, ऐसा तथ्य जो वस्तुतः उजागर नहीं हुआ और इसलिए उसे प्राक्कलित करना होगा। यह आकलन भारत की जीडीपी वृद्धि दरों की अन्य देशों की जीडीपी वृद्धि दर

बॉक्स 1: जीडीपी सीरीज के आधार वर्ष में परिवर्तन

संयुक्त राष्ट्र की राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए) 2008 के अनुरूप स्रोतों एवं पद्धतियों के अनुकूलन के पश्चात् जीडीपी सीरीज के आधार वर्ष को 2004-05 से बदलकर 2011-12 किया गया और 30 जनवरी, 2015 को इसे जारी किया गया। अकादमिक संस्थाओं, राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) वित्त मंत्रालय, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, नीति आयोग और चयनित राज्य सरकारों के विशेषज्ञों से युक्त राष्ट्रीय लेखा सांख्यिक सलाहकार समिति (एसीएनएएस) द्वारा समष्टि समुच्चयों के संकलन की पद्धति को अंतिम रूप दिया गया। समिति द्वारा यह निर्णय आंकड़ों की उपलब्धता और विभिन्न पद्धतिमूलक पहलुओं पर विचार करने के बाद सर्वसम्मति से और सामूहिक रूप से लिया गया।

वैश्विक स्तर पर मानकीकरण और तुलनात्मक के प्रयोजन के लिए सभी देश सुविचारित परामर्श के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से तैयार की गई एसएनए व्यवस्था का अनुसरण करते हैं। एसएनए-2008, वर्ष 2009 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग (यूएनएससी) द्वारा अंगीकृत राष्ट्रीय लेखा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय मानकों का नवीनतम संस्करण है और पूर्ववर्ती एसएनए-1993 का अद्यतन रूप है। भारत में राष्ट्रीय लेखा पर अंतर-सचिवालयी कार्य-समूह (आईएसडब्ल्यूजीएनए) को अधिदेश दिया गया कि सदस्य देशों के साथ गहन चर्चा और परामर्श के माध्यम से एसएनए-2008 का विकास किया जाए। भारत ने सलाहकारी विशेषज्ञ समूह की चर्चाओं में भी भाग लिया। एसएनए-2008 के अंगीकरण के अंतर्गत यूएनएससी ने सदस्य देशों, क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय संगठनों को अपनी सिफारिशों को कार्यान्वित करने हेतु और उपलब्ध डाटा स्रोतों के आधार पर राष्ट्रीय राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग हेतु इसका उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया।

के साथ तुलना करके किया जाता है। प्रभाव रूप में, इस विधि के अंतर्गत इस प्रश्न का उत्तर ढूँढ़ा जाता है कि, “यदि पद्धतिमूलक परिवर्तन को कार्यान्वित नहीं किया गया होता तो भारतीय जीडीपी वृद्धि दर का प्राक्कलन क्या होता”, तथा फिर उस प्राक्कलन की तुलना वास्तविक वृद्धि दर से करते हुए इन प्राक्कलनों की अशुद्धता का अनुमान लगाया जाता है।

10.5 यह कार्यप्रणाली उस जैसी ही है जैसे कि किसी औषधि के अनुसंधानकर्ता यह अनुमान लगाते हैं कि औषधि प्रभावी है कि नहीं। इसकी प्रमाणिकता के लिए, यह सोचे कि हम रक्तचाप के लिए औषधि का परीक्षण कर रहे हैं। एक जैसे दिखने वाली परीक्षा वस्तुओं के दो समूहों का सृजन करे उपचार किए जाने वाले समूह को औषधि दी जाए तथा नियंत्रण समूह को शक्कर की गोली दी जाए। एक जैसे दिखने वाले समूहों में तुलना सेब से संतरों की तुलना करने के बजाए सेब से सेब की तुलना सुनिश्चित होती है। जब समूह हम शक्कर होते हैं तब उपचार समूहों के लिए रक्तचाप में पहले तथा बाद के अंतर को नियंत्रण समूह के लिए वैसे ही अंतर से हटाकर किसी गलत साबित करने वाले प्रभाव को हटाकर औषधि के सही प्रभाव का अनुमान लगाते

हैं। प्रभावी रूप से, नियंत्रण समूह के लिए रक्तचाप में बदलाव यह प्रश्न पूछता है कि “रक्तचाप में क्या बदलाव होगा जबकि औषधि दी ही नहीं गई थी” यह कार्यप्रणाली जिसे अनुसंधानकर्ता “अंतरांतर” पुकारते हैं, इसका आर्थिक अनुसंधान में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

10.6 जीडीपी विकास दर अनुमान लगाने के संदर्भ में भारत उपचार समूह का प्रतिनिधित्व करता है तथा अन्य देश नियंत्रण समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। देश उपाय में एक दूसरे से अंतर रखते हैं ताकि इसे विशेषरूप से मापा जा सके उपायो में (जिसे मापा न जा सके) अंतर दोनों समुच्चय में आर्थिक गनिविधियों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए देशों के बीच तुलना विभिन्न गलत साबित करने वाले घटकों के कारण गलत अनुमान के जोखिम से भरी हुई है जो ऐसी अन्तर्निहित मनान्तर से उपजी है। परिणाम स्वरूप देशों के बीच विश्लेषण ध्यान पूर्वक किया जाना चाहिए ताकि सह-संबंध कारण कार्य सिद्धांत से अलग पहचाना जाता है। इसलिए अनुसंधानकर्ता विभिन्न देशों के बीच आंकड़ों का उपयोग करते हुए सांख्यिकी तकनीकों का ध्यानपूर्वक कार्यान्वयन करता है जिसे पैनल आंकड़े अर्थ-मिती पुकारते हैं देशों

के बीच ऐपल-टू-ऐपल तुलना को सुनिश्चित करने के लिए तथा इसके द्वारा रक्तचाप पर औषधि की प्रभाविता परखने की उपर्युक्त जांच की नकल करता है।

10.7 इसे मुद्दे के महत्व के साथ न्याय करने वाले सांख्यिकीय और अर्थमितीय विश्लेषण का सावधानीपूर्वक उपयोग करते हुए, हम भारत की जीडीपी वृद्धि के गलत आकलन का कोई सबूत नहीं पाते हैं। वास्तव में, हम पाते हैं कि जिस मॉडल से वर्ष 2011 के बाद भारत के लिए जीडीपी वृद्धि का 2.77% के रूप में गलत तरीके से अनुमान लगाया गया था, नमूने शामिल में 95 देशों में से 51 अन्य देशों के लिए इसी अवधि में जीडीपी वृद्धि का गलत अनुमान लगाता है। गलत अनुमान में + 4% से -4.6% की भिन्नता है, जिसमें यूके + 1.6% जर्मनी +1.0% सिंगापुर -2.3% दक्षिण अफ्रीका -1.2% और बेलजियम -1.3% शामिल है। हालांकि, जब देशों के बीच सभी अंतरित अंतरों के साथ-साथ देशों के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में अंतर रुझानों के लिए लेखांकन द्वारा मॉडल का सही अनुमान लगाया जाता है, तो इन 52 देशों में से अधिकांश के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि न तो कम या कम अनुमानित होती है। संक्षेप में, भारत की जीडीपी के अधिक आकलन की चिंताएं निराधार हैं।

10.8 हम अन्य संकेतों की जांच करके विश्लेषण को समाप्त करते हैं जो जीडीपी अनुमान कार्यप्रणाली के साथ समस्या का संकेत दे सकते हैं। जैसा कि सुब्रमण्यन (2019), जीडीपी वृद्धि दर अन्य सूचकों के साथ सहसंबंधित है जिसकी कार्यप्रणाली में किसी भी रूप में परिवर्तित नहीं हुए हैं। आधारभूत रूप से कार्यप्रणाली में “हासपद” चर-जीडीपी वृद्धि दर को बहुत से अन्य “विश्वसनीय” के साथ सहसंबंधित करना शामिल है। ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध पद्धति का खुलासा किया जा सके। जैसा कि सुब्रमण्यन (2019) में, इन “विश्वसनीय” चर में निर्यात, आयात, उद्योग, के लिए वास्तविक ऋण, पेट्रोलियम उपभोग, रेलवे माल ढुलाई, बिजली की खपत, इत्यादि शामिल हैं। हम इस नैदानिक प्रयोग को शुरू करते हुए स्वीकारते हैं कि सहसंबंध गैर-स्थिर हो सकते हैं, अर्थात् समय के साथ-साथ उन

कारकों के कारण अलग-अलग हो सकते हैं जो जीडीपी कार्यप्रणाली में परिवर्तन से असंबंधित हो सकते हैं।

10.9 हमारे परिणाम स्पष्ट रूप से इस प्रसंग को स्थापित करते हैं कि जीडीपी वृद्धि के निदान के लिए सह संबंध एक निर्विवाद रूप से गैर-स्थिर है: वे न केवल 1980 से 2015 तक विभिन्न 3- वर्ष या 5-वर्ष की अवधि में चिन्ह परिवर्तन का संकेत करते हैं, बल्कि समय के साथ-साथ उनके मूल्य भी काफी बदलाव आते हैं। 2011 में जीडीपी कार्यप्रणाली में विशिष्ट परिवर्तन से संबंधित कारणों के संबंध में इस तरह के बदलाव को देखते हुए, हम भारत की जीडीपी के गलत आकलन के प्रसंग का कारण खोजने में विफल हैं। इसके अलावा, हम पाते हैं कि नई जीडीपी श्रृंखला के साथ इन संकेतकों का संबंध पुरानी श्रृंखला के साथ उनके संबंधों से अलग नहीं है। दूसरे शब्दों में, इन संकेतकों और जीडीपी के बीच संबंध कार्यप्रणाली संशोधन के बाद भी संरक्षित है, जिससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि संशोधित कार्यप्रणाली हमारे जीडीपी का सही अनुमान लगाती है।

क्या जीडीपी का गलत आकलन किया गया है?

मॉडल का चयन: क्या अंतरांतर विधि उपयुक्त है?

10.10 हमने पूर्णानंदम (2019) और सुब्रमण्यन (2019) में विश्व बैंक के विश्व विकास संकेतक (डब्ल्यूडीआई) डेटाबेस से क्रॉस-कंट्री डेटा इकट्ठा किए। हमने इन अध्ययनों के अनुरूप तेल निर्यातकों¹, 1 मिलियन से कम आबादी वाले देशों, युद्धग्रस्त और राजनीतिक रूप से कमजोर देशों को सुब्रमण्यन (2019) के अनुरूप इसमें शामिल नहीं किया है। हालांकि हमारे नमूने में इन अध्ययनों के नमूनों की एक सटीक प्रतिकृति² होने की संभावना नहीं है, हम एक पर्याप्त अधिव्यापन की उम्मीद करते हैं। किसी भी मामले में, इस अध्याय का उद्देश्य एक स्वतंत्र सत्यापन के लिए परिणामों की मजबूती का परीक्षण करना है। एक नमूना जो मूल से थोड़ा भिन्न है, नमूना चयन के लिए मजबूती की जांच के रूप में कार्य करता है।

1. नमूना अवधि के दौरान घाना और अजरबैजान की शुद्ध निर्यात स्थिति अस्पष्ट होने के कारण इन देशों को नमूने में शामिल किया गया है।
2. हम यह पाते हैं कि हमारे प्रतिदर्श का उपयोग करते हुए सुब्रमण्यन 2019 के प्रमुख अनुभवजन्य विशेषताओं को लगाते हुए भारत की जीडीपी 2.77 प्रतिशत का अनुमान लगा दी गई है जोकि 2.5 प्रतिशत के मूल अध्ययन के अनुमान के बहुत निकट हैं, यह प्रतिदर्श में मजबूत अधिव्ययन इंगित करता है। हम तब हमारे प्रतिदर्श में देशों के बीच विजतियता के अतिरिक्त साधन को ध्यान रखते हुए मॉडल को आधुनिक करने के लिए विद्वानों के साहित्य का लाभ उठाते हैं।

10.11 मानक अंतरांतर (डीआईडी) मॉडल एक अर्थमितीय तकनीक है जो एक अर्ध-प्रयोग जैसे जीडीपी मापनप्रणाली परिवर्तन के अंतर प्रभाव का अध्ययन करके एक प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन की नकल करने का प्रयास करता है। अध्ययन किए गए विभेदक

प्रभाव किसी देश की औसत सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में अंतर है, जो भारत (प्रशोधन समूह), बनाम अन्य देशों जो परिवर्तन (नियंत्रण समूह) जहां परिवर्तन नहीं किए गए हैं, के माध्यम आंकलित किए गए हैं। इस कार्यप्रणाली से संबंधित नोट के लिए बॉक्स 2 देखें।

बॉक्स 2: अंतरांतर विधि-पर एक टिप्पणी

अंतरांतर (डीआईडी) कार्यप्रणाली सवाल पूछती है “यदि प्राविधिकी बदलाव कार्यान्वित नहीं होता हो भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या होता” तथा वास्तविक वृद्धि दर से इस अनुमानों की तुलना इस अनुमान में त्रुटिपूर्णता साबित करने की तुलना करती है।

माना कि जीडीपी देश सी में वर्ष टी में औसत जीडीपी वृद्धि को दर्शाता है जहां सब्सक्रिप्ट सी हमें बताता है। कि क्या हम अध्ययन में भारत अथवा उपयोग किए गए अन्य देशों से औसत जीडीपी वृद्धि दर देख रहे हैं तथा सब्सक्रिप्ट टी हमें यहां बताता है कि क्या हम 2011 (जीडीपी प्राविधिकी बदलाव से पहले) अथवा 2012-2016 (जीडीपी प्राविधिकी बदलाव के पश्चात्) से औसत वृद्धि दर को देख रहे हैं। भारत की औसत जीडीपी विकास अनुमान में जीडीपी प्राविधिकी बदलाव के प्रभाव का डीआईडी अनुमान है:

$$\delta_{DID} = \left(\overline{GDP}_{India,2012-2016} - \overline{GDP}_{India,2002-2011} \right) - \left(\overline{GDP}_{Controls,2012-2016} - \overline{GDP}_{Controls,2002-2011} \right)$$

भारत तथा नियंत्रित देशों की औसत जीडीपी वृद्धि की तुलना करने के बजाए डीआईडी भारत तथा नियंत्रित के बीच औसत जीडीपी विकास में बदलाव पर प्रकाश डालता है।

औसत जीडीपी विकास स्तरों की तुलना करने के बजाय इस तथ्य को समायोजित करता है कि जीडीपी प्राविधिकी बदलाव (पूर्व उपचार अवधि) से पहले भारत की औसत जीडीपी वृद्धि नियंत्रित की जीडीपी वृद्धि से अधिक हो सकती थी। इसे देखने के लिए यह नोट करें कि हम इस प्रकार से जमीनी स्तर डीआईडी निर्माण कर सकते हैं:

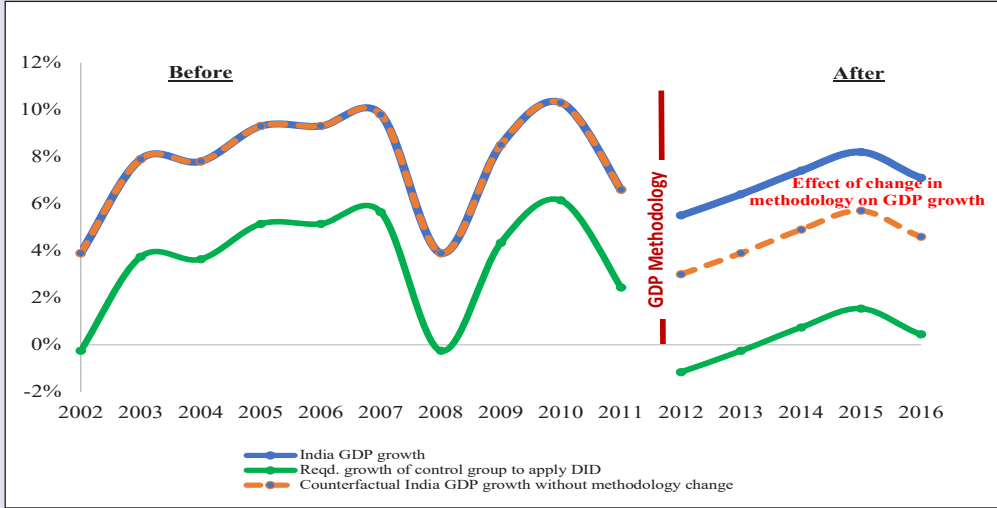
$$\delta_{DID} = \left(\overline{GDP}_{India,2012-2016} - \overline{GDP}_{Controls,2012-2016} \right) - \left(\overline{GDP}_{India,2002-2011} - \overline{GDP}_{Controls,2002-2011} \right)$$

डीआईडी परिकलन का यह संस्करण जीडीपी प्राविधिकी बदलाव (उपचार पश्चात् अंतर) के बाद औसत जीडीपी विकास दर अंतर से भारत और नियंत्रित समूह के बीच जीडीपी प्राविधिकी बदलाव (पूर्व उपचार अंतर) पूर्व औसत जीडीपी वृद्धि दर अंतर को घटाता है। जिसके द्वारा तथ्य को समायोजित करके कि अध्ययन में भारत तथा नियंत्रक के रूप में उपयोग किए गए अन्य देशों में जीडीपी विकास दर आरंभिक रूप में एक जैसी नहीं थी।

डीआईडी तर्क चित्र-1 में वर्णित किया गया है जिसमें गहरी रेखा के द्वारा 2012-16 (पश्चात्) अवधि के साथ 2002-2011 (पहले) अवधि के लिए भारत तथा नियंत्रित देशों की जीडीपी वृद्धि का वर्णन करता है डीआईडी उपकरण भारत तथा अन्य नियंत्रित देशों के बीच औसत जीडीपी विकास में प्रवृत्तियों की तुलना का कुल योग होता है। चित्र में बिन्दुअंकित पंक्ति परिकल्पित परिणाम है जो कि डीआईडी अनुसंधान रूपरेखा के आधार पर है। यह बिन्दुअंकित पंक्ति हमें यह बताती है कि बिना जीडीपी प्राविधिकी बदलाव के तथा अधिक आवश्यक रूप से जीडीपी संवृद्धि अनुमान क्या होता यदि भारत में वे सभी घटनाक्रम हुए होते जो देशों में हुए थे। अर्थात् जीडीपी विकास अंशतः भारत एवं नियंत्रित देशों के बीच समान रहा होता। डीआईडी प्रतित्थ्य आसानी से कह दिया जाता है परंतु फिर भी इसमें समान प्रवृत्ति का विकट पूर्वानुमान भरा है। जीडीपी प्राविधिकी अर्ध-परीक्षण में, डीआईडी को यह मान लिया जाता है कि किसी जीडीपी प्राविधिकी बदलाव के अभाव में अध्ययन में नियंत्रक के रूप में

उपयोग किए गए देशों में औसत जीडीपी वृद्धि प्रवृत्ति वही है जैसे कि हमें भारत की जीडीपी अनुमान में रही है। इस पूर्वानुमान को आवश्यकता होती है कि 2011 में “उपचार” से पहले भारत तथा अन्य देशों ने जीडीपी विकास में समानांतर प्रवृत्तियों को पालन किया हो। अगर यह चालू रहता तो तथा भारत प्राविधिकी संशोधन से ‘उपचारित’ नहीं होता तो चित्र 2 अतः यथोचित नहीं होगा। ऐसा तथ्य होते हुए भी कि डीआईडी जीडीपी वृद्धि का अनुमान करने के लिए केवल एक त्रुटिपूर्ण मॉडल है, यह अध्याय तथापि प्राविधिकी की इस विषय पर अन्य अध्ययनों के साथ तुलना करने के लिए चेतावनी के साथ उपयोग में लाता है।

चित्र 1: आदर्श अंतरांतर रूपरेखा में उपचार प्रभाव का चित्रण।



स्रोत: विश्व बैंक डब्ल्यू डीआई डेटा बेस

चित्र 2: डीआईडी को गलत पूर्वानुमान लगाने के लिए त्रुटिपूर्ण मॉडल बनाते हुए भारत तथा अन्य देशों ने 2012 के पहले “उपचार” से पहले समानांतर प्रवृत्तियों का पालन नहीं किया है।



स्रोत: विश्व बैंक डब्ल्यू डीआई डेटा बेस

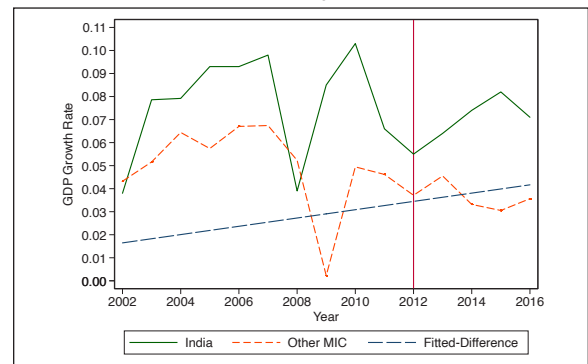
10.12 जीडीपी वृद्धि में गलत अनुमान लगाने के परिणाम को सही तरीके से मापने के लिए मानक डीआईडी मॉडल हेतु अपेक्षित आधारभूत पूर्वानुमान

“समानांतर प्रवृत्ति” पूर्वामान है। जीडीपी प्राविधिकी अर्ध-परीक्षण में, डीआईडी को यह मान लिया जाता है कि किसी जीडीपी प्राविधिकी बदलाव के अभाव में

अध्ययन में नियंत्रक के रूप में उपयोग किए गए देशों में औसत जीडीपी विकास प्रवृत्ति वही होनी चाहिए जैसे भारत की जीडीपी का अनुमान लगाने में होती है। इस पूर्वानुमान को आवश्यकता होती है कि 2011 में “उपचार” से पहले भारत तथा अन्य देशों ने जीडीपी विकास में समानांतर प्रवृत्तियों का पालन किया था अगर यह चालू रहता तो भारत प्राविधिकी संशोधन से उपचारित नहीं होता। केवल इसके पश्चात् हम बराबर तुलना कर सकते हैं। यदि समानांतर प्रवृत्ति पूर्वानुमान का उल्लंघन होता है तो फिर मानक डीआईडी वर्तमान समस्या के लिए उपयुक्त उपकरण नहीं है। (समानांतर प्रवृत्ति पूर्वानुमान के चित्रण के लिए बाक्स 2 देखें)

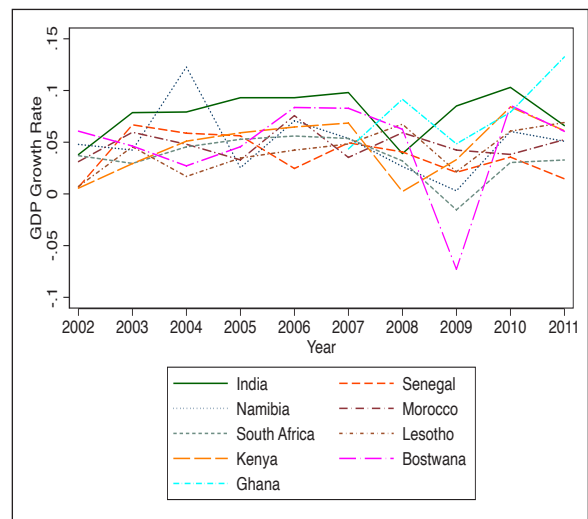
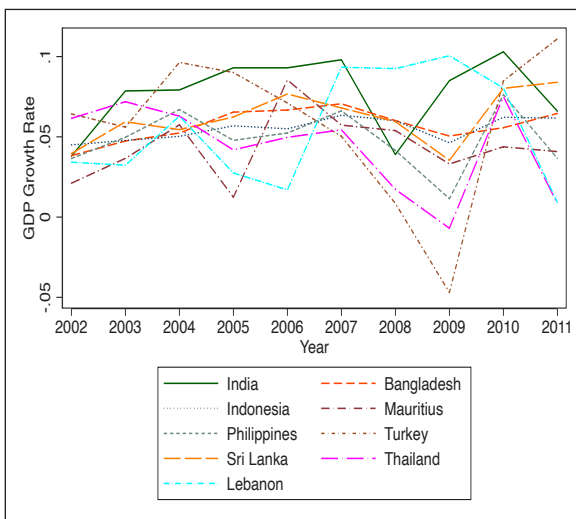
10.13 चित्र 3 को पूर्णानंदम (2019) से लिया गया है जो क्रमशः दो पैनल में तुलना करता है (क) सभी अन्य प्रतिदर्श देशों के साथ भारत का संवृद्धि वक्रपथ (ख) प्रतिदर्श में अन्य मध्य आय देशों के औसत के साथ भारत का वक्रपथ। चित्र 4 प्राविधिकी बदलाव के वर्ष, 2011-12 तक से अन्य मध्य आय देशों की तुलना में भारत के वक्रपथ को दर्शाता है। सभी चार्ट यह स्पष्ट करते हैं कि भारत तथा अन्य देशों ने 2011 से पहले संवृद्धि में समानांतर प्रवृत्ति का पालन नहीं किया था। यहां तक कि जब अन्य एशियाई मध्य आय देशों (चित्र 4 का प्रथम पैनल) से तुलना की जाती है तो हम समानांतर प्रवृत्ति देखने में असफल रहते हैं। परिवर्तन

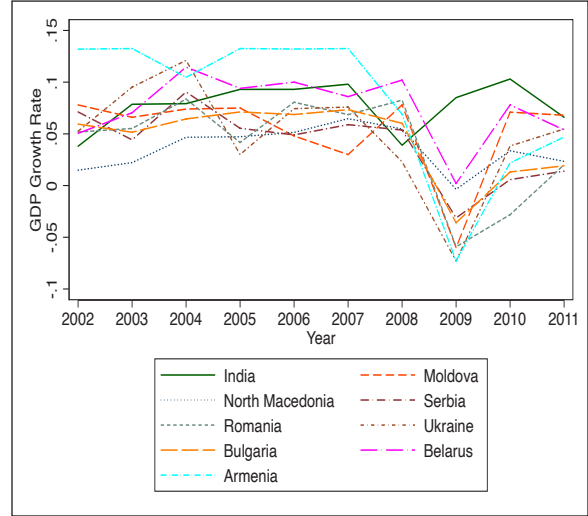
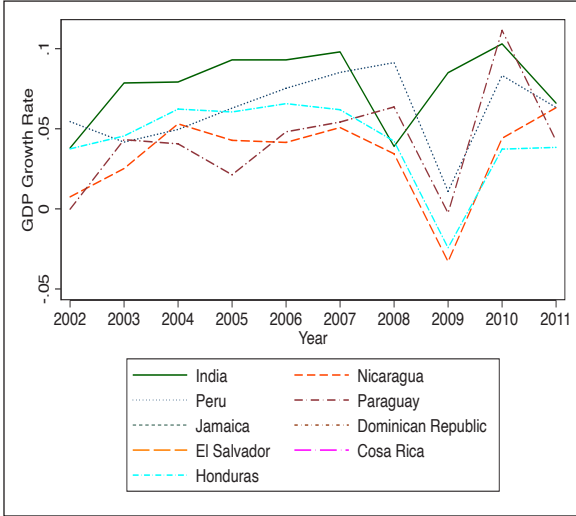
चित्र 3: 2011 से पहले भारत एवं अन्य देश समानांतर जीडीपी प्रवृत्ति का अनुपालन नहीं करते हैं



स्रोत: पूर्णानंदम (2019)

चित्र 4: भारत और अन्य मध्य आय देश, 2011 से पहले जीडीपी विकास में समांतरता का पालन नहीं





Source: World Bank WDI Database.

न सिर्फ उपचार तथा नियंत्रित समूह के बीच है बल्कि नियंत्रित समूह के भीतर भी परिवर्तन है।

10.14 एक मानक डीआईडी मॉडल से कोई भी निष्कर्ष प्राप्त करने हेतु समानान्तर रुझानों का पूर्वानुमान लगाना महत्वपूर्ण होता है। तथापि जैसा कि आंकड़ों से स्पष्ट होता है भारत 2011 से पूर्व अन्य देशों की तुलना में किसी समानान्तर रुझान का अनुसरण नहीं करता अतः किसी कार्य-पद्धति में संशोधन न होने से ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि भारत 2011 के बाद भी समानान्तर रुझान जारी रखता और परखे गए डीआईडी (2011 संशोधन का परिशोधन प्रभाव) को सावधानी से उपयोग में लाना चाहिए।

10.15 अन्य चुनौती है स्वतंत्र चर का चुनाव है। चूंकि जीडीपी एक अत्यंत जटिल तथ्य है जो कि सापेक्ष और निरपेक्ष तौर पर बहुत से सामाजिक-आर्थिक कारकों से प्रभावित होता है जिनमें से कुछ को मापा जा सकता है और अधिकांश का मापन नहीं किया जा सकता। ऐसे में छोड़े गए चर के पूर्वाग्रह का अधिक खतरा है। इस मुद्दे पर हम अगले खंड में विचार करेंगे।

10.16 प्रशोधन और नियंत्रण के बीच एक समानान्तर रुझान की कमी साथ ही विलोपित चर पूर्वाग्रह की संभाव्यता, मानक डीआईडी कार्य-प्रणाली को कि क्या भारत का जीडीपी का गलत अनुमान लगाया गया है कि नहीं? यह आंकलन करने के लिए एक दोषयुक्त उपकरण बनाता है। तथापि यदि शुरू करें तो जैसा कि सुब्रामणियन (2019) में कार्यान्वित किया गया एक मानक डीआईडी मॉडल को एक आधार के रूप में

मानते हैं। हम इसे अन्य अध्ययनों, जैसे कि सुब्रामणियन (2019), के साथ तुलना के लिए करते हैं। बाद के खंडों में हम इन सीमाओं से पार पाने के लिए मॉडल समायोजित करने के तरीके का पता लगाएंगे।

10.17 हम निम्नांकित क्रॉस-सैक्शनल प्रतीपगमन का दो बार अनुमान लगाते हैं, एक बार बदलाव-पूर्व अवधि के लिए और एक बदलाव बाद की अवधि हेतु:

$$g_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \theta \text{India}_i + \varepsilon_i$$

आश्रित चर अवधि T में देश i की वास्तविक जीडीपी बढ़त दर है। स्वतंत्र चर में निर्यातों, आयातों और निजी क्षेत्र में क्रेडिट और साथ ही साथ भारत हेतु प्रतिरूप चर के रूप में शामिल है। प्रत्येक देश हेतु लगातार चरों को पहले अनुमान हेतु बदलाव पूर्व वर्षों और द्वितीय अनुमान हेतु बदलाव पश्चात वर्षों पर औसत किया गया। रूचि का गुणांक भारत प्रतिरूप चर है। बदलाव-पश्चात विशिष्टीकरण और बदलाव-पूर्व के गुणांक में अंतर से बदलाव-पश्चात की अवधि में गलत अनुमान की विशालता का पता चलता है।

10.18 दो पूल किए उपरोक्त क्रॉस-सैक्शनल प्रतीपगमन निम्न रूप से एक विशिष्टता में जोड़े जा सकते हैं:

$$g_{iT} = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_1 X_i \times T + \theta_1 \text{India}_i + \theta_2 \text{India}_i \times T + \gamma T + \varepsilon_{iT}$$

इस मॉडल में प्रशोधन अवधि T द्वारा दर्शाई जाती है जो बदलाव पश्चात अवधि हेतु एक के बराबर और बदलाव-पूर्व अवधि हेतु शून्य के बराबर होता है। रूचि का चर अब 02 है जो भारतीय जीडीपी के

बदलाव-पश्चात दोषपूर्ण-अनुमान के स्तर को दर्शाता है। 10.19 तालिका 1 में परिणाम दर्शाया गया है। इस मूलभूत विशिष्टता का उपयोग करते हुए हम यह पाते हैं कि भारत का जीडीपी 2.77 प्रतिशत अंकों से अधिक दर्शाया गया है। हमारे परिणाम सुब्रमणियन (2019) के परिणामों की झलक दे रहे हैं जो कि 2.5 प्रतिशत

का अधिक अनुमान पाते हैं। हम अब इस मॉडल से जुड़े मुद्दों और समायोजनों को कार्यान्वित करने पर विचार करने की ओर बढ़ते हैं। हम यह पाते हैं कि इन समायोजनों के बाद एक दोषपूर्ण रूप से अनुमानित जीडीपी के पक्ष में साक्ष्य वैचारिक तौर पर कमजोर हो जाता है।

तालिका 1 क्रॉस-देशीय स्तर डीआईडी मॉडल को अपनाते हुए असामान्य संवृद्धि का आकलन

आश्रित चर औसत जीडीपी विकास	2002-11	2012-16	एकत्रित
भारत	0.0092** (2.4151)	0.0369*** (15.7342)	0.0092** (2.4151)
भारत x बदलाव पश्चात			0.0277*** (6.1757)
बदलाव पश्चात			0.0042 (1.0690)
निर्यात वृद्धि दर	0.0929* (1.9697)	0.0805** (2.1591)	0.0929* (1.9697)
आयात वृद्धि दर	0.1856*** (3.3672)	0.0225 (0.6245)	0.1856*** (3.3672)
साख वृद्धि दर	0.0632*** (3.3336)	0.1892*** (6.4593)	0.0632*** (3.3336)
निर्यात वृद्धि x बदलाव पश्चात			-0.0125 (-0.2075)
आयात वृद्धि x बदलाव पश्चात			-0.1631** (-2.4767)
साख वृद्धि x बदलाव पश्चात			0.1260*** (3.6123)
निरंतर	0.0139*** (4.3905)	0.0181*** (7.7800)	0.0139*** (4.3905)
टिप्पणी	95	95	190
आर ²	0.5323	0.5304	0.5443

टिप्पणी: कालम 1 और 2 निम्नलिखित क्रॉस-सैकशनल प्रतीपगमन का आकलन: $g_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \theta India_i + \epsilon_i$ प्रत्येक देश के लिए प, कॉलम 1 और 2 में क्रमशः 2002-11 और 2012-16 के समयावधि में आश्रित और स्वतंत्र चर औसत रहे। कॉलम 3 में दोनों अवधियों टिप्पणियों को एकत्र किया गया है¹ और निम्नलिखित प्रतीपगमन: $g_{iT} = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i \times T + \theta_1 India_i + \theta_2 India_i \times T + \gamma T + \epsilon_{iT}$. g_i देश के लिए 2002-11 अथवा 2012-16 अवधि के दौरान वृद्धि दर समान है। यदि T परिवर्तन पश्चात् अवधि के लिए 1 के समतुल्य है तो यही परिवर्तन पूर्व अवधि में शून्य होगा। भारत के लिए 1 और अन्य देशों की स्थिति में यह शून्य होगा T सांख्यिकी कोष्ठक में दी गई है। *, ** और *** क्रमशः 10% 15% और 1% से महत्वपूर्ण स्तरों का सूचक है।²

3. इस तालिका में और अन्य कहीं सूचित मान त्रुटियां, यदि अन्यथा स्पष्टतया वर्णित न हो, बिखरी हुई है क्योंकि एक सुदृढ़ सहचरण मैट्रिक्स की गणना करने हेतु शोधन समूह (एक देश मात्र) का छोटा आकार अनुपयुक्त है। सुब्रमणियन (2019) अपनी कुछ विशिष्टताओं में सामूहिक मानक त्रुटियों की सूचना देते हैं तो कि शोधा न समूह में अत्यन्त छोटी संख्या को देखते हुए उपयुक्त नहीं होगा। (देखें कैमरून, गैलवाच और मिलर (2008); कैमरून और मिलर (2015))

सहविचरों में चुनाव: हटाए गए पूर्वाग्रह से निपटने हेतु एक सामान्यीकृत डीआईडी

10.20 एक प्रतीगमन मॉडल में महत्वपूर्ण चर का लोप होने से हटाए गए चर पूर्वाग्रह की स्थिति आ जाती है (देखें बाक्स 3) उदाहरण के तौर पर ऊपर प्रयुक्त प्रतीगमन में महत्वपूर्ण कृषि और सेवा संबंधी संकेतकों और साथ ही साथ अन्य अप्रत्यक्ष कारकों को भी शामिल नहीं किया गया है जो जीडीपी बढ़त को प्रभावित कर सकता है। हटाए गए परिवर्तनशील पूर्वाग्रह के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए हम स्वतंत्र परिवर्तनकारी तत्वों के विविध संयोजनों का अपने प्रारंभिक आधारभूत मॉडल के साथ पुनः आंकलन करते हैं।

$$g_{iT} = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i \times T + \theta_1 India_i + \theta_2 India_i \times T + \gamma T + \varepsilon_{iT}$$

विशेषकर मौजूदा कोवेरिएटों के अतिरिक्त - आयात-निर्यात और ऋण में रियल ग्रोथ - वृषि रियल ग्रोथ स्मिलरर ग्रोथ और सेवाओं में रियल ग्रोथ जो मॉडल में जोड़ा गया है। तालिका 2 में परिणाम दिए गए हैं। कॉलम/यह दर्शाता है कि बेस लाइन आकलन में पर्व में जिसमें भारत की जीडीपी विकास को 2.77

प्रतिशत बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया गया है। कॉलम 2 में मॉडल में रियल सेवाओं के विकास को शामिल किया गया है जिसमें 1.18 प्रतिशत के निम्नतर गलत आकलन को दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त इस मामले में ब्याज को गुणाक ही इसे महत्वपूर्ण रूप से क्षीण करता है जिसके कारण गलत आकलन से 3.6 प्रतिशत जीडीपी गिर गई। कॉलम 4 में कृषि एवं सेवाओं के विकास को शामिल किया गया है जिसके कारण गलत आकलन से जीडीपी 1.1 प्रतिशत और गिर गई। अंतिम कॉलम के मॉडल में केवल कृषि एवं सेवाओं के संकेतक है और गलत आकलन के स्तर को नकारात्मक करता है।

10.21 तालिका 2 का उद्देश्य गलत आकलन के स्तर के परिशुद्ध आकलन को प्रदान करना नहीं है हालांकि मॉडल में प्रयोग किए थोवारियेटस के चयन की टिप्पणियों की अत्यधिक गंभीरता की व्याख्या करता है। स्पष्ट रूप से बेसलाईन मॉडल केवल तीन थोवारियेटस में साथ महत्वपूर्ण रूप से अत्याधिक आकलन के स्तर का अत्यधिक आकलन करता है।

बॉक्स 3: प्रतिगमन मॉडलों में विलोपित पर पूर्वाग्रहों पर एक नोट

प्रतिगमन एक सांख्यिकीय तकनीक है जिसे यदि सही रीति से किया जाए तो यह चरों के प्रभावों को हटाने या उसे नियंत्रित करके अन्य वस्तुओं को बराबर करने का एक तरीका है (जैसाकि सेवाओं, उद्योग और अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्रों से प्राप्त संकेतक) जो कि आश्रित चर से संबंधित है (जैसेकि जीडीपी बढ़त दर)। कोई भी जीडीपी बढ़त दर पर जीडीपी प्रक्रिया विधि परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभाव में रूचि रख सकता है और ना कि विशेषतः अर्थव्यवस्था के सेवाओं, उद्योग और कृषि क्षेत्रों से आए चरों पर। लेकिन समानता केवल नियंत्रणों के रूप में शामिल चरों हेतु ही स्थापित किया जाता है। पर्याप्त नियंत्रणों अथवा सही नियंत्रणों को शामिल चरों हेतु ही स्थापित किया जाता है पर्याप्त नियंत्रणों अथवा सही नियंत्रणों को शामिल कर पाने में असफलता से प्रतिगमन से पूर्वाग्रह युक्त परिणाम प्राप्त होता है। परिव्ययों का यही पूर्वाग्रह विलोपित चर पूर्वाग्रह (ओवीबी) कहलाता है।

माना कि निम्नांकित “छोटे प्रतिगमन में या तो पर्याप्त नियंत्रण नहीं है या सही नियंत्रण नहीं है।

$$GDP = \alpha_S + \beta_{1S} X_1 + \beta_S X_{India} + \varepsilon_S$$

जहां जीडीपी किसी वर्ष में किसी देश में जीडीपी बढ़त को दर्शाता है, छोटे प्रतिगमन का अवरोधन है, β_{1S} को प्रतिगमन गुणाक है, X_1 , X_1 ‘छोटे’ प्रगमन में स्वतंत्र चरों का वाहक है। उदाहरणार्थ औद्योगिक संकेत और तदनुसार जीडीपी बढ़त

हेतु वहां पर्याप्त/सही नियंत्रण नहीं होता। जीडीपी बढ़त दर पर जीडीपी कार्य पद्धति परिवर्तन से अनुमानित कारणगत प्रभाव है π पदकंप भारत त्रुटिगत पारिभाषिक 2015 है। अब यदि हम माने कि निम्न 'लंबा' प्रतिगमन इस प्रकार से चलाया जाए कि उनमें पर्याप्त/सही नियंत्रण हों:

$$GDP = \alpha_L + \beta_{1L}X_1 + \beta_{2L}X_2 + \beta_L X_{India} + \varepsilon_L$$

जहां α_L लंबे प्रतिगमन का अवरोधन है, β_{2L} का प्रतिगमन गुणांक है, X_1, X_2 विलोपित नियंत्रणों का वाहक है, β_L जीडीपी बढ़त दर पर जीडीपी कार्य पद्धति परिवर्तन का अनुमानित कारणगत प्रभाव है, और ε_L शेष होता है।

विलोपित चरों के कारण कार्य पद्धति परिवर्तन से जीडीपी बढ़त दर के अनुमान में पूर्वाग्रह है।

$$OVB = \beta_S - \beta_L = \pi_1 \beta_{2L}$$

जहां π_1 निम्न प्रतिगमन का गुणांक है:

निम्न विवरण विलोपित चर पूर्वाग्रह के दिशा को सारगर्भित करता है। आश्रित चर है जीडीपी, X_1 और X_2 स्वतंत्र चर है, और X_2 विलोपित चर है।

	X_1 और X_2 धनात्मक रूप से सहसंबंधित है	X_2 और X_1 ऋणात्मक रूप से सहसंबंधित है
X_2 का जीडीपी पर धनात्मक प्रभाव है	धनात्मक पूर्वाग्रह	ऋणात्मक पूर्वाग्रह
X_2 का जीडीपी पर ऋणात्मक प्रभाव है	ऋणात्मक पूर्वाग्रह	धनात्मक पूर्वाग्रह

उदाहरणार्थ सुब्रह्मनियन (2019) द्वारा किए गए शोध के संबंध में जिसका उद्देश्य वास्तविक आर्थिक गतिविधि के संकेतकों का उपयोग कर जीडीपी बढ़त को स्पष्ट करना है, हाल ही में आर्थिक सलाहकार परिषद ने लिखा, "संकेतकों पर एक सरसरी निगाह डालने पर उद्योग संकेतकों के साथ एक मजबूत संबंध का पता चलता है जो भारत के जीडीपी पर औसत 22 प्रतिशत का योगदान करता है, जबकि सेवाओं (जीडीपी का 60 प्रतिशत) और कृषि (जीडीपी का 18 प्रतिशत) का प्रतिनिधित्व ना होने के बराबर ही है। यह मानना बहुत कठिन है कि सेवा क्षेत्र के संकेतक भारतीय जीडीपी के साथ संबंध नहीं रखते।" (प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद, 2019)

उपर्युक्त विश्लेषण में X_1 विनिर्माण संबंधी संकेतकों को दर्शाता है और X_2 सेवाओं और कृषि के लीप किए गए संकेतकों को दर्शाता है। उद्योगों के संकेतक सकारात्मक रूप से सेवाओं और कृषि के साथ सहसंबंधित है/इसी प्रकार सेवाओं और कृषि के लोप किए गए संकेतकों से जीडीपी ग्रोथ रेट पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार पूर्वाग्रह के सकारात्मक होने की आशा है। तथापि यह सच है कि जीआरडी/जीडीपी के अत्यधिक आकलन के लिए एक अपरिपूर्ण मॉडल है यह 2.5 प्रतिशत का अत्यधिक आकलन सुब्रह्मनियन (2019) में पाया गया है जो कि अपने आय में विलोपित पूर्वाग्रह के कारण संभावित रूप से अत्यधिक आकलित हुआ क्योंकि व्याख्यात्मक चर (निर्यात, आयात, और ऋण) जीडीपी ग्रोथ में भिन्नताओं के सभी स्रोतों को कवर करता है।

तालिका 2: गलत अनुमान के स्तर पर पूर्वाग्रह के प्रभाव का चित्रण

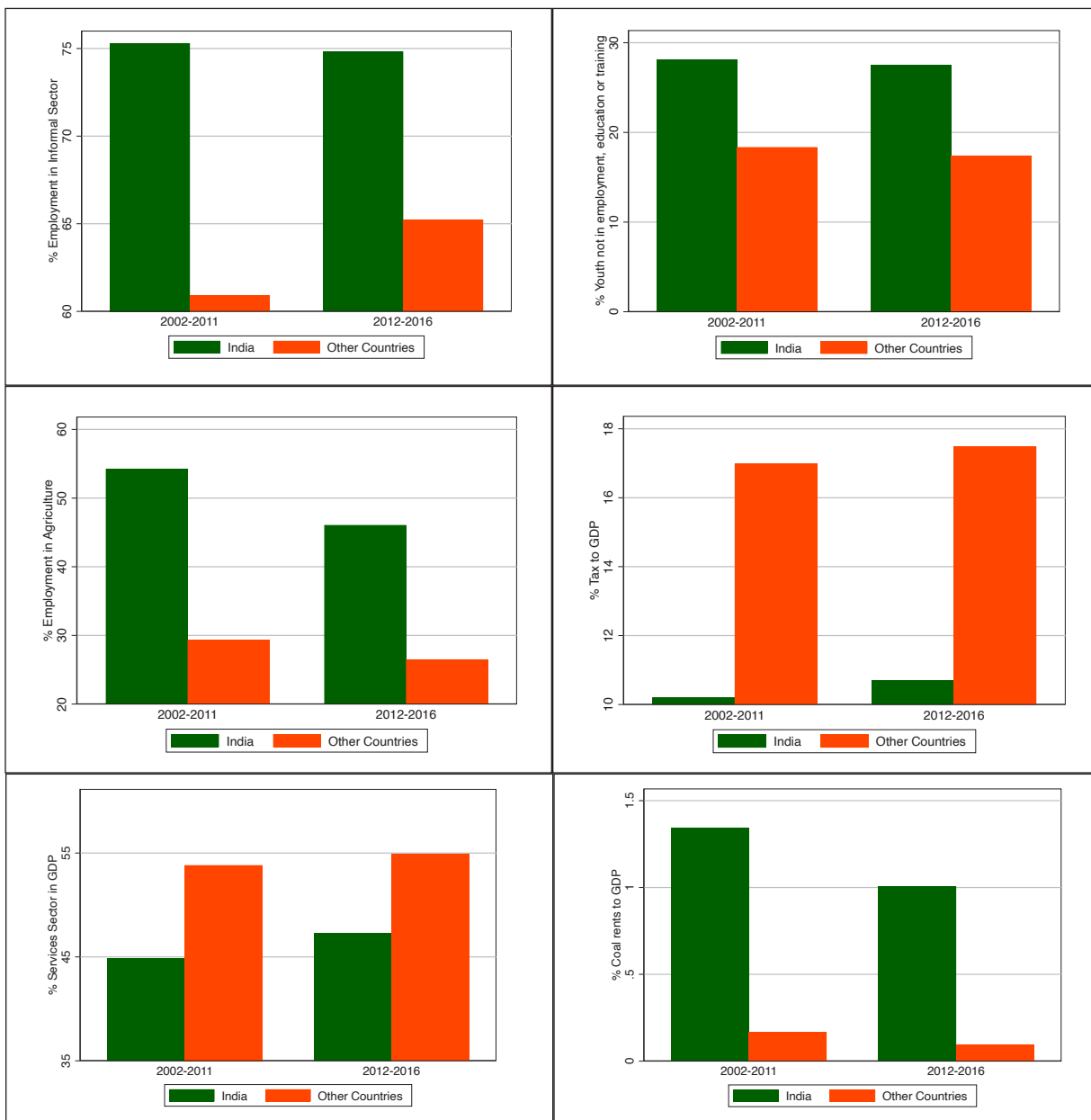
	आधाररेखा	सेवाओं सहित	कृषि सहित	सेवा तथा कृषि दोनों के साथ	निर्यात आयात ऋण अतिरिक्त
भारत x परिवर्तन के बाद	0.0277*** (6.1757)	0.0118* (1.9719)	0.0261*** (5.7183)	0.0112** (2.1128)	-0.0090** (-2.0210)
भारत	0.0092** (2.4151)	0.0059* (1.8999)	0.0087** (2.2617)	0.0066** (2.4470)	0.0173*** (7.4551)
परिवर्तन के बाद	0.0042 (1.0690)	0.0064* (1.9675)	0.0051 (1.3677)	0.0076** (2.4421)	0.0034 (0.8392)
कृषि वृद्धि			0.0022*** (3.8005)	0.0019*** (5.2800)	0.0021*** (4.6917)
सेवा वृद्धि		0.5485*** (8.5362)		0.5094*** (8.5219)	0.6592*** (9.3156)
निर्यात वृद्धि	0.0929* (1.9697)	0.0401 (1.2310)	0.0819* (1.7386)	0.0541* (1.9165)	
आयात वृद्धि	0.1856*** (3.3672)	0.1234*** (2.6379)	0.1991*** (3.3378)	0.1107*** (2.9288)	
ऋण वृद्धि	0.0632*** (3.3336)	0.0125 (0.8320)	0.0377* (1.9493)	0.0010 (0.0758)	
कृषि वृद्धि x परिवर्तन के बाद			-0.0004 (-0.4541)	-0.0006 (-1.1001)	-0.0007 (-1.0330)
सेवा वृद्धि x परिवर्तन के बाद		-0.1085 (-0.9346)		-0.1060 (-0.9803)	-0.0728 (-0.6774)
निर्यात वृद्धि x परिवर्तन के बाद	-0.0125 (-0.2075)	0.0024 (0.0449)	-0.0022 (-0.0368)	-0.0090 (-0.1851)	
आयात वृद्धि x परिवर्तन के बाद	-0.1631** (-2.4767)	-0.0965 (-1.5804)	-0.1866*** (-2.6874)	-0.0912* (-1.7305)	
ऋण वृद्धि x परिवर्तन के बाद	0.1260*** (3.6123)	0.0720** (2.0397)	0.1409*** (4.2821)	0.0847*** (2.6902)	
स्थिर	0.0139*** (4.3905)	0.0026 (1.2230)	0.0106*** (3.4347)	0.0006 (0.2944)	0.0056* (1.9176)
समायोजित अवलोकन	190 0.5443	187 0.7608	190 0.6073	187 0.7962	187 0.7218

नोट: सभी कॉलम निम्नलिखित परिवर्तन का अनुमान लगाते हैं: $g_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i \times T + \theta_1 India_i + \theta_2 India_i \times T + \gamma T + \varepsilon_{it}$. g_i या तो 2002-11 अथवा 2012-16 की अवधि में आई देश के लिए औसत वृद्धि दर जी आई के बराबर है। टी परिवर्तन के बाद की अवधि तथा अन्य शून्य के बराबर है। भारत, भारत के लिए एक तथा सभी अन्य देशों के लिए शून्य के बराबर है। कॉलम मॉडल में उपयोग किये गए सहचरों के चुनाव द्वारा भिन्न है। कोष्ठक में टी-स्टैटिस्टिक्स दी गईं। *, ** तथा *** क्रमशः 10% 5% तथा 1% के विशिष्ट स्तर को द्योतक है।

10.22 छोड़े गए चर पूर्वाग्रह का समाधान इतना सरल नहीं है जितना कि मॉडल में अधिक चर जोड़ना। हजारों सूचक स्वयं को तुरंत प्रतिभागी की तरह प्रस्तुत करते हैं जिनमें से अधिकांश आश्रित चर राशि पर अपना अरैखिक प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए अन्य देशों

की तुलना में, भारत में काफी उच्च अनौपचारिक क्षेत्र रोजगार तथा बड़ी संख्या में नौजवान हैं जो बेरोजगार, अशिक्षित तथा प्रशिक्षण रहित हैं। कृषि का भारत के रोजगार में योगदान का अनुपात असंगत है जबकि जीडीपी में सेवाओं का योगदान असंगत अनुपात में है।

चित्र 5: भारत और अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के बीच संरचनात्मक अंतर



स्रोत: विश्व बैंक डब्ल्यूडीआई डाटाबेस

टिप्पणी: औपचारिक क्षेत्र के रोजगार की हिस्सेदारी कुल गैर-कृषि रोजगार का एक प्रतिशत है। 15 से 24 वर्ष के बीच की आयु के युवाओं में शिक्षा, रोजगार तथा प्रशिक्षण में हिस्सेदारी के अनुपात को दर्शाता है। विश्व बैंक द्वारा बताये गए कोयले के किराए, विश्व कीमतों तथा उत्पादन की कुल लागत पर कठोर तथा कोमल कोयला उत्पादन दोनों की कीमतों के बीच भिन्नता है। यह जीडीपी के लिए प्राकृतिक संसाधन के योगदान के मापदण्ड को दर्शाता है।

10.23 चित्र 5 भारतीय अर्थव्यवस्था अन्य के मध्य से कुछ संरचनात्मक भिन्नताओं को चित्रित करता है। ये सभीचर, निस्संदेह, जीडीपी पर प्रभाव डालते हैं, किन्तु सीधे तौर पर इन्हीं आसानी से मापा नहीं जा सकता अथवा इनकी निगरानी नहीं की जा सकती।

10.24 एक पूर्ण मॉडल को आदर्श के तौर पर, प्रत्येक देश की वृद्धि के विद्रूपतापूर्ण संचालकों को भी ग्रहण करना चाहिए। जैसे, देशों में संस्थागत तथा विधिक संरचनाएं सहज रूप में भिन्न हैं, जो देशों को उस तरह प्रभावित करती हैं जिसे हम सीधे रूप में नहीं माप सकते। पूर्वनन्द (2019) तर्क करते हैं कि इस प्रकार के देश भर में होने वाले प्रतीपगमनों को देशों में ऐसी अनवलोकित विभिन्नताओं के हिसाब से देश विशिष्ट प्रभावों को शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार की विभिन्नताओं को नियन्त्रित करने के उपरान्त, उन्होंने पाया कि उनके मॉडल में 2.4 प्रतिशत का गलत पूर्व अनुमान एक साथ अदृश्य हो गया।

10.25 चित्र सं. 6 2002-16 की अवधि में हमारे प्रतिमान में सभी देशों की औसत वृद्धि दर को दर्शाता है। स्पष्ट रूप से, देश अपनी औसत जीडीपी वृद्धि दर में शानदार विभिन्नताएं दर्शाते हैं। क्योंकि औसत वृद्धि दर बदल जाती है, प्रत्येक देश का आश्रित चर पर भिन्न औसत 'प्रभाव' होता है, जिसे पहले स्थिर किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, औसत वृद्धि दर में भिन्नताएं, देशों के बीच महत्वपूर्ण संरचनात्मक भिन्नताओं का प्रतिनिधित्व करती है, हमारे द्वारा व्यवहार के प्रभाव की जांच किए जाने के बाद ही जिसे निश्चित किया जाना चाहिए। इस मॉडल की उपलब्धियां देश विशिष्ट प्रभावों के साथ-साथ सटीक रूप से यह भी है।- देशों में सभी अनवलोकित भिन्नताएं जो आश्रित चर को प्रभावित कर सकती हैं का विस्तार करके यह औसत वृद्धि दर में होने वाली विभिन्नताओं का हिसाब रखता है। मॉडल में देश विशिष्ट प्रभावों को शामिल करने मात्र से, हम ऐसी अनवलोकित भिन्नता के प्रभाव को अलग कर सकते हैं, जो पूर्वाग्रह का विरोध कर सकते हैं। जिसकी ऊपर चर्चा की गई है, तथा व्यवहार के प्रभाव का निष्पक्ष अनुमान कर सकते हैं।

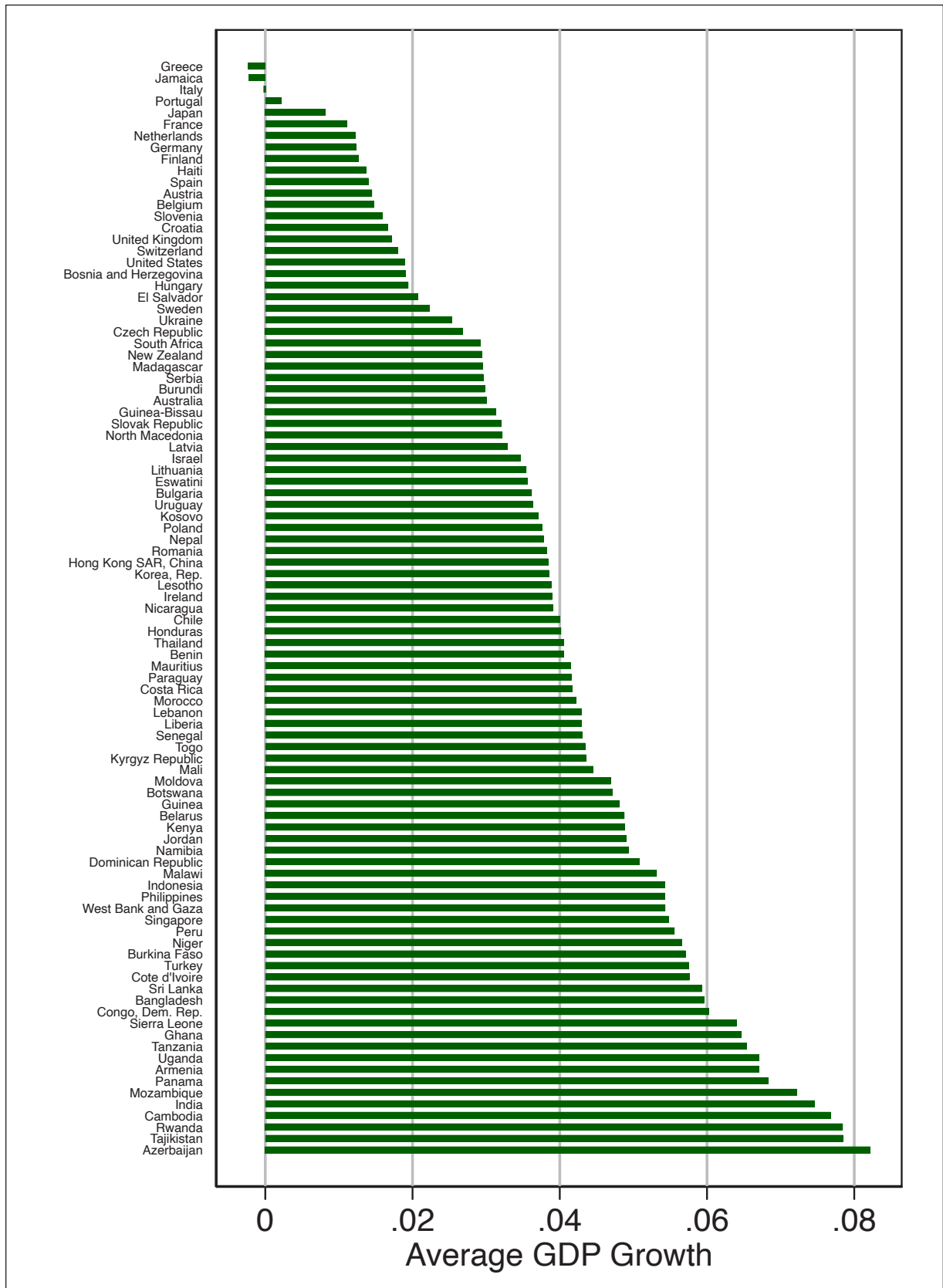
10.26 इसी सिलसिले में, चित्र 7 वर्ष विशिष्ट प्रभावों के मामले को प्रस्तुत करता है। यह चार्ट 2002 से

2016 तक प्रतिवर्ष सभी नमूना देशों की प्रतिनिध्यात्मक औसत जीडीपी वृद्धि को दर्शाता है। यह औसत स्थिर नहीं रहती; प्रति वर्ष, नमूना देशों की औसत जीडीपी वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अलग तरह से होती है। 2009 में, सभी आदर्श देशों की औसत जीडीपी वृद्धि वित्तीय संकट के कारण सबसे नीचे पहुंच गई- एक महत्वपूर्ण तथ्य जिसने सभी देशों को प्रभावित किया तथा इसलिए जिसे हमारे मॉडल में नियन्त्रण के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। वह वर्ष विशिष्ट प्रभाव सभी ऐसे अनवलोकित तथ्यों को नियन्त्रित करेंगे जो दिए गए वर्ष में सभी देशों को प्रभावित करते हैं तथा इस प्रकार विलोपित चर पूर्वाग्रह के अन्य स्रोत का समाधान करते हैं।

10.27 पुर्णानंदम (2019) के साथ सहमति में, देश के लिए निर्धारित प्रभावों को शामिल करने हेतु आधारभूत विनिर्देशों में संशोधन किया गया है और इसके परिणाम सारणी 3 में दिए गए हैं। आधार रेखा के रूप में प्रथम दो कालम निर्धारित प्रभाव के बिना क्रमशः 2002-11 तथा 2012-16 के लिए क्रास सेक्शनल प्रतीपगमन को चित्रित करते हैं। भारत में एक ओर रूचिपूर्ण चर भारत हेतु प्रतिचर है और जो पूर्व प्रदर्शन के अनुसार 2.77% मिथ्या अनुमान को दर्शाते हुए परिवर्तन पूर्व 0.92% से बढ़कर परिवर्तन पश्चात् 3.69% हो गया है। तीसरा कालम, 1 तथा 2 में टीका-टिप्पणी अर्थात् परिवर्तन पूर्व तथा परिवर्तन पश्चात् टीका-टिप्पणियों को सामान्य रूप से मिलाता है जैसे कि ब्याज का गुणांक अब भारतीय प्रतिचर तथा टी, परिवर्तन पश्चात् प्रतिचर के बीच संबंध है। पहले की भांति ही गुणांक ने 2.77% के मिथ्या गुणांक को दर्शाया है।

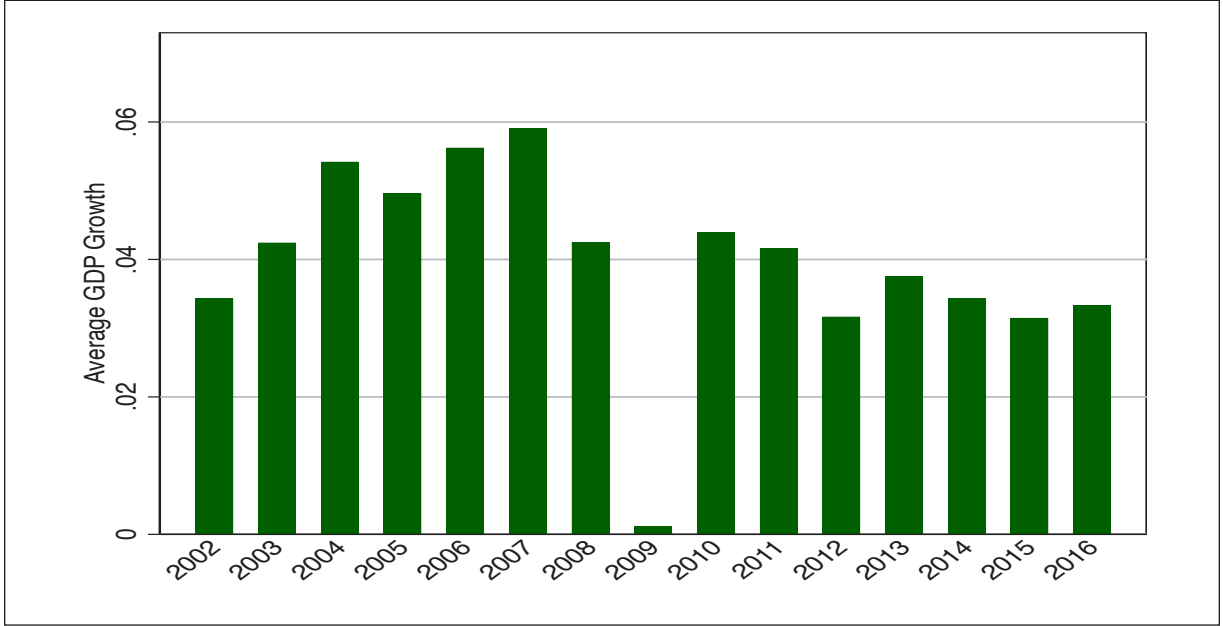
10.28 अंतिम कालम तरजीह वाले विनिर्देश, जिसमें देश विशिष्ट नियत प्रभाव शामिल है, को दर्शाता है, और इस प्रकार सामान्यकृत डीआईडी मॉडल को कार्यान्वित कर रहा है। यहां का भारत परिवर्तन पश्चात् संबंध गुणांक महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। वास्तव में, वृद्धि में पर्याप्त भिन्नता है जिससे भारत की जीडीपी वृद्धि दर पर कुछ साक्ष्य को छोड़ते हुए गलत अनुमानों के सबूत का गलत अनुमान है।

चित्र 6: देशों में औसत जीडीपी वृद्धि में भिन्नता के लिए नियन्त्रण की आवश्यकता।



स्रोत: विश्व बैंक डब्ल्यूडीआई डाटा बेस।

चित्र 7: वैश्विक वृद्धि दरों में भिन्नता के लिए नियन्त्रण की आवश्यकता



स्रोत: विश्व बैंक डब्ल्यूडीआई डाटा बेस।

तालिका 3: विभिन्न देशों में अन्तर के नियंत्रण के साथ और उसके बिना असमान्य वृद्धि का आकलन

प्रतिदर्श का विवरण	2002-11	2012-16	एकत्रित	एकत्रित
क्या अर्थमिति विनिर्देश देशों के बीच अन्तर को नियंत्रित करता है?	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ और अतः ये एक सही मॉडल है
भारत	0.0092** (2.4151)	0.0369*** (15.7342)	0.0092** (2.4151)	
भारत x परिवर्तन पश्चात			0.0277*** (6.1757)	0.0170 (0.9067)
परिवर्तन पश्चात			0.0042 (1.0690)	-0.0009 (-0.3852)
निर्यात वृद्धि दर	0.0929* (1.9697)	0.0805** (2.1591)	0.0929* (1.9697)	0.0500 (1.2545)
आयात वृद्धि दर	0.1856*** (3.3672)	0.0225 (0.6245)	0.1856*** (3.3672)	0.0725** (2.1073)
साख वृद्धि दर	0.0632*** (3.3336)	0.1892*** (6.4593)	0.0632*** (3.3336)	0.0756*** (3.7686)

निर्यात वृद्धि x परिवर्तन पश्चात्			-0.0125 (-0.2075)	
आयात वृद्धि x परिवर्तन पश्चात्			-0.1631** (-2.4767)	
साख वृद्धि x परिवर्तन पश्चात्			0.1260*** (3.6123)	
स्थिर	0.0139*** (4.3905)	0.0181*** (7.7800)	0.0139*** (4.3905)	0.0247*** (7.1371)
अवलोकन	95	95	190	190
R ²	0.5323	0.5304	0.5443	0.6564
स्थिर प्रभाव				देश

टिप्पणी: कॉलम 1 और 2 निम्न लिखित क्रॉस सेक्शनल प्रतिगमन का अनुमान लगाते हैं $g_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \theta India_i + \varepsilon_i$ हर देश i के लिए, आश्रित और स्वतंत्र चर अवधि 2002-11 और 2012-16 के औसत है। कॉलम 3 दोनों अवधि के अवलोकनों का समूहिक करता है और निम्नलिखित प्रतिगमन का अनुमान लगाया जाता है $g_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_i + \beta_2 X_i \times T + \theta_1 India_i + \theta_2 India_i \times T + \gamma T + \varepsilon_{it}$ कॉलम 4 भी परिवर्तन से पहले और परिवर्तन के पश्चात् के आकलन को दिखाता है और देश के स्थिर प्रभावों में शामिल करता है। g_i देश i 2002-16 औसत वृद्धि दर की अवधि के समान है। T परिवर्तन पश्चात् अवधि के लिए समान भारत के लिए एक और अन्य सभी देशों के लिए जीरो के समान करते हैं। t सांख्यिक कोष्टक में उपलब्ध है *, ** और *** क्रमशः 10% 5% और 1% की विशिष्ट स्तर को बताते हैं।

10.29 अपूर्ण मॉडलों की देशों के अन्तर्गत अन्तर को बिना निरोधक के अनुमान की जोखिम को निम्नलिखित प्रयोगों से समझाया गया है। देश के स्थिर प्रभावों के बिना हमारे बेसलाइन ब्यौरे का इस्तेमाल करते हुए हमने यह पाया है कि अनेक देशों ने अपनी जीडीपी को गलत जारी किया है। सारणी 4, इन देशों के सबसैट हेतु परिणाम बताते हैं। तालिका 4 में परिणामों को लेने हेतु अब तालिका 3 के कॉलम 3 और 4 में अब मॉडल विनिर्देशों के साथ भारत की जगह शोधित समूह के रूप में अन्य देशों के साथ पुनःअंतलित किया जाता है। जब मॉडल देश के नियत प्रभावों से बाहर हो जाता है तब कई देश अपनी जीडीपी को बढ़ा चढ़ा कर या कम करके बताते हैं जैसा कि क्रमशः पैनेल क और ख में दिखाया गया है। जब मॉडल में देश के नियत प्रभावों को प्रस्तुत किया जाता है तब अतिकथन या अल्पकथन उसी आकार में लुप्त हो जाता है। ये परिणाम अन्य स्वतंत्र अध्ययनों में भी समान निष्कर्षों पर बल देते आए

हैं, विशेष रूप से भल्ला (2019) जिसने जर्मनी की जीडीपी को “अतिकथन” और जमैका की जीडीपी को ‘अल्प कथन’ पाया है, जैसा कि हम मॉडल देशों के बीच अन्तर को दिखाया है।

10.30 सारणी 5 हमारे सैंपल में सभी देशों के परिणामों को दर्शाती है जहां हमने गलत आकलन को पाया है जो कि नियत प्रभावों को सम्मिलित करने के पश्चात् खत्म हो गया। इन देशों की संख्या हमारे सैंपल के आधे से अधिक है। औसत निरपेक्ष स्तर जो कि गलतवयानी लगती है वह नियत प्रभावों को शामिल करने के पश्चात् कम होती है। वह बड़ा 1.68 प्रतिशत बिन्दु है। नियत प्रभावों की अनुपस्थिति में, कोई भी गलती से यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि नीचे दिए गई सारणी के सभी देशों में, जिसमें उन्नत अर्थ-व्यवस्थाएं जैसे युनाइटेड किंगडम, सिंगापुर, जर्मनी इत्यादि शामिल है, ने अपने जीडीपी अनुमान को त्रुटिपूर्ण तरीके से दिखाया है, जो कि एक अत्यंत असंभावित परिदृश्य है।

4. कुछ देशों के लिए देश के लिए नियत प्रभावों को शामिल करने के बाद भी यद्यपि गुणांक उल्लेखनीय है तथापि वे आकार में धीरे-धीरे घट जाते हैं।

तालिका 4: बिना नियत प्रभावों के अशुद्ध जीडीपी देने वाले देशों और शुद्धिकरण के परिणामों को स्थिर प्रभाव में जोड़ना।

पैनल क: देश के स्थिर प्रभावों के बिना जीडीपी को अतिकथन दिखाने वाले देश

	यूनाइटेड किंगडम		बांग्लादेश		जर्मनी	
	बिना एफ ई (गलत)	एफ ई (सही)	बिना एफ ई (गलत)	एफ ई (सही)	बिना एफ ई (गलत)	एफ ई (सही)
देश x परिवर्तन पश्चात	0.0163*** (4.3289)	0.0131 (0.7077)	0.0389*** (8.7502)	0.0289 (1.5596)	0.0092** (2.4795)	0.0051 (0.2742)
अवलोकन	190	190	190	190	190	190
R ²	0.5298	0.6552	0.5383	0.6624	0.5315	0.6536

पैनल ख:- देश के नियत प्रभावों के बिना जीडीपी को अल्पकथन दिखाने वाले देश

	सिंगापुर		दक्षिण अफ्रीका		बेल्जियम	
	बिना एफ ई (गलत)	एफ ई (सही)	बिना एफ ई (गलत)	एफ ई (सही)	बिना एफ ई (गलत)	एफ ई (सही)
देश x परिवर्तन पश्चात	-0.0226*** (-8.0765)	-0.0229 (-1.2451)	-0.0116*** (-3.6358)	-0.0130 (-0.6997)	-0.0135*** (-4.3818)	-0.0100 (-0.5377)
अवलोकन	190	190	190	190	190	190
R ²	0.5334	0.6592	0.5292	0.6552	0.5335	0.6544

टिप्पणी: प्रत्येक देश के लिए, पहला कॉलम मॉडल का अनुमान लगाता है $g_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} \times T + \theta_1 Country_i + \theta_2 Country_i \times T + \gamma T + \varepsilon_{it}$ दूसरा कॉलम मॉडल का अनुमान लगाता है $g_{it} = \beta_0 + \gamma t + \beta_1 X_{it} + \theta_1 Country_i \times T + \varepsilon_{it}$ जो कि देश के नियत प्रभावों में है। परिवर्तन पश्चात् अवधि के लिए T एक के बराबर करता है और परिवर्तन पश्चात् अवधि, में जीरो है। एक से संदर्भ देश में एक बराबर और अन्य देशों के लिए जीरो के बराबर होता है। t- सांख्यिक कोष्ठक में उपलब्ध है। *, ** और क्रमशः 10%, * 5% और 1% के विशिष्ट स्तर को जारी करता है।

तालिका 5: नियत प्रभावों के बिना त्रुटिपूर्ण जीडीपी प्रस्तुत करने वाले देश और देशों के बीच विभिन्नता हेतु नियंत्राणे से निकला सुधार गलत-अनुमान की सही की सही कि गई राशि (गुणांक में अन्तर)

देश	देश x परिवर्तन गुणांक पश्चात				“त्रुटिपूर्ण अनुमान” की राशि में संशोधन (गुणांको में अंतर, %)	
	बिना एफ ई के गुणांक (गलत)	एफ ई के साथ गुणांक (सही)	क्या गुणांक एफ ई मॉडल में महत्व रखता है?	यदि हाँ तो क्या आकार छोटा होगा		
1	बरून्डी	0.0404***	0.0113	नहीं	4.04	
2	बांग्लादेश	0.0389***	0.0289	नहीं	3.89	
3	हंगरी	0.0385***	0.0209	नहीं	3.85	
4	रोमानिया	0.0334***	0.0187	नहीं	3.34	
5	सियरा लियोन	0.0309***	0.018	नहीं	3.09	
6	स्लोवेनिया	0.0255***	0.0138	नहीं	2.55	
7	घाना	0.0229***	0.0021	नहीं	2.29	
8	युनाइटेड किंगडम	0.0163***	0.0131	नहीं	1.63	
9	आयरलैंड	0.0495***	0.0338*	हाँ	हाँ	1.57
10	कोसोवो	0.0152***	0.0103	नहीं	1.52	
11	केन्या	0.0147***	0.0163	नहीं	1.47	
12	मोलडोवा	0.0133***	0.0042	नहीं	1.33	
13	किरगिज गणराज्य	0.0130**	0.0145	नहीं	1.30	
14	गुनिया-बिसाव	0.0123*	0.0208	नहीं	1.23	
15	हैती	0.0116***	0.0185	नहीं	1.16	
16	बुल्गारिया	0.0099**	-0.0006	नहीं	0.99	
17	जर्मनी	0.0092**	0.0051	नहीं	0.92	
18	निकारागुआ	0.0088**	0.0197	नहीं	0.88	
19	सेनेगल	0.0079***	0.0171	नहीं	0.79	
20	स्पेन	0.0076*	0.0021	नहीं	0.76	
21	न्यूजीलैंड	0.0058**	0.0118	नहीं	0.58	
22	नाइजर	0.0598***	0.0551***	हाँ	हाँ	0.47
23	कोनो, डेम, गणराज्य	0.0354***	0.0339*	हाँ	हाँ	0.15
24	अजरबैजान	-0.0515***	-0.0474**	हाँ	हाँ	-0.41
25	हांगकांग एसएआर, चीन	-0.0058**	-0.0099	नहीं	-0.58	
26	फिलिपिन्स	-0.0076**	0.0045	नहीं	-0.76	
27	नामीबिया	-0.0091**	-0.0059	नहीं	-0.91	
28	बोटस्वाना	-0.0094***	-0.0037	नहीं	-0.94	
29	होन्डुरस	-0.0095***	-0.0037	नहीं	-0.95	
30	फिनलैंड	-0.0097***	-0.0092	नहीं	-0.97	
31	जमायका	-0.0101*	0.0096	नहीं	-1.01	

32	सर्बिया	-0.0105***	-0.021	नहीं	-1.05	
33	डामनकिन गणराज्य	-0.0108***	0.0031	नहीं	-1.08	
34	दक्षिण आफ्रीका	-0.0116***	-0.013	नहीं	-1.16	
35	मॉरिशियस	-0.0121***	-0.004	नहीं	-1.21	
36	रवान्डा	-0.0122***	-0.0118	नहीं	-1.22	
37	कास्टारिका	-0.0131***	-0.0058	नहीं	-1.31	
38	बेल्जियम	-0.0135***	-0.01	नहीं	-1.35	
39	बुरकीना फासो	-0.0138**	-0.0078	नहीं	-1.38	
40	श्रीलंका	-0.0146***	-0.0073	नहीं	-1.46	
41	वेस्ट बैंक एवं गाज़ा	-0.0501***	-0.0349*	हाँ	हाँ	-1.52
42	स्लोवाक गणराज्य	-0.0164***	-0.0087	नहीं	-1.64	
43	यूनान	-0.0187***	-0.0164	नहीं	-1.87	
44	नेपाल	-0.0221***	-0.0079	नहीं	-2.21	
45	सिंगापुर	-0.0226***	-0.0229	नहीं	-2.26	
46	पेरू	-0.0233***	-0.0159	नहीं	-2.33	
47	माली	-0.0241***	-0.0223	नहीं	-2.41	
48	जारडन	-0.0274***	-0.0252	नहीं	-2.74	
49	लेबनान	-0.0281***	-0.0302	नहीं	-2.81	
50	कंबोडिया	-0.0351***	-0.0084	नहीं	-3.51	
51	अरमेनिया	-0.0465***	-0.0306	नहीं	-4.65	

टिप्पणी: प्रत्येक देश के लिए हम दो मॉडलों का अनुमान लगाते हैं, $g_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{it} + \beta_2 X_{it} \times T + \theta_1 Country_i + \theta_2 Country_i \times T + \gamma T + \varepsilon_{it}$ और $g_{it} = \beta_0 + \gamma T + \beta_1 X_{it} + \theta_1 Country_i \times T + \varepsilon_{it}$ देश के स्थिर प्रभावों के बाद वाला और उन के बिना। परिवर्तन पश्चात् अवधि के लिए γ एक बराबर है और अन्यथा जीरो। देश संदर्भ में एक बराबर और अन्य देशों के लिए जीरो के है। निरंतर चर राशि को संपूर्ण और परिवर्तन पश्चात् अवधि में औसत किया जाता है *, ** और क्रमशः 10%, * 5% और 1% के विशिष्ट स्तर को दिखाता है। आखिरी कॉलम पहले अनुमान से गुणकों को सूची बद्ध करता है यदि दुसरे कालम का गुणांक निरर्थक है, यदि दुसरे अनुमान का गुणांक विशिष्ट (कम से कम 10%) हो तो और दोनों गुणांको के बीच का अन्तर है।

पैनल आंकड़ों की गत्यात्मकता: देश के विशिष्ट प्रवृत्ति के लिए एक संशोधित डीआईडी

10.31 हालांकि ऊपर प्रस्तुत किया गया, डीआईडी मॉडल विलुप्त चर पूर्वाग्रह के जोखिम को कम करता है, हमारे वर्तमान नमूने से पूरी तरह संतुष्ट न होते हुए भी, हमें अभी भी समांतर रूझानो की व्यवस्था के साथ संघर्ष करना चाहिए। जैसे कि पूर्णनंदम (2019) में तर्क दिया गया है, अगर यह व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है तो, कम से कम विनिर्देश में एक रूझान रेखा शामिल कर लेनी चाहिए। हमारे बेसलाइन मॉडल एक ट्रेंड लाइन की समावेश के लिए वश्यक यह आ नहीं है, क्योंकि उसकी सिर्फ दो समय सीमा हैं--पूर्व परिवर्तन और

परिवर्तन अवधि, हालांकी, हम ट्रेंड डाययनामिक्स को लागू करने के लिए, हर देश वर्ष को एक व्यक्तिगत अवलोकन मानकर पैनल डेटा विनिर्देश का उपयोग कर सकते हैं।

10.32 पूर्णनंदम (2019) दर्शाते है कि एक पैनल आंकड़ा अनुमान में, देश निश्चित प्रभाव, वर्ष निश्चित प्रभाव, और देश विशिष्ट रूझान, पर अनुभागीय प्रतीपगमन में प्राप्त असामान्य वृद्धि दर की पूरी तरह से देशों के अंतर रूझान लाइनों द्वारा व्याख्या की गई है। टेबल 6 में हम पैनल आंकड़ा पर हमारे संशोधित डीआईडी मॉडल, जो जीडीपी विकास दर को हर देश

वर्ष को एक व्यक्तिगत अवलोकन मानते हुए, पहले के जैसे समान स्वतंत्र चर पुनः हासिल करने का अनुमान लगाते हैं। कॉलम एक निश्चित प्रभाव या देश के रूझान के बिना एक आधार रेखा है। इस कॉलम के परिणामों का सुब्रमणियन (2019) के एक समान पैनेल आंकड़ों के साथ तुलना की जा सकती है, जिसमें सिर्फ एक उल्लेखनीय अंतर है—पश्चकथित अध्ययन परिणामों की पूर्व निर्धारण में संवृद्धि दर के बदले स्तर का उपयोग किया है। लेकिन हम संवृद्धि दर का उपयोग करना चुनते हैं, क्योंकि लेवल में जिन चरों का प्रयोग किया है, वह गैर-स्थिर है। जब चर बढ़ता है स्तरों में

एक प्रतीपगमन सहज परिणाम दे सकता है। (गोयल और कुमार, 2019) हमारे विनिर्देश में नियत गति के बिना बेसलाइन मॉडल भी, परिवर्तन पश्चात भारत के महत्वपूर्ण गुणांक को प्राप्त करने में विफल रहता है।

10.33 इसके अलावा, बेसलाइन पैनेल डेटा विनिर्देशों से देश या वर्ष के निश्चित प्रभावों को शामिल करने से ब्याज के चर गुणांक के आकार को कम करता है, भारत X परिवर्तन पश्चात्। अंततः भारत रूझान अथवा प्रत्येक देश हेतु रूझान का समावेशन होने पर गुणांक ऋणात्मक हो जाता है (यद्यपि फिर भी उतना उल्लेखनीय नहीं है)

Table 6: Estimation of abnormal growth with panel dynamics, including country-specific trends

	स्थिर प्रभाव बिना	देश स्थिर प्रभाव	वर्षिक स्थिर प्रभाव	देश एवं वर्षनियन प्रभाव	देश और वार्षिक स्थिर प्रभाव, भारत में प्रवृत्ति	देश और वार्षिक स्थिर प्रभाव देश के रूझान
भारत बदलाव के पश्चात्	0.0221 (1.4838)	0.0198 (1.4930)	0.0199 (1.3629)	0.0166 (1.3057)	-0.0144 (-0.6535)	-0.0138 (-0.6522)
भारत	0.0193** (2.2456)		0.0209** (2.4765)			
बदलाव के बाद	-0.0006 (-0.3777)	-0.0016 (-1.1147)		0.0022 (0.6384)	0.0019 (0.5477)	-0.0185 (-0.4221)
भारत x इस समय प्रवृत्ति					0.0041* (1.7200)	
निर्यात संवृद्धि दर	0.0670*** (8.1153)	0.0601*** (7.8152)	0.0587*** (7.1055)	0.0471*** (6.2332)	0.0475*** (6.2844)	0.0491*** (6.6301)
आयात संवृद्धि दर	0.0936*** (11.4934)	0.0867*** (11.6266)	0.0839*** (10.3110)	0.0731*** (10.0078)	0.0729*** (9.9931)	0.0703*** (9.5350)
साख संवृद्धि दर	0.0705*** (13.7564)	0.0529*** (10.6660)	0.0645*** (12.5500)	0.0422*** (8.6036)	0.0424*** (8.6377)	0.0355*** (6.8477)
अवलोकन	1349	1349	1349	1349	1349	1349
समायोजित R ²	0.3810	0.5102	0.4050	0.5507	0.5514	0.5897
देश नियत प्रभाव	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
वर्ष नियत प्रभाव	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ
समय रूझान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	भारत	देश

टिप्पणी: हर कॉलम 2002-16 तक के जिन देशों के वार्षिक आंकड़ें लक्षित हैं, का पैनेल आंकड़ों पर प्रतीपगमन विश्लेषण है। कॉलम 1 में कोई निश्चित प्रभाव सम्मिलित नहीं है, कॉलम 11 देश निश्चित प्रभाव, कॉलम 111 वर्ष निश्चित प्रभाव और कॉलम IV दोनों निश्चित प्रभाव। कॉलम 6 दोनों निश्चित प्रभाव और भारत के लिए एक अलग समय रूझान अतिरिक्त शामिल है। आश्रित चर जीडीपी के वार्षिक वृद्धि दर है। टी आंकड़ों में दिए गए हैं। *,** और *** क्रमशः 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के महत्व को दर्शाते हैं।

एक निदानकारी विश्लेषण

10.34 हमारा जीडीपी मॉडल भारतीय जीडीपी के किसी भी गलत अनुमानों को दर्शाने में असमर्थ है। हम इस विश्लेषण का जीडीपी अनुमान पद्धति की किसी कमी को सूचित करने वाली संकेतों की जांच करने हम उपसंहार करते हैं। सुब्रमण्यन एक उपयोगी निदान का प्रयोग करते हैं, जिसमें जीडीपी विकास दर को अन्य संकेतकों, जिन की कार्यप्रणाली में कोई भी बदलाव न हुआ है, के साथ सहसंबद्धित किया है। संक्षेप में, इस कार्यप्रणाली में 'संदिग्ध' चर-संवृद्धि दर को कई अन्य विश्वसनीय चर के साथ सह-संबंध करना शामिल है।

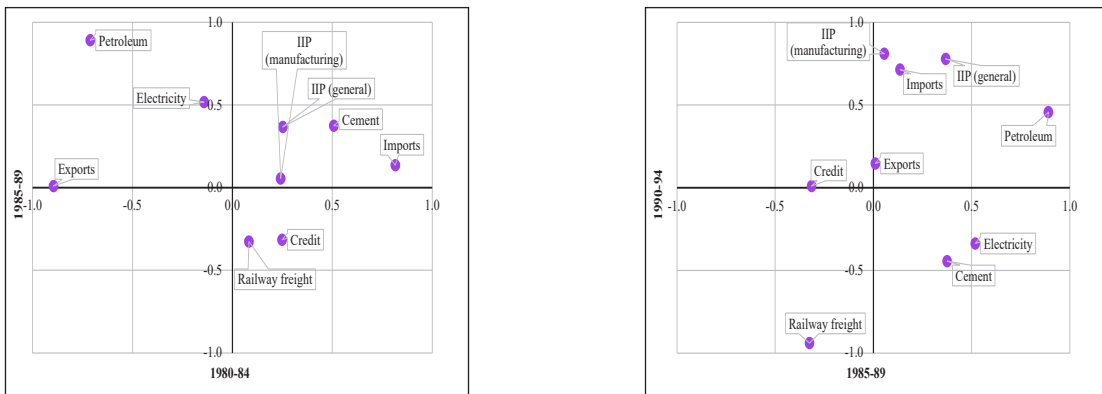
10.35 चित्र 8 1980-84 से शुरू होके पांच सालकी कालावधि के आर्थिक गतिविधियों के कई संकेतों और जीडीपी संवृद्धि दरके बीच के सह संबंध को दर्शाते है। वास्तव में नवीनतम अवधि में आधे से ज्यादा सह संबंध बदलते है। किन्तु संकेतों के लिए 2011 के कार्यप्रणाली संशोधन और उस के परिणामी जीडीपी का गलत-अनुमान करना चाहिए कि 2011 से पहले क्या इन संकेतों का जीडीपी के साथ एक स्थाई और पूर्वानुमेय संबंध रहा है या नहीं। हालांकि, अतीत में, इन संकेतों और जीडीपी विकास दर के बीच का संबंध स्थाई से कोसों दूर रहा है। 2011 के कार्यप्रणाली

संशोधन के पहले भी ये सह-संबंध और नके संकेत बदले है। इन बदलानों को टेबल 7 में सारगर्भित द्वारा है।

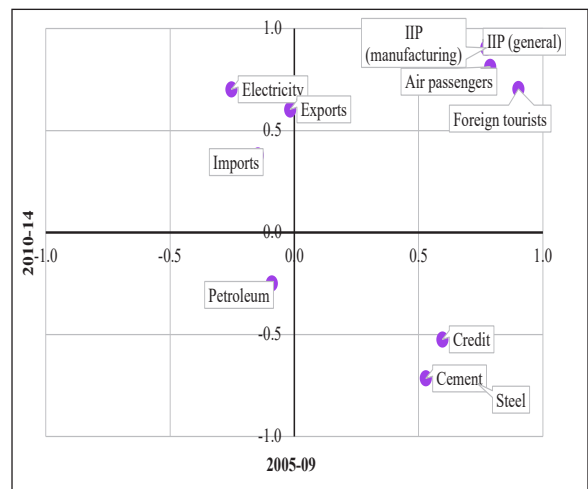
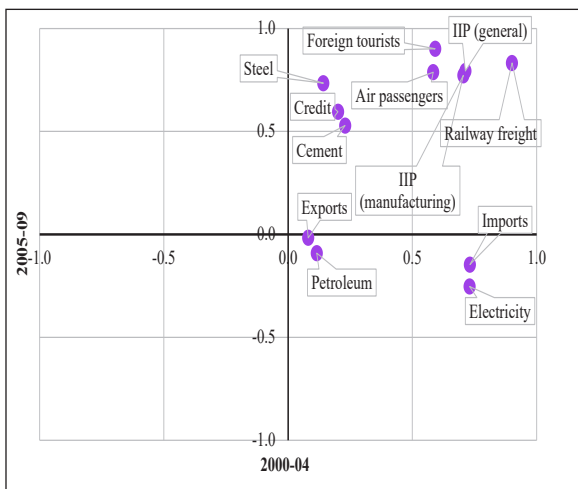
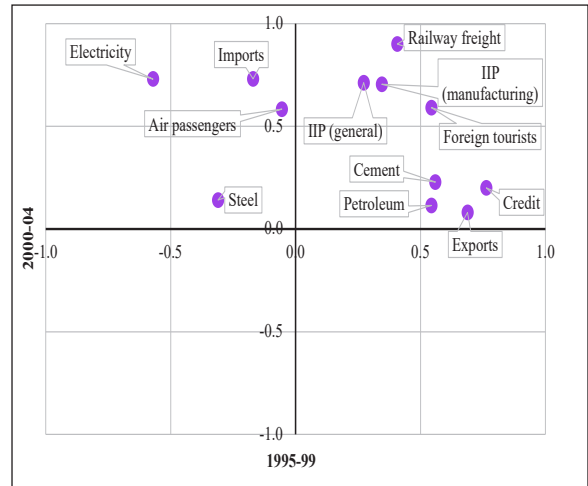
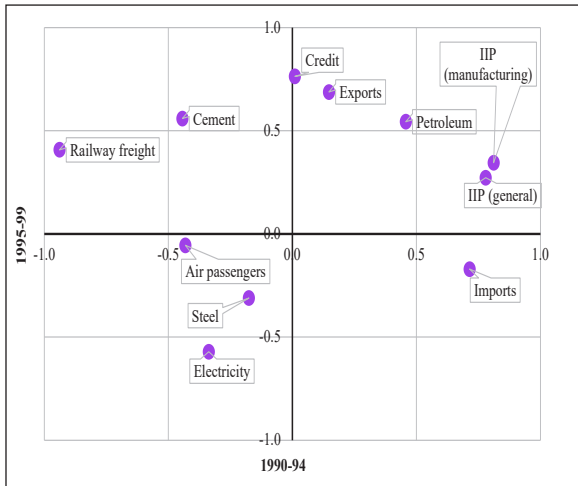
10.36 यदि इन संकेतों 2011 में कार्यप्रणाली संशोधन के बाद सकारात्मक से नकारात्मक से हटकर पूर्व में जीडीपी के साथ एक सकारात्मक संबंध प्रदर्शित करते तो ये लक्षण चिंता का कारण बनते। मगर, इन संकेतकों और जीडीपी वृद्धि के बीच के सहसंबंध पूर्व में जब कार्यप्रणाली संशोधन नहीं हुए थे तब भी पलटने के लक्षण दर्शाते थे।

10.37 उदाहरण के लिए बिजली के उपभोग का जीडीपी के साथ 1980-84 में नकारात्मक सहसंबंध, 1985-89 में सकारात्मक सहसंबंध में नकारात्मक, 2000-2004 में सकारात्मक और 2005-09 में नकारात्मक सह संबंधित किया गया है। समान रूप से वास्तविक निर्यात वृद्धि को जीडीपी के साथ 1980-84 में नकारात्मक, 1985-2004 में सकारात्मक और 2005-09 में नकारात्मक रूप से सहसंबंधित किया गया। स्पष्ट है कि नकारात्मक सहसंबंध गणक अतीत में असमान्य नहीं था। 10 इन सहसंबंधों के मानक विचलन का उपयोग करते हुए, विशिष्ट रूप से दर्शाते है।

चित्र 8: संकेतकों और जीडीपी बढ़त के बीच ऐतिहासिक रूप से सहसंबंधा (सुब्रमणियन (2019) में प्रयुक्त श्रृंखलाओं से मेल खाता है।



5. यह प्रक्रिया सुब्रमणियन (2019) के अनुरूप है जो दो अवधियों: 2001-11 और 2016 में संबंध बनाता है। सुब्रमणियन (2019) में उपयुक्त संकेतक निम्न के विकास दर है: बिजली की खपत, दो पहिया वाहनों की बिक्री वाणजियक की वाहनों की बिक्री, ट्रैक्टर की बिक्री, वायु यात्री यातायात, विदेशी पर्यटकों का आगमन, रेल मालभाडा यातायात, औद्योगिक उत्पादक का सूचकांक, औद्योगिक उत्पादक का सूचकांक (विनिर्माण), औद्योगिक उत्पादक का सूचकांक (उपभोक्ता वस्तु), पेट्रोल खपत, सीमेंट, स्टील, सम्पूर्ण वास्तविक साख, उद्योग में वास्तविक साख, वस्तु और सेवाओं का निर्यात और वस्तु और सेवाओं का आयात



स्रोत: आई एमएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक से जीडीपी विकास, विश्व बैंक डब्ल्यूडीआई डाटाबेस, आरबीआई और संबंधित संघ मंत्रालय डाटाबेस से क्षेत्रवार संकेतक

टिप्पणी: सह संबंध प्रत्येक संकेतों का वास्तविक संवृद्धि दर और वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर के मध्य में संगणित है।

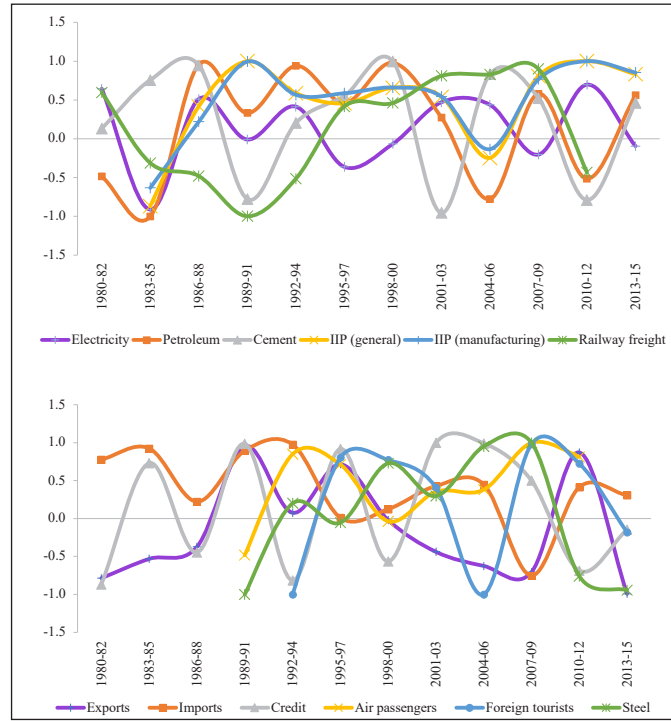
तालिका 7: जीडीपी वृद्धि के साथ क्षेत्रीय संकेतक वृद्धि के सहसंबंध के इतिहास में कई बार पलटने के चिन्हों का साक्ष्य।

क्षेत्रीय संकेत वृद्धि एवं जीडीपी वृद्धि के बीच सहसंबंध के चिन्ह							
संकेतक	1980-84	1985-89	1990-94	1995-99	2000-04	2005-09	2010-14
निर्यात	-	+	+	+	+	-	+
आयात	+	+	+	-	+	-	+
ऋण	+	-	+	+	+	+	-
विद्युत	-	+	-	-	+	-	+
पेट्रोलियम	-	+	+	+	+	-	-
रेलमाल-भाड़ा	+	-	-	+	+	+	-
सीमेंट	+	+	-	+	+	+	-
स्टील	-	-	-	-	+	+	-

स्रोत: आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य से ली गई जीडीपी वृद्धि (सुब्रामणियन (2019) में ली गई श्रृंखला से मेल खाती है, विश्व बैंक डब्ल्यूडीआई डाटाबेस आरबीआई एवं संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के आंकड़ों आंकड़ों से लिए गए क्षेत्रीय संकेतक।

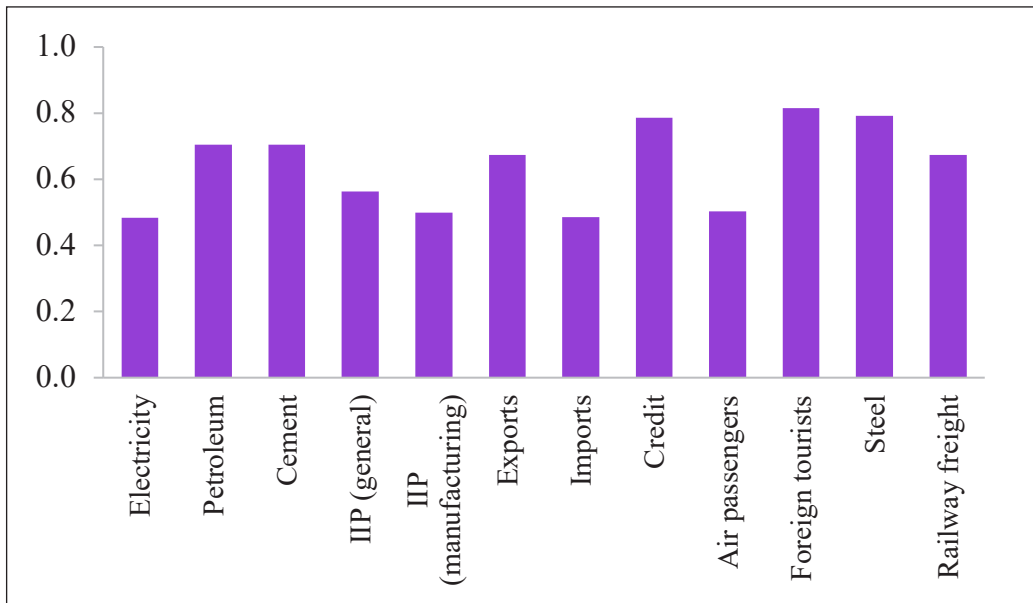
टिप्पणी: 2011 में जीडीपी प्रक्रिया संशोधन से पहले सहसंबंध के विवर्तन के चिन्हों को दर्शाते हुए चिन्हित सैल।

चित्र 9: समय के साथ-साथ जीडीपी वृद्धि एवं क्षेत्रीय संकेतकों के बीच सहसंबंध में भिन्नता



स्रोत: आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य से ली गई जीडीपी वृद्धि (सुब्रमणियन 2019) में ली गई श्रृंखला से मेल खाती है), विश्व बैंक डब्ल्यूडीआई डाटाबेस, आरबीआई एवं संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के आंकड़ों से लिए गए क्षेत्रीय संकेतक।

चित्र 10: संकेतकों एवं जीडीपी वृद्धि के बीच सहसंबंध में उच्च अस्थिरता



स्रोत: आईएमएफ विश्व आर्थिक परिदृश्य से ली गई जीडीपी वृद्धि (सुब्रमणियन 2019) में ली गई श्रृंखला से मेल खाती है), विश्व बैंक डब्ल्यूडीआई डाटाबेस, आरबीआई एवं संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों के आंकड़ों से लिए गए क्षेत्रीय संकेतक।

टिप्पणी: प्रत्येक क्षेत्र के लिए वार्षिक क्षेत्रीय वृद्धि और जीडीपी वृद्धि के बीच सहसंबंध की गणना तीन वर्ष की अवधि: 1980-82, 1983-85 और इसी प्रकार 2013-15 तक में से प्रत्येक वर्ष की गई है। उपयुक्त चार्ट इन बारह सह संबंधों के मानक विचलन को दर्शाता है।

तालिका 8: सुब्रमणियन (2019) संकेतकों द्वारा परिवर्तन पूर्व व्याख्यायित जीडीपी वृद्धि: भारत और अन्य देश

	भारत	मध्यम-आय वाले देश		सभी देश	
	I	II	III	IV	V
निर्यात वृद्धि दर	-0.2009 (-0.7939)	0.0631** (2.1967)	0.0431 (1.4057)	0.0661*** (3.8160)	0.0398** (2.3403)
आयात वृद्धि दर	0.0870 (0.4671)	0.1080*** (4.1062)	0.0747** (2.3428)	0.1054*** (6.4254)	0.0750*** (4.4388)
ऋण वृद्धि दर	0.2077 (0.7735)	0.0598*** (5.2346)	0.0419*** (4.2707)	0.0618*** (6.6422)	0.0392*** (4.8548)
सतत	0.0661** (2.6757)	0.0286*** (10.8528)	0.0312*** (7.6420)	0.0225*** (9.9046)	0.0254*** (6.9846)
अवलोकन	10	364	364	872	872
R²	0.1054	0.4125	0.5813	0.3934	0.6293
देश एफई	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
देश एफई	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
समूहबद्ध	नहीं	देश	देश	देश	देश

टिप्पणी: स्तंभ 1 वर्ष 2002-11 की अवधि के लिए भारत के निर्यात, आयात और ऋण वृद्धि दर पर इसकी जीडीपी वृद्धि में हास दर्शाता है। स्तंभ II विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार सभी मध्यम-आय वाले देशों (भारत को छोड़कर) हास दोहराता है। और स्तंभ IV सैपल में सभी देशों (भारत को छोड़कर) के लिए हास दर्शाता है। स्तंभ III और V क्रमशः स्तंभ II और IV में हास दोहराता है तथा अतिरिक्त रूप से देश और वर्ष के आधार पर नियत प्रभाव शामिल करता है। स्तंभ II और V के जरिए, स्तरीय प्रयास देश द्वारा सुदृढ़ और समृद्ध है। टी-आंकड़े निक्षिप्त वाक्यों में दिए गए हैं। *** और *** क्रमशः 10 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 1 प्रतिशत के महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाते हैं।

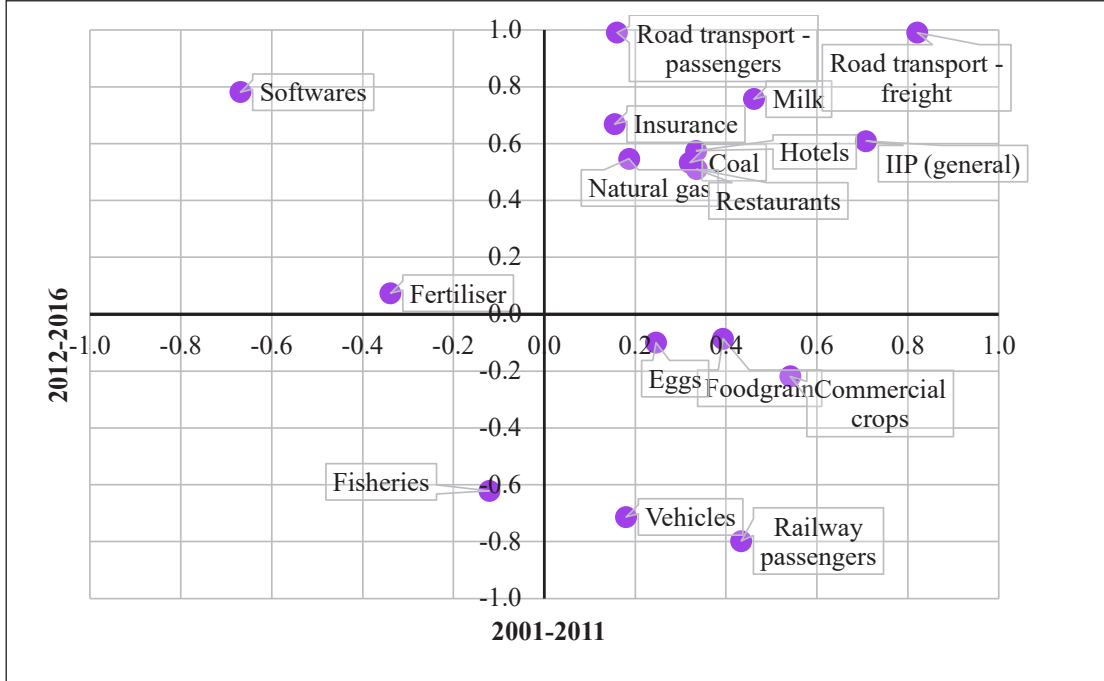
10.38 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये संकेतक 2011 से पहले भी जीडीपी वृद्धि के साथ स्थिर संबंध प्रदर्शित नहीं करते हैं, 2011 के बाद भी उन्हें गलत अनुमान का निदान करने के लिए भी उन्हें भलीभांति तैयार नहीं किया गया है। हम इस परिणाम को अधिक औपचारिक रूप में इस प्रकार से स्थापित करते हैं। 2011 से पूर्व इन संकेतकों की पुर्वाकलन शक्ति की जांच करने के लिए भारत के लिए आयातों, निर्यातों और ऋण में वास्तविक वृद्धि के संबंध में वास्तविक जीडीपी वृद्धि का हास कर देते हैं। तुलना के लिए, हम मध्यम-आय वाले सभी देशों के लिए हास को दोहराते हैं, और अंततः अपने सैपल में सभी देशों के लिए हास को दोहराते हैं। हम केवल 2002 से 2001 तक के ही अवलोकनों को शामिल करते हैं जिससे कि पद्धति पुनरीक्षण से पूर्व संकेतकों की व्याख्यात्मक शक्ति की जांच की जा सके। तालिका में परिणाम प्रस्तुत किए गए हैं।

10.39 यह आश्चर्यजनक है कि इन तीन संकेतकों में से कोई भी संकेतक 2011 से पहले भारत में जीडीपी वृद्धि की व्याख्या करने में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, जबकि अन्य देशों के लिए वे महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं। इसके अलावा, इन संकेतकों द्वारा भारतीय जीडीपी वृद्धि में अंतर के केवल नगव्य 10.5 प्रतिशत की ही

व्याख्या की जाती है। इसके विपरीत, दूसरे देशों के लिए R² 40 प्रतिशत से 63 प्रतिशत के बीच है। परिणाम 2011 से पहले भी भारतीय जीडीपी वृद्धि की व्याख्या करने में इन संकेतकों की असमर्थता की पुष्टि करते हैं। भारत में जीडीपी वृद्धि का तरीका आर्थिक कार्यकलाप के पूर्वाकलन कर सकने वाले कुछ संकेतकों की तुलना में काफी अधिक जटिल है, और इसलिए, इन संकेतकों के आधार पर ही गलत अनुमान का दावा करना उचित नहीं है।

10.40 प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जून, 2019 की अपनी रिपोर्ट में नैदानिक प्रक्रिया में कृषि-और सेवाओं-आधारित संकेतकों के महत्व को उजागर किया है (प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, 2019)। अतः इस बार हम कृषि और सेवा क्षेत्रों से संकेतकों सहित वैकल्पिक संकेतकों के समूह के साथ नीचे एक सहसंबद्ध रेखाचित्र प्रस्तुत करते हैं। हम यह पाते हैं, जैसा कि चित्र 11 में दर्शाया गया है, कि पद्धति पुनरीक्षण से पहले और इसके पश्चात् दोनों ही स्थितियों में अनेक संकेतकों का जीडीपी के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध होता है (इस तथ्य के बावजूद कि इस प्रकार सहसंबंधों की प्रवृत्ति अंतरनिहित रूप से अस्थिर होती है तथा ये केवल जीडीपी के सहज पूर्वाकलक

चित्र 11: अधिकांश कृषि-और सेवाओं से संबंधित संकेतक 2001-11 और 2012-16 में जीडीपी वृद्धि के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध होते हैं।



स्रोत: आईएमएफ वर्ल्ड इकॉनामिक आउटलुक (सुब्रमणियम 2019 में श्रृंखलाओं के अनुरूप) वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूडीआई डाटाबेस, आरबीई से क्षेत्रक संकेतकों, और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय डाटाबेस से जीडीपी वृद्धि।

टिप्पणी: संकेतक निम्नवत परिभाषित किए गए हैं कृषि क्षेत्र के संकेतकों के खाद्यान्नों, वाणिज्यिक फसलों, मत्स्य पालन, दूधा और अंडों के उत्पादन में वार्षिक वृद्धि दरें शामिल हैं। विनिर्माण क्षेत्र के संकेतकों में कोयला, प्राकृतिक गैस, एनएडपी 205 उर्वरक, और आईआईपी (सामान्य) के उत्पादन में वार्षिक दरें शामिल हैं। सेवा क्षेत्र के संकेतकों में निम्नलिखित वार्षिक दरें शामिल हैं: भारतीय रेल पर मौलिक यात्रियों की संख्या, भारतीय सड़क मार्गों पर प्रति किलोमीटर ढोए जाने वाला भार मालभाड़ा, भारतीय सड़क मार्गों पर चलने वाले यात्रियों की प्रति किलोमीटर संख्या, होटल कक्षों की संख्या, भुगतान किया गया सकल बीमा प्रीमियम, सॉफ्टवेयर की बिक्री, तथा रेस्टोरेंट और होटलों पर किया गया खर्च शामिल है।

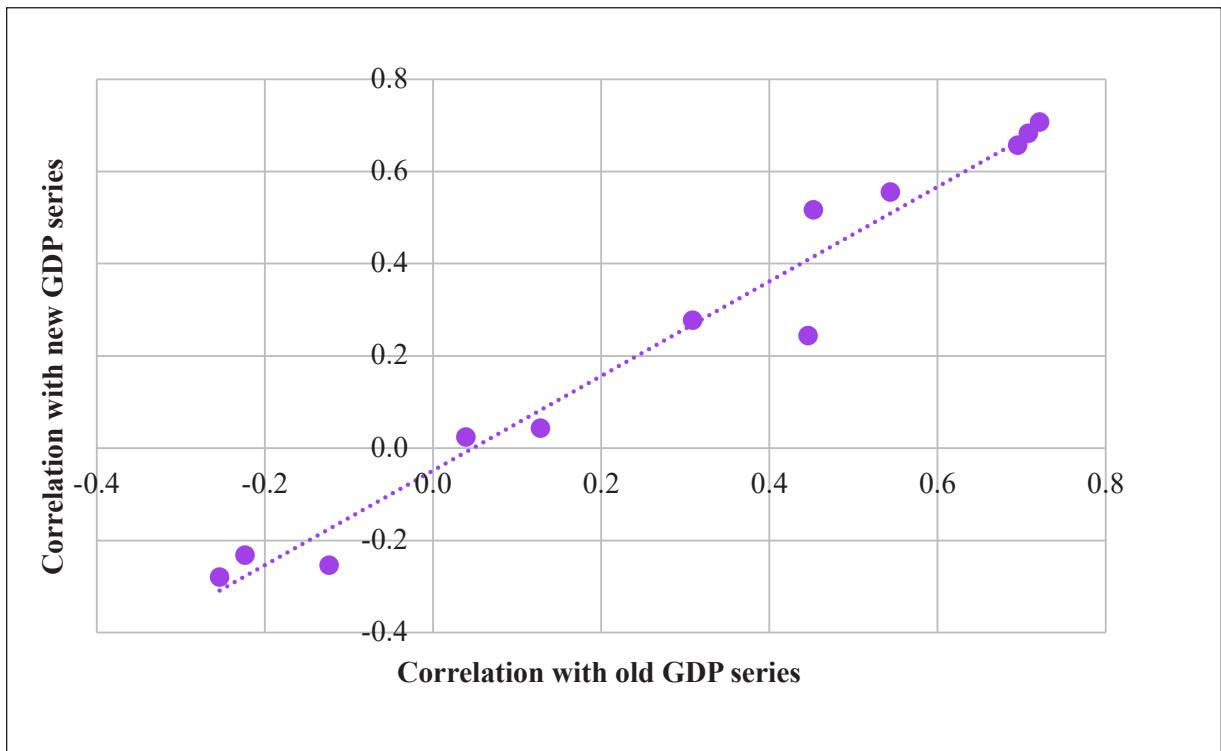
होते हैं)। जैसाकि चित्र 11 में दर्शाया गया है, बहुत से संकेतक जो कार्य पद्धति के संशोधन से पूर्व और पश्चात् जीडीपी के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंधित है (इस तथ्य के बावजूद कि इस प्रकार के सहसंबंध पूर्व से ही अस्थायी होते हैं और जीडीपी के मात्र नौसिखिए अनुमानकर्ता ही है; जैसाकि पूर्व में तर्क किया गया है।

10.41 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आर्थिक कार्यकलाप और जीडीपी वृद्धि के क्षेत्रक संकेतकों के बीच सहसंबंध ऐतिहासिक रूप से अस्थिर रहा है, अधिक उपयोगी निदान पुरानी जीडीपी श्रृंखलाओं के साथ किसी नियत संकेतक के सहसंबंध और नई जीडीपी श्रृंखलाओं के साथ उसी संकेतक के सहसंबंध की तुलना करना है। दोनों मूल्यों में विविधता से नई पद्धति के साथ एक समस्या का संकेत मिलेगा। तथापि, जैसा कि चित्र 12 सुस्पष्ट रूप से दर्शाता है, जीडीपी

के साथ संकेतक का संबंध पद्धति पुनरीक्षण मौटे तौर पर अपरिवर्तित है।

10.42 चित्र 12 यह भी सुझाव देता है कि यदि, 2011 के बजाय, हमने सहसंबंधों में उतार-चढ़ावों के लिए पृथक करने वाली रेखा के रूप में 2010 या 2012 का प्रयोग किया होता, तो हमने पृथक करने वाली रेखा के रूप में 2011 की तरह के ही परिणामों पर पहुंचे होते। वस्तुतः, वैद्यनाथन द्वारा किए गए एक अध्ययन (2019) से यह पता चलता है, “जब हम कागजों में आंकड़ों को एक वर्ष पूर्व पश्चात्: - 2010 से पूर्व और 2010 से पश्चात्, या 2012 से पूर्व और 2012 से पश्चात् में विभाजित करते हैं- तो हमें उतार-चढ़ाव और ऋणात्मक सहसंबंधों के वैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं,” इससे यह पता चलता है कि पद्धति पुनरीक्षण वर्ष, 2011 के बारे में कुछ भी अलंघ्य नहीं है।

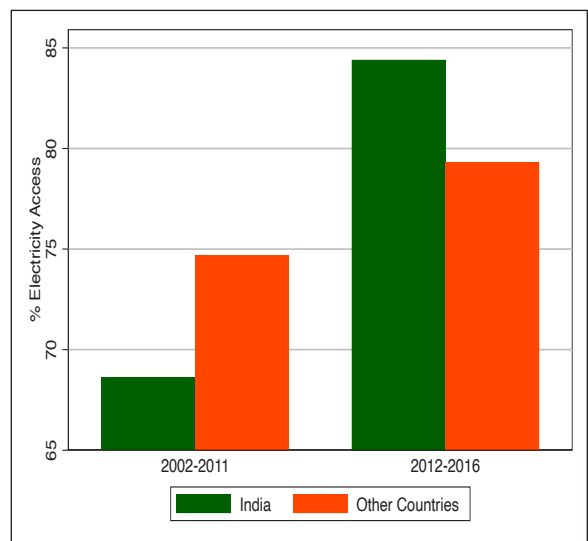
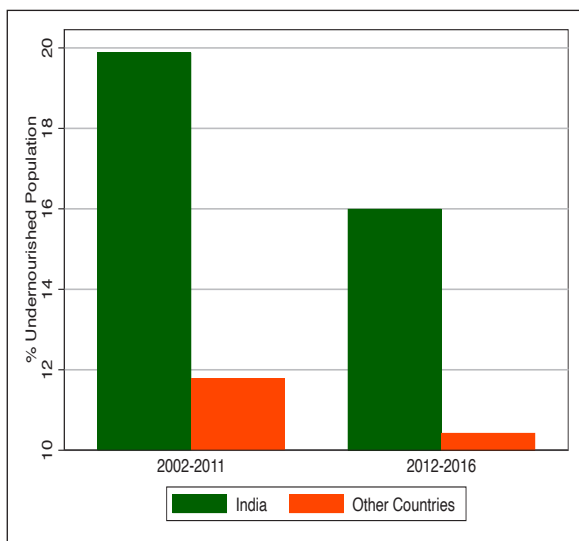
चित्र 12: नई श्रृंखलाओं से समान प्रकार की पिछली जीडीपी श्रृंखलाओं के साथ संकेतकों का संबंध

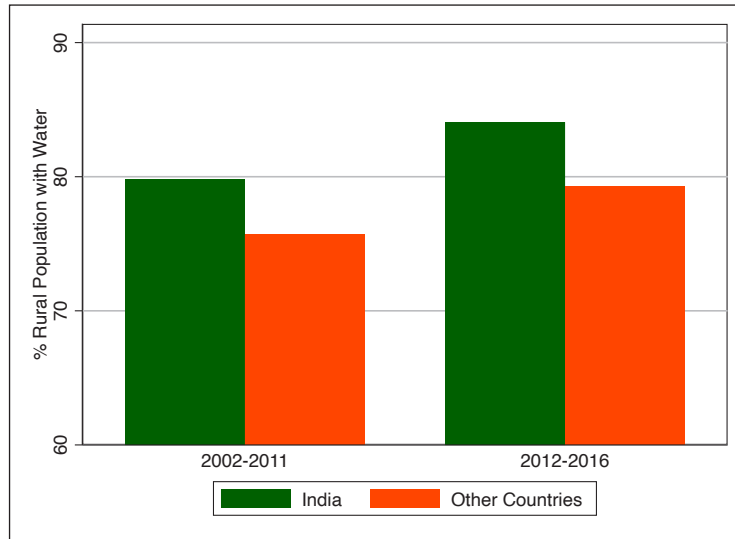


स्रोत: आईएमएफ वर्ल्ड इकॉनामिक आउटलुक (सुब्रमणियन 2019 में श्रृंखलाओं के अनुरूप) वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूडीआई डाटाबेस, आरबीआई से क्षेत्रक संकेतकों, और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय डाटाबेस से जीडीपी वृद्धि।

टिप्पणी: वास्तविक क्षेत्रक वृद्धि और वास्तविक जीडीपी वृद्धि के बीच सहसंबंध की प्रथम गणना वर्ष 2004-05 आधार के साथ पुरानी पद्धति के अंतर्गत जीडीपी वृद्धि का उपयोग करके, इसके बाद वर्ष 2011-12 आधार के साथ नई पद्धति के अंतर्गत जीडीपी वृद्धि के साथ की गई थी। वर्ष 2001-11 के लिए पुरानी और नई दोनों ही श्रृंखलाएं उपलब्ध हैं।

चित्र 13: सामाजिक विकास संकेतक





Source: Purnanandam (2019)

10.43 इस अध्याय का विश्लेषण स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि अधिवर्णित भारतीय जीडीपी के पक्ष में साक्ष्य सही रूप से विनिर्दिष्ट अर्थव्यवस्था के मॉडल में पूरी तरह से विलुप्त हो जाता है। साथ ही, समय के अनुसार भारत की वृद्धि दर के निर्धारकों को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक कार्य किया जाना आवश्यक है। एक उदाहरणात्मक कवायद के रूप में हालांकि इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारत के जीडीपी का वास्तविक ढांचा और वो समय के साथ कैसे परिवर्तित हुआ है, ये स्पष्ट नहीं है। इस महत्वपूर्ण घटना का और अधिक अध्ययन करने की जरूरत है। चित्र 13 पूर्णानन्दम (2019) से लिए गए कुछ संभावित निधियों को दर्शाता है।) भारत ने अनेक सामाजिक विकास संकेतकों, जैसे पोषणाहार और विद्युत, जो परिवर्तन के बाद की अवधि में भारतीय जीडीपी में उच्चतर वृद्धि दर की व्याख्या कर सकते हैं, में महत्वपूर्ण सुधार किया है। तथापि, इसकी जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए कि भारत की जीडीपी का सटीक पैटर्न क्या है और समय के अनुसार विकसित होने से यह स्पष्ट रूप से दूर क्यों है इस महत्वपूर्ण घटना के संबंध में और अनेक अध्ययन किया जाना आवश्यक है।

निष्कर्ष

10.44 यह अध्याय भारत की जीडीपी के आकलन की वास्तविकता के महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार करता है। देश की जीडीपी का स्तर एवं विकास विभिन्न जटिल पहल की जानकारी देता है जो कि अर्थव्यवस्था के आकार

एवं स्वास्थ्य का बोरोमीटर है। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जीडीपी को जहां तक संभव है वास्तविकता से मापा जाए। अभी हाल ही में विद्वानों, नीति निर्धारकों और नागरिकों में इस बात पर बहुत बहस एवं विचार विमर्श हुआ कि क्या आज की जीडीपी का सटीक अनुमान लगाया गया है।

10.45 यदि दोषपूर्ण आकलन के सबूत विश्वसनीय और तगड़े हैं तब क्रांतिकारी आकलन विधि से परिवर्तन करना होगा। हालांकि ऐसे भारी कदम की लागत को देखते हुए यह महत्वपूर्ण होगा कि आकलन विधि को फिर से देखने की जरूरत है। इसी दृढ़ता से इस अध्याय में साक्ष्यों की ध्यानपूर्वक समीक्षा की गई है। मौजूदा बौद्धिक साहित्य और इकनोमीट्रीक उपायों को और अधिक मजबूती से उठाया गया है जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि भारत की जीडीपी, जिसकी आकलन प्रक्रिया 2011 में संशोधित नहीं की गई थी, उससे उच्चतर है। निर्धारित प्रभावों के साथ एक से दूसरे देश के सामान्य अंतर विधि का प्रयोग करते हुए इस भारतीय जीडीपी के दोषपूर्ण आकलन के पक्ष में किसी मजबूत साक्ष्य की कमी को दर्शाया है।

10.46 इस अध्याय में कही गई बड़ी बात का, अध्याय 2 में दिए गए सूक्ष्म-स्तरीय साक्ष्यों के साथ इसके निष्कर्षों को योगवाही तरीके से समझने की जरूरत है, जहां भारत के 504 जिलों में औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत नई फर्मों के सृजन से संबंधित विश्लेषण किया गया है। इस संदर्भ में किए गए दो प्रेक्षण महत्वपूर्ण

हैं। प्रथम, सूक्ष्म साक्ष्य दर्शाता है कि किसी नवीन फर्म-सृजन में 10 प्रतिशत वृद्धि से जिला स्तर की जीडीपी में 1.8 प्रतिशत वृद्धि होती है। चूंकि औपचारिक क्षेत्र में नवीन फर्म-सृजन की गति में वर्ष 2014 के बाद विशेष रूप से वृद्धि हुई है अतः जिला स्तरीय वृद्धि पर और तद्द्वारा देश-स्तरीय वृद्धि पर पड़ने वाली परिणामी प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए। इन बातों के साथ, पूर्णानंदय् (2019) दर्शाते हैं कि पौष्टिकता और बिजली की उपलब्धता जैसे संकेतकों में भारत के सुधार से, पद्धतिमूलक परिवर्तन के बाद भारत की जीडीपी में उच्चतर वृद्धि दर को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। द्वितीय, नवीन फर्म-सृजन के विषय में सूक्ष्म साक्ष्य दर्शाते हैं कि सेवा क्षेत्र में नवीन

फर्मों का सृजन विनिर्माण, अवसंरचना या कृषि क्षेत्र के मुकाबले बहुत अधिक है। यह सूक्ष्म स्तरीय साक्ष्य भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के सापेक्षिक महत्व संबंधी चिरपरिचित समष्टिगत तथ्य से पूरी तरह से मेल खाता है। भारत की सांख्यिकीय अवसंरचना को बढ़ाने में निवेश की आवश्यकता असंदिग्ध में इस संदर्भ में, भारत के भूतपूर्व मुख्य सांख्यिकीविद् की अध्यक्षता में 28 सदस्यीय, आर्थिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति (एससीईएस) का गठन किया जाना महत्वपूर्ण है। तथापि, जब भारतीय आंकड़ों की गुणवत्ता का आकलन किया जाए तो इस समीक्षा में सतर्कतापूर्वक निर्मित साक्ष्यों को ध्यान में अवश्य रखा जाए

अध्याय एक नजर में

- जीडीपी वृद्धि किसी भी निवेश को साथ ही साथ नीति निर्धारकों द्वारा नीति निर्माण के लिए एक जटिल उता-चढ़ाव है। अतः हाल ही के भारत की जीडीपी के सही आकलन के संबंध में छिड़ी बहस में 2011 में आकलन प्रक्रिया में संशोधन को अपना अति महत्वपूर्ण है।
- जैसा कि देश विभिन्न देखे अनदेखे तरीकों में मिला है, एक देश से दूसरे देश की तुलना बहुत सावधानीपूर्वक की जाती है जिसमें अन्य उलझाने वाले घटकों के प्रभाव को सावधानी से अलग किया गया है और केवल जीडीपी विकास आकलन पर प्रक्रिया संशोधन के प्रभाव को अलग किया गया है।
- वह मॉडल जिसमें 2001 के बाद जीडीपी विकास 2.7 प्रतिशत गलतीवश अनुमान से अधिक हो गई है उसने सैंपल समय में 95 देशों में से 51 अन्य देशों में भी जीडीपी विकास अनुमान से अधिक हो गई। विभिन्न विकसित अर्थव्यवस्थाएं जैसे यूके, जर्मनी और सिंगापुर ने अपनी जीडीपी को गलत आकलन किया, जब कि अर्थमिक्तिक प्रतिमान को गलत रूप निर्दिष्ट किया गया था।
- सही रूप में निर्दिष्ट मॉडल, जिसमें सभी देशों के बीच अनदेखी भिन्नताएं साथ ही भिन्न देशों में जीडीपी वृद्धि में अंतराष्ट्रीय रूझान भारत अथवा अन्य देशों में वृद्धि की किसी भी दोषपूर्ण आकलन का पता नहीं लगा सके।
- दोषपूर्ण रूप से अनुमानित भारतीय जी डी पी की चिंताएं डाटा द्वारा निराधार कर दी जाती है अतः इनका कोई आधार नहीं है। समीक्षा में और अधिक विस्तार से सावधानी पूर्वक सृजित साक्ष्य विशेष रूप से इस अध्याय में जिन्हे की अध्याय 2 के सूक्ष्म-स्तरीय साक्ष्य के साथ जुड़े हुए है, का भारतीय डाटा की गुणवत्ता का आंकलन करते समय अवश्य उपयोग में लाना चाहिए।

संदर्भ

Bhalla, S. S. 2019. "Arvind Subramanian's method suggests Germany overestimates GDP the most." *Financial Express*. June 22, 2019. <https://www.financialexpress.com/opinion/arvind-subramanians-method-suggests-germany-overestimates-gdp-the-most/1615118/>

Cameron, A. C., & Miller, D. L. 2015. "A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference". *The Journal of Human Resources*, 50(2), 317-372.

Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. 2008. "Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors." *The Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414-427.

Government of India. Economic Advisory Council to the Prime Minister. 2019. GDP estimation in India- Perspectives and Facts. by Bibek Debroy, Rathin Roy, Surjit Bhalla, Charan Singh and Arvind Virmani. New Delhi: Government of India.

Goyal, A., & Kumar, A. 2019. "Indian Growth is Not Overestimated: Mr. Subramanian You Got it Wrong." WP-2019-019, Indira Gandhi Institute of Development Research.

Goyal, A., & Kumar, A. 2019. "Measuring Indian GDP: Arvind Subramanian Can't Be Taken Seriously." *Bloomberg Quint*. June 20, 2019. <https://www.bloombergquint.com/opinion/measuring-indian-gdp-arvind-subramanian-cant-be-taken-seriously>

Mazumdar, R. 2019. "World's Fastest-Growing Economy May Not Be So Fast After All." *Bloomberg*. June 11, 2019 <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-11/world-s-fastest-growing-economy-may-not-be-so-fast-after-all>

Nag, A., & Mazumdar, R. 2019. "India Has Been Accused of Overstating Its Growth Statistics." *Bloomberg*. July 25, 2019 <https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-24/india-has-been-accused-of-overstating-its-growth-statistics>

Panagariya, A. 2019. "View: Why Arvind Subramanian's GDP over-estimation argument is flawed." *The Economic Times*. June 26, 2019. <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/view-why-arvind-subramanians-gdp-over-estimation-argument-is-flawed/articleshow/69949029.cms?from=mdr>

Press Trust of India. 2019. "CEA rejects Arvind Subramanian claims, says hard to create wrong narrative." *Livemint*. July 4, 2019. <https://www.livemint.com/budget/economic-survey/cea-rejects-arvind-subramanian-claims-says-hard-to-create-wrong-narrative-1562246329862.html>

Purnanandam, A. 2019. "Is India's GDP Growth Rate Really Overstated? A Note." Stephen M. Ross School of Business, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan. July 22, 2019.

Roy, R., & Sapre, A. 2019. "GDP over-estimation argument is flawed." *The Hindu BusinessLine*. June 19, 2019. <https://www.thehindubusinessline.com/opinion/gdp-over-estimation-argument-is-flawed/article28066659.ece#>

Shrivastava, R. 2019. "PM's economic council rejects Arvind Subramanian's claims on GDP growth over-estimation." *India Today*. June 20, 2019. <https://www.indiatoday.in/india/story/arvind-subramanian-gst-over-estimation-pm-economic-panel-rebuttal-1552636-2019-06-20>

Subramanian, A. 2019 "India's GDP Mis-estimation: Likelihood, Magnitudes, Mechanisms, and Implications." Faculty Working Papers No 354. Center for International Development at Harvard University, Cambridge, MA. June, 2019.

Subramanian, A. 2019. "Validating India's GDP Growth Estimates." Faculty Working Paper No. 357. Center for International Development at Harvard University, Cambridge, MA. July, 2019.

The Wire. 2019. " 'Right Data, Wrong Conclusions': Modi's Economic Council Rebutts Subramanian's GDP Paper." *The Wire*. June 19, 2019. <https://thewire.in/economy/arvind-subramanian-pmeac-india-gdp>

Vaidya Nathan, K. 2019. "View: What's wrong with Arvind Subramanian's GDP math." *The Economic Times*. June 17, 2019. <https://economictimes.indiatimes.com/news/economy/indicators/view-whats-wrong-with-arvind-subramanians-gdp-math/article-show/69816811.cms?from=mdr>

थालीनॉमिक्स: भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र

उपनःपितवाचरशिवःशिवाभिरूतिभिः ।

मयोभुरद्विषेण्यःसखासुशेवोअद्वयाः ॥

आओ पास हमारे, आओ, हे भोज्य! हे मंगल-धन्य सहायक!
आरोग्यदायी, अनिर्दय, हे प्रिय और निश्छल स्नेही आओ।

-ऋग्वेद

हालांकि अर्थव्यवस्था का जन साधारण के जीवन पर ठोस प्रभाव पड़ता है किंतु इस तथ्य पर लोगों का ध्यान कम जाता है। अर्थशास्त्र को जनसाधारण के जीवन से जोड़ने का भोजन की थाली, एक ऐसी वस्तु जिससे उसका सामना प्रतिदिन होता है, से अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? “थालीनॉमिक्स : भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र” भारत में एक सामान्य व्यक्ति द्वारा एक थाली हेतु किए जाने वाले भुगतान के मापन का एक प्रयास है। क्या थाली की वहनीयता कम हुई है या बढ़ी है। क्या थाली सस्ती हुई है या महंगी? क्या शाकाहारी थाली और मांसाहारी थाली दोनों के लिए मुद्रास्फीति समान रही है? क्या भारत के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में थाली के मूल्य में मुद्रास्फीति भी अलग-अलग रही है? थाली के मूल्य में परिवर्तन किस घटक-अन्न, दालें, सब्जियां, अथवा भोजन पकाने में उपयोग किए जाने वाले ईंधन - के मूल्य परिवर्तित होने के कारण हुआ है? यह ऐसे प्रश्न हैं जो लुटियन दिल्ली में अथवा देश के अंदरूनी हिस्से में सड़क किनारे के ढाबे में रात्रि भोजन पर संवाद का विषय बन सकते हैं। इनका उत्तर अब दिया जा सकता है और ‘स्वस्थ’ बहस में कोई भी पक्ष लिया जा सकता है। भारतीयों के लिए दैनिक आहार से संबंधित दिशा-निर्देशों (राष्ट्रीय पोषण संस्थान), 2011 की सहायता से थाली के मूल्य का परिकलन किया गया है। हमने अप्रैल, 2006 से अक्टूबर, 2019 की अवधि में 25 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के लगभग 80 केंद्रों से, उद्योगों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मासिक कीमतों के आंकड़ों का डाटा का उपयोग किया। संपूर्ण भारत के साथ-साथ इसके चारों क्षेत्रों-उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम - में हमने पाया कि शाकाहारी थाली के मूल्य में वर्ष 2015-16 में काफी कमी हुई है, हालांकि 2019 में इसके मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप एक परिवार जिसमें दो शाकाहारी थालियों का भोजन प्रतिदिन करने वाले पांच सदस्य हैं और उसके लिए औसत लगभग 10887 रु. प्रतिवर्ष की लाभ प्राप्ति हुई है जबकि मांसाहारी थाली में औसतन प्रतिवर्ष 11787 रु. की लाभ प्राप्ति हुई है। वर्ष 2006-07 एक औसत औद्योगिक श्रमिक की वार्षिक आय से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2019-20 की अवधि में शाकाहारी थाली की वहन क्षमता में 29 प्रतिशत का सुधार हुआ है जबकि मांसाहारी थाली में 18 प्रतिशत का सुधार हुआ है।

प्रस्तावना

11.1 हालांकि अर्थशास्त्र हम में से प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है किंतु इस तथ्य पर साधारण पुरुष या महिला किसी का भी ध्यान अक्सर नहीं जाता है। अर्थशास्त्री संभवतः स्वयं ही इस

स्थिति के लिए उत्तरदायी हैं क्योंकि प्रसरण-विषमता पर गंभीर और तकनीकी संवाद सबसे मेहनती तथा मेधावी व्यक्ति को भी डरा सकते हैं। क्या हम अर्थव्यवस्था को जनसाधारण के दैनिक जीवन से जोड़ सकते हैं? भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अध्याय 6

“टहोका का व्यावहारिक अर्थशास्त्र” के द्वारा मानव को स्वार्थी स्वचालित मशीन की बजाय मानव के रूप में समझने का नम्र प्रयास किया गया है, ताकि जनसाधारण उसकी विशिष्टताओं से अपने आपको जोड़ सके और उस सुगम स्पेक्ट्रम का प्रयोग व्यावहारिक परिवर्तन को समझने के लिए आर्थिक नीति के एक उपकरण के रूप में कर सके। अर्थशास्त्र को जनसाधारण से जोड़ने के इस विनम्र प्रयास को जारी रखने का थाली ऐसी वस्तु जिससे उसका सामना प्रतिदिन होता है, के उपयोग से बेहतर तरीका क्या हो सकता है?

11.2 “थालीनॉमिक्स: भारत में भोजन की थाली का अर्थशास्त्र” में आइए-यह एक ऐसा प्रयास है जिसमें यह परिकलन किया गया है कि भारत में पौष्टिक थाली के लिए आम आदमी को कितना खर्च करना पड़ता है। थाली अधिक वहन योग्य हुई है या कम? मुद्रास्फीति ने थाली के मूल्य को बढ़ाया अथवा घटाया है? क्या निरामिष भोजी थाली अथवा आमिषभोजी थाली दोनों पर मुद्रास्फीति का समान प्रभाव पड़ा है? क्या भारत के अलग-अलग राज्यों और क्षेत्रों में थाली के मूल्य में मुद्रास्फीति भी अलग-अलग रही है? थाली के मूल्य में परिवर्तन अन्न, सब्जियों, दालों, भोजन पकाने में उपयोग किए जाने वाले ईंधन में से किस घटक के मूल्य में परिवर्तन होने के कारण हुआ है? ये ऐसे प्रश्न हैं जो लुटियन दिल्ली में अथवा देश के किसी भीतरी भाग में सड़क किनारे ढाबे में संवाद का विषय बन सकते हैं। इनका उत्तर अब दिया जा सकता है और इस “स्वस्थ बहस कोई भी पक्ष लिया जा सकता है।

11.3 चूंकि जीवन के लिए भोजन आवश्यक होता है इसलिए थाली की तेजी से बढ़ती कीमत का प्रभाव सीधे आम आदमी (जनसाधारण) पर पड़ता है तथा इसे सुस्पष्ट रूप से देखा भी जा सकता है। वास्तव में खाद्य वस्तुएं तथा पेय पदार्थ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त का 45.9 प्रतिशत भाग होते हैं। इसलिए सबसे प्रभावी विधि जिसके द्वारा जन साधारण को मूल्यों की प्रवृत्ति के विषय में समझाया जा सकता है वह यह है कि घर में तैयार की जाने वाली सम्पूर्ण भोजन की थाली भारतीय थाली, में कितना खर्च आता है के द्वारा यह बात स्पष्ट की जाए।

11.4 भारत की विविधता के कारण, यहां पकने वाले भोजन में भी विविधता है। यहां विभिन्न प्रकार को खाद्य

वस्तुओं को पकाया जाता है। इनमें विविध सब्जियों, अन्न, फल और मसालों का स्वादिष्ट मिश्रण होता है जिनकी उपज देश के विभिन्न स्थानों पर होती है। भारत के परंपरागत पौष्टिक आहार में अन्न और सब्जियों के साथ-साथ मछली, मांस और अंडों का स्वस्थ मिश्रण रहा है। हमने 25 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए ‘थाली’ के मूल्य का परिकलन किया है जिसमें अन्न (चावल या गेहूं), सब्जी (सब्जियां और अन्य घटक), दाल (दाल के साथ-साथ अन्य घटक) और इसके साथ-साथ उस ईंधन की लागत सम्मिलित की गई है जिसका उपयोग घरों में भोजन पकाने के लिए किया जाता है (बॉक्स 1)। हम दो प्रकार की थाली का विश्लेषण करते हैं—एक निरामिष भोजी (शाकाहारी) थाली और एक आमिषभोजी (मांसाहारी) थाली। निरामिष भोजी थाली में अन्न, सब्जी और दाल होती हैं तथा आमिषभोजी थाली में अन्न, सब्जी और आमिषघटक (मांस-गोश्त) होती है। हमने इन दो प्रकार की थालियों की कीमतों में वर्ष 2006-07 से अक्टूबर 2019-20 तक की अवधि में मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण किया है।

11.5 अखिल भारत में और चारों क्षेत्रों—उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में हमने देखा कि निरामिष थाली के निरपेक्ष मूल्य में वर्ष 2015-16 से कमी हुई है, हालांकि वर्ष 2019 में इसमें कुछ वृद्धि हुई है। ऐसा पिछले वर्षों में बढ़ते मूल्यों की प्रवृत्ति की तुलना में वर्ष 2015-16 के बाद सब्जियों और दाल के मूल्यों में व्यापक रूप से होने वाली कमी के कारण है। दरअसल इस वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर 2019) थाली के मूल्य में वृद्धि होने का कारण दालों और सब्जियों के मूल्यों में होने वाली वृद्धि है। यदि निरामिषभोजी थाली के मूल्य में वर्ष 2015-16 तक व्याप्त वृद्धि जारी रहती तो एक औसत परिवार को, जिसमें पांच सदस्य¹ हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम दो पौष्टिक थालियों से भोजन करने हेतु प्रति वर्ष 10887 रु. अधिक खर्च करना पड़ता है दूसरे शब्दों में वर्ष 2015-16 के बाद औसत परिवार को खाद्य कीमतों में नरमी से औसतन प्रतिवर्ष 10887 रु. का लाभ हुआ है। इसी प्रकार इसी अवधि में औसत परिवार जिसमें प्रति व्यक्ति प्रति दिन दो पौष्टिक आमिषभोजी थालियों का सेवन किया जाता है उसे इसी अवधि में लगभग 11787 रूपये का लाभ हुआ है। दूसरा पैमाने के तौर पर हमने एक औसत औद्योगिक श्रमिक की अपने पांच सदस्यों के परिवार हेतु दो थालियां खरीदने की क्षमता की जांच की। इस

¹ प्रति परिवार पांच सदस्यों की पूर्वाधारणा इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में औसत परिवार में 4.8 व्यक्ति होते हैं (जनगणना 2011 के अनुसार)

पैमाने के अनुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि निरामिषभोजी थाली की वहन क्षमता में वर्ष 2006-07 से वर्ष 2019-20 की अवधि में 29 प्रतिशत का सुधार हुआ है और आमिषभोजी थाली की क्रय क्षमता में 18 प्रतिशत का सुधार हुआ है। यहां नोट करने वाली बात

यह है कि हालांकि आमिषभोजी थाली महंगी होती है और निरामिषभोजी थाली सस्ती होती है, लाभ व इसके कारण वहन क्षमता में सुधार इन थालियों की कीमतों में वर्ष 2015-2016 तक की अवधि में व्याप्त प्रवृत्तियों के कारण हुआ है।

बॉक्स 1: थालियों की कीमतों का निर्धारण

इन थालियों का निर्माण अप्रैल, 2006 से अक्टूबर, 2019 तक की अवधि में श्रमिक ब्यूरो, भारत सरकार से 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 78 केंद्रों हेतु प्राप्त औसत मासिक मूल्य डाटा के आंकड़ों (जोकि औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को तैयार करने के लिए उपयोग किया जाते हैं) की सहायता से किया गया है। विभिन्न वस्तुओं (पण्य पदार्थ) का औसत मासिक मूल्य किसी प्रदत्त केंद्र में चयनित बाजारों के चयनित दुकानों में व्याप्त उस मद की विनिर्दिष्ट किस्म के खुले बाजार में मूल्यों का औसत है। राशन की मदों के लिए केंद्रों हेतु मूल्य “भारित औसत मूल्य” है। यहां “भार” औसत श्रमिक वर्ग परिवार की आधार वर्ष (2001) की आवश्यकताओं के संबंध में ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली’ के माध्यम से उपलब्ध होने वाली मात्रा और खुले बाजार में विभिन्न केंद्रों में प्राप्त मात्रा का अनुपात है।

दो प्रकार की थालियों का विश्लेषण किया गया-निरामिष (शाकाहारी) थाली तथा आमिषभोजी (मांसाहारी) थाली। थाली तैयार करने के लिए घटकों की मात्रा (एन.आई.एन, 2011) की रिपोर्ट में भारतीयों के लिए दिए गए आहार-विषयक दिशानिर्देशों के अनुसार थी। हमने कठोर परिश्रम करने वाले व्यस्क पुरुष की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा है। इसलिए हो सकता है कि प्राक्कलित मूल्य परिवार के भोजन के खर्च को कम आकलित करने के स्थान पर अधिक आकलित करें। प्रत्येक थाली के लिए हमने अन्न, सब्जी, दाल और आमिष पदार्थों की मात्रा का निर्धारण इस प्रकार किया है, जिससे कि दिन में कम से कम दो बार किए गए भोजन से मनुष्य शरीर के लिए आवश्यक इन पदार्थों की दैनिक आवश्यकताओं पूर्ति होती रहे। निरामिषभोजी थाली में अन्न की मात्रा (300 ग्राम) सब्जियों की मात्रा (150 ग्राम) और दाल की मात्रा (60 ग्राम) है। दो प्रकार के अन्न लिए गए हैं-चावल और गेहूं। आलू, प्याज, टमाटर को मुख्य सब्जियों और बैंगन, बंदगोभी, फूलगोभी व भिंडी को अतिरिक्त सब्जियों के रूप में लिया गया है, इससे सभी मौसम, पूरे भारत में उपलब्धता व सामान्य उपभोग सम्मिलित हो जाते हैं। दालों में अरहर, चने की दाल, मसूर दाल, मूंग दाल और उड़द की दाल का चयन किया गया है। अन्य वस्तुओं में सब्जी व दाल, से खाद्य पदार्थ बनाने हेतु आवश्यक मसाले शामिल हैं। भोजन पकाने में सरसों का तेल, मूंगफली का तेल और नारियल के तेल का चयन किया गया है, यह चयन राज्य-वार भोजन में उपयोग किए जाने वाले तेल के प्रकार के अनुसार किया जाता है। आमिषभोजी व्यंजनों के लिए मुर्गी के अंडों, मछली (ताजी) और बकरे के मांस का चयन किया गया है क्योंकि इसको भोजन के रूप में सभी प्रांतों व धर्मों में खाया जाता है। आमिषभोजी थाली में दाल के स्थान पर गोश्त (60 ग्राम) या कोई आमिष घटक होता है, शेष घटकों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। ईंधन के लिए हमने घरेलू-गैस के मूल्य के साथ-साथ जलाऊ लकड़ी का चयन किया है, जिनके (आंकड़े) हमें उपलब्ध हैं। वैसे भी यहां विश्लेषण में मदों की मात्रा अधिक महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि घटकों के इस प्रकार “भार” को कम या अधिक किया जा सकता है कि कीमत परिवर्तन की दिशा अपरिवर्तित रहे।

भोजन की प्रत्येक थाली में (300 ग्राम) अन्न का ‘भारित मूल्य’ एन.एस.एस. के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के 68वें राउंड के आंकड़ों में चावल व गेहूं के राज्यवार मात्रात्मक भारों के अनुसार निर्धारित किया गया है। प्रत्येक राज्य के लिए प्रति व्यक्ति गेहूं और चावल की औसत मासिक खपत का परिकलन घरेलू सर्वेक्षण के आंकड़ों से किया गया है। इसी प्रकार सब्जियों के साथ-साथ दालों के अंश के भारित मूल्य का परिकलन इन्ही आंकड़ों के आधार पर किया गया है। इसी प्रकार आमिषभोजी थाली के भोजन के लिए भी विभिन्न मदों का परिकलन किया गया है। घरों में भोजन के प्रत्येक समय में होने वाली ईंधन की खपत का परिकलन किसी परिवार में उपयोग की जाने वाली एल.पी.जी. और जलाऊ लकड़ी की माह में उपयोग की गई मात्रा घर में बनाए गए औसत भोजनो की मात्रा से विभाजन द्वारा किया है। यह मात्रा एन.एस.एस. की 68वीं रिपोर्ट के डाटा के अनुसार है। इसकी सहायता से एक भोजन हेतु ईंधन की भारित औसत कीमत की गणना की गई है।

उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से प्राप्त भारों को कीमत आंकड़ों के साथ प्रयोग करके मुख्य घटकों की भारित कीमतें ज्ञात की गई हैं। अन्य घटकों का भार थालियों को बनाने में उपयोग होने वाली मानकीकृत विधियों पर आधारित है। (तालिका क)

थाली की कीमत संबंधित थाली को तैयार करने में लगे सभी घटकों पर हुए कुल खर्च को दर्शाती है। थाली की राज्यवार

तालिका क: अन्य अवयव

थाली के घटक	अन्य अवयव
सब्जी	हल्दी 0.2 ग्राम, सूखी मिर्च 0.5 ग्राम, नमक-1 ग्राम, धनिया 0.5 ग्राम, खना पकाने का तेल-10 ग्राम
दाल	हल्दी 0.2 ग्राम, नमक 0.2 ग्राम, सूखी मिर्च 0.2 ग्राम, जीरा/सरसों के दाने 1 ग्राम, तेल 10 ग्राम
मांसाहारी	हल्दी 0.1 ग्राम, सूखी मिर्च 0.2 ग्राम, नमक 0.5 ग्राम, धनिया 0.2 ग्राम, मिश्रित मसाले 0.1 ग्राम, अदरक 0.5 ग्राम, लहसुन 0.5 ग्राम, प्याज 15 ग्राम, टमाटर 12 ग्राम, खना पकाने का तेल 10 ग्राम

कीमतों को व्यंजन विधियों, घटकों, भाarों पर आधारित राज्यवार गणनाओं से ज्ञात किया गया है। क्षेत्रवार व अखिल भारतीय थाली का निर्माण सभी राज्य की थाली की कीमतों के भारित औसत से किया गया है जहां राज्यवार जनसंख्या का उपयोग भार के तौर पर किया गया है।

प्रति परिवार पांच सदस्यों के पूर्वधारण इस तथ्य पर आधारित है कि भारत में औसत परिवार में 4.9 प्रतिशत व्यक्ति होते हैं (जनगणना 2011 के अनुसार)

थाली की कीमतें

11.6 वर्ष 2015-16 को भोजन की कीमतों की गतिकी में तब्दीली के वर्ष के रूप में लिया जा सकता है। विश्लेषण अवधि के दौरान पश्चात कृषि क्षेत्र की उत्प.

ादकता को बढ़ाने के लिए तथा अच्छी और अधिक पारदर्शी कीमत-खोज हेतु कृषि बाज़ार में कुशलता और प्रभाविकता को बढ़ाने के लिए कई सुधारात्मक उपाय किये गए हैं (तालिका-1) ये अखिल भारत स्तर पर थाली की कीमतों में आई मंदी में परिलक्षित होते हैं। (चित्र 1)। इस विश्लेषण के लिए हम वर्ष 2006-07 से आंकड़े लेते हैं, ताकि हमारे पास स्थिति परिवर्तन से पहले की कीमत प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिए 10 वर्ष के आंकड़े हों।

तालिका 1: कृषि उत्पादकता और कृषि बाजार की कुशलता को बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ मुख्य कदम।

क्र. स.	योजना का नाम	विवरण
1	प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)	2018 में शुरू की गई पीएम-आशा योजना में तीन उप-योजनाएं सम्मिलित हैं मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), कीमत की कमी हेतु *भुगतान योजना (पीडीपीएस) और निजी अधिप्रापण एवं भंडार योजना (पीडीपीएस) को प्रायोगिक रूप से चलाना। पीएसएस के अन्तर्गत दालों, तिलहन, कोपरा का भौतिक अधिप्रापण राज्य सरकार की सक्रिय भूमिका से केन्द्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा किया जाता है। पीडीपीएस के अन्तर्गत वे सभी तिलहन शामिल हैं। जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिसूचित किया जाता है। इसके अन्तर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा ब्रिकी/मॉडल कीमत के बीच के अन्तर को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार यार्ड में अपने उत्पादों को बेचने वाले पूर्व किसानों को किया जाता है।
2	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) प्रति बूंद अधिक फसल	पीएमकेएसवाई को वर्ष 2015-16 में लागू किया गया था। इसमें सुनिश्चित सिंचाई के अधीन कृषि योग्य भूमि के विस्तार, पानी की बर्बादी को कम करने के लिए खेत में पानी के उपायोग संबंधित दक्षता को सुधारने, संकेंद्रित-सिंचाई तथा अन्य जल बचत प्रौद्योगिकियों जल स्रोतों का पुनर्भरण बढ़ाने तथा संधारणीय जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने के अंगीकरण को बढ़ाने जैसे उपायों से जल उपयोग दक्षता को बढ़ाने पर ध्यान है।

3	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमबीवाई)	पीएमएफबीवाई को कृषि फसलों को बेहतर बीमा कवरेज प्रदान और उसके द्वारा जोखिम न्यूनीकरण के लिए वर्ष 2015-16 में शुरू किया गया था। पीएमएफबीवाई से कुल 69.9 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को व्यापक कवरेज प्रदान करना है।
4	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को देश में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करने के लिए राज्य सरकार को सहायता देने हेतु वर्ष 2014-15 में शुरू किया गया था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड किसानों को उनकी मिट्टी के पोषक तत्वों पर सूचना देने के साथ उनकी मृदा स्थिति के लिए उपयोग किए जाने वाले पोषक तत्वों की उपयुक्त मात्रा पर अनुशंसाएं भी प्रदान करता है।
5	ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नैम)	ई-नैम पारदर्शी कीमत खोज हेतु कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन व्यापार प्लेटफार्म है। अब तक 16 राज्यों एवं 2 संघ-शासित प्रदेशों में 585 थोक विनियमित बाजारों को ई-नैम से जोड़ा जा चुका है।
6	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन एफ एस एम)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चावल, गेहूँ, दलहल एवं मोटे अनाज के उत्पादन में वृद्धि हेतु वर्ष 2007-08 से कार्यान्वित है। इसे वर्ष 2014-15 में पुनः डिजाइन किया गया था।
7	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एन एफ एस ए)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को वर्ष 2013 में अधिनियमित तथा वर्ष 2014 में क्रियान्वित किया गया था। यह उच्च सब्सिडी दर पर खाद्यान्न प्राप्त करने हेतु 67 प्रतिशत जनसंख्या (ग्रामीण क्षेत्रों में 75 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्रों में 50 प्रतिशत) को कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 कि. ग्रा. की दर से तथा ए ए वाई परिवारों को 35 किग्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह दर से पोषक अनाज, गेहूँ और चावल क्रमशः 1 रुपए, 2 रुपए तथा 3 रुपए की उच्च सब्सिडी युक्त कीमत पर आर्बिट्रि किए जाते हैं। इस अधिनियम के तहत 2011 की जनगणना के जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को आधार बनाया गया है। यह अधिनियम सभी 36 राज्यों/संघ शासित राज्यों में कार्यान्वित किया गया है। तथा इससे लगभग 81.35 करोड़ व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है।

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण

11.7 यदि कीमतें 2015-16 से पहले की दर से बढ़ती रहती तो क्या होता, इसे हम देखने हेतु 2015-16 से पूर्व 10 वर्षों हेतु रेखीय प्रवृत्ति ज्ञात करते हैं व उसे उस वर्ष से आगे प्रक्षेपित करते हैं। इससे हमें यह संकेत मिलता है कि यदि सारणी 1 में वर्णित नीतियां कार्यान्वित नहीं होती हैं तो कीमतें क्या होती। इसकी वास्तविक कीमतों से तुलना करने पर हम उस सांकेतिक लाभ की गणना कर सकते हैं जिसे थाली के उपभोक्ता ने 2015 से कृषि नीति कार्यक्रम के कारण प्राप्त किया है।

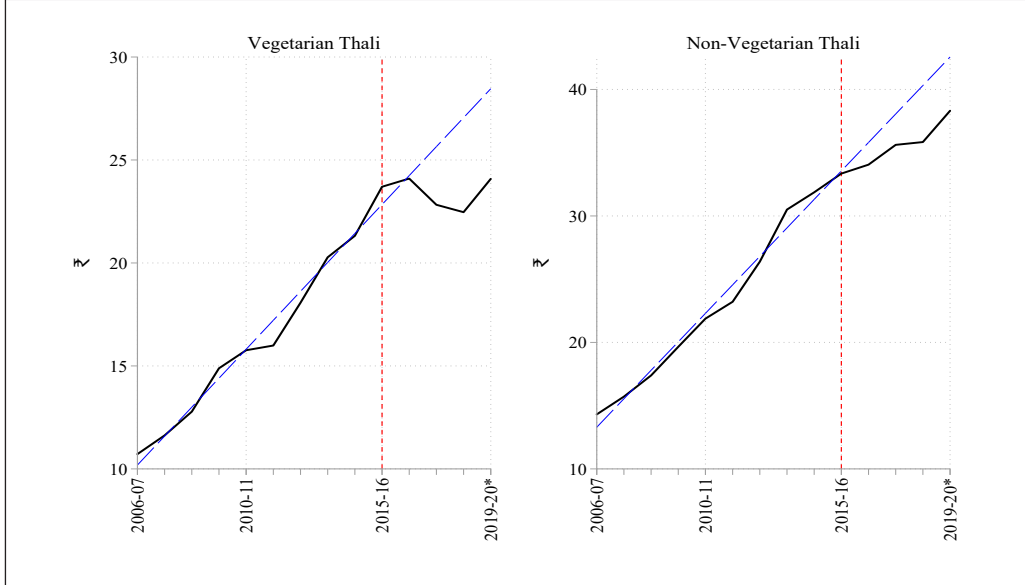
11.8 चित्र 1 में वर्ष 2015-16 लाल बिन्दुकित ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा दर्शाया गया है। नीली डैश रेखा 2015-16 तक रैखिक फिट है तथा तब से पांच वर्षों

के लिए अनुमानित (प्रक्षेपित) है। 2015-16 की अनुवर्ती अवधि के लिए हम प्रक्षेपित रेखा जो कि प्रतितथ्यात्मक कीमत देती हैं, तथा वास्तविक के बीच अन्तराल की गणना करते हैं। अखिल भारतीय स्तर पर शाकाहारी थाली के लिए 2015-16 के पश्चात लगभग 3 रूपये प्रति थाली का औसत लाभ था (2016-17 में 0.1, रु. 2017-18 में 2.8 रु., 2018-19 में 4.6 रु., तथा 2019-20 में 4.4 रु.) (चित्र 1)। यह पहली नजर में कम प्रतीत हो सकता है परन्तु परिवारों हेतु भोजन की लागत में बड़ी गिरावट है। इसको समझने के लिए मान लीजिए कि प्रतिनिधि शाकाहारी परिवार में पांच लोग हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति दिन में दो बार भरपेट खाना खाता है। इस परिवार के लिए औसत

वार्षिक लाभ 2015-16 की अनुवर्ती अवधि के लिए 10887 रु. के आसपास होगा। यह लाभ औसतन एक श्रमिक की वार्षिक मजदूरी का 6.5 प्रतिशत है। (तालिका-2). मांसाहारी (आमिष) थाली के लिए

वर्ष 2016-17 में प्रति थाली पर 1.8 रु., 2017-18 में 2.4 रु., 2018-19 में 4.5 रु. तथा, 2019-20 में 4.2 रु. का लाभ हुआ। इस प्रकार 5 सदस्यों के परिवार में लगभग रु. 11787 का औसत लाभ होगा।

चित्र 1: अखिल भारतीय स्तर पर थाली का मूल्य



स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: नीली डेश लाइन 2015-16 तक रेखीय प्रवृत्ति को और इसके बाद अनुमान दर्शाती है। लाल बिंदुओं वाली रेखा 2015-16 को व्यक्त करती है।

*अप्रैल-अक्तूबर, 2019

तालिका 2: एक दिन में पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिदिन दो थाली के लाभ

वर्ष	लाभ रु. में	श्रमिक की वार्षिक आय के अनुपात (प्रतिशत में) के रूप में	
		शाकाहारी थाली	मांसाहारी थाली
2016-17	526.9	0.4	6408.2
2017-18	10304.3	6.5	8910.3
2018-19	16744.4	10	16318.2
2019-20*	15972.3	9	15511.5

स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: 2019-20 हेतु गणनाएं अप्रैल-अक्तूबर, 2019 की अवधि के लिए मूल्यों पर आधारित परिकलन हैं।

11.9 भारत एक विविधता वाला देश है और इस कीमतों के रुझानों में क्षेत्रावार अन्तर को देखना आवश्यक है। इसलिए भारत के राज्यों को भौगोलिक स्थिति के आधार पर चार क्षेत्रों में बांटा गया है:

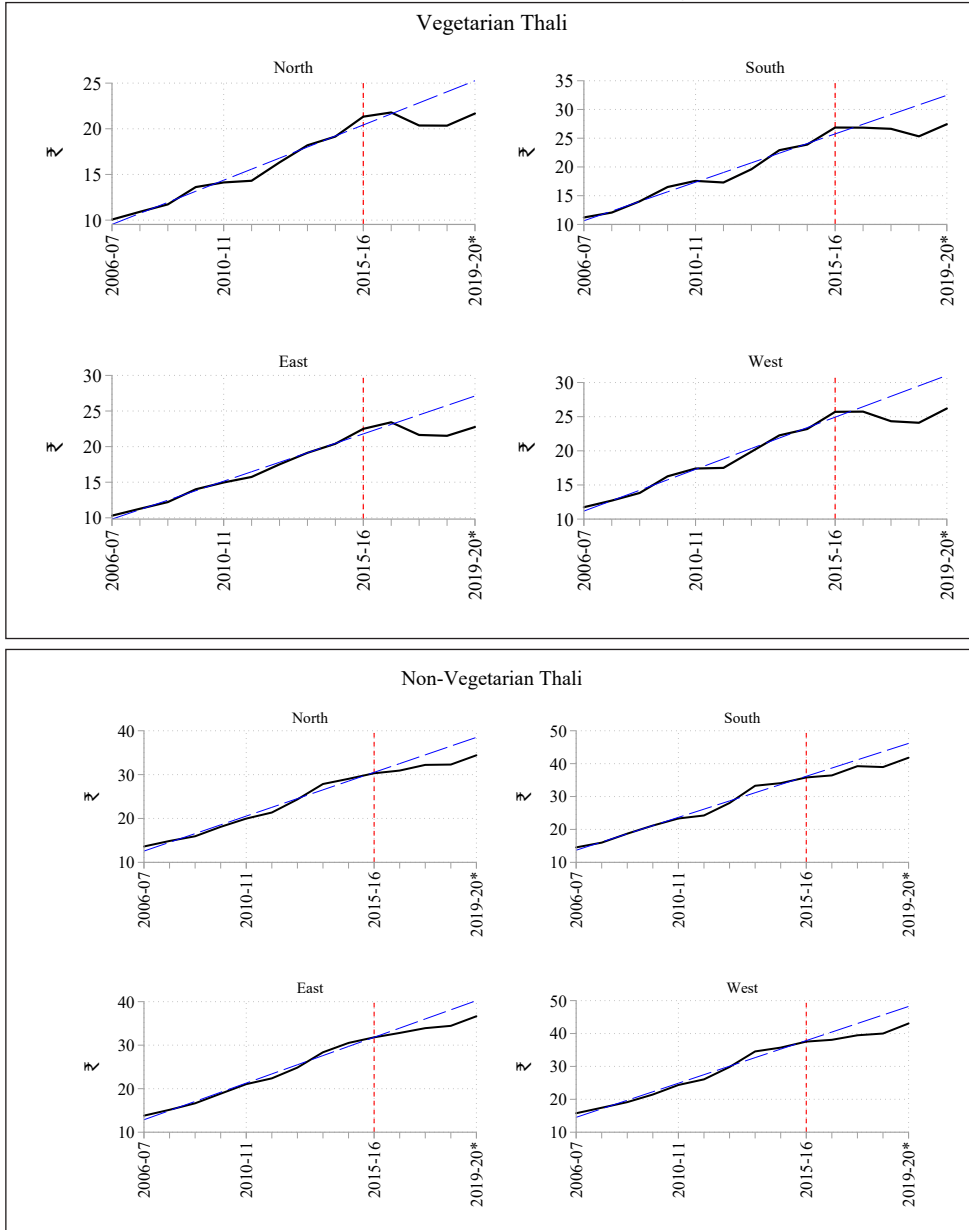
- उत्तर क्षेत्र में चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश शामिल है।
- दक्षिण क्षेत्र में कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी,

तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल है।

- पूर्व क्षेत्र में असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, त्रिपुरा व पश्चिम बंगाल शामिल है।
- पश्चिम क्षेत्र में गोवा, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल है।

11.10 समूचे क्षेत्र में इसी प्रकार के लाभ देखे जा सकते हैं। केवल 2016-17 में शाकाहारी थाली के मामले में उत्तर-क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर (चित्र 2 व तालिका 3)। किसी वर्ष में सर्वाधिक लाभ दक्षिण क्षेत्र में 2018-19 में शाकाहारी के मामले में देखा गया, जो कि एक श्रमिक की वार्षिक आय का 12 प्रतिशत थी।

चित्र 2: क्षेत्रीय स्तर पर थाली का मूल्य



स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: नीली डेश लाइन 2015-16 तक रेखीय प्रवृत्ति को और इसके बाद अनुमान दर्शाती है। लाल बिंदुओं वाली रेखा 2015-16 को व्यक्त करती है।

अप्रैल-अक्तूबर, 2019

तालिका 3: एक दिन में पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए दो थाली के साथ क्षेत्रवार लाभ

वर्ष	श्रमिक की वार्षिक आय के अनुपात (प्रतिशत में) के तौर पर		श्रमिक की वार्षिक आय के अनुपात (प्रतिशत में) के तौर पर	
	लाभ रु. में		लाभ रु. में	
उत्तरी क्षेत्र				
	शाकाहारी थाली		मांसाहारी थाली	
2016-17	-578.7	-0.4	5,795.3	4.3
2017-18	9,055.1	6.2	8,348.0	5.8
2018-19	13,528.9	8.8	15,354.9	10
2019-20*	13,087.3	8	14,920.3	9.2
दक्षिणी क्षेत्र				
	शाकाहारी थाली		मांसाहारी थाली	
2016-17	2,166.1	1.5	8,169.5	5.7
2017-18	9,031.2	6	7,035.0	4.7
2018-19	19,935.9	12.4	17,118.1	10.7
2019-20*	18,361.6	10.8	15,865.5	9.3
पूर्वी क्षेत्र				
	शाकाहारी थाली		मांसाहारी थाली	
2016-17	-1,091.9	-0.7	4,044.1	2.6
2017-18	10,254.8	6.1	7,705.6	4.6
2018-19	15,558.5	8.8	13,454.7	7.6
2019-20*	15,886.0	8.5	13,123.8	7.1
पश्चिमी क्षेत्र				
	शाकाहारी थाली		मांसाहारी थाली	
2016-17	2,612.9	1.6	8,632.2	5.1
2017-18	13,317.6	7.5	13,053.8	7.4
2018-19	19,724.3	10.5	20,563.7	10.9
2019-20*	17,661.4	8.9	18,885.2	9.5

स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिपपणी: 2019-20 हेतु गणनाएं अप्रैल-अक्टूबर, 2019 की अवधि के लिए मूल्यों पर आधारित हैं।

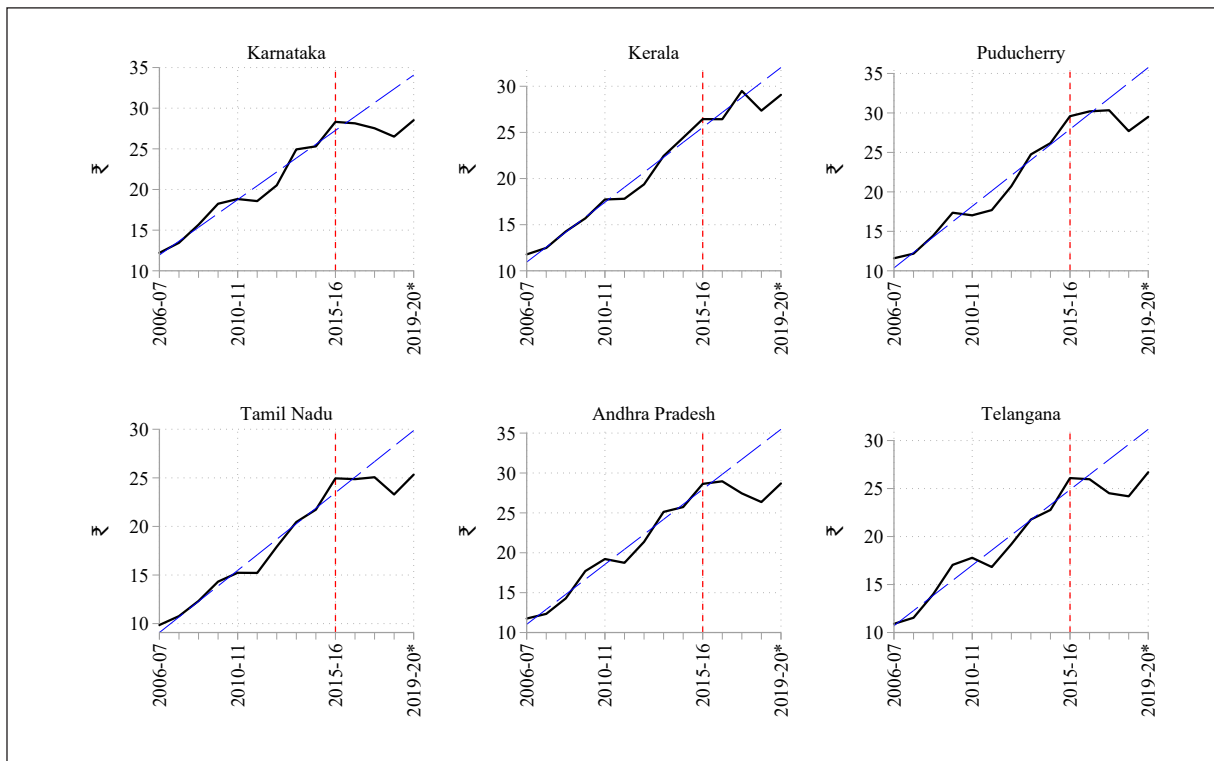
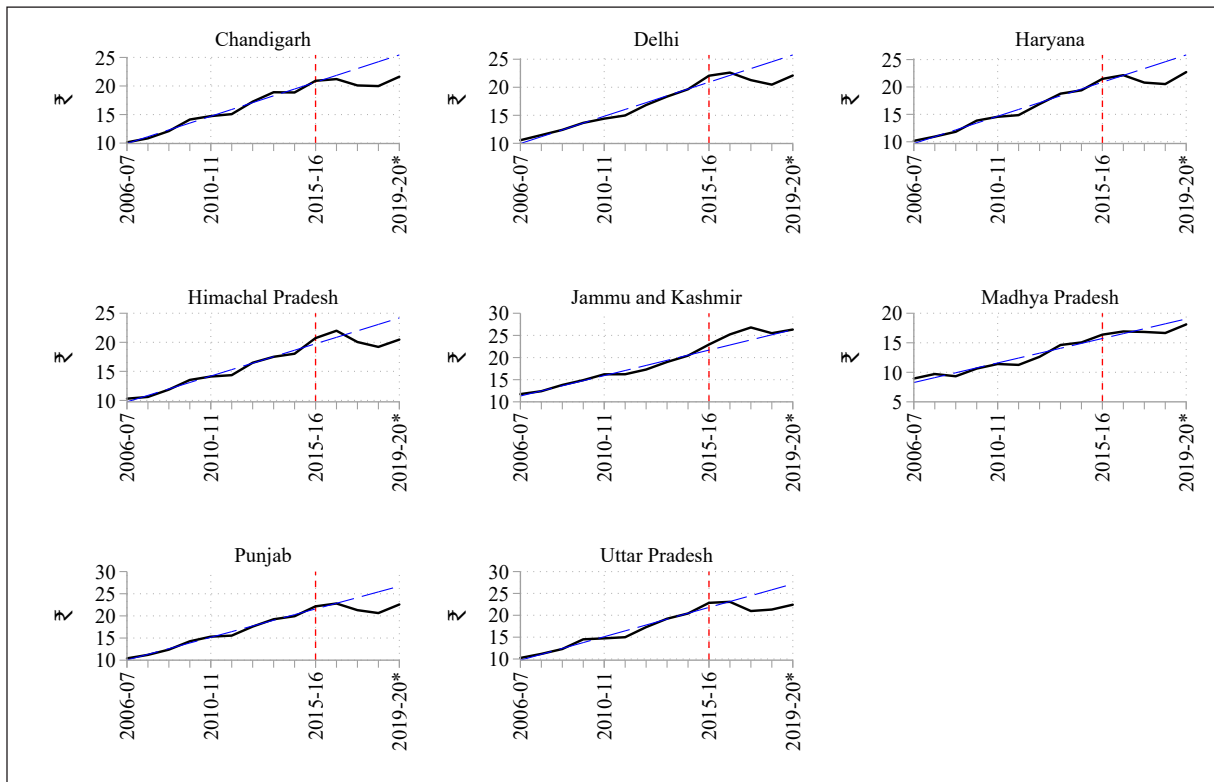
चित्र 3 और 4 राज्यवार थाली के मूल्यों को दर्शाते हैं। इनमें समान प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं।

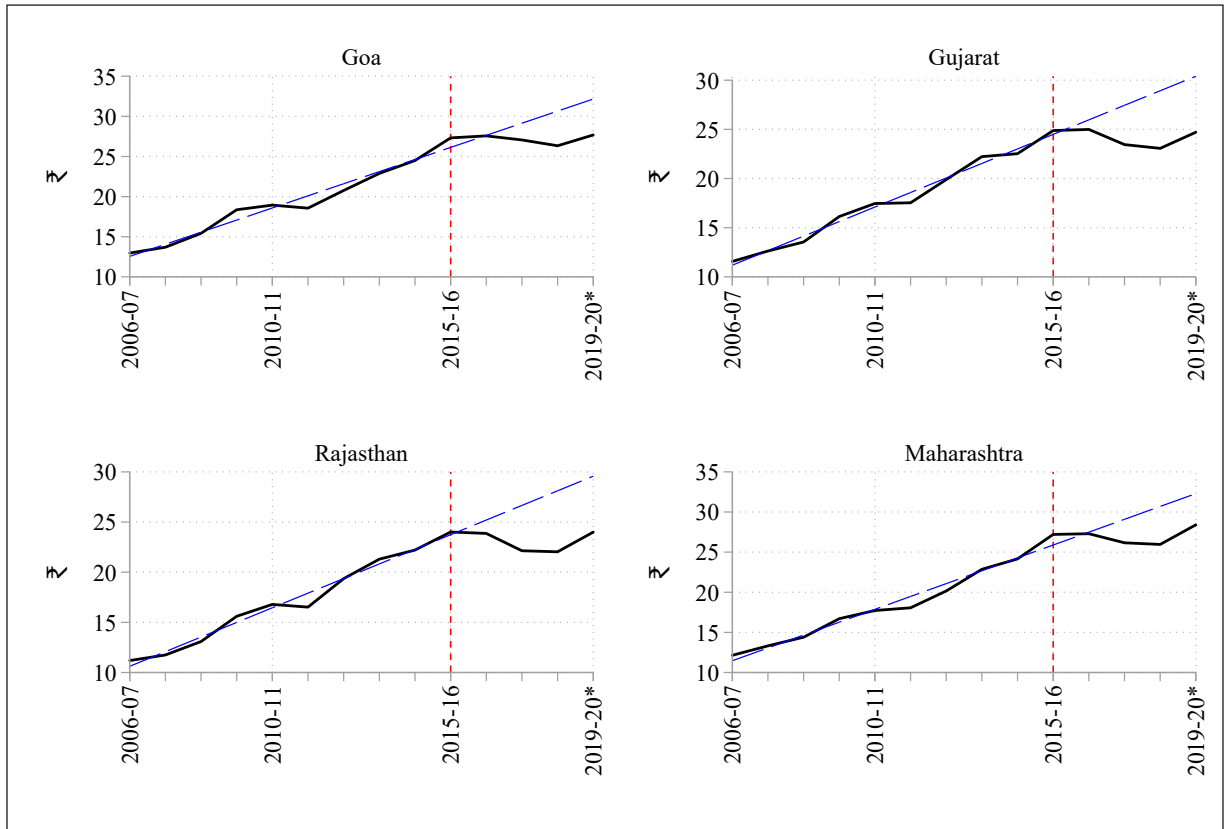
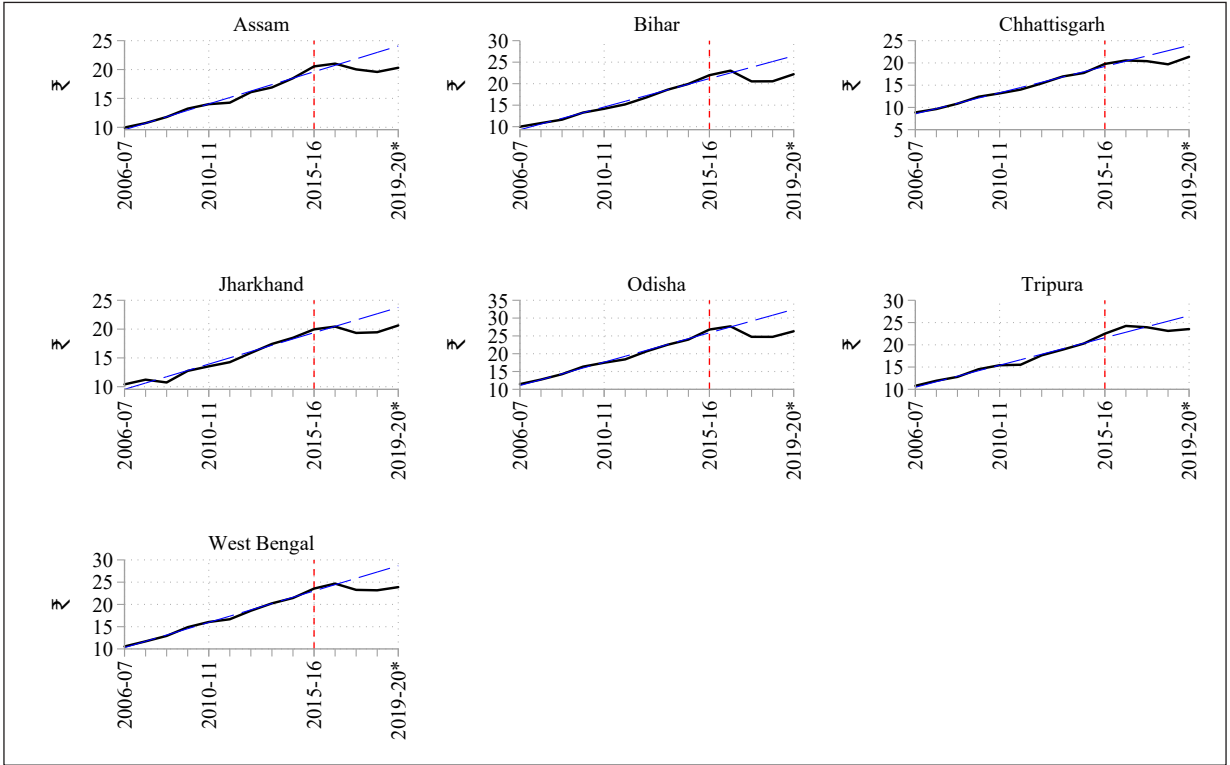
थाली की वहनीयता

11.11 हालांकि थालियों की कीमतों से यह पता चलता है कि एक व्यक्ति को थाली की कितनी लागत आएगी यह जानना कि मूल्य घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं इस बात की जानकारी देने के लिए अपर्याप्त है कि एक आम आदमी बदतर स्थिति में है या बेहतर स्थिति में है। यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि उसी अवधि में थालियों के

मूल्यों की तुलना में व्यक्तियों की आय में भी कैसा परिवर्तन आया है। इस उद्देश्य के लिए हम यह देख सकते हैं कि श्रमिक को अपनी दैनिक मजदूरी का कितना हिस्सा अपने परिवार के सदस्यों के लिए दो थालियों को खरीदने के लिए आवश्यक होगा। यदि ये मैट्रिक समय के साथ गिरता है तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि स्थिति बेहतर है। दूसरी ओर यदि यह मैट्रिक घटता है तो स्थिति विपरीत होगी। हमने इस मैट्रिक के

चित्र 3: शाकाहारी थाली की राज्य वार कीमते



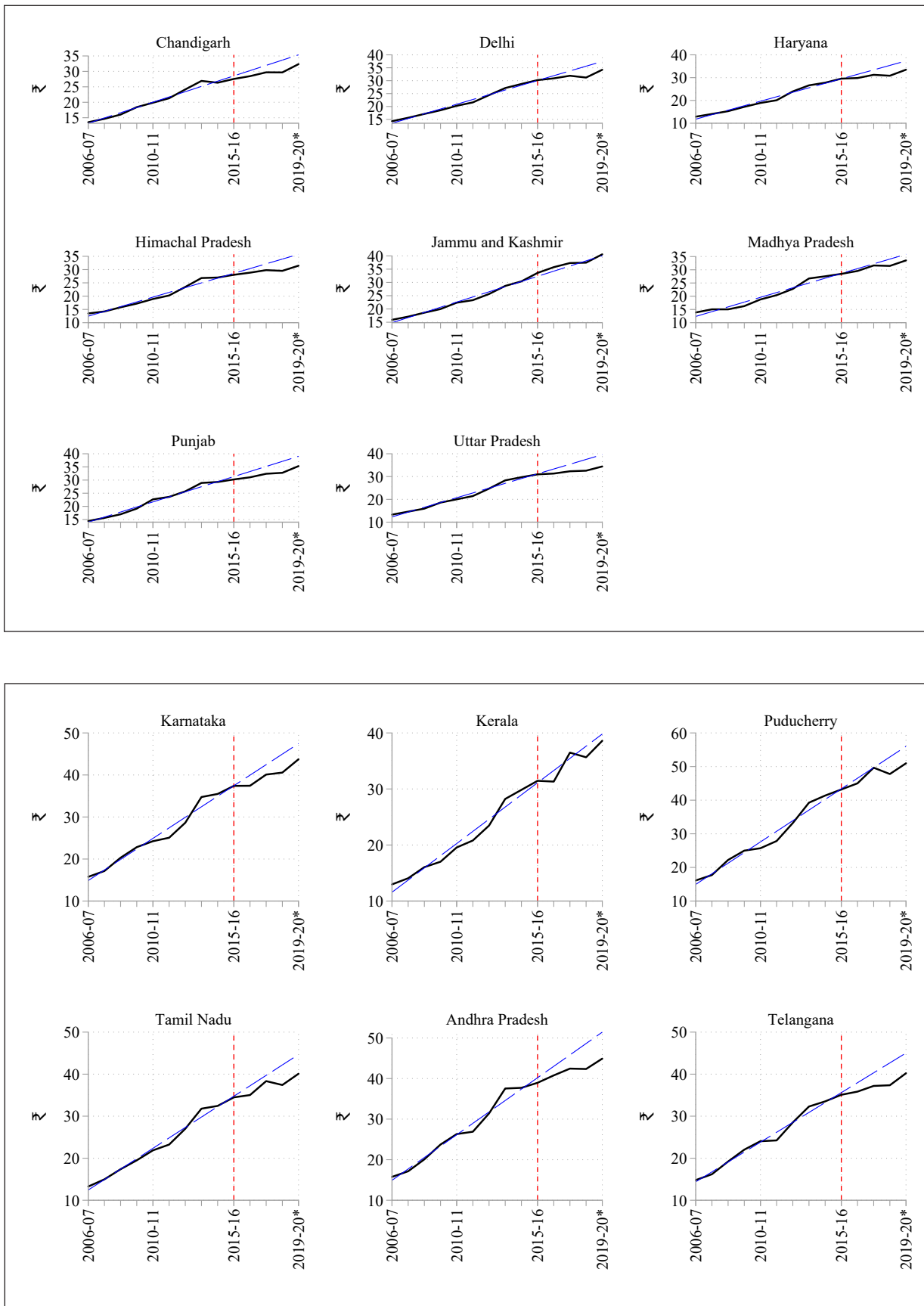


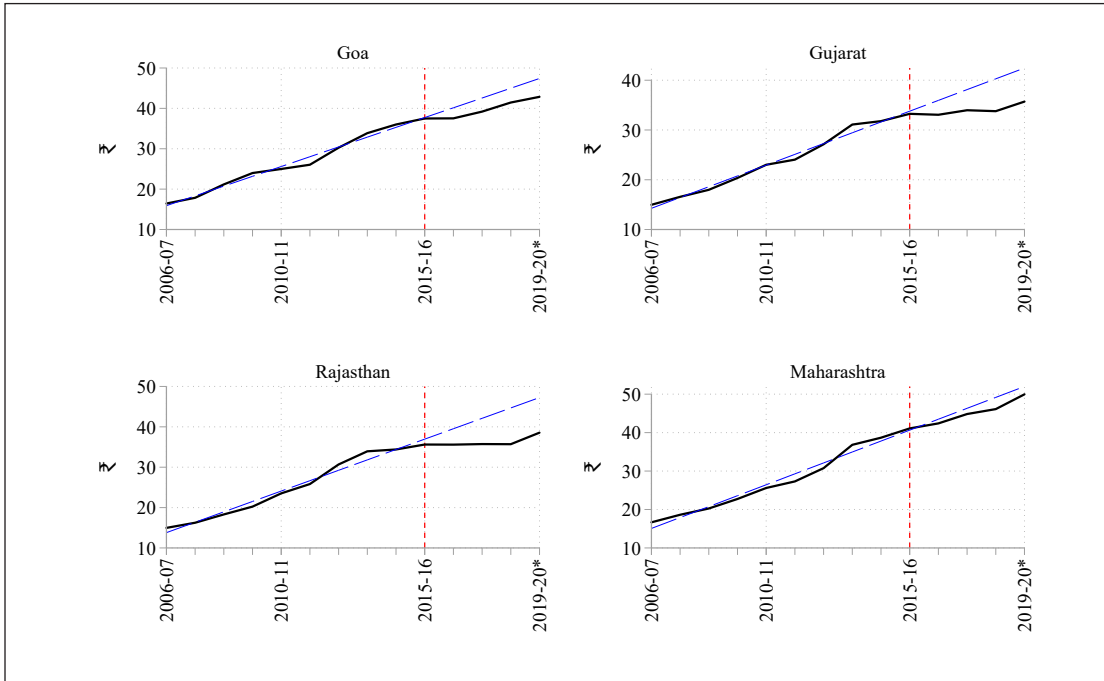
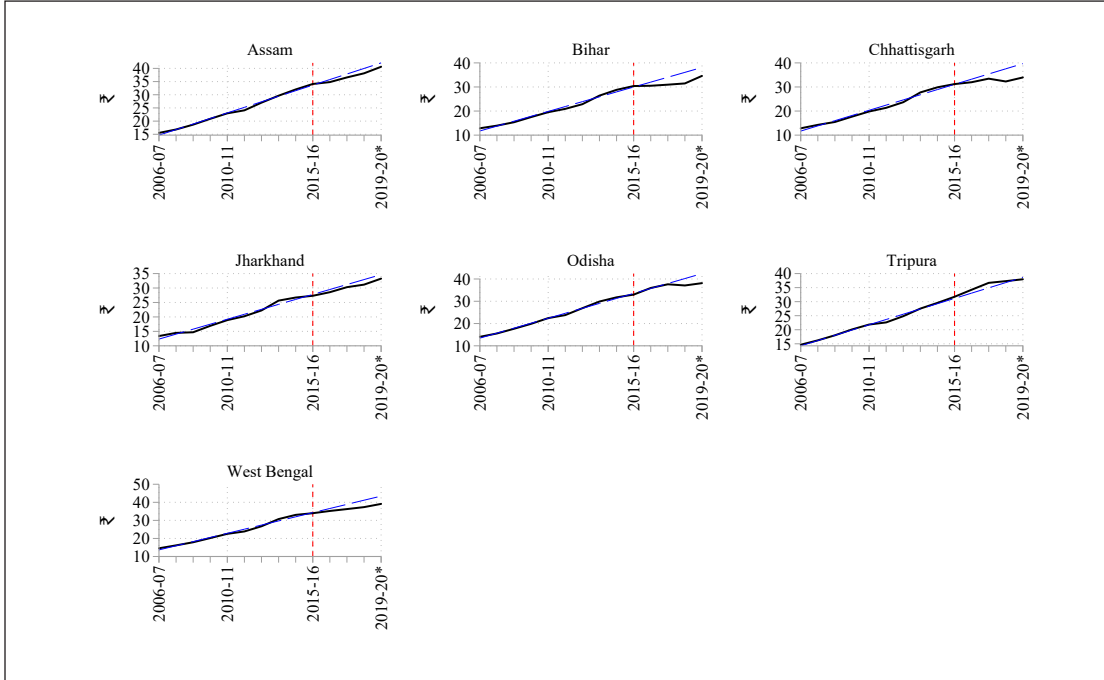
स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: नीली डेश लाइन 2015-16 तक रेखीय प्रवृत्ति को और इसके बाद अनुमान दर्शाती है। लाल बिंदुओं वाली रेखा 2015-16 को व्यक्त करती है।

अप्रैल-अक्टूबर, 2019

चित्र 4: मांसाहारी थाली का राज्यवार मूल्य





स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: नीली डेश लाइन 2015-16 तक रेखीय प्रवृत्ति को और इसके बाद अनुमान दर्शाती है। लाल बिंदुओं वाली रेखा 2015-16 को व्यक्त करती है।

अप्रैल-अक्टूबर, 2019

उस वर्ष में 2 थालियों के मूल्य को उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण से प्राप्त दैनिक मजदूरी के आंकड़ों (2017-18 तक उपलब्ध और 2019-20 तक ज्ञात प्रवृत्ति के आधार पर अनुमानित) से भाग देकर बनाया है। हमने मजद.

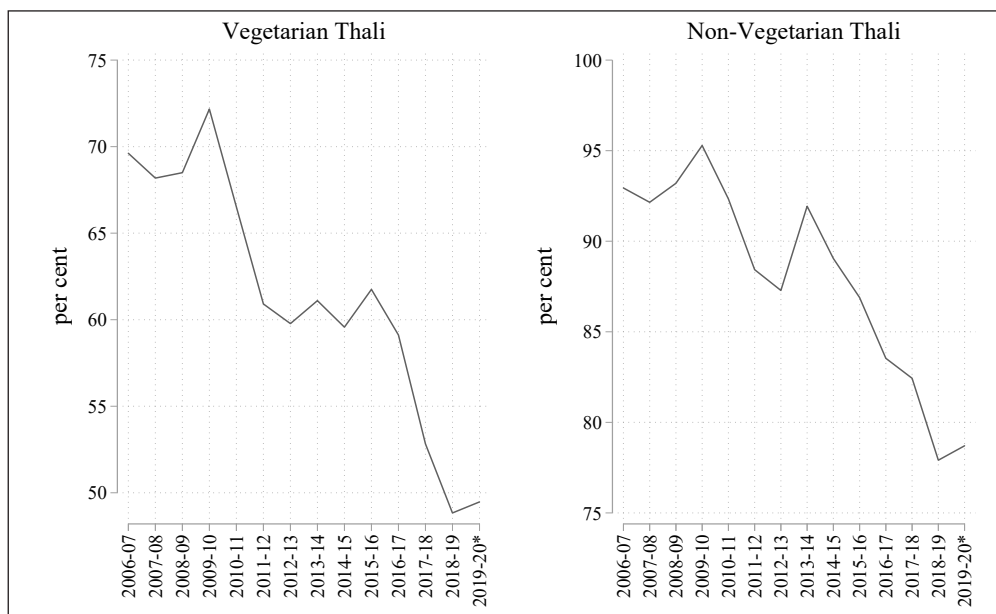
ूरियों के लिए ए एस आई के आंकड़ों का प्रयोग किया है क्योंकि खाद्य मदों के मूल्यों को सी पी आई-डब्ल्यू के निर्माण के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों से लिया गया है। विश्लेषण में शामिल की गई समयावधि के

लिए ए एस आई व्यवस्थित विनिर्माण क्षेत्र में नियोजित श्रमिकों को वार्षिक मजदूरी का आकलन देता है। हमने श्रमिकों की कुल संख्या से श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को भाग देकर श्रमिकों की वार्षिक मजदूरी ज्ञात की हैं। हमने इस प्रत्येक श्रमिक की वार्षिक मजदूरी को 365 दिनों से भाग देकर एक मजदूर की दैनिक मजदूरी निकाली है। चित्र 5 यह दर्शाता है पिछले वर्षों में थाली की वहन क्षमता में वृद्धि हुई है। शाकाहारी थाली के मामले में हमने देखा है कि जो व्यक्ति अपने पांच सदस्य के परिवार के लिए दो थाली पर अपनी मजदूरी का 70% को व्यय करता है वह अपनी दैनिक मजदूरी के 50% से ही थालियों की उसी संख्या को वहन कर सकता है। इसी प्रकार मांसाहारी थाली की वहन क्षमता में भी वृद्धि हुई है। तथा पांच सदस्यों हेतु दो थाली खरीदने हेतु आवश्यक मजदूरी का अंश

2006-07 तथा 2019-20 के मध्य 93 प्रतिशत से घटकर 79 प्रतिशत पर आ गया है।

11.12 वर्ष 2019-20 में (अप्रैल-अक्टूबर 2019) सबसे अधिक किफायती थाली झारखण्ड में थी; झारखण्ड में दो शाकाहारी थालियों के लिए पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए श्रमिक की दैनिक मजदूरी का लगभग 25% की जरूरत थी (चित्र 6)। मांसाहारी थाली भी झारखण्ड में सबसे अधिक वहनीय थी (चित्र 7)। 2006-07 और 2019-20 (अप्रैल-अक्टूबर) के बीच तुलना करने पर पता चलता है कि शाकाहारी थाली सभी विचाराधीन राज्यों में और अधिक किफायती बन गई है। मांसाहारी थाली के मामले में इस अवधि के दौरान बिहार और महाराष्ट्र को छोड़कर सभी राज्यों में वहन क्षमता बढ़ी है। इन दो राज्यों में मामूली गिरावट देखी गई हैं।

चित्र 5: (अखिल भारत स्तर) पांच सदस्य वाले परिवार के लिए दो थालियां खरीदने हेतु श्रमिक की एक दिन की मजदूरी का आवश्यक हिस्सा थाली की वहनीयता



स्रोत: समीक्षा परिकलन

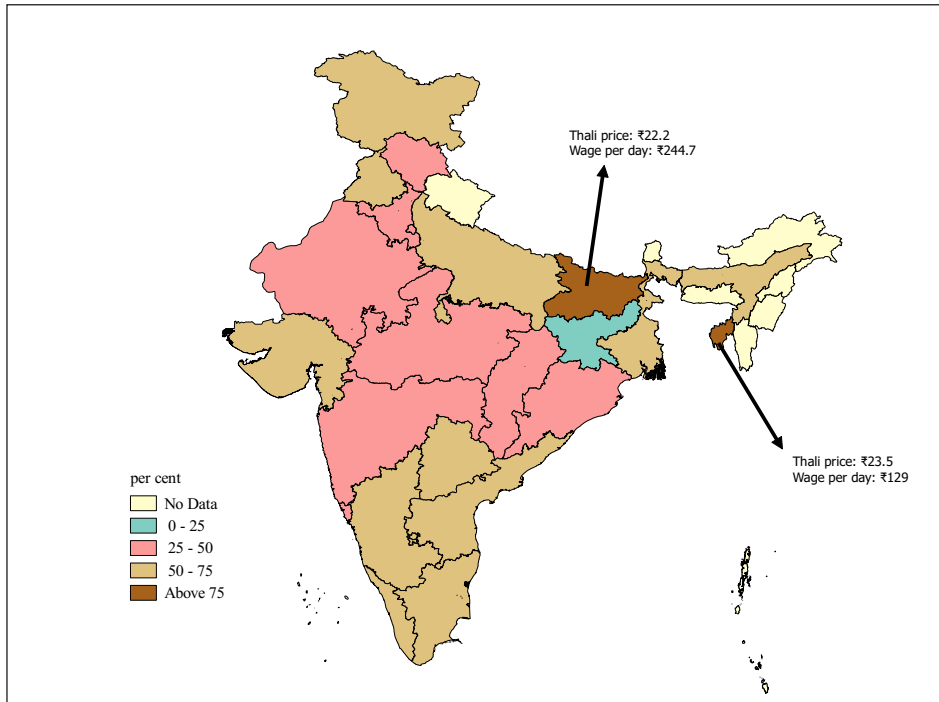
टिप्पणी: वर्ष 2019-20 हेतु गणनाएं अप्रैल-अक्टूबर, 2019 की अवधि के लिए मूल्यों पर आधारित हैं।

थाली के घटकों के मूल्यों का रुझान

11.13 थालियों के मूल्यों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय रुझानों को देखते हुए यह देखना हमें और गहन जानकारी देगा कि थालियों की कीमतों में देखी गई प्रवृत्तियों में किन घटकों का योगदान है। हमने यह

देखा कि अखिल भारतीय स्तर पर लगभग सभी घटकों के मूल्य 2015-16 (चित्र: 8) से अनुमानित मूल्यों की तुलना में कम रहे हैं। दाल के मूल्य 2016-17 तक बढ़े रहे, जिसके पश्चात् एक बड़ी गिरावट देखी गई। इसी प्रकार का स्वरूप पूरे देश

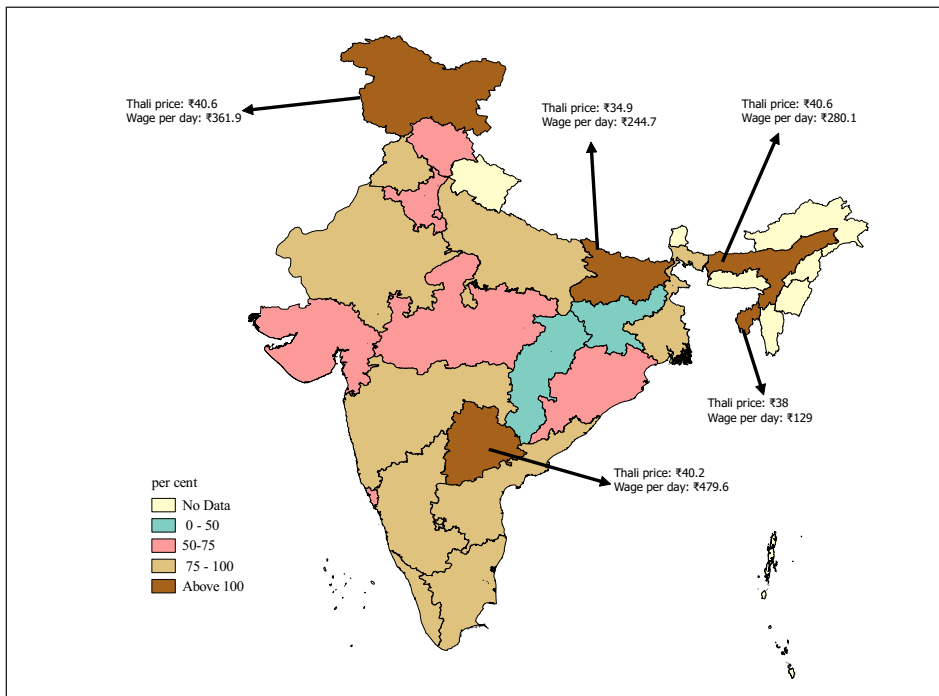
चित्र 6: पांच सदस्यीय परिवार को दो शाकाहारी थालियां उपलब्ध कराने में खर्च एक श्रमिक की मजदूरी का अंश (अखिल भारतीय स्तर पर) वर्ष 2019-20 में



स्रोत: समीक्षा परिकलन

नोट: अप्रैल-अक्तूबर 2019

चित्र 7: पांच सदस्यीय परिवार को दो शाकाहारी थालियां उपलब्ध कराने में खर्च एक श्रमिक की मजदूरी का अंश (अखिल भारतीय स्तर पर) वर्ष 2019-20 में



स्रोत: समीक्षा परिकलन

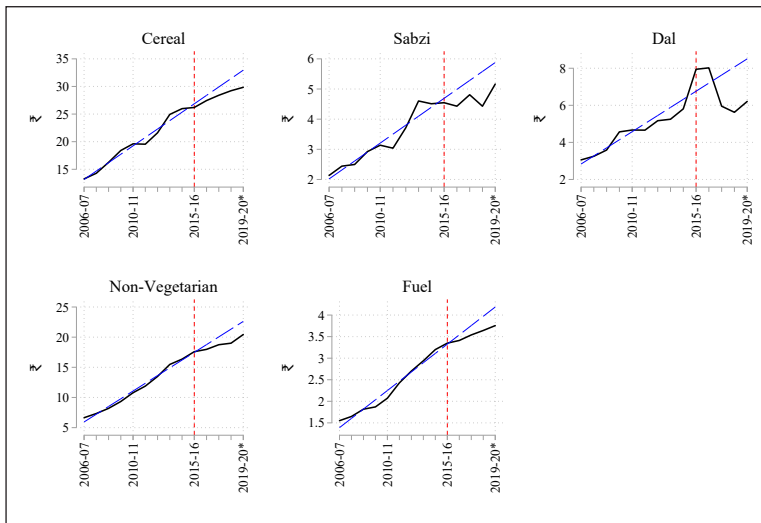
नोट: अप्रैल-अक्तूबर 2019

में देखा गया (चित्र 9-12) हालांकि अन्य क्षेत्रों में सब्जियों के मूल्य स्पष्ट रूप से अनुमानित मूल्य से नीचे रहे, दक्षिण क्षेत्र में सब्जियों के मूल्यों में उतार-चढ़ाव अधिक रहे हैं तथा सब्जी के मूल्य अनुमानित मूल्यों से अधिक रहे हैं।

थाली स्फीति

11.14 थाली स्फीति (थाली के मूल्यों में वर्ष-दर वर्ष वृद्धि), जोकि हमारे विश्लेषण की प्रारंभिक अवधि के दौरान उच्च स्तर पर रही, में काफी गि.

चित्र 8: थाली घटकों के अखिल भारतीय मूल्य

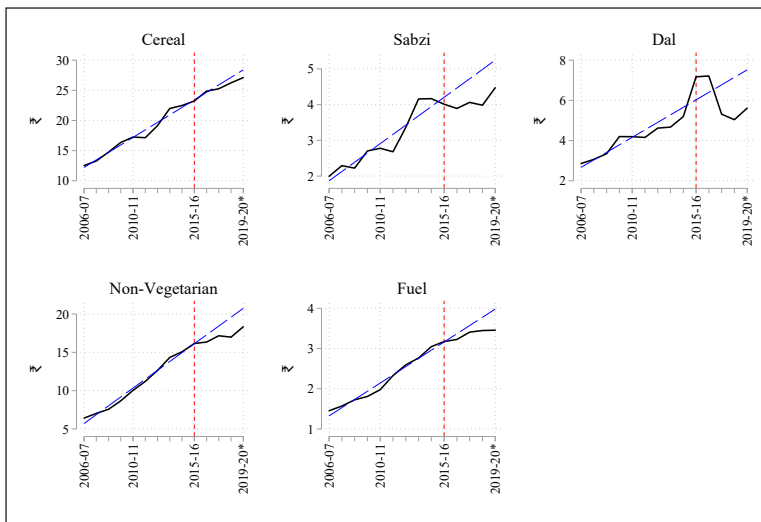


स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अनाज की कीमत 1 किलो अनाज के लिए है, अन्य घटकों की कीमतें एक भोजन के लिए है।

* अप्रैल-अक्टूबर, 2019

चित्र 9: घटकों के मूल्य- उत्तरी क्षेत्र

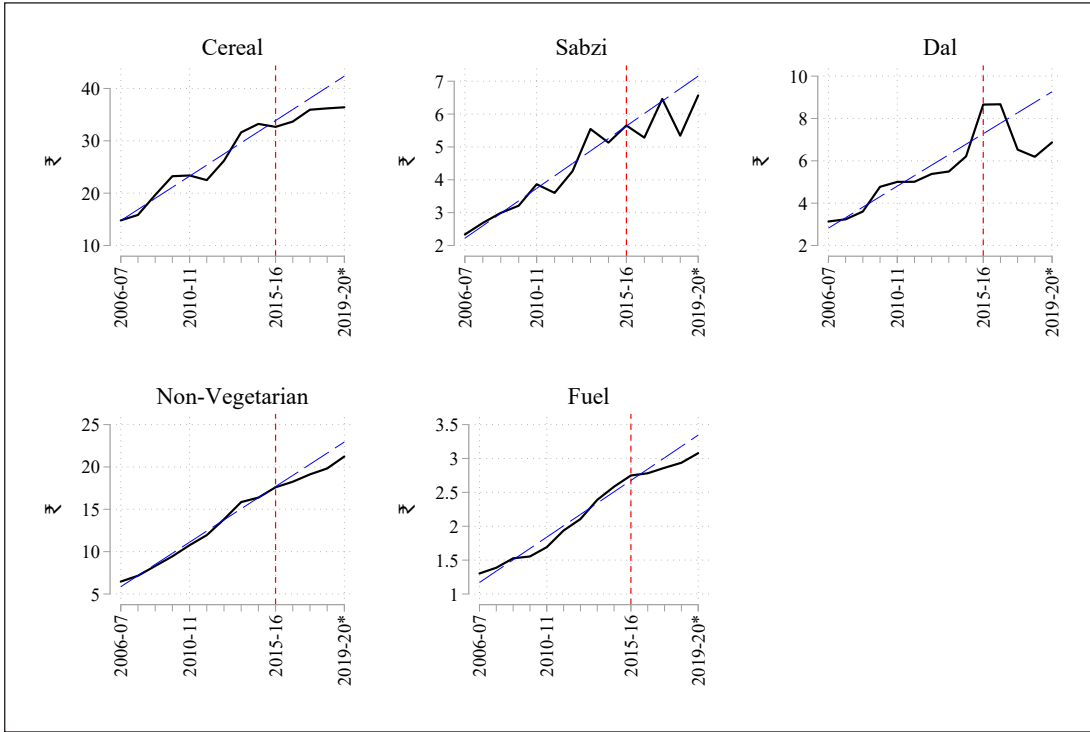


स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अनाज की कीमत 1 किलो अनाज के लिए है, अन्य घटकों की कीमतें एक भोजन के लिए है।

* अप्रैल-अक्टूबर, 2019

चित्र 10: घटकों के मूल्य - दक्षिण क्षेत्र

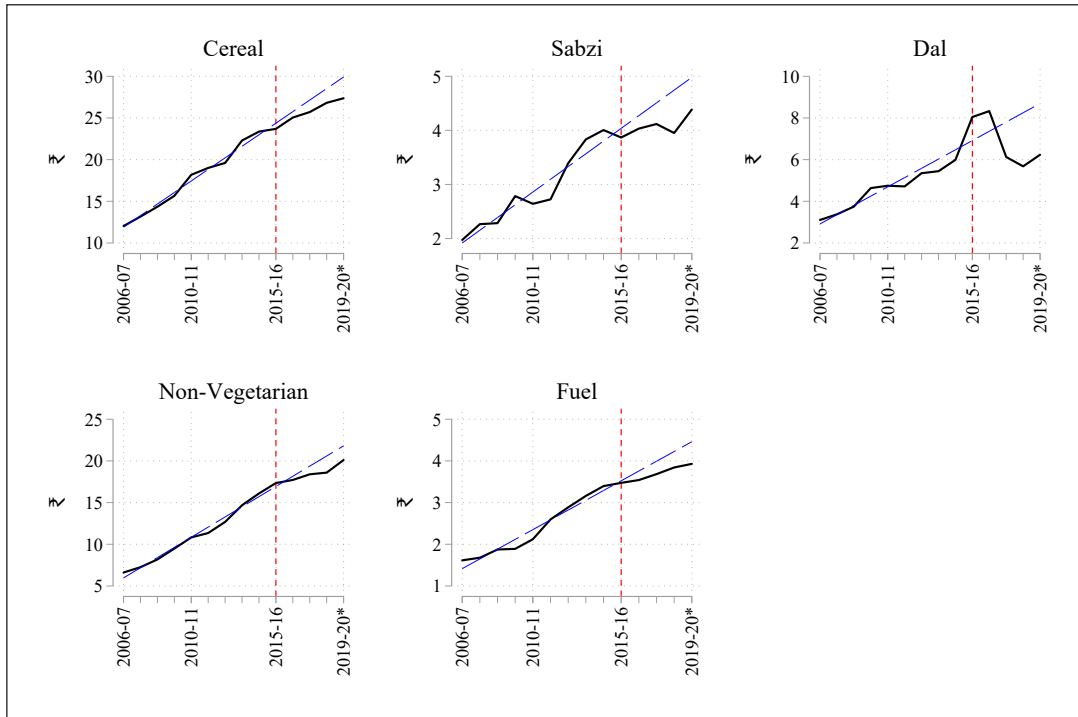


स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अनाज की कीमत 1 किलो अनाज के लिए है, अन्य घटकों की कीमतें एक भोजन के लिए है।

* अप्रैल-अक्टूबर, 2019

चित्र 11: घटकों के मूल्य - पूर्वी क्षेत्र

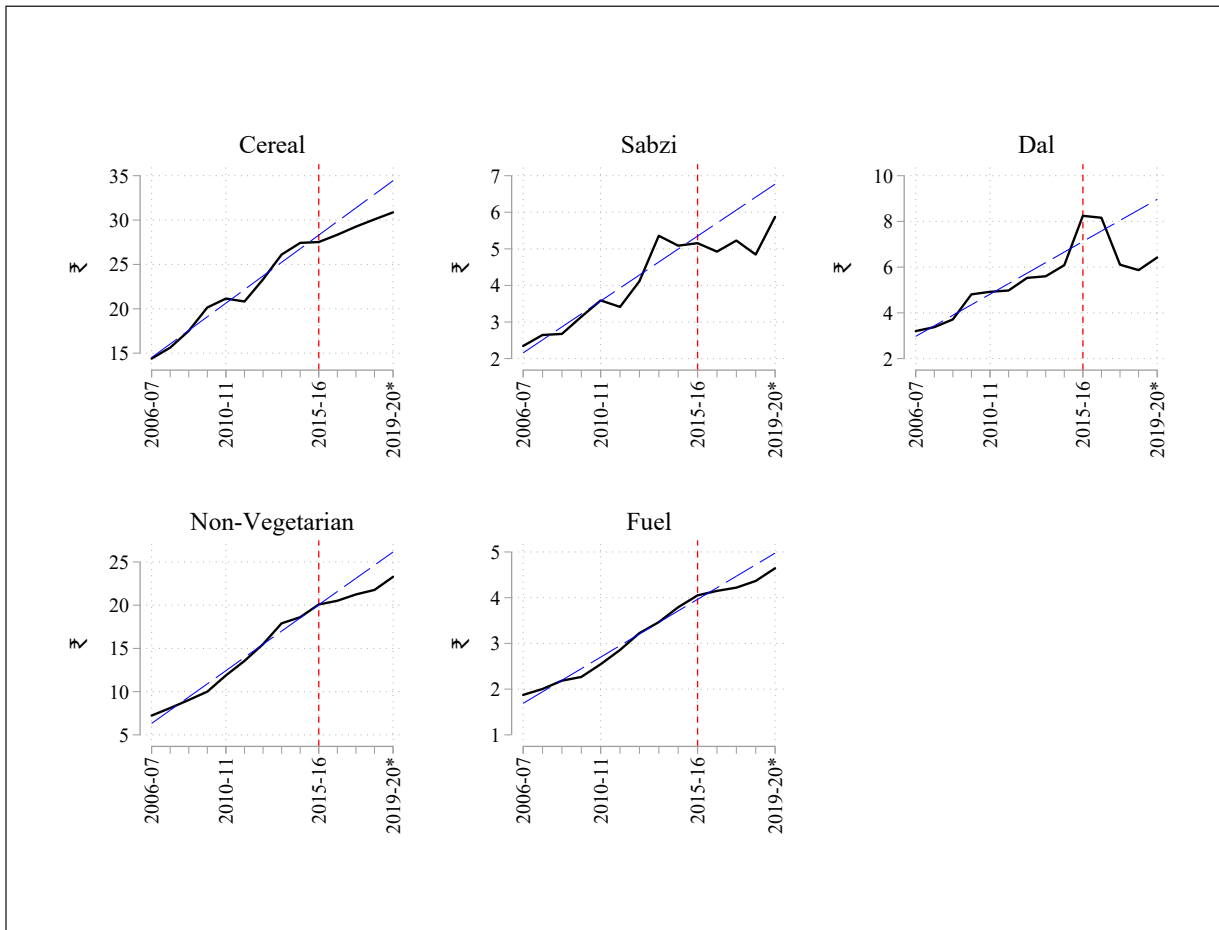


स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अनाज की कीमत 1 किलो अनाज के लिए है, अन्य घटकों की कीमतें एक भोजन के लिए है।

* अप्रैल-अक्टूबर, 2019

चित्र 12: घटकों के मूल्य - पश्चिम क्षेत्र



स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अनाज के मूल्य 1 किलो अनाज के लिए है, अन्य घटकों की कीमतें एक भोजन के लिए है।

* अप्रैल-अक्टूबर, 2019

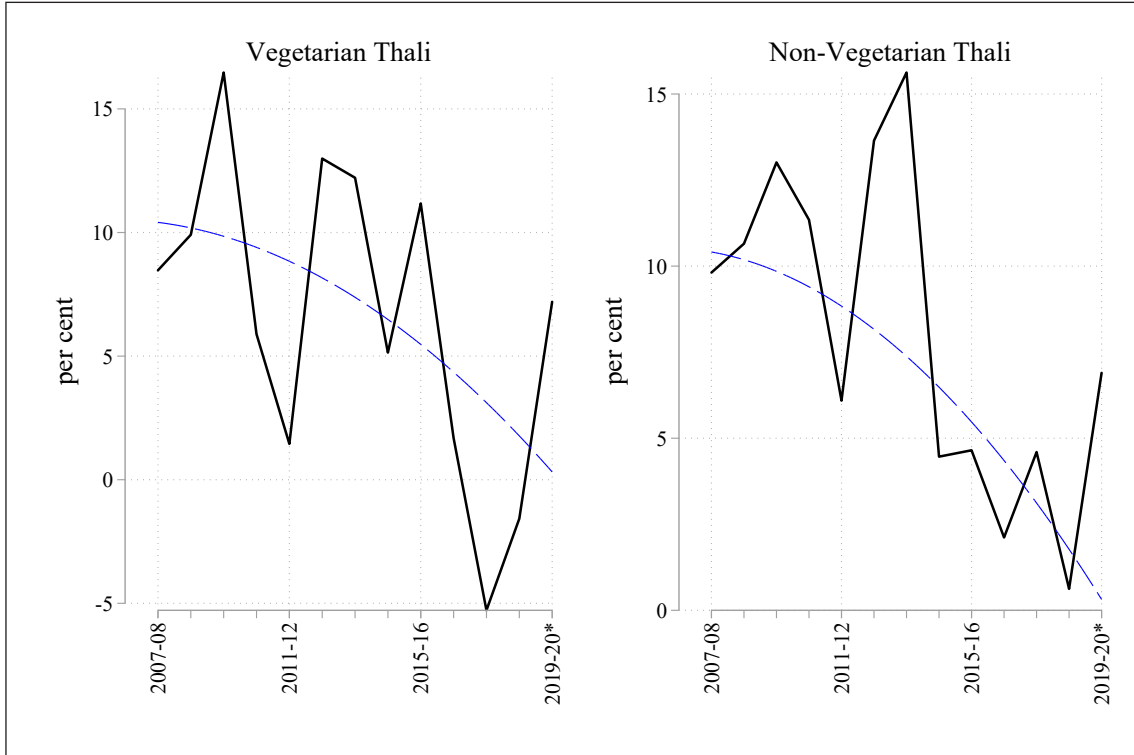
रावट देखी गई है। जैसाकि चित्र 13 स्पष्टतौर पर दर्शाता है, कि 2019-20 में शाकाहारी एवं मांसाहारी थालियों में स्फीति की दर में वृद्धि एक अस्थायी घटना है जोकि पूर्वस्थिति में वापस आ जाएगी जैसा कि पूर्व वर्षों में हुआ है। शाकाहारी थाली के मामले में, अखिल भारतीय स्तर पर स्फीति 2015-16 में प्राप्त किए गए काफी उच्च स्तर से अनुगामी वर्षों में गिरकर शून्य स्तर से भी नीचे पहुंच गई। मांसाहारी थाली के मामले में, 2013-14 के बाद स्फीति में तेजी से गिरावट (चित्र 13) आई है। हम देखते हैं कि समय के साथ-साथ सभी घटकों में स्फीति में गिरावट आई है। जहां अनाज में स्फीति दर इस अवधि के दौरान स्थिर दर पर घट रही है, वहीं सब्जी

(चित्र 14) के अलावा अन्य सभी घटकों में स्फीति में गिरावट में तेजी आई है। पिछले वर्ष के दौरान, दाल, सब्जी एवं मांसाहारी घटकों के लिए स्फीति की दर में वृद्धि हुई है। सभी क्षेत्रों और राज्यों में, सम्पूर्ण थाली की स्फीति में हमें एक ही रूझान नजर आता है जो कि गिरावट का है। (चित्र 15 से 20)

थाली की कीमतों में परिवर्तनशीलता

11.15 इतने वर्षों में यह देखा गया है कि अखिल भारतीय स्तर पर कीमतों में माह-दर-माह परिवर्तनशीलता का कोई स्पष्ट रूझान नहीं है (चित्र 21)। इसी प्रकार क्षेत्रवार और राज्यवार परिवर्तनशीलता में भी कोई विशिष्ट रूझान नहीं है (चित्र 22 व 23)।

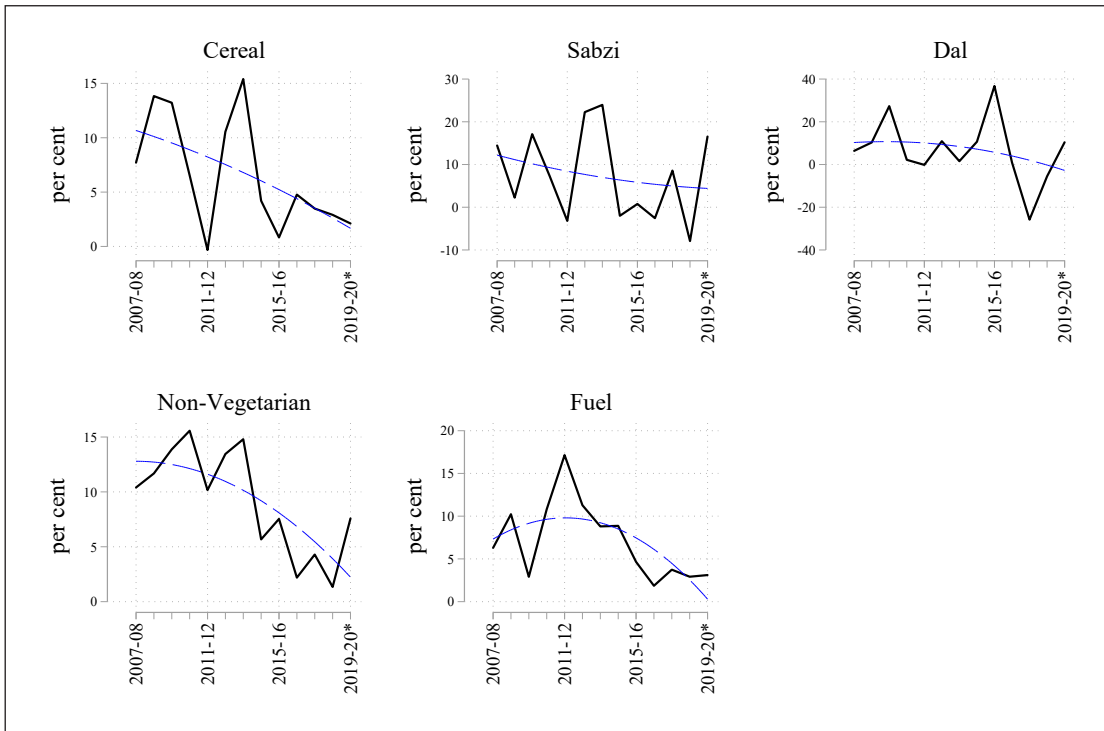
चित्र 13: थाली में अखिल भारतीय स्फीति



स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अप्रैल-अक्टूबर, 2019

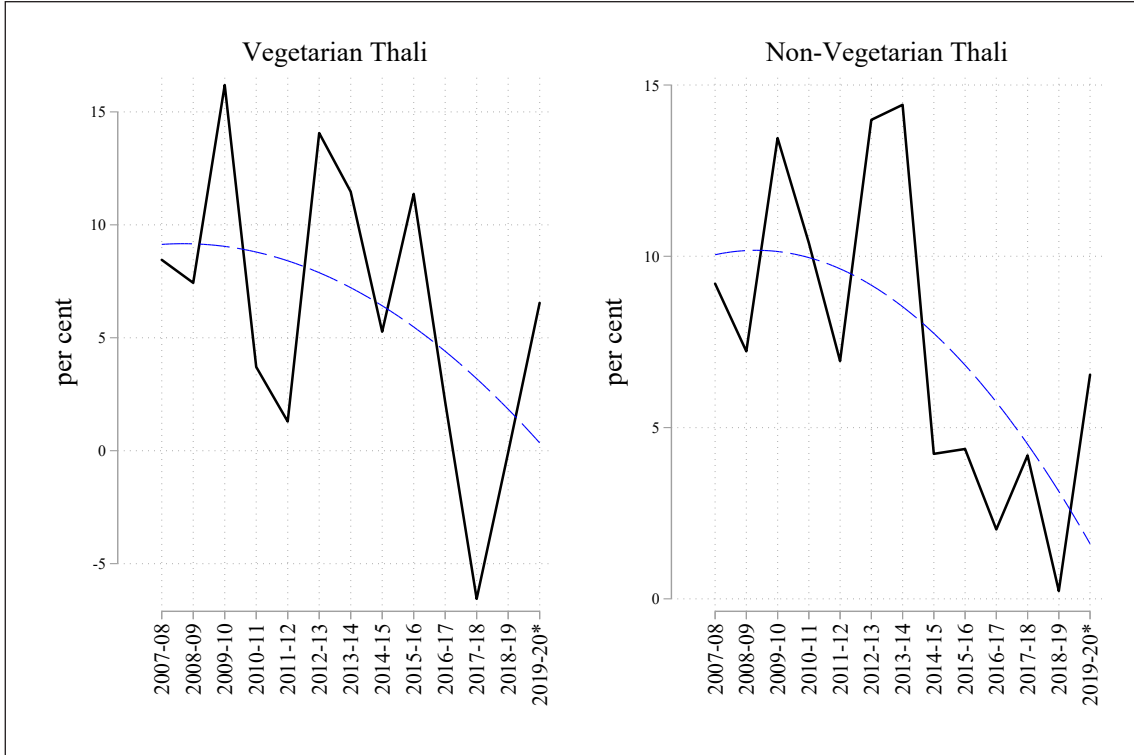
चित्र 14: थाली घटकों में अखिल भारतीय स्फीति



स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अप्रैल-अक्टूबर 2019

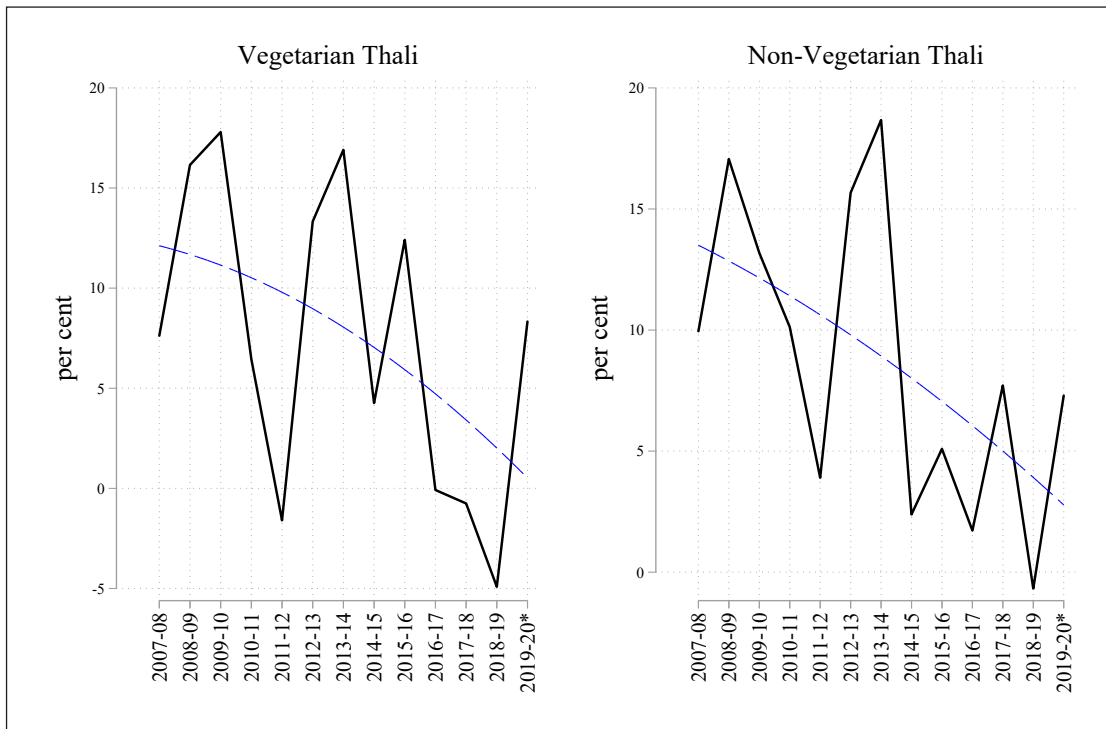
चित्र 15: थाली में उत्तरी क्षेत्र में स्फीति



स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अप्रैल-अक्टूबर, 2019

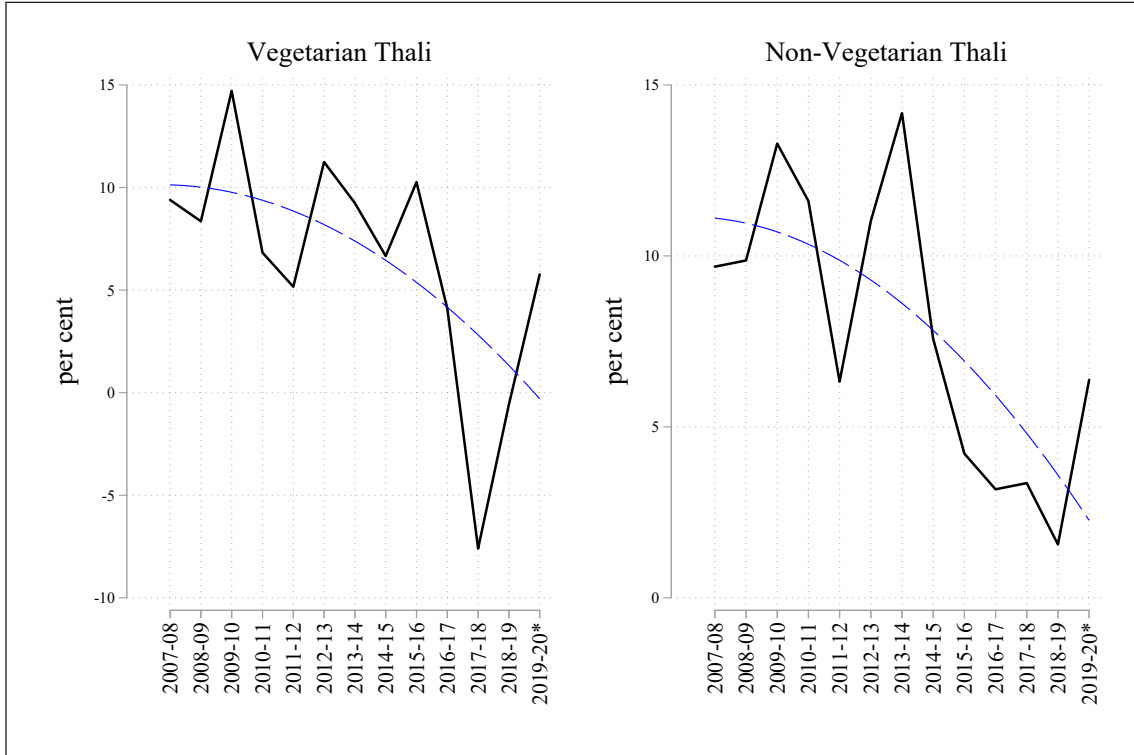
चित्र 16: थाली में दक्षिण क्षेत्र में मुद्रास्फीति



स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अप्रैल-अक्टूबर, 2019

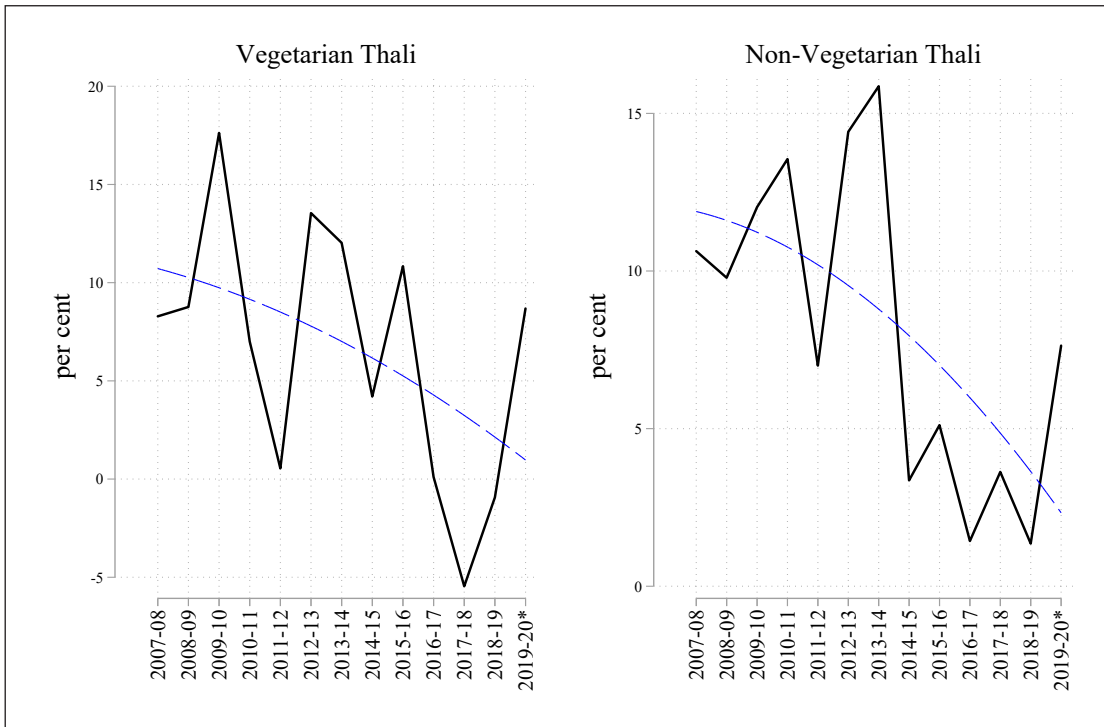
चित्र 17: थाली में पूर्वी क्षेत्र में स्फीति



स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अप्रैल-अक्टूबर 2019

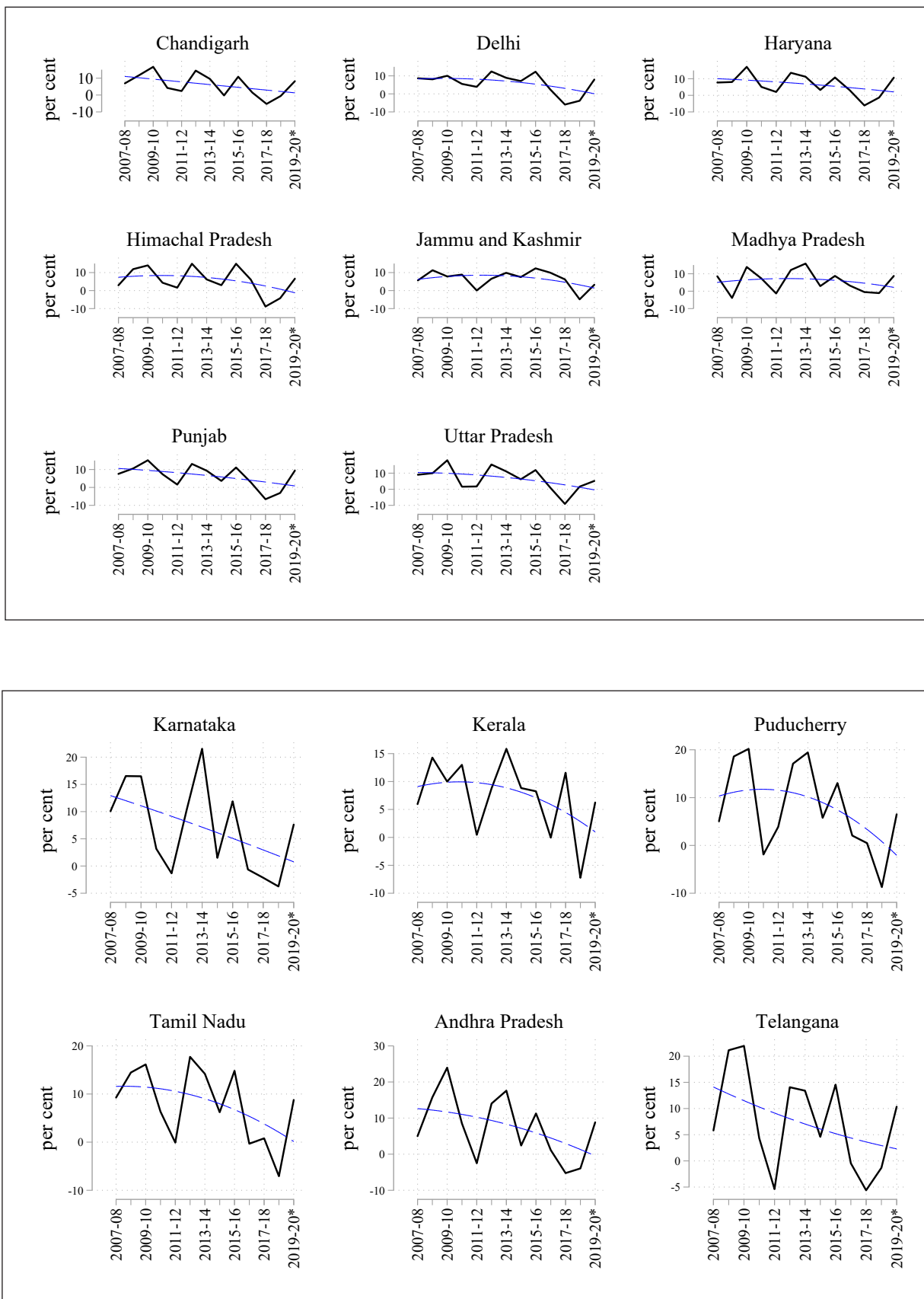
चित्र 18: थाली में पश्चिम क्षेत्र में स्फीति

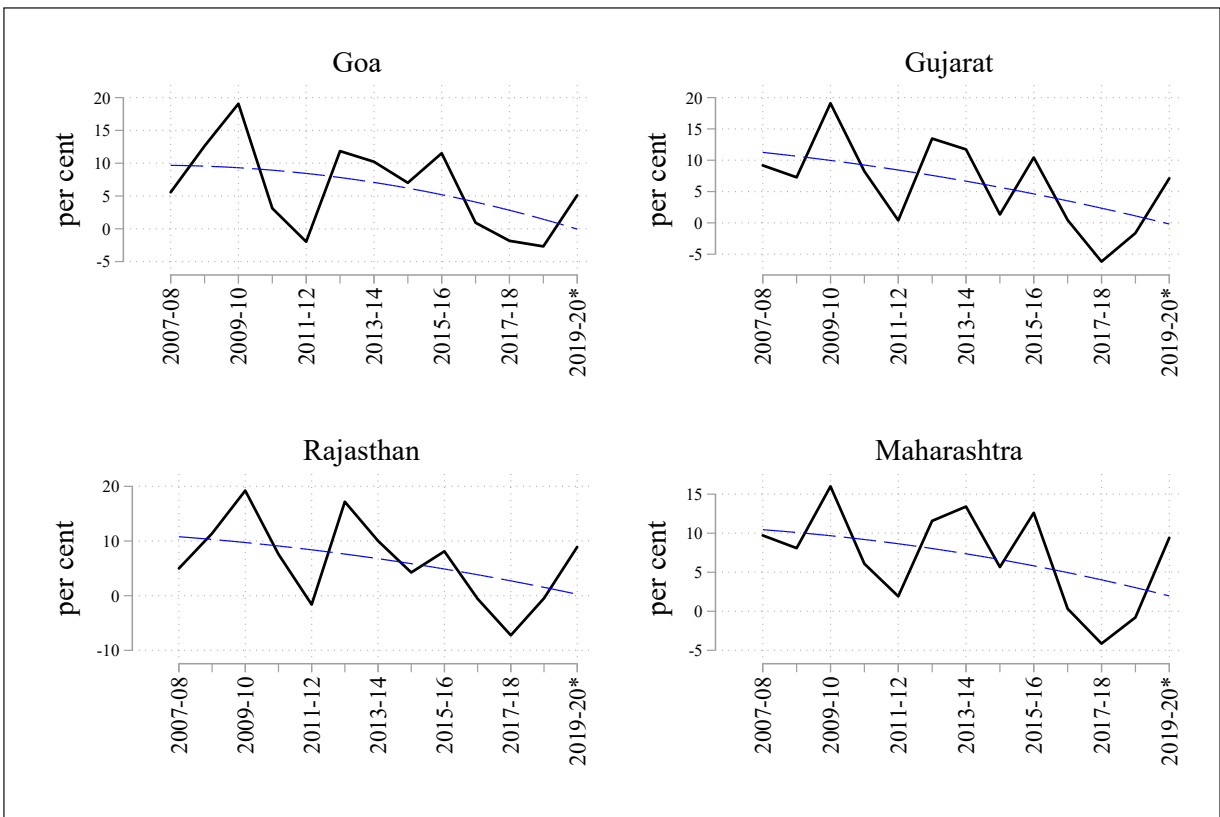
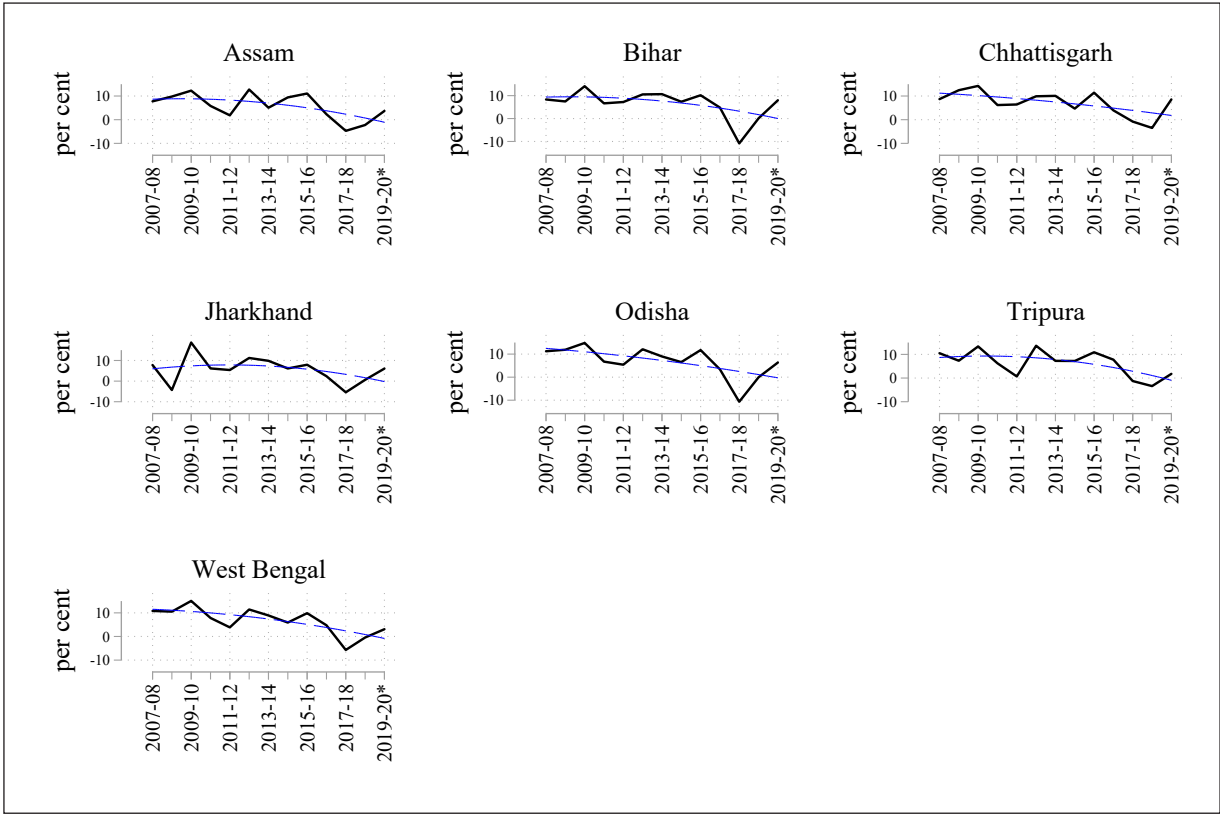


स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अप्रैल-अक्टूबर 2019

चित्र 19: शाकाहारी थाली के मूल्यों में राज्य-वार स्फीति

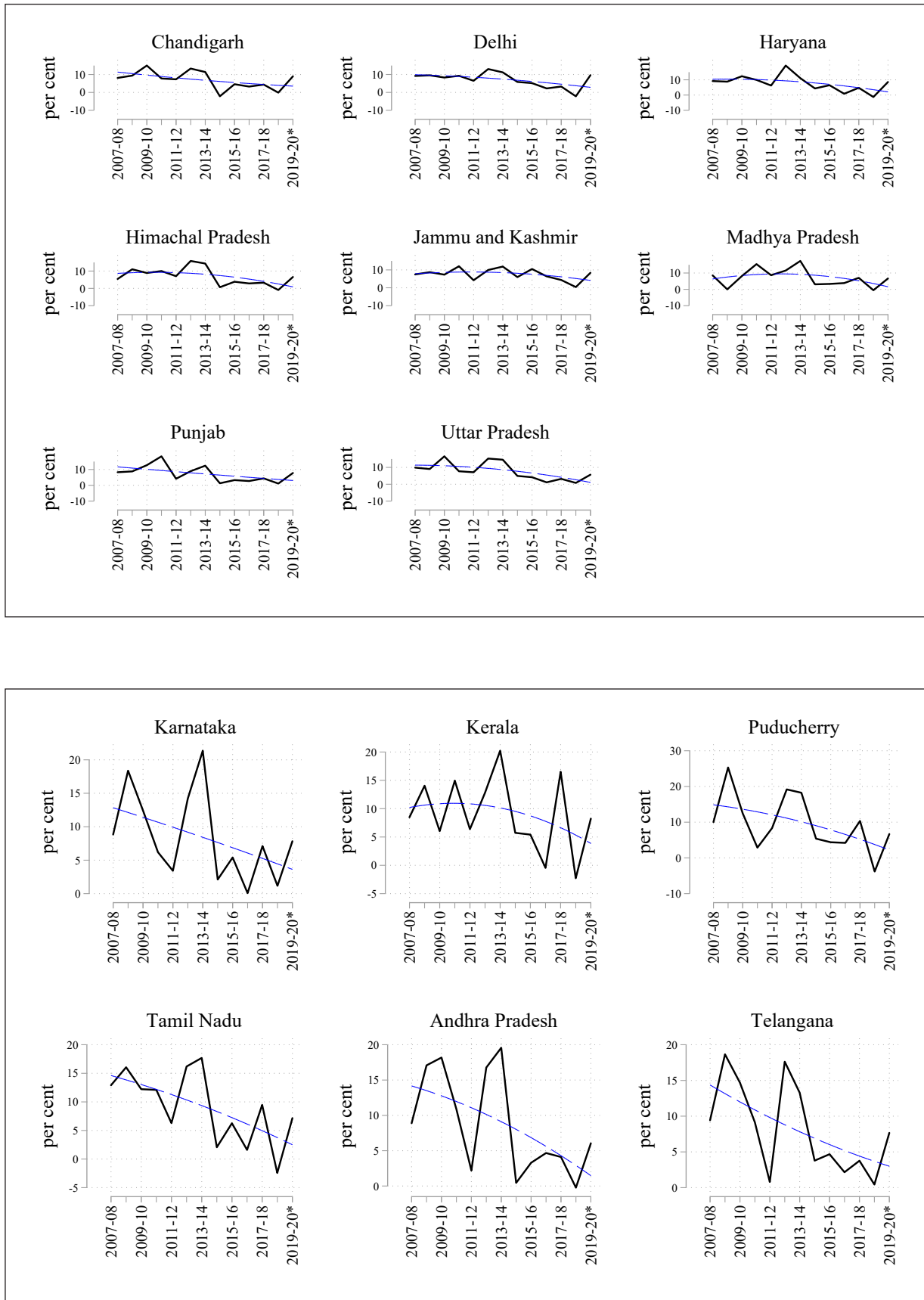


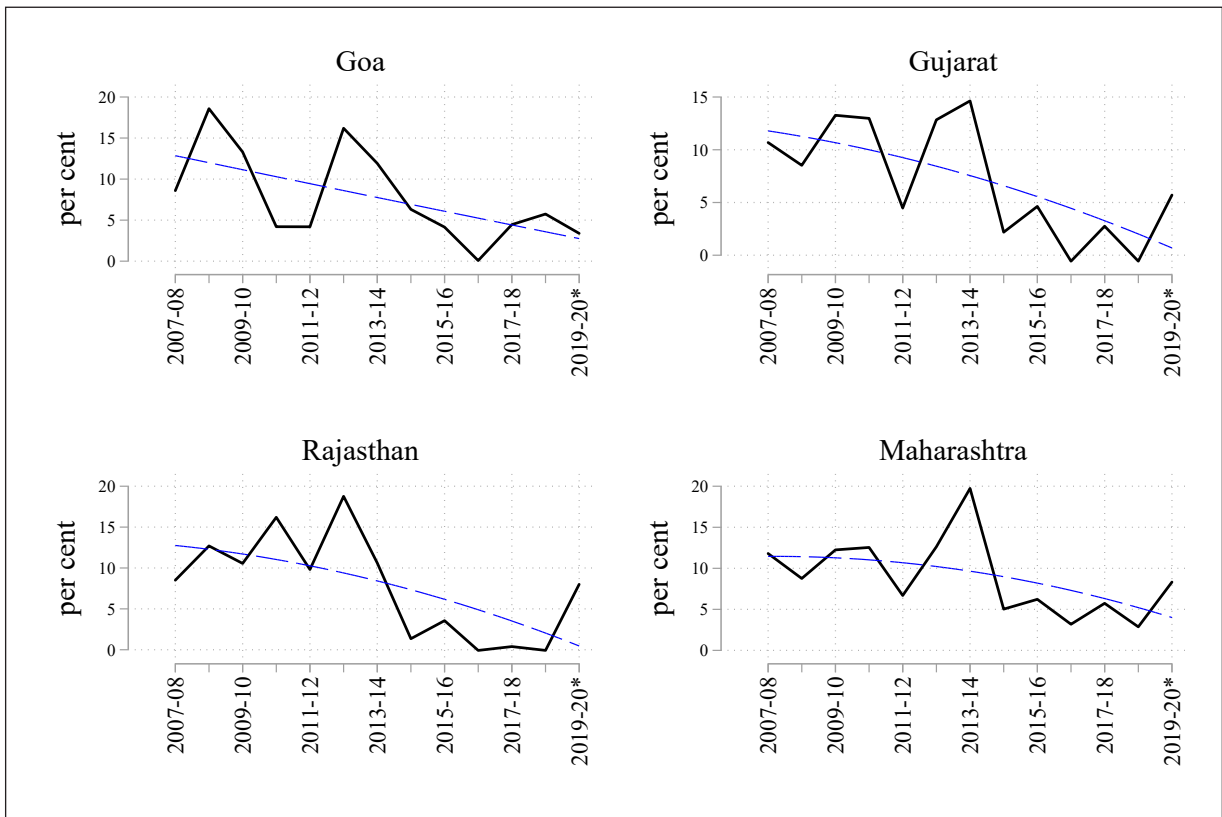
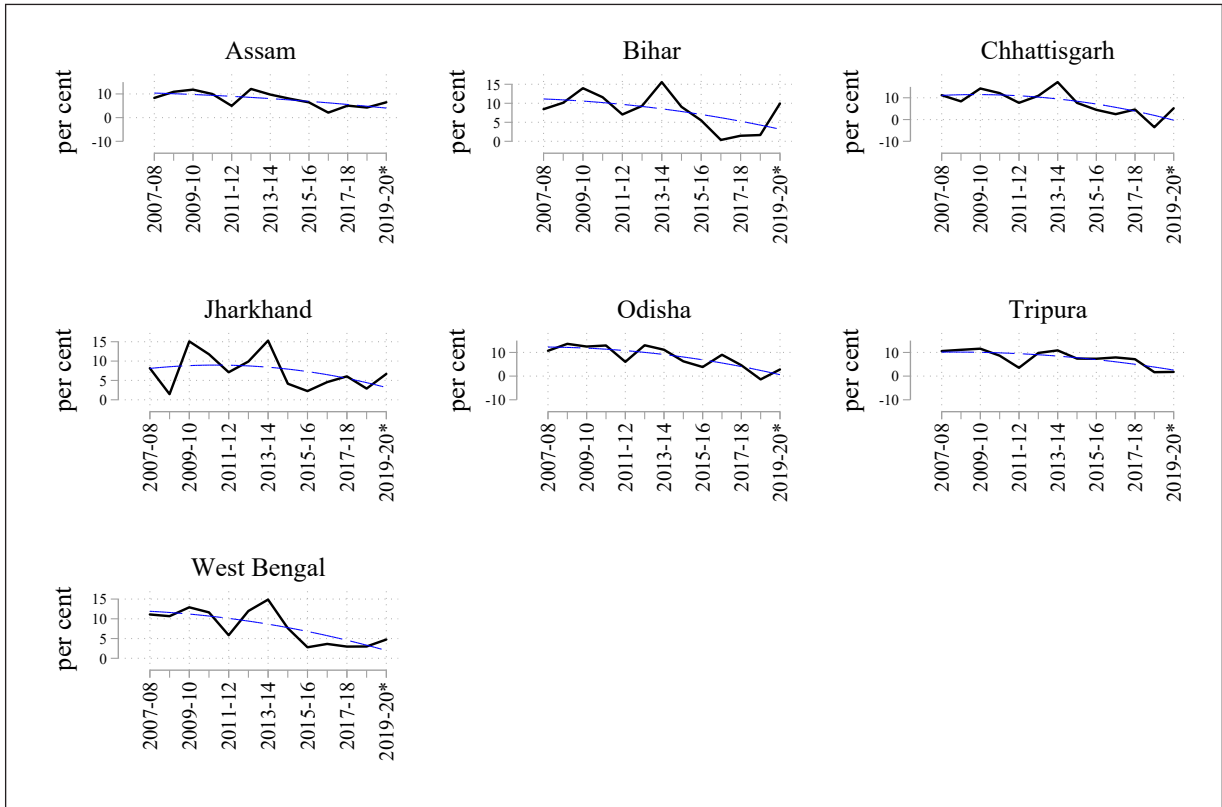


स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अप्रैल-अक्टूबर 2019

चित्र 20: मांसाहारी थाली के मूल्यों में राज्यवार स्फीति

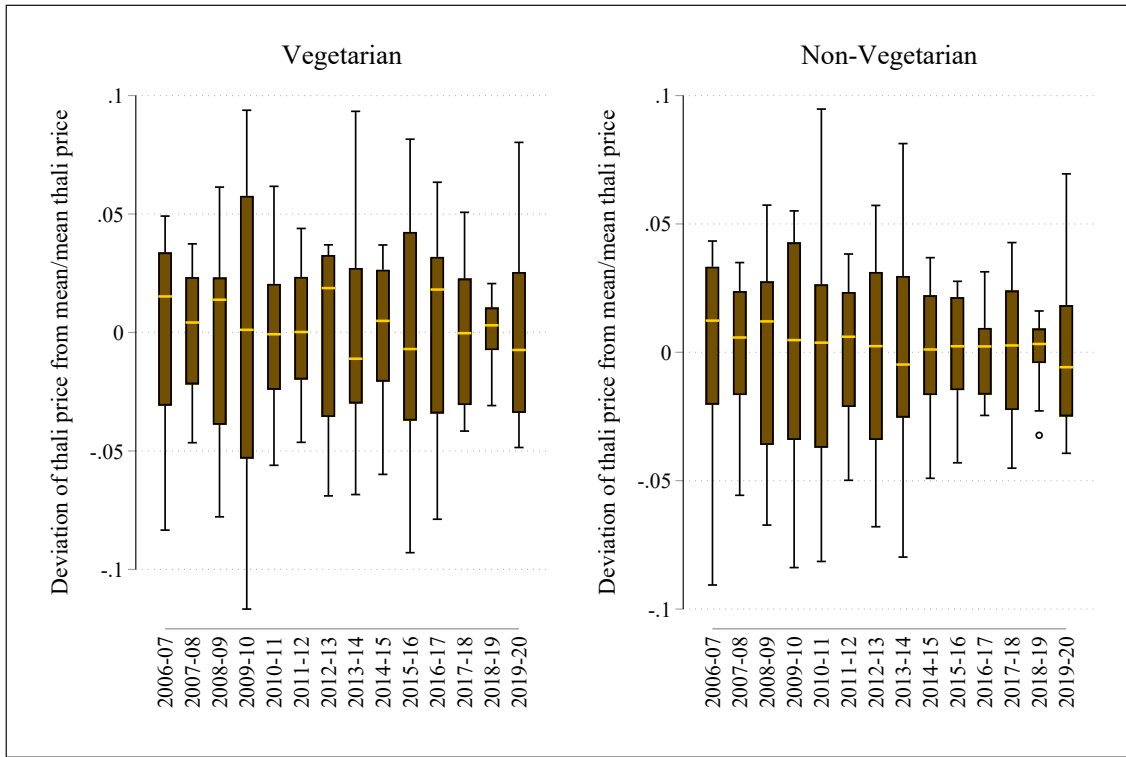




स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अप्रैल-अक्टूबर 2019

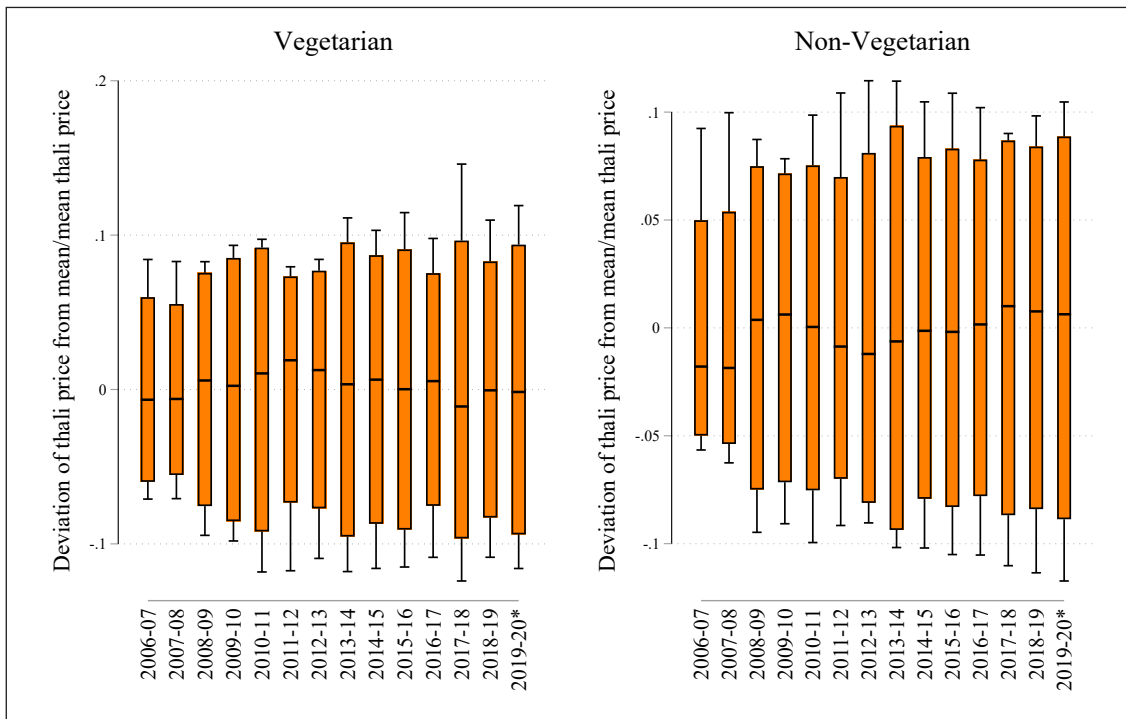
चित्र 21: अखिल भारतीय स्तर पर थाली की कीमतों में माह वार परिवर्तनशीलता, 2006-07 से 2019-20



स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अप्रैल-अक्टूबर 2019

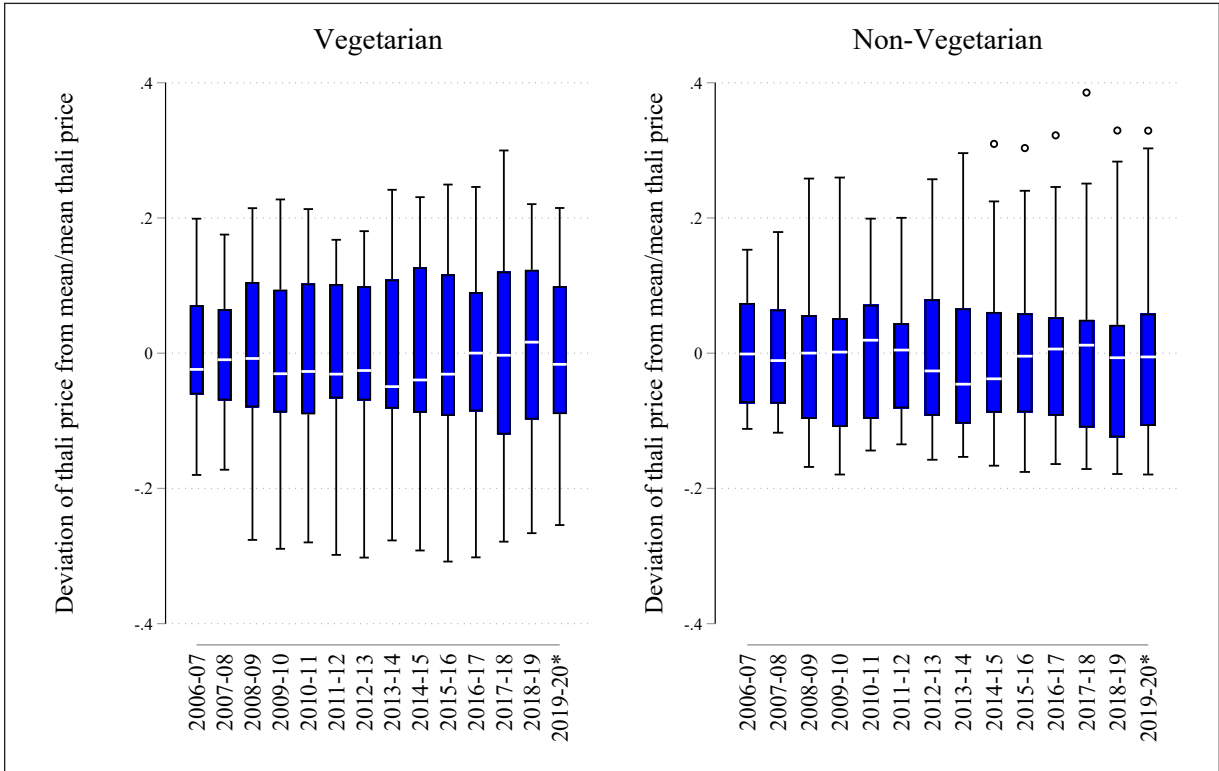
चित्र 22: विभिन्न क्षेत्रों में थाली की कीमत में विभिन्नता, 2006-07 से 2019-20



स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अप्रैल-अक्टूबर 2019

चित्र 23: थाली की कीमतों में राज्यवार विभिन्नता, 2006-07 से 2019-20



स्रोत: समीक्षा परिकलन

टिप्पणी: अप्रैल-अक्टूबर 2019

निष्कर्ष

11.16 भोजन केवल साध्य नहीं बल्कि मानव पूंजी के विकास में भी एक आवश्यक घटक है इसलिए राष्ट्रीय संपदा निर्माण के लिए भी महत्वपूर्ण है। 'जीरो हंगर' को विश्व के राष्ट्रों द्वारा एक सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) के रूप में स्वीकार किया गया है। यह लक्ष्य (एसडीजी 2) अन्य एसडीजी जैसे लक्ष्य 1 (गरीबी का अंत), लक्ष्य 4 (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा), लक्ष्य 5 (लैंगिक समानता), लक्ष्य 12 (जवा. बदेह खपत एवं उत्पादन), लक्ष्य 13 (जलवायु अनुयोजन) और लक्ष्य 15 (भूमि पर जीवन) से संबंधित है।

11.17 इस अध्याय में 2006-07 से 2019-20 (अप्रैल-अक्टूबर, 2019) के दौरान खाद्य पदार्थों की कीमतों के क्रमिक विकास को थाली के माध्यम से देखा गया है। 2015-16 से शाकाहारी थाली की कीमतों में अखिल भारतीय स्तर के सा. थ-साथ क्षेत्रीय स्तर पर गिरावट देखी गई, यद्यपि इस वर्ष थाली की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। ऐसा सब्जियों और दालों की कीमतों में पहले के सालों के मुकाबले आई गिरावट के कारण हुआ है। सभी अन्य घटकों एवं थाली की कीमतों में गिरावट के कारण हमें समीक्षाधीन अवधि के दौरान गिरावट की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। थाली की वहन करने की क्षमता में कामगारों के वेतन के मुकाबले सुधार से आम व्यक्ति के कल्याण में बेहतरी का संकेत मिलता है।

एक नजर में अध्याय

- थालीनॉमिक्स, पूरे भारत में थाली के लिए आम व्यक्ति द्वारा कितना भुगतान किया जाता है परिमाणित करने का एक प्रयास है।
- विश्लेषण के लिए 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 80 केन्द्रों के लिए अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2019 तक औद्योगिकी कामगारों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से मासिक आंकड़ों का उपयोग किया गया है।
- 2015-16 को वह वर्ष माना जा सकता है जब खाद्य मूल्य के व्यवहार में परिवर्तन हुआ था। 2014-15 से अनेक सुधारात्मक उपाय किए गए थे ताकि बेहतर और अधिक पारदर्शी मूल्य खोज हेतु कृषिगत उत्पादों के बाजारों की प्रभाविता व कुशलता व कृषि क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाई जा सके।
- पूरे भारत और चारों क्षेत्रों-उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम- में हम देखते हैं कि 2015-16 से शाकाहारी थाली के मूल्य में काफी कमी आई है हालांकि मूल्य में 2019-20 में वृद्धि हुई है।
- 2015-16 के बाद शाकाहारी थाली के मामलों में खाद्य मूल्यों में कमी होने से औसत परिवार को औसतन 10887 रु. का लाभ हुआ है। इसी प्रकार जो परिवार औसतन दो मांसाहारी थाली खाता है उसे समान अवधि के दौरान औसतन 11787 रु. का लाभ हुआ है।
- एक औसत औद्योगिकी कामगार की वार्षिक आमदनी का उपयोग करते हुए हम पाते हैं कि 2006-07 से 2019-20 तक शाकाहारी थाली की वहनीयता में 29 प्रतिशत सुधार हुआ जबकि मांसाहारी थाली की वहनीयता में 18 प्रतिशत तक सुधार हुआ है।

संदर्भ

NIN, “*Dietary Guidelines for Indians -- A Manual*,” National Institute of Nutrition, Hyderabad, 2011.